सत्यमेव जयते

विदेश मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट 2015-16

UFA
MAKE IN INDIA
PRIME MINISTER OF THE REPUBLIC OF INDIA

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2015-16

विदेश मंत्रालय
नई दिल्ली

प्रकाशित :

नीति नियोजन एवं अनुसंधान प्रभाग, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

यह वार्षिक रिपोर्ट वेबसाइट www.mea.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

पुस्तक के आवरण पर साउथ ब्लॉक को दर्शाया गया है, जहां 1947 से ही विदेश मंत्रालय स्थित है। इसके पीछे के कवर पर जून 2011 के बाद बने विदेश मंत्रालय के नए भवन, जवाहरलाल नेहरु भवन के बाहरी तथा भीतरी परिसर की विभिन्न तस्वीरों का कोलाज है। इस भवन को हाल ही में जुलाई 2015 में सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार सर्वश्रेष्ठ कार्यालय भवन घोषित किया गया तथा राजधानी में 49 सरकारी भवनों के बीच समग्र स्वच्छता के लिए हुई जांच में स्वच्छ भारत अभियान (एसबीए) रेटिंग में प्रथम रहा।

मुख्य पृष्ठ के अंदर की तरफ विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की भारत यात्रा तथा माननीय राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री एवं विदेश राज्य मंत्री की विदेश यात्राओं के दौरान ली गई तस्वीरों का एक कोलाज दर्शाया गया है।

अभिकल्पन एवं मुद्रण :

डॉल्फिन प्रिन्टो–ग्राफिक्स
4ई / 7, प्रथम तल, पाबला बिल्डिंग,
झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली – 110055
दूरभाषा : 011–23593541–42
ई–मेल : dolphinprinto2011@gmail.com

विषयवस्तु

	प्रस्तावना और सारांश	i-xxvi
1.	भारत के पड़ोसी देश	1
2.	दक्षिण–पूर्व एशिया और एशिया–प्रशांत	25
3.	पूर्वी एशिया	43
4.	यूरेशिया	49
5.	खाड़ी तथा पश्चिम एशिया	58
6.	अफ्रीका	72
7.	यूरोप और यूरोपीय संघ	94
8.	अमेरिका	120
9.	संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संगठन तथा विधि एवं संधि प्रभाग	141
10.	निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामले	158
11.	बहुपक्षीय आर्थिक संबंध	163
12.	दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) और बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक)	168
13.	विकास सहयोग	171
14.	निवेश तथा प्रौद्योगिकी संवर्धन	176
15.	ऊर्जा सुरक्षा	179
16.	राज्य प्रभाग	181
17.	आतंकवाद का सामना	186
18.	वैश्विक साइबर मुद्दे	187
19.	सीमा प्रकोष्ठ	188
20.	नीति नियोजन एवं अनुसंधान प्रभाग	189
21.	प्रोटोकॉल	191
22.	कोंसली, पासपोर्ट और वीजा सेवाएं	194
23.	प्रवासी भारतीय कार्य	206
24.	प्रशासन और स्थापना	221
25.	सूचना का अधिकार और मुख्य जनसूचना अधिकारी का कार्यालय	224
26.	ई–गवर्नेंस तथा सूचना प्रौद्योगिकी	225
27.	संसद और समन्वय प्रभाग	226
28.	विदेश प्रचार तथा लोक राजनय प्रभाग	229
29.	विदेश सेवा संस्थान	232
30.	नालंदा प्रभाग	236
31.	राजभाषा कार्यान्वयन नीति और विदेशों में हिंदी का प्रचार–प्रसार	237
32.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद	240
33.	विदेशी मामलों की भारतीय परिषद	244
34.	विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली	249
35.	पुस्तकालय और अभिलेखागार	260
36.	वित्त और बजट	262

परिशिष्ट

परिशिष्ट I	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 की अवधि के दौरान अन्य देशों के साथ नवीकृत अथवा संपन्न किए गए संधि/अभिसमय/करार	265
परिशिष्ट II	01 जनवरी–31 दिसंबर, 2015 की अवधि के दौरान जारी पूर्णाधिकार दस्तावेज	311
परिशिष्ट III	जनवरी 2015 से दिसंबर 2015 की अवधि के दौरान जारी अनुसमर्थन/सहमति दस्तावेज	312
परिशिष्ट IV	आई टी ई सी तथा स्काप देशों की सूची	318
परिशिष्ट V	आई टी ई सी/स्काप के पैनल में शामिल संस्थाओं की सूची	321
परिशिष्ट VI	नीति नियोजन तथा अनुसंधान प्रभाग द्वारा, 2015–16 के दौरान आंशिक अथवा पूरी तौर पर वित्तपोषित किए गए विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा आयोजित/चलाए गए सम्मेलन/संगोष्ठियां/अध्ययन परियोजनाएं	323
परिशिष्ट VII	01 जनवरी से दिसंबर 2015 के दौरान प्राप्त पासपोर्ट आवेदन तथा जारी किए गए पासपोर्टों की कुल संख्या, कुल विविध आवेदन प्राप्त तथा प्रदान की गई सेवाएं, तत्काल योजना के तहत जारी किए गए पासपोर्टों की कुल संख्या एवं अर्जित राजस्व एवं पासपोर्ट कार्यालय का कुल राजस्व एवं व्यय दर्शाता विवरण।	324
परिशिष्ट VIII	31 दिसंबर, 2015 तक केंद्रीय पासपोर्ट संगठन के संवर्ग में कर्मचारियों की कुल संख्या	326
परिशिष्ट IX	31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार मुख्यालय तथा विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों में संवर्ग संख्या (वाणिज्य मंत्रालय द्वारा बजट में शामिल किये गये पदों एवं संवर्ग–बाहय पदों सहित)	327
परिशिष्ट X	01 अप्रेल, 2015 से 31 मार्च, 2016 की अवधि के लिए आरक्षित रिक्तियों सहित मंत्रालय में सीधी भर्ती, विभागीय पदोन्नति तथा सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा की गई भर्तियों का ब्यौरा	328
परिशिष्ट XI	विभिन्न भाषाओं में प्रवीणता रखने वाले भारतीय विदेश सेवा अधिकारियों की संख्या	329
परिशिष्ट XII	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा अप्रैल से नवंबर 2015 की अवधि के दौरान आयोजित प्रदर्शनियों एवं सेमीनारों की सूची	330
परिशिष्ट XIII	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा अप्रैल से नवंबर 2015 की अवधि के दौरान आयोजित प्रदर्शनियों (देश के बाहर जाने वाले और आने वाले) की सूची	332
परिशिष्ट XIV	आर आई एस प्रकाशनों की सूची	334
परिशिष्ट XV	2015–16 में विदेश मंत्रालय के लिए वित्तीय व्यवस्था	336
परिशिष्ट XVI	2015–16 बजट अनुमानों में प्रमुख क्षेत्रों के लिए आबंटन	337
परिशिष्ट XVII	भारत के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के प्रमुख गंतव्य	338
परिशिष्ट XVIII	लंबित सी तथा एजी लेखापरीक्षा पैरा की स्थिति	339
संक्षिप्तियां		342

प्रस्तावना और सारांश

अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 की अवधि के बीच शेष विश्व के साथ भारत के कार्यकलापों में नवीन ऊर्जा, शक्ति और आयोजना की झलक मिली। सरकार ने अनेक क्षेत्रों में ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने कार्यकाल के पहले कुछ महीनों में विदेश नीति की जो प्राथमिकताएं निर्धारित की थी उनमें और मजबूती आई। न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि घरेलू स्तर पर भी विदेश नीति की सक्रियता नजर आने लगी, और इसमें निरंतरता तथा बदलाव दोनों के तत्व मौजूद थे।

भारत ने एक ऐसे आत्मविश्वासी, बेबाक, उभरती शक्ति के रूप में विश्व में अपनी नई भूमिका निभानी जारी रखी जो विश्व में अपनी जगह बनाने और अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए इच्छुक है। हमने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया ही नहीं दी अपितु अक्सर ऐसे घटनाक्रमों को आकार दिया और उनकी पहल की। विश्व ने भी क्षेत्रीय और वैश्विक विजन वाले एक दृढ़प्रतिज्ञ तथा निर्णायक नेतृत्व में एक प्रमुख शक्ति के रूप में भारत की क्षमताओं को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक शासन सुधार, जलवायु परिवर्तन, बहुपक्षीय व्यापार सौदों, इंटरनेट अभिशासन तथा साइबर सुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जैसे विभिन्न मुद्दों पर वैश्विक बहस को आकार देने में भारत के दृष्टिकोण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

"पड़ोसी देश पहले" की घोषित नीति के तहत इस अवधि के दौरान हमारे निकटस्थ पड़ोस पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया। नियमित आदान–प्रदान तथा साहसिक निर्णय लेने की इच्छा के कारण प्रत्येक पड़ोसी देश के साथ हमारे संबंधों में प्रगति हुई। बांग्लादेश के साथ संपन्न ऐतिहासिक सीमा करार से न सिर्फ दोनों देशों के एन्क्लेवों में रहने वाले लोगों के जीवन में आशा जगी अपितु दोनों देशों के बीच भरोसे का माहौल भी बना। नेपाल में आए भूकंप के पश्चात् भारत ने आपातकालीन राहत तथा दीर्घावधिक पुनर्निर्माण में दायित्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के लिए वहां के लोगों की व्यापक प्रशंसा प्राप्त की। श्रीलंका के साथ हमारे संबंध उतरोत्तर सौहार्दपूर्ण तथा ठोस हुए और हमने राष्ट्रपति सिरिसेना की सरकार के साथ बेहतर कार्यकलाप जारी रखा। पहली बार भारत ने सभी तटीय राज्यों की सुरक्षा एवं प्रगति को ध्यान में रखकर हिंद महासागर क्षेत्र के लिए एक व्यापक विजन को रेखांकित किया तथा भारत की बढ़ती क्षमताओं का उपयोग हिंद महासागर में जल दस्युता, तस्करी, पर्यावरण क्षरण और प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम हेतु करने का वायदा किया। भारत ने म्यामां की सभी राजनैतिक ताकतों के साथ ठोस संबंध बनाये रखा, क्योंकि इस महत्वपूर्ण पड़ोसी देश में ऐतिहासिक चुनाव संपन्न हुए। चुनाव के परिणामों ने म्यामां में एक नई राजनैतिक वास्तविकता का सृजन किया जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। भूटान में चल रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं में तेजी लाने तथा अन्य कार्यकलापों के जरिए भूटान के साथ पारंपरिक रूप से घनिष्ठ एवं लाभकारी संबंध और भी संवर्धित हुए। अफगानिस्तान के नये संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए प्रधान मंत्री जी की अफगानिस्तान यात्रा सहित वहां के नेतृत्व के साथ अन्य कार्यकलापों के जरिए भारत ने एक स्थिर, समृद्ध और शांतिपूर्ण अफगानिस्तान के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई। सरकार ने पाकिस्तान के साथ वार्ता प्रक्रिया बहाल करने की पहल की और इस प्रकार आतंकवाद से संबंधित मुद्दे पर कड़ी नजर रखते हुए दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय शांति एवं साझे विकास के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई।

विश्व की प्रमुख ताकतों के साथ निरंतर संबंध बनाये रखना हमारे राजनयिक कार्यकलापों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा। अमरीका, चीन, यू के, फ्रांस, जर्मनी जापान और रूस के साथ उच्च स्तरीय संबंधों का लाभ भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी के बेहतर प्रवाह के रूप में मिला। द्विपक्षीय संबंधों में सरकार ने अवसरों एवं संपूरकताओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करते हुए तथा जरूरत पड़ने पर अपनी चिंताओं को अभिव्यक्त करते हुए आपसी लाभकारी कार्य संपन्न किये। इसके लिए समग्र रणनीतिक नजरिये में सामंजस्य रखते हुए विभिन्न भागीदारों के साथ विभिन्न हितों को ध्यान में रखकर भरोसेमंद कार्यकलापों में शामिल होने की योग्यता की आवश्यकता थी।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान विश्व के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ भारत के कार्यकलापों में अन्य बदलाव भी आये। अलग–अलग देशों के साथ अपने संपर्कों को सीमित रखने की जगह हमने समेकित एवं समावेशी तरीके से पूरे क्षेत्र के साथ संपर्क बढ़ाया और द्विपक्षीय संबंधों की संपूरकताओं का लाभ उठाया। हमने भारत के राजनयिक संपर्कों को बढ़ाते हुए नये क्षेत्रों और देशों को जोड़ा। इस क्रम में उन देशों की उच्च–स्तरीय यात्राएं हुईं जहां की यात्रा पूर्व में नहीं हो सकी थी या वहां की यात्राओं में

लंबा अंतराल आ गया था। प्रधान मंत्री जी की सभी मध्य एशियाई गणराज्यों की यात्रा, श्रीलंका सहित हिंद महासागर द्वीप समूह के देशों की यात्रा, प्रशांत द्वीप देशों के साथ उनके कार्यकलाप (जिसके पश्चात् प्रशांत द्वीप मंच शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ) और नई दिल्ली में भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में इन प्रवृत्तियों की स्पष्ट झलक मिली। इन कार्यकलापों से मौजूदा संबंधों को सुदृढ़ बनाने, तथा नये संपर्क स्थापित करने में मदद मिली और साथ ही इनसे हितों के समेकन एवं सांस्कृतिक तथा सभ्यतामूलक संपर्कों को समन्वित करते हुए विश्व के विभिन्न भागों के साथ संबंधों का समन्वयन करने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन हुआ।

बहुपक्षीय स्तर पर भारत ने जी–20, ब्रिक्स, राष्ट्रमंडल तथा एस सी ओ जैसे महत्वपूर्ण समूहों के कार्यकलापों में उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री जी ने अत्यधिक बैंकिंग गोपनीयता तथा जटिल नियामक ढांचों की बाधाओं को दूर करते हुए काले धन को मूल देश में वापस लाना सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान करने हेतु जी–20 मंच का उपयोग किया। ब्रिक्स समूह में भारत द्वारा समर्थित दो पहलकदमियां प्रचालित हो गई 50 बिलियन अमरीकी डालर का नया विकास बैंक तथा 100 बिलियन अमरीकी डालर का आकस्मिक आरक्षित कोष करार। शंघाई सहयोग संगठन में भारत को पर्यवेक्षक की स्थिति से आगे बढ़ाकर पूर्णकालिक सदस्य बनाने का अनुमोदन किया गया। संयुक्त राष्ट्र के भीतर भारत के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार पर पाठ–आधारित वार्ताएं आरंभ हुईं जिससे इस निकाय में भारत को स्थायी सदस्यता प्रदान किये जाने की संभावना बढ़ी है। पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय के 21वें सम्मेलन में भारत ने विनाशकारी जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए वास्तविक वैश्विक भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया, स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करने के लिए भारत ने जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किये हैं, उन्हें रेखांकित किया और विकसित देशों से विकासशील देशों के लिए रियायती स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आह्वान किया ताकि कार्बन की शेष मात्रा के भीतर वे भी विकास करना जारी रखें। आसियान समूह तथा इसके संबद्ध निकायों के साथ हमारे कार्यकलाप ने इस क्षेत्रीय निकाय के भीतर हमारे द्वारा निर्मित ठोस वार्ता ढांचे को और सुदृढ़ बनाया और यह सरकार की 'एक्ट ईस्ट' कार्य सूची का महत्वपूर्ण भाग था।

नीचे के पृष्ठों में उल्लिखित सभी द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय कार्यकलापों में कुछ ऐसी विशेषताएं एवं प्रवृतियां हैं जिनका विशेष रूप से उल्लेख करना समीचीन होगा।

इस वर्ष के दौरान शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रवृति थी हमारी विदेश नीति और घरेलू विकास आकांक्षाओं के बीच घनिष्ठ संपर्क की स्थापना पर सरकार द्वारा विशेष बल दिया जाना। पिछले 12 महीनों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रयासों का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा पर्यावरण की दिशा में कार्य करने सहित अन्य कार्यकलापों के जरिए घरेलू विकास के लिए सर्वोत्तम माहौल का निर्माण करना रहा है।

अमरीका, जापान, चीन, यू के, जर्मनी, फ्रांस, रूस, कोरिया गणराज्य, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों के साथ हमारे कार्यकलाप भारत में निर्मित हो रहे उपयुक्त निवेश के वातावरण को दर्शाते हुए सरकार के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को आकार देने पर केन्द्रित रहा है। संपर्क स्थापित करने के इन सक्रिय प्रयासों से पिछले 12 महीनों के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और आशा है कि आगामी वर्ष में इसमें और वृद्धि होगी। यह तथ्य कि भारत पिछले वर्ष विश्व में तीव्रतम गति से प्रगति करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा, इस सकारात्मक प्रवृत्ति का द्योतक है। भारत–अमरीका अवसंरचना सहयोग मंच का शुभारंभ, चेन्नै मेट्रो परियोजना के लिए जापान का सहयोग, मुम्बई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, चेन्नै बंगलुरु औद्योगिक गलियारा और हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में सड़क नेटवर्क में सुधार; 75 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश लक्ष्य के साथ यू ए ई–भारत अवसंरचना निवेश कोष की शुरुआत; तथा भारत–यू के भागीदारी कोष हाल के कुछ उल्लेखनीय द्विपक्षीय तंत्र हैं जिनसे भौतिक अवसंरचना के विकास हेतु नये सिरे से विदेशी निवेश प्राप्त होगा।

'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम का प्रत्यक्ष रूप से समर्थन करने के लिए जापान और भारत ने 12 बिलियन अमरीकी डालर के 'मेक इन इंडिया विशेष वित्त सुविधा' को अंतिम रूप दिया। नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत, इस्पात तथा लघु उद्योग क्षेत्रों के लिए चीन की कंपनियों के साथ 22 बिलियन अमरीकी डालर के करार संपन्न किये गये। कोरिया गणराज्य ने भारत में अवसंरचना विकास के लिए 10 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश का वादा किया। जर्मनी की अनेक कंपनियों ने नवीकरणीय ऊर्जा, कौशल विकास, नागर विमानन इत्यादि क्षेत्रों में निवेश करने की प्रतिबद्ध ता व्यक्त की है। भारत में स्टार्ट अप निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सैन जोस, कैलिफोर्निया में भारत निवेश कोष की स्थापना की गई, जबकि नई प्रौद्योगिकियों के लिए उपयुक्त वातावरण का सृजन करने के उद्देश्य से भारत–अमरीका नवाचार मंच की स्थापना की गई।

'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के अंतर्गत रक्षा निर्माण क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया और पिछले वर्ष अमरीका, फ्रांस और रूस की कंपनियों ने भारतीय समकक्षियों के साथ मिलकर भारत में निर्माण संयंत्रों की स्थापना करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

इसी प्रकार सक्रिय राजनयिक संपर्कों के कारण 100 स्मार्ट शहर बनाने की सरकार की महत्वाकांक्षा को भी लाभ पहुंचा है। तीन ऐतिहासिक नगरों–विशाखापतनम, इलाहाबाद और अजमेर को स्मार्ट नगरों में बदलने के लिए अमरीका के साथ समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया। फ्रांस ने भारतीय स्मार्ट नगरों में निवेश हेतु 2 बिलियन यूरो के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की जिसमें चंडीगढ, नागपुर और पुडुचेरी पर विशेष बल दिया जाएगा। इन्दौर, पुणे और अमरावती के संदर्भ में यू के के साथ नगर भागीदारियों पर हस्ताक्षर किये गये। इसी तरह स्थायी शहरी विकास की दिशा में 360 मिलियन यूरो के जर्मन निवेश के वायदे के साथ–साथ 3 स्मार्ट नगरों के विकास में जर्मन निवेश की योजना को मूर्त रूप देने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया गया। चीन, मलेशिया और सिंगापुर ने भी आगामी वर्षों में भारत में आधुनिक शहरी अवसंरचना का विकास करने के लिए भारत के साथ भागीदारी करने में ठोस रुचि का प्रदर्शन किया है। भारत में हो रहे तीव्र शहरीकरण के लिए ये प्रतिबद्धताएं हमारे भावी शहरी नागरिकों के लिए सुंदर और आरामदायक जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है।

लंबे समय से भारतीय रेल के आधुनिकीकरण और उन्नयन की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। एक महत्वाकांक्षी आधुनिकीकरण कार्य सूची के लिए पिछले वर्ष उन देशों के साथ महत्वपूर्ण करार संपन्न किये गये जिनकी रेल क्षेत्र में सिद्ध क्षमताएं रही हैं। इसमें जापान के साथ मुम्बई और अहमदाबाद के बीच भारत का प्रथम बुलेट लिंक बनाने से संबंधित करार भी शामिल है। इसी प्रकार चीन के साथ अंतिम रूप दी गई परियोजना से चेन्नई–बंगलुरू–मैसूर लाइन पर गति बढ़ाई जाएगी जबकि बंगलुरू, कोच्ची और नागपुर में मेट्रो अवसंरचना का वित्तपोषण करने और चंडीगढ़–दिल्ली रेलवे लिंक को उच्च गति लिंक में परिवर्तित करने के लिए फ्रांस के साथ एक सहमति पर पहुंचा गया है। सरकार ने रेलवे अवसंरचना के वित्तपोषण हेतु लंदन में रुपया बौंड की शुरुआत करने का निर्णय लिया। सुरक्षित तथा समेकित परिवहन प्रणाली के विकास में सहायता करने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका के साथ परिवहन भागीदारी करार पर हस्ताक्षर किये गये।

परिवहन संपर्क व्यवस्था के लिए देश की सीमाओं के बाहर भी ध्यान दिया गया। बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के बीच मोटर वाहन करार को अंतिम रूप दिया गया जिससे इस क्षेत्र के भीतर सड़क से आवाजाही आसान हो जाएगी। भारत ने 1 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण पत्रों की वचनबद्धता इस परियोजना के लिए व्यक्त की जिससे भारत और आसियान क्षेत्रों के बीच संपर्क सुविधा बढ़ेगी। भारत, म्यामां और थाइलैंड को जोड़ने वाले त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना और कलादन बहु–माडल परिवहन परियोजना में उल्लेखनीय प्रगति हुई। हमारी पश्चिमी सीमाओं के आगे ईरान के चबाहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण गलियारे में भारत के निवेश से भारत, ईरान, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के बीच सामान तथा लोगों की त्वरित आवाजाही का मार्ग प्रशस्त हुआ।

भावी निर्माण क्षमताओं के लिए देश की मानव पूंजी के उन्नयन हेतु चलाया गया 'कौशल भारत' कार्यक्रम 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को संपूरित करता है। देश में युवाओं की संख्या अधिक होने के कारण अगले दशक के दौरान 400 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य सतत रोजगार विकास तथा आर्थिक समानता की गारंटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले वर्ष के दौरान हमारे राजनयिक प्रयासों के आधार पर भावी उद्योगों के लिए युवाओं के प्रशिक्षण हेतु निवेश एवं सर्वोतम प्रथाएं लाने के लिए अमरीका, कनाडा, जर्मनी, यू के, जापान, सिंगापुर तथा मलेशिया के साथ महत्वपूर्ण पहलकदमियों की शुरुआत की गई।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के जरिए डिजिटल खाई को पाटना सरकार की महत्वपूर्ण घरेलू प्राथमिकताओं में से एक है। जर्मनी, यू के, जापान जैसे देशों, विशेषकर अमरीका में सिलिकॉन वैली की प्रधान मंत्री जी की यात्रा के दौरान हमारे राजनयिक विचार–विमर्श में भारत में प्रौद्योगिकियां लाने तथा आई टी कंपनियों को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। माइक्रोसाफ्ट, क्वालकॉम तथा गूगल जैसी अनेक कंपनियों द्वारा भारत में पर्याप्त निवेश किये जाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। भारत ने इंटरनेट अभिशासन के संबंध में भी नपा–तुला और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर इंटरनेट की आजादी तथा इसके एकीकृत स्वरूप पर चल रही वैश्विक बहस के प्रगतिशील विकास में योगदान दिया और सरकारों को अपने नागरिकों के वैध सुरक्षा हितों को संरक्षित रखने की अनुमति दी।

ऊर्जा कूटनीति के क्षेत्र में भी पिछले 12 महीनों के दौरान महत्वपूर्ण सक्रियता देखी गई और इस पर विशेष ध्यान दिया गया। हरित ऊर्जा पर विशेष बल दिया गया जिसमें सबसे उल्लेखनीय घटना रही अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत जिसका सचिवालय गुड़गांव में होगा। भारत के पावर ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा की मात्रा में वृद्धि करने के उद्देश्य से भारत और अमरीका ने 30 मिलियन अमरीकी डालर की पहल की शुरुआत की। जापान, यू के, कनाडा, कजाकिस्तान तथा फ्रांस के साथ संपन्न करारों से भी भारत में नवीकरणीय ऊर्जा एवं असैन्य नाभिकीय ऊर्जा के विकास को बल मिला। हाइड्रोकार्बन आधारित ऊर्जा के क्षेत्र में तुर्कमेनिस्तान–अफगानिस्तान–पाकिस्तान–भारत (टी ए पी आई) पाइपलाइन को प्रचालित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई।

स्वदेशी निर्माण के अतिरिक्त सरकार ने अपने प्रमुख भागीदारों के साथ सक्रिय सामरिक वार्ता करके और भारतीय सैन्य सेवाओं

के लिए आधुनिक रक्षा मंचों की प्राप्ति एवं विकास के लिए मिलकर कार्य करते हुए रक्षा तैयारियों को संवर्धित करने पर भी विशेष बल दिया। भारत–अमरीका रक्षा प्रौद्योगिकी एवं व्यापार पहल एक महत्वपूर्ण माध्यम था और इसके तहत चार मार्गदर्शी परियोजनाओं में पर्याप्त प्रगति हुई। भारत और अमरीका ने विमान प्रौद्योगिकी तथा जेट इंजन प्रौद्योगिकी की डिजाइन एवं विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए संयुक्त कार्य दलों को भी सक्रिय किया। एक अन्य समर्थकारी करार के आधार पर जापान से रक्षा उपकरणों एवं प्रौद्योगिकियों के अंतरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। हमने अमरीका, जापान, मारीशस, सेशल्स, मलेशिया तथा सिंगापुर जैसे देशों के साथ समुद्रीय सुरक्षा सहयोग को भी संवर्धित किया।

पिछले वर्ष के दौरान भी आतंकवाद आधुनिक विश्व की प्रमुख त्रासदी बनी रही जिससे इसके विरुद्ध एकीकृत वैश्विक कार्रवाई करने के लिए लंबे समय से भारत द्वारा किये जा रहे आह्वान की पुष्टि हुई। प्रधानमंत्री जी ने महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंचों पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध व्यापक अभिसमय को पारित किये जाने संबंधी आह्वान को दोहराया। सरकार ने आतंकी वित्तीय प्रवाह पर रोक लगाने तथा आतंकी गुटों की संपत्तियों की पहचान करने के लिए अमरीका, रूस, फ्रांस, यू के और जापान के साथ मिलकर सहयोगी तंत्रों की स्थापना की। अनेक भगोड़े अपराधियों को उन देशों के राजनयिक सहयोग से सफलतापूर्वक वापस लाया गया जहां उन्होंने आश्रय ले रखा था ताकि उन्हें भारतीय कानून के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात सामरिक सुरक्षा वार्ता तंत्र की स्थापना करने और आतंकवाद–रोधी सहयोग में वृद्धि करने पर सहमत हुए। आतंकवाद की रोकथाम करने के लिए चीन के साथ एक मंत्रिस्तरीय तंत्र बनाने पर भी सहमति हुई। आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पाकिस्तान के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता की शुरुआत की गई है।

घरेलू विकास के लिए राजनय पर विशेष बल देते हुए भारत ने शेष विश्व के साथ विकास के अपने अनुभवों को बांटने की नीति जारी रखी। इसकी झलक न सिर्फ हमारे निकटस्थ पड़ोस में की गई अनेक पहलकदमियों में मिली बल्कि नई दिल्ली में आयोजित तीसरे भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन तथा प्रशांत द्वीप देशों के शिखर सम्मेलन में भी मिली। भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीका की विकास परियोजनाओं के लिए 600 मिलियन अमरीकी डालर की अनुदान सहायता के अतिरिक्त 10 बिलियन के ऋणपत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणा भी की गई। हमारे अधिकांश पड़ोसी देशों के साथ–साथ मारीशस, सेशल्स, जोर्डन, फिलीस्तीन एवं मंगोलिया में चलाई जा रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति होती रही। प्रशिक्षण स्लाट्स तथा छात्रवृत्तियों के रूप में मानव पूंजी का विकास करना विदेश में भारत के विकास सहयोग का एक महत्वपूर्ण भाग रहा। पिछले वर्ष के दौरान भारत ने अनेक देशों में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना तथा दूर–शिक्षा एवं दूर–चिकित्सा परियोजनाओं की शुरुआत की।

सांस्कृतिक राजनय एक अन्य क्षेत्र था जिसमें पिछले वर्ष के दौरान उल्लेखनीय सफलता मिली। भारत के सभ्यतामूलक मूल्यों तथा लोकाचारों का उपयोग करने से हमें स्थायी विकास जैसे मुद्दों पर विलक्षण संदेश देने का अवसर मिला। 21 जून, 2015 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना भारत की सांस्कृतिक आवाज और मूल्यों की स्वीकृति थी। सांस्कृतिक महोत्सवों तथा स्मारक सप्ताहों का आयोजन पूरे वर्ष जापान, चीन और रूस सहित अनेक देशों में किया गया।

पिछले वर्ष पूरे विश्व में फैले अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों के साथ भारत ने अभूतपूर्व तरीके से संपर्क स्थापित किया। प्रधान मंत्री ने न्यूयार्क, सिडनी, पेरिस, टोरंटो, सेन–फ्रांसिस्को, दुबई, क्वालालम्पुर, सिंगापुर तथा लंदन सहित अनेक देशों में भारतीयों और भारतीय मूल के उत्साही श्रोताओं को संबोधित किया। इन सबों में अपनी मातृभूमि की सफलता की कहानी पर गर्व का भाव दिखा और इन लोगों ने भारत के विकास एवं प्रगति में योगदान देने के उपायों को जानने की इच्छा व्यक्त की। भोपाल में आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में संपूर्ण विश्व से भारतीय प्रवासियों एवं हिंदी विद्वानों की बड़ी भागीदारी हुई। जनवरी 2016 में नई दिल्ली में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन के अतिरिक्त लॉस एंजिल्स और लंदन में क्षेत्रीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया।

मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों तथा विदेशी यात्रियों के लिए सार्वजनिक सेवा प्रदायगी को और भी उपभोक्ता अनुकूल एवं प्रभावी बनाने के ठोस उपाय किये। विदेश में भारतीय नागरिकों के लिए हमारे मिशनों एवं केन्द्रों द्वारा सहायता सुलभ कराने के लिए 'मदद' नामक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत की गई। प्रवासी भारतीयों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए पी आई ओ एवं ओ सी आई योजनाओं को मिलाकर एक कर दिया गया। 123 पासपोर्ट सेवा शिविरों और 401 पासपोर्ट मेलों के आयोजन तथा पूर्वोत्तर राज्यों में नये पासपोर्ट सेवा शिविरों के आयोजन से पासपोर्ट आवेदनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 96 प्रतिशत आवेदनों के लिए कार्रवाई किये जाने में 21 दिन से भी कम समय लगा। शायद इस मंत्रालय द्वारा विदेश में रह रहे अपने नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए किया गया सबसे महत्वपूर्ण कार्य था युद्ध ग्रसित देश यमन से उन्हें खाली कराने की कार्रवाई जहां फंसे हुए 4700 भारतीयों को सफलतापूर्वक बचाया गया। भारतीय दलों ने 50 देशों के लगभग 2000 विदेशी नागरिकों को भी बचाया जिससे देश की काफी सराहना हुई और इसने हमें इस क्षेत्र में स्थिरता के कारक के रूप में स्थापित कर दिया।

उत्तरोत्तर जटिल हो रही राजनयिक चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए विदेश मंत्रालय ने अपने नीति नियोजन एवं अनुसंधान प्रभाग के आकार तथा अधिदेश का विस्तार करते हुए अपनी आंतरिक आयोजना एवं रणनीतिक क्षमताओं का संवर्धन किया। मंत्रालय ने भारत और भारत से बाहर स्थित अनुसंधान संस्थानों के रणनीतिक समुदाय के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए सक्रिय प्रयास किये। पहली बार विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को संविदा के आधार पर शामिल करके मंत्रालय में औपचारिक तौर पर बाहरी विशेषज्ञता लाई गई। दीर्घावधिक भू–रणनीतिक संदेशों के आदान–प्रदान पर वार्ताओं की पहल भी हमारे कुछ भागीदार देशों के साथ की गई।

विदेश नीति के निर्माण एवं कार्यान्वयन में राज्य सरकारों को शामिल करना सरकार का एक और अनोखा प्रयास रहा। इस बात को स्वीकार करते हुए कि विशेषकर वाणिज्यिक एवं सांस्कृतिक राजनय की सफलता में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मंत्रालय में नव सृजित 'राज्य प्रभाग' ने सभी राज्य सरकारों के साथ सक्रियता से संपर्क किया है। यह प्रभाग राज्यों को उनके लक्ष्य देशों तथा वाणिज्यिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, पर्यटन एवं डायस्पोरा संपर्कों की पहचान करने तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यकलापों से होने वाले लाभ को ईष्टतम बनाने के लिए उपयुक्त रणनीतियां बनाने में सहायता कर रहा है। इस वर्ष भारतीय एवं विदेशी नगरों/प्रांतों का जोड़ा बनाने से संबंधित अनेक करारों पर हस्ताक्षर किये गये जिसका उद्देश्य शहरी विकास, सांस्कृतिक प्रचार–प्रसार, विरासत संरक्षण तथा लोगों से लोगों के बीच संपर्कों का विस्तार करने में घनिष्ठ सहयोग करना था। भारत और चीन के बीच उप–राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच प्रांतीय–राज्य नेता मंच का शुभारंभ किया गया।

निम्नलिखित पृष्ठों में हमारे द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय कार्यकलापों के ब्यौरों तथा विदेश मंत्रालय की सेवाओं एवं सहयोगी गतिविधियों को क्रम में रखते हुए अन्य प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया है। कुल मिलाकर ये विदेश नीति के क्षेत्र में अनेक सफलताओं एवं उपलब्धियों के साथ आपवादिक रूप से एक सक्रिय वर्ष की कहानी कहते हैं जिससे विश्व में भारत का कद ऊंचा हुआ है। इनमें उन कार्यों का भी संकेत दिया गया है जो आगामी वर्षों में भी मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करते रहेंगे।

पड़ोसी देश

अफगानिस्तानः अप्रैल, 2015 में राष्ट्रपति अशरफ घानी की पहली राजकीय यात्रा और 25 दिसंबर, 2015 को हमारे प्रधान मंत्री जी की अफगानिस्तान यात्रा से भारत और अफगानिस्तान के बीच दीर्घकालिक एवं घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों की पुष्टि हुई। भारत के सहयोग से निर्मित अफगानिस्तान के संसद भवन को हमारे प्रधान मंत्री एवं राष्ट्रपति घानी द्वारा संयुक्त रूप से अफगानिस्तान को समर्पित किए जाने तथा अफगानिस्तान की प्रतिरक्षा क्षमताओं को संवर्धित करने के लिए भारत द्वारा एमआई–25 हेलीकॉप्टर दिए जाने से हमारे संबंध और सुदृढ़ हुए। हार्ट ऑफ एशिया–अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सहयोग के लिए इस्तांबुल प्रक्रिया के 5वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिसंबर, 2015 में विदेश मंत्री जी की इस्लामाबाद यात्रा और साथ ही अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एवं उप विदेश मंत्री की भारत यात्रा से द्विपक्षीय कार्यकलाप और गहन हुए। अफगानिस्तान को मध्य एवं दक्षिण एशिया को जोड़ने वाले व्यापार, पारगमन तथा ऊर्जा केंद्र के रूप में बदलने तथा क्षेत्रीय बाजारों तक इसकी संपर्क सुविधा बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में हार्ट ऑफ एशिया प्रक्रिया की अगली (छठी) मंत्रिस्तरीय बैठक वर्ष 2016 की अंतिम तिमाही में भारत में होगी।

बांग्लादेशः समीक्षाधीन वर्ष के दौरान की गई अनेक पहलकदमियों के जरिए बांग्लादेश के साथ भारत के घनिष्ठ संबंधों का और संवर्धन हुआ। जून, 2015 में प्रधान मंत्री जी की ढाका यात्रा के दौरान लिए गए निर्णयों से दोनों देश और भी निकट आए हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान कुछ ऐसे मुद्दों पर प्रगति हुई, जिनका समाधान दशकों से नहीं हो पा रहा था। भारत और बांग्लादेश ने भू–सीमा मुद्दों, सुरक्षा, अवसंरचना विकास, विद्युत, व्यापार और निवेश तथा संपर्क सुविधा के क्षेत्र में सहयोग, उपक्षेत्रीय सहयोग तथा लोगों से लोगों के बीच आदान–प्रदान सहित अन्य सभी मुद्दों पर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मिलकर कार्य किया है।

भूटानः भारत और भूटान के बीच घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण संबंध हैं तथा आपसी विश्वास एवं समझबूझ इन संबंधों की विशेषता है। जून 2014 में प्रधानमंत्री तथा नवंबर 2014 में राष्ट्रपति द्वारा भूटान की द्विपक्षीय यात्राओं के अनुसरण में वर्ष 2015–16 में सहयोग के सभी क्षेत्रों में सतत प्रगति देखी गई है। वर्ष 2015–16 में पनबिजली, परिवहन, संचार, अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति एवं कृषि जैसे सभी क्षेत्रों में सतत प्रगति हुई है। उच्चस्तरीय यात्राओं एवं अन्य कार्यकलापों के जरिए द्विपक्षीय संबंधों की गतिशीलता को बनाए रखा गया है। भूटान की राष्ट्रीय एसेम्बली के सभापति ल्योन्पो जिगमे जांगपो तथा राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष डॉ. सोनम किंगा के संयुक्त नेतृत्व में भूटान के एक संसदीय शिष्टमंडल ने 9–14 अगस्त 2015 को भारत का दौरा किया। भूटान के प्रधान मंत्री श्री शेरिंग टोबगे ने न्यूयार्क में 25 सितंबर, 2015 को आयोजित सतत विकास से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के दौरान हमारे प्रधान मंत्री से मुलाकात की। प्रधान मंत्री टोबगे ने 13–17 नवंबर, 2015 तक गोवा में आयोजित द्वितीय इंडिया आइडियाज कन्कलेव में और पुनः 6–9 जनवरी 2016 को कोलकाता में आयोजित बंगाल वैश्विक कारोबार शिखर

बैठक 2016 में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। इस अवधि के दौरान भूटान की 11वीं पंचवर्षीय योजना (2013–18) के लिए भारत द्वारा प्रदत्त 4500 करोड़ रुपए के पैकेज के अंतर्गत विकास परियोजनाओं में पर्याप्त प्रगति होती रही। भारत ने परियोजना से जुड़ी सहायता के लिए 2800 करोड़ रुपए, योजना अनुदान के लिए 850 करोड़ रुपए और भूटान की 11वीं पंचवर्षीय योजना में लघु विकास परियोजनाओं के लिए 850 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

चीनः वर्ष 2015 के दौरान भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों के विकास की तीव्र गति बनी रही। उच्चस्तरीय राजनैतिक आदान–प्रदान और आर्थिक कार्यकलापों से संदर्भित संपर्कों में और वृद्धि हुई है। मई, 2015 में प्रधान मंत्री मोदी की चीन यात्रा हमारे द्वि पक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुई। भारत और चीन इस बात पर सहमत हुए कि इस क्षेत्र तथा विश्व में दो महत्वपूर्ण ताकतों के रूप में उनके उदय से एशियाई सदी को मूर्त रूप देने का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हुआ है। दोनों देशों ने पारस्परिक आधार पर समर्थन करते हुए और एक–दूसरे की चिंताओं, हितों एवं आकांक्षाओं के प्रति सम्मान एवं संवेदनशीलता का प्रदर्शन करते हुए अपने–अपने विकास लक्ष्यों एवं सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

घनिष्ठ विकासात्मक भागीदारी, जो भारत–चीन द्विपक्षीय संबंधों की खास विशेषता है, को रेलवे, व्यापार, वाणिज्य, विकास एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष तथा पारस्परिक आदान–प्रदान और 22 बिलियन अमरीकी डॉलर के 26 वाणिज्यिक/व्यावसायिक करारों सहित अन्य क्षेत्रों में अभूतपूर्व स्तर पर 24 करार/समझौता ज्ञापन संपन्न किए जाने से और बल मिला।

इस वर्ष के दौरान हुई अन्य यात्राओं में नवंबर, 2015 में हुई गृह मंत्री की यात्रा भी शामिल है। चीन पक्ष से हुई यात्राओं में जून, 2015 में एनपीसी अध्यक्ष की यात्रा तथा नवंबर, 2015 में चीन के उप राष्ट्रपति और केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष की यात्राएं शामिल हैं।

म्यांमाः भारत और म्यांमा के संबंध बहुफलकीय है तथा इनकी जड़े हमारे साझे ऐतिहासिक, जातीय एवं सांस्कृतिक संबंधों से निकलती हैं। भारत और म्यांमा के बीच द्विपक्षीय सहयोग का उद्देश्य समावेशी विकास और प्रगति का संवर्धन तथा दोनों देशों में एवं इस क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थायित्व में योगदान करना है।

उच्चस्तरीय यात्राओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में हमारे सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए संस्थागत तंत्रों की स्थापना किए जाने से पिछले वर्ष भारत–म्यांमा संबंध और संवर्धित हुए। सुरक्षा, प्रतिरक्षा, व्यापार एवं निवेश, विकास भागीदारी गतिविधियों, वैश्विक तथा बहुपक्षीय मुद्दों इत्यादि में सहयोग के संभावित क्षेत्रों के चौतरफा विकास को बढ़ावा देने से नवगठित भारत म्यांमा संयुक्त परामर्शी आयोग की पहली बैठक हेतु म्यांमा के विदेश मंत्री की भारत यात्रा विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही।

नेपालः खुली सीमाएं, लोगों से लोगों के बीच व्यापक संपर्क तथा बहुफलकीय सामाजिक–आर्थिक कार्यकलाप भारत–नेपाल मैत्री और सहयोग की विशेषता रही है। अप्रैल 2015 में आए भूकंप के उपरांत नेपाल को राहत एवं पुनर्वास सहायता मुहैया कराने में भारत सबसे आगे रहा। "मैत्री अभियान" के जरिए भारत नेपाल में आपदा राहत से संबंधित सबसे बढ़ा अभियान चलाने वाला पहला देश था। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने जून, 2015 में पश्च–भूकंप पुनर्निर्माण के लिए नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दाता सम्मेलन में भाग लिया और नेपाल को अगले पांच वर्षों के दौरान एक बिलियन अमरीकी डॉलर की वर्तमान सहायता के अलावा एक बिलियन अमरीकी डॉलर (इसका एक–चौथाई अनुदान के रूप में है) की सहायता देने की घोषणा की, जो अंतर्राष्ट्रीय दाताओं द्वारा दी गयी सबसे बड़ी प्रतिबद्धता थी।

एक समृद्ध, शांतिपूर्ण, स्थिर तथा लोकतांत्रिक राष्ट्र की दिशा में बदलाव के इस दौर में भारत नेपाल का सतत समर्थन कर रहा है। भारत ने 20 सितंबर, 2015 को नेपाल के नए संविधान को प्रख्यापित किया जाना नोट किया है। यह दोहराया गया कि नेपाल के मुद्दे राजनैतिक और आंतरिक हैं और इनका समाधान वार्ता के जरिए हिंसा मुक्त वातावरण में तथा संस्थागत तरीके से इस प्रकार किया जाना चाहिए कि ये सभी को स्वीकार्य हों। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि नेपाल जाने वाली आपूर्तियो पर भारत ने किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई है और यह नाकेबंदी नेपाली जनता द्वारा ही की गई है, जिसमें भारत सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्तूबर, 2015 को नवनिर्वाचित प्रधान मंत्री के पी एस ओली को शुभकामनाएं दीं और आशा व्यक्त की कि वे समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे, जिससे कि नेपाल में शांति और स्थायित्व आ सके। अक्तूबर, 2015 में नेपाल के उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री श्री कमल थापा की भारत यात्रा के दौरान भी इसी प्रकार का संदेश दिया गया था।

पाकिस्तानः 2015–16 की अवधि के दौरान औपचारिक एवं अनौपचारिक उच्चस्तरीय कार्यकलाप हुए, जिनमें दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने पर बल दिया गया ताकि सार्थक वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो सके। शांतिपूर्ण तरीकों से सभी बकाया मामलों का समाधान करने के लिए नयी द्विपक्षीय वार्ता पर दोनों देशों के बीच करार संपन्न करने की शुरूआत हुई। इसके बावजूद सीमा पार आतंकवाद, युद्धविराम उल्लंघन तथा नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आस–पास घुसपैठ हमारी प्रमुख चिंताएं बनी रहीं। शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता के जरिए पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुदृढ़ बनाने की हमारी दीर्घकालिक नीति के अनुसरण में प्रधान मंत्री ने उफा (रूस) में 10 जुलाई को

आयोजित शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधान मंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने आतंकवाद, बीएसएफ महा निदेशक तथा पाकिस्तान रेंजर्स के महा निदेशक के बीच शीघ्रातिशीघ्र बैठक कराने और इसके बाद सैन्य कार्यवाहियों के महा निदेशकों के बीच बैठक और मुंबई हमलों की सुनवाई के लिए आवाज के नमूने उपलब्ध कराने सहित अन्य प्रकार की जानकारी देकर इस सुनवाई प्रक्रिया में गति लाने के तौर–तरीकों पर चर्चा करने सहित दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बैठक कराने पर सहमति व्यक्त की। अगस्त, 2015 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक नहीं हो पायी, क्योंकि पाकिस्तान यात्रा पर आए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक में हुर्रियत के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने और बैठक की कार्यसूची को एकपक्षीय आधार पर विस्तारित करने पर जोर दे रहा था। 30 नवंबर, 2015 को कॉप–21 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पेरिस की यात्रा के दौरान भी हमारे प्रधान मंत्री जी ने प्रधान मंत्री नवाज शरीफ के साथ शिष्टाचार का आदान–प्रदान किया था। दोनों नेताओं ने बिना किसी सहयोगी के संक्षिप्त बातचीत की, जिसके दौरान उन्होंने एक दूसरे के साथ बातचीत करने हेतु उपयुक्त माहौल सृजित करने का आपसी स्वीकार्य तरीका तलाशने की दोनों देशों की आवश्यकता पर चर्चा की। पेरिस में प्रधान मंत्री नवाज शरीफ के साथ हमारे प्रधान मंत्री की बातचीत के उपरांत तथा उफा में हुई सहमति के अनुसरण में दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 6 दिसंबर, 2015 को बैंकाक में मुलाकात की। विदेश मंत्री ने हार्ट ऑफ एशिया से संबद्ध पांचवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए 9 दिसंबर, 2015 को इस्लामाबाद को दौरा किया। 25 दिसंबर, 2015 को काबुल से भारत आते समय प्रधान मंत्री जी लाहौर में रुके। काबुल की संक्षिप्त यात्रा के दौरान उन्होंने उसी सुबह भारत के सहयोग से निर्मित अफगानिस्तान की संसद का उद्‌घाटन किया था। लघु सूचना पर प्रधान मंत्री जी का लाहौर में रुकना नए एवं अनौपचारिक तरीकों के जरिए तथा अन्य सभी तरीकों से दक्षिण एशिया में सामान्य और अंतर्संबंधित पड़ोस का निर्माण करने के कार्य में भारत के नेतृत्व के नजरिए को रेखांकित करता है।

हिंद महासागर क्षेत्रः वर्ष 2015 के दौरान भारत ने एक सुरक्षित एवं संरक्षित हिंद महासागर में अपने हितों को संरक्षित रखने तथा स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र की दिशा में निरंतर प्रयास किए। इस प्रकार की दिशा मार्च, 2015 में प्रधान मंत्री जी की सेशल्स, मॉरीशस और श्रीलंका की यात्राओं से निर्धारित हुई। जनवरी, 2016 में विदेश मंत्रालय में हिंद महासागर क्षेत्र के लिए अलग प्रभाग बनाने से इस प्रक्रिया को गतिशीलता मिली, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र के भू–सामरिक सुरक्षा, आर्थिक एवं विकास हितों को प्राप्त करने के लिए श्रीलंका, मालदीव, सेशल्स, मॉरीशस जैसे क्षेत्र के प्रमुख देशों तथा निर्धारित त्रिपक्षीय समुद्रीय सुरक्षा वार्ता (भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच) के साथ संबंधों को बढ़ावा मिला। हिंद महासागर क्षेत्र संघ (आईओआरए) की भावी गतिविधियों के संबंध में भारत के नजरिया को भी इस दृष्टिकोण का अभिन्न भाग बनाया गया।

श्रीलंकाः पिछले वर्ष के दौरान भारत–श्रीलंका संबंधों में महत्वपूर्ण एवं गुणात्मक परिवर्तन आया। वर्ष 2015 के दौरान हुई अनेक उच्चस्तरीय यात्राओं के आधार पर द्विपक्षीय संबंध नई ऊंचाई पर पहुंच गए। श्रीलंका के प्रधान मंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने 14–16 सितंबर, 2015 तक भारत का आधिकारिक दौरा किया। अगस्त, 2015 में वहां हुए संसदीय चुनावों के पश्चात यह विदेश की उनकी पहली यात्रा थी। "पहले पड़ोसी" सिद्धांत के अनुसरण में श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों में लगातार प्रगति हो रही है। वर्ष 2005 से ही भारत सरकार ने आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के पुनर्वास और श्रीलंका के उत्तरी एवं पूर्वी प्रांतों में अवसंरचना के पुनर्निर्माण हेतु दी गई अनुदान सहायता के रूप में 2300 करोड़ भारतीय रुपए और ऋण–पत्रों के रूप में 12900 करोड़ भारतीय रुपए की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। श्रीलंका की सहायता के लिए भारत की प्रायोगिक परियोजना अर्थात आवासीय परियोजना, जिसके लिए 1372 करोड़ भारतीय रुपए की प्रतिबद्धता अनुदान के रूप में व्यक्त की गयी है, में अच्छी प्रगति हो रही है और आशा है कि दूसरा चरण शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। वर्ष 2015 में पूर्ण परियोजनाओं में शामिल हैं– मताले में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय केंद्र; अंपारा, मतारा, बदुल्ला और जाफना में भाषा प्रयोगशालाएं तथा ववूनिया में 200 बिस्तरों वाला अस्पताल विशेष रूप से रक्षा, आर्थिक, शिक्षा, कृषि, विकास भागीदारी, संस्कृति, लोगों के आदान–प्रदान के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग निरंतर बढ़ता रहा है। भारतीय तटरक्षक दल और श्रीलंकाई तटरक्षक कर्मचारियों के बीच पहली वार्ता 8–10 सितंबर, 2015 तक कोलंबो में हुई। सद्भावना प्रदर्शन के रूप में अगस्त, 2015 में भारतीय तटरक्षक जहाज वराह श्रीलंका को उपहार दिया गया। दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं में विकास के आधार पर द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में लगातार वृद्धि हुई। दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा वर्ष 2014–15 में तेजी से बढ़कर 7.45 बिलियन अमरीकी डॉलर की हो गयी है। जहां तक निवेश का प्रश्न है, भारत श्रीलंका में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है और इसका कुल निवेश वर्ष 2003 से अब तक लगभग 1 बिलियन अमरीकी डॉलर का रहा है। विश्वस्तर पर भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा विकास भागीदार है, जबकि श्रीलंका सार्क के भीतर भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। वर्ष 2015 में श्रीलंका में सबसे अधिक पर्यटक भारत से ही पहुंचे।

मालदीवः वर्ष 2015 भारत–मालदीव राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ थी। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 5वें भारत–मालदीव संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए 10–11 अक्तूबर, 2015 तक मालदीव का दौरा किया। यह

बैठक 15 वर्षों के अंतराल पर हुई। अभूतपूर्व सम्मान का प्रदर्शन करते हुए मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गय्यूम अपने मंत्रिमंडल के सभी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ माले स्थित भारतीय उच्चायोग आये और पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की मौत के बाद रखी शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए और अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। विदेश सचिव डॉ. एस. जयशंकर ने अपनी सार्क यात्रा के भाग के रूप में 3–4 अगस्त, 2015 तक मालदीव का दौरा किया। विदेश सचिव डॉ. अली नसीर ने भारत–मालदीव संबंधों पर दिल्ली नीति समूह द्वारा आयोजित गोल मेज चर्चा में भाग लेने के लिए 7–8 अगस्त, 2015 तक भारत का दौरा किया। द्विपक्षीय रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग, रक्षा हार्डवेयर एवं क्षमता निर्माण सहित अनेक क्षेत्रों में संबंध और भी व्यापक और गहन हुए। इनमें भारतीय नौसैनिक पोतों एवं विमानों द्वारा मासिक ईईजेड निगरानी, ईकुवेरिन–2015 का आयोजन, त्रिवेंद्रम में आयोजित भारतीय सेना– एमएनडीएफ समुद्री कोर प्रशिक्षण अभ्यास, द्वितीय टेबल टॉप अभ्यास (टीटीईएक्स–15) में भारत, श्रीलंका तथा मालदीव की भागीदारी, भारत द्वारा वित्तपोषित परियोजना मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बलों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण केंद्र के पहले चरण की सुपुर्दगी इत्यादि शामिल हैं।

मॉरीशसः भारत और मॉरीशस के बीच घनिष्ठ राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा डायस्पोरा संबंध हैं। मॉरीशस की 70 प्रतिशत जनसंख्या भारतीय मूल की है। मॉरीशस वित्तीय सेवाओं का भी केंद्र है और यह भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सबसे बड़ा मार्ग बनकर उभरा है। मॉरीशस अफ्रीका में भारतीय निवेश का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। भारत–मॉरीशस व्यापार लगभग 2 बिलियन अमरीकी डॉलर का है। समुद्रीय सुरक्षा विषय पर हमारी घनिष्ठ भागीदारी भी है। इस अवधि के दौरान भारत–मॉरीशस भागीदारी और गहन तथा व्यापक हुई। प्रधान मंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ के नेतृत्व में मॉरीशस के एक शिष्टमंडल ने अक्तूबर, 2015 में नई दिल्ली में आयोजित तीसरे भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यह यात्रा मार्च, 2015 में हमारे प्रधान मंत्री की मॉरीशस यात्रा के बाद हुई। उस यात्रा के दौरान वे मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि थे, जिसके दौरान अनेक द्विपक्षीय करारों को अंतिम रूप दिया गया। इसके उपरांत मॉरीशस की राष्ट्रपति श्रीमती अमीना गरीब फाकिम की दिसंबर, 2015 में भारत की राजकीय यात्रा हुई, जो हाल ही में मॉरीशस की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। भारतीय नौसैनिक और तटरक्षक पोतों ने जल विज्ञान सर्वेक्षण करने के अतिरिक्त विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की संयुक्त निगरानी करने के लिए 2015 में मॉरीशस का दौरा किया।

सेशल्सः वर्ष 2015 भारत–सेशल्स भागीदारी के लिए एक विशेष वर्ष रहा, जिसमें विकास भागीदारी, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, समुद्री सुरक्षा सहयोग एवं सांस्कृतिक आदान–प्रदान जैसी गतिविधियां शामिल थीं। मत्स्य अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन एवं स्वास्थ्य कुछ उभरते क्षेत्र है, जिन पर विशेष बल दिया जाना है। सेशल्स की 10 प्रतिशत जनसंख्या भारतीय मूल के लोगों की है। प्रधान मंत्री मोदी की सेशल्स यात्रा (मार्च, 2015) के कुछ महीनों के भीतर ही सेशल्स के राष्ट्रपति जेम्स एलिक्स मिशेल्स ने 25–27 अगस्त, 2015 तक भारत का दौरा किया। विकास सहायता के क्षेत्र में भारत ने सार्वजनिक परिवहन के लिए बसों, दवाओं, आईसीटी उपकरणों एवं शैक्षिक मदों के प्रापण हेतु 4.3 मिलियन अमरीकी डॉलर का अनुदान दिया। लोगों से लोगों के बीच संपर्कों एवं यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए सेशल्स को अगस्त, 2015 से भारत सरकार की ई–टूरिस्ट वीजा योजना में शामिल किया गया है। अगस्त, 2015 में द्विपक्षीय हवाई सेवा करार संपन्न किया गया। इस अवधि के दौरान रणनीतिक भारत–सेशल्स रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग और भी गहन हुए, जिसमें समुद्रीय सुरक्षा तथा सेशल्स के विस्तृत विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा और निगरानी पर विशेष बल दिया गया। 29 जून, 2015 को आयोजित सेशल्स राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत की उल्लेखनीय उपस्थिति थी।

दक्षिण–पूर्व एशिया तथा एशिया प्रशांत

आस्ट्रेलियाः वर्ष 2014 में प्रधान मंत्री की पिछली आस्ट्रेलिया यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली थी। आस्ट्रेलिया खनिज संसाधनों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं कौशल तथा जल संसाधन प्रबंधन सहित अन्य क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण भागीदार बनकर उभरा है। प्रधान मंत्री मेलकॉम टर्नबुल ने 15 नवंबर, 2015 को तुर्की में आयोजित जी–20 शिखर सम्मेलन के दौरान हमारे प्रधान मंत्री से मुलाकात की और द्विपक्षीय असैनिक परमाणु सहयोग करार के अनुसमर्थन की घोषणा की। इसके आधार पर अब आस्ट्रेलियाई कंपनियां भारत में यूरेनियम का निर्यात आरंभ कर सकती हैं। विदेश मंत्री जुली विशोप ने विदेश मंत्री के साथ होने वाली वार्षिक विदेश मंत्रिस्तरीय रूपरेखा वार्ता के लिए 12–15 अप्रैल, 2015 तक भारत का दौरा किया। पहले द्विपक्षीय समुद्रीय अभियान ऑसिनडैक्स, जिसका आयोजन 11–17 सितंबर, 2015 तक बंगाल की खाड़ी में किया गया, के जरिए रक्षा सहयोग को प्रोत्साहन मिला। आस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। आस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों ने भारत से लगभग 50,000 छात्रों को आकर्षित किया है और अब भारत को कुशल प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है।

ब्रुनेई दार–ए–सलामः ब्रुनेई दार–ए–सलाम के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध अत्यंत घनिष्ठ एवं महत्वपूर्ण बने रहे तथा ब्रुनेई जून, 2015 तक आसियान में भारत के लिए समन्वयक देश था। पिछले वर्षों की तरह ही दोनों देशों के बीच अधिकारी स्तरीय

यात्राएं हुईं, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, इसरो तथा ब्रुनेई के संस्कृति, युवा एवं खेल उप मंत्री की यात्राएं शामिल हैं। वर्ष 2012 से भारतीय सैन्य बलों के अधिकारी नियमित रूप से स्टॉफ कालेज ब्रुनेई में रायल ब्रुनेई सैन्य बल कमान स्टाफ पाठ्यक्रम में भाग लेते रहे हैं।

कंबोडिया: भारत और कंबोडिया के बीच द्विपक्षीय संबंध सौहार्दपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण बने रहे और ये निरंतर मजबूत हुए। भारत और कंबोडिया के बीच प्राचीन काल से ही नजदीकी सभ्यतामूलक एवं सांस्कृतिक संपर्क रहे हैं, जो आज भी जारी हैं। हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के लिए माननीय उप राष्ट्रपति श्री मोहम्मद अंसारी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 15–17 सितंबर, 2015 तक कंबोडिया का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान पर्यटन क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन और मिकांग गंगा सहयोग के अंतर्गत त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भारतीय अनुदान सहायता से संबद्ध करार पर हस्ताक्षर किए गए। वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण एवं कृषि तथा कौशल विकास से संबद्ध 5 त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाओं के लिए 50,000 अमरीकी डॉलर की अनुदान सहायता की घोषण ा की गयी। ता प्रोम मंदिर के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार का पहला और दूसरा चरण जुलाई, 2015 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न किया गया।

इंडोनेशिया: वर्ष 2015 के दौरान अनेक उच्चस्तरीय राजनीतिक कार्यकलाप हुए, जिनसे हमारे संबंधों को संवर्धित करने में मदद मिली। इन कार्यकलापों से द्विपक्षीय संबंधों को आवश्यक गति मिली है। भारत के उप राष्ट्रपति श्री एम. हामिद अंसारी ने 1–4 नवंबर, 2015 तक इंडोनेशिया का दौरा किया। वर्ष 2015 में भारत–इंडोनेशिया रक्षा सहयोग में महत्वपूर्ण गुणात्मक एवं परिणामात्मक वृद्धि हुई। जनवरी–सितंबर, 2015 (उपलब्ध अद्यतन आंकड़ा) की अवधि में इंडोनेशिया के साथ भारत का व्यापार 11 बिलियन अमरीकी डॉलर का था, जिसमें 8.9 बिलियन अमरीकी डॉलर वस्तुओं के आयात के लिए और 2.1 बिलियन निर्यात के लिए है।

लाओ पीडीआर: इस वर्ष के दौरान लाओ पीडीआर के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों में लगातार प्रगति हुई है। सिंचाई प्रणाली के क्षेत्र में अवसंरचना परियोजनाएं, विद्युत पारेषण, क्षमता निर्माण एवं मानव संसाधन तथा विरासत स्मारकों के संरक्षण में सांस्कृतिक सहयोग और नियमित आधार पर होने वाली उच्चस्तरीय यात्राएं हमारे सहयोग की विशेषता रही। इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं के तहत भारत में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं नियमित पाठ्यक्रमों के लिए लाओ के छात्रों एवं तकनीकी कार्मिकों को 100–150 छात्रवृत्तियां भी दी गयीं। इस वर्ष 17–18 सितंबर, 2015 को पहली बार भारत के किसी उप राष्ट्रपति ने लाओ पीडीआर का दौरा किया।

मलेशिया: पारंपरिक मैत्री एवं सौहार्द पर आधारित मलेशिया के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति हुई है। भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 23 नवंबर, 2015 को मलेशिया की राजकीय यात्रा की। इससे पूर्व प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21–22 नवंबर, 2015 को आसियान–भारत शिखर सम्मेलन और पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। प्रधान मंत्री जी ने ब्रिकफील्ड्स, कुआलालाम्पुर में तोराना गेट का उद्घाटन किया, जो मलेशिया को भारत की ओर से उपहार स्वरूप दिया गया है। इस यात्रा के पश्वात संवर्धित सामरिक भागीदारी के लिए संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया गया।

न्यूजीलैंड: आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक संपर्क एवं वैश्विक महत्व के क्षेत्रीय मुद्दों पर समन्वय जैसे विभिन्न क्षेत्रों में न्यूजीलैंड के साथ भारत के संबंधों में लगातार प्रगति हुई है। माननीय कौशल विकास, उद्यमशीलता एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राजीव प्रसाद रूडी ने दोनों देशों की संसदों के बीच संपर्कों के संवर्धन हेतु एक सद्भावना संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ न्यूजीलैंड का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने इस अवसर का उपयोग करते हुए व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए न्यूजीलैंड में उपलब्ध सुविधाओं तथा भारत–न्यूजीलैंड आर्थिक एवं व्यावसायिक संबंधों को संवर्धित करने तथा स्थानीय भारतीय समुदाय के साथ कार्यकलाप करने की संभावना की जानकारी ली।

फिलीपींस: भारत–फिलीपींस भागीदारी भी इस अवधि के दौरान सुदृढ हुई। द्विपक्षीय सहयोग से संबद्ध द्विवार्षिक आयोग जो सर्वोच्च संस्थागत द्विपक्षीय तंत्र है, की तीसरी अर्द्धवार्षिक बैठक 14 अक्तूबर, 2015 को नई दिल्ली में हुई। 1–4 नवंबर, 2015 तक आईएनएस सहयाद्री की मनीला यात्रा से रक्षा सहयोग का संवर्धन लगातार जारी रहा। वित्तीय वर्ष 2015–16 की पहली छमाई के दौरान पूरे विश्व में आई मंदी के बावजूद भारत और फिलीपींस के बीच का व्यापार संबंध 1.8 बिलियन अमरीकी डॉलर का रहा और व्यापार संतुलन सकारात्मक रूप से भारत के पक्ष में रहा। फिलीपींस में भारतीय निवेश की विशेषता बड़ी संख्या में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं एवं भेषज फर्मों की उपस्थिति रही है, जो क्रमशः सूचना प्रौद्योगिकी तथा जेनरिक दवाओं के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही हैं। अवसंरचना, आटोमोबाइल, नवीकरणीय ऊर्जा तथा कृषि जैसे क्षेत्र में आज भारतीय निवेश की नई प्रवृत्ति स्पष्ट है।

सिंगापुर: भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र

मोदी की 23–24 नवंबर, 2015 की सिंगापुर यात्रा के दौरान सिंगापुर के साथ हमारे संबंधों को सामरिक भागीदारी के नए स्तर तक उन्नयित किया गया। एक संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया गया, जिसमें सहयोग एवं आपसी हित के क्षेत्रों का उल्लेख भी किया गया। संवर्धित रक्षा सहयोग करार पर हस्ताक्षर करने के कारण भारत और सिंगापुर के बीच रक्षा सहयोग भी सुदृढ़ हुए। इसके अतिरिक्त भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य नौसेना के बीच स्वेत नौवहन सूचना का आदान–प्रदान किए जाने से संबंधित तकनीकी करार को प्रधान मंत्री जी की यात्रा के दौरान लागू किया गया। साथ ही भारत और सिंगापुर की तीनों सेनाओं एवं रक्षा संस्थापनाओं के बीच भी नियमित रूप से आदान–प्रदान होते रहे हैं। भारत और सिंगापुर के बीच घनिष्ठ आर्थिक एवं व्यावसायिक संपर्क हैं, जिसमें वर्तमान वर्ष के दौरान कुछ कमी आने की प्रवृत्ति देखी गयी (द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा में 17 प्रतिशत की कमी)। वित्तीय वर्ष 2015–16 (अप्रैल–अक्तूबर) के लिए कुल द्विपक्षीय व्यापार 8.6 बिलियन अमरीकी डॉलर का था, जिसमें भारतीय निर्यात 4.2 बिलियन अमरीकी डॉलर का था। सिंगापुर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वर्ष 2004–2005 में 351 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 38.9 बिलियन अमरीकी डॉलर (अक्तूबर, 2015) हो गया, क्योंकि सिंगापुर विदेशों में भारतीय निवेश के लिए सबसे अनुकूल गंतव्यों में से एक रहा। इस वर्ष (1 अप्रैल–31 अक्तूबर, 2015) सिंगापुर में भारतीय निवेश 2.18 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। सिंगापुर भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है और इस क्रम में अप्रैल, 2000 से सितंबर, 2015 तक भारत में सिंगापुर का कुल निवेश 38.9 बिलियन अमरीकी डॉलर का रहा। इस वर्ष भी अब तक सिंगापुर सबसे बड़ा निवेशक रहा है और सिंगापुर से (1 अप्रैल– 30 सितंबर, 2015) 6.69 बिलियन अमरीकी डॉलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हुआ है।

थाईलैंडः इस वर्ष के दौरान उच्चस्तरीय यात्राओं के आदान–प्रदान तथा सभी स्तरों पर संवर्धित कार्यकलापों के आधार पर थाईलैंड के साथ भारत के संबंध और भी गहन तथा सुदृढ़ हुए। जनवरी–सितंबर, 2015 की अवधि के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 6.18 बिलियन अमरीकी डॉलर का रहा। समुद्री सहयोग तथा विधिक एवं न्यायिक सहयोग से संबद्ध संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक 27 और 28 अक्तूबर, 2015 को नई दिल्ली में हुई। त्रिपक्षीय राजमार्ग से संबद्ध मोटर वाहन करार को अंतिम रूप देने के लिए भारत, म्यांमार तथा थाईलैंड के परिवतन मंत्रालय के अधिकारियों के बीच चार बैठकें हुईं। 2015 में लगभग 1 मिलियन भारतीय पर्यटक थाईलैंड गए, जबकि 1 लाख थाई पर्यटक भारत आए।

वियतनामः वर्ष 2015–16 के दौरान भारत और वियतनाम के बीच विद्यमान सामरिक भागीदारी और भी सुदृढ़ हुई। आर्थिक सहयोग को रणनीतिक प्राथमिकता दी गयी, जबकि व्यापक द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों में सर्वोच्च स्तर पर लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु सतत प्रयास जारी रहे। रक्षा सहयोग पर वर्ष 2015–2020 की अवधि के लिए संयुक्त विजन वक्तव्य तथा दोनों देशों के तटरक्षकों के बीच सहयोग से संबद्ध एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया। भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय व्यापार में पिछले कुछ वर्षों के दौरान लगातार वृद्धि हुई है। अब भारत वियतनाम के सबसे बड़े 10 व्यापार भागीदारों में से है। दोनों पक्षों ने वर्ष 2020 में 15 बिलियन अमरीकी डॉलर के नए व्यापार लक्ष्य पर अपनी सहमति व्यक्त की है। रक्षा उत्पादन सहित रक्षा सहयोग के सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय रक्षा संबंध व्यापक और गहन हो रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान वियतनाम भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटेक) कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का एक प्रमुख लाभार्थी रहा है।

प्रशांत द्वीप के देशः भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच का दूसरा शिखर सम्मेलन 21 अगस्त, 2015 को जयपुर में आयोजित किया गया। मार्शल द्वीप, नौरू तथा पलाऊ से 3 राज्याध्यक्षों, माइक्रोनेशिया के उप राष्ट्रपति, फिजी, नियु, पपुआ न्यू गिनी, समोआ, तुबालु और बनवातू से 6 शासनाध्यक्षों और सोलोमन द्वीप, टोंगा, कुक द्वीप तथा किरिबाती से उप प्रधान मंत्री/मंत्रियों/विशेष दूतों ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

दक्षिण–पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ (आसियान): नवंबर, 2014 में आसियान–भारत शिखर सम्मेलन तथा पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में "एक्ट– ईस्ट" पॉलिसी का प्रतिपादन किए जाने के उपरांत 2015 में भारत–आसियन रणनीतिक भागीदारी में एक नई गति आई है,। आसियान भारत की एक्ट–ईस्ट पॉलिसी का संचालक है तथा भारत ने आसियान में भारतीय मिशन की स्थापना सहित अन्य कार्यों से वर्ष 2015 में आसियान सदस्य राष्ट्रों के साथ राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा एवं आर्थिक संबंधों को गहन बनाना जारी रखा है। इसने क्षेत्रीय रूपरेखा विशेषकर पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन, आसियान क्षेत्रीय मंच, आसियान रक्षा मंत्री बैठक प्लस तथा विस्तारित आसियान समुद्री मंच को आकार देने वाले आसियान केंद्रित अनेक मंचों के साथ सक्रिय संपर्क बनाए रखा है। 1 जुलाई, 2015 को आसियान– भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र करार लागू हो जाने के साथ तथा 31 दिसंबर, 2015 को आसियान समुदाय की स्थापना होने के बाद से भारत आसियान और वृहत्तर एशिया प्रशांत के साथ बेहतर एकीकरण करना चाहता है।

पूर्व एशिया

पूर्व एशिया भारत के विस्तारित पड़ोस का भाग है। इस क्षेत्र के साथ सांस्कृतिक, व्यापारिक तथा लोगों से लोगों के बीच संपर्क सदियों पुराने हैं। साझे मूल्य एवं शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व, बहुलवाद एवं शांति की परंपराओं, जो बौद्ध धर्म की विशेषता

है, ने इन कार्यकलापों को बनाए रखने में मदद की है। विश्व में उत्तरोत्तर बढ़ते भारत के राजनैतिक एवं सुरक्षा दर्जे तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में और सक्रिय भूमिका निभाने की इसकी इच्छा तथा बढ़ती आर्थिक ताकत भारत एवं पूर्व एशिया के बीच घनिष्ठ एकीकरण को बल दे रहा है। पूर्वी एशिया के साथ भारत के बढ़ते कार्यकलाप अर्थव्यवस्था एवं सुरक्षा के दोहरे तर्क द्वारा मुख्य रूप से संचालित होते हैं। भारत एक समावेशी, विधि सम्मत एवं बहुलवादी तथा संतुलित क्षेत्रीय रूपरेखा चाहता है, जिससे कि आर्थिक एवं सुरक्षा क्षेत्रों में भारत और पूर्व एशिया दोनों के लिए लाभ के अवसर बन सके।

शांतिपूर्ण एवं स्थिर पूर्व एशिया भारत के आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है। भारत के व्यापार का एक महत्वपूर्ण भाग इस क्षेत्र के देशों के साथ होता है। यह महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं विवादों के शांतिपूर्ण समाधान; नौवहन तथा उड़ान की स्वतंत्रता; तथा इस क्षेत्र के मामलों को शासित करने वाले आवाध वैध व्यापार जैसे सिद्धांतों पर सहमति बने।

लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य कोरिया (डीपीआरके): भारत और लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य कोरिया (डीपीआरके) के बीच राजनयिक संबंध दिसंबर, 1973 में स्थापित हुए। भारत और लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य कोरिया के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध है। 2015 में विदेश मंत्री श्री रि सु यांग ने 12–14 अप्रैल, 2015 तक भारत की यात्रा की। यह डीपीआरके की ओर से भारत की पहली विदेश मंत्रिस्तरीय यात्रा है। विदेश मंत्री श्री रि सु यांग ने भारत द्वारा लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य कोरिया को दी गई मानवीय सहायता के प्रति अपने देश की सराहना व्यक्त की ओर इस संबंध में अतिरिक्त सहायता की मांग की।

जापानः हाल के वर्षों में भारत–जापान संबंधों में निरंतर बदलाव आया है और ये दीर्घावधिक राजनैतिक, आर्थिक एवं सामरिक लक्ष्यों की व्यापक समानता को परिलक्षित करते हैं। वर्ष 2014 में प्रधान मंत्री मोदी की जापान यात्रा, जो पड़ोसी देशों से आगे विदेश की उनकी पहली यात्रा थी, ने द्विपक्षीय संबंधों में गुणात्मक बदलाव लाने का मार्ग तैयार कर दिया था, जिसके आधार पर द्विपक्षीय संबंधों को "विशेष सामरिक एवं वैश्विक भागीदारी" के स्तर तक उन्नयित कर दिया गया। 11–13 दिसंबर, 2015 तक जापान के प्रधान मंत्री श्री ऐबे की यात्रा से भारत–जापान "विशेष सामरिक एवं वैश्विक भागीदारी" और सुदृढ़ हुई। इस यात्रा के परिणामस्वरूप जापान प्रतिरक्षा सहयोग एवं असैनिक परमाणु ऊर्जा करारों के साथ–साथ अनेक महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के लिए धन प्रदान करने के लिए सहमत हो गया। दोनों पक्षों ने भारत में तीव्र गति रेलवे परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए भी एक करार पर हस्ताक्षर किए।

भारत और जापान ने भारत के भीतर तथा भारत और इस क्षेत्र के अन्य देशों के बीच संपर्क सुविधा बढ़ाने वाला लोचनीय, स्थायी एवं टिकाऊ अवसंरचना का विकास करने के लिए भारत की "एक्ट ईस्ट" नीति तथा जापान की "अच्छी अवसंरचना के लिए भागीदारी" के बीच सहक्रिया का लाभ उठाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत में सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना का निर्माण करने हेतु जापान द्वारा दिए गए आधिकारिक विकास अंशदान की सराहना की गयी। वित्तीय वर्ष 2015 में भारत को जापान द्वारा येन में दिया जाने वाला आधिकारिक विकास ऋण लगभग 400 बिलियन येन तक पहुंच सकता है, जो भारत को अब तक दिया जाने वाला सबसे बड़ा ऋण है।

मंगोलियाः भारत और मंगोलिया दो ऐसे लोकतंत्र हैं, जिनकी साझी बौद्ध विरासत है और जिनके बीच सांस्कृतिक आदान–प्रदान सदियों से किया जा रहा है। मई, 2015 में प्रधान मंत्री श्री मोदी की मंगोलिया यात्रा, जो किसी भारतीय प्रधान मंत्री की मंगोलिया की पहली यात्रा थी, हमारे द्विपक्षीय संबंधों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस यात्रा के दौरान भारत और मंगोलिया ने अपने द्विपक्षीय सहयोग को सामरिक भागीदारी के स्तर तक उन्नयित किया और द्विपक्षीय सहयोग के अनेक नए क्षेत्रों की पहचान की। इनमें समान एवं पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग शामिल हैं, जो संतुलित एवं सतत हो ताकि दोनों देशों में समृद्धि आ सके।

कोरिया गणराज्यः वर्ष 2015 दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ थी। भारत और कोरिया गणराज्य के बीच द्विपक्षीय संबंधों का निरंतर विस्तार हो रहा है और आर्थिक, राजनैतिक एवं सुरक्षा हितों में महत्वपूर्ण समानता के आधार पर ये बहुफलकीय हो रहे हैं। इस वर्ष विदेश मामले, प्रतिरक्षा, व्यापार और निवेश, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक एवं लोगों से लोगों के बीच आदान–प्रदान तथा क्षेत्रीय सहयोग जैसे व्यापक क्षेत्रों में इस भागीदारी को नई गति मिली, जिसके आधार पर हमारे संबंध नई ऊंचाई पर पहुंच गए। भारत कोरिया गणराज्य को अपनी "एक्ट ईस्ट" नीति के लिए महत्वपूर्ण मानता है और कोरिया गणराज्य तथा भारत द्विपक्षीय भागीदारी के मूल्य और एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थायित्व एवं सुरक्षा में इसके योगदान के महत्व को स्वीकार करते हैं।

यूरेशिया

रूस के साथ हमारे संबंध भारत की विदेश नीति का केंद्रीय स्तम्भ है। रूस के साथ भारत की "विशेष एवं मूल्यवान रणनीतिक भागीदारी" को आगे बढ़ाने पर इस वर्ष विशेष बल दिया गया। इस वर्ष के दौरान भारत से रूस में राज्याध्यक्ष/शासनाध्यक्ष स्तर के तीन दौरे हुए। राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 9 मई, 2015 को मॉस्को में द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में भाग लिया। प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र

मोदी ने 8–10 जुलाई को उफा, रूस में आयोजित 7वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन तथा शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए और फिर 23–24 दिसंबर, 2015 को मॉस्को में आयोजित 16वें भारत–रूस वार्षिक शिखर बैठक में भाग लेने के लिए रूस का दौरा किया। जुलाई, 2015 में प्रधान मत्री श्री नरेंद्र मोदी की सभी पांच मध्य एशियाई देशों– उज्बेकिस्तान, कजाख्स्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गीज गणराज्य और तजाकिस्तान की एतिहासिक यात्रा से मध्य एशियाई भागीदारों के साथ हमारे कार्यकलाप और भी गहन हुए। बेलारूस, यूक्रेन तथा दक्षिण काकेसस (आर्मेनिया, अजरबेजान, जॉर्जिया) के साथ भी हमारे संबंधों का निरंतर विकास होता रहा है।

रूसी परिसंघः उच्चस्तरीय यात्राओं तथा मंत्रियों एवं अधिकारियों के स्तर पर होने वाले कार्यकलापों के कारण विविध क्षेत्रों में भारत–रूस संबंधों में महत्वपूर्ण संवर्धन हुआ और इनमें गहनता आई। इस वर्ष प्रतिरक्षा, असैनिक परमाणु सहयोग, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हाइड्रो–कार्बन, रेलवे, सौर ऊर्जा, वीजा सरलीकरण, आयुर्वेद, उपग्रह प्रक्षेपण, भारी इंजीनियरिंग तथा सुपर कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए 25 द्विपक्षीय करारों एवं समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। 16वीं वार्षिक शिखर बैठक के दौरान रणनीतिक भागीदारी के ठोस स्तम्भ के रूप व्यापार और आर्थिक संबंधों के संवर्धन पर विशेष बल दिया गया। "साझा विश्वास, नए क्षितिज" नाम से एक व्यापक संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया गया, जो भारत–रूस संबंधों में विविधता और गतिशीलता को पूरी तरह परिलक्षित करते हैं।

द्विपक्षीय संबंधों में हुई पर्याप्त प्रगति के अतिरिक्त भारत और रूस ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर घनिष्ठ विचार–विमर्श करने की प्रक्रिया कायम रखी। रूस ने पुनर्गठित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी, बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं तथा शंघाई सहयोग संगठन जैसे अन्य बहुपक्षीय संगठनों में भारत के ठोस समर्थन करने की पुष्टि की। भारत और रूस ने ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में रूस के कार्यकाल में अपना घनिष्ठ सहयोग जारी रखा।

व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक एवं सांस्कृतिक सहयोग से संबद्ध भारत–रूस अंतर–सरकारी आयोग की 21वीं बैठक 20 अक्तूबर, 2015 को मॉस्को में हुई, जिसकी सह–अध्यक्षता विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज और रूस के उप प्रधान मंत्री दिमित्री रोजोजिन ने की। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने अपने समकक्षी विदेश मंत्री श्री सरगेई लागरोव से भी मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों ने सितंबर, 2015 में न्यूयार्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भी मुलाकात की थी और उन्होंने रूस–भारत–चीन विदेश मंत्री बैठक के दौरान अतिरिक्त समय में फरवरी, 2015 में बीजिंग में भी द्विपक्षीय बैठक की थी। विदेश सचिव डॉ. एस. जयशंकर ने 19 अक्तूबर, 2015 को मॉस्को में विदेश कार्यालय परामर्शों मे भाग लिया।

रक्षा सहयोग भारत–रूस भागीदारी का एक महत्वपूर्ण प्रेरक बल रहा। रक्षा मंत्री श्री मनोहर पारीकर ने अक्तूबर–नवंबर, 2015 में मॉस्को का दौरा किया और उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री सरगेई सोइगु के साथ सैन्य एवं तकनीकी सहयोग से संबद्ध भारत–रूस अंतर–सरकारी आयोग (आईआरआईजीसी–एमटीसी) की 15वीं बैठक की सह–अध्यक्षता की। रक्षा मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह ने अप्रैल, 2015 में चौथे मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया। दोनों देशों के सैन्य बलों के बीच संयुक्त अभियानों एवं उच्चस्तरीय यात्राओं सहित अन्य आदान–प्रदान भी हुए।

द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय कार्यान्वित किए गए, जिनमें व्यावसायियों के लिए वीजा व्यवस्था का सरलीकरण, आगमन पूर्व सूचनाओं के आदान–प्रदान से संबद्ध प्रोतोकोल (ग्रीन कॉरीडोर) पर हस्ताक्षर, अप्रसंस्कृत हीरों के व्यापार हेतु विशेष अधिसूचित क्षेत्र की स्थापना एवं कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच शामिल हैं। इस वर्ष के दौरान दोनों देशों में विशेषकर हाइड्रो कार्बन क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेशों की भी घोषणा की गयी।

बेलारूसः जून, 2015 में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा से बेलारूस के साथ द्विपक्षीय संबंधों को काफी प्रोत्साहन मिला। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री ने भी सितंबर, 2015 में अंतर–सरकारी आयोग बैठक में भाग लेने के लिए बेलारूस की यात्रा की। बेलारूस के विदेश मंत्री ने मई 2015 में भारत की यात्रा की।

उक्रेन एवं दक्षिण काकेससः उक्रेन के साथ भारत के संबंधों में लगातार प्रगति होती रही। सक्रिय सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक आदान–प्रदानों के जरिए आर्मेनिया, जार्जिया तथा अजरबेजान के साथ हमारे संबंध और सुदृढ हुए।

मध्य एशिया

सभी मध्य एशियाई देशों अर्थात कजाखस्तान, किर्गीज गणराज्य, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान की जुलाई, 2015 में हुई प्रधान मंत्री की यात्रा से इन देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों के स्वरूप का उन्नयन हुआ और इन देशों के साथ और इस पूरे क्षेत्र हमारे द्विपक्षीय संबंध नई ऊंचाई पर पहुंच गए। विदेश मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारीस्तरीय यात्राओं एवं कार्यकलापों से भारत के विस्तारित पड़ोस में अवस्थित इन देशों के साथ हमारे संबंध और सुदृढ़ हुए। भारत ने इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण तथा मानव संसाधनों के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना जारी रखा।

अंतर्राष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी):

इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारे के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। आईएनएसटीसी मार्ग पर भारतीय मालभाड़ा अग्रेषण संगठन द्वारा किए गए परीक्षण अध्ययन के उपरांत भारत ने जून, 2015 में मुंबई में आईएनएसटीसी पर एक सक्रिय सत्र का आयोजन किया, जिसके बाद अगस्त, 2015 में नई दिल्ली में विशेषज्ञस्तरीय बैठक तथा आईएनएसटीसी परिषद की बैठकें हुईं। इसके उपरांत, दिसंबर, 2015 में आईएनएसटीसी मार्ग को लोकप्रिय बनाने पर एक सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। भारत, रूस और अजरबेजान के सीमा शुल्क अधिकारियों की बैठक नवंबर, 2015 में अस्तराखान, रूस में हुआ।

तुर्कमेनिस्तान–अफगानिस्तान–पाकिस्तान–भारत (टीएपीआई) गैस पाइपलाइन परियोजना:

भारत के माननीय उप राष्ट्रपति श्री मोहम्मद अंसारी ने 13 सितंबर, 2015 में मैरी, तुर्कमेनिस्तान में आयोजित तुर्कमेनिस्तान–अफगानिस्तान–पाकिस्तान–भारत (टीएपीआई) गैस पाइपलाइन परियोजना के उद्घाटन समारोह में तुर्कमेनिस्तान एवं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति तथा पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ भाग लिया। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेन्द्र प्रधान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 6–8 अगस्त, 2015 तक टीएपीआई की संचालन समिति की 22वीं बैठक में भाग लिया। संचालन समिति की बैठक में तुर्कमेनिस्तान ने टीएपीआई कंसोटियम का नेतृत्व करने का प्रस्ताव किया, जिस पर अन्य तीनों सदस्यों ने अपनी सहमति व्यक्त की। टीएपीआई संचालन समिति की 23वीं बैठक का आयोजन 24 अक्तूबर, 2015 को अश्गाबाद में किया गया, जिसमें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। संचालन समिति की बैठक में चारों पक्षकारों ने मैसर्स टीएपीआई लिमि. के लिए शेयर होल्डिंग करार की शुरूआत की।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ):

इस वर्ष शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के साथ भारत के संबंधों का नया दौर शुरू हुआ है। जुलाई, 2015 में उफा, रूस में आयोजित राज्याध्यक्ष परिषद की बैठक के दौरान एससीओ ने भारत के लिए सदस्यता का शुभारंभ करने की घोषणा की। प्रधान मंत्री जी ने एससीओ के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वी. के. सिंह ने चीन के झेंगझु में 15 दिसंबर, 2015 को आयोजित एससीओ शासनाध्यक्षों की बैठक में भाग लिया। इस वर्ष एससीओ की विभिन्न बैठकों में भारत के अनेक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें स्वास्थ्य, आंतरिक सुरक्षा, न्याय, व्यापार एवं वाणिज्य स्तर पर हुई मंत्रिस्तरीय बैठकें और एससीओ महा अभियोजकों की बैठकें शामिल हैं।

खाड़ी पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका:

खाड़ी देशों के क्षेत्रों के साथ भारत के ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ संबंध रहे हैं, जो सदियों पुराने सभ्यतामूलक संपर्कों एवं लोगों से लोगों के बीच विद्यमान ठोस संबंधों के आधार पर और सुदृढ़ हुए हैं। नियमित आधार पर होने वाली उच्च स्तरीय बैठकों के जरिए ये मैत्रीपूर्ण संबंध और भी सुदृढ़ हुए हैं। खाड़ी क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार क्षेत्र है, जिसके साथ वर्ष 2014–15 में हमारा द्विपक्षीय व्यापार 150 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का रहा। यह क्षेत्र भारत के लिए कच्चा तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस का बड़ा आपूर्तिकता है, जहां से भारत के कुल कच्चे तेल आपूर्तियों का आधे से अधिक और भारत के कुल प्राकृतिक गैस आयातों का 85 प्रतिशत से अधिक किया जाता है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के सबसे बड़े 6 तेल स्रोतों में से चार– सऊदी अरब, इराक, कुवैत तथा संयुक्त अरब अमीरात खाड़ी क्षेत्र के हैं। खाड़ी क्षेत्र में लगभग 7 मिलियन प्रवासी भारतीय समुदाय भी रहते हैं, जो न सिर्फ मेजबान देशों के विकास में योगदान देते हैं, अपितु भारत और खाड़ी देशों के बीच महत्वपूर्ण संपर्क सेतु का भी कार्य करते हैं।

भारत ईरान इस्लामिक गणराज्य को भारत के निकटस्थ आर्थिक एवं सुरक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण देश मानता है। दोनों देशों के नेताओं एवं वरिष्ठ मंत्रियों के बीच हुए कार्यकलापों से वर्ष 2015 में आर्थिक क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को संवेग प्राप्त हुआ है। भारत ने जुलाई, 2015 में ईरान और पी–5+1 के बीच संयुक्त व्यापक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत किया है। जैसा कि संयुक्त व्यापक कार्य योजना में सहमति बनी थी। जनवरी, 2016 में कार्यान्वयन दिवस की घोषणा किया जाना धैर्यवान कूटनीति एवं वार्ता की विजय है।

अफ्रीका

यह वर्ष भारत–अफ्रीका भागीदारी में एक अत्यंत ही विशेष और ऐतिहासिक वर्ष रहा, जिसमें नेतृत्व के स्तर पर अभूतपूर्व कार्यकलाप हुए। भारत ने अक्तूबर, 2015 में भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें उन सभी 54 अफ्रीकी देशों ने भाग लिया, जिनके साथ हमारे राजनयिक संबंध है। रिकार्ड संख्या में 41 अफ्रीकी देशों ने राज्ययक्ष/शासनाध्यक्ष स्तर पर इस शिखर सम्मेलन में भागीदारी की। शिखर सम्मेलन से पूर्व 16 राज्य मंत्रियों ने शिखर सम्मेलन के लिए व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण देने के लिए प्रधान मंत्री के दूत के रूप में 49 अफ्रीकी देशों का दौरा किया। इसके अतिरिक्त इस अवधि में तंजानिया, मोजांबिक और सेशल्स के राष्ट्रपतियों की भारत की राजकीय

यात्रा तथा मॉरीशस के राष्ट्रपति की सरकारी यात्रा भी हुई। इन यात्राओं के तत्काल बाद मार्च, 2015 में मॉरीशस एवं सेशल्स के प्रधान मंत्रियों की यात्राएं हुईं।

वर्ष 2015 संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ थी और इस वर्ष अफ्रीका में अनेक महत्वपूर्ण विश्व सम्मेलन आयोजित हुए, जिनमें वित्तपोषण एवं विकास से संबद्ध तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आदिस अबावा, जुलाई 2015) और विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (नैरोबी, दिसंबर 2015) भारत ने सतत विकास के लिए 20–30 कार्यसूची से जुड़े मुद्दों पर अफ्रीकी भागीदारों के साथ घनिष्ठ सहयोग किया, जिसमें सितंबर, 2015 में संयुक्त राष्ट्रमहा सभा द्वारा पारित किया गया। भारत ने जलवायु परिवर्तन से संबद्ध पश्च 20–20 करार के संबंध में भी सहयोग किया, जिसे दिसंबर 2015 में पेरिस में आयोजित यूएनएफसीसीसी के कॉप–21 में अंतिम रूप दिया गया।

भारत–अफ्रीका कार्यकलापों ने शिक्षा, क्षमता निर्माण, कृषि, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी अवसंरचना, स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग करने सहित बहुफलकीय विकास भागीदारी वाले विलक्षण दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर आधारित व्यापार एवं निवेश संपर्कों तथा राजनैतिक कार्यकलापों को संवर्धित करने पर और बल दिया। इस भागीदारी ने नीली अर्थव्यवस्था, आतंकवाद का मुकाबला एवं समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के उभरते हुए मुद्दों पर भी विशेष ध्यान दिया। दीर्घकालिक डायस्पोरा संपर्क भारत–अफ्रीका संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

इस अवधि के दौरान दोनों देशों के बीच अनेक उच्चस्तरीय यात्राएं एवं कार्यकलाप हुए। साथ ही इसी अवधि के दौरान 23 अक्तूबर, 2015 में नई दिल्ली में भारत–अफ्रीका व्यापार मंत्रियों की चौथी बैठक भी आयोजित हुई। इस बैठक में व्यापार मंत्रियों/अधिकारियों तथा 8 क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों के 37 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चौथे भारत–अफ्रीका हाइड्रो कार्बन सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 21–22 जनवरी, 2016 तक किया गया। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए 25 अफ्रीकी देशों को निमंत्रित किया गया था।

पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र में अफ्रीका की सबसे अधिक जनसंख्या रहती है और यहां की अर्थव्यवस्थाओं का विकास सबसे तेजी से हो रहा है। यहां ऊर्जा संसाधनों के भी बड़े भंडार हैं। पिछले 10 वर्षों के दौरान इस क्षेत्र की अनेक अर्थव्यवस्थाओं ने विश्व के अन्य भागों की अर्थव्यवस्थाओं के विकास की गति को पीछे छोड़ दिया है और इस त्वरित आर्थिक प्रगति ने वहां विश्व में सबसे तेजी से विकास करने वाले मध्य वर्ग का निर्माण किया है।

उत्तरोत्तर बढ़ती जनसंख्या तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता यह सुनिश्चित करती है कि पश्चिम अफ्रीका में विभिन्न देशों एवं व्यवसायों के लिए निवेश एवं आर्थिक कार्यकलापों के महान अवसर उपलब्ध है। वर्ष 2000 से पूर्व इस पूरे क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद अनुमानतः 250 बिलियन अमरीकी डॉलर से कुछ कम था, परंतु एक दशक की अवधि के भीतर ही यह सकल घरेलू उत्पाद दोगुने से अधिक बढ़कर 565 बिलियन अमरीकी डॉलर का हो गया। विभिन्न प्रकार के आर्थिक एवं राजनैतिक सुधार इस आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण रहे हैं, जिनसे पूरे पश्चिम अफ्रीका में नए व्यावसायिक अवसरों को प्रोत्साहन मिला। वस्तुतः सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के साथ–साथ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में भी वृद्धि हुई है। 1990 के दशक के मध्य से पश्चिम अफ्रीका में सैन्य व्यवस्थाओं से संवैधानिक शासन की ओर ऐतिहासिक बदलाव हुआ है; अनेक देशों में गृह युद्ध समाप्त हुआ तथा नए सिरे से क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण पर बल दिया गया।

पश्चिम अफ्रीका क्षेत्र अभी भी भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है और फिलहाल यह लगभग 31 बिलियन अमरीकी डॉलर का है। यानी इसमें वर्ष 2003 के बाद से 15 गुने की वृद्धि हुई है। भारत कच्चे तेल की अपनी जरूरतों का लगभग 18 प्रतिशत इसी क्षेत्र से प्राप्त करता है। क्षमता निर्माण, कौशल विकास तथा भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचनाओं का संवर्धन इस क्षेत्र के साथ भारत की उत्तरोत्तर विस्तारित हो रही विकास भागीदारी का केंद्र बिंदु है। भारत ने इस क्षेत्र में संवैधानिक व्यवस्था, शांति, सुरक्षा एवं स्थायित्व की पुनर्स्थापना के उद्देश्य से किए जाने अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिए लगातार अपना समर्थन दिया है। पश्चिम अफ्रीका के कई देशों में चलाई जा रही अनेक शांति रक्षा कार्रवाइयों में भारतीय सैनिक शामिल हैं। तृतीय भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में पश्चिम एशिया के नेताओं के साथ उच्चस्तरीयों संपकों को नवीकृत करने का अवसर उपलब्ध कराया।

यूरोप

पश्चिम यूरोप

पश्चिम यूरोप के साथ संपर्क स्थापित करने पर विशेष बल दिया जाता रहा और इसके तहत अप्रैल–नवंबर, 2015 तक प्रधान मंत्री स्तर की 6 यात्राएं हुईं। प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड और यूके का दौरा किया, जबकि नीदरलैंड के प्रधान मंत्री तथा जर्मनी की चांसलर ने इस अवधि के दौरान भारत की यात्रा की। इन यात्राओं से आपसी हित के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में इन महत्वपूर्ण देशों के साथ संवर्धित भागीदारियों के लिए ठोस कार्य योजना स्थापित कार्ययोजना बनाने में मदद मिली।

मध्य यूरोप

भारत का मध्य यूरोप में स्थित देशों के साथ घनिष्ठ एवं सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहे। परस्पर दौरों, कारोबारी संबंध तथा सांस्कृतिक आदान–प्रदान के जरिए वर्ष के दौरान द्विपक्षीय संबंध और प्रगाढ़ हुए। वर्ष के दौरान भारत सरकार की नीतियों और प्रायौगिक परियोजनाओं विशेषतः मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ गंगा, कौशल भारत आदि जैसी परियोजनाओं के बारे में सूचनाएं देने के लिए सेमिनारों तथा अन्य ऐसे मंचों पर ध्यान केंद्रित किया गया, भारत–मध्य यूरोप कारोबार मंच का दूसरा सत्र 4–5 अक्तूबर, 2015 तक बेंगलूरू में आयोजित किया गया जिसमें मध्य यूरोप के 18 देशों के पदाधिकारियों तथा कारोबारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस वर्ष के मंच में पोलैंड सहभागी देश था। पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस का भी आयोजन किया गया जिसमें क्षेत्र भर के कई शहरों में योग की कक्षाएं, व्याख्यान तथा प्रदर्शनियां आयोजित की गई। भारत और मध्य यूरोप के देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में दोनों देशों के अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर एक–दूसरे को समर्थन देना जारी रखा।

अमरीकी देश

कनाड़ाः भारत–कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों में हाल के वर्षों में भारी परिवर्तन देखे गए हैं जिसके तहत साझा लोकतांत्रिक मूल्य, बहुवाद, निरंतर बढ़ता आर्थिक विनियोजन, नियमित तौर पर उच्चस्तरीय बातचीत और लोगों के बीच दीर्घकालिक आपसी संबंध विशेष हैं। इस संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा अप्रैल 2015 में की गई कनाडा यात्रा से एक नई गति आई और हमारे द्विपक्षीय संबंध रणनीतिक भागीदारी तक पहुँच गए। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रडियू के नेतृत्व में कनाडा में नव निर्वाचित सरकार के साथ भारत अपने संबंध जारी रखेगा। कनाडा में भारतीय मूल के लगभग 1.2 मिलियन लोग रहते हैं जो कनाडा की कुल आबादी का 3 प्रतिशत से भी अधिक है। लोगों के बीच अपसी संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी कनाडा यात्रा के दौरान कनाडियाई नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अधिप्रमाणन की घोषणा की। कनाडियाई नागरिकों के लिए 10 वर्ष की लम्बी अवधि के वीजा की भी घोषणा की गई।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कनाडा एक 'ऊर्जा सुपर पावर' है जहां यूरेनियम, प्राकृतिक गैस, तेल, कोयला, खनिज के सबसे बड़े भंडारों में से एक है तथा जल विद्युत, खनन, नवीकरणीय ऊर्जा तथा परमाणु ऊर्जा में उन्नत प्रोद्यौगिकीयां मौजूद है, हमारा मुख्य ध्यान ऊर्जा पर ही रहा है। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में इंडियन ऑयल ने प्रशांत उत्तर–पश्चिम, एलएनजी परियोजना, ब्रिटिश कोलम्बिया में 10ः की साझेदारी हासिल की है। प्रधानमंत्री की कनाडा यात्रा के दौरान परमाणु ऊर्जा विभाग और मैसर्स कैमेको इंक., कनाडा के बीच वर्ष 2015–20 के दौरान भारत को 3000 मीट्रिक टन यूरेनियम खनिज की आपूर्ति करने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। यूरेनियम की पहली खेप दिसम्बर 2015 में भारत पहुँची। वर्ष 2014 के दौरान 4.48 बिलियन अमरीकी डॉलर का द्विपक्षीय कारोबार हुआ। वर्ष 2014 में समग्र भारतीय एफडीआई 2781.1 मिलियन अमरीकी डॉलर था जबकि भारत में कनाडियाई एफडीआई 789.6 मिलियन अमरीकी डॉलर का था। द्विपक्षीय कारोबार तथा आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए दोनों पक्ष सक्रियता से व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) और द्विपक्षीय निवेश संरक्षण तथा संवर्धन करार (बीआईपीपीए) पर बातचीत कर रहे हैं।

संयुक्त राज्य अमरीकाः भारत–संयुक्त राज्य अमरीका द्विपक्षीय संबंध व्यापक द्विपक्षीय रणनीतिक तथा वैश्विक भागीदारी में परिणत हुए है, जो कि साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, तथा वैश्विक मुद्दों पर बढ़ती साझे हितों पर आधारित है। इस वर्ष भी शिखर सम्मेलन स्तरीय बातचीत तथा उच्चस्तरीय नियमित परस्पर दौरों के कारण विनियोजन हेतु दीर्घकालिक कार्यढांचे सहित व्यापक तथा निरन्तर बढ़ते वार्ता तंत्र के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग हेतु स्थायी गति प्राप्त हुई। सितम्बर 2015 में प्रधानमंत्री की दूसरी अमरीका यात्रा का उद्देश्य अमरीकी पूंजी तथा प्रोद्यौगिकी का लाभ उठाना और विभिन्न क्षेत्रों विशेषतः नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवाचार तथा विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में अमरीकी उद्योग के साथ मौजूदा निवेश तथा प्रोद्यौगिकी भागीदारी को और सुदृढ़ बनाना था। भारत के विकासमूलक उद्देश्यों के साथ अमरीका में मुख्य भागीदारों के हितों पर भी बल दिया गया। इस यात्रा से अमरीका में रह रहे जीवंत तथा निरंतर विस्तारित होते भारतीय मूल के लोगों के साथ सम्पर्क साधने का अवसर भी प्राप्त हुआ।

वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों जैसे व्यापार तथा अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, ऊर्जा, विज्ञान तथा प्रोद्यौगिकी, घरेलू सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला, जलवायु परिवर्तन तथा अन्य विषयों में राजनीतिक तथा कार्यात्मक स्तरों पर प्रमुख रूप से आदान–प्रदान किए गए, जो सितम्बर 2015 में प्रथम रणनीतिक तथा वाणिज्यिक वार्ता स्तर तक पहुँचा। इस वर्ष दोनों पक्षों की ओर से द्विपक्षीय आर्थिक विनियोजन को और सुदृढ़ बनाने के प्रति एक नई रूचि भी दिखाई दी। रक्षा प्रोद्यौगिकी तथा कारोबार के अन्तर्गत अधिकाधिक रक्षा विनियोजन हुआ जिसके तहत सह–विकास तथा सह–निर्माण पर ज्यादा ध्यान दिया गया। इस वर्ष रक्षा मंत्री स्तर पर परस्पर यात्राओं से यह सहयोग और मजबूत हुआ जिसके परिणामस्वरूप '10 वर्षीय भारत अमरीका रक्षा संबंध कार्यढांचा' पर हस्ताक्षर किए गए।

वर्ष 2015 में भारत–अमरीका कारोबार तथा वाणिज्यिक विनियोजन का विस्तार होता रहा जिसके कारण कारोबार (वस्तु तथा सेवाएं), निवेश तथा प्रोद्यौगिकी साझेदारी में काफी बढ़ोत्तरी हुई। अमरीका वस्तु एवं सेवाओं के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार बना रहा। वर्ष 2014–15 में अमरीका भारत में निवेश करने वाला छठा सबसे बड़ा निवेशक रहा।

लातिन अमरीका तथा कैरीबियाई देश

भारत लातिन अमरीकी देशों के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है तथा इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ इसके हार्दिक एवं मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। कैरीबियाई देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सभ्यता मूलक संबंध हैं। भारत तथा लैक क्षेत्र के देश कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साझा सदस्य हैं तथा संयुक्त राष्ट्र, जी–77, एनएएम आदि में एक साथ करीबी रूप से कार्य करते हैं।

लैक क्षेत्र के साथ भारत के संबंध 2015 में अत्यधिक गहरे हुए हैं तथा कई क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। इस क्षेत्र के लगभग सभी देशों को ई–पर्यटक वीजा जारी करने के लिए शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2015 को इस क्षेत्र के सभी देशों में स्थानीय राजनैतिक समर्थन एवं उच्चतम राजनीतिक स्तरों सहित सामान्य जनता की भागीदारी से एक व्यापक स्तर पर मनाया गया जिससे भारत द्वारा की गई पहल में उनका साथ दिखता है।

व्यापार में वृद्धि लाने, नए क्षेत्रों की पहचान करने तथा मौजूदा क्षेत्रों में मजबूती लाने के लिए कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) द्वारा विदेश मंत्रालय तथा वाणिज्य विभाग के सहयोग से सातवां भारत–लैक कान्क्लेव आयोजित किया गया जिसमें इस क्षेत्र में उच्च स्तर की भागीदारी रही।

2015 में उच्च स्तरों की यात्राओं एवं बैठकों का विनिमय किया गया जिसमें इस संबंध को आगे ले जाने के लिए अधिदेश एवं योजना प्रदान की गई। प्रधान मंत्री ने न्यूयॉर्क में यू एन जी ए के अवसर पर मेक्सिकोए गुयाना तथा सेंट लूसिया एवं सेंट विन्सेंट तथा ग्रेनाडिन्स के राष्ट्रपति के साथ बैठक की। संयुक्त आयोग की बैठक विदेश मंत्री द्वारा नई दिल्ली में ब्राजील तथा सूरीनाम के विदेश मंत्री के साथ की गई। ब्राजील के विदेश मंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तथा वित्त मंत्री के साथ मुलाकात की। उरुग्वे के विदेश मंत्री ने भारत की विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता हेतु भारत की यात्रा की। विदेश राज्यमंत्री जनरल (डॉ) वी. के सिंह (सेवानिवृत्त) ने 2015 में डोमिनिक गणराज्य, जमैका, वेनेजुएला, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, कोस्टारिका तथा साल्वाडोर को व्यापक रूप से शामिल करते हुए इस क्षेत्र की यात्रा की। होन्डुरास, बारबाडोस तथा पराग्वे के साथ विदेशी कार्यालय परामर्श हुआ। ब्राजील तथा अर्जेन्टीना के साथ सचिव स्तरीय बातचीत भी हुई। कोस्टारिका के द्वितीय उप राष्ट्रपति ने अक्तूबर 2015 में 6वें भारत–लैक कॉन्कलेव में भाग लिया।

इस क्षेत्र के क्षेत्रीय समूहों के साथ भारत के कार्यकलापों का उल्लेखनीय विकास हुआ है। भारत–सीका की तीसरी मंत्रिस्तरीय बैठक मई 2015 को ग्वाटेमाला में हुई थी जिसमें विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ) वी. के सिंह (सेवानिवृत्त) ने भाग लिया था तथा भारत–केरिकॉम संयुक्त आयोग की पहली बैठक जून 2015 को गुयाना में हुई थी जिसके बाद सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में मंत्रिस्तरीय बैठक हुई जिसमें विदेश मंत्री ने भाग लिया। विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में सेलेक (सी ई एल ए सी) चतुष्क के साथ भी मुलाकात की। सेलेक के साथ हमारे संबंध महत्वपूर्ण समूहों के साथ हमारी वार्ता प्रक्रिया को मजबूत करने में सहायता करेंगे।

व्यापार एवं निवेश निःसंदेह हमारे संबंधों का मुख्य प्रेरक हैं। वर्ष 2000 में 2 बिलियन अमरीकी डॉलर से हाल के वर्षों में 46 बिलियन अमरीकी डॉलर तक व्यापार बढ़ा है। लैक क्षेत्र भारत के लिए कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है (हमारे कच्चे तेल का 19% इस क्षेत्र से आता है)

संयुक्त राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन

संयुक्त राष्ट्रः भारत ने वर्ष 2015 के दौरान संयुक्त राष्ट्र तथा संयुक्त राष्ट्र संगठनों के साथ उच्च.स्तरीय संबंध बनाना जारी रखा। संयुक्त राष्ट्र संगठन की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अप्रैल 2015 में यूनेस्को मुख्यालय की यात्रा की। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के उच्च–स्तरीय खंड का नेतृत्व भी किया। माननीय प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अवसंरचना कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) में पक्षों के सम्मेलन के 21वें सत्र के उच्च–स्तरीय खंड में भी भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पर्यावरण, जलवायु तथा वन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया जहां एतिहासिक पेरिस करार को पारित किया गया। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने इंकियोन में आयोजित विश्व शिक्षा मंच में भाग लिया था। वित्त राज्यमंत्री श्री जयंत सिन्हा ने अदीस अबाबा में विकास हेतु वित्त पोषण पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। श्रीमती निर्मला सीतारमण, वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री (आई/सी) ने बैंकॉक में एशिया–प्रशांत यूएनस्काप हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक आयोग के 71वें वार्षिक आयोग के सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। लोकसभा की सभापति श्रीमती सुमित्रा महाजन ने अक्तूबर 2015 में जेनेवा में संसद के 133वें आइपीयू सत्र के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था ।

विधि तथा संधि प्रभाग

रिपोर्ट की संबंधित अवधि के दौरान विधि तथा संधि प्रभाग ने संयुक्त राष्ट्र की 6ठी समिति, आतंकवाद, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर विधि सम्मत शासन, मिशन पर गए संयुक्त राष्ट्र के कार्मिकों तथा विशेषज्ञों का आपराधिक उत्तरदायित्वय, वैश्विक न्यायाधिकार, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर विशेष समितिय विदेशी आपराधिक न्यायाधिकार से संयुक्त राष्ट्र कार्मिकों की उन्मुक्ति तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के विचाराधीन शीर्षकों से जुड़े सहित विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कानून से जुड़े कार्यों का अनुसरण किया।

इस प्रभाग ने न्यूयार्क में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कानून सप्ताह में भाग लिया जिसमें संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के विधि सलाहकारों की बैठकों के अतिरिक्त, एशिया–अफ्रीका विधि परामर्शदात्री संगठन द्वारा आयोजित विचार–विमर्श भी शामिल थे।

समुद्री कानून इस प्रभाग की प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है तथा इसने सीबेड क्षेत्र, समुद्री परिसीमन, समुद्री पर्यावरण का सतत विकास, कांटीनेंटल सेल्फ से जुड़े मुद्दों सहित विभिन्न विधि क्षेत्रों के कानूनी पहलुओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं।

प्रभाग ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग के कार्यदलों की बैठक, निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून पर हेग सम्मेलन तथा एशिया–अफ्रीका विधि परामर्शदात्री संगठन की बैठकों में भाग लिया। इसके अलावा, मुक्त व्यापार करारों, निवेश संरक्षण करारोंए सामाजिक सुरक्षा करारों, प्रत्यर्पण, परस्पर विधि सहायता मामलों इत्यादि से जुड़े द्विपक्षीय, बहुपक्षीय विचार–विमर्श भी हुए जिसमें प्रभाग ने भाग लिया।

इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फोर द लॉ ऑफ द सी तथा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत से जुड़े दो अंतर्राष्ट्रीय विवाद चल रहे हैं। वे एमवी एनरिका लेग्जी मामला (आईटीएलओएस में इटली बनाम भारत); तथा परमाणु हथियारों की दौड़ तथा परमाणु निरस्त्रीकरण के विराम से जुड़े विचार–विमर्श की बाध्यताएं (आईसीजे में मार्शल द्वीप समूह बनाम भारत) हैं। यह प्रभाग इन मामलों की देखरेख में सक्रिय रूप से शामिल है।

यह प्रभाग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय करारों/संधियों/समझौता ज्ञापनों पर निर्णय लेने से पूर्व उनके पुनरीक्षण से जुड़े मामलों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2015 के दौरान इस प्रभाग ने ऐसे सैकड़ों दस्तावेजों की जांच की। भारत द्वारा की गई इन संधियों/करारों के संग्रहण के अलावा यह प्रभाग उन करारों तथा संधियों की सॉफ्ट प्रतियों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए भी प्रयासरत रहता है।

वर्ष 2015 के दौरानए इस प्रभाग ने अंतर्राष्ट्रीय संधि प्रथाओं के भाग के रूप में 54 अनुसमर्थन दस्तावेजों तथा पूर्ण शक्तियों के 11 दस्तावेजों पर कार्रवाई की।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क): भारत अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और इस क्षेत्र के प्रति अपनी वचनबद्धता के कारण सार्क के लिए महत्वपूर्ण है। सार्क में भारत का योगदान मौलिक भी है। भारत ने सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए सार्क संस्थाओं को 530 मिलियन अमरीकी डॉलर से भी अधिक का अंशदान किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने काठमांडू में आयोजित 18वें सार्क शिखर सम्मेलन (नवंबर 2014) में कई एकपक्षीय पेशकश की थी जैसे कि सार्क देशों के कारोबारियों को 3 से 5 वर्ष के लिए दीर्घकालिक कारोबारी वीजा दिए जा रहे हैं, भारत के उप राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस में अफगानिस्तान के स्वास्थ्य अधिकारियों/विशेषज्ञों ने भाग लिया, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय ने प्रत्येक सार्क देश में कम से कम एक विश्वविद्यालय के साथ भागीदारी की है, सार्क देशों में स्थित हमारे मिशनों द्वारा प्राथमिकता आधार पर मरीजों तथा उसके साथ आने वाले सहायकों के लिए वीजा जारी किया जा रहा है और सार्क ऊर्जा सहयोग (विद्युत) कार्य ढांचा करार पर हस्ताक्षर किए गए। उपर्युक्त के अलावा भारत ने 23–26 नवंबर, 2015 तक नई दिल्ली में सार्क देशों की आपदा प्रबंधन योजनाओं तथा क्षमताओं पर चर्चा करने के लिए प्रतिभागियों को अवसर प्रदान करने हेतु दक्षिण एशियाई वार्षिक आपदा प्रबंधन अभ्यास का आयोजन किया। भारत के अपने पड़ोसी देशों के प्रति एक नये दृष्टिकोण के तौर पर वर्ष 2004 से सार्क में भारत का सक्रिय रवैया उसके उद्घोषणा मूलक मोड से क्रियान्वयन की दिशा में संगठन का एक सतत एवं अपरिवर्तनीय बदलाव सुनिश्चित करने में एक परिवर्तनकारी कारक रहा है। आकलित क्षमताओं से अधिक जिम्मेदारी उठाने की भारत की प्रतिबद्धता का इस क्षेत्र में स्वागत किया गया है।

बहुक्षेत्रीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाडी पहल (बीआईएमएसटीईसी): अप्रैल–दिसम्बर, 2015 की अवधि के दौरान भारत ने बीआईएमएसटीईसी के सभी सदस्य राष्ट्रों के लिए साझा महत्व के विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जैसे कि परिवहन तथा संचार, व्यापार तथा निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, कृषि, जन–स्वास्थ्य, आतंकवाद का मुकाबला तथा अन्तर्राष्ट्रीय अपराध और जलवायु परिवर्तन। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आतंकवाद के वित्त पोषण की रोकथाम से निपटने संबंधी बीआईएमएसटीईसी उपसमूह की बैठक थिंपू, भूटान में 27–28 मई, 2015 तक आयोजित की गई। पारम्परिक औषधि से संबंधित राष्ट्रीय समन्वयन केंद्रों का एक बीआईएमएसटीईसी नेटवर्क स्थापित किया गया है। बीआईएमएसटीईसी–प्रौद्योगिकी अन्तरण सुविधा (टीटीएफ) से संबधित तीसरे बीआईएमएसटीईसी

विशेषज्ञ समूह की बैठक 25–26 अगस्त, 2015 तक कोलम्बो में आयोजित की गई। बीआईएमएसटीईसी कारोबार वार्ता समिति (टीएनसी) की 20वीं बैठक 7–9 सितम्बर, 2015 तक खौन खाएन, थाईलैंड में आयोजित की गई। आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता से संबंधित बीआईएमएसटीईसी अभिसमय के पाठ को अंतिम रूप दिए जाने में भी प्रगति हुई है और यह अगले बीआईएमएसटीईसी मंत्रालयी बैठक में हस्ताक्षर किए जाने हेतु तैयार है।

निरस्त्रीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलेः वर्ष 2015–16 में भारत ने वैश्विक एवं गैर पक्षपातपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुसरण में निरस्त्रीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले से संबंधित विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय भूमिका निभाना जारी रखा। जिसका उद्देश्य सामान्य एवं संपूर्ण निरस्त्रीकरण का लक्ष्य हासिल करना था। इन मुद्दों पर भारत के पक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा हितों और विभिन्न पारंपरिक तथा गैर–पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ अपने घनिष्ठ विनियोजन की परंपरा द्वारा अभिप्रेरित थे। भारत न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र की प्रथम समिति, संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग, जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन, जिनेवा में जैविक तथा जहरीले हथियार कन्वेन्शन (बीटीडब्ल्यूसी), द हेग में रसायनिक हथियार कन्वेन्शन, जिनेवा में कतिपय पारंपरिक हथियार कन्वेन्शन, न्यूयार्क में लघु हथियार तथा हल्के हथियार संबंधी कार्रवाई पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम की बैठकों में सक्रिय भूमिका निभाता रहा।

बहुपक्षीय आर्थिक संबंध

उफा, रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलनः प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उफा, रूस में 8–9 जुलाई, 2015 तक आयोजित 7वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया। इस शिखर सम्मेलन का विषय "ब्रिक्स भागीदारी–वैश्विक विकास का एक सशक्त कारक" था। नेताओं ने व्यापक मुद्दों पर बातचीत की जिनमें संयुक्त राष्ट्र सुधार, आई एम एफ सुधार, विश्व व्यापार संगठन, जी–20 क्षेत्रीय तथा वैश्विक राजनैतिक विकास, आतंकवाद, न्यू डेवलपमेंट बैंक, (एनडीबी), ब्रिक्स आकस्मिक प्रारक्षण व्यवस्था (सीआरए), सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सहयोग और अंतर ब्रिक्स सहयोग से संबंधित अन्य मुद्दे शामिल हैं। नेताओं ने शिखर सम्मेलन में उफा उद्घोषणा तथा कार्ययोजना को स्वीकार किया। 7वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणामों में सांस्कृतिक सहयोग पर करार, संयुक्त ब्रिक्स वेबसाइट तैयार करने से संबंधित एक समझौता ज्ञापन और एनडीबी के साथ सहयोग हेतु ब्रिक्स अंतर बैंक तंत्र पर सहयोग के तहत एक समझौता ज्ञापन शामिल है। आर्थिक भागीदारी हेतु ब्रिक्स रणनीति जिसे शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा स्वीकार किया गया, में व्यापार, निवेश, वित्त, विनिर्माण, ऊर्जा, कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, आईसीटी आदि क्षेत्रों में सहयोग शामिल हैं।

ईब्सा वार्ता मंचः ईब्सा (भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका) वार्ता मंच के मुख्य बिन्दुओं (वरिष्ठ अधिकारियों) की 25 सितंबर, 2015 को न्यूयार्क में बैठक हुई। यह जून, 2003 में ईब्सा की स्थापना के पश्चात 25वीं बैठक थी। उन्होंने दक्षिण–दक्षिण सहयोग के बढ़ते महत्व के परिप्रेक्ष्य में ईब्सा की सतत प्रासंगिकता की पुर्नअभिपुष्टि की। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने माइक्रो वित्त पोषण, उपग्रह आधारित अनुप्रयोग, स्मार्ट सिटी और संयुक्त अंटार्कटिका अभियान के क्षेत्र में भारत द्वारा प्रस्तावित ईब्सा सहयोग हेतु नई पहलकदमियों का स्वागत किया।

10वां जी–20 शिखर सम्मेलनः प्रधानमंत्री ने अंतालिया, तुर्की में दिनांक 15–16 नवंबर, 2015 तक आयोजित 10वें जी–20 शिखर सम्मेलन में भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया। इस शिखर सम्मेलन के एजेंडे में आतंकवाद, शरणार्थी संकट, जलवायु परिवर्तन, 10वां डब्ल्यूटीओ मंत्रालयी सम्मेलन, वैश्विक अर्थव्यवस्था, विकास एवं रोजगार तथा निवेश रणनीतियां, सहनशीलता में वृद्धि, वित्तीय विनियमन, अंतर्राष्ट्रीय कर, आतंकवादरोध, आईएमएफ सुधार तथा ऊर्जा जैसे मुद्दे शामिल थे।

विकास सहयोग

विकास सहयोग भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। भारत द्वारा विकासशील देशों में संचालित विदेशी विकास सहायता कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में इसके दायरे में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी हुई है। इनमें ऋण ऋंखला, अनुदान सहायता, तकनीकी परामर्श, आपदा राहत, मानवीय सहायता, शैक्षिक छात्रवृत्तियां और अल्पकालिक असैनिक तथा सैन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों सहित व्यापक क्षमता विकास कार्यक्रम शामिल हैं।

विकास सहभागिता प्रशासन की स्थापना विदेश मंत्रालय में जनवरी, 2012 में की गई जिसका उद्देश्य भारत के विकास परियोजनाओं की अभिकल्पना, शुरूआत, क्रियान्वयन तथा प्रचालन जैसे चरणों से होते हुए इनका कारगर निष्पादन एवं निगरानी करना है।

अवसंरचना, जलविद्युत, विद्युत पारेषण, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग तथा अन्य क्षेत्र जो मेजबान सरकारों द्वारा तय किए गए हों, से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाएं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यामां, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका तथा अन्य देशों में लागू किए जा रहे हैं। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा पार कनेक्टिविटी विकसित करने तथा इन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं और ये क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य

एशिया, अफ्रीका तथा लातिन अमरीका, में सूचना तथा कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी, लघु एवं मझौले उद्यम और पुरातत्व सर्वेक्षण में द्वि पक्षीय परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

तीसरे भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (आईएएफएस–III) का आयोजन 26–30 अक्तूबर, 2015 तक नई दिल्ली में किया गया ताकि भारत और अफ्रीका के बीच वर्षों पुरानी सहभागिता को नया बल प्रदान किया जा सके। 54 अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। "दिल्ली घोषणा 2015" शीर्षक संकल्पना दस्तावेज और भारत–अफ्रीका रणनीतिक सहयोग कार्यढांचे में परस्पर विकास को रेखांकित करने के लिए अफ्रीका एजेंडा–2063 के साथ भारत की विकास गाथा का एक साथ उल्लेख करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति तैयार की गई। इस शिखर सम्मेलन में भारत–अफ्रीका सहभागिता के केन्द्र में विकास सहयोग को रखा गया, जिसके तहत अगले 5 वर्षों के दौरान विकास परियाजनाओं के लिए 10 बिलियन अमरीकी डालर की ऋण ऋंखला जुटाई गई और 600 मिलियन अमरीकी डालर की अनुदान सहायता की व्यवस्था की गई। डीपीए ने इस सम्मेलन के दौरान सक्रिय भूमिका निभाई क्योंकि इस अवसर पर भारत की सहायता से अफ्रीका में शुरू की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के बारे में द्विपक्षीय विचार–विमर्श किए गए।

अन्य विकासशील देशों को रियायती शर्तों पर ऋण ऋंखला दिया जाना भारत के बाह्य विकास सहायता का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। वर्ष दर वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में अलग–अलग देशों को कुल 16,898.23 मिलियन अमरीकी डालर की लागत से 226 ऋण ऋंखलाएं आबंटित की गईं जिनमें से 8,705.21 मिलियन अमरीकी डालर अफ्रीकी देशों के लिए और 8,193.02 मिलियन अमरीकी डालर गैर–अफ्रीकी देशों के लिए थीं।

वर्ष 2015–16 के दौरान भारत के तकनीकी एवं आर्थिक सहायता (आईटीईसी)/अफ्रीकी कार्यक्रमों के लिए विशेष राष्ट्रकुल सहायता (एससीएएपी) के तहत विभिन्न विषयों में 161 सहभागी देशों को 8360 नागरिक प्रशिक्षण स्लॉट प्रदान किए गए। भारत में विभिन्न रक्षा संस्थानों में सहभागी देशों को 2000 से भी अधिक रक्षा प्रशिक्षण स्लॉट प्रदान किए गए। पृथक रूप से, एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में सहयोगात्मक एवं आर्थिक, सामाजिक विकास हेतु दोहरी योजना से संबंधित तकनीकी सहयोग के तहत 500 नागरिक प्रशिक्षण स्लॉट प्रदान किए गए। इसके अलावा, सहभागी देशों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर विभिन्न विषयों में विशेष पाठ्यक्रम भी संचालित किए गए। आईटीईसी के पुराने छात्रों के साथ सतत विनियोजन पर बल देने और साथ ही डिजिटल इंडिया पहल के अनुसार आईटीईसी पोर्टल अब उपलब्ध कराया गया है।

वर्ष 2015–16 में सीरिया, फिलिपींस, जोर्डन, लेबनान, यमन तथा नेपाल को मानवीय सहायता प्रदान की गई।

निवेश तथा प्रौद्योगिकी संवर्धन

वर्ष 2015–16 भारत के आर्थिक राजनय के लिए एक उत्साहवध ्क वर्ष रहा। अपने विभिन्न मिशनों/केन्द्रों के माध्यम से विश्व भर में विदेश मंत्रालय का आर्थिक विनियोजन देश के निवेशकों, उद्यमियों, कामगारों तथा उपभोक्ताओं के लिए अवसर सृजित कर रहा है जबकि यह राष्ट्र के आर्थिक उद्देश्यों को भी पूरा कर रहा है। निवेश एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन विभाग (आईटीपी) जो कि विदेश मंत्रालय की आर्थिक शाखा है, ने भारतीय मिशनों/केन्द्रों को अपनी आर्थिक पहुंच को बढ़ाने के लिए सहायता दी; कारोबार तथा निवेश विवादों को सुलझाने में मदद की; भारत में कारोबार के अवसर ढूंढने में विदेशी उद्यमियों को सुविधाएं प्रदान कीं; भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं तथा क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पहलों को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार एवं सम्मेलन आयोजित करने हेतु बिजनेस चैम्बरों तथा विचारकों को वित्तीय सहायता प्रदान की; नामी–गिरामी परामर्श फर्मों को नियोजित करके रिपोर्टें तथा सर्वेक्षण करवाए गए; और नागरिक उड्डयन, रेलवे, जहाजरानी तथा सड़क परिवहन, ऊर्जा संसाधन, शहरी विकास, कृषि, स्वास्थ्य, जल एवं स्वच्छता, वित्त, कारोबार, पर्यटन, संस्कृति तथा सूचना के क्षेत्र में अन्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य किया।

ऊर्जा सुरक्षा

ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग विदेश मंत्रालय में ऊर्जा से संबंधित मामलों हेतु एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है। महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा संबंधी मुद्दों पर निरंतर राजनयिक हस्तक्षेप करना और अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ गहन समन्वयन करना अनिवार्य है। ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग ने अन्य मंत्रालयों के साथ गहन बातचीत करना जारी रखा और साथ ही ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षा संबंध ्ी मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विचार–विमर्श में भी योगदान दिया।

इस प्रभाग ने 14–15 अप्रैल, 2015 के दौरान हैनोवर में आयोजित सी–मेला 2015, 19–20 मई, 2015 के दौरान न्यूयार्क में आयोजित अखिल मंच हेतु द्वितीय संयुक्त राष्ट्र संधारणीय ऊर्जा बैठक, 24–26 मई, 2015 के दौरान मेरिडा, मैक्सिको में आयोजित ऊर्जा दक्षता सहयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी की नीति समिति की बैठक, 16–18 सितंबर, 2015 के दौरान पेरिस में आयोजित ऊर्जा दक्षता सहयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी की कार्यकारी समिति की 13वीं बैठक, वर्ष 2015 के दौरान तुर्की में तुर्की की

अध्यक्षता में आयोजित स्वच्छ ऊर्जा मंत्रालयीय बैठक वियना, ऑस्ट्रिया में 3–4 जून, 2015 तक आयोजित ओपीईसी अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, आबूधाबी में क्रमशः 10–11 जून, 2015 तथा 23–24 नवंबर, 2015 तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी परिषद (आईआरईएनए) की नौवी तथा दसवीं बैठकों, 16 सितंबर, 2015 को टोक्यो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एलएनजी निर्माता उपभोक्ता सम्मेलन, इस्तांबुल, तुर्की में 1–2 अक्तूबर, 2015 के दौरान उप–सहारा अफ्रीका में ऊर्जा सुलभता के संबंध में जी–20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक तथा सम्मेलन, पेरिस में 17–18 नवंबर, 2015 तक आयोजित आईईए बैठक में हिस्सा लिया।

माननीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री ने हाइड्रोकार्बन तथा कोयला क्षेत्र में

आगे और सहयोग के संबंध में 9–10 अप्रैल, 2015 तक मपूतो, मोजाम्बिक का दौरा किया। तेल तथा गैस क्षेत्र में कापार तथा निवेश संबंधी मुद्दों पर ईरान के साथ द्विपक्षीय विचार–विमर्श करने के लिए 18–19 अप्रैल, 2015 तक तथा 28 जुलाई, 2015 को भारतीय शिष्टमंडल ने तेहरान, ईरान की यात्रा की।

इस वर्ष के दौरान प्रस्तावित टीएपीआ पाइपलाइन परियोजना में उल्लेखनीय प्रगति हुई जिसके तहत पक्षकारों द्वारा टीएपीआई लि. में अपनी–अपनी हिस्सेदारी की प्रतिशतता और इस परियोजना के लिए शेयरधारक करार पर हस्ताक्षर किए जाने की घोषणा की गई। इस पाइपलाइन के लिए भू–खनन की रस्म 13 दिसंबर, 2015 को मेरी, तुर्कमेनिस्तान में पूरी की गई।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलंद द्वारा सीओपी 21 के अवसर पर 30 नवंबर, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस (आईएसए) बैठक आयोजित की गई। आईएसए की अंतर्राष्ट्रीय संचालन समिति की पहली बैठक 1 दिसंबर, 2015 को पेरिस में आयोजित की गई। इसकी दूसरी बैठक 18 जनवरी, 2016 को आबूधाबी, संयुक्त राज्य अमीरात में आयोजित की गई।

राज्य प्रभाग

अक्तूबर, 2014 में राज्य प्रभाग की स्थापना के बाद से ही इसकी भूमिका को राज्यों तथा अन्य देशों द्वारा काफी सराहा गया है। राज्य प्रभाग राज्यों, मिशनों तथा विदेश मंत्रालय के बीच समन्वयन हेतु एक धुरी की तरह कार्य करने का प्रयास करता है, जो न केवल राज्यों के विदेशी संबंधों को सुविधाजनक बनाता है बल्कि इस प्रक्रिया में सहयोगात्मक संघवाद की अभिकल्पना को भी मजबूती प्रदान करता है। राज्य प्रभाग एक नई संस्थागत संरचना तैयार करने और राज्यों के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत बनाने की तैयारी में है जो 'विकास हेतु राजनय' की संकल्पना को लागू करने में इस प्रभाग का योगदान होगा।

आतंकवाद का मुकाबला

वर्ष के दौरान भारत ने विभिन्न सहभागी देशों के साथ आतंकवाद का मुकाबला करने संबंधी संयुक्त कार्य समूहों के माध्यम से सुनियोजित परामर्श करना जारी रखा। भारत ने नवंबर, 2015 में ब्रिक्स तथा जी–20 शिखर–सम्मेलनों में आतंकवाद के खतरे के प्रति अपनी कड़ी चिंता व्यक्त की। भारत ने वर्ष 1996 में उसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (सीसीआईटी) के तत्वावधान में इस समस्या से एक जुट होकर निपटने के महत्व पर भी बल दिया।

वैश्विक साइबर मुद्दे

विदेश मंत्रालय का वैश्विक साइबर मुद्दा प्रभाग वैश्विक साइबर मुद्दों से संबंधित सभी मामलों को निपटाता है। 'डिजिटल इंडिया' के लक्ष्य को हासिल करने और साइबर मुद्दों पर महत्वपूर्ण वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती भागीदारी के मद्देनजर इस प्रभाग ने वर्ष 2015–16 की अवधि के दौरान वैश्विक साइबर मुद्दों पर भारत की नेतृत्व की भूमिका की पुरजोर वकालत की है।

सीमा प्रकोष्ठ निरस्त्रीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलेः

सीमा प्रकोष्ठ भारत की अंतर्राष्टीय सीमाओं से संबंधित सभी मानचित्रों/दस्तावेजों/सूचनाओं का भण्डार है। यह प्रकोष्ठ इस मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय प्रभागों को नक्शा संबंधी सलाह तथा तकनीकी सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2015–16 के दौरान, इस प्रभाग ने बांग्लादेश, नेपाल तथा म्यांमार के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय भू तथा समुद्री सीमा से संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय/अंतर–मंत्रालयी बैठकों में हिस्सा लिया।

नीति आयोजना तथा अनुसंधान प्रभाग

वर्ष 2014–15 के दौरान विदेश मंत्रालय के नीति आयोजना तथा अनुसंधान प्रभाग में महत्वपूर्ण फेरबदल हुए। इस प्रभाग को अधि ाकाधिक मानव तथा वित्तीय संसाधन प्रदान करके और मजबूत बनाया गया ताकि यह इस मंत्रालय को वर्तमान मुद्दों/नीतियों पर शोध आधारित दृष्टिकोण प्रदान करने, भारतीय विचारकों को सक्रिय जानकारियां देने, भारत में समकालीन विदेश नीति संबंध ी मुद्दों पर चर्चा हेतु महत्वपूर्ण मंच प्रदान करने के लिए प्रमुख विचारकों के साथ सम्मेलन आयोजित करने और हमारे महत्पूर्ण राजनयिक सहभागियों के साथ नीतिगत आयोजना पर वार्ता शुरू करने संबंधी अपने अधिदेश को पूरा कर सके।

कौंसुली, पासपोर्ट तथा वीजा सेवाएं

पासपोर्ट तथा वीजा जारी करना विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान

की जाने वाली सर्वाधिक प्रत्यक्ष नागरिक केंद्रित सेवा है। वर्ष 2015, देशभर में पासपोर्ट सेवाओं की सुपुर्दगी में कई मात्रात्मक एवं गुणात्मक सुधारों का गवाह बना। पासपोर्ट सेवा, जो राष्ट्रीय ई–अभिशासन योजना के अंतर्गत विशालतम मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है, ने अपने सफल प्रचालन के साढ़े तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं। यदि हम इसे इस संदर्भ में देखें कि मई, 2015 में पासपोर्ट सेवा ने अंतर्राष्टीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) के तीन प्रमाणपत्र (आईएसओ 9001ः आईएसओ 20000–1 : 2011, तथा आईएसओ 27001:2013) हासिल किए, तो यह सचमुच एक उपलब्धि थी। आईएसओ प्रमाणीकरण को गुणवत्ता प्रबंधन एवं सेवा मानकों की कसौटी माना जाता है।

सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति (पीपीपी) से संचालित 77 पासपोर्ट सेवा केंद्रों के अलावा, मंत्रालय ने 8 अतिरिक्त पासपोर्ट सेवा केंद्र अगरतला, आईजॉल, गंगटोक, इंफाल, कालाबुर्गी, करीमनगर, दरभंगा तथा शिलांग में स्थापित किए हैं जिससे पासपोर्ट आवेदकों को विशेषतः पूर्वोत्तर क्षेत्र में अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। वर्ष 2016 के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए 10 और पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं जिससे पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या 95 हो जाएगी।

वर्ष 2015 के दौरान मंत्रालय द्वारा 1.20 करोड़ पासपोर्ट तथा इससे संबंधित सेवाएं प्रदान की गईं। इनमें से 13.85 लाख पासपोर्ट संबंधी सेवाएं विदेश स्थित 183 मिशनों तथा केंद्रों द्वारा प्रदान की गईं। प्रदान की गई सेवाओं की संख्या में वर्ष 2014 की तुलना में 21 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। प्राप्त आवेदनों की संख्या के मामले में अग्रणी 5 राज्य : उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा गुजरात थे (जहां से कुल आवेदनों का 51 प्रतिशत से भी अधिक प्राप्त हुआ)। इसी तरह भारत से बाहर भारतीय पासपोर्ट हेतु आवेदन करने वाले 5 अग्रणी देश थे : संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अमेरिका, कुवैत तथा कतर। 31 दिसंबर, 2015 की स्थितिनुसार लगभग 6.33 करोड़ भारतीयों के पास वैध पासपोर्ट थे। वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान सभी प्रकार की पासपोर्ट सेवाओं से लगभग 2300 करोड़ रुपए का कुल राजस्व अर्जन की उम्मीद है। वित्त वर्ष 20215–16 में केंद्रीय पासपोर्ट संगठन को 902.70 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई।

पासपोर्ट सुपुर्दगी प्रणाली को सरल, त्वरित तथा सुरक्षित बनाने हेतु किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपायों में अग्रलिखित शामिल हैं। लोक शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाना, 17 भाषाओं में कार्य करने वाले राष्ट्रीय कॉल सेंटर की स्थापना, नियमित आधार पर पासपोर्ट पोर्टल को अद्यतन किया जाना, पासपोर्ट संबंधी सूचनाएं देने के लिए एक पासपोर्ट मोबाइल एप, आधार के ई–अधिप्रमाणन हेतु सुआईडीए (यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के साथ ऑनलाइन समेकन, पीएसपी प्रणाली के साथ ई–माइग्रेट प्रणाली को जोड़ा जाना, पासपोर्ट सेवा शिविरों, पासपोर्ट मेलों, अदालतों का आयोजन, एक लाख से भी अधिक साझा सेवा केंद्रों के विशाल नेटवर्क के जरिए पासपोर्ट सेवा संबंधी आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग, हज आवेदकों को उच्च प्राथमिकता दिया जाना, अपीलों तथा सूचना का अधिकार आवेदनों का समयबद्ध निपटारा, पासपोर्ट कार्यालयों में भौतिक अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार और पासपोर्ट पुस्तिकाओं में सुरक्षा संबंधी नई विशेषताएं शामिल करना आदि।

31 दिसंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार, प्रतिदिन जारी किए गए अपवाइन्टमेंट स्लॉटों की संख्या 60,000 से अधिक थी। पासपोर्ट सेवा केन्द्र में जाने के लिए अपवाइन्टमेंट अब देश भर के सभी पासपोर्ट कार्यालयों में 1–7 दिनों के भीतर उपलब्ध है। अखिल भारत आधार पर, 68 प्रतिशत सामान्य पासपोर्ट एक महीने के भीतर जारी किए गए, जिसमें पुलिस सत्यापन शामिल है। यदि पुलिस सत्यापन अवधि को छोड़ दिया जाए तो 38 प्रतिशत सामान्य पासपोर्ट 3 दिनों के भीतर, 74 प्रतिशत 7 दिनों के भीतर, 91 प्रतिशत 14 दिनों के भीतर और 94 प्रतिशत 21 दिनों के भीतर जारी कर दिए गए। तत्काल आवेदनों के मामले में, 34 प्रतिशत पासपोर्ट (आवेदन) जमा करने वाले दिन ही जारी कर दिए गए थे जबकि 65 प्रतिशत एक दिन के भीतर और 87 प्रतिशत 3 दिनों के भीतर जारी कर दिए गए थे। 397 पासपोर्ट मेले प्रतिबंधित (क्लोज्ड) सप्ताहांतों/अवकाशों के दौरान पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा आयोजित किए गए। 2.56 लाख से अधिक पासपोर्ट आवेदनों की सेवा विस्तारित कार्यावधि के दौरान दी गई। 124 पासपोर्ट सेवा कैम्पों में 51,000 से अधिक आवेदनों पर कार्रवाई की गई। मंत्रालय ने सामान्य दरों पर ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए सामान्य सेवा केन्द्रों की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को सक्षम बनाने हेतु नागरिकों के नागरिक ई–गवर्नेंस सेवाओं के साथ सहयोग किया। इस वर्ष के दौरान 1.2 लाख से अधिक आवेदकों ने इन सेवाओं का लाभ उठाया।

पासपोर्टों को समय से भेजे जाने में पुलिस सत्यापन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 731 में से 683 पुलिस जिले, पुलिस सत्यापन के 98.29 प्रतिशत भाग पर कार्रवाई करते हुए पुलिस सत्यापन के जिला पुलिस मुख्यालय (डीपीएचक्यू) मॉडल पर कार्य कर रहे हैं। पुलिस सत्यापन पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या का अखिल भारतीय औसत घटकर 34 (यह 2014 में 42 और 2013 में 49 था) रह गया। लगभग 61 प्रतिशत पुलिस सत्यापन 21 दिनों की इच्छित समय सीमा के भीतर पूरे कर लिए गए, जिससे पिछले वर्ष की तुलना में 15 दिनों और लगभग 24 प्रतिशत का सुधार देखने में आया। तेलंगाना का प्रदर्शन सबसे अच्छा है जहां पुलिस सत्यापन 8 दिनों में पूरे हो जाते हैं, जिसके बाद आंध्र प्रदेश (12 दिन), चंडीगढ़ (12 दिन), गोवा (12 दिन) और दिल्ली (14 दिन) का नम्बर आता है।

निम्नलिखित तरीके अपनाकर पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रियाओं को और उदार व लचीला बनाया गया हैः

- पासपोर्ट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए परित्यक्त/अनाथ बच्चों के मामले में जन्म प्रमाणपत्र स्वीकार करने को उदार बनाया गया।
- पासपोर्ट आवेदनों के लिए सरकारी पदाधिकारियों द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र की अपेक्षा को उदार बनाना
- पते के प्रमाण के रूप में पंजीकृत किराया करार की स्वीकारोक्ति
- स्व–प्रमाणित दस्तावेजों की स्वीकारोक्ति
- कार्मिक शक्ति के ईष्टतम उपयोग के लिए पासपोर्ट जारीकर्ता प्राधिकारियों द्वारा स्याही हस्ताक्षर की अनिवार्यता समाप्त करना
- पता और पहचान के प्रमाण के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित बैंकों द्वारा जारी किए गए फोटो पासबुकों के अलावा, अनुसूचित भारतीय बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जारी किए गए फोटो पासबुक की स्वीकार्यता।

24–26 जून, 2015 की अवधि के दौरान पासपोर्ट अधिकारियों का तीन दिवसीय सम्मेलन सम्पन्न हुआ। पासपोर्ट सेवा दिवस 24 जून को मनाया गया था। राष्ट्र के प्रति उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने और कर्तव्य के प्रति समर्पण के उच्च स्तर का प्रदर्शन करने के लिए इस अवसर पर 27 अधिकारियों को पासपोर्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया। पुलिस सत्यापन के लिए एक ''एम–पासपोर्ट पुलिस'' मोबाईल आवेदन प्रोटोटाइप की भी शुरूआत की गई।

भारतीय मिशनों/केन्द्रों में पासपोर्ट, वीज़ा, ओसीआई और पीआईओ आवेदनों के डिजिटलीकरण के माध्यम से ''इमेज रिट्रिएवल डाटाबेस के सृजन'' के लिए परियोजना चुनिंदा मिशनों/केन्द्रों में चलायी गई। 31 दिसंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार, लगभग 21 करोड़ पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है।

विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों ने वर्ष 2015 में कुल 4.79 मिलियन वीज़ा जारी किए। मिशनों/केन्द्रों द्वारा वीज़ा प्रदान किए जाने की प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है, जिसमें वीजा जारी करने की प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण और वीज़ा सेवाओं की आउटसोर्सिंग शामिल हैं, जिसे 2006 में प्रारंभ किया गया। वर्तमान में, वीजा संबंधी कार्यों को विदेश स्थित 67 मिशनों/केन्द्रों में आउटसोर्स किया गया है। 31 दिसंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार, प्रव्रजन, वीजा तथा विदेशी व्यक्तियों का पंजीकरण व ट्रैकिंग (आईवीएफआरटी) योजना विदेश स्थित 163 मिशनों/केन्द्रों में प्रारंभ की जा चुकी है, जिनमें से 77 मिशनों/केन्द्रों ने बायोमैट्रिक एनरॉलमेंट प्रक्रियाओं को कार्यान्वित कर दिया है।

जनवरी से दिसंबर, 2015 की अवधि के लिए, कांसुलर, पासपोर्ट और वीज़ा (सीपीवी) प्रभाग के सत्यापन प्रकोष्ठ ने 3,53,646 सामान्य तथा 1,74,878 वाणिज्यिक दस्तावेजों का सत्यापन किया और अपोस्तिल सदस्य देशों में उपयोग के लिए 4,36, 601 दस्तावेजों का अपोस्तलिकरण किया। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और गुवाहाटी स्थित विदश मंत्रालय के चार शाखा सचिवालयों में 34,724 दस्तावेजों को सत्यापित/एपोस्तलिकृत किया गया। कुछ प्रकार के कांसुलर दस्तावेजों का पंजीकरण विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय मिशनों/केन्द्रों द्वारा भी किया जाता है।

वर्ष 2015 में, अल्बानिया, क्यूबा, ग्वाटेमाला, मोरक्को, मोजाम्बिक, पोलैण्ड, श्री लंका, स्वीडन और ट्यूनिशिया के साथ वीज़ा से छूट संबंधी करारों पर हस्ताक्षर किए गए और द्विपक्षीय कांसुलर वार्ताएं आष्ट्रिया, ब्राजील, चीन, चेक गणराज्य, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, रूस तुर्कमेनिस्तान और अमरीका के साथ की गईं।

सुशासन संबंधी पहलकदमियों के भाग के रूप में, सीपीवी प्रभाग ने कांसुलर शिकायतों को दूर करने के लिए लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली 'मदद' की शुरूआत की और यह अनेक अन्य माड्यूलों के अलावा, अवैध आप्रवासियों से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय सत्यापन पोर्टल को अंतिम रूप दे रहा है।

प्रशासन, स्थापना तथा परियोजनाएं

वर्ष 2015–16 में, प्रशासन प्रभाग ने नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं को सुचारू बनाए रखने तथा ईष्टतम संसाधन प्रबंधन के उपायों पर विचार करना जारी रखा। मुख्यालय तथा विदेश दोनों स्थानों पर विभिन्न प्रकार की कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सक्षम तथा प्रेरणाप्राप्त कार्यबल बनाने के लिए, अनेक पहलकदमियां की हैं जैसे, विदेश मंत्रालय की ई–समीक्षा और बायोमैट्रिक्स उपस्थिति प्रणाली और बेहतर संवर्ग प्रबंधन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी साधन।

जुलाई, 2015 में सीपीडब्ल्यूडी द्वारा कराए गए हाल के एक सर्वेक्षण में, जवाहरलाल नेहरू भवन को सर्वोत्तम कार्यालय भवन मूल्यांकित किया गया है और इसे सम्पूर्ण स्वच्छता के लिए जांचे गए राजधानी के 49 सरकारी भवनों में से सर्वोत्तम स्वच्छ भारत अभियान (एसबीए) मूल्यांकन मिला है। 'स्वच्छ भारत अभियान' के अनुपालन में, पदाधिकारियों द्वारा स्वच्छता पर समुचित ध्यान देने की आवश्यकता को रेखांकित करने के उद्देश्य के साथ–साथ आस–पास के वातावरण को स्वच्छ बनाने में व्यक्तिगत तौर पर

शामिल होने के लिए, पिछले एक वर्ष के दौरान मंत्रालय के साथ–साथ विदेश स्थित मिशनों तथा केन्द्रों में अनेक कदम उठाए गए हैं।

परियोजनाओं के संबंध में इस अवधि की खास बात रही क्वालालंपुर में तोराना गेट को सफलतापूर्वक पूरा किया जाना और 23 नवंबर, 2015 को भारत और मलेशिया के प्रधानमंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से उसका उद्‌घाटन किया जाना।

सूचना का अधिकार और मुख्य लोक सूचना कार्यालय

वर्ष 2015 के दौरान, मंत्रालय ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के संपूर्ण कार्यान्वयन की दिशा में प्रयास करना जारी रखा। स्वप्रेरणा से खुलासा करने पर कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिशानिर्देशों के अनुरूप, सार्वजनिक डोमेन पर आरटीआई आवेदनों/अपीलों/उत्तरों तथा मासिक आरटीआई आंकड़ों को अपलोड करने की प्रक्रिया के कार्य को क्रियान्वित किया गया है। आरटीआई आवेदनों को ऑनलाइन स्वीकार करने और इनका निपटान करने की प्रक्रिया को उन्हें 17 अगस्त, 2015 से आरटीआई वेब पोर्टल के साथ जोड़कर विदेश स्थित सभी 183 मिशनों/केन्द्रों में क्रियान्वित किया गया है।

ई–गवर्नेंस और सूचना प्रौद्योगिकी

मंत्रालय तथा विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों में ई–क्रान्ति (डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का चौथा स्तंभ) की चार मिशन मोड परियोजनाएं नामतः ई–ऑफिस, ई–प्रापण, आईवीएफआरटी (प्रव्रजन, वीजा, विदेशी व्यक्तियों का पंजीकरण, ट्रैकिंग) और पासपोर्ट सेवा परियोजनाएं (पीएसपी) वर्तमान में क्रियान्वित हैं। विभिन्न स्तरों पर मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की मॉनिटरिंग के लिए एक रीयल–टाइम ऑनलाइन प्रणाली का क्रियान्वयन मुख्यालय तथा विदेश स्थित सभी मिशनों/केन्द्रों में मार्च, 2015 से ही किया जा रहा है। विदेश सचिव द्वारा प्रारंभ किया गया ऑनलाइन ई–पोलिटिकल क्लियरेंस पोर्टल (http://epolclearance.gov.in) 1 जनवरी, 2016 से प्रारंभ हो गया।

संसद तथा समन्वय प्रभाग

मंत्रालय का संसद अनुभाग संसद संबंधी इस मंत्रालय के सभी कार्यों के लिए संसद तथा नोडल केन्द्र से इंटरफेस/संपर्क रखता है। इस प्रभाग ने विदेश मामलों संबंधी परामर्शदात्री समिति की बैठकें आयोजित कीं और विदेश मामलों संबंधी संसदीय स्थायी समिति से संबंधित कार्यों तथा अन्य संसदीय समितियों के साथ मंत्रालय के संपर्क का समन्वय किया।

समन्वय प्रभाग ने मंत्रालय तथा गैर–सरकारी संगठनों सहित भारत सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों, और स्वायत्त निकायों व निजी संस्थाओं के बीच संपर्क/इंटरैक्शन कराया। इस प्रभाग ने मंत्रियों, चुने गए प्रतिनिधियों और सरकारी पदाधिकारियों के सरकारी/निजी विदेश दौरों के लिए राजनैतिक अनापत्ति संबंधी कार्यों को निपटाया। इसने विदेशी प्रतिभागियों की सदस्यता वाले सम्मेलनों/सेमिनारों/कार्यशालाओं के आयोजन, भारत में वैसी खेलकूद प्रतियोगिताएं, जिनमें विदेशी प्रतिभागियों को आमंत्रित किया गया था और विदेशों में खेलकूल के वैसे टूर्नामेंट, जिनमें भारतीय प्रतिभागियों को आमंत्रित किया गया था, विदेशी सैन्य उड़ानों तथा विदेशी नौसैनिक जहाजों के दौरे आदि के लिए भी अनापत्ति जारी करने संबंधी कार्य किए। कुल मिलाकर, लगभग 2912 अनापत्तियां अप्रैल, 2015 – 30 नवंबर, 2015 के दौरान जारी की गईं।

मंत्रालय के शिक्षा प्रभाग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालयों द्वारा इस मंत्रालय को आबंटित किए गए सीटों के लिए स्व–वित्तपोषण विदेशी छात्र योजना के तहत भारत में विभिन्न संस्थाओं में चिकित्सा स्नातक एवं शल्यचिकित्सा स्नातक (एमबीबीएस), दंत शल्य चिकित्सा में स्नातक (बीडीएस), इंजीनियरी में स्नातक (बीई), बी. फार्मेसी, और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए 57 मित्र पड़ोसी तथा विकासशील देशों से विदेशी छात्रों के चयन, नामांकन तथा प्रवेश संबंधी कार्य किये।

विदेश प्रचार तथा लोक राजनय प्रभाग

विदेश मंत्रालय के विदेश प्रचार तथा लोक राजनय प्रभाग (एक्सपीडी) ने अतिविशिष्ट व्यक्तियों की यात्राओं की प्रेस कवरेज को सुविधाजनक बनाकर, मीडिया के लिए नियमित तथा विशेष वक्तव्य/ब्रिफ्रिंग करके, प्रेस वक्तव्यों तथा संवादों एवं विज्ञप्तियों को समय से जारी करने के साथ–साथ भारतीय तथा विदेशी पत्रकारों के परिचय दौरों सहित विदेश नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मुद्दे पर भारत की स्थिति को प्रभावी ढंग से रखना जारी रखा। इसने सोशल मीडिया के मंचों पर मंत्रालय की डिजिटल उपस्थिति को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। आज, विदेश स्थित मिशनों तथा केन्द्रों को छोड़कर केवल मंत्रालय की ही कुल फॉलोविंग लगभग 3.8 मिलियन है। इसके परिणामस्वरूप, ट्विटर पर इसके पोस्टों/प्रकाशनों की औसत मासिक पहुंच 17.5 मिलियन को पार कर गई है, जबकि फेसबुक पर, मासिक पहुंच 15 मिलियन से अधिक हो गई है। विश्व भर में (95 प्रतिशत) लगभग 149 भारतीय मिशनों की फेसबुक पर उपस्थिति है। 90 से अधिक मिशन तथा केन्द्र भी ट्विटर पर सक्रिय हैं।

विदेश सेवा संस्थान

समीक्षाधीन वर्ष में जुलाई, 2013 में अंगीकार किए गए विदेश मंत्रालय के नए प्रशिक्षण स्वरूप/फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन का कार्य रहा। वर्ष 2012 की राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति की संस्तुतियों के बाद, प्रशिक्षण फ्रेमवर्क का उद्देश्य कर्तव्यों तथा कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्षमता तथा कौशल का विकास करके प्रशिक्षण को कार्यात्मक अपेक्षाओं के लिए सीधे तौर पर संगत बनाना है। इसका अंतिम उद्देश्य सेवा प्रदायगी में सुधार करना है। किसी व्यक्ति के सेवाकाल में विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाया जाना है।

उपर्युक्त समर्थन/मैनडेट के साथ, विदेश सेवा संस्थान ने भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विषय–वस्तु और तरीकों दोनों की समीक्षा तथा संशोधन का कार्य किया और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण के नए स्तरों को प्रारंभ किया। आईएफएस बी समूह के लिए प्रशिक्षण को भी प्रशिक्षण में नए तत्वों को शामिल करके नवीकृत किया गया और पीएस/पीपीएस/एसपीपीएस, एमटीएस/साइफर, विदेश स्थित मिशनों में तैनात स्थानीय भर्ती वाले स्टॉफ जैसे पहले शामिल न की गई श्रेणियों को शामिल करके गहन बनाया गया। पहली बार मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर आए स्टॉफ को उन्मुखीकरण प्रशिक्षण भी दिया गया।

उनके प्रशिक्षण कैप्सूल में सरकार से हाल में प्राप्त राज्य विशेषज्ञता, मेक इन इंडिया अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, प्रपत्रों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण इत्यादि से संबंधित दिशा–निर्देशों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा, ऑनलाइन मंच वेबिनार के माध्यम से विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों में तैनात अधिकारियों/पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सामग्री को उपलब्ध बनाया गया है। दूर–दराज के प्रतिभागियों द्वारा केवल कंप्यूटर प्रस्तुतियों को सुना और देखा ही नहीं जा सकता है, बल्कि उनके माइक्रोफोन पर बोलकर तथा उनके वेबकैमों पर उनकी प्रस्तुतियों को प्रदर्शित करके चर्चा में भाग भी लिया जा सकता है। प्रशिक्षण के तरीकों में एक और नवीन तरीका अधिकारियों के नियमित कार्यों में आनेवाली बाधा को न्यूनतम करना सुनिश्चित करते हुए अत्यंत लचीले दो दिन प्रति सप्ताह की हिसाब से प्रशिक्षण सामग्री दिया जाना था। प्रशिक्षुओं द्वारा सत्र समन्वय की शुरूआत, जिसमें एक अधिकारी अथवा अधिकारियों के समूह ने किसी विशेष सत्र पर विस्तृत कागजात तैयार किया हो, के जरिए प्रशिक्षुओं द्वारा अधिकतम भागीदारी और संलग्नता सुनिश्चित किया जाना गया। कुल मिलाकर, एफएसआई ने प्रशिक्षुओं के लक्ष्य समूह से परामर्श करके तथा उनकी कार्यात्मक अपेक्षाओं के लिए प्रशिक्षण को अधिक संगत बनाने के लिए उनसे प्रतिक्रिया/जानकारी प्राप्त करके एक भागीदार–केन्द्रिक दृष्टिकोण अपनाया।

नालंदा विश्वविद्यालय

नालंदा विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान के साथ उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थान के रूप में अपनी यात्रा में इस वर्ष के दौरान अच्छी प्रगति की। राजगीर, बिहार में पट्टे पर लिए गए परिसर से ऐतिहासिक अध्ययन स्कूल, पारिस्थितिकी स्कूल तथा पर्यावरण अध्ययन में अध्ययन कार्य सितंबर, 2014 में प्रारंभ हुआ और शैक्षिक वर्ष 2015–16 के दौरान छात्रों की कुल संख्या 62 तक पहुंच गई है। अब तक, कुल 17 ईएएस और गैर–ईएएस देशों ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के कानूनों/विनियमों संबंधी अधिसूचना की प्रक्रिया 10 जून, 2015 को विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश की अधिसूचना के साथ आगे बढ़ाया गया था।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन तथा विदेशों में हिन्दी का प्रचार–प्रसार

मंत्रालय के पास हमारे मिशनों/केन्द्रों की सहभागिता से विदेश में हिन्दी का प्रचार–प्रसार करने तथा इसे बढ़ावा देने के लिए एक सुस्थापित कार्यक्रम है। मंत्रालय हिन्दी से संबंधित कार्यकलापों के लिए विदेश स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से शैक्षिक संस्थाओं तथा विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों को सहयोग भी देता है। 10वें विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन भोपाल, मध्य प्रदेश में 10–12 सितंबर, 2015 को मंत्रालय द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया। इस सम्मेलन, जिसमें विदेशी शिष्टमंडलों सहित बड़ी संख्या में शिष्टमंडल सदस्यों ने भाग लिया, के दौरान बारह विषयों पर व्यापक विचार–विमर्श करते हुए मुख्य विषय ''हिन्दी जगत – विस्तार एवं संभावनाएं'' पर विशेष बल दिया गया। भारत और मॉरीशस के बीच एक द्विपक्षीय करार के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए, विश्व हिन्दी सचिवालय की स्थापना मॉरीशस में की गई है। मंत्रालय केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा में हिन्दी पढ़ने के लिए विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने से संबंधित कार्यों का समन्वय करता है। भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को मंत्रालय द्वारा उच्च प्राथमिकता दी जाती है।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर)

वर्ष 2015 में, आईसीसीआर ने विदेशों में भारत की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यकलाप किए। अपने शैक्षिक तथा बौद्धिक कार्यकलापों के भाग के रूप में, आईसीसीआर ने अपने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत भारत में अध्ययन के लिए 3339 स्लॉट प्रदान किए। कल्याण संबंधी उपायों के रूप में, आईसीसीआर ने मई–जून, 2015 के दौरान, 12 ग्रीष्म शिविर आयोजित किए और क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ–साथ विदेश

स्थित कुछ मिशनों में नवंबर, 2015 में अंतर्राष्ट्रीय छात्र महोत्सव मनाया।

आईसीसीआर के पास विदेश स्थित विश्वविद्यालयों में भाषा तथा भारतीय अध्ययनों के अन्य पहलुओं पर 70 प्रचालनात्मक पीठ थे। इसके अलावा, आईसीसीआर भारत में भी दो पीठ नामतः दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क/दक्षेस) पीठ और नेल्सन मंडेला पीठ भी संचालित करता है। आईसीसीआर ने ''अंतर्राष्ट्रीय भारत–विद्या विशेषज्ञ सम्मेलन, 2015'', जिसका उद्घाटन भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा राष्ट्रपति भवन में किया गया था, सहित 06 सम्मेलन/सेमिनार आयोजित किए।

परिषद ने विभिन्न देशों को राष्ट्रीय नेताओं की आवक्ष प्रतिमाएं भेजीं।

विदेशों में आईसीसीआर के 35 पूर्ण कार्यरत सांस्कृतिक केन्द्रों और एक उपकेन्द्र ने नृत्य, संगीत, योग, हिन्दी, संवाद तथा प्रदर्शनियों सहित विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों के माध्यम से विदेशों में भारत की मृदु शक्ति को बढ़ावा दिया।

21 जून, 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, परिषद ने योग का ज्ञान बांटने के लिए विभिन्न देशों में भारत आस्थानी 30 योग शिक्षकों की तैनाती की और अपनी हिन्दी पत्रिका 'गगनांचल' का विशेष अंक प्रकाशित किया।

आईसीसीआर ने विदेशों में 87 भारतीय सांस्कृतिक समूहों/कलाकारों को प्रायोजित किया जिन्होंने लगभग 80 देशों में कार्यक्रम प्रस्तुत किए। भारत के एक महोत्सव 'नमस्ते रूस' का उद्घाटन मास्को में 10 मई, 2015 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा अपने रूसी समकक्ष के साथ किया गया।

इसने आईसीसीआर के विभिन्न प्रतिष्ठित महोत्सवों सहित भारत में 28 विदेशी समूहों के प्रस्तुत कार्यक्रम आयोजित किए।

इसने विभिन्न देशों में प्रदर्शन हेतु 11 प्रदर्शनियों को भेजा, जिनमें से 10 इसके स्वयं के संग्रह थे और शंघाई, चीन में 'मैत्री – ?' नामक द्वितीय भारत–चीन महिला कलाकारों के मुकाम का आयोजन किया।

आईसीसीआर ने विचारों के आदान–प्रदान के लिए भारत का दौरा करने हेतु विभिन्न देशों से प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों तथा शिक्षाविदों को आमंत्रित किया। इसने कुछ विदेशी विशेषज्ञों के माध्यम से भारत के अनुसंधान में भी सहयोग किया। भोपाल में सितंबर, 2015 में आयोजित 10वें विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर, 'गगनान्चल' के एक विशेष अंक और 'काव्य रसधारा' नामक एक समृति पुस्तक का प्रकाशन किया गया।

हिन्दी विद्वान फादर कामिल बुल्के (बेल्जियन नागरिक), पर 'फादर कामिल बुल्केः भारतीयता का प्रकाश पुंज' नामक एक किताब का प्रकाशन किया गया।

आईसीसीआर ने विभिन्न देशों में वितरण के लिए हिन्दी, अंग्रेजी, अरबी, फ्रांसीसी और स्पैनिश भाषाओं में पत्रिकाएं निकालीं।

भारतीय विश्व कार्य परिषद

भारतीय विश्व कार्य परिषद (आईसीडब्ल्यूए) ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमरीका, लातिन अमरीका में राजनैतिक तथा आर्थिक विकास पर अध्ययन तथा अनुसंधान पर उच्च प्राथमिकता देना जारी रखा और व्यापक वैश्विक भू–रणनीतिक स्थितियों का विश्लेषण किया। इनके निष्कर्षों का सप्रु हाउस पेपर्स, मुद्दे का सार, नीति सार और लेख/व्यूप्वाइंट्स के रूप में प्रचार–प्रसार किया गया, जिन्हें आईसीडब्ल्यूए की वेबसाइट पर डाला गया। इसके अलावा, आईसीडब्ल्यूए ने अपने शैक्षिक निष्कर्षों का हिन्दी में अनुवाद कराना तथा इन्हें अपनी वेबसाइट पर डालने का कार्य प्रारंभ कर दिया। आईसीडब्ल्यूए ने आम नागरिकों के लिए अपना पुस्तकालय खोल दिया है और इसकी सदस्यता के नियमों को आसान बनाया गया है। आईसीडब्लयूए ने बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों, व्याख्यानों, सम्मेलनों तथा संपर्क कार्यकलापों का भी संचालन किया।

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान तथा सूचना प्रणाली

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान तथा सूचना प्रणाली (आरआईएस) ने वैश्विक तथा क्षेत्रीय आर्थिक मुद्दों पर विकासशील देशों के बीच प्रभावी नीतिगत वार्ता तथा क्षमता निर्माण का पोषण करने के उद्देश्य से, इस अवधि के दौरान अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें शामिल हैः भारत–मध्य एशिया आर्थिक सहयोग, दक्षिण एशिया विकास तथा सहयोग रिपोर्ट 2015 का प्रारंभ; विचारकों के आसियान–भारत नेटवर्क की चौथी गोलमेज बैठक; हिंद महासागर परिधि संगठन (आईओआरए); नीली अर्थव्यवस्था संवाद; विकास हेतु वित्तपोषण पर परामर्श; आसियान–भारत प्रख्यात व्यक्तियों के व्याख्यान; आसियान–भारत सांस्कृतिक संपर्कों पर सम्मेलन; विकास तथा वर्ष 2015 के बाद के एजेंडे हेतु वित्तपोषण, भारत–अफ्रीका भागीदारी पर परामर्श; सतत विकास लक्ष्यों पर परामर्श (एसडीजी); भारत–अफ्रीका भागीदारी; भविष्य के दिशानिर्देश; प्रशांत–पार भागीदारी पर पैनल चर्चा; आसियान–भारत पर गोलमेज बैठक : समेकन और विकास; आसियान–भारत विकास तथा सहयोग रिपोर्ट 2015 जारी करना; महामान्या मदाम एलेन जॉनसन सिरलेफ, माननीय राष्ट्रपति, लाइबेरिया गणराज्य द्वारा भारत–अफ्रीका भागीदारी तथा सतत विकास पर विशेष

संबोधन; डब्ल्यूटीओ तथा एसडीजी पर सम्मेलन; नैरोबी मंत्रिस्तरीय बैठक के समक्ष मुद्दे इत्यादि; आरआईएस ने आईटीईसी के तहत दो क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए, जिनके केन्द्र बिंदु 'दक्षिण–दक्षिण सहयोग अधिगम' और व्यापार नीति तथा विश्लेषण थे। इस संस्थान ने अनेक प्रकाशन निकाले, जिनमें अन्य के साथ–साथ दक्षिण एशिया विकास तथा सहयोग रिपोर्ट, 2015; हिन्द महासागर में नीली अर्थव्यवस्था की संभावनाएं, सतत विकास के लिए भारत–अफ्रीका भागीदारी, आसियान–भारत विकास तथा सहयोग रिपोर्ट, 2015 शामिल हैं।

वित्त तथा बजट

वर्ष 2015–16 के लिए विदेश मंत्रालय के लिए कुल बजट परिव्यय 14966.83 करोड़ रूपए था, जो वर्ष 2014–15 के लिए आबंटित बजट (14730.39 करोड़ रूपए) से 1.67 प्रतिशत अधिक था। इस बजट का एक बड़ा भाग योजना तथा गैर–योजना दोनों के माध्यम से अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय के बजट का योजना घटक अवसंरचना, जलविद्युत शक्ति परियोजनाएं, कृषि, उद्योग आदि के क्षेत्रों में अनेक बड़ी विकास परियोजनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो भारत के पड़ोसी देशों में चलाई जाती है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में भारत के तकनीकी सहयोग कार्यक्रमों के प्रमुख लाभार्थियों में भूटान (1200 करोड़ रूपए), बांग्लादेश (250 करोड़ रूपए), अफगानिस्तान (550 करोड़ रूपए), नेपाल (420 करोड़ रूपए), म्यामार (120 करोड़ रूपए) और अफ्रीकी देशों (200 करोड़ रूपए) शामिल हैं। कुछ अन्य लाभार्थियों में मालदीव, मंगोलिया, लातिन अमरीका, यूरेशिया तथा अन्य क्षेत्रों के देश शामिल हैं।

■ ■

भारत के पड़ोसी देश

1

अफगानिस्तान

भारत और अफगानिस्तान के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंध और एक मजबूत रणनीतिक भागीदारी है जिसे अक्तूबर 2011 में राष्ट्रपति हामिद करजई की भारत यात्रा के दौरान रणनीतिक भागीदारी करार पर हस्ताक्षर करके संस्थागत बनाया गया। इस करार के राजनैतिक एवं सुरक्षा सहयोग, कारोबार एवं आर्थिक सहयोग, क्षमता विकास तथा शिक्षा एवं सामाजिक तथा लोगों के बीच आपसी संबंध सहित व्यापक क्षेत्र शामिल हैं। यह हमारे ऐतिहासिक तथा सभ्यतामूलक संबंधों पर आधारित हैं और पिछले दो दशकों में अफगानिस्तान में आर्थिक विकास तथा पुनर्निर्माण प्रक्रिया में भारत की भूमिका से यह प्रगाढ़ हुए हैं। भारत ने अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा तथा स्थायित्व लाने के लिए एक साधन के रूप में किए जा रहे पुनर्निर्माण प्रयासों में अफगानिस्तान की मदद करने का प्रयास किया है।

अफगानिस्तान के लिए भारत के द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम में 2 बिलियन अमरीकी डालर की प्रतिबद्ध राशि शामिल है। भारत का सहायता कार्यक्रम समूचे अफगानिस्तान में चल रहा है और इसके अंतर्गत लगभग सभी आर्थिक तथा सामाजिक विकास कार्यकलाप शामिल हैं। संभारतंत्रीय तथा सुरक्षा संबंधी चुनौतीपूर्ण स्थिति के बावजूद प्रमुख अवसंरचनात्मक परियोजनाएं पूरी की गईं और अफगानिस्तान सरकार को सौंप दी गई जिनमें– निमरोज प्रांत में जारंज से डेलाराम तक 218 कि.मी. लम्बी सड़क का निर्माण और चिमताला सब–स्टेशन सहित पुल–ए–खुमरी से काबुल तक 220 कि.वो. पारेषण लाइन का निर्माण कार्य शामिल है। वर्ष के दौरान, दोषी स्थित सब–स्टेशन को जुलाई माह में चालू किया गया और चारिकर सब–स्टेशन में एक विद्युत ट्रांसफॉर्मर को नवम्बर माह में चालू किया गया। हेरात प्रांत में सलमा बांध का निर्माण कार्य सही गति से चल रहा है और उम्मीद है कि यह शीघ्र ही पूरा हो जाएगा।

इस अवधि के दौरान भारत और अफगानिस्तान के बीच प्रमुख उच्च स्तरीय आदान–प्रदान/बातचीत का ब्यौरा इस प्रकार हैः–

- प्रधानमंत्री ने 25 दिसम्बर, 2015 को काबुल की यात्रा की जहां उन्होंने राष्ट्रपति गनी के साथ मिलकर भारत के सहयोग से निर्मित संसद भवन अफगानिस्तान को सौंपा। प्रधानमंत्री ने वहां के सांसदों को सम्बोधित किया और अफगानिस्तान के साथ खड़े रहने की भारत की प्रतिबद्धता दुहराई। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति अशरफ गनी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अब्दुल्ला अब्दुल्ला के साथ विचार–विमर्श किया और पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात की।
- विदेश मंत्री ने हार्ट ऑफ एशिया अफगानिस्तान को क्षेत्रीय सहयोग हेतु इस्तानबुल प्रक्रिया से संबंधित पांचवें मंत्रिस्तरीय सम्मलेन में भाग लेने के लिए 8 तथा 9 दिसम्ब 2015 को इस्लामाबाद की यात्रा की। सम्मेलन से अलग विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति गनी से मुलाकात भी की।
- राष्ट्रपति के निमंत्रण पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने 27–29 अप्रैल, 2015 तक भारत की राजकीय यात्रा की (जो अफगान के राष्ट्रपति के रूप में उनकी पहली भारत यात्रा थी)। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति तथा उप–राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की और प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के साथ विचार–विमर्श किया तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एन एस ए) के साथ मुलाकात की।
- अफगान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हनीफ अत्मार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकरा वार्ता के लिए 8 तथा 9 नवम्बर, 2015 को भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान, उन्होंने रक्षा मंत्री तथा विदेश सचिव से भी मुलाकात की।
- अफगान के उप विदेश मंत्री हेकमत करजई ने विदेश कार्यालय परामर्श के लिए 16–20 नवम्बर तक भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान, अफगान के उप–विदेश मंत्री उप–राष्ट्रपति, विदेश मंत्री तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) से मिले; विदेश सचिव के साथ प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्ता के अलावा उन्होंने गृह सचिव, सचिव (एम एवं ई आर), विदेश मंत्रालय, और महानिदेशक, आई सी सी आर से भी मुलाकात की।

भारत हार्ट ऑफ एशिया–अफगानिस्तान को क्षेत्रीय सहयोग दिए जाने हेतु इस्तानबुल प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कर रहा है।

अफगान के राष्ट्रपति महामहिम अशरफ गनी प्रधानमंत्री की अगवानी करते हुए

विदेश मंत्री इस्लामाबाद, पाकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए।

विदेश मंत्री ने इस्लामाबाद में 9 दिसंबर, 2015 को आयोजित हार्ट ऑफ एशिया के 5वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत वर्ष 2016 की अंतिम तिमाही में यहां आयोजित होने वाले हार्ट ऑफ एशिया के अगले (छठे) मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत 'व्यापार, वाणिज्य तथा निवेश अवसरों' से जुड़े वह हार्ट ऑफ एशिया प्रक्रिया के तहत पांच अन्य विश्वास सृजन उपायों (सी बी एम) में भी हिस्सेदारी करेगा।

बांग्लादेश

लोगों के बीच व्यापक आपसी मेलजोल व बातचीत के साथ–साथ बांग्लादेशी नेतृत्व के साथ विभिन्न स्तरों पर निरंतर एवं परस्पर लाभकारी वार्ता के कारण भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए हैं। वर्ष 2015 में द्विपक्षीय सहयोग के तहत करारों, प्रोतोकॉलों तथा समझौता ज्ञापनों को लागू करने और साथ ही जून 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान सम्मत पहलों पर ध्यान दिया गया है।

इस वर्ष के महत्वपूर्ण घटना में शामिल हैं, मई 2015 में भारत–बांग्लादेश भू–सीमा करार, 1974 तथा वर्ष 2011 के इसके प्रोतोकॉल को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से संविधान (सौंवा संशोधन) विधेयक 2015 को सर्वसम्मिति से पारित करना जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच भू–सीमा करार के अनुसमर्थन हेतु मार्ग प्रशस्त हुआ। यह कार्य कई दशकों से लंबित था। 31 जुलाई, 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच एक–दूसरे देशों में अवस्थित इन्कलेवों का आदान–प्रदान किया गया। भू–सीमा से संबंधित लगभग सभी स्पष्ट मानचित्रों पर पूर्णाधिकारी स्तर पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इनका आदान–प्रदान किया गया है। इन इन्कलेवों में रहने वाले निवासियों में से बांग्लादेश व्यवस्थित भारतीय इन्कलेवों के 920 व्यक्तियों ने अपनी भारतीय नागरिकता बनाए रखने का विकल्प दिया और वे 30 नवंबर, 2015 को बांग्लादेश से भारत आ गए। भारत में अवस्थित बांग्लादेशी इन्कलेवों के किसी भी निवासी ने बांग्लादेश वापस जाने का विकल्प नहीं दिया।

सुरक्षा सहयोग क्षेत्र में दोनों देशों के बीच अद्वितीय सहयोग किया जा रहा है। बांग्लादेशी नेतृत्व ने सर्वोच्च स्तर पर आश्वासन दिया है कि उनकी भूमि का दुरूपयोग भारत को हानि पहुँचाने वाले किसी तत्व द्वारा किए जाने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा सहयोग के लिए अपेक्षित सभी समावेशी करारों पर दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और इनका अनुसमर्थन भी किया गया है। वर्ष 2011 से ही दोनों देशों के बीच समन्वित सीमा प्रबंधन योजना (सीवीएमपी) लागू है। सीवीएमपी का उद्देश्य दोनों देशों के सीमा बलों के प्रयासों को समेकित करना है ताकि सीमा पार से चलाई जा रही गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके और भारत–बांग्लादेश सीमा पर शांति तथा अमन–चैन कायम रखा जा सके। सुरक्षा मामलों पर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें नियमित रूप से की जाती रही हैं। रक्षा बलों के बीच किए जाने वाले नियमित आदान–प्रदान के तहत बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल अबु बेलाल मुहम्मद सफ्युल हक ने 8 से 11 सितम्बर, 2015 तक भारत का दौरा किया जबकि बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल मुहम्मद फरीद हबीब 2–5 नवंबर, 2015 तक भारत यात्रा पर रहे। भारत के नौसेना प्रमुख ने बांग्लादेश का दौरा किया। भारत के सेना प्रमुख जनरल दलवीर सिंह ने बांग्लादेश सैन्य अकादमी के पासिंग आउट परेड की समीक्षा करने के लिए जून, 2015 में बांग्लादेश का दौरा किया। दोनों देशों के सेना स्टाफ के बीच पांचवी बैठक का आयोजन अक्तूबर 2015 में बांग्लादेश में किया गया। दोनों देशों के नौसेना स्टाफ की तीसरी बैठक 29–30 जुलाई, 2015 तक नई दिल्ली में हुई। तटरक्षकों के बीच महानिदेशक स्तर की पहली बैठक का आयोजन अप्रैल 2015 में नई दिल्ली में किया गया।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री जी ने 6–7 जून, 2015 तक बांग्लादेश का दौरा किया। यह प्रधानमंत्री का बांग्लादेश का पहला दौरा था। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति श्री मुहम्मद अब्दुल हमीद से मुलाकात की और प्रधानमंत्री हसीना के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष रौशन इरसाद बीएनपी की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया तथा विभिन्न बामपंथी दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान बाइस (22) करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए और उनका आदान–प्रदान किया गया जिनमें निम्नलिखित शामिल हैः 1974 के भू–सीमा करार तथा 2011 के इसके प्रोतोकॉल के अनुसमर्थन दस्तावेजों का आदान–प्रदान; 1974 भूसीमा करार तथा 2011 के इसके प्रोतोकॉल के कार्यान्वयन के तौर तरीकों पर दोनों विदेश सचिवों के बीच पत्रों का आदान–प्रदान; तटीय नौवहन से सम्बद्ध करार; द्विपक्षीय व्यापार करार, अन्तर देशीय जलमार्गों से संबद्ध प्रोतोकाल, पारगमन एवं व्यापार तथा सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम का नवीनीकरण; बांग्लादेश में भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना से संबद्ध समझौता ज्ञापन; बांग्लादेश को दो बिलियन अमरीकी डॉलर का नया भारतीय ऋण दिये जाने से संबद्ध समझौता ज्ञापन; मानव तस्करी की रोकथाम से संबद्ध समझौता ज्ञापन; जाली मुद्रा की तस्करी एवं परिचालन की रोकथाम से संबद्ध से समझौता ज्ञापन; बंगाल की खाडी तथा हिंद महासागर क्षेत्र में नीली अर्थव्यवस्था एवं समुद्री सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन इत्यादि। बांग्लादेश सरकार ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपयी को बांग्लादेश मुक्त युद्ध में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 'बांग्लादेश मुक्ति युद्ध सम्मान' से नवाजा।

भारत से हुई अन्य उच्चस्तरीय यात्राओं में शामिल हैं जनसंख्या एवं विकास भागीदारों की वार्षिक बोर्ड बैठक में भाग लेने के लिए 18–21 नवंबर, 2015 तक माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

भारत और बंगलादेश ने भू–सीमा करार को लागू किए जाने हेतू अनुसमर्थन करार पर हस्ताक्षर किए। फोटो में भारत और बंगलादेश के विदेश सचिव, दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में, भारत–बंगलादेश भू–सीमा करार–1974 तथा प्रोटोकॉल–2011 के अनुसमर्थन दस्तावेजों का आदान–प्रदान कर रहे हैं।

मंत्री श्री जेपी नड्डा की यात्रा। त्रिपुरा के माननीय राज्य पाल श्री तथागत राय ने 9–13 दिसम्बर, 2015 तक बांग्लादेश का दौरा किया। माननीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज्य तथा पेय जल एवं स्वच्छता मंत्री श्री चौधरी विरेन्द्र सिंह ने 9–13 दिसम्बर, 2015 तक बांग्लादेश का दौरा किया। इस यात्रा का उद्देश्य स्वच्छता पर दक्षिण एशियाई सम्मेलन में भाग लेना था। माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने 30–31 जनवरी, 2016 तक दक्षिण एशियाई सभापतियों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ढाका का दौरा किया।

बांग्लादेश से प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की धर्म पत्नी श्रीमती सुब्रा मुखर्जी की अन्तेष्ठ में भाग लेने के लिए 19 अगस्त, 2015 को नई दिल्ली का दौरा किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भू–सीमा करार के कार्यान्वयन में हुई प्रगति तथा क्षेत्रीय सम्पर्क सुविधा बढ़ाने के अन्य उपायों पर चर्चा की।

बांगलादेश से भारत में हुई अन्य उच्चस्तरीय यात्राओं में शामिल हैं। बांग्लादेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री जाहिद मलेक की 8 अप्रैल, 2015 की नई दिल्ली यात्रा जिसके दौरान उन्होंने सार्क स्वास्थ्य मंत्रियों की पांचवीं बैठक में भाग लिया। लोक प्रशासन राज्य मंत्री सुश्री इस्मत आरा सादिक ने 4–8 मई, 2015 तक नई दिल्ली और मसूरी का दौरा किया। तथा उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में बांग्लादेशी सिविल सेवकों के सेवा कालीन प्रशिक्षण के एक बैच का उद्घाटन किया। सड़क परिवहन एवं पुल मंत्री श्री अब्दुल कादर ने 16–18 मई, 2015 तक नई दिल्ली का दौरा किया। विदेश राज्य मंत्री शहरयार आलम ने भारत–बांग्लादेश मैत्री वार्ता के छठें दौर में भाग लेने के लिए 22–24 मई, 2015 को नई दिल्ली का दौरा किया। माननीय आपदा प्रबंधन एवं राहत मंत्री श्री मफजल हुसैन चौधरी माया ने दूसरी क्षेत्रीय समेकित बहु जोखिम पूर्व चेतावनी प्रणाली मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए 9–12 जुलाई, 2015 तक नई दिल्ली का दौरा किया। माननीय युवा एवं खेल राज्य मंत्री श्री बीरन सिकदर ने एशियाई क्षेत्रीय राष्ट्र मंडल युवा मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए 28 जुलाई से 6 अगस्त 2015 तक नई दिल्ली का दौरा किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मुहम्मद नसीब ने स्वास्थ्य से संबंधित एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए 26 अगस्त, 2015 को नई दिल्ली का दौरा किया। वाणिज्य मंत्री श्री तोफेल अहमद ने दक्षिण एशियाई आर्थिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए 28 सितम्बर, 2015 को नई दिल्ली का दौरा किया। बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री श्री अनीसुल इस्लाम महमूद ने सीआईआई

द्वारा जल नवाचारों पर आयोजित सम्मेलन में भाग लेने के लिए 14–17 नवंबर, 2015 तक नई दिल्ली का दौरा किया।

दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय में सार्क चार्टर दिवस के आयोजन में भाग लेने के लिए बांग्लादेश के जल संसाधन नदी विकास तथा गंगा कायाकल्प मंत्री डॉ. गौहर रिजनी तथा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के अंतर्राष्ट्रीय संबंध सलाहकार ने 7–9 दिसम्बर, 2015 को नई दिल्ली की यात्रा की थी। बांग्लादेश के स्थानीय सरकार, ग्रामीण विकास तथा सहयोग मंत्री श्री खंडाकर मोशर्रफ हुसैन ने जिविकोपार्जन एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 9–12 दिसम्बर, 2015 तक नई दिल्ली की यात्रा की थी। बांग्लादेश के खाद्य मंत्री श्री कमरूल इस्लाम ने 'विजय दिवस' आयोजन में भाग लेने के लिए 14–17 दिसंबर, 2015 तक कोलकाता की यात्रा की थी। अन्य महत्वपूर्ण यात्राओं में बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश श्री सुरेंद्र कुमार सिन्हा की 4–9 अक्तूबर, 2015 तक, बांग्लादेश के शिपिंग सचिव की 16–18 नवंबर, 2015 तक तथा ऊर्जा सचिव की 27 नवंबर, 2015 को भारत यात्रा शामिल है। बांग्लादेश के विदेश सचिव ने 1–2 फरवरी, 2016 तक भारत की यात्रा की।

भारत एवं बांग्लादेश 54 नदियों को आपस में साझा करते हैं तथा कम पानी के मौसम (1 जनवरी से 31 मई तक) के दौरान गंगा नदी के पानी को साझा करने के लिए आपस में करार किया है। दोनों देशों में द्विपक्षीय संयुक्त नदी समिति (जेआरसी) है, इसे दोनों देशों के बीच समान नदी प्रणाली से अधिकतम संपर्क बनाए रखने, बाढ़ नियंत्रण कार्य के निरूपण, अग्रिम बाढ़ चेतावनी पर प्रस्तावों के निरूपण, बाढ़ की भविष्यवाणी एवं चक्रवात चेतावनी तथा बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई परियोजनाओं के अध्ययन के लिए वर्ष 1972 में स्थापित किया गया था। 18 सितंबर, 2015 को नई दिल्ली में संयुक्त नदी समिति की तकनीकी समिति की 61वीं बैठक का आयोजन किया गया था। संयुक्त नदी समिति की 38वीं बैठक 2016 में आयोजित किए जाने की संभावना है।

व्यापार, अंतर्देशीय जलमार्ग आवागमन, तटीय शिपिंग, ऊर्जा इत्यादि पर विचार किए जाने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों की कई बैठके आयोजित की गई थी। ये उपयोगी बैठकें थी तथा इसने स्वतः विस्तार के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार करार को पांच वर्षों के लिए नवीकरण पीआईडब्ल्यूटीटी का भी अगले पांच वर्षों के लिए नवीकरण, तटीय जहाजरानी करार के एसओपी पर हस्ताक्षर, फेरी तथा क्रूज जलयानों के आवागमन पर समझौता ज्ञापन की शुरूआत की अनुमति दी गई थी। वर्ष 2015 में व्यापार, वाणिज्य तथा संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग जारी रहा था। विद्युत पर 10वीं जेएससी/जेडब्ल्यूजी का 27 नवंबर, 2015 को आयोजन किया गया था। 28–29 नवंबर, 2015 को गोवा में संयुक्त कार्य दल जेडब्ल्यूजी की दूसरी बैठक आयोजित की गई थी। दोनों देशों के बीच मानव तस्करी निरोध पर समझौता ज्ञापन, तस्करी तथा नकली मुद्रा के परिचालन निरोध पर समझौता ज्ञापन तथा दोनों देशों के तटरक्षकों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन जैसे सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत तथा बांग्लादेश के सीमावर्ती जिलों के डीसी/डीएमएस के बीच नवंबर 2015 से जनवरी 2016 तक बांग्लादेश में बैठकों का दूसरा चरण आयोजित किया गया था।

भारत ने बांग्लादेश में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के विकास हेतु 2 बिलियन अमरीकी डॉलर की दूसरी ऋण–श्रृंखला का विस्तार किया है। यह भारत द्वारा किए गए 862 मिलियन अमरीकी डॉलर की पहली ऋण–श्रृंखला के अतिरिक्त है। वर्ष 2015 में 200 मिलियन अमरीकी डॉलर का सहायता अनुदान निर्मुक्त किया गया था। बांग्लादेश में लघु विकास परियोजनाओं के निष्पादन हेतु एसडीपी परियोजनाओं के लिए बजट को 60 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया था। बांग्लादेश में 14 अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 2 बिलियन अमरीकी डॉलर की दूसरी ऋण–श्रृंखला पर हस्ताक्षर को अंतिम रूप दिए जाने के लिए 14–16 सितंबर, 2015 तक नई दिल्ली में 8वीं ऋण–श्रृंखला समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था।

सतर्कता और पारगमन, जल संसाधन प्रबंधन तथा विद्युत/जल–विद्युत से संबंधित द्वितीय उप–क्षेत्रीय संयुक्त कार्यदल की बैठक 19–20 जनवरी, 2016 को ढाका में आयोजित हुई। इन बैठकों में जल प्रबंधन में सहयोग से संबंधित विभिन्न तरीकों का पता लगाने और संपर्कता को बढ़ाने के संबंध में उपायों पर चर्चा हुई। जून, 2015 में बीबीआईएन मोटर गाड़ी करार पर हस्ताक्षर करना उप क्षेत्रीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था।

बांग्लादेश भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) का एक महत्वपूर्ण सहभागी देश है तथा आईटीईसी कार्यक्रम के तहत बांग्लादेश से कई प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का लाभ उठाया है। इसके अतिरिक्त, बांग्लादेशी अशैक्षिक कर्मचारियों के लिए मध्याह्न–सेवा प्रशिक्षण हेतु विशेष पाठ्यक्रम प्रक्रियाधीन है। इस वर्ष बांग्लादेशी पुलिस अधिकारियों, स्वापक विभाग के कर्मचारियों, सीमा सुरक्षा बल तथा रक्षा संस्थान, नाभिकीय संस्थान, न्यायिक संस्थान, नाभिकीय वैज्ञानिकों आदि के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। बांग्लादेश रक्षा कार्मिकों के प्रशिक्षण स्लाटों को इस वर्ष बढ़ा दिया गया।

भूटान

भारत और भूटान के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध है जो पारस्परिक दृढ़ विश्वास तथा समझबूझ पर आधारित है। 28 अप्रैल, 2015 को प्रधान मंत्री टोब्गे और राजदूत ने जेनेखा, थिम्पु में बांगबामा केंद्रीय विद्यालय में औपचारिक रूप से 24 केंद्रीय विद्यालयों की शुरुआत की। भारत सरकार ने अपनी परियोजना संयुक्त सहयोग (पीटीए) कार्यक्रम परियोजना के माध्यम से रु. 348.719 करोड़ रुपए से 37 केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना में सहयोग दिया है। वर्ष 2015–16 के लिए आठ विद्वानों को

नेहरू–वांगचूक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की गई जबकि जून 2014 में प्रधानमंत्री की अपनी भूटान यात्रा के दौरान की गई घोषणा के अनुसरण में सभी विद्वानों की छात्रवृत्ति राशि को दोगुना कर दिया गया। भारत–भूटान द्विपक्षीय व्यापार तथा पारगमन बैठक थिंपु में 25–27 मई, 2015 के दौरान आयोजित की गई थी जिसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव श्री राजीव खेर ने किया था और भूटानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आर्थिक कार्य मंत्रालय के स्थानपन्न सचिव दाशो सोनम पी. वांग्डी ने किया था। राष्ट्रीय सभा की अध्यक्ष लियोंपो जिग्मे जंग्पो और राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्ष डॉ. सोनम किंगा के संयुक्त नेतृत्व में एक भूटानी संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 9–14 अगस्त, 2015 के दौरान भारत का दौरा किया। इससे पहले संधि अनुसमर्थन प्रक्रिया को समझने के लिए भूटान की शाही सरकार से भूटान के राष्ट्रीय सभा की विधायी समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक पांच सदस्यीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल ने 18–19 जून, 2015 के दौरान नई दिल्ली का दौरा किया। 21 जून, 2015 को मिशन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एक बड़े योग सत्र का आयोजन किया था। प्रधानमंत्री टोब्गे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे।

भूटान के आर्थिक कार्य मंत्री, लियोनपो नोर्बू वांग्चूक ने भारत की दो यात्रा की (1) 8 से 13 जुलाई, 2015 के दौरान एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जिसके दौरान वे विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) से मिले और (2) नई दिल्ली में दक्षिण एशिया आर्थिक सभा में भाग लेने के लिए 28–30 सितंबर, 2015 के दौरान यात्रा की। सचिव (सीमा प्रबंधन), गृह मंत्रालय ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा से संबंधित भारत–भूटान की सचिव स्तरीय बातचीत के 10वें दौर में भाग लेने के लिए 2–4 सितंबर, 2015 के दौरान भूटान की यात्रा की। जल विद्युत सहयोग से संबंधित अधिकार प्राप्त संयुक्त समूह की 14वीं बैठक 3 अगस्त, 2015 को थिंपु में हुई थी। विदेश मंत्रालय में सचिव (एम व ईआर) सुजाता मेहता ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक के दौरान 1520 मेगावाट बिजली उत्पादन करने के लिए तीन और संयुक्त उद्यम (जेवी) जल विद्युत परियोजना के निर्माण का निर्णय लिया गया।

भारत सरकार ने 27 अगस्त, 2015 को थिंपु में आयोजित भूटान–भारत लघु विकास परियोजना समिति की तीसरी बैठक के दौरान रु.240 करोड़ रुपये के 218 में से कुल 182 परियोजनाओं को अनुमोदित किया। भारत–भूटान विकास सहयोग की चौथी वार्षिक बातचीत 2 सितंबर, 2015 को नई दिल्ली में हुई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सुश्री सुजाता मेहता, सचिव (एम व ईआर) ने किया था और भूटानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भूटान के विदेश सचिव दाशो शिरिंग डोर्जी ने किया था।

प्रधानमंत्री टोब्गे ने न्यूयार्क में 25 सितंबर, 2015 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने जल विद्युत परियोजनाओं एसडीजी, जलवायु परिवर्तन, लघु विकास परियोजनाओं की प्रगति, पर्यटन और बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल (बीबीआईएन) पहल पर चर्चा की। प्रधानमंत्री टोब्गे के निमंत्रण पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी ने 5–9 अक्तूबर, 2015 के दौरान भूटान की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री, आर्थिक कार्य मंत्री लियोनपो नोर्बू वांग्चूक और विदेश मंत्री लियोनपो दामचो दोर्जी से मिली। उन्होंने महामहिम नरेश और चौथे ड्रुक ग्यालयो से भी मुलाकात की। भूटान के विदेश मंत्री श्री दामचो दोर्जी ने 22 से 28 अक्तूबर, 2015 के दौरान भारत का दौरा किया। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात यह उनका पहला विदेश दौरा था। दौरे के दौरान उन्होंने नई दिल्ली में विदेश मंत्री के साथ बातचीत की और भारत प्रतिष्ठान द्वारा इंदौर में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय धर्म–धम्म सम्मेलन में भी भाग लिया।

प्रधानमंत्री टोब्गे ने गोवा में ''सभ्यता से सीख'' विषय पर आयोजित द्वितीय भारत विचार सभा–2015 में भाग लेने के लिए 13–17 नवंबर, 2015 के दौरान भारत का दौरा किया। यात्रा के दौरान गृह मंत्री, रेल मंत्री, वाणिज्य राज्य मंत्री, विद्युत राज्य मंत्री तथा विदेश सचिव ने प्रधानमंत्री टोब्गे से मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री टोब्गे ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के निमंत्रण पर ''बंगाल वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन 2016'' में भाग लेने के लिए 6–9 जनवरी, 2016 के दौरान कोलकाता का दौरा किया।

भूटान के श्रम व मानव संसाधन मंत्री, नीमा संगे शेम्पो ने 20–25 दिसंबर, 2015 तक भारत का दौरा किया। उन्होंने कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव प्रताप रूडी, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री बंदारू दत्तात्रेय और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की।

चीन

हाल के वर्षों में भारत के चीन के साथ संबंधों में चहुमुखी प्रगति हुई है। उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान–प्रदान के साथ–साथ परस्पर आर्थिक संबंधों का विस्तार हुआ है। इससे दोनों देशों का विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार, विश्व व्यापार संगठन का दोहा दौर, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्रों में परिलक्षित होता है। सितंबर, 2014 में दोनों पक्ष शांति और समृद्धि के लिए भारत–चीन सामरिक तथा सहयोगात्मक भागीदारी के मुख्य बिंदु के रूप में ''निकट विकासात्मक भागीदारी'' बनाने पर सहमत हुए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14–16 मई, 2015 तक चीन का सफल दौरा किया। राष्ट्रपति शि. जिनपिंग ने प्रोतोकॉल को तोड़ते हुए शियान में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ली किक्यांग से सीमित और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और नेशनल पीपल्स कांग्रेस के अध्यक्ष

भूटान के विदेश मंत्री 22–28 अक्तूबर, 2015 तक अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री से मुलाकात करते हुए।

प्रधानमंत्री शियान, चीन (14 मई, 2015) में चीन जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति शि जिनपिंग से मुलाकात करते हुए।

प्रधानमंत्री और चीन जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति शि जिनिपंग शियांग, चीन (14 मई, 2015)
में प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता में

प्रधानमंत्री और चीन के प्रधानमंत्री बीजिंग स्थित टेंपल ऑफ हिवेन में योगा–ताइशी
संयुक्त कार्यक्रम के दौरान बच्चों

जेंझाऊ में (15 दिसम्बर 2015 को) आयोजित 14वें एससीओ शिखर सम्मेलन में
विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वी.के.सिंह सभा को संबोधित करते हुए

म्यामां के विदेश मंत्री यू वुन्ना मौंग ल्विन भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात करते हुए।

झांग डेजियांग से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने रेल, व्यापार व वाणिज्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, खनन, लोगों का लोगों से आदान–प्रदान आदि से संबंधित अभूतपूर्व 24 करारों/ समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन क्रमशः चेंग्दू और चेन्नई में नया कौंसुलावास स्थापित करने के करार पर सहमत हुए। पहली बार द्विपक्षीय संबंधों पर संयुक्त वक्तव्य के साथ जलवायु परिवर्तन पर एक अलग से संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री ली ने बीजिंग मे हैवेन मंदिर में संयुक्त योगा–ताइशी प्रदर्शन में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, शंघाई में 22 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक के 26 वाणिज्यिक/व्यापार करारों पर हस्ताक्षर किए गए। शंघाई में, प्रधानमंत्री ने चीन के शीर्ष सीईओ से मुलाकात की और भारत–चीन व्यापार मंच को संबोधित किया। दौरा भारत–चीन संबंधों के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ है और सहयोग के कई नए क्षेत्रों को खोलते हुए द्विपक्षीय संबंधों को ज्यादा व्यापक बनाया जा सका है।

मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने अपने चार दिवसीय दौरे पर चीन की सरकार और यूनेस्को द्वारा ''आईसीटी और 2015 पश्च शिक्षा'' पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए मई, 2015 में किन्गडाओ का दौरा किया। उन्होंने भारत और चीन के गहरे संबंधों के भाग के रूप में पारस्परिक अकादमिक उपाधियों को मान्यता प्रदान करने के साथ उच्च शैक्षणिक संस्थानों के एक मंच को स्थापित करने का विचार रखा। विश्वविद्यालय की पारस्परिक मान्यता से दोनों देशों के बीच और अधिक शैक्षिक आदान–प्रदान के रास्ते खुलेंगे

राष्ट्रीय पीपल्स कांग्रेस के स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री झांग देजियांग ने 13–16 जून, 2015 तक भारत का दौरा किया। यह भारत की उनकी पहली यात्रा थी और यह मुंबई से शुरू हुई थी जहां उन्होंने राज्यपाल, मुख्यमंत्री से मुलाकात की और महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के साथ दोपहर का भोजन किया। दिल्ली में झांग ने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उप–राष्ट्रपति से मुलाकात की । श्री झांग और माननीय अध्यक्ष ने भारत–चीन संसदीय मैत्री समूह की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। चर्चा में संसदीय आदान–प्रदान, प्रांतीय विधानसभा आदान–प्रदान, लोगों का लोगों से आदान–प्रदान तथा सांस्कृतिक आदान–प्रदान से संबंधित विभिन्न मुद्दे शामिल थे।

चीन के उप–राष्ट्रपति ली युवानचाऊ ने 3–7 नवंबर, 2015 तक भारत की यात्रा की। 60 वर्षों में किसी चीनी उप–राष्ट्रपति का यह पहला भारत दौरा था। उन्होंने औरंगाबाद के समीप अजंता की गुफाओं का भ्रमण करते हुए यात्रा की शुरुआत की और बाद में कोलकाता गए, जहां वे जरासांको ठाकुरबाड़ी गए जो कि गुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर का पैतृक निवास स्थान है। दिल्ली में उनकी उप–राष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ भी एक बैठक हुई। उन्होंने राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से 6 नवंबर, 2015 को मुलाकात की। यात्रा सार्थक रही। दोनों पक्षों ने सतलुज/लांगकेन जांग्बो नदी के लिए जल वैज्ञानिक सूचना प्रदान करने संबंधी समझौता ज्ञापन और ''चीन में गुप्तकालीन संग्रह'' से जुड़ी प्रदर्शनी संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

सीएमसी के उपाध्यक्ष जनरल फैन चांग्लोंग ने 15–17 नवंबर, 2015 तक भारत का दौरा किया। उन्होंने सेना प्रमुख तथा रक्षा मंत्री के साथ बैठक की और 17 नवंबर, 2015 को प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की। हाल के वर्षों में चीन से भारत का यह उच्च–स्तरीय रक्षा प्रतिनिधिमंडल दौरा था।

वार्षिक रक्षा और सुरक्षा वार्ता (एडीएसडी) का 7वां दौर 9–11 अप्रैल, 2015 तक बीजिंग में आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा सचिव श्री आर. के. माथुर ने किया था। दोनों पक्षों ने पारस्परिक हित के मुद्दों पर गहन विचारों का आदान–प्रदान किया और वर्ष 2015 के लिए वार्षिक आदान–प्रदान के कैलेंडर पर सहमत हुए।

5वां भारत–चीन संयुक्त सैन्य अभ्यास– 2015 कुनमिंग मिलिट्री अकादमी, यून्नन, चीन में 12–22 अक्तूबर, 2015 तक आयोजित किया गया। संयुक्त अभ्यास के द्वारा आतंकरोधी प्रशिक्षण के अनुभव का आदान–प्रदान और आतंकरोधी अभियानों का संचालन, पारस्परिक विश्वास तथा समझ को बढ़ाने और दोनों सेनाओं के बीच स्वस्थ सैन्य मेल–मिलाप को प्रोत्साहित करने संबंधी घोषित उद्देश्य प्राप्त किए गए। दोनों देशों के पास विदेश मंत्रालय और इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के बीच एक **आदान–प्रदान कार्यक्रम** है। दोनों पक्षों ने इस कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए मई, 2015 में प्रधानमंत्री के चीन दौरे के दौरान एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस कार्यक्रम के तहत आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने चीन का दौरा किया और अप्रैल 2015 में श्री झाओ सेनयांग, शांक्सी पार्टी सचिव ने इस कार्यक्रम के तहत भारत का दौरा किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल खट्टर ने 21–25 जनवरी, 2016 तक चीन का दौरा किया। यह यात्रा चीन की साम्यवादी पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग और विदेश मंत्रालय के बीच कार्यक्रम आदान–प्रदान के क्रम में आयोजित किया गया था। यात्रा के दौरान श्री खट्टर ने बीजिंग, शंघाई तथा यून्नन प्रांत का दौरा किया और चीनी निवेशकों के साथ गोलमेज चर्चा की। इस यात्रा से भारत में चीनी निवेश को बढ़ावा मिला।

भारत गणराज्य के गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 18–23 नवंबर, 2015 तक चीन (बीजिंग और शंघाई) का आधिकारिक दौरा किया। एक सहमति बनी कि दोनों पक्ष आगे उच्च–स्तरीय

दौरों का आदान–प्रदान करेंगे और हर दो वर्ष में एक बार बीजिंग और दिल्ली में आयोजित किए जाने वाला भारत के गृहमंत्री और चीन के लोक सुरक्षा मंत्री के नेतृत्व में भारत–चीन उच्च–स्तरीय बैठक तंत्र स्थापित करेंगे। मंत्री स्तरीय बैठक तंत्र को सहयोग करने के लिए, दोनों मंत्रालयों के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विभागों के नेतृत्व में एक संयुक्त सचिव/महानिदेशक स्तरीय बैठक तंत्र को स्थापित किया जाएगा। यह तंत्र वर्ष में एक बार बारी–बारी से बीजिंग और नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस बात पर भी सहमित बनी कि दोनों पक्ष आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, मादक पदार्थ संबंधी अपराध, साइबर अपराध व दूरसंचार संबंधी धोखाधड़ी, आर्थिक अपराध, अवैध आप्रवास गतिविधियों, आग्नेयास्त्रों की अवैध तस्करी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करेंगे और दोनों के बीच कानून प्रवर्तन सहयोग के दीर्घावधिक स्वस्थ और स्थाई विकास को प्रोत्साहित करेंगे।

पर्यटन राज्य मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने कुनमिंग में चाइना इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट में भारत के ''गेस्ट ऑफ आनर'' का उद्घाटन करने के लिए चीन का दौरा किया। उन्होंने भारत–चीन उच्च स्तरीय पर्यटन मंच की सह–अध्यक्षता भी की।

विदेश राज्य मंत्री जन. (सेवानिवृत्त) (डॉ.) वी. के. सिंह ने 2015 में चीन का तीन बार दौरा किया–(i) जब जून 2015 में भारत में कुनमिंग में चीन–दक्षिण एशिया प्रदर्शनी में ''सम्माननीय अतिथि'' देश के रूप में भाग लिया, (ii) 03 सितंबर, 2015 को दूसरे विश्व युद्ध के समापन का प्रतीक बनाने संबंधी कार्यक्रम में भारतीय प्रतिनिधित्व और (iii) जेंग्जउ, हेनन प्रांत, चीन में सरकार के एससीओ प्रमुख की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए।

भारत और **चीन के बीच वार्षिक युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम** हुआ। सितंबर, 2014 में राष्ट्रपति शि के दौरे के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि 2015–2019 से 200–सदस्यीय युवा प्रतिनिधिमंडल का आदान–प्रदान किया जाएगा। एक 200–सदस्यीय भारतीय युवा प्रतिनिधिमंडल ने 20–26 अगस्त, 2015 तक चीन का दौरा किया और एक 200–सदस्यीय चीनी युवा प्रतिनिधिमंडल ने 17–23 नवंबर, 2015 तक भारत का दौरा किया।

सितंबर 2014 में राष्ट्रपति शि जिनपिंग के भारत दौरे के दौरान ना थुला से होते हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए अतिरिक्त मार्ग खोलने से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद जून 2015 से शुरू करते हुए ना थुला मार्ग से होते हुए पांच जत्थों में 216 यात्रियों ने कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा की।

मई 2015 में प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद नीति आयोग और डेवेलपमेंट रिसर्च सेंटर ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ चाइना के बीच 23–25 नवंबर, 2015 तक बीजिंग में पहली वार्ता की गई। चीन–भारत आर्थिक सहयोग के सुदृढ़ीकरण, आरटीए के प्रभाव और वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत और चीन की भूमिका जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

सितंबर 2014 में राष्ट्रपति शि जिनपिंग के भारत दौरे के दौरान नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया (एन बी टी) और चाईनाज स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर प्रेस, पब्लिकेशन, रेडियो फिल्म एण्ड टेलीविजन के बीच सम्माननीय सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद चीन ने नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला–2016 में ''सम्माननीय अतिथि'' देश के रूप में 9–17 जनवरी 2016 तक भाग लिया।

द्विपक्षीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, भारत और चीन सहमत हुए थे कि 2015 को चीन में ''भारत की यात्रा'' वर्ष और 2016 को भारत में ''चीन की यात्रा'' वर्ष के रूप में मनाया जाए। चाइना नेशनल टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन के अध्यक्ष श्री ली जिनजाओ और पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री डॉ. महेश शर्मा की उपस्थिति में चीन की यात्रा वर्ष की शुरुआत के लिए 14 जनवरी, 2016 को नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया गया था। चीन के राष्ट्रपति शि जिनपिंग और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा बधाई संदेश भेजे गए थे।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के निमंत्रण पर चीन के जनवादी गणराज्य के हॉन्ग कॉन्ग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (एच के एस ए आर) के मुख्य कार्यकारी श्री सी. वाई लियोंग ने 2–5 फरवरी, 2016 तक भारत का दौरा किया। उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाकात की और नई दिल्ली में नेताओं से बातचीत की। श्री लियोंग के साथ आए बड़े उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने व्यापार और निवेश संबंधी कई कार्यकलापों में भाग लिया।

म्यांमा

भारत और म्यांमा के बीच मैत्रीपूर्ण पड़ोसी संबंध हैं जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और नृजातीय संबंधों पर आधारित हैं। उच्च स्तरीय दौरे सहित नियमित दौरों के आदान–प्रदान के जरिए द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए हैं। गत वर्ष महत्वपूर्ण आदान–प्रदानों में म्यांमा के विदेश मंत्री तथा रक्षा सेवाओं के कमांडर इन चीफ के भारत दौरे और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तथा विदेश सचिव के विदेश दौरे शामिल हैं।

वर्ष 2015 में भारत तथा म्यांमा ने दो विदेश मंत्रियों की निगरानी में संयुक्त परामर्शदात्री आयोग स्थापित किया है जो नियमित वार्ता तथा समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा के लिए एक तंत्र होगा। प्रथम बैठक 16 जुलाई 2015 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और इसकी सह–अध्यक्षता म्यामां के विदेश मंत्री यू वुन्ना मौंग ल्विन तथा भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने की थी।

रक्षा सेवाओं के कमांडर–इन–चीफ वरिष्ठ जनरल मिन आँग

लैंग ने 27–30 जुलाई, 2015 तक भारत में नौसेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख सहित म्यांमां सशस्त्र बलों के एक सैन्य प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। यह भारतीय सशस्त्र बल के चीफ ऑफ स्टॉफ कमेटी के अध्यक्ष वायु सेना प्रमुख अरुप राहा के निमंत्रण पर हुआ था। इस यात्रा के दौरान उन्होंने वरिष्ठ भारतीय सेना और राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की और मुख्य रक्षा इकाइयों का दौरा किया।

म्यांमा में 2015 में 8 नृजातीय सशस्त्र समूहों और म्यांमा सरकार के बीच राष्ट्रव्यापी युद्ध विराम करार (एनसीए) पर हस्ताक्षर करना और म्यांमा में आम चुनाव कराना दो महत्वपूर्ण घरेलू घटनाक्रम थे। एक घनिष्ठ और मित्रवत पड़ोसी के नाते भारत दोनों ही अवसरों पर उपस्थित था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय साक्षी के रूप में 15 अक्तूबर, 2015 को ने पाई ता, म्यांमा में आयोजित एनसीए हस्ताक्षर समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

म्यांमा में निम्न सदन, उच्च सदन तथा विधानसभा के लिए आम चुनाव तथा 8 नवंबर, 2015 को सफलतापूर्वक समाप्त हुए। म्यांमा में चुनावों के लिए भारत सरकार ने भारतीय चुनाव आयोग द्वारा मनोनीत तीन चुनाव पर्यवेक्षकों के एक दल को तैनात किया था। डॉ आंग सान सू की की नेतृत्व वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने चुनावों में जबरदस्त बहुमत प्राप्त कर जीत हासिल की। इस चुनाव में 90 से भी अधिक राजनैतिक पार्टियों ने भाग लिया। फरवरी–मार्च 2016 में नई सरकार का गठन लगभग होने की संभावना है।

संस्थागत तंत्र

16 जुलाई, 2015 को जेसीसी की प्रथम बैठक के अतिरिक्त गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच 11–15 मई, 2015 तक मुंबई में क्षेत्रीय स्तर की 21वीं बैठक हुई थी। आर्मी कमांडर स्तर पर भारत–म्यांमा क्षेत्रीय सीमा समिति (आरबीसी) की 7वीं बैठक 6–10 जुलाई, 2015 तक लिमाखोंग, मणिपुर में हुई थी। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से तिमाही आर्मी संपर्क बैठक आयोजित की जाती है। पहली बार वायु सेना से वायुसेना स्टाफ वार्ता 21–23 जुलाई, 2015 तक नई दिल्ली में हुई थी। नौसेना से नौसेना स्टाफ की चौथी वार्ता 23–25 नवंबर, 2015 तक यंगून में हुई थी। प्रथम थल सेना से थल सेना स्टाफ वार्ता 28–30 दिसंबर, 2015 तक हुई थी।

वार्षिक ऋण श्रृंखला समीक्षा समिति की बैठक के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि भारत सरकार की परियोजनाएं, जिनकी मई, 2012 में प्रधानमंत्री की म्यांमा यात्रा के दौरान घोषणा की गई थी। 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण श्रृंखला के तहत पूरी की जा रही है। इनमें रेल, सिंचाई, दूर संचार तथा सड़क निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं।

सीमा संबंधी सभी मामलों पर चर्चा करने हेतु वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर स्थापित भारत–म्यांमा संयुक्त सीमा कार्य समूह की प्रथम बैठक 5–8 जनवरी, 2016 तक ने पाइ ता, म्यांमा में आयोजित की गई।

आर्थिक और वाणिज्यिक

2014–15 में कुल 2.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत–म्यांमा का 5वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। निवेश के मामले में, 2015 में 36 देशों से 724 उद्यमों द्वारा 47.228 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल अनुमोदित निवेशों में से 726.149 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमोदित निवेश के साथ भारत 9वें स्थान पर आ गया है। जून, 2015 में भारतीय स्टेट बैंक और न्यू इंडिया एश्योरेंस ने यंगून में अपने प्रतिनिधि कार्यालय खोले। समुद्री तट पर उत्पादन और खोज के लिए 2013 में दूसरे दौरे की बोली के दौरान रिलायंस ने 2 ब्लाक–एम 17 व एम–18 तथा ओ आई एल ने 2 ब्लाक वाईईबी और एम4 जीते। दोनों कंपनियों ने अपने म्यांमा के समकक्ष के साथ मार्च 2015 में पीएससी पर हस्ताक्षर किए।

भारत सरकार ने एक्ट ईस्ट नीति पर पहल के भाग के रूप में सीएलएमवी देशों में भारतीय व्यापार घरानों/समूहों द्वारा निवेश को सुविधाजनक बनाने और इसमें सहायता करने के लिए एक परियोजना विकास निधि के रूप में एक विशेष प्रयोजनार्थ वाहन के गठन को अनुमोदित कर दिया है।

भारत–म्यांमा संयुक्त व्यापार तथा निवेश मंच नामक व्यापारियों के एक मंच की दूसरी बैठक 12 जनवरी, 2016 को चेन्नई में होनी है। भारत, म्यांमा तथा थाईलैंड त्रिपक्षीय मोटरवाहन करार पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। इस संबंध में नवंबर, 2015 में इन देशों के बीच वाहनों का परीक्षणार्थ प्रचालन किया गया।

सीमा पर म्यांमा के साथ सामान्य व्यापार को सहयोग करने हेतु पर्याप्त बैंकिंग सुविधा के मद्देनजर, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से भारत–म्यांमा सीमा पर व्यापार की अदला–बदली प्रणाली को खत्म करने तथा 1 दिसंबर, 2015 से पूरी तरह सामान्य व्यापार करने का निर्णय लिया है। 96.4ः से अधिक टैरिफ श्रृंखलाओं हेतु शून्य शुल्क पर म्यांमा से सामानों के आयात के लिए कम विकसित देश (एलडीसी) के लिए शुल्क मुक्त प्राथमिकता योजना में सुधार हुआ है। मिजोरम से होते हुए म्यांमा और उसके आगे के सीमा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पहले मार्च 2015 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा जावखतर (मिजोरम) पर भूमि सीमा शुल्क केन्द्र का उद्घाटन किया गया था।

म्यांमार में सभी बड़ी विकास सहयोग परियोजनाओं अर्थात कलादान–उद्देशीय–पारमन परिवहन परियोजना, त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना पर कार्य अब निष्पादन स्तर पर पहुंच गया है, क्योंकि वित्तीय अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

नेपाल में भूकंप के पश्चात भारत द्वारा किए गए राहत प्रयास

नेपाल में भूकंप के बाद धुंचे में भारत द्वारा राहत अभियान

आपदा राहत

2015 में तूफान–कोमेन जिससे देश के ज्यादातर भागों में भारी वर्षा के कारण भूस्खलन हुआ। इसके बाद म्यांमा ने सहयोग का अनुरोध किया और भारत सरकार ने मुस्तैदी दिखाते हुए तत्काल कले तथा मण्डाले के लिए भारतीय वायुसेना के वायुयानों के जरिए खाद्य तथा दवाई भेजी।

भारत प्रशिक्षण, विशेषज्ञता का प्रावधन, ऋण श्रृंखला और/अथवा अनुदान सहायता सहित विकास परियोजनाओं के माध्यम से म्यामां की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रशिक्षण केन्द्रों सहित कई परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है और नई परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। म्यामां को हमारी कुल विकास प्रतिबद्धता, जिसमें कलादान उद्देशीय पारगमन परियोजना तथा त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना जैसी पूर्ण तथा निर्माणाधीन अवसंरचना परियोजनाएं हैं, 1.5 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक है।

भारत ने आईटेक, टीसीएस तथा भा. सां. सं. प. छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत म्यामां की मानव संसाधन क्षमता हेतु व्यापक सहायता प्रदान की है। मई 2012 में प्रधानमंत्री के म्यामां दौरे के दौरान दी गई वचनबद्धता के अनुरूप म्यामां को हर वर्ष 500 आईटेक छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं।

यंगून स्थित राजदूतावास और मंडाले स्थित भारत का प्रधान कौंसुलावास द्वारा 21 जून, 2015 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी से सफल कार्यक्रम रहा। 1 जुलाई, 2015 को यंगून में भारत के राजदूतावास में 'डिजिटल इंडिया वीक' का सीधा प्रसारण किया गया था।

नेपाल

खुली सीमाएं लोगों का लोगों से व्यापक संबंध तथा बहुमुखी सामाजिक–आर्थिक संपर्क भारत–नेपाल मित्रता तथा सहयोग की विशेषता रही है। विदेश सचिव ने अपनी सार्क यात्रा के भाग के रूप में 2–3 अप्रैल, 2015 तक नेपाल का दौरा किया और नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा नेपाल के विदेश सचिव से मुलाकात की। 16 अप्रैल, 2015 को, भारत सरकार की ओर से, राजदूत ने कमीशन फॉर दी इन्वेस्टिगेशन ऑफ एब्युज ऑफ अथोरिटी (सी आई ए ए) के मुख्य आयुक्त को रु. 33.12 मिलियन के 35 वाहनों का उपहार सौंपा।

25 अप्रैल, 2015 के विध्वंसकारी भूकंप और 12 मई 2015 के जबरदस्त झटके के बाद भारत सरकार द्वारा प्रथम भूकंप के छः घंटे के अंदर विशेष वायुयानों से बचाव और राहत सामग्री भेजी गई। राहत चरण के दौरान केन्द्र और राज्य सरकारों के साथ–साथ गैर–सरकारी संगठनों से लगभग रु. 400 करोड़ रुपये की बड़ी सहायता की गई थी। नेपाल में भारत द्वारा सबसे अधिक राहत प्रयास किए गए।

विदेश मंत्री ने भूकंप संबंधी पुनर्निर्माण प्रयासों के मकसद से नेपाल सरकार द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दानकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए 24–25 जून, 2015 तक नेपाल का दौरा किया। विदेश मंत्री द्वारा भारत की ओर से 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जिसका एक चौथाई अनुदान है) की सहायता राशि की घोषण ाा की गई। यह अगले पांच वर्षों में 1 बिलियन अमेरिकी डालर की हमारी मौजूदा सहायता के अतिरिक्त थी। नेपाल के नेता पुष्प कमल दहल यूसीपीएन के 'प्रचण्ड' और एन सी के शेर बहादुर देउबा ने क्रमशः 14–20 जुलाई, 2015 तथा 19 जुलाई–3 अगस्त, 2015 तक भारत का दौरा किया। उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री तथा विदेश सचिव से मुलाकात की। एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से भारत सरकार द्वारा दी गई 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर तथा 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण श्रृंखला के तहत विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु 03 अगस्त, 2015 को काठमांडू में भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच तृतीय द्विपक्षीय ऋण श्रृंखला (एल ओ सी) समीक्षा बैठक हुई थी। भूकंप के पश्चात् नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए भारत सरकार द्व ारा प्रतिबद्ध 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण श्रृंखला के कार्यान्वयन हेतु तौर–तरीकों के बारे में चर्चा हुई। नेपाल के वाणि ाज्य तथा आपूर्ति मंत्री सुनील बहादुर थापा ने 17–19 अगस्त, 2015 तक भारत का दौरा किया। उन्होंने विदेश सचिव से मुलाकात की जिन्होंने नेपाल का संविधान बनाने हेतु आम सहमति के आधार पर भारत की स्थिति को दोहराया। श्री मधु सूदन अधिकारी, महानिदेशक, सर्वेक्षण विभाग, नेपाल सरकार के नेतृत्व में एक 15–सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमंडल ने भारत–नेपाल सीमा कार्य समूह (बी डब्ल्यू जी) की द्वितीय बैठक में भाग लेने के लिए 23–28 अगस्त, 2015 तक देहरादून का दौरा किया। सीमा खम्भों के लिए जी पी एस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने संबंधी करार पर सहमति बनी।

24 अगस्त, 2015 को 275 करोड़ रुपए की लागत वाली 41 कि.मी. लंबी रक्सौल–अमलेखगंज पेट्रोलियम पाईपलाइन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 24 अगस्त, 2015 को काठमांडू में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान और नेपाल सरकार के वाणिज्य व आपूर्ति मंत्री श्री सुनील बहादुर थापा द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

विदेश सचिव ने प्रधानमंत्री के एक विशेष दूत के रूप में 18–19 सितंबर, 2015 तक नेपाल का दौरा किया। उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा नेपाल के प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की। यात्रा के दौरान इस बात को दोहराया गया कि भारत नेपाल में संविधान बनाने का पुरजोर समर्थन करता रहा है और नेपाल के राजनीतिक नेताओं और सभी पक्षों को हमारी

सलाह है कि व्यापक स्वीकृति के आधार पर संविधान का निर्माण हो जिसमें आवश्यक लचीलापन तथा परिपक्वता हो। 11 अक्तूबर, 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्री के. पी. एस. ओली को बधाई दी। कार्यभार ग्रहण करने के एक सप्ताह के अंदर ही नेपाल के उप प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री श्री कमल थापा ने 17–19 अक्तूबर, 2015 तक भारत का दौरा किया।

अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री के नेपाल दौरे के दौरान घोषित ''भारत नेपाल मैत्री शिक्षा कार्यक्रम'' के तहत नेपाल तथा भारत में अध्ययन करने के लिए 2015 में लगभग 3000 नेपाली छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थीं।

नेपाल के उप प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री श्री कमल थापा ने 2–3 दिसंबर, 2015 तक भारत का पुनः दौरा किया। उन्होंने नेपाल सरकार द्वारा मधेसी मुद्दों को निपटाने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में विदेश मंत्री को अवगत कराया। मुख्य मधेसी नेता श्री महंता ठाकुर, श्री उपेन्द्र यादव, श्री राजेन्द्र महतो और श्री महेन्द्र राय यादव ने 5–9 दिसंबर, 2015 तक भारत का दौरा किया। इस प्रतिननिधिमंडल ने विदेश मंत्री तथा अन्य राजनीतकि नेताओं से मुलाकात की।

आप्लावन और बाढ़ प्रबंधन संबंधी संयुक्त समिति की 10वीं बैठक नेपाल में 6–10 दिसंबर, 2015 तक आयोजित की गई थी। 21 दिसंबर, 2015 को नेपाल के उप–प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कमल थापा द्वारा विदेश मंत्री को अवगत कराया गया कि आंदोलनकारी मधेस–आधारित पार्टियों द्वारा संविधान के संबंध में उठाई गई मांगों को निपटाने और हल करने के लिए नेपाल के मंत्रिमंडल ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री के. पी. एस. ओली ने 31 दिसंबर, 2015 को प्रधानमंत्री को फोन किया और उन्हें नेपाल के राजनीतिक घटनाक्रमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने नेपाल की राजनीतिक समस्या का आम सहमति के आधार पर स्थायी हल निकालने के महत्व पर बल दिया। 06 जनवरी, 2016 को नेपाली कांग्रेस के उपाध्यक्ष रामचंद्र पॉडेल ने भारत का दौरा किया और विदेश मंत्री से मुलाकात की। 08 जनवरी, 2016 को सद्भावना पार्टी के अध्यक्ष, राजेन्द्र महतो ने विदेश मंत्री से मुलाकात की।

नेपाल की संसद द्वारा 23 जनवरी, 2016 को संसदीय क्षेत्र के सीमांकन तथा आनुपातिक समावेश के मुद्दे से संबंधित दो संवैधानिक संशोधन पारित किए गए थे। भारत ने इसे सकारात्मक घटना बताया और आशा की कि इसी प्रकार के रचनात्मक भावना से अन्य बकाया मुद्दों का भी समाधान होगा।

नेपाल के प्रधानमंत्री श्री के. पी. शर्मा ओली ने कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात अपने प्रथम विदेश दौरे में, 19–24 फरवरी, 2016 तक भारत का दौरा किया। इससे पूर्व प्रारंभिक दौरे के रूप में नेपाल के वित्त मंत्री श्री विष्णु पौडेल ने 7–8 फरवरी, 2016 तक भारत का दौरा किया। प्रधानमंत्री ओली की भारत यात्रा के दौरान भारत–नेपाल संबंधों पर चर्चा हुई जिनमें नेपाल में विकास और साथ ही पुनर्निर्माण, ऊर्जा तथा संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग शामिल है।

नेपाल की राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की संयुक्त परियोजना निगरानी समिति की बैठक 28–29 जनवरी, 2016 को काठमांडू में हुई। नेपाल के सेना प्रमुख ने 2–5 फरवरी, 2016 तक भारत का दौरा किया जब माननीय राष्ट्रपति ने 'भारतीय सेना के जनरल' के मानद रैंक से उन्हें सम्मानित किया। कोसी तथा गंडक से संबंधित संयुक्त समिति की 8वीं बैठक 8–9 फरवरी, 2016 को पटना में हुई। भारत और नेपाल के बीच विद्युत से संबंधित संयुक्त स्थायी समिति तथा संयुक्त कार्य समूह की बैठक 28–29 जनवरी, 2016 को काठमांडू में हुई थी।

नेपाल और भूटान के साथ बहुपक्षीय कार्यक्रम

यात्री वैयक्तिक तथा मालवाहक गाडियों के यातायात विनियमन के लिए बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल (बी बी आई एन) मोटरगाड़ी करार (एम वी ए) पर 15 जून, 2015 को थिम्पू में बांग्लादेश, भूटान, भारत तथा नेपाल के परिवहन मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। बी बी आई एन की संयुक्त कार्य समूह की एक बैठक जल व विद्युत पर, तथा दूसरी बैठक पारगमन व कनैक्टिवटी पर 19–20 जनवरी, 2016 को ढाका में हुई।

पाकिस्तान

एक सार्थक बातचीत का रास्ता निकालने, वर्ष 2015–16 के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने पर केंद्रित, औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही तरह की उच्च–स्तरीय वार्ताएं आयोजित की गई जिससे सार्थक बातचीत का मार्ग प्रशस्त हुआ। शांतिपूर्ण तरीकों से सभी बकाया मुद्दों के हल के लिए दोनों देशों के बीच एक नए व्यापक द्विपक्षीय वार्ता संबंधी एक करार के रूप में शुरुआत हुई। तथापि, सीमा–पार आतंकवाद, युद्धविराम उल्लंघन तथा नियंत्रण रेखा के पार से घुसपैठ तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे मुख्य चिंता के विषय हैं।

उच्च–स्तरीय संपर्क

प्रधानमंत्री ने 30 अप्रैल, 2015 को नेपाल में आए भूकंप के संबंध में और बाद में 16 जून, 2015 को रमजान की बधाई देने और भारतीय जेलों में कैद 88 पाकिस्तानी मछुआरों की रिहाई के संबंध में सरकार के निर्णय के बारे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ से फोन पर बातचीत की। 21 जून, 2015 को मछुआरे रिहा हुए। 19 जून, 2015 को पाकिस्तान ने 113 मछुआरों को रिहा किया।

शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता के जरिए पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने की भारत की लंबे समय से चली आ रही नीति के मद्देनजर, प्रधानमंत्री ने उफा (रूस) में 10 जुलाई को एस सी ओ

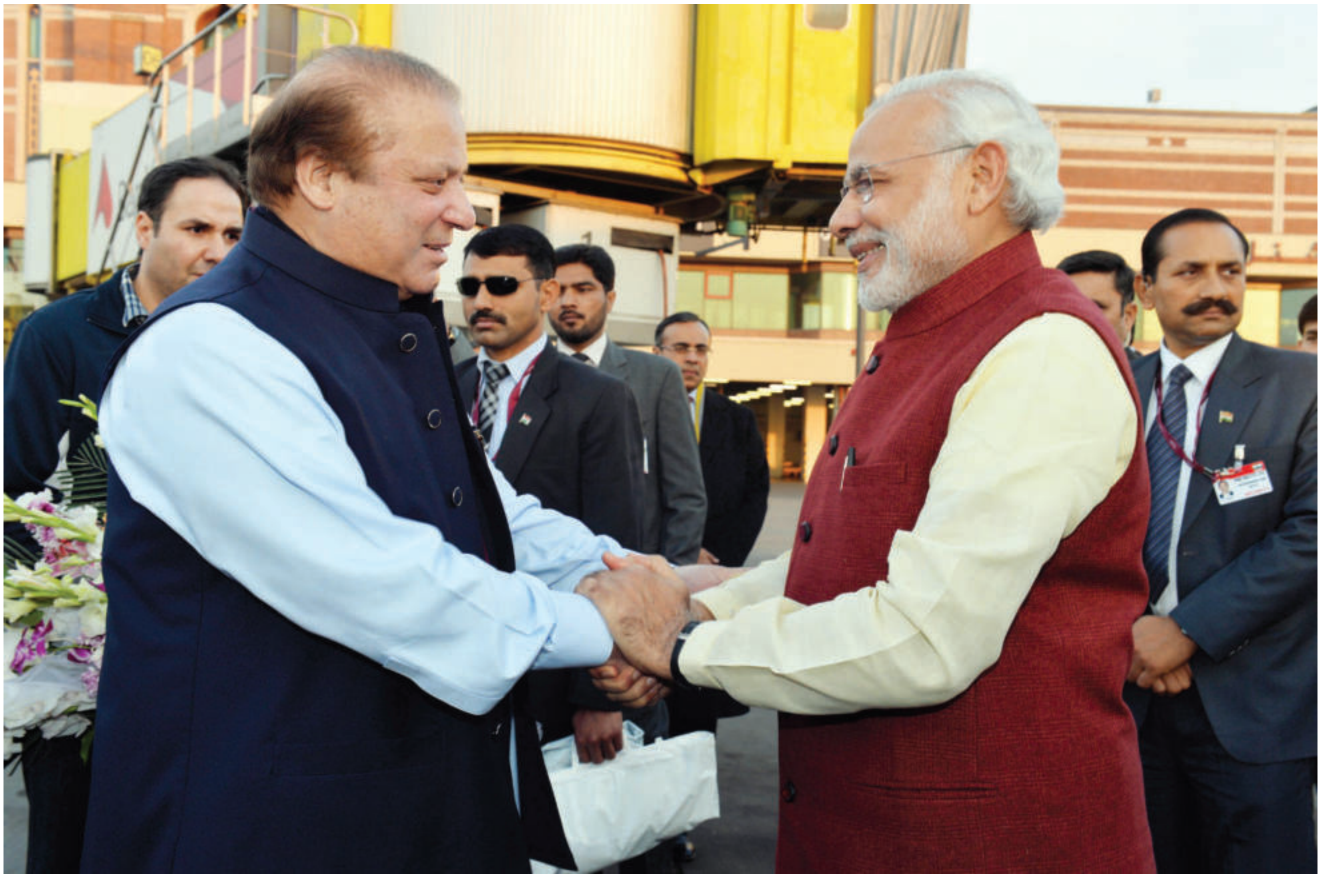

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, श्री नवाज शरीफ लाहौर, पाकिस्तान में 25 दिसंबर, 2015 को प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए।

शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की। बैठक के दौरान, दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि आतंकवाद से संबंधित सभी मुद्दों, महानिदेशक बी एस एफ तथा महानिदेशक–पाकिस्तान रैंजर्स के बाद डी जी एम ओ की जल्दी बैठकें और मुम्बई मामले की सुनवाई को तेज करने के साथ–साथ अतिरिक्त सूचना जैसे कि आवाज के नमूने उपलब्ध कराने पर चर्चा सहित सभी मुद्दों पर चर्चा हेतु दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच नई दिल्ली में एक बैठक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह एक–दूसरे की हिरासत में रह रहे मछुआरों को उनकी नावों के साथ 15 दिनों की अवधि के भीतर रिहाई तथा धार्मिक पर्यटन को सुविधाजनक बनाने संबंधी तंत्र स्थापित करने के संबंध में भी निर्णय लिया गया।

न्यूयार्क में सितंबर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70वें सत्र में विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज और एएफए और दूसरी तरफ विदेश सचिव तथा पाकिस्तान के विदेश सचिव ने उफा (रूस) में यथापरिकल्पित अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक की संभावना के बारे में पत्रों का आदान–प्रदान किया। हालांकि न्यूयार्क में भी यह बैठक नहीं हो पाई, क्योंकि पाकिस्तान इस बैठक के एजेंडे में अन्य बातों को शामिल करना चाहता था।

पाकिस्तान द्वारा हुर्रियत प्रतिनिधि को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ परामर्श करने के लिए आमंत्रित करने संबंधी निरंतर आग्रह करने और बैठक की कार्यसूची को एकतरफा विस्तार करने के प्रयासों के कारण, अगस्त 2015 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बैठक नहीं हुई।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अपने नए समकक्ष सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल नासिर खान जंजुआ को अक्तूबर, 2015 में बधाई संदेश भेजा। श्री सरताज अजीज तब तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सलाहकार और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की दोहरी भूमिका निभा रहे हैं।

माल्टा में 28 नवम्बर, 2015 को आयोजित राष्ट्रमंडल सरकारों के अध्यक्षों की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री डेविड कैमरुन के साथ बैठक के बाद कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ बिना किसी पूर्व शर्तों के बातचीत के लिए तैयार है।

30 नवंबर, 2015 को सीओपी–21 शिखर सम्मेलन में भाग लेने

के लिए अपनी पेरिस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से दुआ सलाम किया। दोनों नेताओं ने बिना किसी सहायक के कुछ क्षण बातचीत की जिसके दौरान उन्होंने एक–दूसरे के साथ पुनःबातचीत करने के लिए माहौल सृजित करने के लिए दोनों देशों के पारस्परिक स्वीकार्य रास्ते की जरूरत पर चर्चा की।

पेरिस में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत के अनुसरण में और उफा समझौते के क्रम में दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 06 दिसम्बर, 2015 को बैंकॉक में मुलाकात की। यह बातचीत शांति तथा सुरक्षा, आतंकवाद, नियंत्रण रेखा के पास शांति और जम्मू व कश्मीर पर केन्द्रित रही।

एशिया इस्तांबूल प्रक्रिया के क्रम में 5वीं मंत्रालयी सम्मेलन में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री ने 9 दिसम्बर, 2015 को इस्लामाबाद का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तथा एएफए से मुलाकात की। पाकिस्तान में मुम्बई आतंकी हमले की कार्रवाई को तेज करने संबंधी उपायों के बारे में पाकिस्तान से आश्वासन मिलने के बाद और सभी प्रकार के आतंकवाद को खत्म करने संबंधी सहयोग के मद्देनजर, दोनों पक्ष सभी मुद्दों पर व्यापक द्विपक्षीय वार्ता के लिए सहमत हुए, जिसमें शांति सुरक्षा, सीबीएम, जम्मू व कश्मीर, सियाचिन, सरक्रिक, वुलर बैराज/ तुलबुल नौसंचालन परियोजना, आर्थिक तथा वाणिज्यिक सहयोग, आतंकवाद निरोध, स्वापक नियंत्रण, मानवीय मुद्दे, लोगों के आपसी संपर्क और धार्मिक पर्यटन शामिल है। दोनों मंत्रियों ने विदेश सचिवों के तौर–तरीकों की रूपरेखा तैयार करने का कार्य सौंपा।

प्रधानमंत्री अपनी काबूल से वापसी में 25 दिसंबर, 2015 को लाहौर में रुके, जहां वे थोड़े समय के लिए आए थे और उसी सुबह में भारतीय सहयोग से बने अफगानिस्तान के संसद भवन का उद्घाटन किया। उनकी लाहौर की यात्रा जब हुई तब प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई दी और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के परिवार में विवाह समारोह की सूचना मिली। दोनों नेता प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के रायविंद निवास स्थान पर साथ में गए, जहां प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के परिवार से मिले। कम समय की सूचना में प्रधानमंत्री का लाहौर में रुकना परिवर्तनात्मक और अनौपचारिक माध्यमों से दक्षिण एशिया में सामान्य और मजबूत पड़ोस बनाए जाने के भारत के नेतृत्व की दूरदर्शिता को दर्शाता है।

पाकिस्तान में मुम्बई आतंकी हमले की सुनवाई

मुम्बई आतंकी हमले (2008) के एक मुख्य अभियुक्त जाकिर–उर–रहमान लखवी की रिहाई पर भारत सरकार ने पाकिस्तान के समक्ष गहरी चिंता व्यक्त की। वह 10 अप्रैल, 2015 को रिहा हुआ, जब लाहौर उच्च न्यायालय ने लोक आदेश रख–रखाव के तहत उसकी हिरासत को खारिज कर दिया और 2 मिलियन पाकिस्तानी रुपए की जमानत पर रिहाई का आदेश दिया। बाद में जून 2015 में चीन ने प्रासंगिक यूएनएससी संकल्प जैसे कि यूनएसआर 1267 के उल्लंघन के कारण कार्रवाई हेतु भारतीय अनुरोध को बाधित कर दिया। मामले को सरकार द्वारा चीन के साथ उच्चतम स्तर पर उठाया गया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1267 समिति के सदस्यों सहित समिति के अध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय रूप में मामले को उठाया गया।

इस्लामाबाद में मुम्बई आतंकी हमले से संबंधित चल रही सुनवाई की प्रगति को पाकिस्तान की अपनी जमीन से उपजी आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में प्रतिबद्धता की एक मुख्य उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, जांच और सुनवाई अत्यंत ध ीमी गति से चल रही है, 07 पाकिस्तानियों पर मुकदमे की आतंकरोधी न्यायालय (ए टी सी) में सुनवाई बार–बार स्थगित होने, गैर–हाजिरी/बार–बार अभियुक्त वकीलों को बदलने जैसी बातों का गवाह बना। अगस्त 2015 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक रद्द होने के बाद, 8 सितंबर, 2015 को पाकिस्तानी विदेश सचिव का विदेश सचिव के साथ पत्राचार/बातचीत, भारत से अपर्याप्त सबूतों के आरोप पर केन्द्रित रहा।

भारत डेविड हेडली की प्रत्यर्पण की लगातार मांग कर रहा है, जिसे मुम्बई आतंकी हमले (2008) की योजना में भूमिका के लिए शिकागो में अमरीकी जिला न्यायालय द्वारा 35 वर्षों की सजा सुनाई गई। 10 दिसंबर, 2015 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुम्बई में टाडा कोर्ट को गवाही देते हुए दोषी पाया गया, हेडली ने गवाह बनना स्वीकार्य किया। उसे 08 फरवरी, 2016 को अभियोजन के गवाह के रूप में गवाही देने के लिए कहा गया।

सीमा पार आतंकवाद और हिंसा

पाकिस्तान से निरंतर जारी आतंकवाद चिंता का मुख्य विषय बना हुआ है। जुलाई और अगस्त के महीनों में कई बार युद्ध विराम उल्लंघन तथा अकारण गोलाबारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा नियंत्रण रेखा के पास देखने को मिली है, जिससे रक्षा कार्मिकों और नागरिकों की मृत्यु हुई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार 01 जनवरी–20 नवम्बर 2015 के दौरान नियंत्रण रेखा पर 152 बार युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ और 01 जनवरी–31 अगरस्त, 2015 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय रेखा पर 207 बार युद्ध विराम का उल्लंघन देखा गया। गुरदासपुर (27 जुलाई, 2015), उधमपुर (5 अगस्त, 2015) और पठानकोट हवाई अड्डा (2 जनवरी, 2016) पर आतंकी हमले ने जम्मू व कश्मीर से पंजाब की ओर आतंकवाद के खतरे को खिसकते देखा है। उधमपुर हमले में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा एक पाकिस्तान आधारित आतंकी नावेद उर्फ उसमान को जिंदा पकड़ा गया था।

उफा में हुई सहमति के अनुसार, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक और पाकिस्तान रेन्जर्स के महानिदेशक नई दिल्ली में 9–12 सितंबर, 2015 तक मिले। बैठक में पूरे सीमा प्रबंधन संबंधी मुद्दों को शामिल किया गया था जो कि पारंपरिक रूप से बीएसएफ

और पाकिस्तान रेन्जर्स के महानिदेशकों की नियमित द्विवार्षिक बैठकों में होता था। विशेषकर, सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बलों के दायित्वों और सीमा के पास रह रहे नागरिकों की सुरक्षा तथा बचाव, बीएसएफ तथा पाकिस्तान रेन्जर्स के बीच उन्नत समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अनजाने में पार करने वाले नागरिकों की शीघ्र रिहाई पर विस्तृत चर्चा हुई। दोनों पक्ष दोनों बलों के कमांडरों के बीच सभी स्तरों पर संपर्क में वृद्धि हो और तस्करी तथा नशीले पदार्थों, नकली भारतीय मुद्रा, हथियार और गोला–बारूदों की तस्करी से निपटने के लिए दोनों बलों के बीच सूचना के आदान–प्रदान के लिए तंत्र स्थापित करने की जरूरत पर सहमत हुए।

जम्मू–कश्मीर

पाकिस्तान ने घरेलू के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जम्मू व कश्मीर पर अपनी वकपटुता को बढ़ा दिया है। कई पाकिस्तानी संगठनों ने सामुदायिक भागीदारी के साथ जम्मू व कश्मीर में विकास संबंधी विभिन्न दिनों को मनाने के लिए स्थानीय बैठकें आयोजित की।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए अपने प्रयासों को उठाया, सार्वजनिक रूप से संयुक्त राष्ट्र को शामिल होने के लिए कहा। 30 सितंबर, 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने चार–बिंदु (सूत्रीय) नए शांति पहल का प्रस्ताव रखा। 01 अक्टूबर, 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान, विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को उत्तर देते हुए कहा कि शांति के लिए पाकिस्तान की ओर से एक बिंदु की आवश्यकता है, वह है आतंकवाद को छोड़ना। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रतिनिधि ने उत्तर का अधिकार का प्रयोग करते हुए 01 अक्टूबर, 2015 को कहा कि, जम्मू व कश्मीर पर भारत की विख्यात स्थिति है कि वह क्षेत्र विदेशी कब्जे में है और कब्जा करने वाला पाकिस्तान है।

पठानकोट हवाई अड्डा हमला

भारतीय हवाई सेना के पठानकोट केन्द्र पर 2 जनवरी, 2016 को आतंकी हमला हुआ था। हमले ने 07 रक्षा कार्मिकों की जान ली। हालांकि शुरुआती उपलब्ध सूचना प्रतिबंधित आतंकी इकाई जैश–ए–मोहम्मद के शामिल होने की ओर इशारा कर रहा था, सईद सलाउदीन के नेतृत्व वाला यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने हमले की जिम्मेदारी ली। इस संबंध में विशिष्ट और कार्रवाई परक सूचना पाकिस्तान को उपलब्ध करा दिया है।

02 जनवरी, 2016 को पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने हमले की निंदा करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया और बताया कि वे भारत सरकार के साथ संपर्क में हैं और उपलब्ध कराए गए सबूतों पर काम कर रहे हैं। बाद में, 05 जनवरी, 2016 को प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कोलम्बो से प्रधानमंत्री से टेलीफोन पर बात की, जबकि प्रधानमंत्री ने हमले से जुड़े तथा उसके जिम्मेदार व्यक्तियों और संगठनों के विरुद्ध पाकिस्तान ने ठोस और तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत पर जोर दिया।

08 जनवरी, 2016 को, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक उच्च स्तरीय बैठक की जिसमें पाकिस्तान के थल सेनाध्यक्ष, वायुसेना अधिकारी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश सचिव तथा अन्यों ने भाग लिया। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी वक्तव्य में उल्लेख था कि बैठक में अन्य मुद्दों पर चर्चा के साथ पठानकोट आतंकी हमले पर भी चर्चा हुई और भारत द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के संबंध में प्रगति की समीक्षा हुई।

मानवीय मुद्दे

सरकार के प्रयासों की बदौलत 26 अक्टूबर, 2015 को गीता उर्फ 'मीतू' को भारत लाया जा सका। करांची स्थित गैर–सरकारी संगठन ईधी फाउंडेशन के सदस्यों के साथ गीता आई, जिसने उसे पाकिस्तान में 10 वर्षों के उसके रहने के दौरान उसे आश्रय दिया, जब वह अनजाने में बचपन में भटक कर पाकिस्तान चली गई थी। उसकी वापसी से पूर्व, सरकार ने विभिन्न सरकारी एजेंसियों और राज्य सरकारों से उसके जन्म स्थान और माता–पिता का पता लगाने के लिए मदद मांगी थी। सरकार इस संबंध में भरसक प्रयास कर रही है।

पाकिस्तान की हिरासत में असैनिक कैदियों और भारतीय मछुआरों से संबंधित मामलों को नियमित आधार पर निपटाया जा रहा है। सरकार के प्रयासों से पाकिस्तान द्वारा वर्ष 2015 के दौरान 4 भारतीय असैनिक कैदियों, 448 भारतीय मछुआरों को रिहा किया गया है। एक 9–सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जिसमें गुजरात से अधिकारी तथा मछली पकड़ने वाली नावों के मालिक शामिल थे, ने मछली पकड़ने वाली भारतीय नावों को छुड़ाने के संबंध में 18–19 जुलाई, 2014 को पाकिस्तान का दौरा किया। तदुपरांत, 23 मार्च 2015 को पाकिस्तान द्वारा 57 मछली पकड़ने वाली भारतीय नावों को छोड़ दिया गया। उसी तर्ज पर, 2016 में मछली पकड़ने वाली 22 भारतीय नावों को छुड़ाने के लिए एक 6–सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा पाकिस्तान का दौरा किए जाने का कार्यक्रम है।

व्यापार

संयुक्त व्यापार मंच, जिसमें दोनों देशों से 15 शीर्ष स्तर के व्यापारिक प्रतिनिधि शामिल थे, लाहौर में 27–28 जुलाई, 2015 तक मिले और कृषि, फार्मास्युटिकल्स, ऑटोमोबाईल, ऊर्जा, एस एम ई, बैंकिंग व वित्त, संपर्क तथा वीजा सुविधा के क्षेत्र में सहयोग के लिए प्राथमिक क्षेत्रों की जांच की।

हिंद महासागर क्षेत्र

2015 में भारत द्वारा कुशल और सुरक्षित हिंद महासागर और एक स्थिर तथा संपन्न हिंद महासागर क्षेत्र में हितों को सुरक्षित रखने

पर काफी बल दिया गया। इस मुहिम की शुरुआत मार्च 2015 में प्रधानमंत्री की सेशल्स, मॉरीशस तथा श्रीलंका के दौरे के साथ हुई। हिंद महासागर के क्षेत्र के लिए विदेश मंत्रालय में जनवरी 2016 में एक अलग प्रभाग सृजित करते हुए प्रक्रिया को एक रूप दिया गया और इस प्रकार इस क्षेत्र में आने वाले मुख्य देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव, सेशल्स, मॉरीशस के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने और हिंद महासागर क्षेत्र में भूरणनीतिक सुरक्षा, आर्थिक तथा विकासात्मक हितों का समाधान करने के वास्ते सुगठित त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा वार्ता (भारत, श्रीलंका तथा मालदीव के बीच) करने का प्रयास किया गया। हिंद महासागर क्षेत्रीय संघ (आई ओ आर ए) के भावी ट्रैक के संबंध में भारत के दृष्टिकोण को भी इस दृष्टिकोण का अभिन्न अंग बनाया गया।

श्रीलंका

गत वर्ष के दौरान भारत–श्रीलंका संबंधों में महत्वपूर्ण और गुणात्मक बदलाव आया है। कई उच्च स्तरीय दौरे के साथ 2015 में द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई हासिल हुई। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने 14–16 सितंबर, 2015 को भारत का आधिकारिक दौरा किया। अगस्त, 2015 में संसदीय चुनावों के बाद उनकी यह पहली विदेश यात्रा थी। यात्रा के दौरान सार्क/दक्षेस क्षेत्र के लिए उपग्रह की कक्षा आवृत्ति समन्वय पर द्विपक्षीय करार, श्रीलंका में आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा स्थापित करने संबंधी दस्तावेजों का आदान–प्रदान, जिला जनरल अस्पताल, वावूनीया में 200 बिस्तरों वाले वार्ड परिसर में चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति से संबंधित समझौता ज्ञापन और लघु विकासात्मक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय अनुदान सहायता के संबंध में समझौता ज्ञापन को नवीकृत किए जाने संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए।

कुछ अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय दौरों और बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:–

- 25 सितंबर, 2015 को न्यूयार्क में 70वें संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठकों के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना से मिले।
- एक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विचार–गोष्ठी में भाग लेने के लिए भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम ने 25–27 जून 2015 को श्रीलंका का दौरा किया।
- वायु सेना प्रमुख के निमंत्रण पर श्रीलंका के कमांडर एयर मार्शल, जी पी कूलाथसिंघला ने 26–30 जुलाई 2015 को

प्रधानमंत्री नई दिल्ली (15 सितम्बर, 2015) में श्रीलंका जनतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के प्रधानमंत्री महामहिम रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात करते हुए।

भारत का दौरा किया।

- गेले में श्रीलंका की नौसेना द्वारा आयोजित छठे वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन "गेले वार्ता, 2015" में भाग लेने के लिए एडमिरल आर. के. धवन, नौसेना प्रमुख ने 23–24 नवंबर 2015 को श्रीलंका का दौरा किया।
- श्रीलंका सेना के कमांडर के निमंत्रण पर सेना प्रमुख जनरल दलवीर सिंह ने 29 नवंबर–3 दिसंबर 2015 को श्रीलंका का दौरा किया।
- भारत–श्रीलंका वार्षिक रक्षा वार्ता (ए डी डी) में भाग लेने के लिए श्रीलंका के रक्षा सचिव, करूणासेना हेतीयारछी के नेतृत्व में एक नौ–सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 20–22 सितंबर, 2015 को नई दिल्ली का दौरा किया।
- श्रीलंका सेना द्वारा आयोजित पांचवें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा संगोष्ठी में भाग लेने के लिए भारत के राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार, श्री अरविंद गुप्ता ने 1–3 सितंबर 2015 को श्रीलंका का दौरा किया।
- विदेश सचिव ने 12–13 जनवरी 2016 को कोलंबो का दौरा किया और विदेश सचिव चित्रांगनी वागीस्वरा के साथ बातचीत के अतिरिक्त राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना, प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे, पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका भंडारनायके कुमारातुंगा, विदेश मंत्री मंगला समारावीरा, विकास कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मलिक समाराविक्रमा, नेता प्रतिपक्ष आर. संपंथन से मुलाकात की।
- वाणिज्य सचिव स्तर की चौथी वार्ता नई दिल्ली में 21 दिसंबर, 2015 को आयोजित की गई थी, जिसमें श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य मंत्रालय, टी एम केबी टेन्नाकून ने किया जो वाणिज्य सचिव रीता ए. तिवशिया के समकक्ष हैं।

'पड़ोसी पहले' सिद्धांत के अनुरूप श्रीलंका के साथ भारत के संबंध सुधर रहे हैं। 2005 से, भारत सरकार श्रीलंका के उत्तरी तथा पूर्वी प्रांतों के अवसंरचना के पुनर्निर्माण और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए भारतीय रूपए 2,300 करोड़ अनुदान के रूप में तथा भारतीय रूपए 12,960 करोड़ ऋण श्रृंखला के रूप में देने के लिए प्रतिबद्ध है। रेल तथा बंदरगाह अवसंरचना विकास, संपर्क तथा परिवहन, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आवास, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा आर्थिक पुनरूद्धार से संबंधित परियोजनाओं को तात्कालिकता की भावना से प्रारंभ किया गया है। भारत की श्रीलंका को सहयोग संबंधी फ्लैगशीप परियोजना–आवास परियोजना, भारतीय रुपए 1,372 करोड़ के अनुदान की समग्र वचनबद्धता के साथ, अच्छी प्रगति पर है और द्वितीय चरण शीघ्र पूरा होने की संभावना है। 2015 में पूरी हुई परियोजनाओं में माताले स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र, अम्पारा, मतारा, बदूल्ला तथा जाफना में भाषा प्रयोगशाला और वावूनिया में एक 200 बिस्तरों वाला वार्ड परिसर शामिल है। अन्य महत्वपूर्ण निर्माणाधीन परियोजनाओं में जाफना में एक सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण, किलीनोछी में कृषि तथा अभियांत्रिकी के संकायों की स्थापना, सामपुर में कोयला विद्युत संयंत्र की स्थापना, जाफना में दुरय्यपा स्टेडियम का पुनरूद्धार और मतारा में रूहूना विश्वविद्यालय में रविन्द्रनाथ टैगोर सभागार का निर्माण शामिल है।

द्विपक्षीय सहयोग विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर रक्षा, आर्थिक, शिक्षा, कृषि, विकास भागीदार, संस्कृति तथा लोगों का लोगों से आदान–प्रदान जारी है।

तृतीय भारत–श्रीलंका वार्षिक रक्षा वार्ता नई दिल्ली में 21–22 सितंबर 2015 तक आयोजित की गई जिसमें रक्षा सहयोग से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। नौसेना का नौसेना स्टाफ के साथ 5वीं वार्ता श्रीलंका में 2–5 सितंबर 2015 तक आयोजित की गई। भारतीय तटरक्षक का श्रीलंकाई तटरक्षक स्टाफ के साथ पहली वार्ता कोलंबो में 8–10 सितंबर 2015 तक आयोजित की गई। वायु सेना का वायुसेना स्टाफ के साथ 6ठी वार्ता 15–17 सितंबर 2015 तक श्रीलंका में आयोजित की गई। थलसेना का थलसेना स्टाफ के साथ 5वीं वार्ता 20–22 जनवरी 2016 तक भारत में आयोजित की गई। इस वर्ष भारत से थल सेनाध्यक्ष तथा नौसेनाध्यक्ष के दौरे हुए। श्रीलंका के वायुसेना कमांडर तथा रक्षा सचिव ने भारत का दौरा किया। रक्षा बलों के नियमित दौरे के आदान–प्रदान के अतिरिक्त, दोनों देशों के बीच स्टाफ वार्ता, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण तथा अभ्यास और जहाज प्रदर्शन किए गए। सद्भावना के रूप में श्रीलंका को अगस्त 2015 में भारतीय तटरक्षक जहाज वराह उपहार स्वरूप प्रदान किया गया।

दोनों अर्थव्यवस्थाओं में विकास से प्रेरित, द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश जारी है। दोनों देशों के बीच व्यापार तेजी से बढकर 2014–15 में 7.45 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया। निवेश के क्षेत्र में 2003 से लगभग 1 बिलियन अमरीकी डॉलर के संचयी निवेश के साथ भारत श्रीलंका के मुख्य विदेशी निवेशकों में से एक है। वैश्विक रूप में भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जबकि सार्क में श्रीलंका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत 2015 में सबसे बड़ा पर्यटक स्रोत रहा है। प्रमुख भारतीय कंपनियों का श्रीलंका में महत्वपूर्ण निवेश है और कई श्रीलंकाई कंपनियों ने सफलतापूर्वक भारतीय बाजार में प्रवेश कर लिया है।

कोलंबो स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के क्रियाकलापों के माध्यम से दोनो देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग बढ़े हैं। 21 जून 2015 को श्रीलंका में आईकोनिक गाले फेस ग्रीन के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। 19 नवंबर, 2015 को कोलंबो में श्रीलंका की पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका भंडारानाइके कुमारातुंगा द्वारा श्रीलंका में संगमः भारत महोत्सव, 2015–16 का उद्घाटन किया गया था।

मालदीव की विदेश मंत्री दुन्या मौमून 20–21 नवम्बर, 2015 को अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान विदेश मंत्री से मुलाकात करते हुए।

विदेश मंत्री नई दिल्ली में (07 दिसम्बर, 2015) मारीशस की राष्ट्रपति बीबी अमीना फिरदौस गुरीब – फाकिम से मुलाकात करते हुए।

शिक्षा के क्षेत्र में भारत आईटेक के तहत प्रशिक्षण तथा अन्य कार्यक्रमों द्वारा श्रीलंका के क्षमता निर्माण प्रयासों में सहयोग कर रहा है। वर्ष के दौरान, कोलंबो योजना तथा भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग योजना के तहत श्रीलंका को 200 स्लॉट दिए गए और 'ए' स्तर, अधोस्नातक, स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान स्तर पर योग्य श्रीलंकाई छात्रों को 790 छात्रवृत्तियां स्लॉट दिए गए। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को और सुदृढ करने के लिए युवा प्रतनिधिमंडलों के आदान–प्रदान के साथ सांस्कृतिक तथा लोगों का लोगों से आदान–प्रदान जारी है।

मालदीव

2015 में भारत–मालदीव के राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। 1 नवंबर 2015 को भारत–मालदीव मित्रता दिवस के रूप में मनाया गया।

भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे. पी. नड्डा ने प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में मालदीव स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। 25–27 जुलाई 2015 तक के अपने दौरे के दौरान वे मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुला यामीन अब्दुल गयूम से मिले, विदेश मंत्री दुन्या मौमून से मुलाकात की, मालदीव के स्वास्थ्य मंत्री इरूथीशैम अदाम के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और इंदिरा गांधी मेमोरियल हास्पीटल का भी दौरा किया जो कि भारत–मालदीव द्विपक्षीय सहयोग का एक फ्लैगशिप परियोजना है।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 5वें भारत–मालदीव संयुक्त आयोग के लिए 10–11 अक्टूबर, 2015 तक मालदीव का दौरा किया, जो कि 15 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित हुआ था। संयुक्त आयोग ने द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा की। विदेश मंत्री मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुला यामीन अब्दुल गयूम से मिलीं तथा स्वास्थ्य मंत्री इर्थीसाम अदाम तथा आर्थिक विकास मंत्री मोहम्मद सईद से मुलाकात की। उनके दौरे में मालदीव में रह रहे भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ मिलना भी शामिल था। दोनों देशों के विदेश सेवा संस्थानों के बीच युवा तथा क्रीड़ा तथा सहयोग के क्षेत्र में दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए।

मालदीव की विदेश मंत्री दुन्या मौमून ने 20–21 नवंबर 2015 तक भारत का आधिकारिक दौरा किया। उन्होंने विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की और दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70वें सत्र के दौरान विदेश मंत्री तथा मालदीव की विदेश मंत्री दुन्या मौमून भी (30 सितंबर, 2015) मिले।

अद्वितीय सम्मान के रूप में मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम और उनके मंत्रिमंडल के सभी वरिष्ठ मंत्रियों ने भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम, जिनका 27 जुलाई 2015 को निधन हो गया था, को श्रद्धांजलि देने के लिए संवेदना पुस्तक पर हस्ताक्षर करने के लिए माले स्थित भारतीय उच्चायोग का दौरा किया। पीपल्स मजलिस के स्पीकर अब्दुल्ला मसीह तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अब्दुल्ला सईद भी अपनी संवेदना प्रकट करने मिशन गए।

विदेश सचिव डॉ. एस. जयशंकर ने 3–4 अगस्त, 2015 तक अपने सार्क यात्रा के भाग के रूप में मालदीव का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति अहमद अदीब, विदेश मंत्री दुन्या मौमून तथा विदेश सचिव डॉ. अली नसीर से मुलाकात की। विदेश सचिव ने 11 जनवरी, 2016 को दोबारा मालदीव का दौरा किया और राष्ट्रपति यामीन, विदेश मंत्री दुन्या मौमून से मुलाकात की और विदेश सचिव डॉ. अली नसीर के साथ बातचीत की।

पर्यटन तथा संस्कृति (स्वतंत्र प्रभार) एवं नागर विमानन राज्य मंत्री, डॉ. महेश शर्मा ने यू एन डब्ल्यू टी ओ क्षेत्रीय मंत्रालयी सम्मेलन तथा प्रशांत और दक्षिण एशिया व पूर्व एशिया के लिए यू एन डब्ल्यू टी ओ आयोग की 27वीं संयुक्त बैठक में भाग लेने के लिए 3–5 जून, 2015 तक मालदीव का दौरा किया। उन्होंने भूतपूर्व पर्यटन मंत्री अहमद अदीब, उप शिक्षा मंत्री यूमना मौमून से मुलाकात की और आतिथ्य तथा पर्यटन अध्ययन हेतु भारत–मालदीव मित्रता संकाय का भी दौरा किया जहां उन्होंने मालदीव राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति से चर्चा की।

सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए मालदीव के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अहमद जुहूर ने भारत का दौरा किया। उन्होंने (9 अप्रैल, 2015) माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की तथा वे अन्य सार्क देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से भी मिले।

भारत–मालदीव संबंधों पर दिल्ली नीति समूह द्वारा आयोजित गोलमेज वार्ता में भाग लेने के लिए विदेश सचिव डॉ. अली नसीर ने 7–8 अगस्त, 2015 तक भारत का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान डॉ. अली ने विदेश मंत्री से मुलाकात की और विदेश सचिव डॉ. एस. जयशंकर के साथ भी बैठक की।

रक्षा हार्डवेयर तथा क्षमता–निर्माण सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग गहरा और विस्तृत हुआ है। भारतीय नौसेना जहाजों तथा वायुयानों द्वारा मासिक ई ई जेड सर्वेक्षण किया गया। मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (एम एन डी एफ) के 45 नौसैनिकों तथा भारतीय सेना से 45 सैनिकों ने त्रिवेन्द्रम में ईकूवेरीन 2015, एक संयुक्त भारतीय सेना–एम एन डी एफ मैरीन कोर्प प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लिया। भारतीय तट रक्षक, भारतीय नौसेना, एम एन डी एफ, श्रीलंकाई तट रक्षक तथा श्रीलंकाई नौसेना कार्मिकों ने गोवा में 19–25 अक्टूबर, 2015 तक आयोजित द्वितीय टेबल टॉप अभ्यास (टी टी ई एक्स–15) में भाग लिया, जो कि भारत, मालदीव तथा श्रीलंका के बीच हुई त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा वार्ता का नतीजा है। मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल

के लिए संयुक्त प्रशिक्षण केंद्र का फेज–1 भारत द्वारा वित्तपोषित एक परियोजना–अगस्त 2015 में पूरा हो गया और सुपुर्द कर दिया गया। भारत ने एक विमानशाला के निर्माण के लिए भी वित्तीय सहयोग दिया और भारत द्वारा दिसंबर 2013 में उपहार स्वरूप भेंट की गई दूसरे उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर रखने के लिए अतिरिक्त सुविधा प्रदान की। तटीय सर्वेक्षण प्रणाली (सी एस एस) परियोजना में तृतीय रडार का संस्थापन कार्य संपन्न किया गया और अगस्त 2015 में एम एन डी एफ को सुपुर्द कर दिया गया।

मॉरीशस

भारत और मॉरीशस के बीच घनिष्ठ राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक संबंध हैं। मॉरीशस की 70% आबादी भारतीय मूल की है। मॉरीशस वित्तीय सेवाओं का केंद्र है और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई) के लिए सबसे बड़े माध्यम के रूप में उभरा है। अफ्रीका में भारतीय निवेशों के लिए भी मॉरीशस एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत और मॉरीशस के बीच लगभग 2 बिलियन अमरीकी डॉलर का व्यापार हुआ है। समुद्री सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर घनिष्ठ रक्षा भागीदारी है।

इस अवधि के दौरान भारत–मॉरीशस भागीदारी का कार्यक्षेत्र और व्यापक तथा विस्तृत हुआ। प्रधानमंत्री सर अनिरूद्ध जगन्नाथ ने अक्टूबर 2015 में नई दिल्ली में आयोजित तृतीय भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में मॉरीशियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री ने मार्च 2015 में मॉरीशस का दौरा किया। जब वे मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि थे और कई द्विपक्षीय करारों को अंतिम रूप दिया गया। इसके बाद हाल ही में निर्वाचित मॉरीशस की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉ. श्रीमती अमीना गुरीब फाकिम का दिसंबर 2015 में भारत का आधिकारिक दौरा हुआ।

अन्य उच्च स्तरीय दौरे की श्रृंखला में निम्न शामिल थे :–

- विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज (मई 2015) जब वे विदेश मंत्री श्री सिनातांबू से मिलीं।
- प्रधानमंत्री के विशेष दूत कौशल विकास व उद्यम (आई सी) तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री राजीव प्रताप रूडी ने मॉरीशस (जुलाई 2015) का दौरा किया, जब वे राष्ट्रपति डॉ. अमीना, प्रधानमंत्री जगन्नाथ तथा विदेश मंत्री सिनातांबू से मिले।
- मॉरीशस में भारत उत्सव तथा अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए संस्कृति, पर्यटन तथा नागर विमानन राज्य मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने मॉरीशस (अगस्त 2015) का दौरा किया। वे प्रधानमंत्री जगन्नाथ, उप प्रधानमंत्री जेवियर दुवल तथा कला व संस्कृति मंत्री एस बाबू से मिले।
- 8वें अफ्रीकी–एशियाई ग्रामीण विकास संगठन (ए ए आर डी ओ) सम्मेलन में भाग लेने के लिए ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल व स्वच्छता मंत्री, भारत सरकार, श्री बिरेन्दर सिंह ने अप्रैल 2015 में मॉरीशस का दौरा किया। वे प्रधानमंत्री जगन्नाथ से भी मिले।

मॉरीशस पक्ष से अन्य उच्च स्तरीय दौरे में निम्नलिखित शामिल थे :–

- वित्त मंत्री ने श्री वी लूचमीनारायडू, वित्तीय सेवाएं व सुशासन मंत्री श्री रोशी भादौन तथा कानून मंत्री आर. येरीगाट्र के साथ जून 2015 में भारत का दौरा किया और विदेश मंत्री, वित्त मंत्री तथा आई सी टी मंत्री से मुलाकात की।
- भारत और मॉरीशस के बीच दोहरा कराधान परिहार अभिसमय के संशोधन से संबंधित संयुक्त कार्य समूह के 11वें सत्र के दौरान (जून–जुलाई, 2015) वित्त मंत्री श्री लुचमीनारायडू ने भारत का दौरा किया।
- नेशनल एसेंबली की अध्यक्ष सुश्री माया हनुमानजी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जुलाई 2015 में भारत का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और संभावित सहयोग पर चर्चा की।
- ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन पर ए ए आर डी ओ द्वारा आयोजित अध्ययन टूर में भाग लेने के लिए सामाजिक एकीकरण तथा आर्थिक सशक्तिकरण मंत्री पृथ्वीराज सिंह रूपन ने सितंबर 2015 में भारत का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल व स्वच्छता मंत्री श्री बिरेन्द्र सिंह से मुलाकात किया।
- शिक्षा व मानव संसाधन मंत्री सुश्री लीला देवी दूखन ने भोपाल में आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन (सितंबर 2015) में मॉरीशियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जहां वे माननीय विदेश मंत्री से मिलीं।
- सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता तथा सुधार संस्थान मंत्री श्रीमती एफ. दौरेयायू ने नवंबर 2015 में भारत का दौरा किया और माननीय सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्री श्री टी सी गहलोत से मुलाकात की।
- श्रम, औद्योगिक संबंध, रोजगार व प्रशिक्षण मंत्री एस. एस. कालीचरन ने दिसंबर 2015 में भारत यात्रा के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

जलीय सर्वेक्षण करने के अतिरिक्त विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ई ई जेड) के संयुक्त निगरानी तथा सर्वेक्षण करने के लिए 2015 के दौरान जिन भारतीय नौसेना तथा तटरक्षक जहाजों ने मॉरीशस का दौरा किया, में आई एन एस सर्वेक्षक (मार्च–अप्रैल 2015), आई एन एस तेग (जुलाई 2015) और आई एन एस सुजाता सहित भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण दल, आई सी जी एस वरूण तथा आई एन एस तीर शामिल हैं। दक्षिण नौसेना कमांड के

फ्लैग अधिकारी कमांडिंग इन चीफ ने भी सितंबर–अक्टूबर 2015 में मॉरीशस का दौरा किया। चीफ हाइड्रोग्राफर, वाइस एडमिरल एस के झा एवीएसएम एनएम ने जून–जुलाई 2015 में मॉरीशस का दौरा किया और जल विज्ञान संबंधी भारत–मॉरीशस संयुक्त समिति की 9वीं बैठक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिसके दौरान जल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग हेतु दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन को आगे पांच वर्ष की अवधि के लिए पुनः नवीकृत किया गया। वाइस एडमिरल झा राष्ट्रपति डॉ. अमीना तथा प्रधानमंत्री सर जगन्नाथ से भी मिले।

भा.सां.सं.प. द्वारा प्रायोजित कई सांस्कृतिक कार्यक्रम मॉरीशस में आयोजित किए गए। रामलीला पर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (नवंबर 2015) में एक मॉरीशियाई समूह ने भी भाग लिया। भारतीय सहायता से नवंबर 2015 में उर्दू स्पीकिंग यूनियन ऑफ मॉरीशस के सहयोग से तृतीय विश्व उर्दू सम्मेलन भी आयोजित किया गया।

सेशल्स

भारत–सेशल्स भागीदारी के मामले में 2015 एक विशेष वर्ष रहा, जिसमें विकास भागीदारी, क्षमता–निर्माण कार्यक्रम, समुद्री सुरक्षा सहयोग तथा सांस्कृतिक आदान–प्रदान शामिल हैं। ब्ल्यू इकोनामी, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन तथा स्वास्थ्य मुख्य रूप से उभरते क्षेत्र हैं। सेशल्स की 10% आबादी भारतीय मूल की है।

प्रधानमंत्री मोदी का सेशल्स दौरे (मार्च 2015) के कुछ महीनों के भीतर ही सेशल्स के राष्ट्रपति जेम्स एलिक्स मिशेल ने 25–27 अगस्त, 2015 तक भारत का राजकीय दौरा किया। राष्ट्रपति मिशेल ने राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री से बातचीत की, रक्षा तथा वित्त मंत्री से मिले और मुंबई का भी दौरा किया, जहां वे महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल से मिले। इस प्रतिनिधिमंडल में अन्यों के साथ–साथ विदेश मामलों तथा व्यापार मंत्री जोए मॉर्गन तथा व्यापार, वित्त तथा ब्ल्यू इकोनामी मंत्री जिन पॉल एडम भी शामिल थे। द्विपक्षीय हवाई सेवाएं, कृषि सहयोग, ब्ल्यू इकोनामी, कर सूचना आदान–प्रदान और सेशल्स को दूसरा डोर्नियर हवाई जहाज उपहार स्वरूप भेंट में देने से संबंधित पांच करारों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री ने इस यात्रा के दौरान सेशल्स को एक फास्ट इन्टर सेप्टर बोट उपहार स्वरूप देने की भी घोषणा की।

कौशल विकास व उद्यमिता (आई सी) एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री राजीव प्रताप रूडी ने प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में सेशल्स (जुलाई 2015) का दौरा किया, जहां वे राष्ट्रपति तथा विदेश मंत्री मॉर्गन से मिले। विदेश मंत्री श्री जोए मॉर्गन ने अक्टूबर 2015 में नई दिल्ली में तृतीय भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अन्य उच्च स्तरीय द्विपक्षीय दौरों में संस्कृति राज्य मंत्री डॉ. महेश शर्मा का 'भारत उत्सव 2015' तथा तृतीय सेशल्स भारत दिवस को मनाने के लिए सेशल्स (अक्टूबर 2015) का दौरा महत्वपूर्ण है। वे राष्ट्रपति मिशेल से मिले और उन्होंने अपने समकक्ष मंत्री से द्विपक्षीय वार्ता की।

विकास सहयोग के क्षेत्र में, भारत ने सार्वजनिक परिवहन बसों, दवाइयों, आई सी टी उपकरण तथा शैक्षणिक चित्रों के प्रापण के लिए 4.3 मिलियन अमरीकी डॉलर का अनुदान उपलब्ध कराया। लोगों से लोगों का संपर्क तथा यात्रा को सुगम बनाने के लिए अगस्त 2015 से सेशल्स को भारत सरकार के ई–पर्यटन वीजा योजना में शामिल कर लिया गया है। अगस्त 2015 में एक द्विपक्षीय हवाई सेवा करार पर हस्ताक्षर किए गए। एयर सेशल्स ने माहे–मुंबई सेक्टर पर मौजूदा हफ्ते में तीन बार की उड़ानों को बढाकर हफ्ते में चार बार कर दिया है।

इस अवधि के दौरान भारत–सेशल्स का सामरिक रक्षा तथा सुरक्षा सहयोग और गहरा हुआ है, विशेषकर समुद्री सुरक्षा तथा सेशल्स के व्यापक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की निगरानी के मामले में। भारतीय नौसेना तथा तटरक्षक जहाज जिसने सेशल्स का दौरा किया, उसमें आई एन एस तेग (जून 2015), संयोग से उसी समय राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा था, भारत से तीन प्रशिक्षण जहाज (आई एन एस तीर, आई एन एस सुजाता तथा आई सी जी एस वरूण) (अक्टूबर 2015) और आई एन एस दर्शक (नवंबर 2015) शामिल थे। भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग योजना के तहत सेशल्स सरकार के लिए भारतीय रक्षा कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता रहा। सोमालिया के तट से जलदस्युता हटाने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संपर्क समूह का जनवरी 2016 में सेशल्स ने अध्यक्ष पद ग्रहण किया।

29 जून, 2015 को सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीयों की अच्छी–खासी मौजूदगी थी। इसमें भारतीय नौसेना से एक टुकड़ी, एक 17–सदस्यीय नौसैनिक बैंड ने भाग लिया और 'श्वेत अश्व' नामक भारतीय सेना के मोटरसाईकल चालक दल ने प्रस्तुति की।

दिसंबर 2015 में सेशल्स में राष्ट्रपति चुनाव हुए। राष्ट्रपति जेम्स मिशेल तीसरी बार पुनः निर्वाचित हुए।

■ ■

दक्षिणी–पूर्वी एशिया और प्रशांत–एशिया

2

आस्ट्रेलिया

2014 में प्रधानमंत्री की पिछली आस्ट्रेलिया यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को गति प्राप्त हुई है। आस्ट्रेलिया विभिन्न क्षेत्रों, यथा खनिज संसाधनों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा और कौशल तथा जल संसाधन प्रबंधन के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मैलकोम टर्नबुल 15 नवम्बर, 2015 को तुर्की में जी–20 शिखर सम्मेलन के मौके पर हमारे प्रधानमंत्री से मिले और द्विपक्षीय असैनिक परमाणु सहयोग करार के अनुसमर्थन की घोषणा की। इससे आस्ट्रेलियाई कंपनियां भारत को यूरेनियम निर्यात कर पाएंगी। विदेश मंत्री जूली बिशप ने बैठक में विदेश मंत्री के साथ विदेश मंत्रियों की वार्षिक ढांचागत परिचर्चा हेतु 12–15 अप्रैल, 2015 तक यात्रा की और उन्होंने आधिकारिक तौर पर चेन्नई में आस्ट्रेलियाई कौंसुलावास का भी उद्घाटन किया।

वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की वार्षिक वार्ता 27 अक्तूबर, 2015 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। आस्ट्रेलिया, भारत एवं जापान के बीच विदेश सचिव स्तर की प्रथम त्रिपक्षीय वरिष्ठ सरकारी अधिकारी वार्ता 8 जून, 2015 को दिल्ली में हुई थी। आस्ट्रेलिया से भारत की अन्य उच्चस्तरीय यात्राओं में मि. क्रिस्टोफर पायने, शिक्षा और कौशल मंत्री की तीसरी आस्ट्रेलिया–भारत शिक्षा परिषद बैठक के लिए 22–25 अगस्त, 2015 तक की यात्रा, द्विपक्षीय रक्षा वार्ता हेतु मि. केविन एन्ड्रयूज़, रक्षा मंत्री की 01–03 सितम्बर, 2015 और महान्यायवादी जॉर्ज ब्रांडिस की 25–27 अक्तूबर, 2015

विदेश मंत्री नई दिल्ली में (14 अप्रैल, 2015 को) ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री जूली बिशप, सांसद से मुलाकात करते हुए।

तक की यात्राएं शामिल हैं। दूसरी ओर, श्री राजीव प्रताप रुड़ी ने 25–31 मई, 2015 तक सांसदों के सद्भावना शिष्टमंडल की अगुवाई की और कौशल विकास और उद्यमशीलता से संबंधित महत्वपूर्ण बैठकों के आयोजन के साथ–साथ कैनबरा में भारतीय संसदीय समूह के मित्रों के साथ परिचर्चा और विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स में राज्य सांसदों से मुलाकात की। श्री नरेंद्र सिह तोमर, इस्पात और खान मंत्री ने एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल की अगुवाई की और इस शिष्टमंडल ने 01–04 सितम्बर, 2015 तक सिडनी में एशिया प्रशांत अंतर्राष्ट्रीय खनन प्रदर्शनी में भागीदारी की। संघ सरकार के वित्तमंत्री और वरिष्ठ राजस्व कार्मिकों के साथ–साथ राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के एक समेकित शिष्टमंडल ने जी.एस.टी. को प्रतिपादित और कार्यान्वित करने में आस्ट्रेलिया के अनुभव के अध्ययन हेतु 27 सितम्बर – 03 अक्तूबर, 2015 तक सिडनी और कैनबरा की यात्रा की। द्विपक्षीय संबंधों संयुक्त कार्य समूहों (जे.डब्ल्यू.जी.)की कई बैठकों के माध्यम से विस्तार हुआ जिनमें समेकित आर्थिक सहयोग करार (सी.ई.सी.ए.) वार्ता का 7वां, 8वां तथा 9वां दौर, 9वीं ऊर्जा और खनिज संबंधी 9वें जे.डब्ल्यू.जी., संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्यगिकी समिति की बैठक और कौंसुलर, पासपोर्ट और वीज़ा मामलों की 5वीं संयुक्त कार्य समूहों की बैठकें शामिल हैं।

भारत की यात्रा हेतु मंत्री एन्ड्रयू रोब ने 10–16 जनवरी, 2015 तक 'भारत सप्ताह' नामक व्यापक कार्यक्रम के लिए 450 सदस्यों के सुदृढ़ शिष्टमंडल का नेतृत्व किया और साथ ही सी.ई.सी.ए. पर परिचर्चा और आस्ट्रेलिया–भारत नेतृत्व वार्ता में उद्घाटन–भाषण में भागीदारी हेतु तीन अतिरिक्त यात्राएं की। भारत–ऑस्ट्रेलिया सी.ई.ओ. मंच का पुनर्गठन किया गया था और इसकी बैठक 23 जून, 2015 को दिल्ली में हुई थी।

रक्षा सहयोग को 11–17 सितम्बर, 2015 तक बंगाल की खाड़ी में पहली बार आयोजित द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास 'ऑसीनडैक्स' से प्रबल प्रोत्साहन मिला। 25 जून, 2015 को कैनबरा में वार्षिक रक्षा नीति वार्ता आयोजित की गई। दोनों देशों के वायुसेना स्टाफ की चौथी वार्ता कैनबरा में 01 एवं 02 अप्रैल तक आयोजित हुईं और दोनों पक्षों के नौसेना स्टाफ की वार्ता 23–25 जून, 2015 तक सिडनी में आयोजित हुई थी। एडमिरल आर.के. धवन, सी.एन.एस. ने द्विपक्षीय वार्ता हेतु 02–07 अक्तूबर, 2015 तक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की और समुद्री शक्ति सम्मेलन 2015 में भाग लिया। भारतीय नौसेना जहाज आई.एन.एस. सतपुड़ा और आई.एन.एस. कामोरटा ने 04–08 जून, 2015 तक फ्रीमैंटल पत्तन की सद्भावना यात्रा की थी।

सांस्कृतिक मोर्चे पर, सिडनी, मेलबर्न, ब्रिसबेन, कैनबरा, पर्थ और ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर अन्य शहरों में 21 जून, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान कला और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग विषयक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के उपरांत राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली से 101 लघु पैंटिंग्स श्रृंखला में ''रामकथा'' नामक एक चित्रकला प्रदर्शनी 22 मई – 23 अगस्त, 2015 तक ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय संग्रहालय कैनबरा में लगाई गई थी। मेलबर्न स्थित ऑस्ट्रेलिया–भारत संस्थान ने ट्रेक–II प्लेटफॉर्म के रूप में प्रथम ऑस्ट्रेलिया–भारत नेतृत्व वार्ता की शुरुआत की और इसका पहला दौर दिल्ली में 25–27 अक्तूबर, 2015 तक आयोजित किया गया था।

ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के आकार और महत्व में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत से लगभग 50,000 विद्यार्थी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय में हैं और भारत को कुशल प्रवासियों के सबसे बड़े स्रोत के रूप में माना जाता है। समुदाय की बढ़ती हुई महत्ता दिवाली जैसे त्यौहारों के बड़े स्तर पर मनाए जाने से प्रदर्शित होती है और इसमें बड़ी संख्या में सभी राजनीति दलों के नेता भाग लेते हैं।

ब्रुनेई दारूसलाम

ब्रुनेई दारूसलाम के साथ द्विपक्षीय संबंध बहुत घनिष्ठ समीपता के और दोस्ताना रहे हैं और ब्रुनेई जून, 2015 तक आसियान में भारत के लिए देश समन्वयकर्ता रहा है। इसी प्रकार पिछले वर्षों में, दोनों देशों के बीच सरकारी स्तर की यात्राएं हुई हैं, जिनमें श्री ए. त्रिपाठी की अगुवाई में, भारत के राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 16 सदस्यीय शिष्टमंडल की 18–21 मई, 2015 तक की ब्रुनेई यात्रा शामिल है। शिष्टमंडल ने उप रक्षा मंत्री और ब्रुनेई के शाही सशस्त्र बल के कमांडर से मुलाकात की। इसरो की दो टीमों ने इसरो उपग्रहों के मार्ग को तय करने के संबंध में अगस्त और सितम्बर, 2015 में ब्रुनेई की यात्रा की।

ब्रुनेई के संस्कृति, युवा और खेल उप मंत्री ने 27–30 जुलाई, 2015 तक नई दिल्ली में आयोजित ''राष्ट्रमंडल युवा मंत्रियों की बैठक'' में भाग लिया। कमांड और स्टाफ पाठ्यक्रम 2015 के लिए 95 सदस्यों के एक शिष्टमंडल ने 10 मई से 17 मई, 2015 तक स्टाफ राइड की व समुद्रपार यात्रा के लिए भारत भ्रमण किया। 2012 से भारतीय सशस्त्र बलों के अधिकारियों ने नियमित रूप से स्टाफ कॉलेज, ब्रुनेई में शाही ब्रुनेई सशस्त्र बल कमांड स्टाफ पाठ्यक्रम में भाग लिया है।

आसियान–भारत विद्यार्थी आदान–प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत 15 ब्रुनेई युवकों ने 10 दिनों के लिए भारत की यात्रा की। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ेगा। वाणिज्यिक शिष्टमंडलों की विशेष तौर पर भैंसा मांस आयातक और कच्चे तेल के निर्यातकों ने कई बार ब्रुनेई से भारत की यात्राएं की थी। निर्गामी उच्चायुक्त, डॉ. अशोक कुमार अमरोही, महामहिम सुल्तान और उनकी शाही महारानी व युवराज कुमार द्वारा जनता के बीच अगवानी की गई थी।

कंबोडिया

भारत और कंबोडिया के द्विपक्षीय संबंध लगातार सौहार्दपूर्ण, दोस्ताना और लगातार सुदृढ़ होते रहे हैं। भारत और कंबोडिया के बीच पुरातन समय से घनिष्ठ सभ्यतामूलक व सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, जो कि आज भी विद्यमान हैं। हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु, माननीय उपराष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी ने कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन सेन के निमंत्रण पर 15–17 सितम्बर, 2015 तक कंबोडिया जाने वाले एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल की अगुवाई की और कंबोडियन प्रधानमंत्री से विचार–विमर्श किया तथा कंबोडियन राष्ट्रीय सभा और कंबोडियन सीनेट के अध्यक्षों से मुलाकात की। यात्रा के दौरान पर्यटन सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन और मेकांग गंगा सहयोग पहल के अंतर्गत क्विक इम्पैक्ट (त्वरित प्रभाव) परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय अनुदान सहायता संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए गए।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और कृषि तथा कौशल विकास से संबंधित पांच त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के लिए 50,000 अमरीकी डॉलर की अनुदान सहायता की भी घोषणा की गई थी। कामपोंग चाम क्षेत्र में भारत–कंबोडिया मैत्री स्कूल के नवीनीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया था और उपराष्ट्रपति द्वारा कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन सेन को एक प्रमाण–पत्र सौंपा गया था। उपराष्ट्रपति द्वारा आईसीसीआर छात्रवृत्तियों की संख्या वर्तमान 17 से बढ़ाकर 28 करने की घोषणा भी की गई थी और विशिष्ट यात्रियों के कार्यक्रम के अंतर्गत दो कंबोडियाई बौद्ध भिक्षु/विद्वानों की अगवानी की पेशकश की। उपराष्ट्रपति और शिष्टमंडल ने विश्व विरासत स्थलों अंकोरवाट और ता–प्रोम मंदिर की भी यात्रा की और उन्होंने कंबोडियाई पक्ष को यह भी सूचित किया कि भारत ता–प्रोम मंदिरों के तीसरे चरण की शुरुआत करेगा। ता–प्रोम मंदिरों के संरक्षण और पुनरुद्धार कार्य के प्रथम और द्वितीय चरण को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जुलाई, 2015 में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया था।

वर्ष 2014 में भारत को प्रिय विहार से संबंधित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति (आईसीसी) का सह–अध्यक्ष नियुक्त किया। प्रिय विहार विश्व विरासत स्थल है और वहां भगवान शिव का प्राचीनतम मंदिर है और वह तीर्थस्थान भी है। 06 सितम्बर, 2015 को आईसीसी प्रिय विहार के प्रथम तकनीकी सत्र की सह–अध्यक्षता भारत ने की थी।

प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए, दूतावास ने कंबोडियाई पर्यटन मंत्रालय, नोम पेन्ह नगरपालिका, जो अंकोरवाट और सीएम रीप क्षेत्र (अपसारा) के संरक्षण और प्रबंधन से संबद्ध प्राधिकरण है और कंबोडिया के युवा संघ के साथ सहयोग करके नोम पेन्ह में रॉयल (शाही) महल, सीएम रीप में अंकोरवाट मंदिर और सिहानोयूक विली में शेखा बीच रिसोर्ट के सामने 21 जून, 2015 को बड़े स्तर पर योग कार्यक्रम आयोजित किया।

भारत ने विभिन्न क्षेत्रों और क्षमता संवर्धन में कंबोडिया को अपनी सहायता जारी रखी थी। इस वर्ष कंबोडियाई सरकार द्वारा मैसर्स

उप राष्ट्रपति, श्री हामिद अंसारी ने कंबोडिया के प्रधानमंत्री, हुन सेन के साथ नोम पेन्ह कंबोडिया में (16 सितम्बर 2015) में मुलाकात की।

वाप्कोस लिमिटेड को अवसंरचना विकास, बांध निर्माण, स्टंग टासाल विकास परियोजना का स्पिल वे और हाइड्रोमैट्रिकल कार्य पूरा करने का पूर्ण प्रमाण–पत्र जारी किया गया था। लगभग 3 मिलियन अमरीकी डॉलर की भारतीय अनुदान सहायता के अंतर्गत, मैसर्स वाप्कोस लिमिटेड वर्तमान में दो जल विकास योजनाओं (क) सीएम रीप बेसिन दृ महायोजना का विकास और (ख) कामपोंग स्पीयू क्षेत्र का भूजल संसाधन अध्ययन पर कार्य कर रही है। इन दो परियोजनाओं का कार्य, जो कि 2014 में शुरू हुआ था, तेजी से चल रहा है और 2017 तक पूर्ण होगा।

आईटीईसी के अंतर्गत कंबोडियाई लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था सुचारू ढंग से हुई है। 1981 में कंबोडिया में आईटीईसी कार्यक्रमों की शुरुआत से आज की तारीख तक, इन कार्यक्रमों से 1200 कंबोडियाई नागरिकों को लाभ पहुंचा है। आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में और अधिक जागरुकता बढ़ाने हेतु दूतावास ने 27 अक्तूबर, 2015 को आईटीईसी दिवस मनाया।

मॉड्यूल में शाही कंबोडियाई सशस्त्र बलों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण कैप्सूल हेतु 21 सितम्बर, 2015 से 04 अक्तूबर, 2015 तक भारतीय सैना से प्रतिनियुक्ति पर विशेषज्ञ भेजे गए जो प्रशिक्षणार्थियों को शांति बनाए रखने और बारूदी सुरंग नष्ट करने का प्रशिक्षण देते थे। इस प्रकार रक्षा क्षेत्र में भारत–कंबोडिया सहयोग जारी रहा। आईटीईसी छात्रवृत्ति के अंतर्गत भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों में कंबोडियाई रक्षा बलों के सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करना जारी है।

एक निर्देशित मिसाईल संहारक, आईएनएस रणवीर और एक पनडुब्बी रोधी जंगी जहाज आईएनएस 'कामोरटा', ने 23–27 जून, 2015 तक सीहानोयूक विली बंदरगाह, कंबोडिया की पांच दिवसीय सद्भावना यात्रा की। इसमें शाही कंबोडियाई नौसेना के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास और स्थानीय समुदायों के लिए एक चिकित्सा कैंप लगाना शामिल है। एक भारतीय तट रक्षक जहाज 'सम्राट' ने 07–10 नवम्बर, 2015 तक सीहानोयूक विली बंदरगाह, कंबोडिया की सद्भावना यात्रा की और शाही कंबोडियाई नौसेना के साथ भी अभ्यास किया।

भारत और कंबोडिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है। मिलर्टक, गुजरात उद्योग फेडरेशन, भारत के स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों के व्यापारिक शिष्टमंडल और भारत के निजी उद्योग/कंपनियों से कई प्रतिनिधियों ने कंबोडिया की यात्रा की। इनके लिए दूतावास ने स्थानीय प्रतिपक्ष के साथ मिलकर व्यापार हेतु कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

इंडोनेशिया

वर्ष 2015 में कई उच्चस्तीय राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनसे हमारे संबंधों को पुनर्जीवित करने में मदद मिली है और द्विपक्षीय संबंधों को आवश्यक गति मिली है। श्री एम हामिद अंसारी, भारत के उपराष्ट्रपति ने 1–4 नवम्बर, 2015 तक इंडोनेशिया की यात्रा की। उपराष्ट्रपति ने इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति श्री जोको विडोडो तथा वहां के उपराष्ट्रपति मि. जूसुफ कल्ला और बाली के राज्यपाल श्री आई मेड मंगकू पास्टीका से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने उदयन विश्वविद्यालय, बाली में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया। यात्रा के दौरान संस्कृति, नवीकरणीय ऊर्जा और बाली में चिकित्सा संकाय में आयुर्वेद पीठ की स्थापना के लिए, तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे। अपनी यात्रा के दौरान माननीय उपराष्ट्रपति ने सुश्री मेधावती सुकर्णोपुत्री, इंडोनेशिया की भूतपूर्व राष्ट्रपति और सत्तारूढ़ पीडीआईपी की अध्यक्ष और इंडोनेशिया में मुस्लिम सिविल सोसाईटी संगठनों के सदस्यों के साथ भी बातचीत की।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 21–24 अप्रैल, 2015 के दौरान 60वें एशिया–अफ्रीका सम्मेलन स्मरणोत्सव में भागीदारी हेतु जकार्ता की यात्रा की। विदेश मंत्री ने एएसीसी के अवसर पर इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति मि. जूसुफ कल्ला और इंडोनेशिया की भूतपूर्व राष्ट्रपति और सत्तारुढ़ पीडीआईपी सुक्षी मेघावती सुकर्णोपुत्री से मुलाकात की। जनरल (सेवानिवृत्त) विदेश राज्य मंत्री, श्री विजय कुमार सिंह ने जकार्ता में 60वीं एएसीसी की मंत्रालयी स्तर की बैठक में भागीदारी हेतु इंडोनेशिया की यात्रा की और इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया गणराज्य की विदेश मंत्री सुश्री रिटनो लेसतारी प्रियनसारी मार्सूदी से वार्ता की। विदेश राज्य मंत्री ने पुनः पदांग, इंडोनेशिया की यात्रा की और 23 अक्तूबर, 2015 को आईओआरए मंत्रियों की परिषद की बैठक में भाग लिया।

17 दिसम्बर, 2015 को जकार्ता में तृतीय विदेश कार्यालय विचार–विमर्श का आयोजन किया गया था जिसके दौरान आपसी हितों के अनेक द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया था। भारतीय शिष्टमंडल की अगुवाई श्रीमती मोनिका कपिल मोहता, अपर सचिव (दक्षिण) द्वारा की गई थी। आतंकवाद विरोध और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध संबंधी संयुक्त कार्य समूह ने 27 अक्तूबर, 2015 को जकार्ता में बैठक की।

वर्ष के दौरान इंडोनेशियाई पक्ष की ओर से प्रमुख यात्राओं में संसदीय शिष्टमंडलों की यात्राएं, प्रतिनिधि सभा के उपाध्यक्ष (डीपीआर) डॉ. फदली जॉन की यात्रा, पीपुल्स कंसलटेटिव एसेंबली (एमपीआर), क्षेत्रीय प्रतिनिधि परिषद (डीपीडी) और लोक प्रतिनिधि सभा (डीपीआर) की यात्राएं शामिल हैं। इंडोनेशिया गणराज्य के शिक्षा और संस्कृति मंत्री, मि. अनीस बासवेडन ने अक्तूबर, 2015 में भारत की यात्रा की।

वर्ष 2015 में भारत–इंडोनेशिया रक्षा सहयोग में महत्वपूर्ण गुणात्मक

और मात्रात्मक वृद्धि हुई है। इस वर्ष सेना से सेना स्टाफ की चौथी वार्ता और नौसेना स्टाफ की 7वीं वार्ता का आयोजन करके परिचालन, प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन के क्षेत्र में सहयोग किया गया था। साझा हित के हमारे समुद्री भाग में समन्वित नौसेना द्वारा दो बार और सीआई/सीटी पर तीसरा संयुक्त सेना अभ्यास 'गरुण शक्ति' किया गया था। भारत–इंडोनेशिया द्वि पक्षीय नौसेना अभ्यास का उद्घाटन सत्र पहले से मजबूत हमारे नौसेना सहयोग में एक महत्वपूर्ण सोपान सिद्ध हुआ। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल द्वारा संपूर्ण इंडोनेशियाई द्वीप समूहों के बंदरगाहों की यात्रा और इंडोनेशियाई नौसेना जहाजों द्वारा भारतीय नौसेना एवं तटरक्षकों द्वारा जहाजों की यात्राओं को बढ़ा कर कार्मिकों के बीच व्यावसायिक वार्ता जारी रखी गई।

प्रारंभ में दोनों सेनाओं के बीच पेशेवर प्रशिक्षण में सर्वोत्तम पद्धतियों की साझेदारी के साथ–साथ पारस्परिक आधार पर प्रशिक्षक और कैडेट विनिमय कार्यक्रम से हमारे कार्मिकों के बीच व्यक्तिगत संबंध सुदृढ़ हुए हैं। दोनों देशों की सेना बलों के शिष्टमडलों ने दोनों देशों की महत्वपूर्ण रक्षा प्रदर्शनियों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं में भाग लिया। आईटीईसी योजना के अंतर्गत प्रस्तावित बहुसंख्य रिक्तियों को भरते हुए इंडोनेशियाई सशस्त्र बलों के साथ प्रशिक्षण में नियमित आदान–प्रदान जारी रहा और हमारे अधिकारियों ने इंडोनेशिया में स्टाफ पाठ्यक्रमों में भाग लेना जारी रखा।

जनवरी–सितम्बर, 2015 (अनंतिम आकड़े उपलब्ध हैं) की अवधि में इंडोनेशिया के साथ भारत का व्यापार 11 बिलियन अमरीकी डॉलर था जिसमें 8.9 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य की वस्तुओं का आयात और 2.1 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात शामिल है। आयात की मुख्य मदों में कोयला, पाम ऑयल, मोती, पत्थर, आभूषण, रबड़, लोहा और स्टील शामिल हैं। भारत ने इंडोनेशिया को ऑर्गेनिक केमिकल्स, मशीनरी, वाहन, ऑयल सीड, खनिज ईंधन, कॉटन (कपड़ा) इत्यादि का निर्यात किया।

3 नवम्बर, 2015 को, भारत के उपराष्ट्रपति की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान, एक 33 सदस्यीय विशिष्ट शक्ति प्राप्त भारतीय शिष्टमंडल, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारतीय कंपनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधि और भारतीय वाणिज्य चैंबर के सदस्य शामिल थे, ने इंडोनेशियाई व्यापार संगठनों के साथ विचार–विमर्श किया। बहासा इंडोनेशिया में स्थानीय व्यापारियों और इंडोनेशियाई वाणिज्य एवं उद्योग चैंबर के प्रतिनिधियों के बीच भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल से संबंधित सी डी का वितरण किया गया।

स्वास्थ्य, कृषि और कोयले के क्षेत्र मे संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) के स्तर पर विचार–विमर्श किया गया जिसमें महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई। वर्ष के दौरान सरकार से सरकार के महत्वपूर्ण विचार–विमर्श में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और उपभोक्ता मामले, खादय और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के शिष्टमंडल ने जकार्ता की यात्रा की और कृषि मंत्रालय से इंडोनेशियाई शिष्टमंडल द्वारा भारत की यात्रा की गई।

15 सदस्यीय सीआईआई की अगुवाई में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और भारतीय कंपनियों के वरिष्ठ कार्यपालकों वाले उच्चस्तरीय व्यापारिक शिष्टमंडल, ने अप्रैल, 2015 में जकार्ता की यात्रा की। लघु और मध्यम उद्यम का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की 35 कंपनियों के एक समूह ने 4–6 नवम्बर, 2015 तक जकार्ता कन्वेंशन सेंटर पर 'कॉन्स्ट्रक्सी इंडोनेशिया 2015' में भाग लिया था।

जकार्ता स्थित मिशन और मेदान और बाली में इसके कौंसुलेट द्वारा 26 जनवरी से 15 अगस्त, 2015 तक जकार्ता में भारत महोत्सव का आयोजन किया गया था। यह लोगों के पारस्परिक संपर्क का एक बृहद कार्यक्रम था जिसमें संपूर्ण इंडोनेशिया के 18 विभिन्न शहरों में 35 विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और इसे इंडोनेशियाई सोसाईटी के विभिन्न खंडों में उत्साहपूर्ण रूप में स्वीकार किया गया। 21 जून, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था। इंडोनेशिया में जकार्ता, बाली, मेदान और सूराबया में और दिली में तिमोर लेस्ते में कार्यक्रम आयोजित किए गए और इसमें 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया।

लाओ पीडीआर

इस वर्ष में लाओं पीडीआर के साथ द्विपक्षीय संबंधों में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है। सिंचाई प्रणाली, विद्युत संचरण, क्षमता संवर्धन की अवसंरचना परियोजनाओं के क्षेत्र में और मानव संसाधन और विरासत स्मारक के पुनरुद्धार में सांस्कृतिक सहयोग और उच्चस्तरीय यात्रा में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। इसके अतिरिक्त 100–150 छात्रवृत्तियां लाओ विद्यार्थियों और तकनीकी कार्मिकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भारत में नियमित पाठ्यक्रम करने के लिए प्रदान की गई थी।

इस वर्ष 17–18 सितम्बर, 2015 तक प्रथम बार भारतीय उपराष्ट्रपति ने लाओ पीडीआर की यात्रा की। उपराष्ट्रपति श्री हामिद एम. अंसारी ने विएनटियाने में मि. बोननहैंग वोराचिट से मुलाकात की और आपसी हितों के द्विपक्षीय मुद्दों के साथ–साथ आसियान और एमजीसी ढांचे के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा की। विचार–विमर्श आर्थिक और व्यापारिक संबंध सुदृढ़ करने पर केन्द्रित था। उप राष्ट्रपति ने लाओस के राष्ट्रपति श्री चौमाली सायासोने से मुलाकात की तथा उन्होंने लाओस के प्रधानमंत्री श्री थोंगसिंग थम्मानोंग उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री श्री थोंगलुन सिसोलिथ तथा नेशनल असेम्बली के वाइस प्रेसीडेंट श्री क्यासोम्फोन फोमविहाने से भी मुलाकात की।

भारत और लाओ लोकतांत्रिक गणराज्य (लाओस पीडीआर) के बीच 8वीं संयुक्त बैठक 10 अगस्त, 2015 को नई दिल्ली में हुई। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज तथा लाओ पीडीआर के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री श्री थोंगलुन सिसोलिथ ने दो शिष्टमंडलों का नेतृत्व किया। द्विपक्षीय संबंधों के सभी आयामों पर विचार–विमर्श किया गया और भावी सहयोग के क्षेत्रों की प्राथमिकता तय की।

भारत और लाओ पीडीआर के बीच विदेश कार्यालय स्तरीय दूसरा विचार–विमर्श 10 अगस्त, 2015 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ जिसमें श्री अनिल वाधवा, सचिव (पूर्व) भारतीय पक्ष का नेतृत्व कर रहे थे जबकि लाओ पक्ष का नेतृत्व लाओस पीडीआर के विदेशी मामलों के उप मंत्री श्री सेलुमक्से कोमोसिथ कर रहे थे।

श्री भारत के राजदूत श्री रवि शंकर ऐसोला ने 10 सितम्बर, 2015 को लाओ पीडीआर के राष्ट्रपति चौमली सायासोने को अपना प्रत्यय–पत्र प्रस्तुत किया ।

फिक्की द्वारा तैयार किए गए बहुक्षेत्रीय शिष्टमंडल ने 9–12 दिसम्बर, 2015 तक लाओ पीडीआर का दौरा किया। इसके बाद उप राष्ट्रपति ने दोनों देशों के व्यापारिक सेक्टरों के बीच गहन विचार–विमर्श की आवश्यकता के संबंध में आश्वासन दिया ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार के स्तर में वृद्धि की जा सके।

आईसीसीआर द्वारा प्रायोजित तथा सुश्री पिनाज मसानी की अध्यक्षता में 12 सदस्यों वाली नृत्य और संगीत मंडली ने वियतनाम का दौरा किया तथा 15 और 16 अगस्त, 2015 को दो कार्यक्रमों का प्रस्तुतीकरण किया।

मलेशिया

मलेशिया के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध परंपरागत मैत्री और सौहार्द पर आधारित हैं और विवेच्य अवधि में इस दिशा में प्रगति व विस्तार जारी रहा। मलेशिया के प्रधानमंत्री महामहिम दातो श्री मोहम्मद नजीब तुन अब्दुल रज्जाक के निमंत्रण पर प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 नवम्बर, 2015 को मलेशिया का सरकारी दौरा किया। पहले भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 21–22 नवम्बर, 2015 तक आशियान–भारत शिखर सम्मेलन तथा पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। इन दोनों प्रधान मंत्रियों ने पुत्राजया में आधिकारिक वार्ता की तथा ब्रिकफील्ड्स, कुआलालम्पुर में तोरणद्वार का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया जो भारत–मलेशिया मैत्री के प्रतीक के रूप में मलेशिया को भारत की ओर से दिया गया एक उपहार है। इस दौरे के बाद अधिकाधिक रणनीतिक भागीदारी के लिए एक संयुक्त बयान जारी किया गया ताकि दोनों देशों द्वारा वर्ष, 2010 में की गई रणनीतिक भागीदारी को आगे बढ़ाया जा सके। दोनों प्रधान मंत्रियों ने मौजूदा क्षेत्रों में सहयोग को घनिष्ठ बना कर तथा सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज कर राजनीतिक भागीदारी को अगले स्तर तक ले जाने के अपने संकल्प को दोहराया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने वर्ष 2015–2020 के लिए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम करार तथा परियोजना हस्तांतरण तथा निगरानी, तथा साइबर सुरक्षा में सहयोग से संबंधित दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आरसीईपी अन्तर्सत्रीय मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए 12–14 जुलाई, 2015 तक मलेशिया का दौरा किया। उन्होंने अपने मलेशियाई समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। एशियाई आर्थिक मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए उन्होंने 23 और 24 अगस्त, 2015 को मलेशिया का फिर से दौरा किया। भारत–मलेशियाई सीईओ की 7वीं बैठक उनके दौरे के दौरान आयोजित की गई। विदेश राज्य मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह ने आशियान–भारत विदेश मंत्रियों की 13वीं बैठक, पूर्वी एशियाई विदेश मंत्रियों की 5वीं शिखर बैठक और आशियान क्षेत्रीय फोरम की 22वीं बैठक में भाग लेने के लिए 4–7 अगस्त, 2015 तक मलेशिया का दौरा किया। राज्य मंत्री (वीकेएस) ने मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री अनिफाह हाजी अमन से द्विपक्षीय बैठक की। राज्य मंत्री (वीकेएस) ने आशियान–इंडिया सेंटर, नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटिजिक एंड इन्टरनेशनल स्टडीज (आईएसआईएस), मलेशिया द्वारा कुआलालम्पुर में आयोजित आशियान–इंडिया थिंक टैंक नेटर्वक के मलेशिया के माननीय उप विदेश मंत्री दातुक सेरी रीजाल मेरिकन नैना मेरिकन के साथ संयुक्त रूप से चौथे दौरे का उद्घाटन किया। माननीय रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर ने 3–4 नवम्बर, 2015 तक कुआलालमपुर में आयोजित होने वाली एशियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (एडीएमएम प्लस) के लिए भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने अपने मलेशियाई समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक की। निर्माण उद्योग विकास बोर्ड (सीआईडीबी) के आमंत्रण पर उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण और सिंचाई मंत्री श्री शिव पाल सिंह यादव की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग के 5 सदस्यीय शिष्टमंडल ने 27–29 अप्रैल, 2015 तक कुआलालम्पुर का दौरा किया ताकि उत्तर प्रदेश की रिवर फ्रंट विकास परियोजनाओं में मलेशियाई कंपनियों द्वारा किए जाने वाले निवेश के बारे में पता लगाया जा सके। अरूणाचल प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री श्री चौना मेन की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय शिष्टमंडल ने 4–7 सितम्बर, 2015 तक मलेशिया का दौरा किया तथा ऑयल पाम तथा रबड़ बगानों का दौरा किया । राजस्थान के लोक निर्माण विभाग और परिवहन मंत्री श्री युनुस खान के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के 4 सदस्यीय शिष्टमंडल ने 16–19 दिसंबर, 2015 तक मलेशिया का दौरा किया। राजस्थान सरकार के शिष्टमंडल ने प्रमुख निवेशकों की राजस्थान की भावी राजमार्ग परियोजनाओं में सहभागिता के बारे में विचार करने के लिए उनके साथ बैठकें आयोजित की।

श्री देवेन्द्र चौधरी, सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने 28–29 सितम्बर, 2015 तक कुआलालम्पुर में लोक प्रशासन और शासन के संबंध में आयोजित तीसरी बैठक में भाग लिया। सड़क, परिवहन और राजमार्ग सचिव श्री विजय छिब्बर के नेतृत्व में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तीन सदस्यीय शिष्टमंडल ने 12–14 अप्रैल, 2015 तक मलेशिया का दौरा किया और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवेलपमेंट बोर्ड (सीआईडीबी), मलेशिया द्वारा कुआलालम्पुर में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के संबंध में आयोजित एक सम्मेलन में भाग लिया। वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अपर सचिव श्री आर. आर. रश्मि के नेतृत्व में दो–सदस्यीय शिष्टमंडल ने कुआलालमपुर में 7–8 मई, 2015 तक प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देशों (एएनआरपीसी) की असेम्बली के एसोसिएशन के विशेष सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

निर्माण कार्य मंत्री वाई बी दातो, उप निर्माण कार्य मंत्री हाजी फादीलाह बिन हाजी युसुफ ने भारतीय निर्माण और राजमार्ग परियोजनाओं में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए एक शिष्टमंडल के साथ 12–16 अक्तूबर तक भारत का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने श्री वेंकैया नायडू, शहरी विकास मंत्री, श्री नितिन गडकरी, सड़क, राजमार्ग और परिवहन मंत्री और और श्रीमती निर्मला सीतारमण, वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के साथ बैठकें कीं। उन्होंने राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया और राजस्थान के लोक निर्माण तथा परिवहन मंत्री श्री यूनुस खान से भी मुलाकात की। मलेशियाई शिष्टमंडल ने श्री अमित मित्रा, अर्थव्यवस्था मंत्रालय, पश्चिम बंगाल से अलग से मुलाकात की। मलेशिया सरकार के लोक सेवा विभाग के महानिदेशक तान श्री मोहम्मद जाबिदी जैनाल के नेतृत्व में एक मलेशियाई शिष्टमंडल ने 6–12 दिसंबर, 2015 तक भारत का दौरा किया। इस शिष्टमंडल ने हैदराबाद और बेंगलुरू का दौरा किया। श्री देवेंद्र चौधरी, सचिव प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग ने 10 दिसंबर, 2015 को नई दिल्ली में इस मलेशियाई शिष्टमंडल का स्वागत किया ताकि उस कार्य योजना पर चर्चा की जा सके जिन पर सितम्बर, 2015 में कुआलालम्पुर में आयोजित संयुक्त कार्यसमूह की तीसरी बैठक में परस्पर सहमति बनी थी। निर्माण कार्य मंत्रालय के महासचिव दातो श्री जोहरी बिन अकोब के नेतृत्व में 6 सदस्यीय शिष्टमंडल ने श्री विजय छिब्बर, सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निमंत्रण पर 6–10 जून, 2015 तक नई दिल्ली और राजस्थान का दौरा किया।

एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने 6–9 दिसम्बर, 2015 तक कुआलालम्पुर में द्वितीय दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशियाई रक्षा स्टाफ के अध्यक्षों के साथ विचार–विमर्श में भाग लिया जिसमें उन्होंने व्यापक प्रतिरक्षा और सुरक्षा सहयोग पर मलेशियाई समकक्ष से विचार–विमर्श किया।

न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड के साथ भारत का संबंध अनेक क्षेत्रों जैसे आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क तथा क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर आगे बढ़ता रहा। विदेशी कार्यालय परामर्श (एफओसी) 8 अप्रैल, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित किए गए। भारतीय पक्ष का नेतृत्व श्री अनिल वाधवा, सचिव (पूर्व) ने किया जबकि सुश्री एन्ड्रूया स्मिथ, उप सचिव (एशिया और अमेरिका समूह) ने न्यूजीलैंड पक्ष का नेतृत्व किया। माननीय कौशल विकास, उद्यमिता और संसदीय कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राजीव प्रताप रूडी के नेतृत्व में एक सद्भावना संसदीय शिष्टमंडल ने 1–3 जून, 2015 तक न्यूजीलैंड का दौरा किया ताकि दोनों देशों की संसदों के बीच संबंधों को मजबूत बनाया जा सके। इस शिष्टमंडल ने न्यूजीलैंड में व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास संबंधी सुविधाय भारत–न्यूजीलैंड आर्थिक तथा वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत बनाने की संभावना तथा स्थानीय भारतीय समुदाय से विचार–विमर्श करने के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए इस अवसर का उपयोग किया।

दूसरी ओर, न्यूजीलैंड के न्याय, न्यायालय, प्रसारण तथा संचार मंत्री सुश्री एमी आदम्स ने 20–25 सितम्बर, 2015 तक भारत का दौरा किया ताकि स्वच्छ प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट सिटीज और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी में भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार और उद्यम को बढ़ावा दिया जा सके।

भारतीय उच्चायोग, वेलिंगटन द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री जॉन की द्वारा 17 अक्तूबर, 2015 को आकलैंड में दीवाली मनाई गई। न्यूजीलैंड की संसद ने भी 10 नवम्बर, 2015 को दीवाली मनाया जिसकी मेजबानी एथनिक समुदाय मंत्री ने की जिसमें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री मुख्य वक्ता थे।

फिलीपींस

इस अवधि के दौरान भारत–फिलीपींस संबंध मजबूत होता रहा। द्विपक्षीय सहयोग विषयक अर्द्धवार्षिक संयुक्त आयोग, जो द्विपक्षीय सहयोग हेतु उच्चतम संस्थागत तंत्र है, का तीसरा संस्करण 14 अक्तूबर, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज तथा फिलीपींस के विदेश सचिव श्री अल्बर्ट एफ. डेल रोसारिया ने बैठक की सह–अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने वर्ष 2016–2018 के लिए सांस्कृतिक विनिमय के द्विपक्षीय निष्पादक कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए तथा भारत–फिलीपींस प्रत्यर्पण संधि के अनुसमर्थन के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए।

अन्य अनेक मंत्रियों और कर्मचारियों का दौरा जारी रहा। अरूणाचल प्रदेश के मंत्री (कृषि, बागवानी, एएच, वेटी और डीडी आदि) ने 31 अगस्त – 1 सितम्बर, 2015 तक फिलीपींस की

यात्रा की और चावल उत्पादन की प्रौद्योगिकी के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का दौरा किया। फिलीपींस के विदेश विभाग में विदेश नीति के अवर सचिव श्री इवान पी गार्सिया ने आशियान–भारत प्रख्यात व्यक्ति व्याख्यान श्रृंखला के तहत 15–17 जुलाई, 2015 तक भारत का दौरा किया।

आई एन एस सहयाद्रि के 01–04 नवम्बर, 2015 तक मनीला की सद्भावना यात्रा, से प्रतिरक्षा सहयोग मजबूत होता रहा; एचसीएस बिष्ट, भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक ने एशियाई तटरक्षक एजेसियों के अध्यक्षों की 11वीं बैठक के लिए 04–06 मई, 2015 तक मनीला का दौरा किया; भारतीय प्रतिरक्षा प्रबंधन कालेज के 26 सदस्यीय शिष्टमंडल ने 25–31 नवम्बर, 2015 तक फिलीपींस का दौरा किया; तथा आर्म्ड फोर्सेज ऑफ फिलीपींस कमांड एंड जनरल स्टाफ कालेज (एएफपीसीजीएससी) के 34 सदस्यीय शिष्टमंडल ने 30 अगस्त से 05 सितम्बर, 2015 तक भारत का दौरा किया।

वैश्विक मंदी के बावजूद वित्त वर्ष 2015–16 की प्रथम छमाही के दौरान भारत और फिलीपींस के बीच व्यापारिक संबंध 1.8 बिलियन अमेरिकी डालर पर बना रहा और व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में बना रहा। फिलीपींस में भारतीय निवेश बड़ी संख्या में प्रमुख भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और फर्मों में है जो आईटी समर्थित सेवाओं और सामान्य सेक्टरों में अच्छा कार्य करती रहीं। भारतीय निवेश की नई प्रवृत्ति, अवसंरचना, ओटोमोबाइल, नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि जैसे सेक्टरों में देखने को मिली है। भारतीय कंपनी 'प्रसाद सीड्स' ने जुलाई, 2015 में फिलीपींस में 10 मिलियन अमेरिकी डालर से कार्न सीड फैसिलिटी खोली। एसोचाम के तत्वावधान में 50 भारतीय कंपनियों ने 9–12 सितम्बर, 2015 तक एशिया फूड एक्सपो में भाग लिया। एआईसीसी, तूतीकोरिन के 12 सदस्यीय शिष्टमंडल ने नवम्बर, 2015 में गवेषण के प्रयोजनार्थ फिलीपींस का दौरा किया।

आईसीसीआर द्वारा प्रायोजित छह सदस्यीय ओडिशी नृत्य मंडली ने नंदिनी घोषाल के नेतृत्व में जून, 2015 में फिलीपींस का दौरा किया तथा 27 जून, 2015 को एशिया प्रशांत कालेज, मकाटी, मनीला में तथा 28 जून, 2015 को दावोस मेडिकल स्कूल फाउंडेशन ओडिटोरियम में कार्यक्रमों का प्रस्तुतीकरण किया। पांच सदस्यीय संगीत मंडली क्रासविंड्ज ने 19–22 नवम्बर, 2015 तक फिलीपींस का दौरा किया तथा मनीला में कार्यक्रम प्रस्तुत किए। आशियान–भारत छात्र विनिमय कार्यक्रम के तहत फिलीपींस के 17 छात्रों ने 25 अक्तूबर – 03 नवम्बर, 2015 तक भारत का दौरा किया। फिलीपींस के विभिन्न मेडिकल संस्थानों में भारतीय छात्रों द्वारा दाखिला लेने की संख्या बढ़ती रही।

सिंगापुर

सिंगापुर के साथ हमारे राजनयिक संबंध स्थापित होने की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर 23 और 24 नवम्बर, 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान सिंगापुर के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक भागीदारी के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई प्राप्त हुई।

प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 और 24 नवम्बर, 2015 को सिंगापुर की सरकारी यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग के साथ रणनीतिक भागीदारी की एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया जिसमें सहयोग और पारस्पारिक हित के क्षेत्रों का उललेख किया गया था। प्रतिरक्षा, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, स्वापक तस्करी, शहरी आयोजना, नागर विमानन और संस्कृति के क्षेत्र में नौ द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। राजनीतिक संबंध स्थापित होने के 50 वर्ष पूरा होने पर दोनों प्रधान मंत्रियों द्वारा दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के भवनों को दर्शाने वाले स्मारक टिकट जारी किए गए।

वित्त, कारपोरेट मामलों और सूचना प्रसारण मंत्री श्री अरूण जेटली ने 18–19 सितम्बर, 2015 तक सिंगापुर की यात्रा की। उन्होंने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग तथा विदेश मंत्री और विधि मंत्री श्री के. शानमुगम से मुलाकात की। उन्होंने सिंगापुर शिखर सम्मेलन में ''भारत : वैश्विक स्तर पर चुनौतियों से भरे समय में अवसरों का स्वर्ग'' विषय पर बातचीत की तथा निवेशकों के साथ मुलाकात की। सिंगापुर सरकार के साथ विश्व बैंक द्वारा आयोजित किए गए अवसंरचना वित्त शिखर सम्मेलन, 2015 में प्रमुख वक्ता के रूप में भाग लेने के लिए रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने भी सिंगापुर की यात्रा की ताकि अवसंरचना के वित्त पोषण में भारतीय रेलवे के अनुभवों को साझा कर सकें। सिंगापुर की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरा होने के अवसर पर 9 अगस्त, 2015 को सिंगापुर में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में श्री अनंत गीते, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री ने भाग लिया। पर्यटन (स्वतंत्र प्रभार) संस्कृति (स्वतंत्र प्रभार) और नागर विमानन मंत्री डॉ महेश शर्मा ने राजनयिक संबंध स्थापित होने की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर एशियाई सभ्यता संग्रहालय में श्ट्रेज़र फॉमएशियाज ओल्डेस्ट म्यूजियम रू बुद्धिस्ट आर्ट फ्राम दि इंडियन म्यूजियमश्कोलकाता, नामक बौद्ध कला प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए 17 और 18 जून, 2015 को सिंगापुर की यात्रा की। उन्होंने संस्कृति, समुदाय और युवा मामलों के मंत्री श्री लारेंस वांग, और श्री एस. ईश्वरन, मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा द्वितीय गृह मंत्री और द्वितीय व्यापार और उद्योग मंत्री से मुलाकात की। रक्षा राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह ने आईआई एसएस शंगरी–ला डायलाग, 2015 में भाग लेने के लिए सिंगापुर

का दौरा किया। उन्होंने दूसरे पूर्ण सत्र में एशिया में सुरक्षा के नए स्वरूप पर एक व्याख्यान दिया।

दूसरी ओर, सिंगापुर के गृह और विधि मंत्री श्री के. शानमुगम ने 17–20 नवम्बर, 2015 तक जयपुर में राजस्थान के पुनरुत्थान में भागीदारी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक व्यापारिक शिष्टमंडल की अध्यक्षता करते हुए भाग लिया। सिंगापुर ने इस सम्मेलन में भागीदार देश के रूप में भाग लिया। उन्होंने जयपुर में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया तथा दिल्ली में गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय के वरिष्ठ राज्य मंत्री श्री जोसेफाइन टियो ने तीसरी भारतीय अफ्रीकी मंच शिखर वार्ता (आईएएफएस) में भाग लेने के लिए 28–30 अक्तूबर, 2015 तक भारत का दौरा किया। इस शिखर वार्ता में भाग लेने के लिए सिंगापुर को दो "विशेष आमंत्रित सदस्यों" में से एक के तौर पर आमंत्रित किया गया था। विदेशी मामलों के मंत्री डॉ. विवियन बालकृष्णन ने द्विपक्षीय सहयोग संबंधी भारत सिंगापुर संयुक्त मंत्री समिति (जेएमसी) की चौथी बैठक में विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के साथ सह–अध्यक्षता करने के लिए 12 अक्तूबर 2015 को भारत का दौरा किया। व्यापार और उद्योग मंत्री एस–ईश्वरन ने दिनांक 22 अक्तूबर, 2015 को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के शिलान्यास समारोह में सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग, जिन्हे आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस समारोह में आमंत्रित किया था, की ओर से भाग लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री और व्यापार और वाणिज्य के द्वितीय मंत्री श्री एस ईश्वरन ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के त्रिचरणीय आधारभूत विकास के मास्टर प्लान का अंतिम मास्टर प्लान आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री चंद्रबाबू नायडू को सौंपने के लिए 20 जुलाई, 2015 को आंध्रप्रदेश का दौरा किया। तीन भाग वाले अमरावती मास्टर प्लान को सिंगापुर सुरबना स्थित जुरांग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया था । इसने शहरी आयोजना, शासन और परियोजना के कार्यान्वयन में सिंगापुर की विशेषता का लाभ उठाया। दि सेंटर फॉर लिवेबल सिटीज एंड सिंगापुर कोऑपरेशन इन्टरप्राइज अमरावती तथा राजधानी क्षेत्र के विकास में संलग्न आंध्र प्रदेश

प्रधानमंत्री और सिंगापुर के प्रधानमंत्री, श्री ली सीन लूंग 23 नवंबर 2015 को सिंगापुर के कोमल विलास रेस्तरां, लिटिल इंडिया में मुलाकात करते हुए।

सरकार के कर्मचारियों को विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। प्रधान मंत्री कार्यालय में मंत्री और द्वितीय व्यापार और वाणिज्य मंत्री श्री एस. ईश्वरन ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती जिसका उद्घाटन 25 मई, 2015 को हुआ था, का मास्टर प्लान मुख्य मंत्री चंद्रबाबू नायडू को सौंपने के लिए हैदराबाद का दौरा किया।

23–24 नवम्बर, 2015 तक प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सिंगापुर दौरे के दौरान संवर्धित प्रतिरक्षा सहयोग करार पर हस्ताक्षर से भारत और सिंगापुर के बीच प्रतिरक्षा सहयोग सुदृढ़ हुआ। इसके अतिरिक्त भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के बीच हवाइट शिपिंग सूचना की साझेदारी पर तकनीकी करार, जिसपर 21 जुलाई, 2015 को एडमिरल आर. के. धवन, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ तथा उनके समकक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, प्रधान मंत्री के दौरे के दौरान लागू कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, भारत और सिंगापुर की तीनों सेवाओं और प्रतिरक्षा अधिष्ठानों के बीच नियमित विनिमय किए गए थे।

भारत और सिंगापुर के बीच घनिष्ठ और वाणिज्यिक संबंध हैं जिसमें चालू वर्ष के दौरान कुछ कमी की प्रवृत्ति देखने को मिली है (द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा में 17 प्रतिशत कमी)। वित्त वर्ष 2015–16 (अप्रैल–अक्तूबर) में कुल द्विपक्षीय व्यापार 8.6 बिलियन अमेरिकी डालर का था जिसमें 4.2 बिलियन का भारतीय निर्यात शामिल था।

सिंगापुर में बहिर्गामी भारतीय एफडीआई 2004–05 में 351 मिलियन अमेरिकी डॉलर था जो बढ़कर 38.9 बिलियन (अक्तूबर, 2015) हो गया । इस प्रकार सिंगापुर विदेशों में भारतीय निवेश के लिए सर्वाधिक पसंद किया जाने वाला स्थान है। इस वर्ष (01 अप्रैल–31 अक्तूबर, 2015) सिंगापुर में भारतीय निवेश 2.18 बिलियन अमेरिकी डालर तक पहुंच गया। सिंगापुर, भारत के लिए एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। अप्रैल, 2000 से सितम्बर, 2015 तक सिंगापुर से भारत में आने वाला कुल एफ डी आई 38.9 बिलियन अमेरिकी डालर रहा है। इस वर्ष अब तक सिंगापुर सबसे बड़ा निवेशक है, जिसमें सिंगापुर से एफडीआई (01 अप्रैल से 30 सितंबर, 2015 तक) 6.69 बिलियन अमेरिकी डालर तक पहुंच गया है।

थाईलैंड

उच्च स्तर पर आपसी दौरों तथा सभी स्तरों पर अधिकाधिक वार्तालाप से विवेच्य वर्ष के दौरान थाईलैंड के साथ भारत का संबंध घनिष्ठ और सुदृढ़ होता चला गया।

श्रीमती सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री ने 27–29 जून, 2015 तक बैंकाक में आयोजित होने वाले 16वें विश्व संस्कृत सम्मेलन में भाग लेने तथा भारत–थाईलैंड संयुक्त आयोग (जेसीएम) की 7वीं बैठक की सह–अध्यक्षता करने के लिए थाईलैंड का दौरा किया। विदेश मंत्री ने महामहिम राजकुमारी महाचक्री सिरीन धोर्न तथा थाईलैंड के प्रिवी काउंसिल के अध्यक्ष जनरल प्रेम तिंसु लानोदा से मुलाकात की। विदेश मंत्री और उप प्रधान मंत्री (डीपीएम) तथा विदेशी मामलों के मंत्री जनरल तानासक पतिमाप्रागर्न ने शिष्टमंडल स्तरीय वार्ताएं की और आर्थिक तथा वाणिज्यिक सहयोग, सुरक्षा, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना संचार तथा प्रौद्योगिकी, शिक्षा कृषि, विधिक और कांसुलर मामलों जैसे विविध क्षेत्रों के संबंध में विचार–विमर्श किया। दोनों मंत्रियों ने प्रत्यर्पण संधि के अनुसमर्थन के विलेखों पर हस्ताक्षर किए तथा दोहरे कराधान से बचाव संबंधी संशोधित करार, नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित करने से संबंधित समझौता ज्ञापन (एमओयू) तथा रांगसित विश्वविद्यालय में आयुर्वेद की एक पीठ (चेयर) स्थापित करने संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

श्री अजीत डोवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने 01 और 02 अप्रैल, 2015 तक थाईलैंड का दौरा किया। श्री डोवाल ने प्रधानमंत्री जनरल प्रयुत्त चान्–ओ'चा, उप प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री जनरल प्रावित वोंगसुआन, उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री जनरल तनासाक से मुलाकात की तथा थाईलैंड की राष्ट्रीय सुरक्षा परिपद के महासचिव श्री अनुसित कुनाकोर्न से मुलाकात की।

वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के 71वें सत्र में भाग लेने के लिए, 28 और 29 मई, 2015 को थाईलैंड का दौरा किया। इस दौरे के दौरान श्रीमती सीतारमण ने थाईलैंड के उप प्रधान मंत्री श्री एम. आर. प्रिदियाथोर्न देवकुल तथा थाईलैंड के वाणिज्य मंत्री जनरल चतचई सारीकुल्या से मुलाकात की तथा दूतावास द्वारा आयोजित व्यापरिक समारोह को संबोधित किया।

जनवरी–सितम्बर, 2015 तक का द्विपक्षीय–व्यापार 6.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। द्विपक्षीय व्यापार विचार–विमर्श समिति (टीएनसी) की 29वीं बैठक 15–17 जून, 2015 तक बैंकाक में आयोजित की गई। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के सचिव श्री अमिताभ कांत ने श्मेकइन इंडिया के संबंध में रोड शो करने के लिए 16 और 17 नवम्बर, 2015 तक थाईलैंड का दौरा किया। भारत सरकार के पर्यटन कार्यालय के सहयोग से दूतावास ने 8 जुलाई, 2015 को बैंकाक में एक पर्यटन प्रोत्साहन समारोह का आयोजन किया। भारत और थाईलैंड ने सूरत तथा थाईलैंड में सूरतथानी के बीच संबंधों की 100वीं वर्षगांठ पर सूरतथानी में 23–26 जुलाई, 2015 तक दक्षिणी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एक्सपो का आयोजन किया। इस एक्सपो में सूरत के 140 व्यापारियों के शिष्टमंडल और प्रदर्शकों ने भाग लिया।

रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर ने आशियान रक्षा मंत्रियों की तीसरी बैठक (एडीएमएम दृ प्लस) के अवसर पर 3 नवम्बर, 2015 को कुआलालमपुर में उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री जनरल प्रवित वोंग्सुवान से मुलाकात की। एयर चीफ मार्शल श्री अरूप राहा, अध्यक्ष, चीफ आफ स्टाफ कमेटी ने 6–9 सितम्बर, 2015 तक थाईलैंड का दौरा किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर. के. धवन, ने 23–27 जुलाई, 2015 तक थाईलैंड का दौरा किया। उच्च स्तरीय रक्षा वार्ता की चौथी बैठक 21 और 22 दिसंबर, 2015 को बैंकाक में आयोजित की जानी है। भारत में 25 मई से 7 जून, 2015 तक 'मैत्री' नामक संयुक्त अभ्यास किया गया। द्विपक्षीय एयर स्टाफ की छठी वार्ता 2–5 सितबंर, 2015 को पट्टाया में आयोजित की गई। समन्वित गश्त का 21वां चक्र (कॉरपट) फुकेत में 12–21 नवम्बर, 2015 तक आयोजित किया गया। भारतीय नौ सेना के दो जहाजों– आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस शक्ति ने 23–27 जून, 2015 तक सत्ताहिप बंदरगाह की सद्भावना यात्रा की। भारतीय तटरक्षक बल का जहाज आईसीजीएस सम्राट 2–5 नवम्बर, 2015 के दौरान बैंकाक गया। भारतीय रक्षा उत्पादन से संबंधित पांच कंपनियों ने बैंकाक में 2–5 नवम्बर तक आयोजित रक्षा और सुरक्षा प्रदर्शनी में भाग लिया।

समुद्री सहयोग और विधिक तथा न्यायिक सहयोग विषयक संयुक्त कार्य दल (जेएफटी) की पहली बैठक 27 और 28 अक्तूबर, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। सुरक्षा सहयोग से संबंधित संयुक्त कार्य समूह की 10वीं बैठक 18 तथा 19 जनवरी, 2016 को भारत में आयोजित की जानी है।

मोटर व्हीकल एग्रीमेंट ऑफ दि ट्राइलेटरल हाईवे को अंतिम रूप देने के संबंध में भारत, म्यांमार और थाईलैंड के परिवहन मंत्रालय की चार बैठकें हुईं। चेन्नै में 18 अप्रैल, 2015 कोय बेंगलूरू में 2 और 3 जून, 2015 को; बैंकाक में 13 और 14 जुलाई, 2015 तथा 16 और 17 सितम्बर को बैठकें आयोजित की गईं। वर्ष, 2015 मे लगभग 01 मिलियन भारतीय पर्यटकों ने बैंकाक की यात्रा की तथा 100,000 से अधिक थाई पर्यटकों ने भारत का दौरा किया। भारत के आमंत्रण पर थाईलैंड के चार पत्रकारों को भारत से परिचित करवाने का कार्यक्रम 14–21 जून, 2015 तक चला।

'थाईलैंड में दूसरा भारत महोत्सव' (फरवरी–मई, 2015) महामान्या राजकुमारी महाचक्री सिरीन धोर्न के 60वें जन्मदिवस की वर्षगांठ की स्मृति को समर्पित किया गया। प्रधान मंत्री जनरल प्रचुत चान–ओ ने 'इंडिया थ्रु दि लेंस ऑफ एचआरएच प्रिंसेज महाचक्री सिरीन धोर्न' फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया तथा महामान्या राजकुमारी सिरीन धोर्न ने 25 मई, 2015 को 'वर्ड्स ऑन वाटर' नामक साहित्यिक उत्सव समापन समारोह में भाग लिया। 21 जून, 2015 को बैंकाक में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग 7000 से अधिक लोगों ने लिया।

वियतनाम

वर्ष 2015–16 के दौरान भारत और वियतनाम में राजनीतिक भागीदारी और सृदृढ़ हुई। आर्थिक सहयोग को रणनीतिक प्राथमिकता प्रदान की गई तथा उच्च स्तर पर लिए गए निर्णयों, जिनमें द्विपक्षीय व्यापक सहयोग के सभी क्षेत्र शामिल थे, को कार्यान्वित करना जारी रहा।

श्रीमती सुमित्रा महाजन, लोक सभाध्यक्ष ने अंतर–संसदीय संघ की 132वीं सभा के लिए 28 मार्च से 01 अप्रैल तक हनोई का दौरा किया था और श्री अजीत डोवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने 3 से 4 अप्रैल, 2015 तक वियतनाम का दौरा किया। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल श्री अरूप राहा ने 9–11 सितम्बर, 2015 तक वियतनाम का दौरा किया। इसी प्रकार वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फुंग कुआंग थान्ह ने 23–26 मई, 2015 तक भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग के संबंध में वर्ष 2015–2020 की अवधि के लिए संयुक्त विजन स्टेटमेंट तथा दोनों देशों के तटरक्षक बलों के बीच सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। वियतनाम परमाणु ऊर्जा संस्थान के अध्यक्ष डा. थीन दि थान्ह, प्राकृतिक संसाधन तथा पर्यावरण के उप मंत्री श्री त्रान होंग हो लांग एन प्रांत के पार्टी सेक्रेटरी श्री नग्यूएन विएट तथा सीपीवी के केंद्रीय विदेशी संबंध आयोग के उपाध्यक्ष ने भी भारत का दौरा किया।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि हुई है। इस समय भारत, वियतनाम के दस बड़े व्यापारिक सहभागियों में से एक है। दोनों पक्ष वर्ष, 2020 तक 15 बिलियन अमेरिकी डालर के नए व्यापारिक लक्ष्य पर सहमत हुए। 1 जुलाई, 2015 में बैंक ऑफ इंडिया को हो चि मिन्ह सिटी में अपनी पहली वाणिज्यिक शाखा खोलने का लाइसेंस दिया गया। हनोई स्थित भारतीय राजदूतावास तथा होचि मिन्ह सिटी में स्थित भारत के वाणिज्य दूतावास ने भारत के विभिन्न भागों में व्यापार करने के संबंध में 25 से अधिक व्यापार संवर्धन कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित किए। पेट्रो वियतनाम ने ओएनजीसी विदेश लिमि. को ब्लॉक 128 पर तेल की अपतटीय खोज करने के लाइसेंस की अवधि जून, 2016 तक बढ़ा दी और 102–106 ब्लॉक को हासिल करने के लिए बातचीत जारी रखी। राष्ट्रपति जी की वियतनाम यात्रा के दौरान सितम्बर, 2015 में रक्षा खरीद के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डालर के ऋण श्रृंखला (एलओसी) के संबंध में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का कार्यान्वयन जारी रहा।

रक्षा उत्पादन सहित रक्षा सहयोग के सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय रक्षा संबंध विस्तृत और गहरा होता जा रहा है। एयर चीफ मार्शल

अरूप राहा ने 9–11 सितम्बर, 2015 तक वियतनाम का दौरा किया। डीआईजी एन. के. कौर की अध्यक्षता में भारतीय तटरक्षक बल के जहाज ''आईसीजीएस सारंग'', ने 27–31 अगस्त, 2015 तक होचि मिन्ह शहर के बंदरगाह की चार दिन की यात्रा की। दोनों देशों के तटरक्षक बलों ने तस्करी और शिकार के खिलाफ की जाने वाली गश्तों के बारे में अपने अनुभवों को साम्या किया और खेलकूद संबंधी गतिविधियां आयोजित कीं। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस सहयाद्रि ने कैप्टन (आईएन) कुणाल सिंह राजकुमार के नेतृत्व में 300 क्रू मेम्बरों सहित 1–6 अक्तूबर, 2015 तक दनांग का 5 दिनों तक सद्भावना यात्रा की। एक्सपर्ट वार्किंग ग्रुप ऑन हुमैनिटेसिन माइन एक्शन – फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइस (एफटीएक्स, 2016) पर विशेषज्ञों के तीसरे सम्मेलन की सह अध्यक्षता वियतनाम और भारत द्वारा की गई जो ह्यू (वियतनाम) में खोली गई थी। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व श्री जीवेश नंदन, संयुक्त सचिव रक्षा मंत्रालय ने की।

वर्षों से वियतनाम, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के अंतर्गत बड़ी संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राप्त करता रहा है। 21 जून, 2015 को हनोई में कुआन नगुआ स्पोर्ट्स पैलेस में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया जिसमें 5000 लोगों तथा 9000 प्रैक्टिशनरों ने भाग लिया। अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। 09 अन्य राज्यों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। सेंटर फार इंडियन स्टडीज होचि मिन्ह एकेडेमी ऑफ पालिटिक्स द्वारा 30 जून, 2015 को हनोई में 'वियतनाम इंडिया कोआपरेशन ऑन कल्चर, सोसाइटी एजूकेशन ऐंड ट्रेनिंग' विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। राजदूत द्वारा होची मिन्ह सिटी के वार रेमनेंट म्यूजियम में 'वियतनाम एंड इंडिया फार पीस ऐंड डेवलपमेंट' नामक फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। सेंटर फार इंडियन स्टडीज ऑफ दि यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेज ऐंड ह्यूमनिटीज द्व ारा भारतीय संस्कृति और वियतनाम–भारत सांस्कृतिक सहयोग और इस क्षेत्र में विकास' विषय पर 28 अक्तूबर, 2015 का एक सेमिनार का आयोजन किया गया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) द्वारा प्रायोजित रॉक क्रासविंड्स ने 13–19 नवम्बर, 2015 तक वियतनाम का दौरा किया गया। उन्होंने हनोई तथा अन्य पड़ोसी प्रांतों में कार्यक्रम प्रस्तुत किये।

प्रशांतद्वीप समूहों के देश

फिजी

वर्ष, 2015 में भारत–फिजी द्विपक्षीय संबंध मजबूत बना रहा और इसमें उल्लेखनीय प्रगति हुई। द्विपक्षीय विचार विमर्श अधिक व्यापक और विविध थे; इसके अनेक पक्ष थे; द्विपक्षीय दौरे भागीदारी विकास, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी); शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सहयोग और सांस्कृतिक विनिमय।

फिजी के प्रधान मंत्री जोसैया वोरेक वैनीमारामा ने 21 अगस्त, 2015 को जयपुर में आयोजित द्वितीय समिट आफ फोरम फार इंडिया स्पेसिफिक आईलैंड्स कोआपरेशन (एफआईपीआईसी) में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। उनकी यात्रा के दौरान जयपुर में आयोजित शिखर वार्ता के साथ–साथ माननीय प्रधानमंत्री और फिजी के प्रधानमंत्री के बीच एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई जिसमें विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों अर्थात् व्यापार, प्रतिरक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य आदि के संबंध में चर्चा की गई ताकि भारत और फिजी के बीच संबंधों में और सुधार लाया जा सके।

ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री बीरेन्द्र सिंह ने एशिया और प्रशांत के समेकित ग्रामीण विकास (सीआईआरडीएपी) से संबंधित 30वीं बैठक कार्यकारी समिति (ईसी 30) और सीआईआरडीएपी शासी परिषद (जीसी–20) की 20वीं बैठक और 17–21 अगस्त, 2015 तक आयोजित 7वें सीआईआरडीएपी क्षेत्रीय नीति वार्ता (आरपीडी–7) के सिलसिले में फिजी की यात्रा की।

भारत सरकार ने 2,81,10,000 रु. की लागत पर सितम्बर, 2015 में स्कूलों के लिए फिजी सरकार को 5000 आकाश यूबीस्लेट टैबलेट और सितम्बर, 2015 में 15,074/– अमेरिकी डालर की लागत पर 300 सिलाई मशीनें महिला, बाल और गरीबी उपशमन मंत्रालय को दान में दीं1 विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई) ने प्रशांत द्वीप समूह के देशों के राजनयिकों के लिए 4–8 मई, 2015 तक फिजी में एक पाठ्यक्रम का आयोजन किया। वर्ष 2015–16 में भारत ने सिविल प्रशिक्षण कोर्स में 140 स्लॉटों (आईटीईसी के तहत 110 तथा टीसीएस कोलम्बो योजना के तहत 30) तथा फिजी की रक्षा के संबंध में 33 स्लॉटों की पेशकश की। इसके अतिरिक्त, आईसीसीआर की सामान्य छात्रवृत्ति स्कीम के तहत वर्ष, 2015–16 के लिए फिजी को 29 छात्रवृतियों की पेशकश की गई थी।

फिजी उच्चायोग द्वारा 21 जून, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया जबकि भारत का संविधान दिवस 26 नवम्बर, 2015 को भारतीय सांस्कृतिक केंद्र (आईसीसी) सूवा में मनाया गया।

पापुआ न्यू गिनी

पापुआ न्यू गिनी (पीएनजी) के प्रधानमंत्री महामहिम श्री पीटर ओनेल ने 21 अगस्त, 2015 को जयपुर मे आयोजित भारत–प्रशांत द्वीप समूह सहयोग (एफआईपीआईसी) के द्वितीय शिखर वार्ता मंच में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान जयपुर शिखर वार्ता के साथ–साथ माननीय प्रधानमंत्री और पीएनजी के प्रधान मंत्री के बीच एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित

की गई जिसमें व्यापार प्रतिरक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य आदि जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई ताकि भारत और पीएनजी के संबंधों में और घनिष्ठता लाई जा सके।

कुक द्वीप समूह

स्वास्थ्य, न्याय और संसदीय सेवा मंत्री माननीय श्री नंदी ग्लासी के 21 अगस्त, 2015 को जयपुर में आयोजित भारत–प्रशांत द्वीप समूह सहयोग (एफआईपीसी) के द्वितीय शिखर वार्ता मंच में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की।

नौरू

महामहिम श्री बारोन दिवावेसी वाका, सांसद और नौरू के राष्ट्रपति ने 21 अगस्त, 2015 को जयपुर में आयोजित भारत–प्रशांत द्वीप समूह सहयोग (एफआईपीसी) के द्वितीय शिखर वार्ता फोरम में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान जयपुर शिखर वार्ता के साथ–साथ नौरू के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच एक द्विपक्षीय बैठक का भी आयोजन किया गया जिसमें नौरू के राष्ट्रपति ने समुद्र के बढ़ते स्तर पर काबू पाने के लिए समुद्री–दीवार बनाने में भारत द्वारा उपलब्ध करवाई गई वित्तीय सहायता की प्रशंसा की।

मेनेन होटल के 7 कमरों को स्वतः संपूर्ण इकाइयों में परिवर्तित करने के लिए भारत सरकार द्वारा नौरू सरकार को मई, 2015 में 260, 421 अमेरिकी डॉलर और समुद्री दीवार के निर्माण के लिए अगस्त, 2015 में 450, 175 अमेरिकी डॉलर का सहायता अनुदान दिया गया।

किरीबाती

महामान्या अम्ब तिकोओ ल्यूट (ताइवान में राजदूत) ने किरीबाती के राष्ट्रपति के विशेष दूत के रूप में 21 अगस्त, 2015 को जयपुर में आयोजित भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग (एफआईपीआईसी) के द्वितीय शिखर वार्ता फोरम में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की।

टोंगा

महामहिम श्री सेमिसी ताउलांगी फाकाहाऊ, कृषि, खाद्य, वन और मत्स्य पालन मंत्री ने 21 अगस्त, 2015 को जयपुर में आयोजित भारत–प्रशांत द्वीप समूह सहयोग (एफआईपीआईसी) के द्वितीय शिखर वार्ता फोरम में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की। उच्चायुक्त श्री ए. गीतेश शर्मा ने 4 जुलाई, 2015 को टोंगा में आयोजित टुपोऊ VI नामक राजा के राज्याभिषेक समारोह में भाग लिया। लोक सेवा आयोग कार्यालय की आईसीसी अवसंरचना के स्तर में सुधार लाने के लिए सहायता अनुदान के अंतर्गत (i) 1,15,000 अमेरिकी डालर (टीओपी 200,000/– अमेरिकी डालर) और (ii) 'स्पेक्ट्रम मानीटरिंग' इनक्लुडिंग डिटेक्शन ऑफ इंटरफियरेंस एंड डल–लीगल ट्रांसमिशन' नामक परियोजना के लिए 71,627/– अमेरिकी डालर सितम्बर, 2015 में टोंगा सरकार को दिए गए थे।

तुवालू

तुवालू के प्रधानमंत्री माननीय एनेले सोसेवे सोपागा, ओबीई ने 21 अगस्त, 2015 को जयपुर में आयोजित भारत प्रशांतद्वीप समूह सहयोग (एफआईपीआईसी) में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की।

वानूआतू

वानूआतू के प्रधानमंत्री माननीय सातो किलमान ने 21 अगस्त, 2015 को जयपुर में आयोजित भारत–प्रशांत द्वीप समूह सहयोग (एफआईपीआईसी) के द्वितीय शिखर वार्ता फोरम में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की।

इस यात्रा के दौरान जयपुर शिखर वार्ता के साथ–साथ वानूआतू के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई जिसमें वानूआतू के प्रधानमंत्री ने चक्रवात पाम के बाद भारत सरकार द्वारा दी गई 2,50,000/– अमेरिकी डालर की नकद सहायता के लिए धन्यवाद दिया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने क्षमता निर्माण, जलवायु परिवर्तन आदि सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

समोआ

समोआ के प्रधानमंत्री महामहिम तुलेपा ल्यूपेसेलियाई सैलेले ने 21 अगस्त, 2015 को जयपुर में आयोजित भारत–प्रशांत द्वीप समूह सहयोग (एफआईपीअईसी) के द्वितीय शिखर वार्ता फोरम में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की।

विलिंगटन स्थित भारत के उच्चायोग द्वारा समोआ सरकार के विदेश मंत्रालय और व्यापार मंत्रालय के सहयोग से सामोआ में 20 जून, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।

निऊ

निऊ के प्रधान (प्रमियर) महामहिम श्री टोके तलागी ने 21 अगस्त, 2015 को जयपुर में आयोजित भारत–प्रशांत द्वीप समूह सहयोग (एफआईपीआईसी) के द्वितीय शिखर वार्ता फोरम में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की ।

पलाऊ

महामहिम श्री टॉकी ई. रेमेनगेसाऊ, जूनियर ने 21 अगस्त, 2015 को जयपुर में आयोजित भारत–प्रशांत द्वीप समूह सहयोग (एफआईपीआईसी) के द्वितीय शिखर वार्ता फोरम में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की।

जयपुर में (21 अगस्त 2015) भारत–प्रशांत द्वीप सहयोग (एफआईपीआईसी) शिखर सम्मेलन के दूसरे फोरम के अवसर पर प्रधानमंत्री वानुअतु के प्रधानमंत्री के साथ बैठक करते हुए।

जयपुर (21 अगस्त 2015) में एफआईपीआईसी शिखर सम्मेलन का समूह चित्र।

माइक्रोनेशिया

माइक्रोनेशिया संघीय गणराज्य के उप राष्ट्रपति माननीय योशिओ पालिकुन जार्ज ने 21 अगस्त, 2015 को जयपुर में आयोजित भारत–प्रशांत द्वीप समूह सहयोग (एफआईपीआईसी) के द्वितीय शिखर वार्ता फोरम में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की।

मार्शल द्वीप समूह

मार्शल द्वीप समूह के राष्ट्रपति महामहिम श्री क्रिस्टोफर जे. लोइक ने 21 अगस्त, 2015 को जयपुर में आयोजित भारत–प्रशांत द्वीप समूह सहयोग (एफआईपीआईसी) के द्वितीय शिखर वार्ता फोरम में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की।

सोलोमन द्वीप समूह

उप प्रधान मंत्री माननीय श्री डोगलास इस्टे ने 21 अगस्त, 2015 को जयपुर में आयोजित भारत–प्रशांत द्वीप समूह सहयोग (एफआईपीआईसी) के द्वितीय शिखर वार्ता फोरम में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की।

भारत–प्रशांत द्वीप समूह सहयोग (एफआईपीआईसी) का द्वितीय शिखर वार्ता फोरम

भारत–प्रशांत द्वीप समूह सहयोग (एफआईपीआईसी) का द्वितीय शिखर वार्ता फोरम 21 अगस्त, 2015 को जयपुर में आयोजित किया गया था। मार्शल द्वीप समूह, नौरू और पलाऊ के तीन राष्ट्राध्यक्षों; माइक्रोनेशिया के उप राष्ट्रपति; फिजी, निऊ, पापुआ, न्यू गुआना, सामोआ, तुवालू और वानूआतू सरकारों के छह प्रधानों; और सोलोमन द्वीप समूह, टोंगा, कुक द्वीप समूह और किरीबाती के उप प्रधान मंत्री, मंत्रियों/विशेष दूतों ने इस शिखर वार्ता में भाग लिया। शिष्टमंडल के नेताओं की सूची अनुबंध–क के रूप में संलग्न है।

अपने स्वागत भाषण में, प्रधानमंत्री ने कहा कि इस शताब्दी के लिए भारत और प्रशांत द्वीप देश (पीआईसी) भागीदारी का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि साझा आकांक्षाओं और चुनौतियों द्वारा रचित है और इस विश्वास से सुसज्जित है कि छोटे और बड़े सभी राष्ट्रों की विश्व में समान हिस्सेदारी है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ऊर्जा, समुद्री संसाधन, नई दवाईयों और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में भारत–प्रशांत द्वीप सहयोग की अत्यधिक संभावनाएं मौजूद हैं।

अपने समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के तत्काल सुधारों पर बल दिया और कहा कि महासभा के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत मसौदे को बातचीत के पाठ के रूप में तत्काल स्वीकार करना चाहिए और विभिन्न क्षेत्रों में प्रशांत द्वीप के देशों के लिए बहुसंख्य घोषणाएं की जैसे कि क्षेत्र में स्थाई तटीय और समुद्री/सागर अनुसंधान संस्थान और विभिन्न द्वीप राष्ट्रों में समुद्री जीव विज्ञान अनुसंधान केंद्रों के नेटवर्क की स्थापना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी प्रयोग केंद्र और सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला की स्थापना, प्रशांत द्वीपों पर भारतीय नौसेना द्वारा सद्भावना यात्राएं, विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी, सौर ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण परिवर्तन, आटीईसी में वृद्धि में क्षमता संवर्धन आदि।

दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों का संगठन (आसियान)

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21 नवम्बर, 2015 को कुआलालंपुर में 13वें आसियान–भारत शिखर सम्मेलन की सह–अध्यक्षता की। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय वास्तुशिल्प में आसियान केंद्रीयता के लिए भारत के समर्थन को दोहराया और आतंकवाद–विरोध, समुद्री सुरक्षा, साईबर सुरक्षा और मानवीय और आपदा राहत में सहयोग का आह्वान किया। दोनों क्षेत्रों के बीच इसके सभी आयामों में संपर्क विस्तारित करने के महत्व को रेखांकित किया और आसियान–भारत आर्थिक भागीदारी की क्षमता/ संभावनाओं का खुलासा किया, उन्होंने परियोजनाओं को आगे बढ़ाने हेतु 1 बिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला की घोषणा की, जो कि भारत और आसियान के बीच डिजिटल संपर्कय कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम देशों में उत्पादन केंद्रों को विकसित करने हेतु परियोजना विकास निधि सृजित करने के प्रयोजन, वर्तमान 1 मिलियन अमरीकी डॉलर से 5 मिलियन अमरीकी डॉलर से आसियान–भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी निधि का आवर्धन, कम लागत प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण की सुविधा हेतु आसियान–भारत नवाचार मंच की स्थापना, नवीकरणीय ऊर्जा में क्षमता संवर्धन में सहयोग, जिसमें सौर प्रौद्योगिकी शामिल है और भारत की देशी विकसित जीपीएस समर्थित भू–संवर्धित नौचालन (गगन) की सेवाओं का भी आसियान सदस्य राष्ट्रों को पेशकश करनाय का समर्थन करता है।

विदेश राज्य मंत्री, जनरल (सेवानिवृत्त) श्री वी.के. सिंह ने 5 अगस्त, 2015 को 13वें आसियान–भारत विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया, जिसमें राजनीतिक–सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक–सांस्कृतिक स्तंभों के साथ–साथ मजबूत पहलों और सहयोग के क्षेत्रों को पहचानते हुए, 2016–20 की अवधि के लिए आसियान–भारत कार्य योजना को स्वीकार किया गया था। सेवाओं और निवेश में व्यापार पर आसियान–भारत करारों को भी 1 जुलाई, 2015 को लागू किया गया था। इससे पूर्व, अप्रैल, 2015 में, आसियान के साथ भारत ने अपनी भागीदारी की वरीयता को मान्यता देते हुए, आसियान और जकार्ता में पूर्व एशिया सम्मेलन में एक स्थाई मिशन खोला है।

कुआलालंपुर में (21 नवंबर, 2015) को 13वें आसियान–भारत शिखर सम्मेलन के दौरान एक समूह तस्वीर में प्रधानमंत्री

कुआलालंपुर में (22 नवंबर, 2015) 10 वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री की एक समूह तस्वीर

आसियान के महासचिव, महामहिम मि. लि. लौउंग मिन्ह ने 9–14 दिसम्बर, 2015 को भारत की सरकारी यात्रा की और इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय विचार–विमर्श किया। उन्हें प्रथम आईसीसीआर प्रतिष्ठित भूतपूर्व छात्र पुरस्कार भी प्रदान किया गया था।

आंतरिक आसियान विकास अंतराल को कम करते हुए आसियान एकीकरण हेतु पहलकदमियों में अंशदान करते हुए भारत आसियान देशों, विशेषकर कंबोडिया, लाओ पीडीआर, म्यांमार और वियतनाम में लगातार परियोजना आधारित वित्तीय सहायता और क्षमता संवर्धन प्रदान करता रहा है। इन परियोजनाओं का वित्तपोषण आसियान–भारत सहयोग निधि (50 मिलियन अमरीकी डॉलर), आसियान–भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास निधि (1 मिलियन अमरीकी डॉलर) और आसियान–भारत ग्रीन निधि (5 मिलियन अमरीकी डॉलर) से किया गया था। आसियान–भारत कूटनीतिक भागीदारी के अंतर्गत विशाल परियोजना के कार्यान्वयन में ट्रैकिंग, टैलीमेटरी और डाटा रिसेप्शन स्टेशन और वियतनाम में आसियान हेतु प्रक्रिया सुविधा की स्थापना, बियाक, इंडोनेशिया में वर्तमान केंद्र का उन्नयन और अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा हेतु केंद्र पर अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी में आसियान कार्मिकों का प्रशिक्षण और एशिया एवं प्रशांत, देहरादून में इसरो द्वारा शुरू किया गया है।

भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच दो सदियों पुरानी सभ्यता संपर्कों पर प्रकाश डालने और समर्थन करने पर विशेष बल प्रदान किया गया था। इन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संपर्कों का दस्तावेजीकरण करने के दृष्टिकोण से, 23 जुलाई, 2015 को नई दिल्ली में सांस्कृतिक संपर्कों पर प्रथम आसियान–भारत सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसके बाद फरवरी, 2016 में जकार्ता में दूसरे सम्मेलन का आयोजन किया गया। व्यक्ति से व्यक्ति विनिमय के कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें सितम्बर से नवम्बर, 2015 में भारत में आसियान देशों से 206 विद्यार्थियों की यात्रा शामिल है। 16 नवम्बर – 12 दिसम्बर, 2015 को आसियान राजनयिकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम विदेश सेवा संस्थान, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 27–31 दिसम्बर, 2015 को राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में आसियान देशों से 30 हाईस्कूल विद्यार्थियों ने भी भाग लिया था।

दोनों पक्षों के शैक्षिक समुदायों के बीच बृहद आदान–प्रदानों को प्रोत्साहित करने हेतु 7 एवं 8 अगस्त, 2015 को कुआलालम्पुर, मलेशिया में आसियान–भारत के विशेषज्ञ समूह के नेटवर्क के चौथे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। ''आसियान–भारत संबंधः एक नया प्रतिमान'' विषय पर 17–19 फरवरी, 2016 को नई दिल्ली में आसियान–भारत कूटनीतिक भागीदारी के सभी आशयों पर मंथन हेतु प्रमुख वार्षिक ट्रैक 1.5 वार्ता मंच, दिल्ली वार्ता के आठवें संस्करण का आयोजन हुआ। इसमें आसियान देशों के साथ–साथ उत्तर–पूर्व से प्रतिभागियों के साथ मंत्रालयी, व्यापार और शैक्षिक सत्र शामिल हैं।

पूर्व एशिया शिखर बैठक (ईएएस)

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कुआलालंपुर में 22 नवम्बर, 2015 को 10वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों जैसे कि आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा आदि पर अपने सहभागियों के साथ एशिया–प्रशांत में समान रूचि और संबंध के कूटनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर परिचर्चा के लिए प्रमुख नेताओं की अगुवाई के मंच के रूप में पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन को सुदृढ़ करने हेतु भारत के समर्थन को पुनः दोहराते हुए इसकी 10वीं वर्षगांठ पर भारत के दृष्टिकोण को साझा किया। इससे पूर्व विदेश राज्य मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) श्री वी.के. सिंह ने 6 अगस्त, 2015 को कुआलालम्पुर में 5वें ईएएस (पूर्व एशिया शिष्ट सम्मेलन) की विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया था।

भारत ने जुलाई, 2015 में नोम पेन्ह में कंबोडिया के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा वास्तुशिल्प पर चौथे पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी द्वारा 2015 में पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में सक्रिय रूप से भागीदारी करना जारी रखा। इसके अतिरिक्त पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के विकास एजेंडा के अंतर्गत भारत ने 15 एवं 16 अक्तूबर, 2015 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में नर्सिंग और ट्रोमा केयर पर पूर्वी एशिया गोलमेज शिखर सम्मेलन और 8 एवं 9 नवम्बर, 2015 को आसियान–भारत केंद्र पर समुद्री सुरक्षा और सहयोग पर पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन सभा का आयोजन किया था।

एशिया–यूरो बैठक (एएसईएम)

विदेश राज्य मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) श्री वी.के. सिंह ने 5 एवं 6 नवम्बर, 2015 को लक्जमबर्ग की मेजबानी में और यूरोपीय संघ की अध्यक्षता में 12वीं एएसईएम विदेश मंत्री बैठक में भाग लिया। वर्ष के दौरान भारत एएसईएम कार्यक्रमों में एक सक्रिय भागीदार और अंशदाता था और 9–21 अगस्त, 2015 से एशिया–यूरोप प्रतिष्ठान (एएसईएफ) के साथ मिलकर 'विरासत शहरों में स्थायी शहरीकरण' पर 19वें ग्रीष्म विश्वविद्यालय परियोजना की मेजबानी कीय और 8 एवं 9 अक्तूबर, 2015 को गोवा में एएसईएम महानिदेशकों/कस्टम आयुक्तों की 11वीं बैठकय सहयोग के ठोस क्षेत्रों में आगे बढ़ने हेतु 20 नवम्बर, 2015 को गांधीनगर में हरित भवनों पर दूसरा एएसईएम गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी की।

मेकांग–गंगा सहयोग

भारत ने लाओ पीडीआर के साथ 3 अगस्त, 2015 को कुआलालम्पुर में मेकांग–गंगा सहयोग वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की सह

लक्जमबर्ग में (5 नवम्बर, 2015) आयोजित 12वीं एएसइएम विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश राज्य मंत्री जनरल (सेवानिवृत) वी.के.सिंह सभा को संबोधित करते हुए।

अध्यक्षता की, जिसमें पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा यातायात एवं संपर्क के साथ–साथ नए क्षेत्रों जैसे कि लघु और मध्यम उद्यम, स्वास्थ्य, कृषि आदि में प्रगति सहयोग के चार परम्परागत क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के रास्तों और माध्यमों पर विचार–विमर्श किया गया। तत्काल प्रभाव वाली परियोजनाओं (क्यूआईपी) जिसके लिए भारत ने वार्षिक 1 मिलियन अमरीकी डॉलर देने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है और जिसमें सीधे सामाजिक प्रभाव के साथ लघु परियोजनाओं के लिए 50,000 अमरीकी डॉलर तक वित्तपोषण की पेशकश की गई, को भी वर्ष के दौरान प्रारंभ किया गया।

क्षेत्रीय समेकित आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी)

भारत से एक मंत्रालयी शिष्टमंडल ने 13 जुलाई को अंतर–सत्रवार आरसीईपी बैठक और कुआलालम्पुर में 24 अगस्त, 2015 को तीसरी आरसीईपी मंत्रालयी बैठक में भाग लिया, जो सफल रही और जिसके अनुगमन में, वस्तुओं, सेवाओं और निवेश में व्यापार पर मूल और पाठ–आधारित बातचीत को तीव्रता से आगे बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री 2016 तक बातचीत को संपन्न करने के लिए पक्षकारों का आह्वान करते हुए 22 नवम्बर, 2015 को कुआलालम्पुर में आरसीईपी पर संयुक्त वक्तव्य की स्वीकृति के साक्षी थे।

■ ■

पूर्वी एशिया

3

कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य

भारत तथा कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य (डीपीआरके) के बीच दिसंबर 1973 में राजनयिक संबंध स्थापित किए गए थे। वर्तमान में भारत तथा डीपीआरके सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करते हैं।

कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य (डीपीआरके) के विदेश मंत्री, श्री री सू योंग ने 12–14 अप्रैल 2015 को भारत की यात्रा की। यह विदेश मंत्री के स्तर पर डीपीआरके से भारत की पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान डीपीआरके के विदेश मंत्री ने उप–राष्ट्रपति हामिद अंसारी से मुलाकात की। विदेश मंत्री री ने स्पष्ट तथा मित्रवत् माहौल में माननीय विदेश मंत्री के साथ बातचीत की, जिसमें भारत की सुरक्षा सरोकारों सहित परस्पर हित के मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया। विदेश मंत्री ने अपने कोरियाई समकक्ष को भारत की ''पूर्वोन्मुखी नीति'' के लिए कोरियाई प्रायद्वीप में शांति तथा स्थिरता के महत्व से परिचित करवाया। कोरियाई विदेश मंत्री री सू योंग ने कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य को भारत द्वारा प्रदान की गई मानवीय सहायता पर अपने देश की ओर से आभार व्यक्त किया तथा इस संबंध में अतिरिक्त सहायता की मांग की। विदेश मंत्री ने डीपीआरके के अनुरोध पर विचार किए जाने पर सहमति जताई।

भारत ने डीपीआरके को अपने मानव संसाधन विकास सहायता का विस्तार किया। भारत ने वर्ष 2015–16 के लिए 15 स्लॉट का प्रस्ताव देकर डीपीआरके के नागरिकों के क्षमता निर्माण प्रयासों में सहायता के लिए भारत ने आईटीईसी स्लॉट आबंटित करना जारी रखा है। भारतीय मिशन ने 27 मार्च 2015 को डीपीआरके में आईटीईसी कार्यक्रम का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया। आईटीईसी स्वर्ण जयंती आयोजन के समापन के लिए मिशन द्वारा 15 सितंबर 2015 को आईटीईसी दिवस का आयोजन किया गया था।

डीपीआरके तथा भारत ने विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर एक–दूसरे को सहयोग करने की मंशा व्यक्त की।

प्रधानमंत्री अबे और प्रधानमंत्री मोदी समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने के दौरान

जापान

वर्ष 2006 से 'वार्षिक शिखर सम्मेलन' के तंत्र से भारत तथा जापान के संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन आया है। अगस्त–सितंबर, 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के द्वारा जो गति प्रदान की गई थी, अत्यधिक उत्साह के साथ इस वर्ष आगे ले जाया गया जिससे जापान के साथ भारत की विशेष, रणनीतिक तथा वैश्विक भागीदारी इसके सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बना। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों के दौरान दोनों प्रधान मंत्रियों ने कई बार मुलाकात की जो दोनों देशों के नेतृत्व की सुदृढ़ प्रतिबद्धता का संदेश देता है। व्यापक राजनीतिक, रक्षा तथा सुरक्षा सहयोग; व्यापक आर्थिक भागीदारी; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; लोगों का लोगों से संपर्क; तथा बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग से भारत तथा जापान के बीच सुदृढ़ संबंध स्तंभों का निर्माण करते हुए इस भागीदारी को समय के साथ महत्व तथा सार प्रदान किया गया।

दोनों ओर से विदेश तथा रक्षा सचिवों की 2+2 बैठक का आयोजन अप्रैल 2015 में किया गया। विदेश सचिव तथा उप विदेश मंत्री के बीच द्विपक्षीय परामर्शों का जून, अक्टूबर तथा दिसंबर 2015 में आयोजन किया गया था। भारत–जापान–अमरीका की त्रिपक्षीय मंत्रालयी वार्ता सितंबर 2015 में आयोजित की गई। जबकि भारत–जापान–आस्ट्रेलिया की त्रिपक्षीय उद्‌घाटन वार्ता जून–2015 में आयोजित की गई थी। दूसरी भारत–जापान समुद्री वार्ता तथा आतंकवाद निरोध पर चौथी भारत–जापान संयुक्त कार्य दल वार्ता नवंबर 2015 में आयोजित की गई। अक्टूबर–2015 में आयोजित भारत–अमरीका मालाबार नौसेना अभ्यास में जापान ने भाग लिया जबकि जापान समुद्री आत्म–रक्षा बल (जेएमएसडीएफ) बेड़ा समीक्षा में भारतीय नौसेना ने भाग लिया। आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने इन राज्यों तथा जापानी प्रशासक प्रांतों के बीच व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 में जापान की यात्रा की। जापानी निवेश प्रस्तावों को सुगम बनाने के लिए एक विशेष प्रबंधन दल ''जापान–प्लस'' को प्रचालन में लाया गया है। 'भारत–जापान निवेश संवर्धन भागीदारी' की प्रगति के अनुवीक्षण के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में अंतर–मंत्रालयी ''कोर–ग्रुप'' ने पिछले वर्ष तीन बैठकों का आयोजन किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 11–13 दिसंबर 2015 तक दसवें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जापानी प्रधानमंत्री श्री शिंजो–आबे की मेजबानी की। माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री आबे से मुलाकात की तथा प्रधानमंत्री आबे ने माननीय राष्ट्रपति श्री प्रण्ब मुखर्जी से भी मुलाकात की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने जापान–भारत नवाचार सेमीनार के प्रतिभागियों से संयुक्त रूप से मुलाकात की तथा 'भारत–जापान बिजनेस लीडर' मंच–2015 की रिपोर्ट स्वीकार की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने गंगा नदी के तट पर ऐतिहासिक 'गंगा आरती' में शामिल होने तथा वाराणसी–क्योटो सिस्टर सिटी सहयोग की प्रगति की समीक्षा के लिए संयुक्त रूप से बनारस की यात्रा की। 'भारत तथा जापान–विजन 2015 पर संयुक्त वक्तव्यः भारत–प्रशांत क्षेत्र तथा विश्व शांति तथा संपन्नता के लिए साथ काम करने हेतु विशेष रणनीति तथा वैश्विक भागीदारी' पर दोनों प्रधानमंत्रियों ने हस्ताक्षर किए तथा 'तथ्य पत्र' भारत तथा जापान शांति एवं संपन्नता के लिए साथ कार्य करते हुए' इसे जारी किया गया था। पूर्व में महसूस किए गए ठोस परिणामों पर काम करते हुए इस यात्रा से गंभीर, विस्तृत–आधारित तथा कार्योन्मुख भागीदारी की ओर कदम बढ़ाए गए। नागरिक परमाणु उर्जा सहयोग के करार पर बातचीत के परिणामों की घोषणा की गई थी, जिस पर आवश्यक आंतरिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के पश्चात् हस्ताक्षर किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने इस उम्मीद के साथ अपने आर्थिक सहयोग को और सुदृढ़ किया कि वित्त वर्ष 2015 के लिए भारत को जापानी ओडीए येन ऋण 400 बिलियन येन की ऐतिहासिक ऊँचाई को छुएगा, जिसमें शहरी मेट्रो रेल, समर्पित माल–भाड़ा कॉरीडोर तथा सड़क नेटवर्क में सुधार जैसी परियोजनाएँ शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र में, यह निर्णय लिया गया कि सह–उत्पादन तथा सह–विकास हेतु संभावित क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान के साथ उपकरण तथा तकनीकी सहयोग के साथ आगे बढ़ेंगे। लोगों का लोगों से आदान–प्रदान को संवर्धित किए जाने के क्रम में भारत ने जापानी यात्रियों के लिए मार्च 2016 से आगमन पर वीजा सुविधा की घोषणा की थी तथा जापानी प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि आगामी पाँच वर्षों में छात्र विनिमय, सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण तथा अन्य लघु–आवधिक विनिमयों में ऐसी अवसंरचनाओं के तहत 10,000 भारतीय युवा जापान की यात्रा करेंगे। शांति एवं स्थिरता हेतु अपने दृष्टिकोण को साझा किया और आतंकवाद की तीव्र आलोचना के साथ–साथ भारत–प्रशांत क्षेत्र को उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य माना। एपैक तथा अंतर्राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण अभिशासनों में भारत की सदस्यता के लिए जापानी समर्थन क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मुद्दों पर भारत का सहयोग करने की जापान की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे की भारत यात्रा के दौरान निम्नलिखित करारों पर हस्ताक्षर किए गए थेः (क) नागरिक परमाणु उर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर करारसे जुड़े ज्ञापन; (ख) उच्च गति रेल पर एमओसी; (ग) रक्षा उपकरणों तथा तकनीकी सहयोग के स्थानांतरण से जुड़े करार; (घ) वर्गीकृत सैन्य सूचना के संरक्षण हेतु सुरक्षा उपायों से जुड़े करार; (ड.) दोहरे कर समाधान पर संशोधित प्रोटोकॉल पर करार; (च) भारत गणराज्य के रेल मंत्रालय तथा जापान के भूमि अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच रेल क्षेत्र में सहयोग पर एमओसी; (छ) भारत गणराज्य के अनुसंधान अभिकल्पना एवं मानक संगठन

(आरडीएसओ) तथा जापान के रेल प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (जेआरटीआरआई) के बीच तकनीकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन; (ज) भारत गणराज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा जापान की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एजेंसी के बीच रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम पर आशय पत्र; (झ) भारत गणराज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा जापान के विज्ञान संवर्धन सोसायटी के बीच युवा अनुसंधानकर्ता विनिमय कार्यक्रम की स्थापना के लिए आशय पत्र; (ञ) भारत गणराज्य के केंद्रीय स्वापक मानक नियंत्रण संगठन तथा जापान के स्वास्थ्य, श्रम एवं कल्याण मंत्रालय के बीच चिकित्सा उत्पाद विनियामक वार्ता तथा सहयोगात्मक अवसंरचना एमओसी; (ट) भारत गणराज्य के मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा जापान के शिक्षा, संस्कृति, खेल, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच शिक्षा के क्षेत्र में एमओसी; (ठ) भारत गणराज्य के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा जापान के कृषि, वन एवं मत्स्य मंत्रालय के बीच सहयोग ज्ञापन (एमओसी); (ड) भारत गणराज्य के नीति आयोग तथा जापान के आर्थिक उर्जा संस्थान के बीच आशय कथन; (ढ) आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार तथा टोयोमा प्रीफेक्चर के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन; (ण) केरल राज्य की सरकार तथा नाकाउमी झील, शिंजी झील एवं माउंट डाईसन क्षेत्र के मेयर संघ के बीच समझौता ज्ञापन; तथा (त) भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (आईआईएमए) तथा राष्ट्रीय स्नातक शिक्षा नीति संस्थान (जीआरआइपीएस) के बीच समझौता ज्ञापन।

विद्युत, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री पीयुष गोयल तथा जापान के आर्थिक व्यापार तथा उद्योग मंत्री श्री मोटो हायाशी की सह–अध्यक्षता में आठवीं भारत–जापान ऊर्जा वार्ता 12 जनवरी, 2016 को टोक्यो में आयोजित की गई थी। वार्ता के साथ–साथ विद्युत उत्पादन, ऊर्जा कौशल, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा ऊर्जा भंडारण तकनीक का कार्य देखने वाले कार्य दल की छः बैठकें भी आयोजित की गई थीं, जिसमें भारतीय तथा जापानी निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था।

मंगोलिया

प्रधानमंत्री की अब तक की पहली मंगोलिया यात्रा 16–18 मई 2015 में हुई थी। वर्ष 2015 में दोनों देशों ने अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 वर्ष तथा मंगोलियाई लोकतंत्र की 25वीं वर्षगांठ मनाई थी। हमारे संबंधों को 'व्यापक सहयोग' से 'रणनीतिक सहयोग' में समुन्नत करने का निर्णय लिया गया था तथा इस दौरान संयुक्त वक्तव्य सहित 14 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए थे। बौद्ध धर्म के माध्यम से गहरे सभ्यतागत संबंधों की पहचान के लिए प्रधानमंत्री ने बोधगया स्थित पवित्र बोधि वृक्ष के पौधे को उलानबातर के गैंडन मठ को उपहारस्वरूप भेंट किया था। प्रधानमंत्री ने संसद से विशेष भाव प्रदर्शन के तौर पर सप्ताहांत में एकत्रित मंगोलियाई संसद को संबोधित किया था। विचार–विमर्श में रक्षा एवं सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, संस्कृति तथा लोगों का लोगों से संपर्क सहित सहयोग के विविध क्षेत्रों को शामिल किया गया था। भारत ने मंगोलिया में क्षमता निर्माण के सहयोग के लिए मंगोलिया का 1 बिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला का विस्तार किया है तथा मंगालियाई अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देने के तौर पर इसका स्वागत किया गया था। प्रधानमंत्री ने भावाट्रॉन–।। कैंसर थेरेपी मशीन उपहारस्वरूप प्रदान की तथा पूर्व में अनुमोदित 20 मिलियन अमरीकी डालर ऋण श्रृंखला के इस्तेमाल से उलानबातर में सूचना प्रौद्योगिकी, संप्रेषण तथा आउटसोर्सिंग के लिए अटल बिहारी वाजपेयी उत्कृष्टता केंद्र के लिए आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री पारंपरिक नदम उत्सव में शामिल हुए तथा 600 से अधिक मंगोलियाई तथा भारतीय नागरिकों के विशाल समूह को उन्होंने अलग से संबोधित किया। आर्ट ऑफ लिविंग दल के योग समर्थकों ने अपना कौशल प्रदर्शित किया और पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया।

29–30 जुलाई, 2015 को मंगोलियाई लोकतंत्र की 25वीं वर्षगांठ के आयोजन में कर्नल (सेवानिवृत्त) राज्यवर्धन सिंह राठौर, राज्य मंत्री (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय) ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भारत की ओर से बीएसएफ तथा मंगोलिया की ओर से जीएबीपी के महानिदेशक स्तर की बातचीत दिनांक– 20 अगस्त 2015 को उलानबातर में आयोजित की गई थी। भारत की ओर से संयुक्त सचिव (पीआईसी), रक्षा मंत्रालय की अध्यक्षता में रक्षा पर संयुक्त कार्य दल की 27वीं बैठक 20 अगस्त 2015 को उलानबातर में आयोजित की गई थी। 26 से 28 अगस्त 2015 तक उलानबातर में आयोजित एनएचआरआई के एशिया प्रशांत मंच के 20वें वार्षिक तथा द्विवार्षिक सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारतीय एनएचआरसी के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधीश साइएरिक जोसेफ ने की थी। 3–5 सितंबर 2015 तक नई दिल्ली में विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन द्वारा ''संघर्ष परिहार एवं पर्यावरण जागरूकता हेतु वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल'' पर आयोजित सम्मेलन में श्री एस. बैयर्टस्गॉट, मंत्री एवं कैबिनेट सचिवालय प्रमुख, गैंडन मठ के अबॉट, अन्य वरिष्ठ कार्मिकों तथा भिक्षुओं ने भाग लिया था। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली सम्मेलन में भाग लिया था तथा विशेष प्रार्थना सभा हेतु बोधगया की भी यात्रा की थी।

कोरिया गणराज्य

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 18–19 मई 2015 को कोरिया गणराज्य की यात्रा की थी। 18–19 मई 2015 तक प्रधानमंत्री की कोरिया गणराज्य की यात्रा के दौरान भारत–कोरिया गणराज्य के संबंधों को संवर्धित कर 'विशेष रणनीतिक सहयोग' तक पहुंचा दिया गया था।

प्रधानमंत्री उलानबातर (17 मई 2015) में गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करते हुए।

सियोल, दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति,चेओंग वा डीएई अपने आधिकारिक निवास पर, प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए (18 मई 2015)

इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री ने कोरियाई राष्ट्रपति पार्क गन हाई (पीजीएच) के साथ शिखर स्तर की बातचीत की तथा पीजीएच के साथ भारत–कोरिया सीईओ मंच के आरंभिक सत्र को संबोधित भी किया था। प्रधानमंत्री ने एशियाई लीडरशिप सम्मेलन को संबोधित किया था। कोरिया के शीर्ष संगुटिकाओं के प्रमुखों ने बारी–बारी से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था। उल्सान में ह्यूंदई भारी उद्योग जलपोत–निर्माण संयंत्र की यात्रा के साथ उनकी यह यात्रा समाप्त हुई थी। रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्रों में रक्षा तथा विदेश कार्य से संबंधित '2+2' वार्ता की स्थापना, नौसेनाओं के बीच स्टाफ स्तर की वार्ता तथा दोनों सशस्त्र सेनाओं के बीच नियमित आदान–प्रदान जैसी पहलों की उद्घोषणा की गई थी। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर जलपोत निर्माण तथा सहयोग पर विचार–विमर्श के लिए अर्थव्यवस्था हार्डवेयर विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में संयुक्त कार्य दल की स्थापना की गई थी। यह निर्णय लिया गया था कि दोनों पक्षों की ओर से भारत–आरओके सीईपीए संशोधन पर वार्ताओं की उद्घोषणा करेंगे। कोरिया के रणनीति तथा वित्त मंत्रालय एवं निर्यात–आयात बैंक ने स्मार्ट शहरों, रेल, विद्युत उत्पादन तथा पारेषण एवं अन्य सहमत क्षेत्रों सहित प्राथमिकता के क्षेत्रों के लिए आर्थिक विकास सहयोग निधि (1 बिलियन अमरीकी डॉलर) तथा निर्यात साख (9 बिलियन अमरीकी डॉलर) सहित अवसंरचना में परस्पर सहयोग हेतु 10 बिलियन अमरीकी डॉलर प्रदान करने के अपने आशय को व्यक्त किया है। दोनों सरकारों तथा दोनों देशों के एक्जिम बैंक प्राथमिकता क्षेत्रों हेतु अभिकल्पित वित्तीय सहयोग को मूर्त रूप देने के क्रम में रूप रेखा तैयार करने के लिए विचार–विमर्श करेंगे। दोहरे कराधान निवारण करार, श्रव्य–दृश्य सह–उत्पादन करार तथा युवा कार्य, समुद्री परिवहन तथा संभार–तंत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों के बीच सहयोग, विद्युत उर्जा विकास एवं नए उर्जा उद्योग तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग क्षेत्र में अवसंरचनात्मक सहयोग के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों सहित सात दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

कोरियाई राष्ट्रीय एसेंबली के स्पीकर श्री चुंग यूई–ह्वा ने 7–10 मई 2015 तक भारत की यात्रा करने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। इस यात्रा के दौरान इन्होंने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की तथा माननीय प्रधानमंत्री से बातचीत की थी। मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने विश्व शिक्षा मंच के लिए 18–22 मई 2015 तक कोरिया की यात्रा की थी। रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने परिवहन तथा संचार–तंत्र नेटवर्क पर एसेम सिंपोजियम में भाग लेने के लिए 9–12 सितंबर 2015 तक कोरिया गणराज्य की यात्रा की थी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ0 हर्षवर्धन ने भारत–कोरिया गणराज्य एस एण्ड टी संचालन समिति की बैठक की सह–अध्यक्षता के लिए 6 नवंबर, 2015 को कोरिया गणराज्य की यात्रा की थी। इसके अतिरिक्त, पंजाब के उप–मुख्यमंत्री श्री सुखबीर सिंह बादल तथा मध्य–प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सितंबर तथा अक्तूबर 2015 में क्रमशः कोरिया गणराज्य की यात्रा की थी।

हमारे द्विपक्षीय संबंध मजबूत आर्थिक सहयोग पर आधारित हैं। वर्ष 2014–15 (अप्रैल–फरवरी, पिछले वर्ष की अनुवर्ती अवधि पर अनंतिम) में 16.65 बिलियन अमरीकी डालर का व्यापार हुआ। कोरिया से (अप्रैल 2000 तथा जुलाई 2014) कुल एफडीआई अंतर्वाह 1.47 बिलियन अमरीकी डालर रहा तथा भारत से प्राप्त (डीआईपीपी में तैयार किए गए आंकड़े के अनुसार) कुल एफडीआई के 64ः शेयर के साथ यह 13वें पायदान पर है। सैमसंग, ह्यूंदई मोटर्स तथा एल जी जैसे मुख्य कोरियाई संगुटिकाओं ने भारत महत्वपूर्ण निवेश किया है तथा कोरिया गणराज्य में भारतीय निवेशों में इसमें वृद्धि भी हो रही है।

परस्पर मजबूती एवं साथ कार्य करने क्षेत्रों में व्यापार के परिमाणात्मक तथा गुणात्मक संवर्धन के मद्देनजर भारत–कोरिया गणराज्य सहयोग हेतु जलपोत तथा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण की शिनाख्त की जा रही है। भारत–कोरिया गणराज्य के बीच उड़ानों की संख्या बढ़ाकर 19 उड़ान प्रति सप्ताह करने के लिए अक्तूबर–2015 में नई दिल्ली में अलग से अद्यतित भारत–कोरिया गणराज्य द्विपक्षीय वायु सेवा करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

हाल के वर्षों में द्विपक्षीय सुरक्षा एवं रक्षा संबंधों में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री ने 15–18 अप्रैल 2015 तक कोरिया गणराज्य की आधिकारिक यात्रा की थी। भारत तथा कोरिया गणराज्य के राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवों के बीच राष्ट्रीय उप–सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर परामर्शों का प्रथम चरण 23 मार्च 2015 को आयोजित किया गया था। नौसेना जलपोत आईएनएस सहयाद्री ने अक्तूबर 2015 में कोरिया गणराज्य की यात्रा की थी; तथा तटरक्षक जलयान आईसीजीएस सारंग ने अगस्त 2015 में कोरिया गणराज्य की यात्रा की थी।

कोरिया में 9–15 नवंबर 2015 तक भारत उत्सव ''सारंग'' का आयोजन किया था। एक सप्ताह तक चले इस उत्सव में नृत्य, संगीत, खाद्य तथा फिल्में प्रदर्शित की गई थी, जिन्हें संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से सिओल, बुसन तथा अन्य कोरियाई शहरों में आयोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त, सिओल, बुसन तथा अन्य कोरियाई शहरों में भारतीय फिल्म महोत्सव भी आयोजित किए गए थे।

14–15 जनवरी, 2016 के दौरान नई दिल्ली में दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े मीडिया व्यापार दल चोसुन इल्बो तथा सी आई आई द्वारा भारत–कोरिया व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए कोरिया से राष्ट्रीय एसेंबली के चार सदस्यों के साथ राष्ट्रीय एसेंबली के स्पीकर, श्री जेयोंग कब यून, व्यापार उद्योग तथा ऊर्जा के उपमंत्री स्तर

के मंत्रीए दागू मेट्रोपोलिटन सिटी के मेयर तथा चोसुन एल्बो के अध्यक्ष ने ह्यूंदई ग्रुपए सैमसंग इलेक्ट्रोनिक्सए दूसान ग्रुपए लॉटे ग्रुपए एल जी ग्रुप तथा कोरिया इलेक्ट्रिक पावर जैसी कोरिया की अग्रगामी कंपनियों के बिजनेस लीडरों ने भारत की यात्रा की थी। चूंकि पिछले दो दशकों से दक्षिण कोरियाई व्यापारियों ने ऑटोमोबाईल से लेकर उपभोक्ता उत्पादों तक भारत में निवेश किया हैए परंतु पहली बार सभी अग्रगामी कोरियाई व्यापारी दल एक साथ व्यापार शिखर सम्मेलन में एक समूह के तौर पर भारत आए हैं। इस शिखर सम्मेलन ने भारतीय कौशल तथा दक्षिण कोरिया के विनिर्माण क्षमताओं को एक साथ लाकर ष्मेकइन इंडियाष पहल को गति प्रदान की है।

भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरीए 2016 को दूतावास में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया था।

■ ■

यूरेशिया

4

रूसी संघ

दिसंबर, 2014 में रूसी राष्ट्रपति श्री ब्लॉदिमीर पुतिन की यात्रा के दौरान अंगीकार किए गए दस्तावेज 'द्रुज़्हबा–दोस्ती' के विजन दृष्टिकोण को कार्यान्वित करने के लिए मिलकर काम करने की दोनों देशों की दृढ़ इच्छा के साथ ही, भारत और रूस के बीच 'विशिष्ट कार्यनीतिक भागीदारी' वर्ष 2015–16 में नए गुणात्मक स्तरों तक पहुंच गई। शासनाध्यक्ष/सरकार के प्रमुख के स्तर पर तीन दौरों सहित व्यापक उच्च स्तरीय बातचीत हुई।

मई, 2015 में द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 70वीं वर्षगांठ समारोह में राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने भाग लिया। इस अवसर के दौरान, यादगार सैन्य पैरेड में भारतीय सेना के एक दस्ते ने भी भाग लिया। इस यात्रा के दौरान, हमारे राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति श्री ब्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और भारतीय संस्कृति वर्ष 'नमस्ते रूस' का उद्घाटन किया। इस दौरान, भारत और रूसी विश्वविद्यालयों/संस्थानों के बीच आठ समझौता ज्ञापनों को संपन्न किया गया जिसमें भारतीय और रूसी विश्वविद्यालयों के संगठनों पर घोषणा शामिल है।

प्रधानमंत्री अपनी रूस यात्रा के दौरान रूसी राष्ट्रपति के साथ

जुलाई, 2015 में, ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में रूस ने ऊफा में 7वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। प्रधान मंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बैठकों में भाग लिया और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के पूर्ण अधिवेशन को संबोधित किया। इसके अतिरिक्त समय में, प्रधान मंत्री और रूसी राष्ट्रपति श्री ब्लॉदिमीर पुतिन ने नई दिल्ली में हुए दिसंबर, 2014 में वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से भारत–रूस संबंधों में हुई प्रगति का जायजा लिया।

इस वर्ष की सबसे प्रमुख घटना रूस के राष्ट्रपति श्री ब्लॉदिमीर पुतिन के साथ 16वें वार्षिक भारत–रूस शिखर सम्मेलन के लिए 23–24 दिसंबर, 2015 के दौरान प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की रूस की यात्रा रही। प्रधान मंत्री ने रूस में 'भारत के मित्र' के एक जनसमूह और भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में 17 करारों और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें महत्वपूर्ण करारों व समझौता ज्ञापनों में शामिल थे दृ हेलिकॉप्टर इंजिनियरिंग के क्षेत्र में एक अंतर–सरकारी करार, जो रक्षा क्षेत्र में पहली बड़ी 'मेक इन इंडिया' परियोजना विकसित करने के लिए फ्रेमवर्क उपलब्ध कराएगा, और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा विभाग तथा रोसातोम के बीच स्थानीयकरण पर कार्ययोजना तथा सौर ऊर्जा एवं रेल पर समझौता ज्ञापन।

व्यापार तथा आर्थिक संपर्कों को और बढ़ाने के लिए दोनों देशों की साझा प्राथमिकता का प्रदर्शन करते हुए, दोनों नेताओं ने भारत–रूसी सीईओ मंच की एक बैठक को भी संबोधित किया, जिसमें दोनों देशों से वरिष्ठ व्यापारी ने भाग लिया। अनेक प्रमुख निवेशों की घोषणा की गई, जिसमें रूस के दूसरे सबसे बड़े तेलक्षेत्र रोसनेफ्ट के वांकोरेन्फ्ट में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड द्वारा 15 प्रतिशत हिस्सेदारी की खरीद के साथ–साथ विशाल निजी क्षेत्र निवेश शामिल हैं। इस शिखर सम्मेलन में एक 'हरित गलियारा' करार स्थापित करके, हीरे में सीधे व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य सहित भारत हीरा सराफा के विशेष अधिसूचित क्षेत्र के सृजन सहित कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पादों के लिए बाजार तक प्रवेश पर प्रगति शामिल है।

रूस ने एक योग्य तथा मजबूत दावेदार के रूप में विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के संबंध में अपने समर्थन को दोहराया। रूस ने बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं के साथ–साथ एससीओ और एपेक जैसे संगठनों में भारत के शामिल होने के संबंध में अपने सतत समर्थन को भी रेखांकित किया। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरूद्ध इसके सभी स्वरूपों और प्रदर्शनों में अपने मजबूत सहयोग पर भी जोर दिया।

इस वर्ष के दौरान अन्य उच्च स्तरीय दौरों में शामिल थे – व्यापार, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग पर भारत–रूस अंतर–सरकारी आयोग (आईजीसी) के लिए 20 अक्तूबर, 2015 को विदेश मंत्री की मास्को की यात्रा और सैन्य–तकनीकी सहयोग पर आईजीसी के लिए नवंबर, 2015 में रक्षा मंत्री की यात्रा। रूसी उप प्रधान मंत्री श्री देमेत्री रोगोजीन ने 8 दिसंबर, 2015 को नई दिल्ली का दौरा किया और प्रधान मंत्री से मुलाकात की तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) से मिले। ब्रिक्स सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने मई, 2015 में रूस का दौरा किया जिसके दौरान अपने रूसी समकक्ष के साथ उन्होंने द्विपक्षीय बैठक की। उप एनएसए ने जून, 2015 में उलान उदे में सुरक्षा प्रतिनिधियों की छठी अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लिया। रूसी आंतरिक मंत्री श्री बलॉदिमीर कोलोकोत्सेव ने सितंबर, 2015 में भारत का दौरा किया और गृह मंत्री से मुलाकात की। विधि एवं न्याय मंत्री तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश ने 27–29 मई, 2015 के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय विधिक मंच में भागीदारी की। भारत के महान्यायवादी ने सोची में अभियोक्ताओं के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 7वें क्षेत्रीय सम्मेलन में भागीदारी की। निदेशक, सीबीआई और मुख्य सतर्कता आयुक्त ने अक्तूबर–नवंबर, 2015 में सेंट पीटर्सबर्ग में भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकारियों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 8वें वार्षिक सम्मेलन तथा आम बैठक में भाग लिया।

विदेश सचिव, डॉ. एस. जयशंकर ने अक्तूबर, 2015 में मास्को की यात्रा की और रूस के प्रथम उप विदेश मंत्री श्री ब्लॉदिमीर तीतोव तथा उप विदेश मंत्री श्री इगोर मोरगुलोव से विदेश कार्यालय परामर्श किए। इसके अलावा, मध्य एशिया; निःशस्त्रीकरण तथा अप्रसार; दक्षिण एशिया; आतंकवाद विरोध; कोंसुली मामले, राजनयिक विशेषताओं पर संयुक्त सचिव–स्तरीय परामर्श हुए। संयुक्त राष्ट्र मामलों पर सचिव–स्तरीय परामर्श नई दिल्ली में सितंबर, 2015 में हुए थे।

रक्षा सहयोग पर बातचीत गहन तथा परिणामदायक रहे। रक्षा सचिव की अगुवाई में द्विपक्षीय उच्च स्तरीय अनुवीक्षण समिति (एचएलएमसी) की बैठक मास्को में 29 जून, 2015 को हुई जिसमें रक्षा सहयोग परियोजनाओं की समीक्षा की गई। थल सेना प्रमुख ने मास्को और सेंट पीटर्सबर्ग का सितंबर, 2015 में दौरा किया। सचिव, रक्षा उत्पादन ने अगस्त, 2015 में मास्को में माक्स–2015 एअरशो के लिए चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। 2015 में (नवंबर) संयुक्त भारत–रूस सैन्य अभ्यास ''इंडिया–2015'' (राजस्थान में) और संयुक्त भारत–रूस नौसैनिक अभ्यास ''इंदिरा–नेवी'' (दिसंबर) में बंगाल की खाड़ी में आयोजित किए गए।

असैनिक परमाणु सहयोग में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई। सचिव (डीएई) ने अप्रैल और मई, 2015 में क्रमशः विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा और परमाणु ईंधन चक्र पर तीन संयुक्त कार्यसमूहों

की बैठकों के बाद जून, 2015 में मास्को का दौरा किया और इस क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर रोस्तोम के सीईओ के साथ चर्चा की। 24 दिसंबर, 2015 के वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान परमाणु उपकरण के भारत में स्थानीयकरण पर एक करार संपन्न किया गया।

अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग पर, वर्ष 2015 रूसी (तत्कालीन सोवियत संघ) के लाउंच वैहिकल ''सोयूज'' पर प्रथम भारतीय सैटेलाइट ''आर्यभट्ट'' के छोड़े जाने की 40वीं वर्षगांठ का वर्ष था। इसरो और रोसकॉसमॉस ने जून, 2015 में शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए बाह्य अंतरीक्ष की खोज तथा उपयोग के क्षेत्र में सहयोग के विस्तार पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सैटेलाइट नेवीगेशन पर आधारित प्रौद्योगिकियों में सहयोग पर सी–डैक और ग्लोनास के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किया गया।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में बातचीत जारी रही। मई, 2015 में, आध ाारभूत और अण्वेषक अनुसंधान के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग और रूसी विज्ञान प्रतिष्ठान के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किया गया। 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान, सी–डैक, आईआईएससी (बंगलौर) और मास्को राज्य विश्वविद्यालय ने उच्च कार्यनिष्पादन कम्प्यूटिंग में सहयोग हेतु एक करार पर हस्ताक्षर किया।

वाणिज्य तथा उद्योग राज्य मंत्री ने जून, 2015 में 19वें सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के लिए एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। वित्त मंत्री ने ब्रिक्स की बैठक के लिए मास्को तथा ऊफा का जुलाई, 2015 में दौरा किया। जून, 2015 में, भारत तथा यूरेशियाई आर्थिक संघ के बीच सीईसीए/एफटीए की व्यवहार्यता पर नेतृत्व के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह की स्थापना की गई। भारत ने यात्केरिनबर्ग में 'इन्नोप्रोम 2015' औद्योगिकी व्यापार मेले में भागीदारी की और यह 'इन्नोप्रोम 2016' में भागीदार देश होगा।

बेलारूस

2–4 जून, 2015 के दौरान राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी की मिन्स्क की अब तक की पहली यात्रा के साथ बेलारूस के साथ द्विपक्षीय संबंध गुणात्मक रूप से उच्चतर स्तर तक पहुंच गए। भारत–बेलारूस के बीच इस यात्रा के दौरान प्रसारण, मानकीकरण, वस्त्र, वित्तीय सुरक्षा की रूपरेखा तैयार की गई और सहयोग के लिए अनेक करारों पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति और बेलारूस के राष्ट्रपति श्री एलेक्जेंडर लुकाशेन्को ने भारत–बेलारूस व्यापार मंच को संयुक्त रूप से संबोधित किया, जिसमें भारत के एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने भी भाग लिया था। इस समारोह में कम्पनियों के बीच अनेक वाणिज्यिक करार तथा समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इस यात्रा के दौरान बेलारूस को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान करने और 100 मिलियन की ऋण

राष्ट्रपति, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको द्वारा आयोजित दोपहर के भोज में, बेलारूस गणराज्य (3 जून, 2015) की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान स्वतंत्रता स्थल, मिन्स्क में।

श्रृंखला प्रदान करने के भारत के निर्णय की भी घोषणा की गई। राष्ट्रपतिजी ने बेलारूस राष्ट्र विश्वविद्यालय के परिसर में महात्मा गांधी की अवक्ष प्रतिमा का उद्घाटन किया। भेल द्वारा पूरी की गई ग्रडोनो पावर परियोजना का उद्घाटन दोनों देशों के राष्ट्रपतियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

बेलारूस के विदेश मंत्री श्री ब्लॉदिमीर मकेई ने अप्रैल, 2015 में भारत का दौरा किया। उन्होंने विदेश मंत्री से मुलाकात की और राष्ट्रपति से मिले। 7वीं भारत–बेलारूस सैन्य तकनीकी आयोग (एमटीसी) की बैठक 21–22 मई, 2015 को मिन्स्क में हुई। दोनों पक्षकारों ने जारी सहयोग की समीक्षा की और सैन्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा की। वाणिज्य तथा उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मिन्स्क में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत–बेलारूस अंतर–सरकारी आयोग (आईजीसी) की 7वीं बैठक की सहअध्यक्षता करने के लिए 6–7 सितंबर, 2015 के दौरान मिन्स्क की यात्रा की। राज्यमंत्री ने बेलारूस के राष्ट्रपति श्री एलेक्जेन्डर लुकाशेन्को से भी मुलाकात की और अपने समकक्ष तथा आयोग के बेलारूस–पक्ष के अध्यक्ष, उद्योग मंत्री श्री विताली वोव्क और बेलारूस गणराज्य परिषद के अध्यक्ष श्री मिखेल मायासनिकोविच के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।

श्री अनुज कुमार बिश्नोई, सचिव, उर्वरक विभाग (डीओएफ) की अगुवाई में एक 3 सदस्यीय भारतीय उर्वरक प्रतिनिधिमंडल ने बेलारूस के साथ पोटाश क्षेत्र में सहयोग के विस्तार के लिए चर्चा करने के लिए 29 अक्तूबर – 2 नवंबर, 2015 के दौरान मिन्स्क का दौरा किया। पूरे वर्ष के दौरान व्यापार सम्मेलनों, बेलारूस–विक्रेता समागम तथा अन्य व्यापार समारोहों के साथ–साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा।

यूक्रेन

रक्षा सहयोग में प्रगति होती रही। रक्षा मंत्रालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने नौसेना सहयोग पर चर्चा करने के लिए अप्रैल, 2015 में यूक्रेन का दौरा किया। रक्षा मंत्रालय, भेल और मेगाजोन डॉक्स के प्रतिनिधियों के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने माइकोलायव, यूक्रेन में ज़ोरिया संयंत्र के साथ सहयोग पर चर्चा करने के लिए दिसंबर, 2015 में यूक्रेन का दौरा किया। मेसर्स लार्सन एण्ड टुब्रो (एल एण्ड टी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने गैस टर्बूलिन के विनिर्माण के लिए तकनीकी वार्ता करने हेतु जून–जुलाई में यूक्रेन का दौरा किया। एक अन्य महत्वपूर्ण घटना में, 5 एन्टोनोव एएन–32 तकनीकी परिवहन विमानों के अंतिम बैच का यूक्रेन में उन्नयन किया गया और नवंबर में भारत भेजे गए।

सांस्कृतिक क्षेत्र में, भारतीय शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन, पकवान, लोककथाओं का पठन और फिल्मों व वृत्तचित्र का प्रदर्शन दर्शाते हुए सप्ताह भर चलने वाला भारत महोत्सव मार्च में लिविव तथा अप्रैल, 2015 में कियेव में संपन्न हुआ। अदामास विश्वविद्यालय, कोलकाता ने 24 नवंबर, 2015 को कियेव के तारास शेवचेन्को राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ सहयोग संबंधी एक करार पर हस्ताक्षर किए।

आईटीईसी छात्रवृत्ति के लिए आवेदनों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि देखने में आई। यूक्रेन को दस स्लॉट आबंटित किए गए। भारतीय दूतावास भवन का नवीकरण किया गया और एक पूर्णतः कार्यरत सभागार स्थापित किया गया जहां भारतीय शास्त्रीय नृत्यों और हिन्दी शिक्षण के लिए नियमित रूप से कक्षाएं चलाई जा रही हैं। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम इस वर्ष के दौरान आयोजित किए गए।

आर्मेनिया

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि के क्षेत्र में सहयोग पर आर्मेनिया के साथ एक अंतर–सरकारी करार पर हस्ताक्षर करने और इसके अनुसमर्थन का अनुमोदन कर दिया। इस पर फरवरी–मार्च, 2016 में आर्मेनिया के कृषि मंत्री की प्रस्तावित यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए जाने की आशा है। शिक्षा के क्षेत्र में दो द्विपक्षीय करारों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और इनपर आर्मेनिया के शिक्षा तथा विज्ञान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए जाने की आशा है, यह यात्रा वर्ष 2016 की प्रथम तिमाही में होने की आशा है।

भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित 'दूरस्थ चिकित्सा' परियोजना आर्मेनिया में सीडैक द्वारा सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई है। व्यापार, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग तथा आईसीटी, शिक्षा एवं संस्कृति तथा अन्य क्षेत्रों सहित 10 से अधिक विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों का इस वर्ष के दौरान आदान–प्रदान किया गया, जिसमें आर्मेनियाई निवेश प्रतिष्ठान के साथ संयुक्त रूप से फिक्की तमिल नाडु चैप्टर द्वारा आयोजित तमिलनाडु के एक 15 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का येरेवान दौरा (28–30 नवंबर); दिल्ली में स्वास्थ्य परिचर्या शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 8–10 अक्तूबर, 2015 के दौरान सात सदस्यीय आर्मेनियाई प्रतिनिधिमंडल का भारत दौरा; और स्वास्थ्य परिचर्या मंत्रालय से एक 15 सदस्यीय आर्मेनियाई प्रतिनिधिमंडल का दौरा, जिसने मुंबई में 13–15 मई, 2015 के दौरान फार्मेक्सिल की मेजबानी में ''आईपीएचईएक्स–2015'' में भाग लिया।

येरेवन भाषा विश्वविद्यालय में हिन्दी पढ़ाया जाना जारी रहा और 'विश्व हिन्दी दिवस – 2015' मनाया गया (मई 2015)। 'आर्मेनिया में गांधी फाउन्डेशन' की शुरूआत आर्मेनिया के शिक्षा मंत्रालय तथा येरेवन राज्य विश्वविद्यालय के सहयोग से येरेवन में की गई। ''भारतीय संस्कृति के दिवस'' का अयोजन दो स्थानीय

मित्रता तथा भारतीय संस्कृति संवर्धन समूहों द्वारा येरेवन में 31 अगस्त–6 सितंबर, 2015 के दौरान आयोजित किया गया जिसका समर्थन/सहयोग भारतीय दूतावास ने किया। 'आर्मेनिया में गांधी फाउन्डेशन' की शुरूआत शिक्षा मंत्रालय तथा येरेवन राज्य विश्वविद्यालय के सहयोग से येरेवन में की गई।

आर्मेनियाई नागरिकों के लिए ई–पर्यटन वीज़ा सुविधा की शुरूआत अगस्त, 2015 में प्रारंभ की गई। 15 आईटीईसी स्लॉट और दो आईसीसीआर छात्रवृत्ति स्लॉट आर्मेनिया को आबंटित किए गए।

अप्रैल–नवंबर, 2015 के दौरान, द्विपक्षीय व्यापार टर्नओवर में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई। व्यापार संबंधी आंकड़े 16.6 मिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर रहे जिसमें व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा।

अजरबैजान

वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने तत्कालीन वित्त सचिव सहित एक प्रतिनिधिमंडल के साथ एशिया विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 48वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए 4–5 मई, 2015 को बाकू का दौरा किया।

भारतीय पर्यटन कार्यालय, फ्रैंकफर्ट और भारत से टूर ऑपरेटरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 2–4 अप्रैल, 2015 को बाकू में संपन्न 14वें अजरबैजान अंतर्राष्ट्रीय यात्रा एवं पर्यटन (एआईटीएफ) में भागीदारी की। 28 भारतीय कंपनियों से बना भारतीय निर्यात संगठन संघ (एफआईईओ) के एक प्रतिनिधिमंडल ने ''बाकूबिल्ड–2015'' प्रदर्शनी (21–24 अक्तूबर, 2015) में भाग लिया।

दस अजरबैजानी नागरिकों ने विदश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के तहत भारत में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भागीदारी की। एक अजरबैजानी छात्र केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा में भारतीय भाषा में एक दीर्घकालिक पाठ्यक्रम कर रहा है।

भारतीय दूतावास ने निम्नलिखित में भारत की ओर से भागीदारी की – अजरबैजानी अंतर्राष्ट्रीय क्वीजिन सेंटर (20 अक्तूबर, 2015) द्वारा आयोजित 'देशों की चाय संस्कृति' प्रदर्शनी, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय चावल उत्सव (11 दिसंबर, 2015), अजरबैजानी राजनयिक अकादमी (एडीए) (20 नवंबर, 2015) द्वारा आयोजित ''5वां अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव'' और तेल और उद्योग अजरबैजानी विश्वविद्यालय (19 दिसंबर, 2015) में आयोजित 'अंतर्राष्ट्रीय दिवस'।

वर्ष 2014 में, अजरबैजान के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 815 मिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया जिसमें भारत द्वारा निर्यात 37 मिलियन अमरीकी डॉलर और अजरबैजान का निर्यात 778 मिलियन अमरीकी डॉलर शामिल था।

जार्जिया

सुश्री तमर झवानीया, अध्यक्ष, जार्जिया का केन्द्र चुनाव आयोग की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने जुलाई, 2015 में भारत का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल ने डॉ. नसीम जैदी, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ बैठकें कीं और दोनों देशों के चुनाव आयोगों के बीच सहयोग पर 13 जुलाई, 2015 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

इस वर्ष के दौरान रूचि के अनेक क्षेत्रों के प्रतिनिधिमंडलों का आदान–प्रदान होता रहा। श्री दिनेश शर्मा, अपर सचिव, आर्थिक मामले विभाग तथा निदेशक "आईटीपी" विदेश मंत्रालय 24–25 अगस्त, 2015 के दौरान बीलीसी में एशिया अवसंरचना निवेश बैंक ख्एआईआईबी, के संस्थापक सदस्यों की बैठक में भाग लिया। बीलीसी के दूतावास द्वारा ''भारतीय संस्कृति के दिवस'' का आयोजन (20–22 नवंबर, 2015) किया गया, साथ ही आईसीसीआर द्वारा प्रायोजित ''भारत लोकनृत्य अकादमी'' का लाइव कंसर्ट किया गया, और जम्मू व कश्मीर राज्य पर 3 भारतीय फिल्मों और फोटो प्रदर्शनी की स्क्रिनिंग की गई। 15 आईटीईसी स्लॉट जार्जियाई लोगों को आबंटित किए गए। जार्जियाई नागरिकों के लिए ई–पर्यटन वीज़ा सुविधा का प्रारंभ 2015 में किया गया। एक जार्जियाई निजी फार्मास्यूटिकल कंपनी के एक सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई में 13–15 मई, 2015 को संपन्न ''आईपीएचईएक्स–2015'' में भागीदारी की। एक 3 सदस्यीय जार्जियाई प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ में संपन्न 7–13 अक्तूबर 2015 के दौरान विश्व न्यायिक शिखर सम्मेलन में भागीदारी की।

43.8 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य द्विपक्षीय व्यापार हुआ जिसमें व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा।

मध्य एशिया

कजाकिस्तान

कजाकिस्तान के साथ भारत के पारंपरिक रूप से सुदृढ़ तथा मित्रवत संबंध में इस वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण गतिशीलता मिली। राजनयिक संपर्क की मुख्य बात प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 7–8 जुलाई, 2015 के दौरान कजाकिस्तान की सफल यात्रा रही।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति श्री नुरसुल्तान नाज़ारबायेव और प्रधानमंत्री श्री करीम मस्सीमोव के साथ ठोस तथा रचनात्मक वार्ताएं कीं। प्रधानमंत्री ने अस्ताना में प्रतिष्ठित नाजरबायेव विश्वविद्यालय में मध्य एशिया के साथ भारत के संबंधों पर एक प्रशंसनीय भाषण दिया। प्रधान मंत्री ने यूरेशियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित भारत–कजाकिस्तान सूचना एवं संचार

प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केन्द्र का उद्घाटन भी किया। इस यात्रा की समाप्ति के समय एक संयुक्त वक्तव्य 'तेज कदम' भी जारी किया गया। पांच अंतर–सरकारी करार/समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिसमें रक्षा तथा सैन्य तकनीकी सहयोग पर एक नया करार, सजायाफ्ता व्यक्तियों के हस्तांतरण पर एक करार और भारत की ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए कजाकिस्तान से प्राकृतिक यूरेनियम खरीदने के लिए एक नई संविदा शामिल है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री और कजाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने एक व्यापार समारोह को संयुक्त रूप से संबोधित किया। भारत के एक उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और पांच बी2बी करार/समझौता ज्ञापनों की घोषणा की गई। दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस व्यापार बैठक के दौरान कैस्पियन सागर में सत्पायोव समुद्रतटीय ब्लॉक में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और कजमुनाई गैस संयुक्त उद्यम द्वारा पहली बार खोजे गए कुएं की खुदाई का औपचारिक उद्घाटन भी किया।

प्रधान मंत्री की यात्रा से पहले अनेक उच्च स्तरीय संपर्क हुए। श्री अस्कर मामीन, अध्यक्ष, कजाकिस्तान तमीर झोले (कजाक रेलवे) ने 9–11 जून, 2015 को भारत का दौरा किया जिसके दौरान वे श्री सुरेश प्रभु, रेल मंत्री तथा श्री नितिन गटकरी, सड़क परिवहन, राजमार्ग तथा नौवहन मंत्री से मुलाकात की और परिवहन के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। श्री असत इसेकेशोव, निवेश तथा विकास मंत्री, कजाकिस्तान गणराज्य ने 15–17 जून, 2015 को भारत आनेवाले एक सरकारी–सह–व्यापार प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री, दूरसंचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और इस्पात तथा खनन मंत्री से मुलाकात की।

व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा सांस्कृतिक सहयोग पर अंतर–सरकारी आयोग की 12वीं बैठक 16–17 जून, 2015 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित की गई। श्री ब्लॉदिमीर शकोल्निक, कजाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री ने 32 सदस्यीय कजाक प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। इस बैठक की सहअध्यक्षता श्री धर्मेन्द्र प्रधान, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री द्वारा की गई। श्री शोलनिक ने ऊर्जा तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से भी मुलाकात की।

कजाकिस्तान ने अप्रैल–दिसंबर, 2015 के दौरान आईसीसीआर सामान्य छात्रवृत्ति योजना के तहत 25 आईटीईसी स्लॉट और 4 छात्रवृत्तियों का उपयोग किया।

किर्गिज गणराज्य

किर्गिज गणराज्य के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण तथा व्यापक

प्रधानमंत्री कजाकिस्तान की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान अस्ताना में। प्रधानमंत्री के होटल (7 जुलाई, 2015) में आगमन पर पारंपरिक स्वागत करते हुए।

संबंधों को 11–12 जुलाई, 2015 के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की किर्गिस्तान की यात्रा से नई प्रेरणा मिली। यह दो दशकों में भारत से किर्गिज गणराज्य की प्रधानमंत्री स्तर की पहली यात्रा थी। प्रधान मंत्री ने किर्गिज राष्ट्रपति, श्री अल्माजबेक अतामबायेव, स्पीकर श्री अजिल्बेक जीनबेकोव और प्रधान मंत्री श्री तमीर सरीयेव के साथ अत्यंत परिणामदायक द्विपक्षीय बैठकें कीं। इस यात्रा के दौरान, प्रधान मंत्री ने किर्गिज गणराज्य के रक्षा मंत्री को चिकित्सा उपकरण भेंट किए, भारत में सुपर विशेषज्ञता अस्पताल और किर्गिस्तान में अस्पतालों के बीच दूरस्थ चिकित्सा संपर्कों का उद्घाटन किया, और बिश्केक में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया। रक्षा सहयोग, संस्कृति, चुनाव तथा मानकीकरण के क्षेत्रों में चार समझौता ज्ञापनों/करारों पर हस्ताक्षर किए गए। इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार के विचार का एक संयुक्त वक्तव्य इस यात्रा के दौरान जारी किया गया।

विदेश मंत्री ने 09 दिसम्बर, 2015 के दौरान इस्लामाबाद में संपन्न हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के अतिरिक्त समय में अपने समकक्ष इरलान अब्दीदाएव से मुलाकात की।

प्रधान मंत्री की यात्रा की एक अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, 15 जुलाई, 2015 को बिश्केक में कृषि के क्षेत्र में सहयोग पर एक गोलमेज का आयोजन किया गया। सचिव, कृषि ने एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। किर्गिज कृषि मंत्री ने किर्गिज पक्ष की अगुवाई की। कृषि सहयोग पर प्रथम गोलमेज में एक भागीदार अवन्ता समूह ने सहयोग के अवसरों की तलाश करने के लिए चीनजीज़ अइत्मातोव फाउन्डेशन के तहत कृषि मंच के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

एक ब्रिगेडियर की अगुवाई में आर्मी वार कॉलेज से 17 अधिकारियों के एक रक्षा प्रतिनिधिमंडल ने छह दिवसीय परिचय यात्रा के लिए 11–16 अक्तूबर, 2015 के दौरान किर्गिस्तान की यात्रा की।

भारत–किर्गिज व्यापार 2014–15 में 38.53 मिलियन अमरीकी डॉलर था। किर्गिस्तान को भारत का निर्यात 37.76 मिलियन अमरीकी डॉलर था जबकि भारत को किर्गिज निर्यात 77 मिलियन अमरीकी डॉलर था। कुल व्यापार में वर्ष 2014–15 में 2013–14 की तुलना में व्यापार में वृद्धि हुई।

ताजिकिस्तान

ताजिकिस्तान के साथ भारत की घनिष्ठ कार्यनीतिक भागीदारी दिनांक 12–13 जुलाई, 2015 के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ताजिकिस्तान की सफल यात्रा और श्री इमोमाली राहमोन, ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति के साथ उनकी बैठक के साथ ही एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। इस यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने व्यापार एवं आर्थिक संबंधों, रक्षा तथा संपर्क के क्षेत्र में सहयोग तेज करने का निर्णय लिया। दोनों देशों ने साझा क्षेत्रों में आतंकवाद के विरूद्ध अपनी लड़ाई का विस्तार करने तथा उसे सुदृढ़ करने के साझा संकल्प को दोहराया। प्रधान मंत्री ने कुरगॉन तेप्पा में भारत–ताजिकिस्तान मैत्री अस्पताल का दौरा किया और रोगियों से बातचीत की। प्रधान मंत्री ने ताजिक राष्ट्रपति के साथ रविन्द्रनाथ टैगोर की अवक्षप्रतिमा का अनावरण भी किया। इस यात्रा के दौरान, दोनों पक्षकारों ने 2016–18 की अवधि के लिए संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग के एक कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। ताजिकिस्तान के 37 स्कूलों में कम्प्यूटर प्रयोगशाला स्थापित करने संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए।

श्री सिरोद्जीदीन अस्लोव, ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री ने 12–15 मई, 2015 के दौरान भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान वे विदेश मंत्री, आरएम तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिले। भारत के विदेश मंत्रालय और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बीच वर्ष 2015–2017 के लिए एक नए सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए।

''इंडिक स्टडिज इन ताजिकिस्तान'' पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार दुशाम्बे में 21 और 22 दिसंबर, 2015 को संपन्न हुआ। इस सेमिनार का आयोजन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, हिमालयन अनुसंधान एवं संस्कृति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली तथा ताजिकिस्तान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, दुशाम्बे द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

मेजर जनरल सतेन्द्र कुमार सैनी की अगुवाई में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के एक प्रतिनिधिमंडल ने 18–22 मई, 2015 के दौरान ताजिकिस्तान की यात्रा की। रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्यसमूह नई दिल्ली में 15 और 16 अप्रैल, 2015 को संपन्न हुआ।

वाणिज्य सचिव, श्रीमती रीता तेवतीया ने 13 और 14 जनवरी, 2016 को दुशाम्बे में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग पर भारत–ताजिकिस्तान संयुक्त आयोग की एक बैठक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। भारत–ताजिकिस्तान व्यापार एवं आर्थिक संबंधों पर एक रूपरेखा पर आईजीसी बैठक के दौरान सहमति हुई।

तुर्कमेनिस्तान

इस वर्ष ताजिकिस्तान के साथ संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिली जिसमें उप–राष्ट्रपति की यात्रा, किसी भारतीय प्रधानमंत्री की दो से भी अधिक दशकों में पहला दौरा और विदेश मंत्री का एक दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 10–11 जुलाई, 2015 के दौरान अश्गाबाद का दौरा किया और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति श्री गुरबांगुली बेरदीमोहामेदोव के साथ

गर्मजाशी से परिपूर्ण तथा ठोस वार्ता की। प्रधान मंत्री ने अश्गाबाद में योग तथा परंपरागत चिकित्सा केन्द्र का उद्घाटन किया जो इस क्षेत्र में अपने प्रकार का पहला केन्द्र था। उन्होंने महात्मा गांधी की एक अवक्षप्रतिमा का अनावरण भी किया और आजादी विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत की, जो हिन्दी सीख रहे हैं। इस यात्रा के दौरान, सात दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें राज्य से संबंधित तुर्कमेहीमिया (तुर्कमेन केमिकल्स) और भारतीय कंपनी राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक के बीच रासायनिक उत्पादों की आपूर्ति संबंधी एक समझौता ज्ञापन, और तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्रालय और भारत के विदेश सेवा संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन, पर्यटन में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन और रक्षा सहयोग पर एक करार शामिल है।

उप राष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी ने 11–13 दिसंबर, 2015 के दौरान तुर्कमेनिस्तान का दौरा किया। उन्होंने 12 दिसंबर, 2015 को अश्गाबाद में परमानेंट न्यूट्रलिटी ऑफ तुर्कमेनिस्तान की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। उप राष्ट्रपति ने तुर्कमेनिस्तान तथा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति व पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ 13 दिसंबर, 2015 को मेरी, तुर्कमेनिस्तान में संपन्न तुर्कमेनिस्तान–पाकिस्तान–भारत (तापी) गैस पाइपलाइन परियोजना के भूमिपूजन/शिलान्यास समारोह में भी भाग लिया।

विदेश मंत्री ने व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग पर भारत–तुर्कमेनिस्तान अंतर सरकारी संयुक्त आयोग की पांचवीं बैठक में भाग लेने के लिए 7–9 अप्रैल, 2015 को अश्गाबाद की यात्रा की। आईजीसी में, अश्गाबाद में तुर्कमेन–भारत प्रशिक्षण एवं औद्योगिकी केन्द्र (टीआईटीआईसी) में सुधार के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा, विदेश मंत्री ने मास्को जाते समय 19 अक्तूबर, 2015 को अश्गाबाद में अपने पारगमन पड़ाव के दौरान री राशिद मेरेदोव, डीपीएम एवं विदेश मंत्री से भी मुलाकात की।

श्री पी. नारायना, माननीय शहरी विकास मंत्री के नेतृत्व में आंध्रप्रदेश के एक 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आंध्रप्रदेश के अमरावती शहर के विकास के संबंध में शहर आयोजना का अध्ययन करने के लिए 5–7 नवंबर, 2015 को अश्गाबाद का दौरा किया। उन्होंने शहर आयोजना की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए अश्गाबाद में विभिन्न सुविधास्थलों का दौरा किया। 'अतुलनीय भारत रोड शो' नामक एक भारत पर्यटन सेमिनार का आयोजन तुर्कमेनिस्तान में टूर ऑपरेटरों के लिए भारत की पर्यटन क्षमता को रेखांकित करने के लिए 22 सितंबर, 2015 को अश्गाबाद में किया गया।

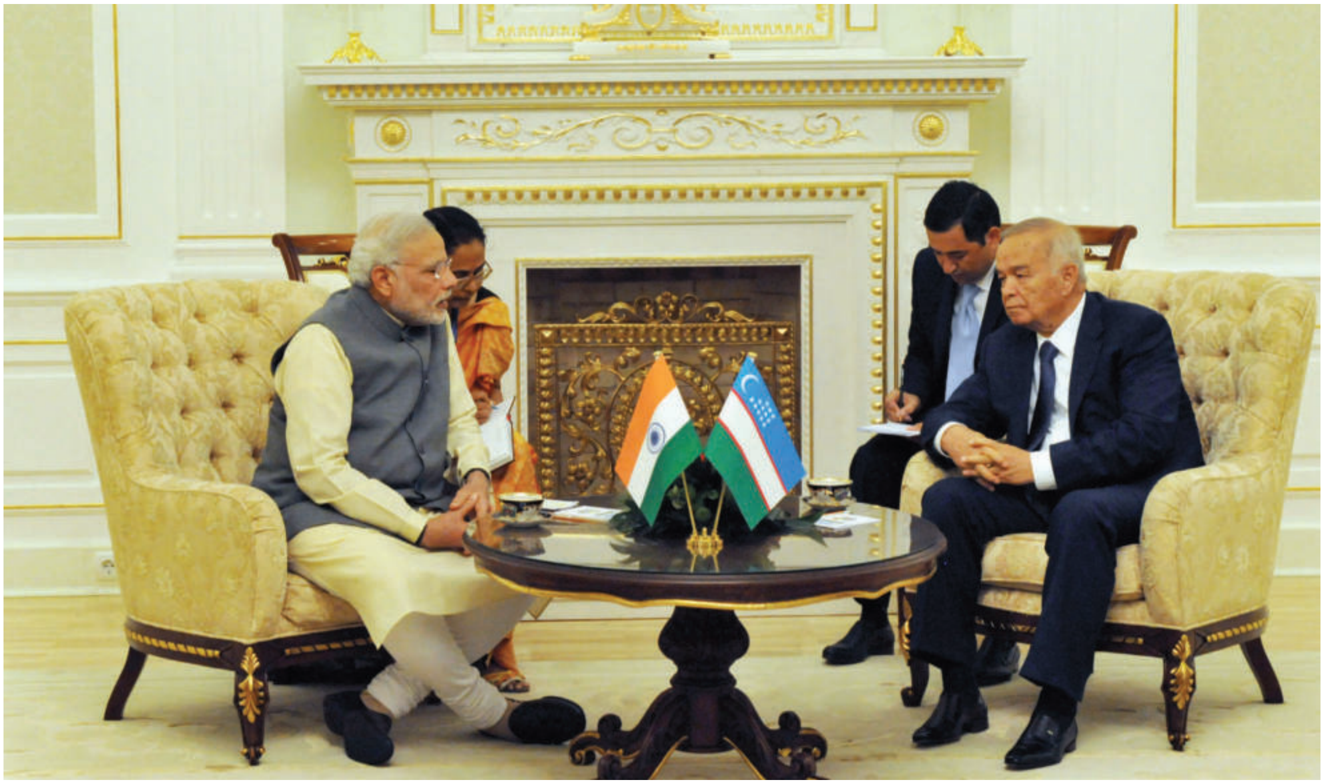

प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपति परिसर में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति श्री इस्लाम करीमोव के साथ बैठक करते हुए (6 जुलाई 2015)

वर्ष 2015–16 में, सामान्य छात्रवृत्ति योजना (जीएसएस –15 सीट) और सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम (सीईपी–5 सीट) के तहत 20 आईटीईसी स्लॉट, 17 रक्षा स्लॉट, 20 सीट तुर्कमेनिस्तान को प्रदान किए गए।

उजबेकिस्तान

भारत के उजबेकिस्तान के साथ ऐतिहासिक संबंध और रणनीतिक भागीदारी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 6–7 जुलाई, 2015 को ताशकंद की यात्रा के साथ ही नई ऊचांइयों पर पहुंचे। मध्य एशियाई देशों की प्रधान मंत्री की यात्रा का पहला पड़ाव ताशकंद था। प्रधान मंत्री ने परस्पर हित के द्विपक्षीय मुद्दों के साथ–साथ क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उजबेकिस्तान के राष्ट्रपति श्री इस्लाम कारिमोव के साथ मैत्रीपूर्ण तथा रचनात्मक चर्चा की। इस यात्रा के दौरान एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया जिसमें तुर्कमेनिस्तान के साथ भारत के विस्तृत संपर्क के विभिन्न पहलु शामिल थे। इस यात्रा के दौरान, पर्यटन में सहयोग पर करारों के साथ–साथ, भारत के विदेश मंत्रालय और उजबेकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बीच सहयोग पर एक प्रोटोकॉल और वर्ष 2015–2017 के लिए सांस्कृतिक सहयोग के एक कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षकारों ने व्यापार तथा अर्थव्यवस्था, आतंकवाद–विरोध, साइबर–सुरक्षा, रक्षा के साथ–साथ शिक्षा तथा सांस्कृतिक विनिमयों में सहयोग में तेजी लाने पर सहमति जताई।

श्रीमती नीरू चड्ढा, एएस (एल एण्ड टी), विदेश मंत्रालय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय करारों की समीक्षा सहित विदेश मंत्रालय के साथ परामर्शों के लिए मार्च, 2015 में ताशकंद की यात्रा की। ताशकंद में भारत सरकार के वित्तपोषण से उद्यमशीलता विकास केन्द्र स्थापित करने पर वार्ताएं जारी रहीं। वित्त सचिव, श्री राजीव महर्षि की अगुवाई में एक छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 18–22 मई, 2015 के दौरान ईएजी कार्यसमूहों की बैठकों में भाग लेने के लिए ताशकंद की यात्रा की। इस वर्ष के दौरान पर्यटन एवं सांस्कृतिक आदान–प्रदान बढ़ने के साथ साथ लोगों के आपसी संपर्कों में भी बढ़ोत्तरी हुई। ऐतिहासिक समरकंद शहर में शर्क़ तारोनालारी महोत्सव में आईसीसीआर प्रायोजित एक समूह ने हिस्सा लिया। भारत उजबेकिस्तान के लिए पर्यटकों के प्रमुख स्रोतस्थल और स्तरीय चिकित्सा परिचर्या चाहने वाले उजबेक नागरिकों के लिए एक प्रमुख ठिकाने के रूप में उभरा।

■ ■

5 खाड़ी तथा पश्चिम एशिया

खाड़ी

भारत के खाड़ी क्षेत्र के देशों के साथ करीबी ऐतिहासिक संबंध हैं, जो वर्षों पुराने सभ्यतामूलक संबंधों और लोगों के बीच मजबूत संपर्क पर आधारित है। इस मैत्रीपूर्ण संबंध को इस वर्ष नियमित उच्च–स्तरीय यात्राओं के आदान–प्रदान के माध्यम से और मजबूत किया गया था। खाड़ी क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार क्षेत्र है जिसके साथ 2014–15 में लगभग 150 बिलियन अमरीकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। यह क्षेत्र भारत को कच्चे तेल और एलएनजी का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना हुआ है जो भारत के कच्चे तेल के आयात का लगभग आधा है और भारत के प्राकृतिक गैस आयात का लगभग 85 प्रतिशत है जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है। भारत को तेल की आपूर्ति करने वाले छः शीर्ष देशों में से चार खाड़ी क्षेत्र से हैं, ये देश सउदी अरब, इराक, कुवैत तथा संयुक्त अरब अमीरात हैं। खाड़ी देशों में सात–मिलियन भारतीय प्रवासी समुदाय रहता है जो मेजबान देशों के विकास में योगदान दे रहा है तथा भारत और खाड़ी राज्यों के बीच एक मूलभूत संबंध स्थापित करता है।

बहरीन

भारत और बहरीन के बीच उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंधों को इस वर्ष के दौरान हुई द्विपक्षीय यात्राओं और बैठकों के द्वारा और मजबूत किया गया था।

बहरीन के आंतरिक (गृह) मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल शेख रशीद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के निमंत्रण पर 1–4 दिसंबर, 2015 को भारत की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान 2 दिसंबर, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की रोकथाम, अंतर्राष्ट्रीय नियोजित अपराध तथा अवैध ड्रग्स व्यापार, स्वापक तथा नशीले पदार्थों व पूर्ववर्ती रसायनों की तस्करी की रोकथाम में सहयोग से संबंधित द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉ अरविंद गुप्ता के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बहरीन के साथ प्रथम द्विपक्षीय संस्थागत सुरक्षा वार्ता में भाग लेने हेतु 1 नवंबर, 2015 को बहरीन की यात्रा की थी। प्रतिनिधिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक अध्ययन संस्थान द्वारा 30 अक्तूबर से 1 नवंबर, 2015 को बहरीन में आयोजित मनामा वार्ता के 2015 संस्करण में भी भाग लिया था।

प्रवासी भारतीय मंत्रालय से एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने श्रम एवं मानवशक्ति विकास पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक में भाग लेने के लिए 15–16 अप्रैल, 2015 को बहरीन की यात्रा की थी।

बहरीन–भारत संयुक्त व्यवसाय समिति की पहली बैठक 28–30 सितंबर, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बहरीन चेंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के श्री खालिद अल अमिन ने बहरीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के श्री नितिन जोशी ने भारतीय प्रतिनिमंडल का नेतृत्व किया था।

दो भारतीय नौसेना जहाजों – आई एन एस ''दीपक'' तथा ''तलवार'' की 9–12 सितंबर, 2015 तक बहरीन की सद्भावना यात्रा के माध्यम से इस वर्ष को चिन्हित किया गया था।

बहरीन में 23–24 जनवरी, 2016 को हुई प्रथम भारत–अरब लीग मंत्री स्तरीय बैठक के अवसर पर भारत गणराज्य की सरकार तथा बहरीन अधिराज्य सरकार के बीच सजायाफ्ता व्यक्तियों के अंतरण संबंधी एक करार पर हस्ताक्षर किए गए।

ईरान

भारत–ईरान के बीच ऐतिहासिक संबंध है जो करीबी सांस्कृतिक तथा सभ्यतामूलक समानताओं पर आधारित है। आधुनिक दौर में, भारत–ईरान संबंध 9 जुलाई, 2015 को ऊफा, रूस में ईरान के राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधानमंत्री के बीच बैठक सहित नियमित बातचीत तथा उच्च–स्तरीय परामर्शों द्वारा चिन्हित किए गए हैं। ईरान भारतीय अर्थव्यवस्था हेतु कच्चे तेल का एक प्रमुख स्रोत है। भारत ईरान संबंध को व्यापार तथा वाणिज्य, उद्योग, ऊर्जा (भारत को ईरान से गैस अंतरित करने सहित), परिवहन तथा संचार, कृषि, कोंसुली, शिक्षा तथा संस्कृति जैसे विविध क्षेत्रों में फैले संबंधों द्वारा चिन्हित किया गया है।

प्रधानमंत्री ऊफ़ा, रूस (9 जुलाई 2015) में 7वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के साथ मुलाकात करते हुए।

नई दिल्ली में हस्ताक्षर समारोह में विदेश मंत्री तथा ईरान के आर्थिक कार्य एवं वित्त मंत्री अली तैयेबनिया (28 दिसंबर 2015)।

विदेश सचिव ने 13–14 जून, 2015 को तेहरान में विदेशी कार्यालय परामर्श का आयोजन किया जिसमें संयुक्त आयोग बैठक (जेसीएम) के मुख्य संस्थागत तंत्र को अर्थपूर्ण ढंग से पुनर्निमित करने का प्रस्ताव रखा गया था। ईरानी पक्ष के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया था कि विदेश मंत्री तथा ईरानी आर्थिक एवं वित्त मंत्री जेसीएम की सह–अध्यक्षता करते रहेंगे और 3 मुख्य संयुक्त कार्य समूहों –1. व्यापार संबंधी संयुक्त कार्य दल 2. अवसंरचना तथा पोत संबंधी संयुक्त कार्य दल तथा 3. ऊर्जा संबंधी संयुक्त कार्य दल के कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे।

विदेश मंत्री तथा डॉ. अलि तेयबिना, आर्थिक एवं वित्ती मंत्री, ईरान ने 28 दिसंबर, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त आयोग बैठक की सह–अध्यक्षता की थी। 18–19 नवंबर, 2015 को व्यापार संबंधी संयुक्त कार्य दल की बैठक आयोजित की गई थी और संयुक्त आयोग की बैठक के अवसर पर ही ऊर्जा एवं अवसंरचना पर संयुक्त कार्य समूहों की बैठक की गई थी।

18–19 मई, 2014 को तेहरान में आयोजित भारत–ईरान संयुक्त कोंसुली समिति की 8वीं बैठक की आगे की कार्यवाही के रूप में 18–19 अप्रैल, 2015 को तेहरान, ईरान में संयुक्त सचिव (सीपीवी) तथा महानिदेशक, कोंसुली मामले, ईरानी विदेश मंत्रालय की सह–अध्यक्षता में राजनयिक तथा आधिकारिक/सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए द्विपक्षीय वीजा सुविधा करार को अंतिम रूप देने हेतु बातचीत के लिए अलग से एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में भारत तथा ईरान के बीच राजनयिक तथा आधिकारिक/सेवा पासपोर्ट धारकों हेतु वीजा जारी करने को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रस्तावित करार के बारे में परस्पर सहमति से एक मसौदा पाठ तैयार किया गया जिस पर दोनों पक्षकारों ने हस्ताक्षर किए थे। 18 दिसंबर, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त कोंसुली समिति की 9वीं बैठक में इस करार पर हस्ताक्षर किए गए थे और 28 दिसंबर, 2015 को संयुक्त आयोग की बैठक में इसका आदान–प्रदान किया गया था।

सड़क परिवहन, राजमार्ग तथा पोत परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 5–7 मई, 2015 को ईरान की यात्रा की तथा चाहबहार पोत पर एक अंतर–सरकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इंडिया पोर्ट ग्लोबल प्राइवेट तथा आर्य बनादर के बीच संविदा हेतु बातचीत जारी है।

अगस्त 2014 में सफल परीक्षण के बाद 19–21 अगस्त, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित विशेषज्ञ समूह की 7वीं बैठक तथा अंतर्राष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारे (आईएनएसटीसी) के समन्वय परिषद की 6वीं बैठक का आयोजन किया गया था।

भारत ने ''कार्यान्वयन दिवस'' (16 जनवरी, 2016) को ईरान पर लगे कुछ प्रतिबंधों को हटाने का स्वागत किया। 4 फरवरी, 2016 को नई दिल्ली में विदेश सचिव और ईरान के उप विदेश मंत्री के बीच हुई विदेशी कार्यालय परामर्श में विशेष तौर पर आर्थिक सहयोग का विस्तार करने पर बल दिया था।

इराक

भारत का इराक के साथ परंपरागत रूप से ऐतिहासिक, घनिष्ठ और बहुआयामी संबंध है तथा हम आतंकवाद के विरुद्ध जंग में उनका समर्थन करते हैं। इराक भारत को कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता राष्ट्र बना हुआ है तथा ऊर्जा सुरक्षा के लिए हमारी खोज में एक विश्वसनीय साझेदार बना हुआ है।

जून, 2014 में आईएसआईएस द्वारा किए गए आक्रमण के परिणामस्वरूप इराक में बनी हुई नाजुक सुरक्षा स्थिति भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इराक में अस्थिर सुरक्षा स्थिति के बावजूद भारत ने इराक सरकार के साथ करीबी संपर्क बनाने के लिए बगदाद में अपना मिशन खोला हुआ है और भारतीय नागरिकों को कोंसुली सहायता प्रदान करने के लिए इरबिल तथा कुर्दिस्तान में नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। इराक में संकट की स्थिति की शुरूआत में ही भारत सरकार ने लगभग 7,195 भारतीय नागरिकों को इराक से सुरक्षित निकालने में सहायता प्रदान की है।

इराक गणराज्य के विद्युत मंत्रालय से उप मंत्री वितरण कार्य के नेतृत्व में चार–सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत से विद्युत उपकरण प्राप्त करने हेतु संभावनाओं की तलाश के लिए 6–10 मई 2015 तक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) का दौरा किया था।

16 नवंबर, 2015 को नई दिल्ली में प्रथम द्विपक्षीय विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया गया। इराकी पक्ष का नेतृत्व इराक के विदेश मंत्रालय के द्विपक्षीय संबंधो के लिए उप मंत्री श्री नजर अल–खैरूल्लाह ने किया तथा भारतीय पक्ष का नेतृत्व श्री अनिल वाधवा, सचिव(पूर्व) ने किया था। दोनों पक्षों ने राजनीतिक, रक्षा एवं सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को संवर्धित करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया था तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मामलों पर विचारों का आदान प्रदान किया था। इराकी प्रतिनिधिमंडल ने 17 नवंबर, 2015 को फिक्की के सदस्यों के साथ बैठक भी की थी तथा द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार और व्यापार एवं वाणिज्य के लंबित मुद्दों से निपटने के उपायों पर चर्चा भी की थी।

इजराइल

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, भारत–इजराइल द्विपक्षीय संबंध साइबर सुरक्षा तथा अंतरिक्ष जैसे नए क्षेत्रों में विस्तारित होने के साथ–साथ रक्षा तथा कृषि जैसे सहयोग के परंपरागत क्षेत्र

में भी मजबूत हुए हैं। 13–15 अक्तूबर, 2015 तक राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी इजराइल की पहली राजकीय यात्रा इस अवधि की विशेष घटना थी। राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन तथा प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतान्याहू के साथ बैठक के अतिरिक्त राष्ट्रपति ने इजराइली संसद ने सेट के एक सत्र को संबोधित किया तथा भारत–इजराइल संबंधों पर एक नीति–परक वक्तव्य दिया था। इस यात्रा के दौरान विश्वविद्यालयों के बीच 8 करारों सहित कई अन्य करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

एयर स्टाफ वार्ता तथा यात्राओं के आदान–प्रदान जैसे संस्थागत तंत्रों के माध्यम से रक्षा सहयोग में प्रगति हुई। आईएनएस त्रिकंद ने अगस्त में हाइफा में रुकने की अनुमति मांगी थी। संयुक्त रूप से विकसित बरक–8 मिसाइल का नवंबर में इजराइल में सफलतापूर्ण प्रक्षेपण किया गया था। नियमित उच्च–स्तरीय रक्षा आदान–प्रदान के भाग के तौर पर इजराइल के नौ–सेना तथा वायु–सेना प्रमुखों ने भारत की यात्रा की। अंतर–सरकारी करार के कार्यान्वयन के माध्यम से स्वदेशी सुरक्षा में सहयोग को मजबूत किया गया था। पुलिस आधुनिकीकरण, क्षमता निर्माण तथा सीमा प्रबंधन संबंधी कार्य समूहों ने इस अवधि के दौरान इजराइल में मुलाकात की थी तथा इन क्षेत्रों में सहयोग के विशेष क्षेत्रों का आकलन किया था।

अन्य क्षेत्रों में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तथा इजराइल अंतरिक्ष एजेंसी के बीच द्विपक्षीय बैठक अक्तूबर में जेरूसलम में हुई थी। साइबर के क्षेत्र में कॉनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई) तथा तेल अवीव विश्वविद्यालय के बीच जून में चौथी साइबर गोलमेज बैठक हुई थी। इस गोलमेज बैठक में दोनों पक्षों के उद्योग तथा शिक्षा से विशेषज्ञ शामिल थे। इसके बाद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर ने इजराइली विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग के क्षेत्र के विभिन्न मॉडलों पर चर्चा कर रहा है। इस अवधि के दौरान भारतीय संस्थानों और इजराइली विश्वविद्यालयों के बीच अकादमिक संबंधों में वृद्धि हुई है। कृषि के क्षेत्र में, भारत–इजराइली कृषि सहयोग (2015–18) का तीसरा चरण सितंबर में आरंभ हुआ था। अगस्त में कृषि में उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन गुजरात में किया गया था।

अक्तूबर, 2015 में इजराइल में 8वां भारत–इजराइल मंच का आयोजन किया गया था। विविध चर्चाओं में अन्य बातों के साथ–साथ द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश, विविध वस्तुओं तथा रक्षा साझेदारी में नए आयाम जैसे विषय शामिल थे। भारतीय यहूदी समुदाय तक मिशन की पहुंच में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अगस्त में भारतीय यहूदियों के लिए तीसरा सम्मेलन हुआ था जिसमें समुदाय के सभी वर्गों ने भाग लिया था। इस अवधि के दौरान आरंभ की गई ओपन हाउस तथा अन्य नई कोंसुली पहलों को इजराइल में भारतीय प्रवासी समुदायों द्वारा स्वेच्छा से स्वीकार किया गया था।

माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 17–18 जनवरी, 2016 तक इजराइल की द्विपक्षीय यात्रा की थी। यह विदेश मंत्री की पहली इजराइल यात्रा थी जिसने इजराइल के साथ भारत के बहुमुखी संबंधों को और आगे बढ़ाया गया था।

जॉर्डन

जॉर्डन के हाशिमी अधिराज्य के नरेश महामहीम अब्दुल्ला–।। इबन अल हुसैन के निमंत्रण पर राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 10–12 अक्तूबर, 2015 तक जॉर्डन की राजकीय यात्रा की थी तथा परस्पर हित के द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहुलओं, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की थी।

अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों तथा उच्च–स्तरीय मिलिटरी एवं आसूचना अधिकारियों के स्तर पर पूर्व अफ्रीका शिखर सम्मेलन (अकाबा 3 बैठक) 23–24 जनवरी, 2016 तक अकाबा में हुई थी। भारत ने आतंकवाद विरोध पर विशेष प्रतिनिधि के तौर पर भाग लिया था।

10–12 जनवरी, 2016 को विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में सीआईआई साझेदारी शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत जॉर्डन व्यावसायिक मंच का आयोजन किया गया था।

भारतीय पक्ष से उप–राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी और जॉर्डन पक्ष से महानिदेशक, आसूचना के स्तर पर भारत तथा जॉर्डन के बीच एक सुरक्षा वार्ता तंत्र संस्थागत किया गया था।

कुवैत

भारत और कुवैत के बीच घनिष्ठ, बहुविद् तथा मैत्रीपूर्ण संबंधों को इस वर्ष के दौरान और मजबूत किया गया था। भारत कुवैत के प्रमुख दस व्यापार साझेदारों में बना हुआ है तथा कुवैत भारत को कच्चे तेल तथा एलपीजी का विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता बना हुआ है जो हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 6ः भाग को पूरा करता है। 8,00,000 के लगभग का भारतीय समुदाय कुवैत का सबसे बड़ा प्रवासी भारतीय समुदाय है।

हाइड्रोकार्बन पर भारत–कुवैत संयुक्त कार्य दल की चौथी बैठक 15–16 सितंबर, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार (डीटीएएः तथा राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए भारत तथा कुवैत के बीच करार को संशोधित करते हुए प्रोतोकॉल पर 25 अगस्त 2015 को कुवैत में हस्ताक्षर किए गए थे। नवंबर, 2013 में कुवैती प्रधान मंत्री की नई दिल्ली की राजकीय यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित भारत तथा कुवैत के बीच सजायाफ्ता व्यक्तियों के ह्स्तांतरण करार 3 अप्रैल, 2015 से लागू हुआ था।

विदेश मंत्री और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त रूप से यरूशलेम (18 जनवरी 2015) में मीडिया को संबोधित करते हुए।

राष्ट्रपति ने अम्मान, जॉर्डन में अल हुसैनिया पैलेस (10 अक्टूबर, 2015) में जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात करते हुए।

कुवैत वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान (केआईएसआर) से आठ–सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 25–26 मई, 2015 को नई दिल्ली की यात्रा की और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) नई दिल्ली के अधिकारियों के साथ बैठक की। 30 सितंबर, 2015 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) तथा कुवैत वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान (केआईएसआर) के बीच द्विपक्षीय सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

श्री बी. अशोक, अध्यक्ष, आईओसीएल ने 5–6 अप्रैल, 2015 तक कुवैत की यात्रा की जिसके अनुसरण में आईओसीएल तथा केपीसी के बीच तेल क्षेत्र में वाणिज्यिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के सीईओ श्री निजार अल–अद्सानी ने 20 अगस्त, 2015 को नई दिल्ली की यात्रा की।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के सहयोग से सीआईआई ने 14–16 सितंबर, 2015 तक कुवैत के ''द बिग 5 कुवैत'' में ''इंडिया पवेलियन'' का आयोजन किया गया था जो कि अंतर्राष्ट्रीय निर्माण प्रोद्यौगिक तथा निर्माण सामग्री व्यापार प्रदर्शनी थी। लर्सेन एंड टर्बो लिमिटेड, एस्सार प्रोजेक्टस लिमिटेड, कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड सहित कुछ प्रमुख भारतीय कंपनियों को हाइड्रोकार्बन और निर्माण क्षेत्रों में कुवैत में 2015 के दौरान लगभग 900 मिलियन अमरीकी डॉलर की लागत वाली ईपीसी संविदा प्रदान की गई थी।

भारतीय नौसेना के दो जलपोतों ''आईएनएस दीपक'' तथा ''आईएनएस तबर'' ने 13–16 सितंबर, 2015 तक कुवैत की सद्भावना यात्रा की थी।

दिसंबर, 2015 को कुवैत निवेश प्राधिकरण ने जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में 300 मिलियन अमरीकी डॉलर निवेश करने की घोषणा की।

कुवैत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अवर सचिव के नेतृत्व में तीन सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने विशाखापट्टनम में 10–12 जनवरी, 2016 को हुए साझेदारी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। कुवैती वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री डॉ. यूसेफ मोहम्मद अब्दुल्ला अल–अली ने मुंबई में 13–18 फरवरी, 2016 को ''मेक इन इंडिया सप्ताह'' में एक कुवैती प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

लेबनान

मई, 2014 से लेबनान एक राष्ट्रपति का चुनाव भी नहीं कर पाया है। इसी प्रकार 2015 के दौरान कई मुद्दे का समाधान अथवा कार्यान्यवन नहीं हो पाया है जैसे कि निर्वाचन संबंधी नए कानून, संसदीय चुनाव तथा तेल एवं गैस अन्वेषण निविदाओं पर निर्णय। चूंकि अर्थव्यवस्था धीमी हुई है परंतु अवसंरचना तथा सिविल समुदाय पर सीरियाई शरणार्थियों का दबाव ज्यों का त्यों बना हुआ है। उत्तर लेबनान में सेना ने अब तक सीरिया में इस्लामिक स्टेट तथा अस–शाम (आईएसआईए) और अन्य जेहादी बलों द्वारा लेबनान के प्रांत में घुसपैठियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है तथा सुरक्षा बलों ने कुछ हद तक देश में आतंकवाद की वारदातों को कम करने में सफलता प्राप्त किया है, हांलाकि नवंबर, 2015 में बेरूत में विध्वंसकारी आत्मघाती हमले हुए थे।

द्विपक्षीय रूप से अकादमिक तथा सांस्कृतिक संबंध, संबंधों के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। लेबनान अमरीकन विश्वविद्यालय में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पहली पीठ स्थापित की गई। आईसीसीआर अध्येतावृत्ति पहली बार एक लेबानीज को प्रदान की गई तथा पहली बार एक लेबानीज प्रतिनिधिमंडल ने वार्षिक ऑबसर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) युवा शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। पुनः पहली बार लेबनान के टूर परिचालकों के एक प्रतिनिधिमंडल को इस वर्ष केरल के अभिज्ञता टूर के लिए प्रायोजित किया गया था। महात्मा गांधी के जन्मदिन को इस वर्ष भारतीय यूएनआईएफआईएल दल के सहयोग से दक्षिण लेबनान में आयोजित प्रथम ''रन फॉर पीस'' द्वारा चिन्हित किया गया था। दूतावास नियमित तौर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है जैसे कि पैनल चर्चा, भारतीय दिवस, खाद्य महोत्सव, लोक नृत्य तथा कठपुतली प्रदर्शन, भारतीय फिल्मों की सक्रीनिंग आदि। स्थानीय प्रदर्शनियों में सहभागिता के साथ व्यापार प्रक्षेपण जारी रहा जिसमें आर्ट ऑफ लिविंग मेले में एक भारतीय पवेलियन में बजाज पल्सर मोटरबाइक तथा बजाज ऑटो रिक्शा, केल्विनेटर जनरेटर तथा भारत से मशीनी कलपुर्जों के रूप में वाटर पंप का प्रदर्शन किया गया, काफी लोग इसकी ओर आकृषित हुए थे।

ओमान

ओमान भारत का समुद्री पड़ोसी है तथा ओमान के साथ हमारे द्विपक्षीय ऐतिहासिक संबंध रणनीतिक साझेदारी में विकसित हुए हैं। वर्ष 2015 भारत तथा ओमान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की हीरक जयंती विशेष तौर पर उल्लेखनीय रहा तथा इसकी 60वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

फरवरी, 2015 में विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज की मस्कट की पहली राजकीय यात्रा ने ओमान के साथ भारत की साझेदारी को नई गति प्रदान की, जिसे 2015–16 में और मजबूत किया गया था। संयुक्त राष्ट्र शासी परिषद (यूएनजीए) के 70वें सत्र के अवसर पर, विदेश मंत्री ने भारत जीसीसीएफटीए तथा भारत जीसीसी रूपरेखा करार को शीघ्र अंतिम रूप देने संबंधी चर्चा के लिए 30 सितंबर, 2015 को ओमान के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी।

उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉ. अरविंद गुप्ता ने अपने ओमानी समकक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महासचिव मेजर जनरल अहमद सलमान खुशबू के साथ रणनीतिक वार्ता का तीसरा दौर आयोजित करने के लिए 2–5 नवंबर, 2015 तक ओमान की यात्रा की थी। यात्रा के दौरान उन्होंने विदेश मंत्री, तेल एवं गैस मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय के महासचिव के साथ मुलाकात की थी।

सुरक्षा तथा रक्षा के क्षेत्रों में सहयोग भारत–ओमान साझेदारी के दो प्रमुख स्तंभ हैं। ओमान ने सुरक्षा मामलों में सहयोग जारी रखा है। जिसमें यमन में फंसे भारतीयों को निकालने में सहायता शामिल है। ओमानी प्राधिकारियों की सहायता से सलालाह में ओमान–यमन सीमा के माध्यम से यमन में फंसे पंद्रह भारतीय छात्रों को निकाला गया था।

इस वर्ष के दौरान भारत तथा ओमान के बीच रक्षा संबंधों में और विस्तार हुआ है। ओमान खाड़ी क्षेत्र का अकेला ऐसा देश है जिसके साथ भारत के सभी तीन रक्षा दल संयुक्त अभ्यास करते हैं।

भारतीय वायु सेना प्रमुख, एयर मार्शल राहा ने अगस्त 2015 में ओमान की यात्रा की तथा रॉयल एयर फोर्स के कमांडर, सुल्तान की सशस्त्र सेना के चीफ ऑफ स्टाफ तथा रक्षा मंत्रालय के महासचिव के साथ बैठक की थी। ओमान के रॉयल नेवी के कमांडर ने 7–10 सितंबर, 2015 तक भारत की यात्रा की तथा अपने भारतीय समकक्ष के साथ मुलाकात की थी।

भारतीय नौसेना तथा तट रक्षा जहाजों ने मस्कट तथा सलालाह को पड़ाव–पत्तन बनाना जारी रखा है। आईएनएस तरंगिनी ने मई 2015 में मस्कट की यात्रा की थी। पश्चिमी भारतीय नौसेना के चार जहाज, आईएनएस दीपक, दिल्ली, तबर तथा त्रिशूल ने सितंबर, 2015 में एक साथ मस्कट पत्तन की यात्रा की थी। नौकायन जहाज आईएनएस तरंगिनी तथा ओमान के रॉयल नेवी के नौकायन जहाज ''शबाब ओमान'' ने नवंबर–दिसंबर, 2015 में मस्कट से कोची तक एक संयुक्त यात्रा में एक साथ यात्रा की थी। उनकी संयुक्त यात्रा के माध्यम से उन्होंने भारत तथा ओमान के बीच हिंद महासागर से होकर प्राचीन मसाला व्यापार मार्ग का पता लगाया। जलदस्युता–रोधी तथा अन्य ऑपरेशनों में शामिल भारतीय नौसेना के जहाज अपने कार्य के लिए सलालाह पोत पर रुकते हैं। इसी प्रकार भारतीय वायु सेना तथा नौसेना के विमान तकनीकी तथा प्रचालन के संबंध में ठहरने के लिए मस्कट तथा सलालाह हवाईअड्डे का प्रयोग करते हैं।

स्वास्थ्य सुरक्षा देखभाल संस्थानों/अस्पतालों से सात तथा खाद्य उद्योग से पंद्रह फर्मों ने सितंबर, 2015 में ओमान मेडहेल्थ तथा कल्याण प्रदर्शनी और ओमान खाद्य एवं आतिथ्य प्रदर्शनी में भाग लिया। नवंबर, 2015 में मस्कट में आयोजित प्रथम खनिज एवं खान प्रदर्शनी में तीन भारतीय कंपनियों ने भाग लिया।

स्वास्थ्य सुरक्षा देखभाल संस्थानों/अस्पतालों से सात तथा खाद्य उद्योग से पंद्रह फर्मों ने सितंबर, 2015 में ओमान मेडहेल्थ तथा कल्याण प्रदर्शनी और ओमान खाद्य एवं आतिथ्य प्रदर्शनी में भाग लिया था। नवंबर, 2015 में मस्कट में आयोजित प्रथम खनिज एवं खान प्रदर्शनी में तीन भारतीय कंपनियों ने भाग लिया था।

ओमान में भारतीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ओमान के आंतरिक निवेश एवं निर्यात प्रचार एजेंसी, इथरा के अध्यक्ष ने 10–13 अगस्त, 2015 तक भारत में खाद्य प्रसंस्करण, उर्वरक तथा प्लास्टिक क्षेत्र से चौदह ओमानी कंपनियों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया तथा एक व्यावसायिक सम्मेलन में सीआईआई के साथ एक विचार विमर्श सत्र का आयोजन किया था और भारतीय आयातकों, एजेंट तथा विनिमार्ताओं के साथ बी2बी बैठकें आयोजित की। अक्तूबर में इथरा के द्वारा भारत–ओमान निवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें बारह भारतीय कंपनियों ने भाग लिया था।

भारत ने एक पवेलियन की स्थापना करके वार्षिक मस्कट महोत्सव (जनवरी–फरवरी, 2015) में भाग लिया। आईसीसीआर द्वारा प्रायोजित भांगड़ा तथा गिद्दा समूहों ने महोत्सव में अपनी प्रस्तुती दी। 60वीं वर्षगांठ समारोह के भाग के रूप में अप्रैल, 2015 में स्थानीय सिनेमा तथा यशराज फिल्म के सहयोग से एक फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था और अक्तूबर, 2015 में 30 से अधिक परंपरागत भारतीय वस्त्र को दर्शाते हुए ''वस्त्रम–स्प्लेंडिड वर्ल्ड ऑफ इंडियन टेक्सटाइल'' नामक एक भारतीय वस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया था । राजस्थान से एक परंपरागत नृत्य समूह ने नवंबर, 2015 में मस्कट, सोहार, सुर तथा सलालाह में वार्षिक भारतीय सामुदायिक महोत्सवों में प्रदर्शन किया था।

आठवीं भारत–ओमान संयुक्त परामर्शी समिति की बैठक 8–9 फरवरी 2016 को मस्कट में हुई। भारतीय प्रतिनिमंडल का नेतृत्व रक्षा सचिव ने किया।

फिलिस्तीन

12–13 अक्तूबर, 2015 तक राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी की फिलिस्तीन की अब तक की पहली राजकीय यात्रा थी। राष्ट्रपति मुखर्जी ने राष्ट्रपति महमूद अब्बास, प्रधानमंत्री डॉ. रमि हमदल्लाह तथा फिलिस्तीनी राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात की और फिलिस्तीन के लिए भारत के मजबूत समर्थन को दोहराया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने फिलिस्तीन सरकार की क्षमता निर्माण एवं मानव संसाधन विकास से जुड़े पहलों का समर्थन करने के लिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया था।

प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर, 2015 में फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भारत का सहयोग

फिलिस्तीन (12 अक्टूबर 2015) की राजकीय यात्रा के दौरान रामल्लाह में राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत

प्रधानमंत्री सऊदी अरब के शाह, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ जी –20 शिखर सम्मेलन के मौके पर अंताल्या में बैठक करते हुए (16 नवंबर, 2015)

व्यक्त किया। यह वर्ष भारत तथा फिलिस्तीन के बीच अभूतपूर्व उच्च–स्तरीय राजनीतिक वार्ता द्वारा भी चिन्हित किया गया है। प्रधान मंत्री मोदी ने सितंबर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा बैठक के अवसर पर न्यूयार्क में राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने नवंबर, 2015 में बांडुंग, इंडोनेशिया में जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक शिखर सम्मेलन के अवसर पर पेरिस में पुनः मुलाकात की। विदेश मंत्री ने अप्रैल, 2015 में बांडुंग, इंडोनेशिया में एशिया अफ्रीका स्मरणोत्सव सम्मेलन के अवसर पर प्रधान मंत्री डॉ. रमि हमदुल्लाह तथा विदेश मंत्री डॉ. रियाद अलमल्की से मुलाकात की थी। सचिव (पूर्व) ने जुलाई, 2015 में फिलिस्तीन की यात्रा की थी तथा प्रधानमंत्री डॉ. रमि हमदल्लाह को आमंत्रित किया एवं उप मंत्री, विदेश मंत्रालय डॉ. तयसिर जरादत के साथ बैठक की। भारत तथा फिलिस्तीन के बीच अब तक का पहला विदेशी कार्यालय परामर्श मई, 2015 को रामल्लाह में आयोजित किया गया था।

वर्ष 2015 के दौरान, मध्यपूर्व शांति प्रक्रिया में कोई प्रगति नहीं हुई है। वर्ष के उत्तरार्ध में हिंसा की छिटपुट घटनओं से तनाव में वृद्धि हुई थी जिसके कारण फिलिस्तीन में जान–माल का भारी नुकसान हुआ। भारत ने संयम बरतने और दोनों पक्षों को उत्तेजना से बचने की आवश्यकता पर बल दिया है।

वर्ष के दौरान भारत ने फिलिस्तीन को 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की कुल वित्तीय सहायता प्रदान की। 4 मिलियन अमरीकी डॉलर 12 जनवरी, 2015 को गाजा के पुनर्निमाण के लिए परियोजना सहायता के रूप में प्रदान किया गया था, 5 मिलियन अमरीकी डॉलर 12 अक्तूबर, 2015 को बजटीय सहायता के रूप में प्रदान किया गया था और 1 मिलियन अमरीकी डॉलर 25 नवंबर, 2015 को फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी को दिया गया था। भारत ने फिलिस्तीनियों के लिए भारत में उच्चतम शिक्षा हेतु 10 आईसीसीआर प्रायोजित छात्रवृत्तियां प्रदान की है। भारतीय तथा फिलिस्तीनी विश्वविद्यालयों ने इस यात्रा के दौरान अकादमिक सहयोग तथा संयुक्त अनुसंधान पर 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत फिलिस्तीनी नागरिकों को 2015 में प्रशिक्षण कोर्स के लिए 80 स्लॉट प्रदान किए गए थे।

21 जून, 2015 को फिलिस्तीन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। प्रतिनिधि कार्यालय ने भारतीय सांसकृतिक संबंध परिषद की सहायता प्रायोजन से भारत में इस्लामिक स्मारकों की प्रदर्शनी तथा डॉ. वर्षा अग्रवाल द्वारा एक संतूर प्रस्तुति का आयोजन किया गया था। इस अवधि के दौरान पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने एक भारतीय खाद्य महोत्सव, भारतीय बाजार तथा तीन फिलिस्तीन टूर संचालकों के लिए भारत का अन्वेषण टूर प्रायोजित किया था।

माननीय विदेश मंत्री ने 17 जनवरी, 2016 को रामल्लाह की यात्रा की। इस यात्रा ने फिलिस्तीनी नेताओं के साथ भारत के संबंधों को और नवीकृत किया तथा फिलिस्तीन के आंदोलन के लिए भारत के मजबूत समर्थन को भी दोहराया था।

सऊदी अरब

भारत और सऊदी अरब के बीच सौहार्दपूर्ण एवं मित्रवत संबंध हें जो वर्षों पुरानी आर्थिक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक संबंधों के प्रतिबिंब है। सऊदी अरब लगभग 2.75 मिलियन भारतीय प्रवासियों की मेजबानी करता है भारत के बाहर भारतीय पासपोर्ट धारकों का सबसे बड़ा समुदाय है। दोनों देशों ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा तथा सुरक्षा सहयोग में नियमित प्रगति की है। दोनों पक्ष नियमित रूप से उच्च–स्तरीय यात्राओं का विनिमय करते हैं और विभिन्न स्तरों पर जुड़े हुए हैं।

प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 नवंबर, 2015 को अन्तल्या, तुर्की में जी–20 बैठक के अवसर पर सऊदी नरेश सलमान बिन अब्दुलाजीज अल साउद के साथ मुलाकात की।

सऊदी वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री डॉ. तौफीक अल राबीह तथा वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली की सह–अध्यक्षता में ग्यारहवीं संयुक्त आयोग की बैठक 28 मई, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। सऊदी वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने विदेश मंत्री तथा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के साथ भी बैठक की और द्वि पक्षीय हित के मुद्दों पर चर्चा की।

आर्थिक संबंध भारत–सऊदी ''रणनीतिक साझेदारी'' का मूलभूत अंग है। सऊदी अरब भारत की तेल आवश्यकताओं की लगभग 20ः की आपूर्ति करता है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा में प्रमुख भूमिका अदा करता है। सऊदी अरब 39 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है।

सऊदी पेट्रोलियम उप मंत्री श्री नैफ अल ओताइबी के नेतृत्व में एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने 16 अक्तूबर, 2015 को भारत की यात्रा की तथा एंटी–डंपिंग मुद्दों पर चर्चा करने हेतु वाणिज्य सचिव एवं अन्य अधिकारियों के साथ मुलाकात की थी।

सऊदी अरब के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के उद्योग मामलों के उप मंत्री इंजीनियर सलेहबिन शबाब अल सोलमि की अध्यक्षता में एक सरकारी तथा व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल ने 8–10 दिसंबर, 2015 तक भारत की यात्रा की और भारत के वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी।

तीस सऊदी व्यावसायिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अप्रैल, 2015 के दौरान नई दिल्ली में सेवाओं पर एक वैश्विक प्रदर्शनी में भाग लिया था। अगस्त, 2015 में 12 सऊदी व्यवासायिकों ने मुंबई में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आभूषण प्रदर्शनी में भाग लिया था।

भारत–सऊदी अरब व्यावसायिक परिषद की पहली बैठक 14 दिसंबर, 2015 को नई दिल्ली में हुई थी। सऊदी–भारत व्यावसायिक परिषद के सह–अध्यक्ष श्री कामेल अल–मुनाज्जेवद ने सऊदी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था।

घरेलू नौकरों की भर्ती पर भारत तथा सऊदी–अरब अधिराज्य के बीच श्रमिक सहयोग पर करार के तहत 12–13 अक्तूबर, 2015 को नई दिल्ली में दूसरी संयुक्त तकनीकी बैठक आयोजित की गई थी।

भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तरंगिनी ने 29 मई, 2015 को जेद्दाह पोत की सद्भावना यात्रा की। भारतीय नौसेना के दो जहाजों आईएनएस दिल्ली तथा आईएनएस त्रिशूल ने भी 10–13 सितंबर, 2015 को अल–जुबैल की यात्रा की।

हज 2015 के दौरान लगभग 136000 भारतीयों ने हज के लिए सऊदी अरब अधिराज्य की यात्रा की थी। विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने 6 अक्तूबर, 2015 को सऊदी अरब अधिराज्य की यात्रा की और भारतीय हज यात्रियों के कल्याण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए सऊदी स्वास्थ्य मंत्री श्री खालिद अल फलीह के साथ बैठक की थी।

कतर

भारत तथा कतर के बीच बहु–आयामी संबंधों को इस वर्ष के दौरान और मजबूत किया गया है। अप्रैल, 2015 में अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय पर दोहा में आयोजित 13वीं संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस में भाग लेने के लिए कानून तथा न्याय मंत्री श्री डी.बी. सदानंद गौड़ा ने एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। यात्रा के दौरान उन्होंने कतर के न्याय मंत्री डॉ. हसन बिन लहद्न अल हसन अल मोहान्नादि के साथ मुलाकात की थी।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के लिए राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने छठे एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक उच्च–स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए 8–10 नवंबर, 2015 तक दोहा की यात्रा की थी। यात्रा के दौरान, उन्होंने कतर के गृह मंत्री तथा प्रधान मंत्री शेख अब्दुल्लाह बिन नासेर खलीफा अल थानी के साथ एक शिष्टाचार मुलाकात की थी। उन्होंने अपने कतरी समकक्ष डॉ. मोहम्मद बिन सलेह ए सदा के साथ भी मुलाकात की थी।

6 जनवरी, 2015 को नई दिल्ली में चौथी द्विपक्षीय संयुक्त रक्षा सहयोग समिति हुई। भारतीय नौसेना के पश्चिमी बल के दो युद्ध पोतों आएनएस दिल्ली तथा आईएनएस त्रिशूल ने 14–17 सितंबर, 2015 को दोहा की सद्भावना यात्रा की। भारतीय तटरक्षक पोत संकल्प ने अरब की खाड़ी में विदेश तैनाती के एक भाग के रूप में 24–28 जनवरी 2016 तक दोहा का दौरा किया।

भारत तथा अरब के बीच मौजूद मोती व्यापार मार्ग का पता लगाने के लिए सांस्कृतिक समुद्री यात्रा, फतह अल खैर के दूसरे संस्करण को 5 अक्तूबर, 2015 को दोहा में हरी झंडी दी गई, जो कप्तान हसन अल कब्बि के नेतृत्व में 30 सदस्यों की एक टीम के साथ परंपरागत नौकायन जहाज पर ओमान से होकर मुंबई के भारतीय पोत की एक ऐतिहासिक 44–दिवसीय समुद्रयात्रा है। यात्रा के दौरान, चालक दल मुंबई से केरल में कालीकट तक गए और उन मुख्य स्थानों की यात्रा की जहां पूर्व में कतर सहित खाड़ी देश के लोग व्यापार करते थे और अपनी नौकायन जहाजों का निर्माण कराते थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री विद्यासागर राव 24 अक्तूबर, 2015 को मुंबई में हुए उनके स्वागत समारोह में मुख्य अतिथि थे। नौकायन जहाज 3 नवंबर, 2015 को मुंबई से दोहा के लिए रवाना हुआ था।

एसोचैम ने मई, 2015 में दोहा में अवसंरचना क्षेत्रों पर एक महत्वपूर्ण प्रदर्शनी, परियोजना कतर में लगभग साठ भारतीय कंपनियों की सहभागिता में सहयोग किया था। भारतीय इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्ट्रिकल निर्माता संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने 13–17 फरवरी, 2016 को बेंगलुरू में होने वाले ''इलेकरामा 2016'' का प्रचार करने के लिए 27 अक्तूबर, 2015 को कतर की यात्रा की।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 19–20 मार्च तक ''ए पैसेज टू इंडिया'' सामुदायिक महोत्सव और 5–6 अगस्त, 2015 को आईसीसीआर–प्रायोजित एक दल द्वारा कत्थक प्रस्तुति शामिल है।

दोहा फिल्म संस्थान ने 11–12 नवंबर, 2015 को दोहा के इस्लामिक कला संग्रहालय में अपने ''स्वतंत्र भारतीय सिनेमा पर स्पॉटलाइट'' में तीन भारतीय फिल्मों की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया था।

सीरिया

सीरिया में जारी संकट के दौरान, भारत ने विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर अपनी स्थिर स्थिति बनाए हुए है। भारत ने सीरिया से जुड़े सभा पक्षों से आह्वान किया है कि वे हिंसा का परित्याग करें ताकि समावेशी राजनैतिक वार्ता के लिए विश्वासपूर्ण स्थितियां बन सकें और सीरिया के लोगों की वैध आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण राजनीतिक समाधान संपूर्ण हो सकें। भारत इस बात पर स्थिर है कि इस विवाद का कोई सैन्य समाधान नहीं है और सीरिया के मामलों में किसी बाहरी सैन्य हस्तक्षेप को दूर रखा जाना चाहिए। भारत राजनीतिक समाधान के माध्यम से सीरिया में जारी संकट को सुलझाने के लिए वैश्विक प्रयासों का समर्थन करता है। इस वर्ष के दौरान भारतीय तकनीकि तथा आर्थिक सहयोग (आईटीईसी)

प्रधानमंत्री अबू धाबी में अबू धाबी के युवराज, माननीय शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठक (16 अगस्त 2015) करते हुए।

और भारतीय तकनीकी संबंध परिषद छात्रवृत्ति के अंतर्गत सीरिया के साथ भारत का सहयोग जारी है।

संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई.)

भारत तथा यूएई के बीच परंपरागत घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों को इस वर्ष के दौरान उच्च–स्तरीय यात्राओं के आदान–प्रदान द्वारा और मजबूत किया गया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16–17 अगस्त, 2015 को यूएई की राजकीय यात्रा की थी। 34 वर्षों के अंतराल के बाद प्रधानमंत्री की इस ऐतिहासिक यात्रा से यूएई के साथ हमारे संबंधों में बदलाव आया है तथा संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया है। दोनों पक्ष न केवल मौजूदा क्षेत्रों में उपलब्धियों को समेकित करने के लिए सहमत हैं बल्कि सहयोग के नए क्षेत्र जैसे अंतरिक्ष, नवीकृत ऊर्जा तथा रक्षा उत्पादन की खोज के लिए भी सहमत हुए हैं। यह भी सहमति हुई कि अगले पांच वर्ष के दौरान द्विपक्षीय व्यापार में 60ः तक वृद्धि की जाए और यूएई के निवेश संस्थानों को भारत में अपना निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिसे अगली पीढ़ी अवसंरचना के तीव्र विस्तार के लिए भारत की योजनाओं में सहयोग हेतु 75 बिलियन अमरीकी डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य के साथ यूएई–भारत अवंसरचना निधि की स्थापना के माध्यम से किया जाएगा। दोनों पक्ष आतंकवाद–रोधी कार्यवाहियों, आसूचना साझा करने तथा क्षमता निर्माण में सहयोग को बढ़ाने और संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर भारत के प्रस्तावित विस्तृत अभिसमय को अंगीकार करने के लिए एक साथ कार्य करने के लिए भी सहमत हुए हैं।

संयुक्त अरब अमीरात के साथ हमारे बढते हुए संबंधो को अबू धाबी के युवराज महामहिम शेख मोहम्मद बिन ज़येद अल नह्यान की 10–13 फरवरी की राजकीय यात्रा के द्वारा और मजबूत किया गया था। इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में नौ करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थेः (i) साइबर स्पेस तथा साइबर संबंधी अपराधों की रोकथाम (ii) संयुक्त राज्य अमीरात में संस्थागत निवेशकों की भारत में अवसंरचनात्मक निवेशों में भागीदारी को सुविधाजनक बनाने हेतु रूपरेखा (iii) नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग पर करार की रूपरेखा (iv) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) तथा संयुक्त अरब अमीरात अंतरिक्ष एजेंसी के बीच शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग तथा खोज में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन (v) भारतीय बीमा विनियमन प्राधिकरण (आईआरडीए) तथा संयुक्त राज्य अमीरात बीमा प्राधिकरण के बीच द्विपक्षीय सहयोग (vi) भारत तथा संयुक्त राज्य अमीरात के बीच सांस्कृतिक सहयोग के लिए कार्यकारी कार्यक्रम (ईपीसीसी) (vii) क्षमता विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय योग्यता

यमन से बचाए गए भारतीयों को लेकर जिबूती पहुंचे आईएनएस मुंबई की फोटो (5 अप्रैल 2015)

प्राधिकरण (एनक्यूए), संयुक्त राज्य अमीरात के बीच क्षमता विकास तथा योग्यताओं की पहचान के लिए सहयोग संबंधी आशय पत्र (viii) दुबई आर्थिक परिषद तथा भारत के निर्यात–आयात बैंक के बीच समझौता ज्ञापन (ix) भारतीय रिजर्व बैंक तथा संयुक्त राज्य अमीरात के केंद्रीय बैंक के बीच भारतीय रुपए (आईएनआर)/संयुक्त राज्य अमीरात दिरहाम (एईडी) द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय व्यवस्था पर समझौता ज्ञापन।

वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने 15–17 नवंबर, 2015 को यू.ए.ई. की यात्रा की और अपने समकक्ष शेख हमदान तथा आबूधाबी निवेश प्राधिकरण के एमडी शेख हामेद के साथ मुलाकात की। वे 16 नवंबर, 2015 को दुबई में हुई यूएई–भारत आर्थिक मंच में एक प्रमुख वक्ता भी थे।

वाणिज्य तथा उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती निर्मला सीथारमन ने एडीआईए के साथ उच्च स्तरीय कार्य दल की तीसरी बैठक की सह–अध्यक्षता करने के लिए 12–13 अक्तूबर, 2015 तक यूएई की यात्रा की थी। यात्रा के दौरान उन्होंने आबूधाबी के युवराज शेख मुहमद बिन जायेद अल नाहयन से मुलाकात की और यूएई के उप प्रधानमंत्री शेख सैफ बिन जायेद अल नहयान के साथ बैठक की थी।

प्रवासी भारतीय मंत्रालय के सचिव श्री ए.के. अग्रवाल ने 14–17 अक्तूबर, 2015 तक यूएई की यात्रा की थी। उन्होंने संस्कृति, युवा एवं सामुदायिक विकास मंत्री शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान से मुलाकात की तथा श्रम मंत्रालय के सहायक सचिव के साथ बैठक भी की और भारतीय श्रमिकों के रोजगार एवं भर्ती से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की थी।

वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा ने 15–17 अप्रैल, 2015 को यूएई की यात्रा की तथा अपने यूएई समकक्ष श्री ओबेद अल तयेर के साथ बैठक की।

यूएई पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय यात्राओं में यू ए ई और भारत के बीच आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग पर संयुक्त समिति की 11वीं बैठक में विदेश मंत्री के साथ इसकी सह–अध्यक्षता करने के लिए यू ए ई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयन की भारत यात्रा भी शामिल है। इस यात्रा में उनके साथ विदेश राज्य मंत्री शेख रीम इब्राहित अल हाशिमी भी आए थे। इस यात्रा के दौरान पर्यटन, उच्चतर शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग, भारत तथा यूएई की संचार नियामक प्राधिकरणों के बीच सहयोग के चार समझौता ज्ञापनों और बीआईएस और ईएएसएम (अमीरात अथॉरिटी फार स्टेंडराईजेशन एंट मेटेरोलॉजी) के बीच तकनीकी सहयोग पर संशोधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

विदेश राज्य मंत्री डॉ. अनवर गर्गश ने 6–7 दिसंबर, 2015 तक भारत की यात्रा की और द्विपक्षीय हितों तथा क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की थी।

यूएई वायुसेना तथा वायुरक्षा के कमांडर के निमंत्रण पर चीफ आफ एयर स्टाफ, एयर मार्शल अरूप राहा ने 19–21 अगस्त, 2015 तक यूएई की सद्भावना यात्रा की थी। भारतीय नौसेना के चार जहाज दिल्ली, तबार, त्रिशूल तथा तबार ने 5–8 सितंबर, 2015 तक विदेशी तैनाती के रूप में दुबई, यूएई की यात्रा की थी। भारत तथा यूएई नौसेना के बीच 5वीं नौसेना स्टाफ वार्ता 16–17 सितंबर, 2015 को आबूधाबी में हुई थी। यूएई राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज से 28 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने 14–20 नवंबर, 2015 को भारत की यात्रा की थी।

यमन

भारत तथा यमन के बीच घनिष्ठ तथा लोगों के बीच ऐतिहासिक संपर्क का लंबा इतिहास है। यमन में बिगड़ती राजनीतिक एवं सुरक्षा स्थिति के कारण, भारत सरकार ने सना तथा अदिस अबाबा स्थित भारतीय मिशनों के सहयोग से अप्रैल, 2015 में लोगों को निकालने के लिए "आपरेशन राहत" नामक एक बड़ा अभियान चलाया था। 4748 भारतीय तथा 48 देशों के 1962 विदेशी नागरिकों सहित कुल 6710 लोगों को सना के हवाई अड्डे तथा अदेन, अल हुदायदाह तथा अल मुकल्ला पोत के हवाई तथा जल मार्ग से निकाला गया था।

यमन स्थित भारतीय दूतावास को 14 अप्रैल, 2015 से अस्थाई रूप से जिबूती स्थानांतरित कर दिया गया है। यह दूतावास यमन में फंसे भारतीय नागरिकों को जिबूती के माध्यम से भारत पहुंचाने में सहयोग कर रहा है।

यमन अंतर्राष्ट्रीय मामला केंद्र के निदेशक डॉ. अहमद समलेम सलेह अल–वहिशी ने समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षा पर 13–14 अक्तूबर, 2015 तक नई दिल्ली में आयोजित भारतीय समुद्री रिम संघ (आईओआरओ) विशेषज्ञों की बैठक में भाग लिया था।

अरब संघ

दिसंबर, 2013 में भारत तथा अरब संघ के बीच 2014–15 के लिए अरब–भारत सहयोग मंच के एक कार्यकारी कार्यक्रम और सहयोग ज्ञापन (एमओसी) के हस्ताक्षर के बाद भारत–अरब संघ संबंधों में सुधार आया था। अरब संघ तथा बहरीन विदेश मंत्रालय के पांच सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने नवंबर, 2015 में नई दिल्ली की यात्रा की तथा विदेश मंत्रालय के सचिव(पूर्व) के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की। उन्होंने उपराष्ट्रपति तथा विदेश मंत्री से भी मुलाकात की थी।

विदेश मंत्री ने भारत–अरब संघ की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए बहरीन की यात्रा की (23–24 जनवरी, 2016)

जिसके दौरान दोनों पक्षों ने मनामा घोषणा जारी की तथा वर्ष 2016–17 के लिए अरब–भारत सहयोग मंच के कार्यकारी कार्यक्रम को नवीकृत किया था। यह अरब–भारत सहयोग मंच के तहत पहली मंत्री स्तरीय बैठक थी तथा अरब देशों, जिससे भारत की घनिष्ठ एवं बहुविध संबंध हैं, के साथ भारत के संबंधों को संवर्द्धित किया था।

खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी)

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज तथा कतर के विदेश मंत्री डॉ. खालिद बिन मुहम्मद अल अतियाह ने 30 सितंबर, 2015 को न्यूयॉर्क में 70वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के दौरान 9वीं वार्षिक भारत–खाड़ी सहयोग परिषद राजनीतिक वार्ता की सह–अध्यक्षता की थी।

चौथी भारत–जीसीसी औद्योगिक मंच 18–19 नवंबर, 2015 को जेद्दाह, सऊदी अरब अधिराज्य में आयोजित की गई, जिसके दौरान मुक्त व्यापार क्षेत्र तथा अवसंरचना, सूचना प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य सुरक्षा, ऊर्जा खाद्य एवं कृषि में साझेदारी सहित आर्थिक तथा निवेश संबंधों पर चर्चा की गई थी।

हज

हज यात्रा भारत सरकार द्वारा भारतीय सीमापार कराए जाने वाला सबसे बड़ा क्रियाकलाप है। हालांकि यह केवल पांच दिन लंबी धार्मिक यात्रा है परंतु यथार्थ में यह एक वर्ष लंबी प्रबंधकीय अध्ययन है। भारतीय हज यात्री, हज करने वाला तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय समूह है।

हज 2015 में कुल 1,35,868 यात्रियों ने हज यात्रा की (99868 यात्रियों ने भारतीय हज समिति (एचसीओआई) तथा 36000 ने निजी टूर परिचालकों (पीटीओ) से) थी।

भारत सरकार हज यात्रा को उच्च प्राथमिकता देती है। सरकार का यह नियमित प्रयास रहता है कि हज यात्रा संबंधी मुद्दों को सुलझाया जाए और हज यात्रियों के लिए प्रबंधों में सुधार किया जाए। विदेश मंत्रालय भारत की हज समिति और भारतीय प्रधान कौंसुलावास, जेद्दा के साथ परामर्श द्वारा हज यात्रा के लिए प्रबंधों में सहयोग करता है। विदेश मंत्रालय हज यात्रियों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रति वर्ष व्यक्तियों को (समन्वयकों, सहायक हज अधिकारी, हज सहायक, डॉक्टर तथा पैरामेडिकल स्टाफ) प्रतिनियुक्ति पर भेजता है। प्रति वर्ष जेद्दा स्थित प्रधान भारतीय कौंसुलावास मीना में अस्थाई टेंट की व्यवस्था करता है, मक्का व मदीना में दवाखाना तथा हज अधिकारियों के लिए शाखा की स्थापना करता है, हज यात्रियों के लिए दवाइयों, एंबुलेंस तथा अन्य स्थानीय परिवहन आदि प्रदान करता है।

हज 2015 के लिए विदेश मंत्रालय ने प्रधान भारतीय कौंसुलावास जेद्दा को 1.76 करोड़ रुपए लागत की दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति की और 543 व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा। जेद्दा स्थित प्रधान भारतीय कौंसुलावास मक्का एवं मदीना में मुख्य कार्यालय, मक्का में 13 शाखा कार्यालय, मदीना में 3 शाखा कार्यालय, जेद्दा तथा मदीना व हज टर्मिनल में दवाखानों सहित मक्का कार्यालय में 40 बिस्तर वाला एक अस्पताल, मक्का में दवाखाना की 13 शाखा, मदीना में 10 बिस्तर वाला मुख्य चिकित्सालय तथा मदीना में दवाखाना की 3 शाखाएं स्थापित की हैं।

हज यात्रियों को बेहतर सुख–सुविधाएं एवं साधन प्रदान करने के लिए कई पहल की गई है। इसमें हज यात्रियों के लिए चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ करना, यात्रियों के लिए विमान के समयबद्ध आगमन व प्रस्थान के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करते हुए हवाई यात्रा प्रबंधों को व्यवस्थित करना, इस्लामिक विकास बैंक से अदाही कूपन की खरीद, सभी यात्रियों के लिए मानकीकृत सामान की आपूर्ति, मोबाइल फोन एप्लीकेशन का 24X7 हेल्पलाइन, भारतीय यात्रियों के लिए सूचना सहित ''भारतीय हाजी आवास लोकेटर'', तीव्र एवं प्रभावी ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली शामिल है।

माननीय संसद सदस्य (लोकसभा) सुश्री महबूबा मुफ्ती सईद तथा श्री अनवर मुहम्मद खान सहित दो सदस्यों के नेतृत्व में एक हज सद्भावना प्रतिनिधिमंडल ने सुविधाओं की प्रत्यक्ष जांच के लिए 17 सितंबर – 7 अक्तूबर, 2015 तक नेता तथा उपनेता के रूप में सऊदी अरब की यात्रा की थी। सुश्री महबूबा मुफ्ती सईद ने सऊदी अरब अधिराज्य के हज मंत्री श्री बंदेर अल हिज्जर से भी मुलाकात की तथा हज यात्रियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

11 सितंबर, 2015 को हरम शरीफ, मक्का में एक क्रेन दुर्घटना हुई जिसमें 13 भारतीय हज यात्रियों की मृत्यु हो गई थी तथा 19 घायल हुए थे। 24 सितंबर, 2015 को मीना में भगदड़ की एक घटना हुई। इस भगदड़ में 120 भारतीय हज यात्रियों की मौत हुई तथा 51 यात्री घायल हुए। 3 भारतीय यात्री लापता पाए गए थे। विदेश मंत्रालय तथा प्रधान भारतीय कौंसुलावास, जेद्दा ने मृतकों के परिजनों तथा घायलों को तत्काल सहायता प्रदान की। प्रतिनियुक्ति पर गए भारतीय डॉक्टरों तथा पैरामेडिकल स्टाफ को प्रभावित यात्रियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय कौंसुलावास, जेद्दा द्वारा तत्काल नियुक्त किया गया था।

■ ■

6

अफ्रीका

अल्जीरिया

भारत–अल्जीरिया विदेश कार्यालय परामर्श का 5वां दौर नई दिल्ली में 7 मई 2015 को आयोजित किया गया। संयुक्त सचिव (डब्ल्यूएएनए)ए विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया गया था और अल्जीरिया विदेश मंत्रालय में राजदूत श्री बोउमेडिने गुएन्नड, महानिदेशक (एशिया ओसनिया) द्वारा अल्जीरिया पक्ष का नेतृत्व किया गया था। अल्जीयर्स में 25.26 मई 2015 तक भारत – अल्जीरिया आर्थिकए व्यापारए वैज्ञानिकए तकनीकी और सांस्कृ तिक सहयोग विषयक संयुक्त आयोग का 9वां सत्र आयोजित किया गया था। माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)ए श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था और श्री बोडजेमा तलाईए अल्जीरिया के परिवहन मंत्री द्वारा अल्जीरिया के शिष्टमंडल का नेतृत्व किया गया था।

भारत ने अल्जीरिया के निमंत्रण पर ″सम्मानित अतिथि″ देश के रूप में 48वें अल्जीरियाई अंतरराष्ट्रीय मेले में भाग लिया जिसके साथ 9वें संयुक्त आयोग की बैठक हुई। डॉ संजीव कुमार बाल्यान, माननीय कृषि राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में अल्जीरिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को अक्तूबर 2015 में नई दिल्ली में तीसरे भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन हेतु आमंत्रण देने के लिए 11–13 जुलाई 2015 तक अल्जीयर्स का दौरा किया।

वाणिज्य मंत्री, श्री भक्ति बेलेब ने तीसरे भारत–अफ्रीका शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्रियों की बैठक की कार्यवाही में नई दिल्ली में 27 अक्तूबर 2015 को अल्जीरिया का प्रतिनिधित्व किया और अक्तूबर 2015 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए तीसरे भारत–अफ्रीका मंच शिखर बैठक में मघरेब कार्य मंत्री, अफ्रीकी संघ और अरब लीग एब्डेलकाडर मेस्साहेल ने अल्जीरिया का प्रतिनिधित्व किया।

अल्जीरिया की जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य सरकार के ऊर्जा मंत्री, माननीय डॉ सालाह खेबरी ने नई दिल्ली में भारत–अफ्रीका हाइड्रोकार्बन सम्मेलन में भाग लेने के लिए 21.22 जनवरी 2016 तक भारत का दौरा किया।

मुंबई में 13.18 फरवरी 2016 तक ″मेक इन इंडिया″ सप्ताह के लिए एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल का आगमन।

अंगोला

अंगोला के साथ लंबे समय से चले आ रहे भारत के घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों को तीसरे भारत–अफ्रीका शिखर सम्मेलन (आईएएफएस– III) के तहत परस्पर उच्च स्तरीय दौरों से आगे बढ़ाया गया है। भारत के प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में विदेश राज्य मंत्री डॉ (जनरल) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने 17 जुलाई 2015 को आईएएफएस–III के लिए निमंत्रण के पत्र सौंपने के लिए लुआंडा का दौरा किया। अंगोला के उप राष्ट्रपतिए श्री मैनुएल विसेंट ने अक्तूबर 2015 में नई दिल्ली में आईएएफएस–III के लिए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जिसमें विदेश, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्रिगण शामिल थे। प्रधानमंत्री ने उप राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी, प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों ने भी अपने भारतीय समकक्षों के साथ सार्थक बैठकें कीं। अंगोला की ओर से यात्रा के परिणाम पर संतोष व्यक्त किया गया। उपसहारन अफ्रीका में भारत को कच्चे तेल के दूसरे सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में, अंगोला भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रहा है। हाइड्रो कार्बन क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने हेतु संभावनाओं का पता लगाने के लिए अक्तूबर 2015 में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नेतृत्व में दो–सदस्यीय शिष्टमंडल ने अंगोला का दौरा किया। द्विपक्षीय व्यापार में भारी बढ़ोत्तरी हुई और यह वर्ष 2006–07 के मात्र 446.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 5169 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया और इसके साथ ही अंगोला भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। एक्जिम बैंक के माध्यम से औद्योगिक पार्क परियोजना और अंगोला में वस्त्र परियोजना की स्थापना के लिए क्रमशः 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण श्रृंखला के तहत प्रगति जारी है। भारतीय/भारतीय मूल की संस्थाओं द्वारा भी अंगोला में निजी निवेश वृद्धि पर है। अंगोला ने विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया।

अंगोला के पेट्रोलियम मंत्रालय और राष्ट्रीय तेल गवेषण कंपनी, सोनांगोल से वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित अंगोला के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 21.22 जनवरी, 2016 को नई दिल्ली

में आयोजित चौथे भारत–अफ्रीका हाइड्रोकार्बन सम्मेलन में भाग लिया।

बेनिन

प्रधानमंत्री के विशेष दूत राज्य मंत्री (एचआरडी) ने 14–15 सितंबर 2015 के बीच कोटोनोउ, बेनिन का दौरा किया और बेनिन के राष्ट्रपति बोनी यायी से मुलाकात की तथा आईएएफएस–III के लिए निमंत्रण पत्र सौंपा। उन्होंने विदेश मंत्री सोलिओ अधिकारी के साथ भी मुलाकात की। इसके अनुसार बेनिन के राष्ट्रपति बोनी यायी ने 26 – 30 अक्तूबर 2015 तक आईएएफएस–III के लिए नई दिल्ली का दौरा किया। उनके साथ 27 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल था जिसमें विदेश मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। इससे पहले, 23 अक्तूबर 2015 को भारत–अफ्रीका व्यापार मंत्रियों की चौथी बैठक में भाग लेने के लिए बेनिन के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने भारत का दौरा किया।

बोत्सवाना

भारत–बोत्सवाना का व्यापार 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। भारतीय मूल के समुदाय की आबादी लगभग 10,000 है। विकास भागीदारी में छात्रवृत्ति, आईटी उपकरण और चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति शामिल है।

बोत्सवाना के उप राष्ट्रपति श्री मोकगवीट्सी ई. मेसिसी ने अक्तूबर 2015 में नई दिल्ली में तीसरे भारतीय–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में भाग लिया। विदेश और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के कार्यवाहक मंत्री उनके साथ थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की।

शिखर सम्मेलन से पहले बोत्सवाना के उप–राष्ट्रपति ने मुंबई में बोत्सवाना व्यापार संगोष्ठी को संबोधित किया। बोत्सवाना निवेश और व्यापार केंद्र, मुंबई द्वारा इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आगे व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए दिसंबर 2015 में सीआईआई के सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बोत्सवाना का दौरा किया।

बोत्सवाना ने अगस्त 2015 में गेबोरोन में 35 वें एसएडीसी शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय (एसएडीसी) का अध्यक्ष पद ग्रहण किया।

बुर्किना फासो

प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में कृषि राज्य मंत्री ने अंतरिम राष्ट्रपति को आईएएफएस–III निमंत्रण पत्र सौंपने के लिए 9 जुलाई 2015 को बुर्किना फासो का दौरा किया। बुर्किनाब विदेश मंत्री ने अक्तूबर 2015 में आईएएफएस–III के लिए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। 21 जून 2015 को ओयूगाडॉउगॉउ में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। सामान्य योग प्रोटोकॉल के अनुसार ओयूगाडॉउगॉउ के तीन योग चिकित्सकों के साथ, भारत से एक योग विशेषज्ञ ने एक प्रदर्शन किया। समारोह में लगभग 150 लोगों ने भाग लिया। सितंबर 2015 में ओयूगाडॉउगॉउ में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रायोजित एक राजस्थानी लोक नृत्य मंडली, श्सपेराश ने दो कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पहले बुर्किना संगीत समूह के साथ एक संयुक्त प्रदर्शन किया गया और दूसरा भारतीय समुदाय के सामने एकल प्रदर्शन किया गया।

बुरुण्डी

भारत–बुरुंडी व्यापार 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। विकास सहायता में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना, रियायती ऋण (80 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के तहत 20 मेगावॉट की एक जल विद्युत परियोजना (काबू) और फार्म यंत्रीकरण परियोजना तथा शिक्षा और प्रशिक्षण छात्रवृत्ति; तथा मानवीय सहायता शामिल हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र को बुरुंडी मिशन के लिए 100,000 अमेरिकी डॉलर प्रदान करता है। बुरुंडी में भारतीय मूल के समुदाय की आबादी 400–500 के आसपास है।

अक्तूबर 2015 में नई दिल्ली में तीसरे भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में प्रथम उप राष्ट्रपति गैस्टन सिण्डिमवो ने बुरूंडी के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी। शिखर सम्मेलन के मौके पर उनके साथ श्री एलेन ए न्यामित्वे थे, जिन्होंने इस अवसर पर विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी।

शिखर सम्मेलन का निमंत्रण देने के लिए प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में जुलाई 2015 में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री सुदर्शन भगत ने बुरुंडी का दौरा किया। उन्होंने राष्ट्रपति पियरे नकुरुंजिजा को आमंत्रण दिया और विदेश मंत्रीएलेन न्यामित्वे से मुलाकात की।

राष्ट्रपति पद के चुनाव के बाद पियरे नकुरुंजिजा ने अगस्त 2015 में एक तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी।

कैमरून

अप्रैल 2015 में सीआईआई द्वारा आयोजित भारत–अफ्रीका स्वास्थ्य फोरम 2015 में भाग लेने के लिए कैमरून के सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सचिव ने भारत का दौरा किया। कैमरून के नेतृत्व के लिए आईएएफएस–III का निमंत्रण पत्र सौंपने के लिए प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में राज्य मंत्री (मा. सं. वि.) ने 15–17 जुलाई 2015 तक कैमरून का दौरा किया। 26–30 अक्तूबर 2015 तक आईएएफएस–III में कैमरून का प्रतिनिधित्व करने वाले कैमरून के विदेश मंत्री थे।

केप वर्डे

आईएएफएस–III हेतु प्रधानमंत्री का निमंत्रण पत्र सौंपने के लिए प्रधानमंत्री के विशेष दूत, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने 16–19 सितंबर 2015 तक प्राइया, केप वर्डे का दौरा किया। प्राइया में 21 जून 2015 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।

समारोह में सरकार के प्रतिनिधियों, राजनयिकों, स्थानीय लोगों, भारतीय समुदाय के सदस्यों और भ्रमण करने वाले पर्यटकों सहित लगभग 50 लोगों ने भाग लिया। भारत द्वारा केप वर्डे को क्षमता संवर्धन सहायता जारी है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में इसके लिए 10 स्लॉट्स उपलब्ध थे। शैक्षणिक वर्ष 2015–2016 में अफ्रीका छात्रवृत्ति योजना के तहत केप वर्डे के लिए 9 छात्रवृत्ति स्लॉट्स प्रस्तावित किए गए हैं। वर्ष 2014–15 में द्विपक्षीय व्यापार 7.09 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा जिसमें भारत से निर्यात 4.12 मिलियन अमेरिकी डॉलर का और भारत में आयात 2.97 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था।

मध्य अफ्रीकी गणराज्य (सीएआर)

भारत सरकार ने बांगुइ में 400 मिलियन टन/दिन सीमेंट निर्माण की क्षमता वाली परियोजना के लिए 24 मिलियन अमेरिकी डॉलर परियोजना की एक ऋण श्रृंखला ख्एलओसी, की मंजूरी दी थी और यह परियोजना लगभग पूरी होने वाली थी जब सुरक्षा कारणों से भारतीय कामगारों को 2014 की शुरुआत में हटा दिया गया था। कार्य पुनः आरंभ करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लाइमस्टोन खनन के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर और दो जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 39,69 मिलियन अमेरिकी डॉलर हेतु दो अन्य ऋण श्रृंखला पर सीएआर की सरकार हस्ताक्षर के लिए तैयार है।

चाड

प्रधानमंत्री के विशेष दूत, राज्य मंत्री (मा. सं. वि.) ने आईएएफएस–III के लिए निमंत्रण पत्र सौंपने के लिए 13–14 जुलाई 2015 तक चाड का दौरा किया। चाड के राष्ट्रपति इदरिस दबे इटनो ने 26–30 अक्तूबर 2015 के दौरान आईएएफएस–III के लिए नई दिल्ली का दौरा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की। राष्ट्रपति इदरिस दबे के साथ विदेश और अफ्रीकी एकीकरण मंत्री, योजना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्री, अब संरचना मंत्री, अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और पर्यटन विकास मंत्री और उच्च स्तरीय अधिकारियों का एक 32 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी था।

कोमोरोस

नई दिल्ली में अक्तूबर 2015 में तीसरे भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में कोमोरोस के राष्ट्रपति इकिलिलोउ धोइनाइन ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ. अब्दुल करीम मोहम्मद थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इससे पहले अगस्त 2015 में शिखर सम्मेलन का निमंत्रण देने के लिए प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री श्री वाई.एस. चौधरी ने कोमोरोस का दौरा किया। उन्होंने राष्ट्रपति धोइनाइन और विदेश मंत्री डॉ. मोहम्मद से मुलाकात की।

अक्तूबर 2015 में विदेश व्यापार मंत्री श्री मोहम्मद सोलिही ने भारत अफ्रीका व्यापार मंत्रियों की चौथी बैठक में भाग लिया।

कोमोरोस के उप राष्ट्रपति मोहम्मद अली सोलिही द्वारा जुलाई 2015 में 18 मेगावॉट की बिजली परियोजना का उद्घाटन किया गया। यह परियोजना भारत के एक्जिम बैंक से वित्तीय सहायता के तहत मोरोनी में चलाई जा रही है।

कोट डी आइवरी (सीआई)

25 अक्टूबर 2015 को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को ध्यान में रखते हुए उद्योग एवं खान मंत्री ने अक्टूबर, 2015 में नई दिल्ली में आईएएफएस–III के लिए आइवरी के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। इसके पहले, आईएएफएस–III के लिए निमंत्रण पत्र सौंपने के लिए प्रधानमंत्री के विशेष दूत के तौर पर व्यक्तिगत रूप से राज्य मंत्री (पेय जल एवं स्वच्छता) ने 13–16 जुलाई 2015 तक आबिदजान का दौरा किया। अफ्रीकी विकास बैंक की वार्षिक बैठक के अवसर पर फिक्की के नेतृत्व में एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने 25–29 मई 2015 तक आबिदजान का दौरा किया।

कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य

भारत सरकार द्वारा 42 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला से बान्डुडु प्रान्त में 9.3 मेगावॉट वाली काकोबोला जल विद्युत परियोजना प्रारंभ की गई थी और विवेच्य वर्ष के दौरान इस परियोजना का काम अच्छी तरह से चल रहा है। बिजली उत्पादन दिसंबर 2015 में शुरू होने की संभावना है। भारत सरकार द्वारा काटेंडे कसाई ऑक्सीडेंटल प्रांत में 64 मेगावॉट वाली काकोबोला जल विद्युत परियोजना के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण श्रृंखला की मंजूरी दी गई है और इस परियोजना का काम जारी है।

मई, 2015 में भारत सरकार ने दो ऋण श्रृंखला की मंजूरी दी (i) बान्डुडु प्रान्त में काकोबोला जल विद्युत परियोजना में उत्पादित विद्युत की निकासी के लिए वितव्य परियोजना हेतु 34.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ;पपद्ध कसाई प्रांत में काटेंडे जल विद्युत परियोजना से विद्युत निकासी हेतु विद्युत पारेषण और परियोजनाओं के निधिकरण के लिए 109.942 मिलियन अमेरिकी डॉलर।

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2013–2014 में 208.74 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2014–2015 में 380.61 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। डीआरसी में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति स्थापना के सबसे बड़े ऑपरेशन के तहत डीआरसी में 5,000 से अधिक भारतीय सैनिकोंए सैन्य पर्यवेक्षकों और पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ख्एम ओ एन यू एस सीओ, में स्थिरीकरण मिशन के रूप में जाना जाता है। भारत ने विशेष रूप से भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (आईएएफएस) और आईटीईसी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के तहत देश के लिए क्षमता बढ़ाने हेतु सहायता जारी रखी है। डीआरसी को वर्ष 2015–2016

के दौरान आईटीईसी कार्यक्रम के तहत 30 प्रशिक्षण स्लॉट आबंटित किए गए हैं। डीआरसी के विदेश मंत्री 26–30 अक्टूबर 2015 तक नई दिल्ली में आयोजित तीसरे भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

जिबूती

जिबूती एक छोटा राज्य है जिसकी आबादी दस लाख से कम है। सुरक्षा और व्यापार के दृष्टिकोण से अफ्रीका के ऊपरी भाग में स्थित यह राज्य सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह पूर्वी अफ्रीका में समुद्री डकैती और इस्लामी आतंकवादी समूहों के विरुद्ध लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिबूती–भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण और सहयोगी बने हुए हैं। अप्रैल 2015 में ऑपरेशन राहत के दौरान जिबूती द्वारा दी गई सराहनीय सहायता के समय सुस्पष्ट हो गया। जिबूती ने 5000 भारतीय नागरिकों सहित करीब 7000 व्यक्तियों को जिबूती हवाई अड्डे और समुद्री बंदरगाह के माध्यम से युद्धग्रस्त यमन से निकालने में भारी मदद पहुंचाई। अदन की खाड़ी में भारत के एंटी–पायरेसी नौसेना ऑपरेशन में जिबूती की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रही। संभारगत सहायता एवं आपूर्तियों की पुनः बहाली के लिए जिबूती में 14 भारतीय नौसैनिक पोत डॉक किए गए।

जुलाई 2015 में तीसरे भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री विशेष दूत के रूप में जनरल वी. के. सिंह ने जिबूती के राष्ट्रपति इस्माइल उमर गुइलेह को आमंत्रित किया। अक्तूबर 2015 में राष्ट्रपति गुइलेह ने विदेश मंत्री महमूद अली यूसुफ के साथ शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इससे पहले, 23 अक्तूबर 2015 को भारत–अफ्रीका व्यापार मंत्रियों की चौथी बैठक में अर्थव्यवस्था एवं वित्त मंत्री इलियास मूसा दवेलेह ने भाग लिया। 20– 21 नवंबर, 2015 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित भारत चिकित्सा पर्यटन सम्मेलन 2015 में स्वास्थ्य मंत्री डॉ कासीम इसाक उस्मान सम्मानित अतिथि थे।

भारत ने 34 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारतीय ऋण श्रृंखला के तहत निर्मित मौजूदा अलि सबियाह सीमेंट फैक्ट्री के उन्नयन के लिए भारतीय निर्यात–आयात बैंक के माध्यम से 15.13 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक अतिरिक्त ऋण श्रृंखला के अनुमोदन के जरिए जिबूती को अपनी विकास सहायता में वृद्धि की। जिबूती ने भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के छः प्रशिक्षण अवसरों और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की छः छात्रवृत्तियों का उपयोग किया।

मिस्र

उच्च स्तरीय आदान–प्रदान और साझेदारी को मजबूत बनाने की एक प्रतिबद्धता के साथ भारत–मिस्र संबंधों में नई गति आई। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल–सिसि से मुलाकात की। राष्ट्रपति सिसि ने अक्तूबर 2015 में भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (आईएएफएस–तृतीय) में भाग लिया और

विदेश मंत्री ने अरब गणराज्य मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसी से काहिरा, मिस्र में मुलाकात की (24 अगस्त, 2015)

राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधानमंत्री दोनों के साथ मुलाकात की। वे घनिष्ठ राजनीतिक – सुरक्षा सहयोग, आधिकारिक आर्थिक संबंधों और निकटतम सांस्कृतिक संबंध और लोगों से लोगों के बीच आदान–प्रदान के तीन स्तंभों के आधार पर संबंधों को उच्च स्तर पर ले जाने पर सहमत हुए।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 23–25 अगस्त 2015 तक मिस्र का दौरा किया और राष्ट्रपति सीसी, विदेश मंत्री समेश शौकरी और अरब लीग के महासचिव नबील एलाराबी से मुलाकात की। उनकी यात्रा के दौरान पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग पर दो समझौता ज्ञापनों (एमओयू) और वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए थे।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आईएएफएस–III के लिए निमंत्रण देने हेतु प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में जुलाई 2015 में राष्ट्रपति सिसी से मुलाकात की। श्री नितिन गडकरीए जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने नए स्वेज नहर के उद्घाटन समारोह के लिए अगस्त 2015 में मिस्र का दौरा किया। श्री मुख्तार अब्बास नकवी, संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने नवंबर 2015 में लक्सर में इस्लामी मामलों के सर्वोच्च परिषद के 25वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉ अरविंद गुप्ता ने जुलाई 2015 में काहिरा में मिस्र के सुरक्षा और रक्षा अधिकारियों के साथ बातचीत की।

संयुक्त रक्षा सहयोग की पांचवीं बैठक में सहमति के अनुसार, दोनों देशों के रक्षा प्रतिनिधिमंडलों की परस्पर यात्राएं नियमित रूप से रहीं। भारतीय नौसेना के जहाजों तरंगिनी और त्रिकंद अलेक्जेंड्रियाए पोर्ट सईद और सफागा के मिस्र के पत्तनों पर ठहरे और विदेशों में तैनाती के दौरानए अपने समकक्षों के साथ बातचीत की।

वैश्विक मंदी के बावजूद, मिस्र के साथ भारत का व्यापार 2014–15 में 4.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। भारत से मिस्र को निर्यात 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया और आयात 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिससे मिस्र के निर्यात के लिए भारत तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य बन गया और आयात के मामले में 11वां स्रोत रहा। भारत की 50 से अधिक कंपनियों ने 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक के कुल निवेश के साथ भारत की आर्थिक संबद्धता के मामले में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखा। दोनों देशों के बीच व्यापारिक शिष्टमंडलों की यात्राएं जारी रहीं जिनमें फार्माएक्सिल, भारतीय शिल्पकार, भारतीय तम्बाकू, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के शिष्ट मंडल, ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैनूफेक्चरर्स एसोसिएशन्स और सिंथेटिक तथा रेयॉन टेक्स्टाइल निर्यात संवर्धन परिषद शामिल रहें। व्यापार, निवेश मानकीकरण तथा उद्भव के मुद्दों पर भारत – मिस्र संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की पहली बैठक 5 नवम्बर 2015 को (वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए) आयोजित की गई तथा 6 सदस्यीय भारतीय जैव वैज्ञानिक शिष्टमंडल – काहिरा गया जहां अक्तूबर 2015 में ष्जैव प्रौद्योगिकी–विकास का टिकाऊ दृष्टिकोण' पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। अक्तूबर 2015 में मिस्र – भारत व्यापार परिषद का पुनर्गठन किया गया और आईएएफएस –III के अवसर पर भारतीय पक्ष के साथ बैठक की गई। भारतीय दूतावास द्वारा आरंभ किए गए भारतीय व्यापार फोरम की बैठक मिस्र के अधिकारियों तथा व्यापार प्रतिभागियों के साथ आर्थिक जुड़ाव बढ़ाने के लिए आयोजित की गई।

भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग एवं मिस्र के लिए सीवी रमन अध्येतावृत्तियों के तहत 100 प्रत्याशियों को मनोनीत किया गया। स्नातक और डॉक्टरेट अध्ययन के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) छात्रवृत्ति का लाभ उठाया गया। मार्च–अप्रैल 2015 में तीसरी बार भारत और नील श्नील द्वारा भारतश (आईबीएन) नामक सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया गया था इस अवधि के दौरान भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रायोजित मंडलियों ने मिस्र का दौरा किया।

मिस्र में 21 जून 2015 को प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाय) मनाया गया और लोगों ने इसमें अच्छा उत्साह दिखाया अक्तूबर 2015 में काहिरा और गीजा में आयोजित कार्यक्रम में 'भारत की झलकें' नामक 21वीं चित्रकला प्रतियोगिता में 430 से अधिक स्कूलों से 4700 से अधिक स्कूली बच्चों ने भाग लिया। 'इंडिया डे' का आयोजन अगस्त में एलेक्सेंड्रिया में तथा नवम्बर के दौरान पोर्टसैड में किया गया, जिसके दौरान 'भारत की झलकें' नामक चित्रकला प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया।

भारत मिस्र के विदेश कार्यालय परामर्श का 11 वां सत्र 14 दिसंबर, 2015 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। मिस्र पक्ष का नेतृत्व महामहिम राजदूत यासर मोराद, सहायक विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय ने किया था, जबकि भारतीय पक्ष का नेतृत्व श्री अनिल वाधवा, सचिव (पूर्व) ने किया गया था। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत मिस्र द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की।

इक्वेटोरियल गिनी

इस अवधि के दौरान इक्वेटोरियल गिनी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध और सुदृढ हुए। प्रधानमंत्री के विशेष दूत, राज्य मंत्री (आयुष) ने आईएएफएस–III का निमंत्रण देने के लिए व्यक्तिगत रूप से 24–25 अगस्त 2015 को भारत से इक्वेटोरियल गिनी का दौरा किया। अपने पहले भारत के दौरे में, राष्ट्रपति ओबियांग न्यूमा मबासोगो ने अक्तूबर 2015 में नई दिल्ली में आयोजित आईएएफएस–III भाग लेने के लिए एक बड़े प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत सरकार ने नई दिल्ली में एक स्थायी मिशन खोले जाने संबंधी उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया।

दिल्ली में 21–22 जनवरी 2016 तक आयोजित चौथे भारत–अफ्रीका

हाइड्रोकार्बन सम्मेलन में भाग लेने के लिए इक्वेटोरियल गिनी के खान, उद्योग और ऊर्जा मंत्री ने भारत का दौरा किया। इस अवसर का उपयोग करते हुए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट ईजी द्वारा 22 जनवरी 2016 को आयोजित किए गए इक्वेटोरियल गिनी–भारत हाइड्रोकार्बन एवं उद्योग मंच में भाग लिया।

इरीट्रिया

भारत द्वारा शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में विकास सहायता प्रदान की गई है और एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण में सहायता की जा रही है। इरीट्रिया में भारतीय समुदाय के 1200 (शिक्षकों और श्रमिकों) के आसपास लोग हैं।

विदेश मंत्री श्री उस्मान सालेह मोहम्मद ने अक्तूबर 2015 में नई दिल्ली में तीसरे भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में इरीट्रियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी।

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री जनरल (सेवा.) वी के सिंह ने प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में सितंबर 2015 में शिखर सम्मेलन के लिए निमंत्रण देने के लिए इरिट्रिया का दौरा किया। उन्होंने राष्ट्रपति इसाइसा अफवेरकी से मुलाकात की।

अफ्रीका के ऊपरी भाग में लाल सागर के किनारे स्थितए इरिट्रिया ने यमन में युद्ध के दौरान भारतीयों की निकासी के लिए आयोजित अभियान में अत्यधिक सहयोग दिया।

इथोपिया

भारत और इथियोपिया में राजनीतिक और आर्थिक घनिष्ठ संबंध हैं जो प्राचीन काल से चले आ रहे व्यापारिक संबंधों पर करीबी संबंध हैं। इथियोपिया भारत द्वारा अफ्रीका को दी जाने वाली विकास सहायता (चीनी संयंत्र, ग्रामीण विद्युतीकरण, रेलवे) का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। इथियोपिया में भारतीय समुदाय कुल 6000 (शिक्षकों की एक बड़ी संख्या सहित) के लोग हैं। द्वितीय भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन अफ्रीकी संघ के मुख्यालय अदीस अबाबा में आयोजित किया गया था।

इस अवधि के दौरान भारत और इथोपिया के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे किए गए। सितंबर 2015 में एक अगले कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित किए गए प्रधानमंत्री हेलीमरियम डेसालेग्न ने अक्टूबर 2015 में नई दिल्ली में तीसरे भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (आई ए एफ एस III) के लिए इथियोपिया के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय विचार–विमर्श किया। विदेश मंत्री डॉ. टेड्रोस अधेनोम भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। इससे पहले जुलाई में, आईएएफएस–III के लिए निमंत्रण हेतु प्रधानमंत्री के विशेष दूत के वस्त्र राज्यमंत्री, श्री संतोष कुमार गंगवार ने अदीस अबाबा का दौरा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री देसालेग्न को आमंत्रण दिया और विदेश मंत्री डॉ. अधेनोम के साथ मुलाकात की।

अन्य उच्च स्तरीय दौरे में निम्नलिखित शामिल थे : जुलाई 2015 में अदीस अबाबा में विकास के वित्त पोषण के संबंध में आयोजित तीसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा ने किया था। श्री सिन्हा ने विदेश मंत्री डॉ. अधेनोम के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी। अगस्त 2015 में इथियोपिया के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. केसेतेबिरहन अदमासु ने नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सह–अध्यक्षता में आयोजित श्कॉल टु एक्शन शिखर सम्मेलन–2015' में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। दिसम्बर 2015 में विदेश मंत्री द्वारा इथियोपिया की महिला, बाल एवं युवा कल्याण मंत्री सुश्री जेनेबु तेडेस्से वोल्डेत्सादिक को आईसीसीआर के प्रथम प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दौरे के दौरान सुश्री वोल्डेत्सादिक ने महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी से मुलाकात की। मई 2015 में नई दिल्ली में भारत–इथियोपिया विदेश कार्यालय परामर्श का तीसरा दौर आयोजित किया गया।

भारत सरकार की सहायता से अदीस अबाबा में ब्लैक लायन अस्पताल में एक 64–स्लाइस सीटी स्कैन मशीन स्थापित की गई। दिसंबर 2015 में इथियोपिया में आईसीसीआर द्वारा प्रायोजित राजस्थानी लोक नृत्य मंडली ने प्रदर्शन किया।

गाम्बिया

12–15 सितंबर 2015 तक आईएएफएस–III में भाग लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण देने के लिए प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री ने गाम्बिया का दौरा किया। गाम्बिया के उप राष्ट्रपति डॉ आजा इसातोऊ निजे – सैडी और विदेश मंत्री श्रीमती नेन्ह मैकड्युअल . गाये ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया। गाम्बिया में भारत की 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की विकासात्मक परियोजनाएं चालू हैं। 21 जून 2015 को बांजुल में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। गाम्बिया के लोगों द्वारा हमारे प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के अवसरों के उच्च उपयोग को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015–16 के लिए 35 स्लॉट आबंटित किए गए हैं। इस के अलावा, भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (आईएएफएस) और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के तहत क्षमता निर्माण सुविधाएं (2015–16 के लिए 30 स्लॉट) उपलब्ध हैं।

घाना

निवेश और व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए अप्रैल 2015 में घाना के 36 सदस्यीय भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने दौरा किया। उन्होंने घाना निवेश संवर्धन केंद्र (जीआईपीसी), घाना औद्योगिक संघ (एजीआई) और वाणिज्य एवं उद्योग घाना चैंबर (जीसीसीआईद्ध स्थानीय भारतीय व्यापारियों और प्रतिनिधियों के साथ सार्थक बातचीत की थी। घाना में विभिन्न ऋण श्रृंखला के तहत जारी परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए एक्जिम बैंक

से 3 सदस्यों के साथ संयुक्त सचिव (डीपीए–आई) और संयुक्त सचिव (डब्ल्यूए) ने 1–4 जून 2015 तक अक्करा का दौरा किया। भारतीय उच्चायोग द्वारा अकरा में आयोजित एक कार्यक्रम में 21 जून 2015 को प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को भव्य तरीके से मनाया गया। घाना के विद्युत मंत्री इसमें सम्मानित अतिथि थे। अक्टूबर 2015 में घाना के राष्ट्रपति जॉन द्रामानी महामा ने नई दिल्ली में आयोजित आईएएफएस–III में अपने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। दस भारतीय कंपनियों ने 3–7 नवंबर, 2015 के बीच घाना में 13वें अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में भाग लिया। कैपेक्सिल के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि ने भी मेले में हिस्सा लिया। सोल ग्रुप लि., ब्रिटेन स्थित विकास कंपनी ने 400 मेगावॉट क्षमता वाले विद्युत स्टेशन को देश में निर्मित करने की परियोजना के संविदाकार के रूप में बीएचईएल को चुना। इस परियोजना की अनुमानित लागत 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। सोल ग्रुप और बीएचईएल ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उप राष्ट्रपति अमिसाह अर्थर ने सीआईआई के नेतृत्व वाले 20 सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल के साथ मुलाकात की, जो घाना में निवेश के अवसरों की खोज में गया था। विदेश में रहने वाले भारतीयों के बच्चे 28 नवम्बर 2015 को उच्चायोग में जमा हुए और उन्होंने भारतीय संविधान का आमुख पढ़ा। सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय, अक्करा के एक अध्यापक ने भारतीय संविधान की बुनियादी विशेषताएं समझाईं और उन्हें एक अंतःक्रियात्मक सत्र में शामिल किया।

गेबन

ऑयल इंडिया लिमिटेड ख्ओआईएल,, इंडियन ऑयल लिमिटेड के साथ साझेदारी में, शक्ति ब्लॉक, लाम्बेरेले में तेल की खोज कर रही है। अब तक ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा 'स्वस्थाने' 44 मिलियन बैरल तेल की खोज की गई है। परियोजना के प्रथम चरण के जनवरी 2017 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। भारत सरकार ने गेबान के पुनर्वास और प्रसारण सुविधाओं के उन्नयन के लिए 67.19 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण श्रृंखला की मंजूरी दी है। गेबन के राष्ट्रपति ने एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जिसने 26–30 अक्तूबर 2015 को नई दिल्ली में आयोजित तीसरे भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

राष्ट्रपति अल्फा कोंडे 11 अक्तूबर 2015 को आयोजित चुनाव में स्पष्ट बहुमत से अपने दूसरे कार्यकाल के लिए जीत हासिल की। चुनाव परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद उन्होंने नई दिल्ली में आईएएफएस–III में अपनी भागीदारी की घोषणा की। उन्होंने विदेश मंत्री, कृषि, ऊर्जा और व्यापार के मंत्रियों सहित एक बड़े प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इससे पहले, 12–13 जुलाई 2015 को आईएएफएस–III के लिए प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत तौर पर निमंत्रण सौंपने के लिए प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में राज्य मंत्री (पेयजल एवं स्वच्छता) ने गिनी दौरा किया। भारत सरकार ने गिनी के विदेश मंत्री को 175 कंप्यूटर, लैपटॉप और बाह्य उपकरण दान किए।

गिनी बिसाऊ

गिनी बिसाऊ में चुनाव सम्पन्न हुए। पुनर्निर्माण और सहयोग प्रक्रिया के लिए भारत सरकार नई सरकार के साथ संपर्क में है। भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (आई ए एफ एस) और आइटेक क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के तहत भारत ने इस देश को क्षमता वृद्धि में सहयोग उपलब्ध कराना जारी रखा है। वर्ष 2015–16 में गिनी बिसाऊ के लिए 25 स्लॉट आबंटित किए गए थे। शैक्षणिक वर्ष 2015–2016 में अफ्रीका छात्रवृत्ति योजना के तहत गिनी बिसाऊ के लिए 5 छात्रवृत्ति स्लॉट्स का प्रस्ताव किया गया है। राजनीतिक अशांति के कारण सामाजिक–आर्थिक कठिनाई और अध्ययन की मुख्य भाषा पुर्तगाली होने के परिण ामस्वरूप गिनी बिसाऊ के आवेदक कार्यक्रम का समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आईएएफएस–III के लिए निमंत्रण पत्र सौंपने के लिए 14 सितंबर 2015 को प्रधानमंत्री के विशेष दूत के तौर पर खनन और इस्पात राज्य मंत्री ने गिनी बिसाऊ का दौरा किया। गिनी बिसाऊ के अध्यक्ष श्री जोस मारियो वाज और विदेश मंत्री ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया। बिसाऊ में 21 जून 2015 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। आय का 90% से अध्िाक हिस्सा काजू की फसल के निर्यात से प्राप्त होता है। भारत कच्चे काजू के लिए एक प्रमुख निर्यात गंतव्य है।

केन्या

भारत और केन्या के घनिष्ठ आर्थिक और सामुदायिक संबंध हैं। भारत केन्या (4 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारतीय कंपनियों ने दूरसंचार, पेट्रोरसायन, रसायन, फूलों की खेती, बैंकिंग आदि में निवेश किया है और बिजली तथा अन्य क्षेत्रों में इंजीनियरिंग अनुबंधों को निष्पादित किया है। भारत ने बिजली, कृषि / सिंचाई के क्षेत्रों में विकास सहायता (रियायती क्रेडिट) प्रदान की है। बड़ी संख्या में केन्या के लोग भारत में अध्ययन करते हैं। केन्या में भारतीय मूल समुदाय के लोगों की कुल संख्या 100,000 के आसपास है।

तीसरे भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति युरु केन्याटा ने केन्याई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। वे विदेश कार्य और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री सुश्री अमीना सी मोहम्मद के साथ थे। राष्ट्रपति केन्याटा ने प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी। जुलाई 2015 में, समारोह के लिए निमंत्रण हेतु प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में विदेश मंत्रालय जनरल राज्यमंत्री (सेवा.) वी के सिंह ने नैरोबी का दौरा किया। उन्होंने राष्ट्रपति केन्याटा को आमंत्रण दिया और विदेश मंत्री सुश्री अमीना मोहम्मद, रक्षा मंत्री राजदूत रायचेले ओमेमो, और गृह मंत्री यूसुफ ओले लेंकु से मुलाकात की।

अन्य उच्च स्तरीय दौरों में, केन्या के आईसीटी मंत्री द्वारा सूचना पर सहयोग आरंभ करने के लिए जुलाई 2015 में केन्या फ्रेड मतियांगी का भारत दौरा करना शामिल है और नैरोबी में सितंबर में आयोजित भारत–अफ्रीका आईसीटी एक्सपो में भाग लेने के

लिए भारतीय कंपनियों को आमंत्रित करना शामिल है। उन्होंने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के माननीय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद से मुलाकात भी की। दिसंबर 2015 में नैरोबी में आयोजित विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (आईसी) श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। दौरे के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति केन्याटा, उप राष्ट्रपति विलियम रुटो, और विदेश और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री डॉ अमीना मोहम्मद से मुलाकात की।

लेसोथो

भारत–लेसोथो का व्यापार 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है। विकास भागीदारी में विभिन्न क्षमता निर्माण परियोजनाओं हेतु लेसोथो को 9.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण श्रृंखला शामिल है। एक आईटी केंद्र पूरा हो गया है। भारतीय सेना का एक प्रशिक्षण दल 2001 के बाद से लिसोथो में है। लिसोथो में कार्य करने वाले भारतीय प्रवासी व्यावसायिक 1300 के आसपास हैं।

प्रधानमंत्री डॉ पकालिथा मोसिसिली ने अक्तूबर 2015 में नई दिल्ली में तीसरे भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में भारत की यात्रा करने वाले लेसोथो प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। वह विदेश मंत्री श्री त्लोहांग सेखामेने और व्यापार मंत्री श्री यहोशू सेतिपा के साथ थे। प्रधानमंत्री मोसिसिली ने प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी और विदेश मंत्री त्लोहांग सेखामेने शिखर सम्मेलन के मौके पर विदेश मंत्री से मुलाकात की।

प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में जुलाई 2015 में संस्कृति, पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और नागर विमानन के राज्यमंत्री डॉ महेश शर्मा ने लिसोथो का दौरा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री डॉ. मोसिसिली और विदेश और अंतरराष्ट्रीय संबंध मंत्री सेखामेने से मुलाकात की।

लाइबेरिया

लाइबेरिया की राष्ट्रपति श्रीमती एलेन जॉनसन सरलीफ ने नई दिल्ली में आईएएफएस–III के लिए एक बड़े प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए विदेश एवं ऊर्जा मंत्रियों सहित भाग लिया। उन्होंने आरआईएस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में एक विशेष व्याख्यान भी दिया। इससे पहले, मोनरोविया में 11 सितंबरए 2015 को इस्लामिक स्टेट प्रधानमंत्री के विशेष दूतए राज्य मंत्री (उच्च उद्योग और सार्वजनिक उद्यम) ने व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण पत्र प्रदान किया।

लीबिया

लीबिया में राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति और बिगड़ गई है। सीरिया में और ऐश–शाम (आईएसआईएस) ने विशेष रूप से सिरते के नगर क्षेत्र में अपनी स्थिति और सुदृढ कर ली है और वे लगभग 200 किलोमीटर क्षेत्र को नियंत्रित कर रहे हैं।

लीबिया के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा जनरल के विशेष प्रतिनिधि बेरनार्डिनो लियोन ने त्रिपोली और टोब्रुक में दोनों प्रतिद्वंद्वी सरकारों के विभिन्न गुटों के साथ कई माहों तक विचार–विमर्श के बाद 8 अक्तूबर 2015 को राष्ट्रीय सहमति से बनने वाली सरकार को एक मसौदा प्रस्तुत किया। 4 नवंबर 2015 को यूएनएसजी के नए विशेष प्रतिनिधि, श्री मार्टिन कोब्लेयर, एक जर्मन नागरिक ने श्री लियोन से पदभार लिया और वे प्रतिद्वंद्वी पक्षों को साथ लाने और जीएनए बनाने के लिए प्रयासरत है।

29, जुलाई 2015 को त्रिपोली जाने वाले राजमार्ग से 50 किलोमीटर की दूरी पर आईएसआईएस द्वारा बनाई गई एक चौकी पर चार भारतीय नागरिकों, जो भारत आ रहे थे, का अपहरण कर लिया गया। 31 जुलाई 2015 को दो को छोड़ दिया गया और दूतावास द्वारा उन्हें भारत वापस भेज दिया गया। सिरते में अन्य दो भारतीयों को इब्न सिना परिसर से 8 सितंबर 2015 को अपहरण कर लिया गया था। भारतीय नागरिकों में से एक को 30 सितम्बर 2015 को छोड़ दिया गया और अब तक की स्थिति के अनुसार अपहरण किए गए छह भारतीयों में से तीन को कैद में रखा गया है। सिरते में एक स्थानीय कंपनी एईईडब्ल्यू के 11 भारतीय श्रमिक आई एस आई एस के गढ में फंस गए थे। संकट की स्थिति में उनके अनुरोध का उत्तर देते हुए मिशन सिरते से उन्हें बाहर लाने में कामयाब रहा और उन्हें 28 अप्रैल 2015 को भारत में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

मिशन ने ट्यूनिसिया में जर्बा से प्रचालन जारी रखते हुए त्रिपोली में अपनी मौजूदगी बनाए रखी और लगभग 2000 भारतीय नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत में स्थित अधिकारियों की चक्रानुक्रम आधार पर तैनाती की गई, जो दूतावास द्वारा बार बार यह अनुरोध करने पर भी वहां बने रहे कि वे देश छोड़ कर चले जाएं। मिशन ने भारतीय नागरिकों को लीबिया से भारत लाने में सहायता जारी रखी। इस समय लगभग 6000 भारतीय नागरिकों में से 3699 को वापस आने के लिए सहायता दी गई है और वे लीबिया से विभिन्न मार्गों से लाए गए हैं। इनमें से अगस्त 2014 के बाद से भारत सरकार के व्यय पर 1324 लोगों को निकाल लिया गया है।

मेडागास्कर

भारत–मेडागास्कर विकास साझेदारी में कृषि उपकरणों की आपूर्ति तथा उर्वरक / कीटनाशक संयंत्रों की स्थापनाय आपदा राहत और छात्रवृत्ति के लिए ऋण श्रृंखला शामिल है। मेडागास्कर में 18वीं शताब्दी में आकर सबसे पहले बसने वाले 2,500 एनआरआई सहित भारतीय समुदाय 22,500 के आस पास है। भारतीय कंपनियों ने खननए तेल एवं गैस, दूरसंचार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया है।

अक्तूबर 2015 में नई दिल्ली में राष्ट्रपति हेरी राजोनरिमामपियानिना ने तीसरे भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में मेडागास्कर

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय विचार विमर्श किया और विदेश मंत्री के साथ मालागासी विदेश मंत्री श्रीमती बीट्राइस अतल्लाह से द्विपक्षीय विचार–विमर्श किया।

भारत सरकार ने अप्रैल 2015 में चेडजा चक्रवात के कारण आई बाढ़ से पीड़ितों को 200,000 अमेरिकी डॉलर का राहत कोष प्रदान करके मेडागास्कर को सहायता प्रदान की। जुलाई 2015 में देश में स्थानीय और नगरपालिका चुनावों के लिए मालागासी सरकार द्वारा अनुरोध करने पर अमिट स्याही भी भेजी गई थी।

भारतीय दूतावास ने अक्तूबर 2015 में अंतानानारिवो में एक व्यापार संवर्धन मेले का आयोजन किया। भारत के कई व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने मेले में भाग लिया। मेडागास्कर में (सितंबर–नवंबर 2015) भारत का एक त्यौहार आयोजित किया गया था।

मालावी

विकास भागीदारी छात्रवृत्ति, ऋण श्रृंखला (सिंचाई, अनाज भंडारण, तंबाकू प्रसंस्करण, कपास प्रसंस्करण, ईंधन भंडारण और चीनी प्रसंस्करण) और अनिवार्य दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति के लिए अनुदान शामिल हैं। मालावी में भारतीय मूल समुदाय की कुल संख्या 7,000 के आसपास है।

विदेश मंत्री डॉ. जॉर्ज चापोंडा ने तीसरे भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में मलावी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। वित्त मंत्री श्री गुडाल गोंडवे, और कृषि, जल संसाधन मंत्री श्री एलन चियेम्बेकेजा, व्यापार और उद्योग मंत्री जोसेफ मवानामबेका और श्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण मंत्री श्री हेनरी आमोन रॉबिन मूसा सहित चार अन्य मंत्रिगण इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे।

विदेश मंत्री चापोंडा ने विदेश मंत्री से मुलाकात की। वित्त मंत्री श्री गुडाल गोंडवे ने अपने समकक्ष वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। व्यापार और उद्योग मंत्री जोसेफ मवानामबेका ने अपने समकक्ष वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन से मुलाकात की। कृषि और जल संसाधन मंत्री श्री एलन चियेम्बेकेजा ने जल संसाधन मंत्री सुश्री उमा भारती के साथ मुलाकात की।

जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम राज्यमंत्री श्री जी एम सिद्धेश्वर ने शिखर सम्मेलन के लिए निमंत्रण देने हेतु मलावी का दौरा किया।। उन्होंने राष्ट्रपति प्रोफेसर आर्थर पीटर मुथारिका को आमंत्रण दिया। मालावी के विदेश मंत्री डॉ. जॉर्ज चापोंडा भी बैठक में उपस्थित थे।

अगस्त 2015 में भारत ने 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के ट्रैक्टर और कृषि औजार प्रदान किए। जुलाई 2015 में भारत ने 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की अनिवार्य औषधियां और दवाएं उपलब्ध करवाई। भारत ने बाढ़ राहत के तौर पर 250,000 अमेरिकी डॉलर भी प्रदान किए हैं।

माली

आईएएफएस–III के लिए मालियान राष्ट्रपति को निमंत्रण देने के लिए अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में इस्पात एवं खान राज्य मंत्री ने माली का दौरा किया। नई दिल्ली में 26–29 अक्तूबर 2015 तक आईएएफएस–तृतीय में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति इब्राहिम बुआबाकार केटा ने विदेश अर्थव्यवस्था और वित्त; सूचना मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता; वाणिज्य और उद्योग; ऊर्जा और जल; और खान मंत्रियों के साथ भारत का दौरा किया।

मॉरीतानिया

आईएएफएस–III के लिए मॉरीतानिया के राष्ट्रपति को निमंत्रण देने के लिए अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में इस्पात एवं खान राज्य मंत्री ने मॉरीतानिया का दौरा किया। अक्तूबर 2015 में आईएएफएस–तृतीय में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति मोहम्मद ओलद अब्देल अजीज ने अपने विदेश मामलों एवं सहकारिता, अर्थव्यवस्था और विकास मंत्रियों के साथ भारत का दौरा किया। प्रत्यक्ष द्विपक्षीय सहायता के अलावा मॉरीतानिया नेपाड (अफ्रीका के विकास के लिए नई भागीदारी) के माध्यम से और आईएएफएस–I और II पहलों के माध्यम से भारतीय सहायता का हकदार है। वर्ष 2015–16 के दौरान मॉरीतानिया के लिए आईटीईसी के तहत प्रशिक्षण स्लॉट की संख्या 15 प्रस्तावित की है। मॉरितानिया के लिए प्रस्तावित अन्य छात्रवृत्तियों में अफ्रीकी संघ (एयू) और अफ्रीकी देशों के लिए आईसीसीआर छात्रवृत्ति के माध्यम से कृषि छात्रवृत्ति, भारत–अफ्रीका मंच की विभिन्न पहलों (अर्थात् मॉरीतानिया में अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण केंद्र, मानव बस्ती केंद्र, और एक खेत विज्ञान केन्द्र का प्रस्ताव) के तहत दी जाने वाली छात्रवृत्ति शामिल हैं। पैन–अफ्रीकी ई–नेटवर्क परियोजना मॉरितानिया में कार्य कर रहा है।

मोरक्को

मोरक्को और भारत के बीच संबंधए ऐतिहासिक, गर्मजोशी से भरपूर और सौहार्दपूर्ण रहे हैं और 2015.16 के दौरान भी इन्हें विकसित करना जारी रहा। वर्ष की मुख्य घटनाओं में माननीय राजा मोहम्मद टप् द्वारा 29 अक्तूबर, 2015 को तीसरे भारत – अफ्रीका फोरम सम्मेलन (आईएएफएस – III) में भाग लिया और उनके साथ 400 सदस्यों के शिष्टमंडल की भागीदारी थी। इस सम्मेलन में विदेश मंत्री श्री सलाहैदिन मजुआर भी शामिल थे। महामहिम राजा मोहम्मद VI ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में दोनों पक्षों के बीच सहयोग को सुदृढ़ बनाने पर सहमति हुई तथा इस विषय में एक उच्च स्तरीय आयोग बनाने का निर्णय लिया गया।

इस अवधि के दौरान, निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों / अधिकारियों द्वारा मोरक्को के दौरे किए गए थे :

(i) डॉ. संजीव कुमार बलियान, माननीय कृषि राज्य मंत्री ने नई

दिल्ली में अक्तूबर 2015 में आईएएसएफ – III में भागीदारी के लिए राजा मोहम्मद VI को आमंत्रण देने के लिए प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में यात्रा कीय (ii) डॉ एस अय्यप्पन, सचिव (कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग) और महानिदेशक (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) ने मई 2015 में शुष्क क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र के न्यासी बोर्ड की 56वीं बैठक में भाग लिया; (iii) अक्तूबर 2015 में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित इष्टतम (आईएनडीसी) फोरम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अपर सचिव ने भाग लिया; (iv) संयुक्त सचिव (सीमा प्रबंधन), गृह मंत्रालय और उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल ने जुलाई 2015 में यूएनसीसीटी – जीसीटीएफ सीमा सुरक्षा पहल के उद्घाटन सम्मेलन में भाग लिया; (v) अक्तूबर 2015 में यूआईसी द्वारा आयोजित रेलवे सुरक्षा पर 5वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में रेलवे सुरक्षा बल से महानिदेशक ने भाग लिया; (vi) अक्तूबर 2015 में अपर निदेशक (एफआईयू), वित्त मंत्रालय ने सामरिक विश्लेषण के लिए रेल और प्रशिक्षक पाठ्यक्रम में भाग लिया; (vii) कार्यक्रम अधिकारी (सांख्यिकी) एवं कार्यक्रम अधिकारी (एआरटी), राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने नवंबर 2015 में वैश्विक एचआईवी कास्केड कार्यशाला मापन और लोगों की निगरानी में भाग लिया; ;अपपपद्ध दिल्ली–चंडीगढ़–अमृतसर द्रुत गति रेल कॉरीडोर के संदर्भ में द्रुत गति रेल समारोह के कार्यकारी निदेशक वित्त (व्यय) और कार्यकारी निदेशक (पीएसयू और हाई स्पीड), रेलवे बोर्ड, पूर्व व्यवहार्यता का अध्ययन किया।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली ने आईएससीएआई कैसाब्लांका के सहयोग से कैसाब्लांकाए मोरक्को में 6.10 जुलाई 2015 तक अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 50 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। मोरक्को में 21 मई 2015 को प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया – छः प्रमुख शहरों नामतःए रबातए कैसाब्लांकाए माराकेचए टंगेरए अगाडिर और मेकनीज़ में आयोजित योग प्रदर्शनों में लोगों की अच्छी भागीदारी रही। समारोह में कुल 1105 लोगों ने भाग लिया। नवंबर 2015 में नई दिल्ली में राजनयिक, सरकारी और सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकताओं से छूट संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

2015 की प्रथम तिमाही में भारत और मोरक्को के बीच द्विपक्षीय व्यापार ने 575.9 मिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया। भारत से मोरक्को को 186.6 मिलियन अमरीकी डॉलर का निर्यात किया गया और मोरक्को से भारत में 389.3 मिलियन अमरीकी डॉलर का आयात किया गया।

मोजाम्बिक

भारत मोजाम्बिक में चौथा सबसे बड़ा निवेशक (प्राकृतिक गैस और कोयला) है। पिछले पांच वर्षों में व्यापार पांच गुना (2014–15 में 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर) बढ़ गया है। भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियां कोयला, अवसंरचना, ऑटोमोटिव और खेती के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। मोजाम्बिक में भारतीय मूल के करीब 20,000 लोग हैं, इसके अलावा अनिवासी भारतीय 1500 के आसपास हैं। 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण श्रृंखला का उपयोग किया जा रहा है (बिजली की आपूर्तिए सौर उपकरण, खाद्य सुरक्षाए ग्रामीण पेयजलए आवास और सड़क निर्माण के लिए निर्धारित)। इससे पहले 140 मिलियन अमेरिकी डॉलर की दी गई ऋण श्रृंखला का प्रस्ताव, सफलतापूर्वक (ग्रामीण विद्युतीकरण, पीने के पानी की आपूर्ति और एक प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार केंद्र) उपयोग किया गया है।

2015 में मोजाम्बिक की आजादी का 40वां वर्ष और भारत – मोजाम्बिक के कूटनीतिक संबंधों की भी 40वीं वर्षगांठ थी। इस वर्षगांठ के अवसर पर मोजाम्बिक के राष्ट्रपति न्यूसी ने भारत की राजकीय यात्रा (4–7 अगस्त 2015) की। उनके साथ उनकी पत्नी डॉ. इसौरा न्यूसी और चार मंत्री (विदेश मामलों, खनिज और ऊर्जा, कृषि और परिवहन एवं संचार) थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ताएं की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन तथा कूटनीतिक एवं आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को वीजा रहित यात्रा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मोजाम्बिक को हाल ही में भारत की ई–पर्यटक योजना में भी शामिल किया गया है। राष्ट्रपति न्यूसी ने भारत के प्रति अत्यंत व्यक्तिगत लगाव व्यक्त किया, क्योंकि अहमदाबाद में 2003 के दौरान भारतीय प्रबंध संस्थान में कार्यपालकों के एक पाठ्यक्रम में अध्ययन के दौरान उन्होंने आईआईएम के अलावा नई दिल्ली और अहमदाबाद में व्यापार आयोजनों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने मीडिया को किए गए संबोधन में आशा व्यक्त की है कि 'अफ्रीकी और हिंद महासागर हमारी विदेश नीति की उच्चतम प्राथमिकताओं में से हैं। मोजाम्बिक दोनों के लिए महत्वपूर्ण है'।

प्रधानमंत्री कार्लोस रोसारियो ने अक्तूबर 2015 में नई दिल्ली में तीसरे भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में मोजाम्बिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उद्योग और वाणिज्य मंत्री मैक्स टोनेला भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। प्रधानमंत्री रोसारियो ने शिखर सम्मेलन के मौके पर हमारे प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की। विदेश राज्य मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वी के सिंह ने जुलाई 2015 में मापुटो का दौरा किया और शिखर सम्मेलन के लिए निमंत्रण देने हेतु मोजाम्बिक के विदेश मंत्री ओल्देमिरो बलोई से मुलाकात की। इससे पहले अप्रैल 2015 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने मोजाम्बिक का दौरा किया और अपने समकक्ष मंत्री पेड्रो कोयूटो के साथ मुलाकात की। उन्होंने विदेश मंत्री ओल्देमिरो बलोई के साथ भी मुलाकात की और प्रधानमंत्री कार्लोस रोसारियो को आमंत्रण दिया।

नवंबर 2015 में भारत के फिक्की और सरकार की संयुक्त पहल से मापुटो में चौथी बार 'नमस्कार अफ्रीका' आयोजित किया गया था।

श्री अनूप वाधवन, विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा 70 से अधिक भारतीय व्यापारियों के भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। एक आईसीसीआर द्वारा प्रायोजित गोवा के एक समूह 'केपेमचिम किरनाम' ने जुलाई 2015 में भारत–मोजाम्बिक कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के 40 वर्षों के पूरे होने के अवसर पर संगीत और नृत्य प्रदर्शन के लिए मापोटो का दौरा किया।

नामीबिया

भारत और नामीबिया के घनिष्ठ राजनीतिक संबंध लंबे समय से चले आ रहे हैं। भारत ने नामीबिया में मुक्ति संघर्ष का सक्रिय समर्थन किया, 1990 में नामीबिया की स्वतंत्रता से पहले नई दिल्ली में एक कार्यालय बनाए रखने के लिए एसडब्ल्यूएपीओ को अनुमति दी है। संयुक्त राष्ट्र संक्रमण सहायता समूह (यूएनटीएजीद्ध के तहत लेफ्टिनेंट जनरल प्रेम चंद ने सैन्य बल की कमान संभाली। पिछले कुछ वर्षों में विकास सहायता कार्यक्रमों में आईसीटी और रक्षा क्षेत्र में क्षमता निर्माण को शामिल किया गया है। नामीबिया में भारतीय मूल समुदाय का एक छोटा समूह है।

अक्तूबर 2015 में नई दिल्ली में तीसरे भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन नामीबिया के राष्ट्रपति डॉ. हेग जी जेनगोव के साथ प्रथम महिला ने भाग लिया। राष्ट्रपति जेनगोव ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में उप प्रधानमंत्री और अंतरराष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री सुश्री नेटुक्षो नंदी दृ नदैतवाह, प्रेसीडेंसी टॉम अल्वींडो में आर्थिक नियोजन मंत्री, खान और ऊर्जा मंत्री ओबेथ कोंडजोज और कृषि, जल और वानिकी मंत्री जॉन मुतोरवा सहित चार मंत्रियों को भी शामिल किया गया। उप प्रधानमंत्री और अंतरराष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री ने माननीय विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की। खान एवं ऊर्जा मंत्री ने इस्पात और खान मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर के साथ से मुलाकात की। खान एवं ऊर्जा मंत्री और कृषि, जल और वानिकी मंत्री ने भी राज्य मंत्री (परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष) डॉ जितेंद्र सिंह के साथ मुलाकात की।

इससे पहले अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में राज्य मंत्री (सूचना एवं प्रसारण) कर्नल रायवर्धन सिंह राठौर (सेवानिवृत्त) ने नामीबिया का दौरा किया और शिखर सम्मेलन के लिए निमंत्रण पत्र सौंपने के लिए उपराष्ट्रपति डॉ. निकी इयाम्बो से मुलाकात की। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंध सहयोग उप मंत्री पेया मुशेलेंगा से भी मुलाकात की।

आईसीसीआर के विशिष्ट आगंतुक कार्यक्रम के तहत नवंबर 2015 में नामीबिया के संस्थापक अध्यक्ष, डॉ सैम नुजोमा ने भारत का दौरा किया। कुलपति, नामीबिया विश्वविद्यालय, प्रोफेसर लाजरस हांगुला और अन्य अधिकारी उनके साथ थे। उन्होंने उप राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की।

नाइजर

नाइजीरिया के गणमान्य व्यक्तियों के लिए आईएएफएस–III का निमंत्रण पत्र वितरित करने के लिए 8–10 जुलाई 2015 तक प्रधानमंत्री के विशेष दूत, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम के राज्यमंत्री ने नाइजर का दौरा किया। अपने सहायता कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने 30 सितंबर, 2015 को नाइजर के महानिदेशक, रेडियो प्रसारण तथा टेलीविजन के लिए दस लैपटॉपों की आपूर्ति की गई। नई दिल्ली में 23 अक्तूबर 2015 को आयोजित चौथी भारत–अफ्रीका व्यापार मंत्रियों की बैठक में नाइजर के वाणिज्य एवं निजी क्षेत्र संवर्धन मंत्री ने भाग लिया। वे छह मंत्रियों, एक उप मंत्री और कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ थे।

नाइजीरिया

भारतीय मिशन ने 25 अप्रैल – 3 मई 2015 तक कादुना में आयोजित 36वें कादुना अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लिया। बजाजए टाटाए सिम्बा और जावा इंट. सहित विभिन्न भारतीय कंपनियों ने मेले में अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। समारोह के दौरान स्थानीय भारतीय डॉक्टरों के सहयोग से भारतीय उच्चायोग ने 'मुफ्त चिकित्सा शिविर' का भी आयोजन किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने नव निर्वाचित राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए 28–29 मई 2015 तक अबुजा का दौरा किया। उद्घाटन समारोह में भाग लेने के अलावा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने राष्ट्रपति बुहारी से मुलाकात की और उन्हें आईएएफएस–III शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री का आमंत्रण सौंप दिया। एचसीआई, अबुजा परिसर में 21 जून 2015 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस समारोह में भारतीय समुदाय और स्थानीय नाइजीरिया के लगभग 200 लोगों ने भाग लिया। इसी प्रकार समारोह में लागोस में एचसीआई कार्यालय में आयोजित किया गया था और खराब मौसम के बावजूद प्रतिभागियों की संख्या 250 से अधिक रही। एचएएल, रक्षा शिपयार्ड, ओएफबी, बीईएल और निजी उद्योग के प्रतिनिधियों वाले 15 सदस्यीय संयुक्त भारतीय रक्षा उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आपसी सहयोग के क्षेत्रों में संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए 6–8 जुलाई 2015 तक नाइजीरिया का दौरा किया। तीन सदस्यीय नाइजीरियाई प्रतिनिधिमंडल ने 27.31 जुलाई 2015 तक आर्मी एविएशन प्रतिष्ठानों का दौरा किया। निदेशक, संयुक्त सेवाएए रक्षा मंत्रालय की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 10–11 अगस्त 2015 तक आयोजित भारत–नाइजीरिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (जेडीसीसीद्ध की तीसरी बैठक में भाग लेने के लिए 6 सदस्यीय नाइजीरियाई रक्षा प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की सहायता तथा भारतीय मिशन के सहयोग से सीआईआई

द्वारा 25–27 अगस्त 2015 को लागोस में 'इंडिया शो' का आयोजन किया गया। नाइजीरिया में व्यापार और निवेश के अवसरों के लिए अपने उत्पादों के प्रदर्शन समारोह में 100 से अधिक भारतीय कंपनियों ने भाग लिया। भारतीय मिशन ने 18 नवम्बर – 2 दिसम्बर 2015 तक 36वें कानो अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लिया। आईसीसीआर द्वारा प्रायोजित एक राजस्थानी लोक नृत्य मंडली ने 17–21 सितंबर 2015 तक नाइजीरिया का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान, मंडली ने नाइजीरिया के लागोसए अबुजा और कानो शहरों में प्रदर्शन किया। आईएएफएस– III में भाग लेने के लिए 26–30 अक्टूबर 2015 तक नाइजीरियाई के राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी ने नई दिल्ली का दौरा किया। कानो राज्य, डेल्टा राज्य, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के राज्यपालोंए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) के अलावा अधिकारियों के 121 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल उनके साथ था। भारतीय मिशन ने 5 नवम्बर 2015 को आईटीईसी दिवस मनाया। इस समारोह में बड़ी संख्या में नाइजीरियाई पूर्व आईटीईसी छात्रों एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों सहित काटसिना राज्य के चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ गवर्नर, विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, योजना आयोग और अन्य मंत्रालयों के अधिकारियों ने भाग लिया। श्री अमिनू बैलो मेहसारी, काटसिना राज्य के राज्यपाल ने 11–13 नवम्बर 2015 तक महिन्द्रा एण्ड महिन्द्र लि. कंपनी के आमंत्रण पर उनसे ट्रेक्टर की खरीद के संबंध में भारत का दौरा किया। भारतीय उच्चायोग ने नाइजीरिया के तथा भारत के सेवानिवृत्त एवं सेवारत सैन्य अधिकारियों, जो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेजए वेलिंगटन के पूर्व छात्र रहे हैं, को 11 दिसम्बर 2015 को रात्रि भोज में आमंत्रित किया।

नाइजीरिया नौ सेना के निमंत्रण पर एक वरिष्ठ भारतीय नौसैनिक शिष्टमंडल 26–28 जनवरी 2016 तक हाइड्रोग्राफिक सहयोग, समुद्री प्रक्षेत्र जागरूकता (एमडीए), विशेष बल प्रशिक्षण, एंटी पायरेसी और समुद्री वार्ता के क्षेत्र में चर्चा के लिए अबुजा, नाइजीरिया गया था। नाइजीरिया के एक वरिष्ठ सैन्य शिष्टमंडल ने 25 – 29 जनवरी 2016 तक यूनाइटिड सर्विसेज इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली का दौरा किया और नाइजीरियाई सेना संसाधन केन्द्र, (एनएआरसी) की स्थापना अबुजा, नाइजीरिया में करने के लिए अध्ययन किया। नाइजीरिया के एक गवेषणात्मक नौ सेना शिष्टमंडल ने 4–8 फरवरी 2015 तक गोवा शिपयार्ड लि. का दौरा किया। अबुजा में भारतीय मिशन ने 26 फरवरी – 6 मार्च 2015 तक कडूना अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में हिस्सा लिया और नाइजीरिया स्थित भारतीय कंपनियों के उत्पाद तथा कैटलॉग प्रदर्शित किए। मेले के दिनों के दौरान स्थानीय भारतीय डॉक्टरों की सहायता से एक मुफ्त चिकित्सा शिविर भी चलाया गया।

कांगो गणराज्य (आर ओ सी)

भारत सरकार की ओर से ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के लिए एक्जिम बैंक से 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण श्रृंखला से संबंधित कार्य प्रगति पर है। 2014 में भारत सरकार ने राजधानी ब्राजावीले और पॉइंट नोइर में परिवहन प्रणाली के विकास के लिए 89.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण का अनुमोदन दिया और 600 टीपीडी वाली ग्रीन फील्ड रोटरी भट्टी आधारित सीमेंट संयंत्र परियोजना के लिए 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक अन्य ऋण भी अनुमोदित किया है। भारतीय अफ्रीकी फोरम सम्मेलन (आईएएफएस–2), के तहत आरओसी को खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला (एफटीएल) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है, जिसका कार्य प्रगति पर है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई है और द्विपक्षीय व्यापार 2013–2014 में 306.53 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2014–2015 में 618.41 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो गया। राष्ट्रपति श्री डैनिस सासोउ एनगुएसो ने घोषणा की है कि राष्ट्रपति के चुनाव मार्च 2016 में आयोजित किए जाएंगे।

रवाण्डा

भारत–रवांडा का व्यापार 88 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। विकास भागीदारी परियोजनाओं में अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ऋण श्रृंखला, क्षमता निर्माण और छात्रवृत्ति में शामिल हैं। रवांडा में भारतीय समुदाय 1500 के आसपास है।

प्रधानमंत्री अनास्तेसे मुरेकेजी ने अक्टूबर 2015 में नई दिल्ली में तीसरे भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में रवांडा के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री के साथ एक बैठक की। जुलाई 2015 में सम्मेलन के लिए निमंत्रण देने के लिए प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में ग्रामीण विकास के राज्य मंत्री श्री सुदर्शन भगत शिखर ने रवांडा का दौरा किया। उन्होंने रवांडा के विदेश मंत्री सुश्री लुईस मुशिकिवाबो से मुलाकात की।

रियायती ऋण (80 मिलियन यूएस डॉलर) के अंतर्गत निर्मित 28 मेगावाट वाले एक जल विद्युत संयंत्र का उद्घाटन 2015 में किया गया। आईएएफएस के तहत एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ किया गया है।

साओ टोमेव व प्रिंसिपे

राज्य मंत्री (आयुष) ने आईएएफएस–III के लिए निमंत्रण देने के लिए प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में 27–28 अगस्त 2015 तक साओ टोम और प्रिंसिपे का दौरा किया। प्रधानमंत्री श्री पैट्रिस एमरी त्रोवोदा ने अक्तूबर 2015 में नई दिल्ली में आयोजित तीसरे आईएएफएस में साओ टोम और प्रिंसिपे के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की थी।

सेनेगल

प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में कृषि राज्य मंत्री ने आईएएफएस–III के लिए सेनेगली नेतृत्व को निमंत्रण पत्र

सौंपने के लिए 8–11 जुलाई 2015 तक सेनेगल का दौरा किया। राष्ट्रपति मैकी सॉल ने सेनेगल के राष्ट्रपति तथा अफ्रीका के विकास के लिए नई भागीदारी (नेपाड) के अध्यक्ष, राज्य तथा सरकार अनुकूलन समिति के प्रमुख की हैसियत से तृतीय भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उनके साथ सेनेगल के विदेश मंत्री थे। सेनेगल ने सम्मेलन चलने तक भारत से निवेश आकर्षित करने के लिए एक रोड शो आयोजित किया। डकार में 21 जून 2015 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था। योग अध्यापक और उनके छात्र, सेनेगल सरकार के प्रतिनिधि, मशहूर हस्तियों, भारतीय समुदाय के सदस्य और कूटनीतिज्ञों एवं स्थानीय नागरिकों ने समारोह में भाग लिया। लोकप्रिय सेनेगल अभिनेता श्री पापा फाय, जानी मानी अभिनेत्री जोसेफिन जाम्बो और रोख्या नियांग इस समारोह में मौजूद थे। भारत की चिमिक डू सेनेगल (आईसीएस) उद्योगों में दिलचस्पी है : आईसीएस सेनेगल में एक प्रधान कंपनी है, जो रॉक फॉस्फेट से फॉस्फोरिक एसिड बनाती है और सेनेगल में रॉक फास्फेट भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। फॉस्फोरिक एसिड उर्वरकों का एक महत्वपूर्ण घटक है, अतः यह भारतीय खाद्य सुरक्षा में योगदान देता है। जिंदल स्टील एण्ड पावर लि. ने डकार के पास कायर में लगभग 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से 350 मेगावॉट वाले थर्मल विद्युत स्टेशन की स्थापना कर रही है। एसईएनईएलईसी (सेनेगल राष्ट्रीय बिजली युटिलिटी) और जिंदल स्टील एण्ड पावर लि. के बीच फरवरी 2015 में बिजली की खरीद के एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जिंदल परियोजना के वित्तीय प्रकटन की दिशा में आगे बढ़ा है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि., सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा सेनेगल में सेंडोओ की एक अन्य विद्युत परियोजना को उपकरण की आपूर्ति की जा रही है। भारत सेनेगल के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता रहा है और वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान इसके लिए 20 स्लॉट उपलब्ध थे जिसमें से 10 स्लॉट उपयोग किए गए। अफ्रीकी छात्रवृत्ति योजना के तहत शैक्षिक वर्ष 2015–16 के लिए 10 छात्रवृत्ति स्लॉट प्रस्तावित किए गए हैं और इस श्रेणी के तहत भारत में 3 अध्येताओं ने अध्ययन किया। सेनेगल में निर्देश का माध्यम फ्रैंच होने के कारण सेनेगल के छात्रों को भारत में अंग्रेजी भाषा के पाठ्यक्रमों में कठिनाई होती है। सेनेगल को दी जाने वाली कुल विकास सहायता लगभग 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, और इनमें 62.95 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण श्रृंखला चावल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए, लिफ्ट सिंचाई के पहले चरण हेतु 27०5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के दूसरे चरण के लिए 19 मिलियन अमेरिकी डॉलर, मत्स्य विकास परियोजना के लिए 41.96 मिलियन अमेरिकी डॉलरए आधुनिक बूचड़खाने, मांस प्रसंस्करण, शीत भंडारण और टैनरी संयंत्र तथा विपणन स्थान के लिए तथा 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर सार्वजनिक परिवहन आदि के लिए हैं। बेयरफुट कॉलेज टोस्टन, सेनेगल में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की दिशा में कार्रवाई कर रहा है और यह आईएएफएस–II के निर्णय का कार्यान्वयन है। उपग्रह आधारित अखिल अफ्रीका ई–नेटवर्क का हब स्टेशन, दूर चिकित्सा और दूर शिक्षा कार्यक्रमों को सभी अफ्रीकी राष्ट्रों में प्रसारित कर रहा है और यह सेनेगल में स्थित है। डकार में फान अस्पताल को एयू द्वारा क्षेत्रीय सुपर स्पेशियलिटी क्षेत्रीय अस्पताल निर्दिष्ट किया गया है और इसे विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदन दिया गया है। रोगी के सिरे वाले स्थान (पीईएल) की सुविधा पहले ही प्रारंभ हो चुकी है। वर्ष 2014–15 में द्विपक्षीय व्यापार 726.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था और भारत से निर्यात 518.75 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जबकि भारत में आयात 308.13 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो 208.13 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।

सेनेगल की ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा विकास मंत्री ने 21–22 जनवरी 2016 को नई दिल्ली में आयोजित भारत–अफ्रीका हाइड्रोकार्बन सम्मेलन के लिए एक सेनेगली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

सिएरा लियोन

फ्रीटाउन, सिएरा लियोन में भारत के भारतीय मानद कौंसलावास द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। खेल मंत्री सिएरा लियोन मुख्य अतिथि थे। समारोह में 100 के आस पास लोगों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री के विशेष दूत पेयजलए पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री आईएएफएस–III के लिए प्रधानमंत्री को निमंत्रण पत्र सौंपने के लिए 16 जुलाई 2015 को सिएरा लियोन का दौरा किया। राष्ट्रपति बाई कोरोमा ने तीसरे आईएएफएस के लिए सिएरा लियोन प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और वे विदेश मंत्री के साथ थे। कार्यवाहक व्यापार और उद्योग मंत्री ने 23 अक्टूबर 2015 को भारत–अफ्रीका व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। सिएरा लियोन के लिए एक ऊर्जा ब्लू प्रिंट विकसित करने के लिए 9–12 दिसंबर 2015 तक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के निदेशक के नेतृत्व में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारतीय सौर ऊर्जा निगम के प्रतिनिधियों वाले भारतीय विद्युत क्षेत्र प्रतिनिधिमंडल ने सिएरा लियोन का दौरा किया।

सोमालिया

सोमालिया के साथ भारत के सौहार्दपूर्ण राजनीतिक संबंध जारी हैं क्योंकि देश दो दशकों से अधिक समय के बाद गृह युद्ध और अनुवर्ती अराजकता के बाद सुदृढ होने के लिए प्रयास कर रहा है। राष्ट्रपति हसन शेख महमूद ने नई दिल्ली में 26–29 अक्टूबर 2015 तक भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (आईएएफएस–तृतीय) के लिए सोमाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जिसके दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी। सोमाली विदेश मंत्री अब्दिसालन हदलिय उमर भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे और उन्होंने सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय

बैठक की थी। बाद में, सोमाली राष्ट्रपति ने भोपाल की यात्रा की, जहां उन्हें बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। वे उक्त विश्वविद्यालय के छात्र रहे थे और उन्होंने 1986–88 में अपना एम. एड किया था। इससे पहले, राज्य मंत्री (वीकेएस) ने आईएएफएस–III के लिए राष्ट्रपति हसन शेख महमूद को आमंत्रित करने के लिए जुलाई 2015 में मोगादिशू का दौरा किया था।

नैरोबी में भारत की नई उच्चायुक्त (एचसीआई), सुश्री सुचित्रा दुरई ने राजदूत का अधिकृत कार्य करने के लिए 14–15, नवम्बर 2015 को सोमालिया की यात्रा की और सोमाली राष्ट्रपति को प्रत्यय पत्र प्रस्तुत किया। सोमाली के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, अब्दि रहमान उस्मानए 23 अक्टूबर 2015 को भारत–अफ्रीका व्यापार मंत्रियों की चौथी बैठक के लिए तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत के उच्चायोग, नैरोबी, ने मोगादिशू में 29–30 जुलाई 2015 तक सोमालिया के संबंध में आयोजित दूसरे उच्च स्तरीय साझेदारी फोरम (एचएलपीएफ) में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सोमालिया के राष्ट्रपति और सोमालिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि (यूएनएसआरएसजी), निकोलस की सह–अध्यक्षता में 32 देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने विवेचना में भाग लिया था। सोमालिया के लिए भारत की सहायता के रूप में विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई) ने अक्टूबर 2015 में 20 कनिष्ठ सोमाली राजनयिकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

मलेशियाई स्वामित्व वाली अपहृत मालवाहक पोत एम वी अल्बेडो के चालक दल के 11 सदस्यों सहितए एक भारतीय श्री अमन कुमार को नवंबर 2010 के बाद से बंधक बनाकर रखा गया था, जिन्हें सोमाली समुद्री डाकुओं ने छोड़ दिया और वे 7 जून 2015 को नैरोबी पहुंचे थे। इस अवधि के दौरान 11 सोमाली नागरिकों को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया।

दक्षिण अफ्रीका

भारत और दक्षिण अफ्रीका में लंबे समय घनिष्ठ, राजनीतिक सामुदायिक और आर्थिक संबंध चले आ रहे हैं। जहां भारतीय मूल के समुदाय (दुनिया के किसी भी स्थान से सबसे बड़ा) लगभग 15 मिलियन होने का अनुमान है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने राजनीतिक सक्रियता शुरू की और 1894 में नेशनल इंडियन कांग्रेस का गठन किया। भारत 1960–1980 के दशकों के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रंगभेद विरोधी आंदोलन के मामले में सबसे आगे था। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ राजनयिक संबंध 1961 में तोड़ लिए और 1994 में दक्षिण अफ्रीका के साथ राजनयिक संबंध को पुनः स्थापित किया। द्विपक्षीय व्यापार लगभग 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने ब्रिक्सए इब्सा और जलवायु परिवर्तन वार्ता सहित विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर भी ठोस व वास्तविक।

इस अवधि के दौरान व्यापक द्विपक्षीय भागीदारी को जारी रखा गया। इसमें दोनों पक्षों की ओर से उच्चस्तरीय यात्राओं की एक श्रृंखला शामिल है। राष्ट्रपति जुमा ने अक्टूबर 2015 में नई दिल्ली में आयोजित तीसरे भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और विदेश मंत्री सुश्री मेते नकोना दृ मेशाबाने भी उनके साथ थीं। राष्ट्रपति जुमा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और विदेश मंत्री मेशाबाने ने शिखर सम्मेलन के मौके पर टीम के साथ एक बैठक की थी।

इससे पहले मई 2015 में विदेश श्रीमती माननीय मंत्री सुषमा स्वराज ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री सुश्री मेते नकोना – मेशाबाने के साथ भारत–दक्षिण अफ्रीका संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग के 9 वें सत्र की सह–अध्यक्षता करने के लिए डरबन का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने आईएएफएस–III के लिए निमंत्रण देने के लिए राष्ट्रपति जैकब से मुलाकात की। संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने और भारत–दक्षिण अफ्रीका तरजीही व्यापार समझौते (पीटीए) के संबंध में वार्ता की शुरुआत करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह बनाने का निर्णय लिया।

प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जुमा ने जुलाई 2015 में ऊफ़ाए रूस में 7 वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और नवंबर 2015 में पेरिस में और यूएनएफसीसीसी कॉप 21 की बैठक के मौके पर भी मुलाकात की

दक्षिण अफ्रीका के गृह मंत्री श्री मालुसी गिगेबा ने जुलाई 2015 में भारत का दौरा किया। उन्होंने गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की। ग्वातेंग प्रांत के प्रमुख श्री डेविड मखुरा ने अप्रैल 2015 में भारत का दौरा किया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। पश्चिमी केप प्रांत के प्रमुख सुश्री हेलेन जिले ने नवंबर 2015 में भारत का दौरा किया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने जुलाई 2015 में दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया। उन्होंने अपने समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एफजेड म्सिमेंग और दक्षिण अफ्रीका के रक्षा सचिव डॉ सैम मखुडु गुलुबे के साथ मुलाकात की।

इस अवधि के दौरान कई भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडलों ने विभिन्न व्यापारिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया। इनमें शामिल हैंः अफ्रीकी उपयोज्य वस्तु सप्ताह (मई 2015)ए जिसमें भारतीय इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण एसोसिएशन ने 10 कंपनियों के एक प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का समन्वय कियाय मई 2015 में अफ्रीका स्वास्थ्य व्यापार मेला जिसमें इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया; जून 2015 में साइटेक्स (व्यापार मेला) जिसमें बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्रीए श्री श्याम रजक ने एक भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया; अगस्त 2015 में डीकोरेक्स मेला जिसमें हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषदए कालीन निर्यात संवर्धन परिषद

और कॉयर बोर्ड के प्रतिनिधियों से गठित भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया; सितंबर 2015 में बौमा एक्सपो जिसमें सीआईआई के नेतृत्व में एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया।

महात्मा गांधी की भारत वापसी की 100 वीं वर्षगांठ के अवसर पर उच्चायुक्त द्वारा सितंबर 2015 में दक्षिण अफ्रीका के रस्टनबर्ग शहर में महात्मा गांधी की एक आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया था। इस अवधि के दौरान दक्षिण अफ्रीका में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रायोजित कई प्रदर्शन आयोजित किए गए।

दक्षिणी सूडान

राष्ट्रपति श्री सालवा किर तथा पूर्व राष्ट्रपति श्री रिक मचार के प्रति वफादार सेनाओं के बीच नृजातीय युद्ध के कारण देश की राजनैतिक तथा सुरक्षा की स्थिति नाजुक बनी रही। देश में चल रहे युद्ध के कारण इसे अकाल और भुखमरी से होने वाली खतरों का सामना करना पड़ता है। अंतरसरकारी प्राधिकरण (आईजीएडीद्धए विभिन्न देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की मध्यस्थता से युद्धरत गुटों के बीच कई शांति समझौतों पर हस्ताक्षर के बावजूद दोनों पक्षों में विश्वास की कमी के कारण इन समझौतों का कार्यान्वयन एक समस्या बना हुआ है। नवीनतम व्यापक शांति समझौता पर अगस्त 2015 में हस्ताक्षर किए गए थे।

राष्ट्रपति सेल्वा किर ने 26–29 अक्टूबर 2015 तक नई दिल्ली में तृतीय भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (आईएएफएस III) में दक्षिण सूडानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। शिखर सम्मेलन के मौके पर राष्ट्रपति किर ने प्रधानमंत्री (प्रधानमंत्री) के साथ द्विपक्षीय बैठक की और दक्षिण सूडान के विदेश मंत्री बरनाबा मरियल बेंजामिन ने विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इससे पहले, राज्य मंत्री (वीकेएस) ने आईएएफएस–III के लिए भारत की यात्रा हेतु दक्षिण सूडानी नेतृत्व को आमंत्रित करने के लिए जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में जुबा का दौरा किया।

दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन (यूएनएमआईएसएस) में 2200 से अधिक भारतीय सैनिक तैनात रहते हैं। 2013 में सात भारतीय सैनिकों की मौत के बावजूद, भारत अपने अधिदेश के लिए प्रतिबद्ध है। देश में आंतरिक संघर्ष से भारतीय कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) और दक्षिण सूडान में इसके भागीदारों के संघ को अपने क्षेत्रों में तेल उत्पादन पूरी तरह बंद कर देना पड़ा है।

सूडान

भारत और सूडान के बीच पारंपरिक एवं बहुमुखी संबंध विवेच्य वर्ष के दौरान सुदृढ़ किए गए और इनका विस्तार किया गया। राष्ट्रपति उमर हसन अहमद अल–बशीर और सूडान के विदेश मंत्री प्रो इब्राहिम घानडोर ने 26–29 अक्तूबर 2015 तक नई दिल्ली में आयोजित तीसरे भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। आईएएफएस–III के मौके पर राष्ट्रपति बशीर और भारत के प्रधानमंत्री के साथ–साथ विदेश मंत्री घानडोर और विदेश मंत्री के बीच द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं। इससे पहले, आईएएफएस–III के लिए निमंत्रण सौंपने के लिए प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में राज्य मंत्री (वीकेएस) ने 19 सितम्बर 2015 को खारटौम का दौरा किया था।

उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉ अरविंद गुप्ता के नेतृत्व में 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 28–31 जुलाई 2015 तक खारटौम का दौरा किया और सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी से संबंधित मामलों में सहयोग के लिए सूडानी आसूचना और सुरक्षा एजेंसियों के साथ विचार–विमर्श किया। उन्होंने इस यात्रा के दौरान सूडान की राष्ट्रीय असेंबली के अध्यक्ष, गृह मंत्रीए वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्रीए विदेश राज्य मंत्री के साथ मुलाकात की। सूडान के व्यापार राज्य मंत्री श्री इलसादिग एम अली ने तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए भारत का दौरा किया और 23 अक्टूबर 2015 को नई दिल्ली में आयोजित भारत–अफ्रीका व्यापार मंत्रियों की चौथी बैठक में भाग लिया।

खारटौम में 13–14 जून 2015 तक एक भारतीय शिक्षा प्रदर्शनी आयोजित की गई जिसमें 7 भारतीय संस्थानों / विश्वविद्यालयों ने भाग लिया। बाद में, 'एडवान्टेज हेल्थ केयर इंडिया–2015' भारत में चिकित्सा मूल्य विषयक अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में सूडान के सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। यह सम्मेलन 05–07 अक्तूबर 2015 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया। एक लंबे अंतराल के बाद, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद से 12 सदस्यीय सांस्कृतिक दल ने सूडान के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से सूडान का दौरा किया और नवंबर 2015 में ओमडरमैन (खारटौम की सिस्टर सिटी) और पोर्ट सूडान में प्रदर्शन किया।

नवंबर 2015 से भारतीय दूतावास में स्थायी रक्षा अताशे के मार्गदर्शन में एक रक्षा स्कंध ने कार्य शुरू कर दिया गया है।

स्वाजीलैण्ड

भारत की ओर से 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के रियायती ऋण के जरिए वित्त पोषण से स्वाजीलैंड में दो परियोजनाओं (एक आईटी पार्क और कृषि मशीनीकरण) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। स्वाजीलैंड में भारतीय समुदाय के लोगों की कुल संख्या करीब 800 है। इसमें व्यापारी, सरकार, अस्पतालों और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत व्यावसायिक शामिल हैं।

महामहिम सम्राट मसवती-III ने अक्टूबर 2015 में नई दिल्ली में तीसरे भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में अपने देश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उनके साथ आर्थिक योजना एवं विकास मंत्री हेलांगुसेम्फी दलेमिनीए विदेश मामलों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्री म्गोगवे गामेडजे भी थे।

इससे पहले जुलाई 2015 में संस्कृतिए पर्यटन और नागरिक

उड्डयन राज्य मंत्री और नागरिक उड्डयन, डॉ महेश शर्मा ने शिखर सम्मेलन के लिए निमंत्रण देने के लिए स्वाजीलैंड का दौरा किया।

तंजानिया

तंजानिया के साथ भारत के संबंध नेतृत्व के बीच घनिष्ठ सौहार्द, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दीर्घकालिक एकता, विकास सहायता और प्रवासी भारतीय समुदाय से संबंध पर आधारित हैं। एक बड़े प्रवासी समूह के साथ भारत, (50,000 पीआईओ और 10,000 एनआरआई) की तंजानिया में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार के साथ भारत तंजानिया के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत शीर्ष तीन निवेशकों (3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास) मुख्य रूप से मोटर वाहन, दूरसंचार और कृषि से संबंधित क्षेत्रों में है। भारत से तंजानिया को विकास सहायता में छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण, 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण श्रृंखला शामिल हैं।

भारत – तंजानिया के घनिष्ठ संबंधों को जून 2015 में राष्ट्रपति जकाया एम कीक वेटे की भारत की प्रथम राजकीय यात्रा से और भी मजबूत बनाया गया और उन्होंने राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ताएं आयोजित की। उप राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, श्री जे पी नड्डा और एमएसएमई मंत्री श्री कलराज मिश्रा ने तंजानिया के राष्प्रति से मुलाकात की। नेतृत्व स्तर के विचार विमर्श से कृषि, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला, विकास सहयोग तथा आर्थिक व व्यापारिक संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग को बल मिला। 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें हाइड्रोग्राफी पर समझौता ज्ञापन के अलावा लेक विक्टोरिया पाइपलाइन परियोजना के विस्तार के लिए 268.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण श्रृंखला और उपरोक्त परियोजना के लिए विस्तृत डीपीआर तैयार करने के लिए डब्ल्यूएपीसीओएस के साथ एक समझौता ज्ञापन शामिल है। जंजीबार में जल आपूर्ति प्रणाली के पुनःस्थापना और सुधार हेतु 92 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक अन्य ऋण श्रृंखला की घोषणा की गई थी। दो समझौता ज्ञापन के क्षेत्र में सहयोग पर है। समारोह के दौरान दर एस सलाम और जंजीबार के पत्तनों के लिए नैवीगेशन चार्ट औपचारिक रूप से तंजानिया पक्ष को सौंपे गए। प्रधानमंत्री ने अगले चरण में भारत में आपातकालीन चिकित्सा स्थिति और पर्यटन के लिए यात्रा की सुविधा हेतु तंजानिया के लिए ई–पर्यटन वीजा योजना के विस्तार की भी घोषणा की। तंजानिया में एनएसआईसी द्वारा इंक्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान से की जाएगी। सी–डैक द्वारा नेल्सन मंडेला विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान को उन्नत बनाने का कार्य किया जाएगा और 1.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान से सुपरकम्प्यूटर का उपहार भी दिया जाएगा। राष्ट्रपति कीक वेटे ने व्यापारिक बैठकें भी आयोजित की जिसमें मुख्य फोकस कृषि मशीनीकरण (ट्रेक्टर विनिर्माण), स्वास्थ्य देखभाल (अस्पताल), आधारभूत संरचना (मेट्रो परियोजनाएं) के अलावा अन्य क्षेत्रों में भारतीय निवेश व विशेषज्ञता आकर्षित करने पर था।

उप–राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद गरीब बिलाल ने अक्टूबर 2015 में नई दिल्ली में तीसरे भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में तंजानिया के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी। इससे पहले कौशल विकास और संसदीय कार्य राज्य मंत्रीए श्री राजीव प्रताप रूडी ने प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में आयोजन में शामिल होने के लिए तंजानिया नेतृत्व को निमंत्रण देने के लिए सितंबर 2015 में तंजानिया का दौरा किया। इस यात्रा के दौरानए श्री रूडी ने राष्ट्रपति किकवेटे को आमंत्रण दिया।

जॉन पोम्बे यूसुफ मेगुफुली अक्टूबर 2015 में हुए चुनावों के बाद तंजानिया के राष्ट्रपति चुने गए थे। डॉ ऑगस्टाइन महिगा को विदेश मामलों, पूर्वी अफ्रीकी, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्री नियुक्त किया गया था।

टोगो

भारतीय मानद कौंसलावास ने लोम में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए, मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृति मंत्री के साथ अगोरा सेगर परिसर में एक समारोह का आयोजन किया। लगभग 130 लोगों ने समारोह में भाग लिया। टोगोलेस नेतृत्व को आई ए एफ एस III का निमंत्रण पत्र देने के लिए प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में कृषि राज्य मंत्री ने 7 जुलाई 2015 को टोगो का दौरा किया। टोगो के विदेश मामलों, सहयोग और अफ्रीकी एकता के मंत्री ने आईएएफएस–III में टोगोलेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। पर्यटन व्यापारए उद्योग और निजी क्षेत्र संवर्धन मंत्री ने 23 अक्टूबर 2015 को भारत – अफ्रीका व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।

ट्यूनीशिया

1958 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से भारत ने ट्यूनीशिया के साथ सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखा है। ट्यूनीशिया की क्रांति के बाद निर्वाचित सरकारों ने अपनी किसी भी क्रांति पूर्व व्यवस्थाओं की तुलना में भारत के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए और अधिक कार्य किया है। परिणामस्वरूप इससे विशेष रूप से ऑटोमोबाइलए रक्षा और सुरक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भारतीय कंपनियों को काफी लाभ मिला है। ट्यूनीशिया फॉस्फेट के लिए एक विश्वसनीय स्रोत रहा है। दूसरी ओर, भारत उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्यात करता है। इनमें नॉकड डाउन किट, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल आइटम, कपास, मैकेनिकल इंजन, कार्बनिक रसायन उत्पाद, रबर, चावल, कॉफी / मसाला आदि महत्वपूर्ण हैं। वर्ष 2014 के दौरान वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार 432.37 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। वर्ष 2015 की पहली छमाही के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 161

मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। इसमें 132 मिलियन अमेरिकी डॉलर भारतीय निर्यात और 29 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भारतीय आयात भी शामिल है। ट्यूनीशिया–भारत फर्टिलाइजर्स एसए (टीआईएफईआरटी) का प्रचालन 2013 में किया गया था, जो प्रतिवर्ष 360,000 टन का फॉस्फोरिक एसिड उत्पादन करने की क्षमता के साथ 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से स्थापित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। दो भारतीय कंपनियांए कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स लिमिटेड इस कंपनी में 30% इक्विटी के मालिक हैं। मे. केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड और ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड नामक भारतीय कंपनियां कई वर्षो से ट्यूनीशिया में बिजली पारेषण लाइनों का विनिर्माण कर रही हैं। महिंद्रा पिकअप ट्रकों का एक असेंबली संयंत्र वर्ष 2013 से प्रचालनरत है और प्रति वर्ष 2500 के उत्पादन के लक्ष्य के साथ प्रति वर्ष 1200 से अधिक वाहनों की बिक्री कर रही है। मे. टाटा मोटर्स ने जून 2015 में ट्यूनीशियाई कंपनियों 'ली मोटेयूर' और आईकारश के साथ पिकअप ट्रकों का उत्पादन शुरू कर दिया है। डाबर की एक टूथपेस्ट निर्माण परियोजना है जिसका मूल्य 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है।

शेख राशिद घान्नोची, ट्यूनीशिया ;सरकार में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और गठबंधन साथी), के एन्नहडा पार्टी के अध्यक्ष ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के एक अतिथि के रूप में 5–8 अप्रैल 2015 तक भारत का दौरा किया। उन्होंने माननीय उप राष्ट्रपति और माननीय विदेश मंत्री (ईएएम), और लोक सभा के उपाध्यक्ष के साथ मुलाकात की।

भारतीय सांस्कृतिक समूह श्लोक रंगश्ए भांगड़ा नृत्य के कलाकारों ने 26–27 अप्रैल 2015 तक को ट्यूनीशिया का दौरा किया और कई स्थानों पर तीन नाटकों का मंचन किया। श्री अनिल वाधवाए सचिव (पूर्व) ने 30 अप्रैल 2015 को विदेश कार्यालय के परामर्श के तीसरे दौर के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अर्थात् 21 जून 2015 को ट्यूनिस में पहली बार योग का एक बड़ा सत्र आयोजित किया गया था। नई दिल्ली में 29 जून 2015 को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विषयक संयुक्त कार्य समूह का दूसरे सत्र आयोजित किया गया। आईटी–आईटी समर्थित सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, डिजिटल भारत की पहलए ई–शासन से संबंधित उत्कृष्ट पद्धतियों का आदान–प्रदान करने और संबंधित एजेंसियों के बीच टेक्नोपार्क्स, डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सहयोग पर दोनों पक्षों ने सहमति जताई।

श्री तैब बैकोउचे, ट्यूनीशिया के विदेश मंत्री ने तीसरे भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत के लिए ट्यूनीशियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने नेशनल डायलॉग क्वार्टेट द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार जीतने के लिए ट्यूनीशिया को बधाई दी। श्री तैब बैकोउचे ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की।

भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन के तहत ट्यूनिस के पेस्टेयर संस्थान और नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय नुवंशिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र (आईसीजीईबी) के बीच सहयोग की शुरूआत की गई है। सीवी रमन अध्येतावृत्ति के तहत, भारत में अनुसंधान के लिए ट्यूनीशियाई विद्वानों ने हर वर्ष अध्येतावृत्ति का लाभ उठाया।। भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत लगभग 50–60 ट्यूनीशियाई उम्मीदवारों ने भारत में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा कैरोअन शहर में 05–12 दिसम्बर 2015 तक प्रायोजित प्रदर्शनी के अंतिम चरण में 'भारत के स्मारक' और 'भारत के इस्लामी स्मारक' का आयोजन किया गया।

ट्यूनिस में 18–20 जनवरी 2016 तक दवाओं और औषधि विषयक संयुक्त कार्य समूह की छठी बैठक हुई।

फरवरी 2016 में ट्यूनीशियाई पर्यटन मंत्रालय ने सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय मेले में ट्यूनीशियाई कलाकारों की भागीदारी प्रायोजित की।

युगाण्डा

भारत–युगांडा के संबंध औपनिवेशिक समय से जुड़े हैं जब भारतीय कामगार मोम्बासा बंदरगाह से युगांडा रेलवे के निर्माण में लगे हुए थे। भारत–युगांडा व्यापार 290 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। आज भारतीय समुदाय की संख्या 27,000 के आसपास है।

राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने अक्तूबर 2015 में नई दिल्ली में तीसरे भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में युगांडा के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उनके साथ विदेश मंत्री श्री सैम कुटेसा थे। राष्ट्रपति मुसेवेनी ने हमारे प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी। शिखर सम्मेलन के लिए निमंत्रण देने के लिए प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में जुलाई 2015 में ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री सुदर्शन भगत ने युगांडा का दौरा किया।

2015 के सितंबर में राष्ट्रपति मुसेवेनी कोलकाता में मार्गस्थ विराम किया जहां उनके साथ संयुक्त राष्ट्र सुधार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सचिव (एम एंड ईआर) को आमंत्रण दिया गया। विदेश मंत्री सैम कुटेसा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

जाम्बिया

भारत और जाम्बिया के काफी अच्छे आर्थिक संबंध हैं। भारत–जाम्बिया का व्यापार 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है। भारत का निवेश 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (बैंकिंग, खनन और खनिज, दूरसंचार आदि) के आसपास होने का अनुमान है। जाम्बिया में भारतीय मूल समुदाय के लोगों की संख्या 13,000 के आसपास है।

अक्टूबर 2015 में नई दिल्ली में उप–राष्ट्रपति सुश्री इनोंगे डब्ल्यू विना ने तीसरे भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में जाम्बिया के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उनके साथ कृषि मंत्री श्री त्रिवेन लुबिंडा, उप विदेश मंत्री श्री रेफोर्ड मबुलु, और उप स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चितालु चिलुका भी थे। उप राष्ट्रपति श्रीमती इनोंगे ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की। उप स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चिलुबा और उप विदेश मंत्री श्री मबुलु ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ जे पी नड्डा से भी मुलाकात की। जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम राज्यमंत्री श्री जी एम सिद्धेश्वर ने शिखर सम्मेलन के लिए निमंत्रण देने हेतु जाम्बिया का दौरा किया। शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति भवन में 8 सदस्यीय जाम्बियन पारंपरिक मास्क नृत्य मंडली 'छोटा सांस्कृतिक समूह' ने प्रदर्शन किया।

अक्टूबर 2015 में दिल्ली में भारत–अफ्रीका व्यापार मंत्रियों की चौथी बैठक में वाणिज्य, व्यापार और उद्योग मंत्री सुश्री मारग्रेट मवानाकाटवे ने जाम्बिया का प्रतिनिधित्व किया। इसके पहले विवेच्य वर्ष में अप्रैल 2015 में नई दिल्ली में आयोजित भारत–अफ्रीका स्वास्थ्य फोरम 2015 में उप स्वास्थ्य मंत्री डॉ चिलुका ने जाम्बिया के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। कार्यक्रम का आयोजन सीआईआई, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया था। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव से भी मुलाकात की।

अक्टूबर 2014 में राष्ट्रपति साता के कार्यालय में निधन के बाद राष्ट्रपति के उपचुनाव में राष्ट्रपति एडगर चाग्वा लुंगा को जनवरी 2015 में निर्वाचित किया गया था।

भारत ने दिसंबर 2015 में लुसाका में कोमेसा के मंत्रियों की परिषद की 35 वीं बैठक में भाग लिया। इससे पहले जून 2015 में ईएसी और कोमेसा ने मिस्र में एक त्रिपक्षीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (टीएफटीएद्ध एसएडीसी का शुभारंभ किया।

जिम्बाब्वे

भारत–जिम्बाब्वे विकास भागीदारी में छात्रवृत्तिए अन्य क्षमता निर्माण और जल आपूर्ति और बिजली क्षेत्र के लिए रियायती ऋण शामिल है। द्विपक्षीय व्यापार 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का है। जिम्बाब्वे में भारतीय समुदाय 9,000 के आसपास है।

जिम्बाब्वे ने इस अवधि के दौरान अफ्रीकी संघ की अध्यक्षता की। भारत और जिम्बाब्वे ने तीसरे भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन के प्रारूप के तहत बैठकों (वरिष्ठ अधिकारी, मंत्रिस्तरीय और पूर्ण शिखर सम्मेलन) की सह अध्यक्षता की। राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे ने शिखर सम्मेलन में जिम्बाब्वे के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और पूर्ण सह–अध्यक्षता की। उनके साथ विदेश मंत्री श्री सिंबाराशे मुमबेनगेगवी थे। राष्ट्रपति मुगाबे ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की। इससे पहले सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ (रिटा.) ने अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में अगस्त 2015 में जिम्बाब्वे का दौरा किया और शिखर सम्मेलन के लिए निमंत्रण दिया।

जिम्बाब्वे के कृषि, मशीनीकरण और सिंचाई विकास मंत्री डॉ यूसुफ उतारा ने नई दिल्ली में पूसा संस्थान में आयोजित ईआईएमए एग्रीमैक इंडिया 2015 में भाग लेने के लिए दिसंबर 2015 में भारत का दौरा किया।

अक्तूबर 2015 में बुलावायो ताप विद्युत संयंत्र के नवीकरण / उन्नयन के लिए ऋण श्रृंखला करार (87 मिलियन अमेरिकी डॉलर) पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) ने 19 जून 2015 खरीदारों के लिए एक्जिम बैंक की ऋण योजना के तहत खनन उपकरणों की आपूर्ति की। एक्जिम बैंक की अन्य क्रेता ऋण योजना के तहत अशोक लीलैंड ने अक्टूबर 2015 में 650 वाहनों की आपूर्ति की।

भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (आई ए एफ एस)

अफ्रीकी महाद्वीप के साथ भारत के संबंध तीसरे भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन आईएएफएस–III (26 – 29 अक्तूबर 2015, नई दिल्ली) में पूर्णरूपेण उभरकर सामने आया। समारोह का आयोजन अभूतपूर्व पैमाने पर किया गया। आमंत्रित सदस्यों की प्रतिभागिता संभारगत तैयारियों, शिखर सम्मेलन के परिणामों और विचार–विमर्श के संदर्भ में इस कार्यक्रम को निस्संदेह सफलता मिली थी। पहले दो शिखर सम्मेलनों का आयोजन 2008 में नई दिल्ली और 2011 में अदीस अबाबा में किया गया

पहली बार, सभी 54 अफ्रीकी देशों, जिनके साथ भारत के कूटनीतिक संबंध हैं, को आमंत्रित किया गया है और उनमें से सभी ने भाग लिया। इनमें से 41 ने राष्ट्र प्रमुख / सरकार प्रमुख के स्तर पर प्रतिनिधित्व किया था, जो अब तक भारत की मेजबानी में किसी भी समारोह के संदर्भ में एक रिकॉर्ड है।

इसके कार्यक्रम से सर्वोच्च स्तर पर विचार–विमर्श के अलावा प्रधानमंत्री के साथ 41 और ईएएम के साथ 31 द्विपक्षीय बैठकों का अवसर प्राप्त हुआ। इससे पहले आईएएफएस–III के लिए प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में व्यक्तिगत निमंत्रण देने के लिए 16 राज्य मंत्रियों ने 49 अफ्रीकी देशों का दौरा कियाए जो अभूतपूर्व है।

आईएएफएस–III के दौरान कई प्रकार के व्यापारिक, शैक्षिक, मीडिया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वाणिज्य मंत्रालय ने आईएएफएस–III से एक सप्ताह पहले भारत–अफ्रीका व्यापार मंत्रियों की एक बैठक का आयोजन किया।

इस सम्मेलन का आयोजन एक ऐसे ऐतिहासिक वर्ष में किया गया जो संयुक्त राष्ट्र की 70वीं वर्षगांठ है, और इसी वर्ष के जून 2015 में अफ्रीकी संघ (एयू) द्वारा कार्यसूची 2063 अंगीकार किया, जुलाई 2015 में अदीस अबाबा में विकास के निधिकरण पर तीसरा

मोजाम्बिक के प्रधानमंत्री महामहिम श्री कारलोस अगोस्तिनबो डो रोजारियो के नई दिल्ली आगमन (28 अक्टूबर, 2015) पर विदेश राज्य मंत्री उनका स्वागत करते हए।

नई दिल्ली में भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन, 2015 के उद्घाटन सत्र का सामूहिक फोटो 29 अक्टूबर, 2015

भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम

नई दिल्ली में भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (29 अक्टूबर 2015) के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री द्वारा संबोधन

नई दिल्ली में तृतीय भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (29 अक्टूबर, 2015) के समापन समारोह में भारत तथा अफ्रीका के महामहिम

तृतीय भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (29 अक्टूबर, 2015) में भारत के राष्ट्रपति तथा प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख और उनके पति/पत्नी

अंतरारष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सितम्बर 2015 में यूएनजीए द्वारा टिकाऊ विकास हेतु 2030 कार्यसूची को अंगीकार किया गया और यूएनएफसीसीसी के कॉप 21 में जलवायु परिवर्तन के संबंध में 2020 के बाद करार को अंतिम रूप दिया गया और इसके बाद डब्ल्यू टी ओ मंत्रालयी समूह की बैठकें हुईं। ये दोनों कार्य दिसंबर 2015 में नैरोबी, अफ्रीका में ही किए गए। इन सभी ने वैश्विक मुद्दों के संदर्भ में आईएएफएस–III को एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान किया, जहां भारत और अफ्रीका के बीच समन्वय जारी है।

आईएएफएस– I के माध्यम से 2008 में एयू के साथ संरचित संबद्धता की शुरुआत के बाद से, भारत की ओर से अफ्रीका के लिए 40,000 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं जिनमें विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के साथ 60 संस्थानों में 300 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रस्ताव है। आईटी, अक्षय ऊर्जा, कृषि, समुद्री और एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, समुद्री जल सर्वेक्षण, एसएमई उद्यमशीलताए ग्रामीण विकास, संसदीय कार्य, संभरण और प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलनए आपदा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, फोरेंसिक विज्ञान तथा रक्षा और सुरक्षा जैसे अन्य अनेक क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण शामिल हैं।

भारत ने पिछले दशक में 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रियायती ऋण श्रृंखला (2008 में आईएएफएस–I के बाद से 7.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का प्रस्ताव किया है। इनमें से आईएएफएस–III तक 6.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। इसमें 40 देशों में 114 परियोजनाएं शामिल हैं (मुख्य रूप से बिजली उत्पादन और वितरण, जल आपूर्ति और सिंचाई, कृषि, प्रकाश विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, और मूलसंरचना निर्माण के क्षेत्रों में)। आईएएफएस–I के बाद से मुख्य तौर पर क्षेत्रीय और अखिल–अफ्रीकी स्तरों पर विशिष्ट क्षेत्रों में संस्थाओं की स्थापना के माध्यम से क्षमता निर्माण के लिए मुख्य तौर पर 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान भी अनुमोदित किया गया है।

प्रधानमंत्री ने अपने उद्‌घाटन भाषण मेंए अफ्रीका की ओर से बड़े पैमाने पर सकारात्मक योगदान और भारत तथा अफ्रीका के बीच पूरकताओं के बारे में बात की थी। उन्होंने अफ्रीकी नागरिकों के लिए छात्रवृत्तियों को दोगुना कर 50,000 तक करने और अगले पांच वर्षों में रियायती ऋण के रूप में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एक अतिरिक्त प्रस्ताव की घोषणा की। उन्होंने इस अवधि में 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान की भी घोषणा की। उन्होंने समुद्री अर्थव्यवस्था और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे दो नए क्षेत्रों में पर प्रकाश डाला है, जहां भारत अफ्रीका के देशों के साथ इन क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं देखता है।

शिखर सम्मेलन में दो संयुक्त दस्तावेजों को अंगीकार किया गया दिल्ली घोषणा 2015 और रणनीतिक सहयोग की रूपरेखा। दिल्ली घोषणा 2015 में इस तथ्य पर बल दिया गया है कि संपूर्ण मानव जाति का एक तिहाई भाग होने के बावजूद भारत और अफ्रीका को यूएनएससी जैसे संस्थानों से अलग रखा गया है। इस प्रकार उन्होंने वैश्विक मुद्दों पर सामान्य लोगों की स्थिति स्पष्ट की है। यह 2015 की ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के वैश्विक संदर्भ में आईएएफएस–III की स्थिति दर्शाता है। यह भारत–अफ्रीका संबंधों की पृष्ठभूमि उपलब्ध कराता है, भारत–अफ्रीका रणनीतिक भागीदारी की विशेषताएं बताने के साथ–साथ दक्षिण–दक्षिण सहयोग की अद्भुत प्रकृति पर प्रकाश डालता है। यह सतत विकास और आर्थिक विकास से संबंधित साझा प्राथमिकताओं और चिंताओं के बारे में बताता है, जो सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों में रूपांतरित हो जाता है। इनमें शिक्षा और क्षमता निर्माण, कृषि, व्यापार और निवेश, ऊर्जा/ समुद्री अर्थव्यवस्थाए अवसंरचना, स्वास्थ्य, शांति और सुरक्षा तथा बहुपक्षीय मुद्दे शामिल हैं। रणनीतिक सहयोग की रूपरेखा राजनीतिक घोषणा का अधिक से अधिक विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध कराती है।

एयू के साथ संयुक्त कार्रवाई योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक संयुक्त निगरानी तंत्र स्थापित करने के लिए एक नया निर्णय किया गया है जिससे भारत और अफ्रीकी संघ के बीच अधिक से अधिक नियमित समन्वय संभव हो सकने की उम्मीद है। इस पर सहमति हो गई थी कि अगले शिखर सम्मेलन को 5 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित किया जाए जिससे भागीदारी की पहल के संबंध में बेहतर कार्यान्वयन किया जा सके।

कुछ सामान्य विषय प्रधानमंत्री / विदेश मंत्री स्तर पर 72 द्विपक्षीय बैठकों में कुछ सामान्य विषय उभरे। इसे स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया गया कि भारत और अफ्रीकाए जो संपूर्ण मानवजाति के एक तिहाई भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं, के बिना यू एन एस सी अधूरा बना हुआ है और इसे बदलने की जरूरत है ताकि यूएनएससी द्वारा समकालीन समस्याओं को सुलझाया जा सके। जलवायु परिवर्तन और डब्ल्यूटीओ वार्ता और आतंकवाद का मुकाबला करने में द्विपक्षीय और वैश्विक सहयोग में वृद्धि के बारे में स्थिति का समन्वयन जारी रखने की आवश्यकता पर सहमति बनी थी। कृषि, सिंचाई, शहरी जल आपूर्ति, जल विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, एसएमई, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों और उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियों और अध्येतावृत्तियों की संख्या में वृद्धि जैसे विकास सहयोग पर चर्चा की गई।

■ ■

7

यूरोप और यूरोपीय संघ

अलबेनिया

17 नवंबर 2015 को अल्बानियाई राष्ट्रपति महामहिम श्री बुजर निशानी को तिराना में राजदूत ने अपने प्रत्यय पत्र प्रस्तुत किए।

राजनयिक और सरकारी / सेवा पासपोर्ट धारकों द्वारा वीजा मुक्त यात्रा पर एक समझौते पर 27 नवंबर 2015 को भारत और अल्बानिया के बीच हस्ताक्षर किए गए।

ऑस्ट्रिया

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने छठी ओपेक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने के लिए 3.6 जून 2015 को वियना का दौरा किया।

भारत–आस्ट्रिया संयुक्त आर्थिक आयोग का 14वां सत्र 31 अगस्त 2015 को वियना में आयोजित किया गया।

27–28 मई 2015 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भारत–ऑस्ट्रिया संयुक्त समिति की तीसरी बैठक का आयोजन वियना में किया गया।

श्री अमिताभ कांतए सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने 22–25 जून 2015 को यूनिडो, औद्योगिक विकास बोर्ड में भाग लेने के लिए वियना का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान श्री कांत ने 22 जून 2015 को ऑस्ट्रिया के चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ सहयोग में वियना और लिंज़ मिशन द्वारा आयोजित ''मेक इन इंडिया फोरम'' पर प्रस्तुतिकरण दिया।

दूतावास ने 26–27 नवंबर 2015 को साल्जबर्ग में नवीकरणीय ऊर्जा प्रदर्शनी रैनेक्सपो में भी भाग लिया।

बोस्निया और हरजेगोविना (बीआईएच)

साराजेवो में श्री मिरसाद जसरस्फिक, बीआईएच चैंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष और श्री कृष्ण कुमार, भारत–बोस्नियाई चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने 19 मई 2015 को एक सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए।

बुल्गारिया

23–24 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली में बुल्गारिया–भारत रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की 17वीं बैठक आयोजित की गई।

26 मई 2015 को भारतीय दूतावास की पहल पर प्रतिष्ठित बुल्गेरियाई कंपनियों की भागीदारी के साथ बुल्गारिया में, भारतीय–बुल्गेरियाई बिजनेस चैंबर का गठन किया गया। सितंबर 2015 में चैंबर के पंजीकरण के लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया।

नई दिल्ली में 2015.2017 की अवधि के लिए भारत और बुल्गारिया के बीच विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग के लिए कार्यक्रम पर 4 सितम्बर 2015 को हस्ताक्षर किए गए।

बुल्गारिया भारतीय फिल्मों की शूटिंग के लिए एक गंतव्य के रूप में भी उभरा।

23–24 नवम्बर 2015 के दौरान बल्गेरियाई पर्यटन मंत्री ने भारत का दौरा किया। उन्होंने डॉ महेश शर्मा, पर्यटन और संस्कृति, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) से मुलाकात की।

सोफिया में एएसईएम श्रम एवं रोजगार मंत्रियों के 5वें सम्मेलन के अवसर पर राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रम एवं रोजगार) श्री बी दत्तात्रेय ने बल्गेरिया के उप प्रधानमंत्री एवं श्रम और सामाजिक नीति मंत्री, श्री इवैलो कालफिन से 2 दिसंबर, 2015 को मुलाकात की।

क्रोएशिया

क्रोएशिया में भारतीय दूतावास में आयुर्वेद प्रकोष्ठ स्थापित किया गया था। उसकी गतिविधियों और कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विस्तार के लिए आयुर्वेद चिकित्सकों के साथ विचार–मंथन सत्र का आयोजन किया गया। दूतावास ने भारत सरकार की मुख्य योजनाओं जैसे 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' और 'स्मार्ट सिटी' में भागीदारी को प्रोत्साहित किया। इनका उचित रूप से अनुपालन किया जा रहा है।

साइप्रस

मिशन द्वारा 23 अप्रैल 2015 को साइप्रस के टूर ऑपरेटरों के लिए भारत पर्यटन कार्यालय, मिलान के साथ सहयोग से एक पर्यटन संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

मिशन ने 30 मार्च – 7 अप्रैल 2015 को नमस्ते इंडिया बैनर के तहत एआरटीओएस, एक साइप्रस सांस्कृतिक और रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग में एक सप्ताह तक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया।

चेक गणतंत्र

27–28 जनवरी 2015 को नई दिल्ली में आयोजित आर्थिक सहयोग पर संयुक्त आयोग के 10 वें सत्र में माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, सुश्री निर्मला सीतारमन और चेक के उद्योग तथा व्यापार मंत्री श्री जन मलाडेक ने संयुक्त रूप से अध्यक्षता की। सत्र के अंत में दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए।

फरवरी 2015 में एअरो इंडिया शो के संबंध में रक्षा मंत्री श्री मार्टिन स्ट्रोपनिकी ने नई दिल्ली और बेंगलुरू का दौरा किया।

मई 2015 के दौरान मास्को में विजय दिवस समारोह के अवसर पर चेक राष्ट्रपति मिलोस जेमन ने महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात की।

चैंबर ऑफ डिप्टी (निचले सदन) के उपाध्यक्ष, डॉ वोजटेक फिलिप के नेतृत्व में चेक संसद की आर्थिक मामलों की समिति के सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 19–24 मार्च 2015 को भारत का दौरा किया। अन्य बैठकों के अलावा प्रतिनिधिमंडल ने डॉ वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में वित्त संबंधी संसदीय समिति के साथ भी मुलाकात की।

चेक संसद की सीनेट के विदेश मामले, रक्षा और सुरक्षा पर समिति के सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 26–30 अप्रैल 2015 को भारत का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने संसदीय कार्य माननीय मंत्री श्री वेंकैया नायडु के साथ मुलाकात की।

भारी इंजीनियरिंग पर तीसरी जेडब्ल्यूजी का आयोजन 24 नवंबर 2015 को मुंबई में किया गया। जेडब्ल्यूजी के पश्चात उच्च प्रौद्योगिकी के निर्माण पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

मुंबई में 24 नवंबर 2015 को भारी उद्योग के क्षेत्र में सहयोग पर भारत के भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय और चेक गणराज्य के व्यापार और उद्योग मंत्रालय के बीच प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए।

13 जनवरी 2016 को दिल्ली में वीजा संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भारत–चेक वाणिज्य दूत संबंधी परामर्शों के दूसरे दौर की वार्ता आयोजित की गई ।

डेनमार्क

वर्ष 1995 में पुरूलिया में हथियार गिराए जाने संबंधी मामले में संलिप्त डेनमार्क निवासी नील्स हॉक उर्फ किम डेवी को भारत को प्रत्यर्पित न किए जाने के कारण भारत–डेनमार्क के संबंध प्रभावित रहे।

एस्टोनिया

एस्टोनिया में अनेक भारतीय आईटी कंपनियों द्वारा अपने विकास केंद्र स्थापित करने के साथ वर्ष के दौरान भारत एस्टोनिया आर्थिक संबंधों में बढ़ावा देखा गया। वर्ष के दौरान शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थानों के बीच आदान–प्रदान में भी वृद्धि हुई। न्यूयॉर्क में 30 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के मौके पर एस्टोनिया की विदेश मंत्री सुश्री मरीना कालजुर्नाद ने विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की।

फिनलैंड

अक्टूबर 2014 में माननीय राष्ट्रपति की सफल यात्रा के बाद सभी क्षेत्रों में फिनलैंड के साथ भारत के संबंध लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं। कई भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों ने फिनलैंड में अपने सामान्य कार्यों के अलावा अपने अनुसंधान और विकास केंद्रों की स्थापना द्वारा अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। भारत–फिनिश जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा निदान संगोष्ठी 27– 28 अक्टूबर 2015 को टूर्कू में आयोजित की गई।

फिनलैंड के प्रधानमंत्री श्री जूहा सिपीला ने भारत की यात्रा की और फरवरी 2016 में मुम्बई में 'मेक इन इंडिया वीक' में एक उच्च स्तरीय व्यापारी प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की।

ग्रीस

एएसईएम के मौके पर नवंबर 2015 में राज्य मंत्री जनरल (डॉ) वी के सिंह (सेवानिवृत्त) और ग्रीस के विदेश मंत्री के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया। ग्रीक के रक्षा मंत्री ने 17–18 दिसम्बर 2015 को भारत का दौरा किया।

उनतीस भारतीय कंपनियों (एमएसएमई) ने आईटीपीओ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तत्वावधान में 05–13 सितम्बर, 2015 को 80 वें थेसालोनिकी अंतरराष्ट्रीय मेले में भाग लिया। भारत मेले में भाग लेने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश था जिसमें

विभिन्न बी2बी और बी2सी बैठकें की गई।

दूतावास द्वारा 4–5 जुलाई 2015 को तीसरे बॉलीवुड नृत्य और बहुसांस्कृतिक नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके अलावा वर्ष के दौरान थेसालोनिकी और एथेंस में भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग; 12–18 जनवरी 2015 को भारतीय सिनेमा सप्ताह भारतीय कलाकार श्रीमती संगीता गुप्ता के चित्रों की एकल प्रदर्शनी, 25–29 मार्च को भारत खाद्य महोत्सव सहित ग्रीस में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

भारत से चार स्कूलों की क्रिकेट टीमों ने हेलेनीकी क्रिकेट फेडरेशन द्वारा 19–25 अप्रैल, 2015 को कोर्फू में आयोजित पांचवें इंटरनेशनल स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लिया। भारत की ओर से 25 अक्तूबर – 5 नवम्बर 2015 को हाल्कीडिकी, ग्रीस में आयोजित विश्व युवा और कैडेट शतरंज चैम्पियनशिप में पचास जूनियर शतरंज खिलाड़ियों ने भाग लिया। भारतीय दल 5 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ इस सूची में सबसे शीर्ष पर है। समारोह में 91 देशों ने भाग लिया।

ग्रीक रक्षा मंत्री श्री पेनोस काम्मेनोस ने 17–19 दिसंबर 2015 को भारत का दौरा किया। उनके साथ एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल आया जिसने सार्वजनिक और नीजि क्षेत्रों के भारतीय स्टेकहोल्डरों के साथ बात–चीत की और भारत और ग्रीस के बीच संयुक्त रक्षा उत्पादन के लिए बी–टू–बी बैठकों का आयोजन किया। इस यात्रा के दौरान, यूनानी रक्षा मंत्री ने श्री मनोहर पार्रिकर, रक्षा मंत्री और जनरल (डॉ) वी के सिंह (सेवानिवृत्त), विदेश राज्य मंत्री से मुलाकात की।

हंगरी

प्रधानमंत्री विक्टर ऑरबैन ने 10 अप्रैल 2015 को झोंघोशालास, हंगरी में अपोलो टायर कारखाने की आधारशिला रखी। अपोलो ने हंगरी में 475 मिलियन यूरो के निवेश की घोषणा की है।

रक्षा उत्पादन सचिव श्री जी मोहन कुमार और डॉ एटिला पुस्कास, राज्य उप सचिव, रक्षा मंत्रालय ने 7वीं संयुक्त रक्षा समिति की बैठक की सह अध्यक्षता की।

विश्व थोक बाजार विश्व संघ द्वारा 26–29 मई 2015 को आयोजित सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ श्री ओम प्रकाश धनखड़, हरियाणा के कृषि मंत्री ने बुडापेस्ट का दौरा किया।

पीटर शिजजेट्रो, विदेश और व्यापार मंत्री ने 20 मई 2015 को मुंबई का दौरा किया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की तथा भारत में प्रमुख सीईओएस के साथ भी मुलाकात की।

हंगरी पोस्ट ने 'सद्भाव और शांति के लिए योग' शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी किया।

एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ हंगरी के विदेश और व्यापार राज्य मंत्री डॉ लैस्ज़लो झाबो ने दूसरे इंडिया सेंट्रल यूरोप बिजनेस फोरम के लिए भारत का दौरा किया जो 05–06 अक्तूबर 2015 को बेंगलुरू में आयोजित किया गया। डॉ झाबो ने विदेश राज्य मंत्री और सचिव (पश्चिम) के साथ बैठकें कीं और महाराष्ट्र के राज्यपाल ने आमंत्रित किया। यात्रा के दौरान हंगरी और कर्नाटक राज्य के बीच आर्थिक सहयोग के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

लक्जमबर्ग में एएसईएम के विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर 6 नवम्बर 2015 को हंगरी के विदेश मामलों और व्यापार मंत्री, श्री पीटर शिजजेट्रो के साथ विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ) वी के सिंह (सेवानिवृत्त) ने एक द्विपक्षीय बैठक की थी।

लातविया

एएसईएम के विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर 5 नवंबर, 2015 को लक्जमबर्ग में विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ) वी के सिंह और लातविया के विदेश मंत्री श्री एडगर्स रिंकीविक्स ने मुलाकात की।

आईसीसीआर विशिष्ट आगंतुक कार्यक्रम के तहत 03.12 अप्रैल 2015 को श्री अतिस लेजिन्स, संसद सदस्य और भारत–लातविया मैत्री समूह के सह–अध्यक्ष ने भारत का दौरा किया।

लातवियाई विदेश मामले मंत्रालय ने 28 मई 2015 को आयुर्वेद सहित अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में लातविया और भारत के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए समर्पित 'लातविया–भारत सहयोग को बढ़ावा देने' के अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक मंच का उद्घाटन किया गया।

भारत पर्यटन कार्यालय, फ्रैंकफर्ट 6 जुलाई 2015 को, और भारतीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा एक पर्यटन रोड शो का रीगा में आयोजन किया गया।

रीगा के बॉटनिकल गार्डन में 1000 से अधिक प्रतिभागियों के साथ प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।

लिकटेंस्टीन

संस्कृति केंद्र, गैसोमीटर, लिकटेंस्टीन में 21 जून 2015 को लगभग 30 लोगों की भागीदारी के साथ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।

लिथुआनिया

महात्मा गांधी तथा उनके लिथुआनियाई मित्र हरमन केलेनबेख की आदम कद मूर्ति के अनावरण के लिए कृषि राज्य मंत्री श्री मोहन भाई कुदारिया ने लिथुआनिया की यात्रा की। कालेनबाख के जन्मस्थान, रूसने में 2 अक्टूबर 2015 को लिथुआनिया के प्रधानमंत्री और राज्यमंत्री (कृषि) द्वारा संयुक्त रूप से मूर्ति का अनावरण किया गया था। राज्यमंत्री ने लिथुआनियाई कृषि उप मंत्री श्री विलियस मार्ट्युसेविकस के साथ विलनियस में द्विपक्षीय वार्ता भी आयोजित की जहां भोजन और दुग्ध प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण क्षमता का दोहन करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को तीव्र करने के लिए सहमत हुए।

लिथुआनिया के प्रधानमंत्री श्री अल्ग्रेडस बटेकीवीशस ने 12–16 फरवरी, 2016 को उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल के साथ श्मेक इन इंडिया वीकश् में भाग लेने के लिए मुम्बई का दौरा किया। उन्होंने 13 फरवरी, 2016 को प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर बात की।

मैसेडोनिया

पहले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में 100 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया।

माल्टा

श्री गॉडफ्रे फरुगिया, माननीय सांसद ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) संसद और मीडिया कानून सम्मेलन के दौरान 07–11 अप्रैल 2015 के दौरान विशाखापट्टनमए आंध्र प्रदेश का दौरा किया

प्रो. के. वी. थॉमस, अध्यक्ष, लोक लेखा समिति ने माल्टा में 5 वीं वेस्टमिनिस्टर कार्यशालाः प्रभावी, स्वतंत्र और पारदर्शी लोक लेखा समितियों में वित्तीय अनियमिता पर 01–05 जून, 2015 चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

आईएनएस तरंगिनी ने 20.22 जून 2015 और 06.08 अक्तूबर 2015 को दोबारा अन्य देशों के साथ माल्टा का दौरा किया।

25–29 नवम्बर, 2015 को माल्टा में आयोजित सीएचओजीएम शिखर सम्मेलन में माननीय विदेश मंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ) वी.के. सिंह ने 25–26 नवम्बर, 2015 को विदेश मंत्रियों के खंड में और 26–29 नवम्बर, 2015 के बीच विदेश मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के रूप में प्रतिनिधित्व किया।

मोल्दोवा

मोल्दोवा के राष्ट्रपति निकोलाय तिमोफ्ती चिशिनाउ, के समक्ष 9 दिसंबर, 2015 को राजदूत (श्रीमती) रीवा गांगुली दास ने प्रत्यय पत्र प्रस्तुत किया। अपनी यात्रा के दौरान राजदूत ने उप प्रधानमंत्री और अर्थव्यवस्था मंत्री श्री स्टीफन ब्राइड, उप विदेश मंत्री श्री ट्यूडर उलियानोवसची अंतरराष्ट्रीय संबंध और कृषि और खाद्य उद्योग मंत्रालय के उप मंत्री, श्री व्लादिमीर लोगहिन से भी मुलाकात की तथा मोल्दोवा गणराज्य के वाणिज्य उद्योग चैंबर के अध्यक्ष, श्री वेलेरियू लाजर से भी मुलाकात की।

मोल्दोवा में 8 दिसंबर 2015 को दूतावास द्वारा एक व्यापार नेटवर्क समारोह आयोजित किया गया था। भारतीय समुदाय के सदस्यों, भारतीय और मोल्दोवन व्यवसायियों, टूर ऑपरेटरों आदि ने समारोह में भाग लिया।

मोंटेनेग्रो

17 जून 2015 को सेटिंजे में राजदूत ने प्रत्यय पत्र की प्रस्तुति के बाद राष्ट्रपति के साथ एक संक्षिप्त बातचीत की।

नॉर्वे

नई दिल्ली में 16–18 अप्रैल 2015 को नॉर्वे एशिया व्यापार शिखर बैठक आयोजित की गई थी जिसमें एशिया और नॉर्वे से व्यापार, उद्योग और सरकारी क्षेत्रों से 185 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

ओस्लो में 19 मई 2015 को बहुपक्षीय मुद्दों पर भारत–नार्वे के परामर्श का दूसरा दौर आयोजित किया गया।

नेपाल भूकंप के बाद जून 2015 को काठमांडू में अंतरराष्ट्रीय दानदाता सम्मेलन के मौके पर, विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने नार्वे के विदेश मंत्री श्री बोरर्ज ब्रेंडे के साथ मुलाकात की।

18 अगस्त 2015 को मत्स्य पालन और जलीय कृषि के सहयोग पर भारत–नार्वे जेडब्ल्यूजी की दूसरी बैठक त्रोनधीम में आयोजित की गई।

पर्यावरण पर संयुक्त कार्य समूह की 8वीं बैठक 17 सितंबर, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

नई दिल्ली में नॉर्वे दूतावास द्वारा आयोजित युवा भारतीय नेताओं के लिए नॉर्वे के एक अध्ययन दौरे पर 30 सितंबर – 6 अक्तूबर 2015 तक डॉ हिना गावित, सांसद और पूर्व मंत्री श्री सचिन पायलट ने नॉर्वे का दौरा किया। यह 12 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल (श्री गीर पोलेस्टेड, व्यापार और उद्योग पर स्थायी समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में) के प्रत्युत्तर में था, जिन्होंने 19–21 फरवरी 2015 को भारत का दौरा किया।

चौथे भारत–नॉर्वे जेसीएम के 2010 में आयोजन के बाद, नई दिल्ली में 2 नवंबर, 2015 को विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज

और नार्वे के विदेश मंत्री श्री बोर्ज ब्रेंडे की सह–अध्यक्षता में 5वीं जेसीएमआयोजित की गई थी। आठ संयुक्त कार्य समूह (समुद्री संसाधन, समुद्री मामलों, हाइड्रोकार्बन, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और स्थानीय प्रशासन) के तहत कार्य की प्रगति सहित अतिरिक्त क्षेत्रों (रक्षा, ध्रुवीय अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, पनबिजली और पानी) की समीक्षा की भी गई। जबकि नॉर्वे के विदेश मंत्री, श्री बोर्गे ब्रेंडे ने आश्वासन दिया कि यूएनएससी के लिए स्थायी सदस्यता हेतु भारत और एमटीसीआर और एनएसजी के सदस्य बनने के लिए भारत की इच्छा का समर्थन करता है, दोनों देशों के विदेश मंत्रिगण दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश (डीटीआई) पर एक वार्षिक संवाद स्थापित करने के लिए सहमत हुए।

पोलैंड

वारसॉ में 15 जून 2015 को भारत–पोलैंड आर्थिक सहयोग संयुक्त आयोग (जेसीईसी) के चौथे सत्र का आयोजन किया गया। इससे पूर्व 12–13 जून 2015 को कोयलाए आईटी और खाद्य प्रसंस्करण पर तीन नए बनाए गए द्विपक्षीय संयुक्त कार्य समूहों से मुलाकात की और उनके संबंधित डोमेन में सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की।

पहला भारत पोलैंड आईटी मंच (8–9 जुलाई 2015) क्राको में आयोजित किया गया था।

आइकिया (भारत) ने 8 सितंबर 2015 को वारसॉ में एक अभूतपूर्व आउटरीच संगोष्ठी का आयोजन किया जिसमें पॉलिस और अन्य यूरोपीय आपूर्तिकर्ताओं को न केवल नियामक शर्तों को पूरा करने के लिएए बल्कि विशाल भारतीय बाजार में खरीदने की क्षमता और उत्पादों की लाभप्रदता में सुधार लाने के लिए भी भारत में और अधिक निर्माण के लिए प्रेरित किया। आइकिया भारत को लंबी अवधि के कई अवसरों के साथ अपने 'अंतिम बड़ा बाजार' के रूप में और 50 स्टोर जो भारत आ सकते हैं के स्थानीय स्तर पर 50 प्रतिशत उत्पादों की संभाव्यता के रूप में देखता है।

बैंगलोर में 5–6 अक्तूबर 2015 को भारत–मध्य यूरोप व्यापार शिखर सम्मेलन में पोलिश उप विदेश मंत्री लेसजेक सोकजेविका ने भाग लेने के लिए एक उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जिसमें पोलैंड एक भागीदार देश था।

अर्थव्यवस्था मंत्रालय के राज्य सचिव जेर्जी पिट्रेविज ने लुब्लिन के उप तार्शल वोईवोडेशिप क्रिजीस्जटोफ ग्रेबार्किजक के साथ प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन 2015 में भाग लिया। पोलैंड शिखर सम्मेलन में एक भागीदार देश था।

पौलैंड के उप प्रधान मंत्री और विकास मंत्री की मैटीयूज मोराविन्शकी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने 13–18 फरवरी, 2016 को श्मेक इन इंडियाश में भाग लेने के लिए मुंबई की यात्रा की।

दूसरे आईसीईबीएफ के दौरान बैंगलोर में 5 अक्टूबर 2015 को राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की आवश्यकता से छूट पर भारत गणराज्य की सरकार और पोलैंड गणराज्य की सरकार के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

रोमानिया

भारत पर्यटन, फ्रैंकफर्ट और दूतावास की मदद से टैगोर सांस्कृतिक केंद्र, बुखारेस्ट द्वारा 05–09 जून 2015 को 'नमस्ते भारत' नामक सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया। यह अत्यंत लोकप्रिय त्योहार बुखारेस्ट में बड़ी संख्या में लोगों के बीच भारत प्रदर्शन में मदद करता है।

सितंबर 2015 में हिंदी पीठ की स्थापना के लिए आईसीसीआर और बुखारेस्ट विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

सर्बिया

यूनेस्को के आम सम्मेलन में 9 नवम्बर 2015 को यूनेस्को की सदस्यता के लिए भारत के अपना मत कोसोवो के विरुद्ध सर्बिया को दिया जाने को सर्बिया ने महत्व दिया।

मास्को में 8 मई 2015 को राष्ट्रपति और सर्बिया के राष्ट्रपति तोमिस्लाव निकोलिक के बीच द्विपक्षीय बैठक में उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद को आगे बढ़ाया गया।

बेलग्रेड विश्वविद्यालय ने विशेष मांग के आधार पर श्भारत के सांस्कृतिक इतिहासश पर एक नया पाठ्यक्रम शुरू दिया।

भारतीय रक्षा उद्योग संघ ने श्मेक इन इंडियाश के तहत प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए सर्बियाई रक्षा उद्योग के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। सर्बिया ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना पाठ्यक्रम के एक स्लॉट का उपयोग किया और परस्पर जवाब में भारत को सीबीआरएन में पाठ्यक्रम के एक अवधि के लिए निमंत्रण दिया।

50 से अधिक सर्बियाई कंपनियों ने भारतीय कंपनियों और संस्थाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु भारत का दौरा किया। इसके अलावा, 26–30 अक्टूबर 2015 को नई दिल्ली में आयोजित सर्बिया की राष्ट्रीय पेट्रोलियम समिति की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल ने विश्व पेट्रोलियम परिषद (डब्ल्यूपीसी) की बैठकों में भाग लिया। विंटेज क्वादरात मिसाइलों के नवीनीकरण कार्य के सिलसिले में सर्बियाई रक्षा पीएसयू युगोइमपोर्ट से एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के निमंत्रण पर भारत (नवंबर 2015) का दौरा किया। सेंट्रोनिस एडी से बार्क द्वारा 3 डी चुंबकीय क्षेत्र मानचित्रण प्रणाली की स्थापना और

प्रचालन के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बार्क) (नवंबर 2015) द्वारा सर्बियाई अनुसंधान एवं विकास कंपनी सेंट्रोनिस एडी के दो सदस्यीय दल को आमंत्रित किया गया। कुछ प्रयोगों के निष्पादन और वैज्ञानिक व्याख्यान हेतु मैटलर्जिकल और सामग्री इंजीनियरिंग विभाग के सहयोग के लिए आईआईटी–मद्रास (जनवरी 2016) द्वारा परमाणु विज्ञान संस्थान, विनकाए बेलग्रेड से प्रो. डॉ. ब्रैंको मैटोविक और डॉ बिलजाना बैबिक को आमंत्रित किया गया था।

बेलग्रेड अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेले में सफल भागीदारी और भारत पर्यटन के प्रोत्साहन से भारत की यात्रा पर आने वाले सर्बियाई पर्यटकों की संख्या में वर्ष दर वर्ष 17% की वृद्धि हुई है।

फिल्मों के क्षेत्र में लगातार सक्रिय सहयोग के कारण बहुत–सी भारतीय फिल्मों की शूटिंग सर्बिया में की जा रही है।

स्लोवाक गणराज्य

भारत स्लोवाकिया संयुक्त आर्थिक समिति का आठवां सत्र 25 फरवरी 2015 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत की पहली आधिकारिक स्तर पर बी4 (चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया) के साथ बातचीत 27 फरवरी 2015 को ब्रेटीस्लावा में आयोजित की गई थी। स्लोवाकिया के अर्थव्यवस्था मंत्री श्री वेजिल हुडक ने 7–10 अक्टूबर 2015 को भारत का दौरा किया और श्री सुरेश प्रभु, रेल मंत्री से मुलाकात की। भारतीय रेल और स्लोवाक रेलवे के बीच एक समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में 12 अगस्त, 2015 को हस्ताक्षर किए गए।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और स्लोवाक मानक कार्यालयए मैट्रोलोजी और परीक्षण के बीच समझौता ज्ञापन पर 29 जुलाईए 2015 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे।

स्लोवेनिया

माननीय लोकसभा अध्यक्ष के निमंत्रण पर स्लोवेनिया की राष्ट्रीय विधानसभा के अध्यक्ष, डॉ मिलान ब्रेगलेज ने 24–27 नवम्बर 2015 को एक 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत का वापसी दौरा किया।

श्री के डी त्रिपाठी, सचिव, लोक उद्यम विभाग ने आईसीपीई परिषद की बैठक की अध्यक्षता हेतु तथा इसकी महासभा की बैठक में भाग लेने के लिए 7–8 अप्रैल 2015 को लजूबलजाना का दौरा किया। एएफएचक्यू के 24 अधिकारियों ने 31 अगस्त 2015 को शुरू किए गए अनिवार्य मिड–कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में 31 अगस्त से 4 सितंबर 2015 और उसके बाद 9 सितंबर – 11 सितंबर 2015 के बीच आईसीपीई द्वारा आयोजित दूसरे व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद के में 27 अधिकारियों के एक समूह ने 12–16 अक्तूबर 2015 को आईसीपीई पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 'बजट, लेखा और वित्तीय प्रबंधन' में भाग लिया।

लजुबलजाना में 07–09 जुलाई 2015 को आयोजित 9वें डीआईएएफईएसटी में भारतीय बूथ में को भारत में पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

भारत ने सेल्जे में आयोजित 48वें अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय और व्यापार मेले (एमओएस) में 08–13 सितम्बर 2015 को भाग लिया जो स्लोवेनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार मेला है।

भारत गणराज्य की सरकार और स्लोवेनिया गणराज्य की सरकार के बीच 24 अप्रैल 2015 को राजनयिक मिशनों और कौंसुलर पोस्ट के सदस्य के आश्रितों के लाभकारी व्यवसाय पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

स्लोवेनियाई फर्म पिपिस्ट्रल ने भारतीय नौसेनाए वायु सेना और एनसीसी के लिए 194 अल्ट्रा लाइट ट्रेनर विमान की आपूर्ति करने के लिए अक्टूबर 2015 के लिए 17 मिलियन यूरो के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

स्वीडन

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 31 मई से 2 जून 2015 तक स्वीडन की पहली ऐतिहासिक राजकीय यात्रा की। राष्ट्रपति के प्रतिनिधिमंडल में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री हंसराज गंगाराम अहीर सहित श्री गुलाम नबी आजाद, राज्यसभा में विपक्ष के नेता; और श्री अश्विनी कुमार लोकसभा सदस्य शामिल थे। उच्च स्तरीय शैक्षिक और व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल भी राष्ट्रपति के साथ था। यात्रा के दौरान सतत विकास तथा लघु और मध्यम उद्यमोंए और शैक्षिक संस्थाओं के बीच 15 सहमति पत्रों सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में छः अंतरराष्ट्रीय समझौतों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडिश प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में मुलाकात की। विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ) वी के सिंह ने एएसईएम के विदेश मंत्रियों की बैठक के मौके पर नवंबर में लक्जमबर्ग में स्वीडन के विदेश मंत्री सुश्री मार्गोट वेलस्ट्रोम से मुलाकात की।

स्वीडिश आधारभूत ढांचा मंत्री अन्ना जोहानसन ने 31 मार्च से 3 अप्रैल 2015 तक भारत का दौरा किया। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य सचिव श्री हंस दहलर्जन ने 29 अप्रैल 2015 को भारत का दौरा किया। रक्षा मंत्री श्री पीटर हल्टक्विस्ट राज्य सचिव ने 9–12 जून 2015 के बीच भारत का दौरा किया। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य सचिव श्री हंस दहलर्जन ने 6–7 अक्टूबर 2015 के बीच

एक बार फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ पुन आरंभ किए गए सामरिक वार्ता के पहले दौर के लिए भारत का दौरा किया। उसी समय सुश्री एन लिंडे, न्याय मंत्रालय में गृह राज्य सचिव ने भारत का दौरा किया। आवास, शहरी विकास और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री मेहमत कापलान ने 13–18 अक्तूबर 2015 को भारत का दौरा किया।

भारत की ओर से, महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री मेनका गांधी ने अपने समकक्ष से मुलाकात और 'नमस्ते स्टॉकहोम' के उद्घाटन के लिए 23–26 मई 2015 के बीच स्वीडन का दौरा कियाय जो दूतावास द्वारा स्वीडन में आयोजित अपनी तरह का पहला भारतीय संस्कृति, भोजन और हस्तशिल्प का त्योहार है। श्री जेनिथ एम संगमा, मेघालय सरकार के खेल मंत्री ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। तीन भारतीय राज्यों से उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों ने वर्ष के दौरान स्वीडन का दौरा किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 'मेक इन महाराष्ट्र' को बढ़ावा देने के लिए 15–16 अप्रैल 2015 को स्वीडन का दौरा किया। तेलंगाना से डॉ राजीव शर्मा मुख्य सचिव और श्री अरविंद कुमार, उद्योग सचिव ने 14–17 सितंबर 2015 को स्वीडन का दौरा किया। श्री सत्येंद्र कुमार जैन, स्वास्थ्य, आवास, बिजली, लोक निर्माण विभाग और उद्योग मंत्री के नेतृत्व में दिल्ली सरकार के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 24–30 अक्टूबर 2015 को स्वीडन का एक अध्ययन दौरा किया गया जिसमें श्री गोपाल राय, परिवहन मंत्री भी शामिल थे।

सतत शहरी विकास पर भारत–स्वीडन संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक 14 अक्टूबर 2015 में नई दिल्ली में हुई। नई दिल्ली में 29–30 सितम्बर 2015 को रक्षा सहयोग में भारत–स्वीडन संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक आयोजित की गई थी।

एक 24 सदस्यीय नैसकॉम प्रतिनिधिमंडल ने नॉर्डिक क्षेत्र के दौरे के भाग के रूप में 29–30 मई 2015 के बीच स्टॉकहोम का दौरा किया। 28–30 सितम्बर 2015 को भारत से एक 21 सदस्यीय लुगदी और कागज प्रतिनिधिमंडल ने स्वीडन का दौरा किया।

भारतीय दूतावास द्वारा समन्वित असीमित भारत मंच के तहत दूसरे वर्ष में स्टॉकहोम में अनेक व्यापार सम्मेलनों का आयोजन किया गया। इन सम्मेलनों में इस वर्ष का व्यापक विषय था 'मेक इन इंडिया''ग्रो विद इंडिया" और राष्ट्रपति के दौरे के साथ 31 मई – 3 जून 2015 के बीच आयोजित किया गया।

स्वीडन के कई हिस्सों में प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। शहर के मेयर द्वारा गोटेबोर्ग में आयोजित मुख्य समारोह का उद्घाटन किया गया और इसमें 400 से अधिक लोगों ने उत्साह से हिस्सा लिया।

स्वीडन के प्रधानमंत्री महामहिम स्टेफिन लोफोविन की अध्यक्षता में एक सरकारी–सह–व्यापारी प्रतिनिाधिमंडल ने 13–14 फरवरी, 2016 को मुंबई में प्रथम मेक इन इंडिया वीकश में भाग लिया। यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री लोफोविन ने द्विपक्षीय मुद्दों पर प्रधान मंत्री मोदी से चर्चा की। इस यात्रा ने 31 मई–2 जून, 2015 को राष्ट्रपति की प्रथम महत्वपूर्ण ऐतिहासिक यात्रा से भारत–स्वीडन संबंधों में आई गति को बनाए रखा। इससे भारत और स्वीडन के बीच इससे विस्तृत आर्थिक सहभागिता को गति मिली, विशेषतः प्रधान मंत्री मोदी की सरकार द्वारा किए गए फ्लैगशीप कार्यक्रम जिसमें मेक इन इंडियाए स्मार्ट सिटी, डिजीटल इंडिया, स्किल इंडिया और स्वच्छ भारत शामिल है।

स्विट्जरलैंड

दोनों पक्षों से उच्च स्तरीय यात्राओं ने साझेदारी को और अधिक मजबूत किया। भारत 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के लिए स्विस क्षमताओं का लाभ उठा सकता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड वैश्विक नवाचार और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की रैंकिंग में सबसे ऊपर है। दोनों देशों के बीच आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण क्षेत्र और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने की क्षमताओं का पता लगाया जा रहा है।

इंडो–स्विस संयुक्त आर्थिक समिति का 14 वां सत्र 14 मई, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। लगभग 20 व्यापार प्रतिनिधियों, संघीय और प्रांतीय अधिकारियों और संसद सदस्यों के एक आर्थिक मिशन की अध्यक्षता करते हुए 15–17 मई 2015 को श्री जौहान श्नाइडर– अम्मान्न, संघीय पार्षद, आर्थिक मामलों, शिक्षा और अनुसंधान, स्विट्जरलैंड ने भारत का दौरा किया।

होरासिस, वैश्विक दृष्टि समुदाय ने 5–6 जुलाई 2015 को इंटरलेकन, स्विजरलैंड में अपनी 6वीं होरासिस भारत बैठक बुलाई।

विदेश सचिव ने 10–13 सितंबर 2015 को विदेश मामलों के स्विस राज्य सचिव के साथ विचार विमर्श के लिए स्विट्जरलैंड का दौरा किया। उन्होंने विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर आर्थिक मामलों के राज्य सचिव और अन्य स्विस प्रतिभागियों के साथ विचार विमर्श भी किया।

बर्न में 18 सितंबर 2015 को एस एंड टी पर भारत–स्विस संयुक्त समिति की तीसरी बैठक में भाग लेने के लिए 16–19 सितंबर 2015 को सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने स्विट्जरलैंड का दौरा किया

माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन के नेतृत्व में, एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल (संसद सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा नौ सांसदों सहित) ने जिनेवा में 17–21 अक्टूबर 2015 को आयोजित अंतर संसदीय संघ

(आईपीयू) सभा के 133 वें सत्र में हिस्सा लिया।

ईपीएफएल इनोवेशन पार्क, लॉज़ेन में 19–20 नवंबर 2015 के बीच प्रथम स्विस भारत अक्षय ऊर्जा (एस आई आर ई एन) संगोष्ठी को अयोजन किया गया। संगोष्ठी में श्री पीयूष गोयल, बिजली, कोयला और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया गया था।

माननीय वित्त मंत्री, श्री अरुण जेटली के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने 20–23 जनवरी, 2016 तक दावोस, स्विट्ज़रलैंड में आयोजित विश्व आर्थिक मंच में भाग लिया। इस बैठक के अवसर पर माननीय वित्त मंत्री ने कई मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की थीं जिनमें स्विस फेडरल काउंसलर फॉर फाइनेंस, श्री उएली मॉरर शामिल थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्वमें एक उच्चाधिकारी प्राप्त शिष्टमंडल ने भी जूरिक के निवेशकों के साथ कई बैठकें की जिनमें लगभग 12 स्विस कंपनियों ने प्रस्तुति दी जिसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश में स्विस कंपनियों के लिए अवसर तलाशना था। आर बी आई के गवर्नर श्री रघुराम राजन ने भी विश्व आर्थिक मंच में हिस्सा लिया। विगत की ही तरहएइस बैठकमें भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र ने बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया जिसका नेतृत्व भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने किया।

तुर्की

उप प्रधानमंत्री अली बाबाकान ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित बी 20 क्षेत्रीय परामर्श फोरम में भाग लेने के लिए 03–07 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली का दौरा किया।

कानाक्काला समुद्र और भूमि संग्राम की शताब्दी वर्षगांठ पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए विदेश राज्य मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वी के सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल 24–25 अप्रैल 2015 को तुर्की गया।

भारत–तुर्की के विदेश कार्यालय परामर्श का 9वां दौर 17 अप्रैल 2015 को अंकारा में आयोजित किया गया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री नवतेज सिंह सरना, सचिव (पश्चिम) ने किया था और तुर्की प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री फेरिदुन

प्रधानमंत्री तुर्की में तुर्की के राष्ट्रपति, रिसेप तईप एरडोगन के साथ जी –20 शिखर सम्मेलन 2015 के मौके पर बैठक (16 नवंबर 2015) करते हुए।

सिनिरलिओग्लु, तुर्की के विदेश कार्य मंत्रालय अवर सचिव द्वारा किया था।

इस्तांबुल में 07–08 मई 2015 को जी–20 कृषि मंत्रियों की बैठक के अवसर पर, कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने श्री मेहमत मेहदी एकर, तुर्की के खाद्य, कृषि और पशुधन मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी।

अंकारा में जी –20 के वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने 03–05 सितम्बर 2015 को तुर्की का दौरा किया। अंकारा में रहते हुए, वित्त मंत्री ने तुर्की उद्यमियों के साथ एक सीआईआई व्यापार गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।

वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 05–06 अक्टूबर 2015 को इस्तांबुल में जी–20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। जी 20 बैठक के दौरान अतिरिक्त समय में सीआईएम ने श्री निहात जेयबेकी, तुर्की के अर्थव्यवस्था मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14–16 नवंबर 2015 को अंताल्या में जी –20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान 16 नवम्बर 2015 को राष्ट्रपति रिसेप तईप एरडोगन के साथ बैठक की थी। नेताओं ने द्विपक्षीय एजेंडे पर और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार–विमर्श किया।

जी–20 की बैठकों में भाग लेने के लिए 2015 के दौरान भारत से कई प्रतिनिधिमंडलों ने तुर्की का दौरा किया। इन में, 16–17 जून 2015 को बोडरम में जी –20 शेरपा की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रेल मंत्रीए श्री सुरेश प्रभु ने भाग लिया; 03–04 सितम्बर 2015 को अंकारा में जी –20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री बंडारू दत्तात्रेय राज्य मंत्री ने भाग लिया; और 13–14 अक्टूबर 2015 को अंकारा में जी –20 शेरपा की बैठक में उपाध्यक्ष, नीति आयोग, डॉ अरविंद पनगढ़िया ने भाग लिया।

द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तुर्की के वस्तु विनियम (टीओबीबी) और मंडलों के संघ के साथ 6 अप्रैल 2015 को भारतीय उद्योग परिसंघ ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत–तुर्की कार्य समिति और निवेश मंच की स्थापना के लिए फिक्की सहित टीओबीबी ने भी एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। तुर्की–इंडिया व्यवसाय मंच में भाग लेने के लिए 6–9 अप्रैल 2015 को श्री अदनान यल्दीरीम तुर्की की अर्थव्यवस्था के उप मंत्री के नेतृत्व में तुर्की निर्यातक परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई का दौरा किया। भारतीय स्टेट बैंक और तुर्की के अकबैंक एक सहयोग समझौते के तहत 6 अगस्त 2015 को द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को समर्थन देने के लिए करार किया।

19 वीं सदी में ओटमैन फ्रिगेट एर्टुग्रुल की जापान की यात्रा का मार्ग पता लगाते हुए, तुर्की नौसेना जहाज टीसीजी गेडिज़ क्रमशः 20–23 अप्रैल 2015 और 02–04 जुलाई 2015 को मुंबई और चेन्नई के बंदरगाहों पर पहुंचा। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने सामरिक पड़ोस अध्ययन दौरे के भाग के रूप 22–26 अगस्त 2015 को तुर्की का दौरा किया। आईएनएस त्रिकंद ने 4–6 अक्टूबर 2015 को इस्तांबुल में एक बंदरगाह का दौरा किया।

इस्तांबुल में 23 अक्तूबर, 2015 को पांचवें भारत–तुर्की फोरम (ट्रैक द्वितीय) आयोजित किया गया था।

अंतरराष्ट्रीय विद्वान सम्मेलन 2015 में भाग लेने के लिए प्रो कोरहम काया, विभागाध्यक्ष, अंकारा विश्वविद्यालय ने 21–25 नवंबर 2015 तक नई दिल्ली का दौरा किया।

भारत ने 20 जुलाई 2015 को सुरुक में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। अंकारा में 10 अक्टूबर 2015 को दोहरे बम विस्फोटों पर दुख और उदासी व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति एरडोगन को संबोधित करते हुए एक पत्र भेजा।

यूरोपीय संघ

भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंध लोकतंत्र, कानून का शासन, मौलिक स्वतंत्रता सम्मान और बहुसंस्कृतिवाद के साझा मूल्यों पर आधारित है। यूरोपीय संघ भारत का एक महत्वपूर्ण सामरिक भागीदार है; दोनों पक्षों ने 2014 में अपनी सामरिक भागीदारी की 10वीं वर्षगांठ मनाई है। हालांकि शुरूआत से संबंध का केंद्र आर्थिक था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में और विशेष रूप से, लिस्बन संधि और यूरोपीय बाह्य कार्यसेवा के सृजन के बाद से सामरिक साझेदारी के राजनीतिक और सुरक्षा आयामों के लागू होने के बाद से इन्हें काफी बढ़ावा मिला है।

अंताल्या में 15 नवंबर, 2015 को जी –20 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यूरोपीय परिषद के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड टस्क और यूरोपीय आयोग की राष्ट्रपति श्री ज्यां क्लाड जंकर से मुलाकात की। उन्होंने भारत–यूरोपीय संघ संबंध और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की।

यूरोपीय संसद के अध्यक्षए श्री मार्टिन शुल्ज के आमंत्रण पर लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने 22–26 जून 2015 को ब्रसेल्स में एक 13 सदस्यीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उनका ब्रसेल्स में यूरोपीय संसद के समग्र में आधिकारिक तौर पर स्वागत किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने यूरोपीय संसद के सदस्यों के साथ विकासात्मक प्राथमिकताओं और द्विपक्षीय हित के मुद्दों के एक व्यापक दृष्टिकोण पर घनिष्ठ और व्यापक विचार विमर्श किया। इस यात्रा के दौरान अध्यक्ष

ने भारत (डी–आईएन) के साथ संबंध के लिए यूरोपीय संसद के प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की। इससे पहले, भारत के राजनीतिक नेतृत्व से मिलने के लिए मार्च 2015 में भारत के साथ गठित संबंधों के लिए यूरोपीय संसद के प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया।

लक्ज़मबर्ग में 4–7 नवंबर 2015 को 12वें एशिया–यूरोप बैठक (एएसईएम) के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ) वी के सिंह (सेवानिवृत्त) ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इसके अलावा एएसईएम के विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर भारतीय स्थिति पर विचार विमर्श के लिए, माननीय विदेश राज्य मंत्री ने लक्समबर्ग, लातविया, स्वीडन, हंगरी, ब्रिटेन, वियतनाम, बुल्गारिया, पुर्तगाल और आयरलैंड से अपने समकक्षों से भी मुलाकात की।

भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक ने यूरोपीय कोर्ट ऑफ ऑर्डर के अध्यक्ष, श्री विटर क्लेडेरा के निमंत्रण पर 6–8 सितंबर 2015 को लक्ज़मबर्ग का दौरा किया। उन्होंने अपने संगठनों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा के लिए संस्थागत तंत्र पर चर्चा की।

यूरोपीय संघ 28 देशों के ब्लॉक के रूप में भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापार भागीदार है जबकि वर्ष 2014 में भारत यूरोपीय संघ का 9वां सबसे बड़ा क्षेत्रीय भागीदार था। वर्ष 2014 (जनवरी–दिसम्बर) के दौरान यूरोपीय संघ 28 के साथ भारत का समग्र द्विपक्षीय व्यापार (माल और सेवाएं दोनों) 95.51 बिलियन यूरो (माल का द्विपक्षीय व्यापार 72.52 बिलियन यूरो और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार 22.99 बिलियन यूरो) था। वर्ष 2014 में भारत का यूरोपीय संघ के लिए माल का निर्यात 36.8 बिलियन यूरो था, जबकि यूरोपीय संघ से भारत के लिए आयात 35.9 बिलियन यूरो आंका गया।

वर्ष 2015 (जनवरी–अगस्त 2015) के शुरुआती 8 माह के दौरान यूरोपीय संघ 28 के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 52.3 बिलियन यूरो रहा, जिसमें भारत का निर्यात 26.9 बिलियन यूरो और यूरोपीय संघ से भारत का आयात 25.4 बिलियन यूरो था। वर्ष 2014 में यूरोपीय संघ से भारत को 4.956 बिलियन यूरो मूल्य के प्रत्यक्ष विदेश निवेश के प्रवाह के साथ यूरोपीय संघ से भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का सबसे बड़ा स्रोत बना रहा। वर्ष 2014 में यूरोपीय संघ 28 में भारतीय निवेश 1.078 बिलियन यूरो का रहा।

वर्ष के दौरान भारत और यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय संस्थागत कार्यतंत्र की बैठक भी हुई। आतंकवाद से निपटने पर 20 मई 2015 को भारत–यूरोपीय संघ वार्ता आयोजित की गई थी तथा 21 मई 2015 को ब्रुसेल्स में साइबर सुरक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

नई दिल्ली में चार बैठकें आयोजित की गई– स्वच्छता एवं फाईटो स्वच्छता (एसपीएस)/कारोबार में तकनीकि बाधाओं से संबंधित यूरोपीय संघ संयुक्त कार्य समूह (टीबीटी) (11 जून 2015): कृषि तथा समुद्री उत्पादों पर यूरोपीय संघ संयुक्त कार्य समूह (7 अक्टूबर 2015) और आर्थिक सहयोग संबंधी भारत–यूरोपीय संघ उप–आयोग (16 अक्टूबर 2015)।

शैक्षिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी सम्पर्कों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इस दिशा में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय योग विशेषज्ञ श्री श्री रविशंकर ने ब्रूसल्स में यूरोपीय संसद में आयोजित कार्यक्रम में योग विषय पर अपना भाषण देकर और ध्यान एवं प्रश्नोत्तरी सत्र में मार्गदर्शन करके 21 अप्रैल 2015 को इस समारोह में उदघाटन सत्र का नेतृत्व किया।

पश्चिम यूरोप

प्रिंसिपैलिटी ऑफ एन्डोरा

भारत और प्रिंसिपैलिटी ऑफ एन्डोरा के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे। वर्ष के दौरान भारत और एन्डोरा ने कर सूचना आदान प्रदान करार के मसौदे पर बातचीत जारी रखी। भारत सरकार ने वर्ष 2015 में एन्डोरा को ई–पर्यटक वीजा सुविधा प्रदान की।

बेल्जियम

वर्ष के दौरान, भारत और बेल्जियम के बीच संबंध राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति जारी रही। अत्यधिक कुशल भारतीय व्याप्ति की मौजूदगी, मुख्यतः बेल्जियम में हीरे के कारोबार में सक्रिय उपस्थिति ने संबंध को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने 22–26 जूनए 2015 तक बेल्जियम में उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जिसमें लोक सभा और राज्य सभा, दोनों के सांसद शामिल थे। माननीय अध्यक्ष ने बेल्जियम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट के अध्यक्षों के साथ बैठकें कीं।

राज्यसभा से सांसदए श्री तरुण विजय और श्री ए. डब्ल्यू. रबी बर्नार्ड ने 13–16 सितम्बर 2015 तक ब्रूसेल्स में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के लिए अमेरिकी मिशन का दौरा किया था।

जनवरी से अगस्त 2015 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 8.29 बिलियन यूरो थाए जिसमें से भारत की ओर से बेल्जियम को किया गया निर्यात 2.88 बिलियन और आयात 5.41 बिलियन यूरो था। द्विपक्षीय व्यापार में रत्नों एवं आभूषणों का वर्चस्व रहा था। जबकि भारत में अधिकतर बिना तराशे हुए हीरे का आयात हुआ, जनवरी से अगस्तए 2015 में बेल्जियम से भारत में आयात प्रमुख रूप

से रत्न और आभूषण (4.31 बिलियन)ए रसायन और रासायनिक उत्पाद (241 मिलियन)ए मशीनरी और इंजीनियरिंग उत्पाद (220 मिलियन) और प्लास्टिक और वस्तुएं (203 मिलियन था। भारत द्वारा बेल्जियम को निर्यात में मुख्यतः रत्न एवं आभूषण (1.31 बिलियनद्धए रसायन और रासायनिक उत्पाद (326 मिलियन) और कपड़ा (280 मिलियन) के क्षेत्रों में था।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए), 21–23 अप्रैल 2015 को ब्रूसेल्स में भारतीय दूतावास के सहयोग से, आयोजित सीफूड एक्स्पो ग्लोबल में भाग लिया था। 22 भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातकों ने इस आयोजन में भाग लिया था। भारतीय दूतावास ने 27–29 मई, 2015 को मेक इन इंडिया समारोह आयोजित किया जिसमें भारतीय उद्योग संघ के प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान आयोजित समारोह भी शामिल है।

28–29 सितम्बर 2015 को नई दिल्ली में 14वां भारत–बेल्जियम–लक्ज़ेमबर्ग आर्थिक संघ (बीएलईयू) संयुक्त आयोग आयोजित किया गया था। वाणिज्य सचिव ने भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया जबकि बेल्जियम का नेतृत्व श्री गीर्ट मुएले, द्विपक्षीय मामलों के महानिदेशक ने किया था।

भारत और बेल्जियम में 2014–18 की अवधि के दौरान प्रथम विश्व युद्ध की शती के स्मरण के लिए सतत् सहयोग जारी है। 12 नवंबर 2015 को वाईप्रेसए बेल्जियम में उन भारतीय सैनिकों के लिए वार्षिक स्मरणोत्सव समारोह आयोजित किया गया जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। इस स्मरणोत्सव समारोह में 11 नवम्बर 2015 को बेल्जियम के नॉक हिस्ट में आयोजित स्मरण संगीतमय कार्यक्रम भी शामिल है।

बेल्जियम के साथ सांस्कृतिक और जन–जन संपर्क का जश्न मनाने के लिए, गुरुदेव की 154 वीं जयंती के अवसर पर 7 मई 2015 को कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूवेन में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया।

26 नवम्बर 2015 को भारत के प्रथम संवैधानिक दिवस के अवसर पर कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूवेन में "भारत में संघवाद– तुलनात्मक और यूरोपीय परिप्रेक्ष्य" विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था।

भारत सरकार ने पर्यटन और जन का जन से संपर्क को बढ़ावा देने के लिए 15 अगस्तए 2015 से बेल्जियम को ई–पर्यटन वीजा की सुविधा प्रदान की है।

बेल्जियम में 21 जून 2015 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया जिसमें लोगों ने ब्रुसेल्सए एंटवर्पए ल्युवेन, घेन्ट, बेल्जियम अर्डेनीस में राधादेश, एंघीन और कोर्टिजिक में सार्वजनिक योग समारोहों में भाग लिया। ब्रुसेल्स में ए पिक्चरेस्क्यू बोईस डी ला काम्ब्रे (फोरेस्ट ऑफ ब्रसेल्स) में एक बडा सार्वजनिक योग समारोह आयोजित किया गया जिसमें 4788 पंजीकृत प्रतिभागियों ने भाग लिया। एंटवर्प इंडियन एसोसिएशन ने एंटवर्प में योग समारोह आयोजित किया जिसमें लगभग 1500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

फ्रांस

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 09–12 अप्रैल 2015 तक फ्रांस के अत्यधिक सफल दौरे के परिणामस्वरूप भारत–फ्रांस के संबंधों को अत्यधिक संवर्धन हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति श्री फ्रेंकोइस होलैंडे के बीच सितंबरए 2015 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर द्विपक्षीय बैठक भी हुई थी। जलवायु परिवर्तन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन के 21 वें सत्र (सीओपी –21) के दौरान 30 नवंबर 2015 को पेरिस में दोबारा उनकी फिर से मुलाकात हुई थी।

प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे के दौरानए 09–12 अप्रैल 2015 के बीच प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ अकेले बैठक की और प्रतिनिधिमंडल स्तर पर वार्ताएं कीए जहां दोनों नेताओं ने परस्पर हित वाले विभिन्न द्विपक्षीयए क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की थी। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष में भारत–फ्रांस सहयोग के 50 वर्ष पूरे होने की याद उपलक्ष्य में सरल और मेघा ट्रोपीक्वेस सेटेलाइटों की छवि वाले दो संयुक्त डाक टिकटों का विमोचन किया। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के संसदीय नेताओं से भी मुलाकात की और श्री क्लाड बार्टोलोनए फ्रांसीसी राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष द्वारा एक मध्याह्न भोज का आयोजन किया गया था।

9 अप्रैल 2015 को भारत–फ्रांस के सीईओ मंच की 7 वीं बैठक भी आयोजित की गई थी और इसकी सिफारिशें प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के समक्ष पेश की गईंए जिनमें (i) ऊर्जा (पारंपरिक और अक्षय) (ii) जल और अपशिष्ट (iii) जीव विज्ञान (iv) रक्षा एवं विमान निर्माण तकनीक और, (v) मूलसंरचना वित्तपोषण के संबंध में पांच कार्यबलों का सृजन भी शामिल था। प्रधानमंत्री को अवसंरचना और रक्षा विनिर्माण के संबंध में व्यावसायिक गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करने के लिए एमईडीईएफ (फ्रेंच व्यापार परिसंघ) द्वारा आमंत्रित किया गया था। फ्रांस की शीर्ष कंपनियों के 15 सीईओ ने दो गोलमेल सम्मेलनों में से प्रत्येक में भाग लिया था।

प्रधानमंत्री ने पेरिस में यूनेस्को में विशाल सभा को संबोधित कियाए और यूनेस्को की महानिदेशक सुश्री इरिना बोकोवा के साथ बैठक की थी। उन्होंने यूनेस्को परिसर में स्थापित श्री औरोबिन्दो की प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित की और योग को समर्पित एक वेब पोर्टल का उद्घाटन किया।

प्रधानमंत्री ने फ्रांस के मिडी पाइरीनीज क्षेत्र में टाउलोस शहर का भी दौरा किया जहां उन्होंने एयरबस की विनिर्माण इकाई का दौरा किया। उन्होंने सीएनईएस (फ्रांस राष्ट्रीय अंतरिक्ष अध्ययन

केन्द्र) का दौरा भी किया था।

प्रधानमंत्री ने फ्रांसीसी रक्षा मंत्री श्री जीन यवेस ले ड्रायन के साथ फ्रांस के उत्तर में न्यूचे चैपेल मेमोरियल का दौरा किया, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वाले 4,700 से अधि ाक भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था। उन्होंने पेरिस क्राउसेल ड्यू लोवरे, फ्रांस में भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों की एक विशाल सभा को भी संबोधित किया था।

दौरे के दौरान 19 करारों/ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए जिनमें भारत और फ्रांस के बीच सहयोग के विविध क्षेत्रों जैसे परमाणु ऊर्जाए अंतरिक्षए रेलवेए सांस्कृतिक विरासत का संरक्षणए विज्ञान और प्रौद्योगिकीए खेलए पर्यटनए मानव आदान–प्रदानए नवीकरणीय ऊर्जा और ऐतिहासिक स्मारकों की ट्विनिंग आदि शामिल थे।

अप्रैल, 2015 में प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान हस्ताक्षरित दो करारोंः भारत और फ्रांस के बीच इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए एक पूर्व इंजीनियरिंग करार (एनपीसीआईएल) और फ्रांसीसी कंपनी अरेवा और लार्सन एण्ड टूब्रो के बीच समझौता ज्ञापन के जरिए द्विपक्षीय सिविल नाभिकीय सहयोग मजबूत हुआ है।

इस दौरे के दौरान, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के संयुक्त विकास, अंतर–ग्रहीय अभियानों में सहयोग और भारतीय उपग्रह पर एक फ्रांसीसी पेलोड की मेजबानी के लिए भी दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इस दौरे के दौरान हस्ताक्षरित दो अन्य अंतरिक्ष समझौता ज्ञापनों में मेघा ट्रापिकेस सैटेलाइट परइसरो–सीएनईएस समझौता ज्ञापन का विस्तार और भारतीय उष्णकटिबंधीय पर काबैंड प्रचार प्रयोग के हेतु इसरोए सीएनईएस और ओएपनईआरए के बीच समझौता ज्ञापन शामिल है। एरियन स्पेस द्वारा अभी तक 19 भारतीय सैटेलाइटें शुरू किए गए हैं। 10 नवंबर, 2015 को भारत के उन्नत दूरसंचार उपग्रह जीसैट –15 को फ्रेंच प्रक्षेपण व्हीकल एरियन –5 से कोरू, फ्रेंच गयाना में इंटेंडेड भू–तुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा में रखा गया था।

भारत और फ्रांस के बीच मजबूत रक्षा सहयोग है जिसमें दोनों ओर से दौरों से लेकर रक्षा अधिप्राप्ति के लिए संयुक्त अभ्यास भी शामिल हैं। अप्रैलए 2015 में प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान, सरकार से सरकार के बीच करार के तहत उड़ान करने की अवस्था में भारत द्वारा 36 रैफेल जेट खरीदने की घोषणा की गई थी। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री श्री जिन यूवस ली ड्रायन ने 06 मई, 2015 को भारत का दौरा किया तथा रक्षा मंत्री से मुलाकात की।

28 अप्रैल– 02 मई, 2015 तक गोवा के तट से भारत– फ्रांसीसी नौसेना अभ्यास वरुण को आयोजित किया गया जिसमें दोनों देशों के वायुयान वाहकों अर्थात चार्ल्स डी ग्आले और विराट ने भाग लिया था। आईएनएस त्रिकंद ने 25–29 सितंबर, 2015 को टाउलॉन नेवल बेस में पोर्ट कॉल लिया। रक्षा राज्य मंत्री श्री राव इंदरजीत सिंह ने 15–18 जूनए 2015 तक पेरिस वायु प्रदर्शनी में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और फ्रांसीसी रक्षा मंत्री श्री जिन यूवस ली ड्रायन के साथ बैठकें की थीं और विभिन्न भारतीय कंपनियों के साथ भी बैठकें आयोजित की थी।

अन्य महत्वपर्ण मंत्री स्तरीय दौरों में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री वैंकया नायडू द्वारा 5–6 अक्तूबर, 2015 को बोरडिएक्स में इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स वर्ल्ड कांग्रेस में शिरकत करने के लिए किया गया दौरा शामिल है। श्री अशोक गजपति राजू, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ने 15–21 जून, 2015 तक पेरिस ली बोरजेट में 51वीं अंतरराष्ट्रीय पेरिस हवाई प्रदर्शनी में भाग लिया। राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), वाणिज्य और उद्योग, श्रीमती निर्मला सीतारमन ने 3 जून, 2015 को पेरिस में ओईसीडी मंत्रीस्तरीय परिषद बैठक के इतर विषयों पर वार्षिक विश्व व्यापार संगठन मंत्रीस्तरीय बैठक के अनौपचारिक समूह में भाग लिया था।

फ्रांस की ओर से किए गए प्रमुख दौरों में सीओपी–21 के लिए तैयारी में 20 नवंबर, 2015 को जलवायु परिवर्तन हेतु राजदूत सुश्री लारेंस टुर्बियाना और फ्रांसीसी विदेश मंत्री श्री लोरेंट फेबियस की भारत यात्रा शामिल है। यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री प्रकाश जावेडकर और विद्युत, कोयला और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पीयूष गोयल और श्री सुरेश प्रभु, रेल मंत्री से मुलाकात की।

2015 के पहले नौ माह के दौरान, भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय व्यापार 6.5 बिलियन था जिसने विगत वर्ष की तुलना में 11.89 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। भारत से फ्रांस को निर्यात, 4.1 बिलियन यूरो था, जो विगत वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा में 7.86 प्रतिशत अधिक था। फ्रांस में सौ से अधिक भारतीय कंपनियां चल रही है जिनमें लगभग 1 बिलियन यूरो संचयी स्टॉक और 7,000 लोग नियोजित हैं। वर्तमान में भारत ने 750 बड़ी फ्रांसीसी कंपनियां मौजूद हैं जिससे अप्रैल, 2000 से जून, 2015 तक फ्रांस 4.2 बिलियन यूरो के संचयी निवेश के साथ भारत में 9वां सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। अप्रैल–जून 2015 से फ्रेंच एफडीआई 123 मिलियन यूरो था।

भारत और फ्रांस में शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में लंबे समय से सहयोग चला आ रहा है। भारत फ्रांसीसी उन्नत अनुसंधान संवर्धन केन्द्र (सीईएफआईपीआरए) ने 79 द्विपक्षीय परियोजनाओं, वैज्ञानिकों के 150 दौरों और 6 संगोष्ठियों में सहायता दी है। सीईएफआईपीआरए ने पेरिस में 26 अप्रैल, 2015 को एयरोस्पेस कार्यक्रम के लिए एयरबस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत और फ्रांस, दोनों ने विस्तारित वीआईई स्कीम को प्रचालित कर दिया है जिसमें दो वर्ष ठहरने का परमिटए छात्रों को उनके अध्ययन क्षेत्र संबंधी उपयुक्त रोजगार तलाशने की संभावनाएं प्रदान करना शमिल है। 2015 मेंए दोनों देशों के बीच जीवंत विद्यालय विनिमय कार्यक्रमों के भाग के रूप में 30 फ्रांसीसी विद्यालयों के छात्रों ने भारत का दौरा किया और 15 भारतीय विद्यालयों से छात्रों ने फ्रांस का दौरा किया था।

भारत सरकार ने अप्रैल 2015 में फ्रांस को ई–पर्यटन वीजा सुविधा का विस्तार किया है।

फ्रांस में 21 जून, 2015 को प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया जिसमें पेरिस में दूतावास द्वारा पार्स डी ला विलेट में आयोजित फ्लैगशिप समारोह में 3000 से अधिक लोगों ने योग किया।

भारत और फ्रांस ने 2015 में फ्रांस में आतंकी हमलों के संदर्भ में आतंकवाद से मुकाबला करने की अपनी दृढ़ता दोहराई है। 13 नवंबर, 2015 को पेरिस में आतंकी हमलों को देखते हुएए जिसमें 130 लोग मारे गए थे, प्रधानमंत्री ने आतंकवाद की भर्त्सना करते हुए एक बयान जारी किया और फ्रांस के लोगों से सहानुभूति व्यक्त की। राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी और विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने फ्रांस के साथ शोक एवं सहानुभूति व्यक्त करते हुए अपने फ्रांसीसी समकक्ष को पत्र लिखा है।

प्रधानमंत्री ने सीओपी–21 की शुरूआत में 30 नवंबर, 2015 को लीडर्स इवेंट में भाग लेने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और विद्युत, कोयला और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के साथ भी पेरिस का दौरा किया था। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ओलांद से मुलाकात की और उन्होंने एक साथ 30 नवंबर, 2015 को ली बॉर्जेट में 'अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन' का उद्घाटन किया। उन्होंने संयुक्त रूप से 'इकोलॉजी ऑफ आवर वर्ल्ड' शीर्षक कोटेशन की पुस्तक का विमोचन किया जिसमें दोनों नेताओं द्वारा आमुख लिखा गया है। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो के साथ द्विपक्षीय बैठकें की थी। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाने के लिए नवीन प्रोद्यौगिकियों में निवेश एवं निधियन को प्रोत्साहित करने के लिए सीओपी–21 के मौके पर प्रधानमंत्री ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति और कारोबारी बिल गेट्स के साथ संयुक्त राज्य फाउंडेशन द्वारा शुरू किए गए 'मिशन इनोवेशन' को भी संबोधित किया।

फ्रांस के राष्ट्रपति श्री फ्रांकोईस ओलांद ने 24–26 जनवरीए 2016 तक भारत के 67वें गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि के तौर पर भारत का दौरा किया थी। इसके साथ फ्रांस गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर सबसे अधिक संख्या में निमंत्रण (5) पाने वाले देश बन गया।

भारत के गणतंत्र दिवस के समारोहों के इतिहास में पहली बारए 126 सदस्य वाली फ्रांसीसी सैन्य टुकडी ने 26 जनवरी, 2016 को गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया है। राष्ट्रपति ओलांदए ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठकें की जहां उन्होंने द्विपक्षीयए क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री की अत्यधिक सफल फ्रांस यात्रा के अनुसरण में यह उनकी पांचवी मुलाकात थी।

राष्ट्रपति ओलांद की भारत यात्रा से भारत.फ्रांस सामरिक साझेदारी एक मजबूत पथ पर अग्रसर हुई है। इससे रक्षा, असैन्य परमाणु सहयोग और अंतरिक्ष के तिहरे संबंधों में ठोस प्रगति के साथ आगे प्रोत्साहन मिला, जिसमें रक्षा हेतु राफेल लड़ाकू जेट विमानों की खरीद पर एक समझौता ज्ञापन का समापनए एनपीसीआईएल और ई डीएफ के बीच संशोधित समझौता ज्ञापन और सहयोग के एक रोडमैप के समापन के साथ भारत के ओशनसैट 3 उपग्रह और मंगल मिशन सहित भविष्य अंतर.ग्रहों के अन्वेषण में फ्रांस के संभव भागीदारी पर असैनिक परमाणु क्षेत्र में जैतापुर परियोजना पर कार्य 2017 के आरंभ में और संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन और आर्गोस पेलोड के शुभारंभ में भागीदारी की घोषणा की गई। कुल मिलाकर, रक्षाए असैन्य परमाणुए अंतरिक्षए स्मार्ट सिटीए एस एंड टीए स्मार्ट गवर्नेंस, खाद्य सुरक्षा, संस्कृति आदि के रूप में विविध क्षेत्रों में 17 जी 2 जी समझौतोंध समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा 13 समझौता ज्ञापनोंध्करारों से निष्कर्ष निकाला गया और चंडीगढ़ में 24 जनवरी 2016 को भारत.फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन में इनकी घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री श्री मोदी और राष्ट्रपति ओलांद ने संयुक्त रूप से गुड़गांव में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की अंतरिम सचिवालय का उद्घाटन किया। इसके लिए फ्रांस ने भविष्य में आईएसए परियोजनाओं के लिए 300 मिलियन यूरो की प्रतिबद्ध ता दर्शाई है। भारत और फ्रांस द्वारा आतंकवाद पर हमारे संयुक्त दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता को दोहराते हुए आतंकवाद की इस समस्या से लड़ने के लिए एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया है।

50 से अधिक करारों/समझौता ज्ञापनों पर अंतिम निर्णय लिए जाने और 9 महीने की छोटी सी अवधि में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ओलांद की यात्राओं से भारत एवं फ्रांस के बीच भागीदारों के रूप में मेक इन इंडियाए स्मार्ट सिटीए डिजिटल इंडियाए अक्षय ऊर्जा आदि जैसे हमारे प्रमुख पहल में फ्रांस सबसे चर्चित रणनीतिक अग्रणी भागीदारी में से एक बन गया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजित के डोवल ने भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक वार्ता का 27वां दौर आयोजित करने के लिए 12–13 जनवरीए2016 को पेरिस में भारतीय प्रतिनिधि ामंडल का नेतृत्व किया था। फ्रांस की ओर से फ्रांसीसी राष्ट्रपति

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि, फ्रांस के राष्ट्रपति श्री फ्रांसवा ओलांद, 26 जनवरी, 2016 को नई दिल्ली में 67वें गणतंत्र दिवस की परेड के अवसर पर राजपथ पर सलामी मंच पर

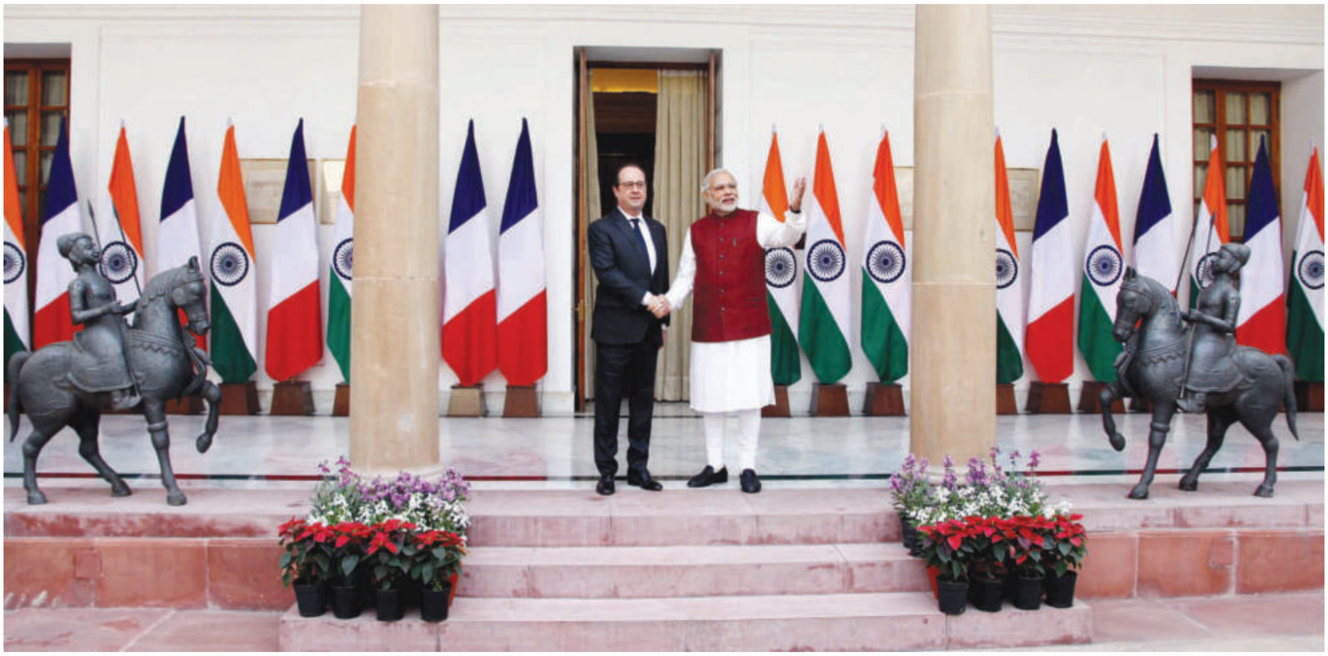

प्रधानमंत्री नई दिल्ली (25 जनवरी 2016) में फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करते हुए।

के राजनैतिक सलाहकार श्री जैक्स आडिबर्ट ने फ्रांस का नेतृत्व किया गया था। दोनों पक्षों ने सुरक्षा, रक्षा सहयोगए सिविल नाभिकीय सहयोगए आतंकवाद विराध करने आदि के रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की थी।

श्री अरविंद के. गुप्ताए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने 14–16 जनवरीए 2016 को भारतीय महासागरीय क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर पहली बार भारत–फ्रांस वार्ता करने के लिए पेरिस में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था।

अरेवा के अध्यक्ष के नेतृत्व में और ई डीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के एक फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल ने 7–8 जनवरी 2016 को भारत का दौरा किया और जैतापुर में परमाणु बिजली परियोजना को आगे बढ़ाने पर विचार–विमर्श किया।

जर्मनी

इस वर्ष भारत और जर्मनी के बीच गहन द्वीपक्षीय संबंध देखे गए जिसमें दोनों देशों के राष्ट्र अध्यक्षों की यात्राएं शामिल है। सभी स्तरों पर कई दौरों से द्विपक्षीय संबंधों की गति बरकरार रखी गई है। जर्मनी, यूरोप में भारत का अग्रणी व्यापार, तकनीक, निवेश और सामरिक साझेदार बना रहा जो भारत के विकासात्मक एजेन्डे के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हैनोवर मैसी– 2015 का उदघाटन करने के लिए 12–14 अप्रैल, 2015 को वाणिज्य और उद्योग मंत्री के साथ जर्मनी का दौरा किया जहां भारत ने साझेदार देश के रूप में भाग लिया। प्रधानमंत्री और जर्मनी के चांसलर ने संयुक्त रूप से 'इंडिया पवेलियन' और 'इंडो–जर्मन व्यापार शिखर सम्मेलन' का उदघाटन किया और 13 अप्रैल, 2015 को हैनोवर मेले में मेला ग्राउंड का पैदल दौरा किया। प्रधानमंत्री ने जर्मन उद्योग को दिए अपने संबोधन में 'मेक इन इंडिया' और अन्य प्रमुख आर्थिक उपायों का विस्तार से वर्णन किया था।

विश्व के प्रमुख व्यापार मेले में भारत की मजबूत भागीदारी जिसमें 350 भारतीय व्यापारों, 120 सीईओ और 14 राज्य शामिल थे, द्वारा आर्थिक रूप से प्रबल भारत में बेहतर अवसर सफलतापूर्वक दर्शाए गए और भारत को जर्मन तथा यूरोपीय उद्योगों के समक्ष पर दृढ़ता से प्रस्तुत किया।

प्रधानमंत्री ने हैनोवर और बर्लिन में जर्मन चांसलर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ताएं की। दोनों नेताओं द्वारा द्विपक्षीय सहयोग के लिए साझा बयान जारी किया गया था। यूरोप में हमारी अग्रणी व्यापार, तकनीकी और निवेश साझेदारी में जर्मनी की भूमिका का निर्माण करने में दोनों नेताओं ने भारत–जर्मनी रणनीतिक साझेदारी का मजबूत करने और जर्मनी को भारत के फ्लैगशिप उपायों जैसे 'मेकइन इंडिया', 'स्वच्छ भारत', डिजिटल भारत' और कौशलभारत' में विकल्प के साझेदार बनाने के लिए स्पष्ट रूपरेखा तैयार की है।

हैनोवर में, प्रधानमंत्री ने हैनोवर के लार्ड मेयर से मुलाकात की और महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने बहुत से जर्मन सीईओ से भी मुलाकात की। बर्लिन मेंए प्रधानमंत्री ने जर्मन उप–चांसलर सिग्मर गैब्रिअल और विदेश मंत्री स्टेनमिअर के साथ भी बैठक की थीं। उन्होंने बर्लिन मध्य रेलवे स्टेशन और सिमेंन्स तकनीकी अकादमी का भी दौरा किया था। प्रधानमंत्री ने बर्लिन में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया और जर्मनी में अध्ययनरत भारतीय छात्रों से बातचीत भी की।

हैनोवर मैसे के दौरानए नवीकरणीय ऊर्जाए शहरी विकास और कौशल विकास के क्षेत्रों में सरकार से सरकार तक 3 इच्छा पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इनके अलावाए विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/व्यवसाय संघों/कंपनियों के बीच भारी इलेक्ट्रॉनिक्सए सौर और पवन ऊर्जा प्रणालियोंए मशीन उपकरणोंए इलेक्ट्रिकल क्षेत्र, लघु, सूक्ष्म और इंटेलीजेंट ग्रिड, नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों आदि के क्षेत्र में 23 व्यवसाय से व्यवसाय/अर्ध सरकारी समझौता ज्ञापनों/आशय पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 26 अक्तूबरए 2015 को यूएनजी, के मौके पर न्यूयॉर्क में जी–4 शिखरसम्मेलन के दौरान चांसलर मार्केल के साथ द्विपक्षीय बैठकें की थी।

तीसरे भारत–जर्मनी अंतर– सरकारी परामर्शी के लिए जर्मन चांसलर के भारत दौरे के लिए तैयारी करने हेतु विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 26–28 अगस्तए 2015 को जर्मनी का दौरा किया था। उन्होंने जर्मन बंडेस्टेग के अध्यक्ष शिक्षा और अनुसंधान मंत्रीए बंडेस्टेका के विदेश कार्य समिति के अध्यक्ष और जर्मन विदेश सचिव से भी मुलाकात की थी।

जर्मनी के चांसलर डा. अंजेला मार्कल ने तीसरे भारत–जर्मनी अंतर– सरकारी विचार विमर्श के लिए 4–6 अक्तूबरए 2015 को भारत का सरकारी दौरा किया। उनके साथ विदेशए आर्थिक सहयोग और विकासए कृषि और शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्रीय 3 संसदीय राज्य सचिव (ए रक्षा और वित्त)य 3 राज्य सचिव और एक व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल ने भी भारत की यात्रा की थी।

नई दिल्ली में, चांसलर मार्केल का जोशपूर्ण स्वगत किया गया था तथा उन्होंने राजघाट का दौरा किया और माननयी राष्ट्रपति से मुलाकात भी की थी।

प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ताओं मेंए चांसलर मार्केल और प्रधानमंत्री ने परस्पर हित के द्विपक्षीयए क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री के अप्रैल, 2015 में बर्लिन के सफल दौरे का लाभ उठाते हुए दोनों नेताओं ने परस्पर सरोकार के

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री जर्मन संघीय गणराज्य की चांसलर,
माननीय डॉ एंजेला मार्केल के साथ (5 अक्टूबर 2015)

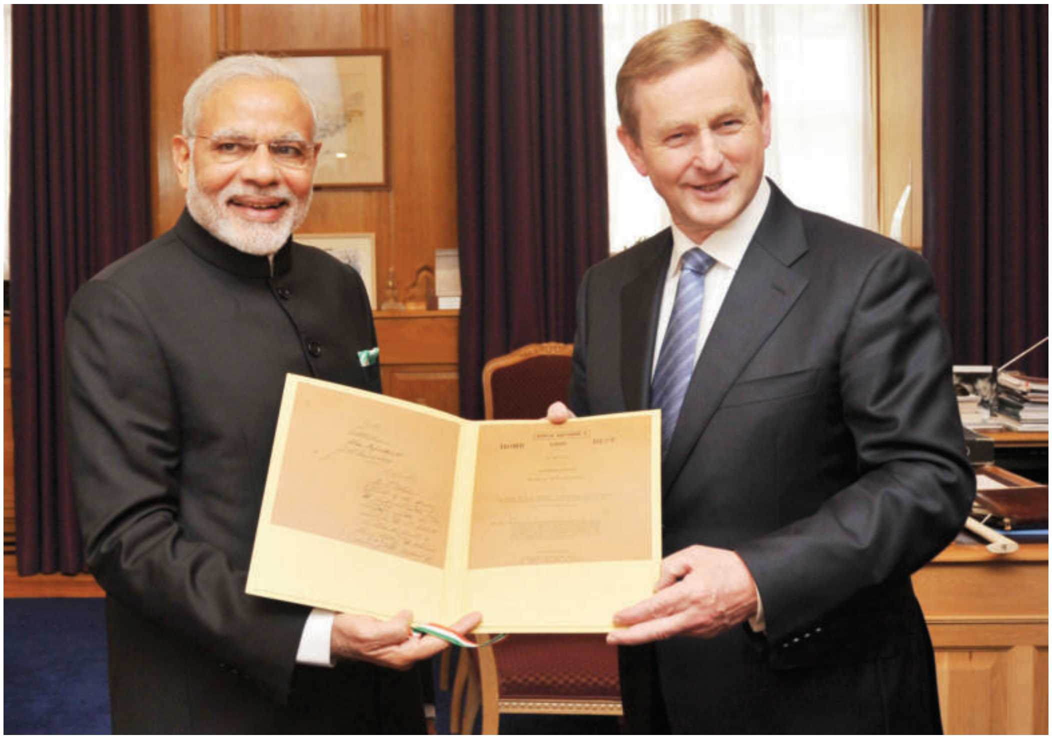

प्रधानमंत्री आयरलैंड के प्रधानमंत्री, श्री इंडा केनी को दो आयरिश अधिकारियों से संबंधित कागजात की पांडुलिपियां और प्रतिकृतियां डबलिन के सरकारी इमारत में 23 सितम्बर, 2015 को उपहार में देते हुए।

चिह्नित किए गए क्षेत्रों में उन्नत सहयोग के लिए साझा बयान जारी किया।

इस यात्रा के दौरान सुरक्षा सहयोग, नागर विमानन सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, निवेश में तीव्र ट्रैकिंग, विनिर्माणए कौशल, नवाचार और उच्चतर शिक्षा, रेलवे, कृषि और पौध सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, भाषा और विज्ञान एवं तकनीक जैसे क्षेत्रों में कुल 18 द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों एवं करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत–जर्मनी सौर ऊर्जा साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए जिसके तहत जर्मनी की सरकार अन्य बातों के साथ साथ अगले पांच वर्षों में 1 बिलियन यूरो का रियायती ऋण प्रदान करने की लिए सहमत हुई हैं।

जर्मनी के चांसलर और प्रधानमंत्री ने 6 अक्तूबर, 2015 को बंगलुरू का दौरा भी किया जहां उन्होंने व्यवसाय शिखर सम्मेलन 4.0 को संबोधित किया और प्रधानमंत्री द्वारा सीईओ की मेजबानी में दिए गए मध्याह्न भोजन में भी उपस्थित हुए। दोनों नेताओं ने बंगलुरू में जर्मन बॉश अनुसंधान एवं विकास का भी दौरा किया था।

वर्ष के दौरान, दोनों देशों की ओर से कई मंत्री स्तरीय और उच्च स्तरीय दौरे किए गए थे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्रीए श्री प्रकाश जावेडकर ने 18–19 मई, 2015को बर्लिन में छठी पिट्सबर्ग वार्ता में हिस्सा लिया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरित कौर बादल ने 11–16 अक्तूबर, 2015 को कोलोन में खाद्य व्यापार मेला अनुगा–2015 में भाग लिया था।

जर्मनी के रक्षा मंत्री उर्सुला वॉन डर लेयेन ने 26–28 मई 2015 को भारत का सरकारी दौरा किया। वह प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से भी मिले।

चालू वर्ष में भी संसदीय आदान–प्रदान में अत्यधिक वृद्धि हुई है। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (सीडीयू) से जर्मनी की संसद के 13 युवा सदस्यों ने 26–30 अक्तूबर, 2015 को भारत का दौरा किया। डॉ. सिमोन राट्ज की अध्यक्षता में जर्मन संसद की शिक्षा, अनुसंधान और तकनीकी आकलन संबंधी संसदीय समिति के प्रतिनिधिमंडल ने 15–21 नवंबर, 2015 के बीच नई दिल्ली और बंगलुरू का दौरा किया। इसी प्रकार, श्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में भारत से युवा सांसदों के एक समूह ने 3–8 सितंबर को जर्मनी का दौरा किया था।

इस वर्ष के दौराए 4 अप्रैल, 2015 को बर्लिन में आयोजित व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर संयुक्त कार्य दल की 8वीं बैठकए 18 अगस्त, 2015 को बॉन में जलय अपशिष्ट प्रबंधन तथा सर्कुलर अर्थव्यवस्था पर आयोजित पहली बैठक 14–15 सितंबर, 2015 को नई दिल्ली में भारत–जर्मनी उच्च तकनीक भागीदारी दल; एच टी पी जीद्ध तथा निर्यात नियंत्रण पर द्विपक्षीय परामर्शी पर आयोजित दूसरी बैठक 16 सितंबर, 2015 को लेपजिग में धारणीय शहर विकास पर संयुक्त कार्यदल की पहली बैठक तथा 9 अक्तूबर, 2015 को बर्लिन में आयोजित भारत–जर्मनी साइबर वार्ता सहित कई द्विपक्षीय संस्थागत तंत्रों पर बैठक की गई थी।

जर्मनी ईयू में भारत का सबसे बडा व्यापार सहभागी है और विश्व में छठा सबसे बड़ा व्यापार सहभागी है। वर्ष 2014–15, में, भारत ओर जर्मनी के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 20.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। जर्मनी में हमारा निर्यात लगभग 7.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर और जर्मनी से आयात लगभग 12. 79 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारत में सीधे निवेश के मामले में जर्मनी 7वां सबसे बड़ा विदेश देश रहा। भारत में 3.18 प्रतिशत की एफडीआई के हिसाब से अप्रैल 2000 से जनवरी से जनवरी 2015 के दौरान भारत में जर्मन एफडीआई 8.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रही। वर्तमान में, लगभग 1600 भारत–जर्मन सहयोग कार्यक्रमों और लगभग 600 संयुक्त उद्यमों का संचालन किया जा रहा है। जर्मनी में भारतीय निवेश भी अनुमानतः 6 अरब यूरो से अधिक रहा। जर्मनी में जो 215 से अधिक भारतीय कंपनियां हैं मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी की, ऑटोमोटिव, फार्मा बायोटेक क्षेत्रों में प्रचालन में है।

'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, जर्मन मिटलस्टैंड (एसएमई) कंपनियों को भारतीय बाजार में प्रवेश में सहयोग हेतु भारतीय दूतावास ने बर्लिन में अपने ही प्रकार की एक नई, निवेश सुविधा कार्यक्रमः 'मेक इन इंडिया मिटलस्टैंड' (एमआईआईएम) की शुरुआत की गई है। दूतावास ने ''उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण में भारत–जर्मन सहयोग संभावना'' पर एक अध्ययन रिपोर्ट प्रकाशित की है। जर्मन फेडरल चांसलर डॉ एंजेला मर्केल की उपस्थिति में हेन्नोवर मेस 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह रिपोर्ट जारी की थी।

जर्मनी ने भारत में हरित ऊर्जा कॉरिडोर, ऊर्जा दक्षता, सौर प्रसार परियोजना, शहरी अवसंरचना विकास, कौशल विकास गंगा की सफाई और कृषि/खाद्य क्षेत्र में नवीनीकरण जैसे क्षेत्रों में विभिन्न विकास सहयोग परियोजनाओं के लिए वर्ष 2015 के लिए कुल 1.49 मिलियन यूरो की सहायता का वचन दिया है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। नई दिल्ली में 5 अक्टूबर, 2015 को आयोजित तीसरी आईजीसी में दोनों पक्षों द्वारा प्रतिवर्ष अधिकतम चार मिलियन यूरो तक वित्तपोषण को बढ़ाए जाने के साथ भारत–जर्मन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र की अवधि की 2017 से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से दोनों पक्षों ने संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए थे। डॉ. जॉर्ज सउती, राज्य सचिव, शिक्षा एवं अनुसंधान के संघीय मंत्रालय और एंटिप्रोटॉन एवं आयरन अनुसंधान (एफएआईआर) के नए अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 25 अगस्त, 2015 को नई दिल्ली का दौरा किया

और अपने सहयोगियों के साथ बैठक की।

जर्मनी में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जर्मनी के हमबोल्ड्ट यूनिवर्सिटी, बर्लिन और यूनिवर्सिटी ऑफ लीपजिंग में वर्ष 2015 में 2 अल्प कालिक आईसीसीआर अध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी। जर्मनी के संस्कृत के विद्वान एवं इंडोलॉजिस्ट, डॉ एन्नेटी सच्मीड्चेन को भी 2015 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तीसरे आईजीसी के दौरान, जर्मन पक्ष ने स्टटगार्ट स्थित लिंडन म्यूनियम की ओर से 10वीं शताब्दी में चोरी हुए दुर्गा महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति भारत को लौटाई।

शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा में भारत–जर्मन भागीदारी हेतु तीसरे आईजीसी में जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस (डीएएडी) और भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। वर्तमान में, 11,000 से अधिक भारतीय छात्र जर्मनी में विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि लगभग 800 जर्मन छात्र भारत में अध्ययन कर रहे हैं अथवा अपनी इंटर्नशिप कर रहे हैं।

बर्लिन में 14–16 जनवरी, 2016 को आयोजित खाद्य एवं कृषि वैश्विक फोरम (जीएफएफए) में भाग लेने के लिए कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री श्री राधामोहन सिंह के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने बर्लिन का दौरा किया था।

जर्मनी में भारतीय छात्रों की सुविधा के लिए बर्लिन स्थित भारतीय दूतावास ने 17 दिसंबर, 2015 को एक वेब पोर्टल ू पदकपंदेजनकमदजेहमतउंदलण्वतह की शुरुआत की। इस पोर्टल का उद्देश्य जर्मनी में रहने वाले युवा भारतीय छात्रों को आपस में जोड़ना है। इसके अतिरिक्त, जर्मनी में उच्च शिक्षा की संभावनाएं तलाश रहे भावी भारतीय छात्र भी इस पोर्टल से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

जर्मनी में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (आईसीसीआर) द्वारा तीन अल्प कालिक अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया जारी है।

आयरलैण्ड

संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए न्यूयार्क जाते समय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 23 सितंबर, 2015 को मार्ग में पड़ने वाले आयरलैण्ड का अल्पकालिक आधिकारिक दौरा किया। करीब 60 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा आयरलैण्ड (यूरोप में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था) का यह पहला दौरा था। औपनिवेशिक काल एवं स्वतंत्रता आंदोलन काल को याद करने पर पता चलता है कि भारत के आयरलैण्ड से घनिष्ठ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। इस दौरे से संकेत मिलता है कि भारत –आयरलैण्ड संबंधों को आगे बढ़ाने और आपसी हितों के प्रमुख क्षेत्रों में भागीदारी हेतु आगे की योजनाएं तैयार करने के प्रति आश्वासन हैं।

यात्रा के दौरान, प्रधान मंत्री ने आयरलैण्ड के प्रधान मंत्री एंडा केनी, विदेश मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री के साथ चर्चा की थी। इन्होंने ने आपसी हितों से संबंधित द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। दोनों प्रधान मंत्रियों ने प्रमुख क्षेत्रों जैसे व्यापार एवं निवेश, अनुसंधान एवं नवाचार, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और प्रवासी संपर्क में भारत–आयरलैण्ड के बीच संबंधों में गुणात्मक सुधार हेतु सहमति जताई थी। द्विपक्षीय व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दोनों नेताओं ने एक दूसरे के देश में फ्लाइट संपर्क और पर्यटन रोड शो अधिकार को बढ़ावा दिया। आयरलैण्ड ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थाई सदस्यता और अंतर्राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण शासन प्रणाली के हमारे अनुरोध को समझने और स्वीकार करने में रुचि दिखाई।

23–24 जून, 2015 को दुर्घटनाग्रस्त एअर इंडिया कनिष्क प्लेन की 30वीं स्मारक सेवा में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश राज्यमंत्री जनरल (डॉ) वी के सिंह (सेवानिवृत्त) ने आयरलैण्ड का दौरा किया था। आयरिश कवि, डब्ल्यू बी यीट्स की 150वीं जयंती समारोह के अंश के रूप में, इन्होंने काउंटी स्लोगन के साथ रवीन्द्रनाथ टैगोर की अर्ध–प्रतिमा का अनावरण किया। अपने दौरे के समय और साथ ही 5–6 नवंबर, 2015 को लक्जेमबर्ग में आयोजित एएसईएम सम्मेलन के मौके पर आयरलैंड के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की थी।

आयरलैण्ड के रोजगार, उद्यम एवं नवाचार मंत्री श्री रिचर्ड बर्टन ने अप्रैल, 2015 में आयोजित सेवाओं में वैश्विक नवाचार कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था। 18–22, अक्टूबर 2015 को आयोजित आईसीएएनएन की 54वीं बैठक में भाग लेने के लिए विशेष सचिव (साइबर सुरक्षा) डॉ गुलशन राय ने आयरलैण्ड की यात्रा की थी।

भारतीय निर्यात में 83.34 प्रतिशत (760 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की वृध्दि और निर्यात में 4.51 प्रतिशत (533 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की कमी के साथ भारत और आयरलैण्ड की बीच द्वि पक्षीय व्यापार में वर्ष 2013–14 में 972 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वर्ष 2014–15 में 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार के साथ 23 प्रतिशत की दर से की वृद्धि हुई। द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय दूतावास ने 18 नवबर 2015 को आयोजित आयरलैण्ड भारत व्यापार संघ के वार्षिक भोज कार्यक्रम और 'मेक इन इंडिया' के प्रचार अभियान में सहयोग दिया था।

दोतरफा पर्याटन विस्तार और लोगों का लोगों से सम्पर्क को बढ़ावा देने के लिए आयरलैण्ड को उन देशों की सूची में

सम्मिलित किया गया, जहां, 15 अगस्त 2015 से ईटीवी सुविधा का विस्तार किया गया है। वर्ष के दौरान दो–तरफा पर्यटन में 14 प्रतिशत की वृध्दि हुई। वर्तमान में लगभग 1400 भारतीय छात्र आयरलैण्ड के उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत हैं।

स्थानीय योग संस्थानों और भारतीय समुदाय के सहयोग से डबलिन के सेंट एन पार्क में 21 जून, 2015 को दूतावास ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया था और समाज के सभी वर्गों के लगभग 500 व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

डबलिन में 9 जनवरी, 2016 को भारतीय दूतावास ने प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया था। आयरलैण्ड के ओसीआई/पीआईओ समुदाय के प्रमुख सदस्यों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था। ज्ञान का आदान–प्रदान, नवपरिवर्तन और भारत के सामाजिक एवं विकासात्मक प्रयासों में सहयोग प्रदान करने हेतु और प्रवासी भाइयों के योगदान को प्रोत्साहित करना कार्यक्रम का विषय था।

22–24 जनवरी, 2016 को डबलिन में आयोजित वार्षिक पर्यटन प्रदर्शनी 'हॉलिडे वर्ल्ड' में लंदन स्थित भारतीय पर्यटन कार्यलय ने भाग लिया था। प्रमुख अखबारों और पत्रिकाओं के यात्रा वृत्तांत लेखकों तथा सरकारी अधिकारियों सहित यात्रा एवं पर्यटन उद्योग के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

इटली

वर्ष के दौरान आपसी हितों से संबंधित क्षेत्रों में भारत–इटली के आर्थिक संबंधों में गतिशीलता बनी रही है। मिलान स्थित भारतीय पर्यटन कार्यालय ने एअर इंडिया और पेसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन (पीएटीए) के साथ मिलकर 28 अक्टूबर 2015 को मिलान में ''पीएटीए–भारत व्यापार सम्मेलन–इटली'' नामक रोड शो का आयोजन किया।

फैक्ट्री स्वीकृति परीक्षणों, परीक्षण–पूर्व निरीक्षण एवं प्रशिक्षण को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा इटली के दौरे से, रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति हुई है। फैक्ट्री स्वीकृति परीक्षणों को कार्यान्वित करने के लिए भारतीय नौसेना प्रतिनिधिमण्डल ने 25 अप्रैल, 2015 को मैसर्स, डब्ल्यूएएसएस, लिबोर्नो तथा 12–16 मई, 2015 को मैसर्स कल्जोनी, बोलोग्ना इटली का भी दौरा किया था।

01 सीएनसी ओडी ग्राइंडिंग मशीन के पूर्व–प्रेषण निरीक्षण के लिए भारतीय आर्डिनेंस फैक्ट्री के प्रतिनिधिमंडल ने 5–10 जुलाई, 2015 तक मैसर्स रोबी, वेरोना, 12–18 जुलाई, 2015 तक मैसर्स एमसीएम, मोंटेवार्ची, इटली का भी दौरा किया था।

इटली को 2.062 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भारतीय निर्यात और इटली से भारत में 2.135 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आयात के साथ अप्रैल से सितंबर, 2015 के दौरान भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय व्यापार 4.197 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

150 से अधिक स्कूलों की सहभागिता से 21 जून, 2015 को इटली में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था। अत्यधिक उत्साहवर्धन प्रतिक्रिया प्राप्त हुई और मिशन के सहयोग से पूरे देश में कार्यक्रमों का सिलसिलेवार आयोजन किया गया।

लेजियो क्षेत्र में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए दूतावास के अंदर एवं बाहर आयोजित विभिन्न प्रदर्शनियों, एक क्रिकेट मैदान (इटली में अपने प्रकार का पहला) के निर्माण हेतु पोन्टेनिया की नगर पालिका के साथ सहयोग, नैनोमेटेरियल्स पर भारत–इटली द्विपक्षीय कार्यशाला हेतु सहयोग एवं सहभागिता, रोम के प्रतिष्ठित सीएनआर कैंम्पस में आयोजित नीम 2015 (नेनोस्केल एक्साइटेशंस ऑन इमर्जेंट मटेरियल्य 2015), पुस्तक प्रदर्शन और फैशन शो सहित सूचना एवं संस्कृति के क्षेत्र में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण पहल किए गए थे। दूतावास ने 'सेलेंटो फिल्म फेस्टिवल', 'एशियाटिका फिल्म मीडियल' और पूरी तरह भारतीय फिल्मों को समर्पित 'रिवर टू रिवर इंडियन फ्लोरेंस फिल्म फेस्टिवल जैसे फिल्म महोत्सवों को भी प्रोत्साहित किया था। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य था, इटली वासियों में भारतीय संस्कृति एवं धरोहर के प्रति जागरूकता और रुचि पैदा करना और स्थानीय भारतीय प्रवासियों से दूतावास के संबंधों को और मजबूत करना था।

भारतीय पर्यटन कार्यालय, मिलान और वैग्लियोनी होटल ऋंखलाओं के सहयोग से 13–21 जनवरी, 2016 को रोम और वेनिस में इंडियन फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था।

लक्जेमबर्ग

भारत और लक्जेमबर्ग के बीच घनिष्ठ और मित्रवत संबंध हैं।

जनवरी–जुलाई, 2015 के दौरान भारत और लक्जेमबर्ग के बीच 30.34 मिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। वर्ष 2015 में लक्जेमबर्ग में भारतीय निर्यात 3.58 मिलियन यूरो रहा जबकि लक्जेमबर्ग में भारत में 26.76 मिलियन यूरो का आयात हुआ। भारत से लक्जेमबर्ग को निर्यात की गई मुख्य वस्तुओं में, अभियांत्रिकी उत्पाद, टेक्सटाइल्स एवं गारमेंट्स और केमिकल्स थे। लक्जेमबर्ग से भारत में आयात की गई मुख्य वस्तुओं में अभियांत्रिकी से संबंधित सामान, बेस मेटल्स और स्टोन आर्टिकल्स थे।

महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था मंच में भाग लेने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने 18–19 जुलाई 2015 को लक्जेमबर्ग का दौरा किया था। 28–29 सितंबर 2015 को नई दिल्ली में 14वें भारत–बेल्जियम–लक्जेमबर्ग आर्थिक संघ

(बीएलईयू) के संयुक्त अभियान का आयोजन किया गया था। भारतीय पक्ष का नेतृत्व वाणिज्य सचिव ने तथा लक्जेमबर्ग का नेतृत्व वहां के उप–महासचिव श्री लियो फेवर ने किया था।

अप्रैल 2015 में लक्जेमबर्ग आधारित कार्गो एयर लाइंस, कार्गोलक्स ने ओमान एयर के सहयोग से ओमान के रास्ते लक्जेमबर्ग से चेन्नई तक की पूर्ण माल भाड़ा सेवाएं शुरू की है। इसने 11 अगस्त, 2015 से चेन्नई के साथ सीधी एयर कार्गो लिंक की भी शुरूआत की है।

दो तरफा पर्यटन विस्तार और लोगों का लोगों से संपर्क को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रानिक टूरिस्ट वीजा (ई–टीवी) सुविधा का लक्जेमबर्ग तक विस्तार किया गया है।

4–7 नवंबर, 2015 तक लक्जेमबर्ग में आयोजित एशिया – यूरोप विदेश मंत्रियों की 12वीं बैठक में विदेश राज्य मंत्री, जनरल (सेवानिवृत्त) वी के सिंह ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। इन्होंने लक्जेमबर्ग के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की थीं।

मोनाको

भारत और मोनाको के बीच द्विपक्षीय संबंध सौहार्दपूर्ण और मित्रवत् हैं। दोनों देशों ने व्यापार एवं पर्यटन, खेल, शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विस्तार की इच्छा व्यक्त की है।

दोनों तरफ से पर्यटन का विस्तार करने और लोगों का लोगों से संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2015 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक – टूरिस्ट वीजा (ई–टीवी) सुविधा का मोनाको तक विस्तार किया गया है।

नीदरलैंड

भारत और नीदरलैंड के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति हुई है। हमारे प्रधान मंत्री के निमंत्रण पर डच प्रधान मंत्री, मार्क रुटे ने 5 – 6 जून, 2015 को भारत का आधिकारिक दौरा किया। विदेश व्यापार एवं विकास सहयोग मंत्री, श्रीमती लिलीयोने प्लोमेन, कृषि मंत्री श्री शेरॉन डिजेस्कमा, वरिष्ठ अधिकारी और 80 से अधिक डच कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधि–मंडल भी डच प्रधान मंत्री के साथ भारत आया था। प्रधान मंत्री रुटे ने प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी से अकेले में बैठक की और दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी की थी।

डच प्रधान मंत्री के दौरे से द्विपक्षीय संबंधों में सुधार लाने और संबंधों की सभी संभावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए आधार मिला। बंदरगाहों, बुनियादी ढ़ांचों, अंतर्देशीय जलमार्गों, कृषि, डेयरी, कौशल विकास, स्मार्ट सिटीज़, स्वच्छ गंगा मिशन इत्यादि सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारे सामर्थ्य और संपूरकताओं का लाभ उठाने के लिए दौरे के समय एक स्पष्ट कार्य योजना के अंतर्गत संयुक्त विज्ञप्ति के अंश के रूप में द्विपक्षीय सहयोग हेतु नीतिनिर्धारण पर समझौता हुआ था।

दोनों देशों के बीच व्यापार एवं निवेश सहयोग, हमारी द्विपक्षीय वचनबद्धता का महत्वपूर्ण घटक रहा है। 2015 के प्रथम आठ महीनों के दौरान, नीदरलैंड में भारतीय निर्यात में 13.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि सकल द्विपक्षीय व्यापार में 11.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2015 – 16 (अप्रैल – जून) के दौरान नीदरलैंड से भारत में आने वाली एफडीआई इक्विटी 625 मिलियन अमेरिकी डॉलर रही। वित्तीय वर्ष 2014 – 15 के दौरान कुल एफडीआई अंतर्वाह 3.436 बिलियन अमेरिकी डॉलर रही। अप्रैल 2000 से जून 2015 की अवधि के दौरान नीदरलैंड से भारत में कुल अंतर्वाह एफडीआई 15.323 बिलियन अमेरिकी डॉलर रही, जो कुल अंतर्वाह में 6 प्रतिशत के योगदान के साथ इसे भारत में एफडीआई अंतर्वाह का 5वां सबसे बड़ा देश बनाता है। वित्त वर्ष 2015–16 (अप्रैल – अगस्त) के दौरान, नीदरलैंड भारत का 30वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा और जर्मनी, यू.के., बेल्जियम, इटली और फ्रांस के बाद यूरोपीय संघ का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा।

सचिव (पश्चिम) श्री नवतेज सिंह सरना और नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय की महासचिव श्रीमती रेनी जॉन्स – बॉस ने 4 मई, 2015 को हेग में भारत – नीदरलैंड विदेश सेवा परामर्श का आयोजन किया था। भारत और नीदरलैंड के बीच आतंकवाद नियंत्रण हेतु संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी) की पहली बैठक 19 जून, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

भारत और नीदरलैंड के बीच स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग हेतु संयुक्त कार्य दल की पहली बैठक 28 – 30 सितंबर, 2015 को नीदरलैंड में आयोजित की गई। कंपनियों, शिक्षा संस्थानों और हेग नगर पालिका के प्रतिनिधियों के 17 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने हेग के डिप्टी मेयर के नेतृत्व में 13 – 17 अक्तूबर, 2015 तक नई दिल्ली और हैदराबाद का दौरा किया था। इस मिशन में आईटी और साइबर सुरक्षा पर जोर दिया गया। दौरे के समय अनेक करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

भारतीय नौसेना पोत 'तरंगिणी' ने सेल (एसएआईएल) एम्सटर्डम – 2015 में भाग लिया था।

सभी डच पासपोर्ट धारकों को भारतीय टूरिस्ट वीजा ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 15 अगस्त 2015 से इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट वीज़ा (ई–टीवी) का नीदरलैंड तक विस्तार किया गया।

14 दिसंबर, 2015 को जेट एयरवेज़ ने घोषणा की कि वह 27

मार्च 2016 से अपने गृह केंद्रों मुंबई और नई दिल्ली से एम्सटर्डम आने जाने के लिए एक – एक नॉन स्टॉप फ्लाइट्स और साथ–साथ कनाडा के टोरंटो तक एक नॉन स्टॉप फ्लाइट का दैनिक प्रचालन करेगा।

दूतावास ने हेग स्थित गांधी केंद्र में 9 जनवरी 2016 को 'प्रवासी भारतीय दिवस 2016 का आयोजन किया था।

हेग के डिप्टी मेयर, श्री कार्स्टेन क्लेन ने छः सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ 21 – 28 जनवरी, 2016 तक भारत का दौरा किया था।

गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए आईसीसीआर द्वारा प्रायोजित कत्थकली नृत्य मंडली श्री नंदकुमारन नोयर के नेतृत्व में 25 – 29 जनवरी 2016 को नीदरलैंड का दौरा किया।

पुर्तगाल

व्यापार एवं व्यावसायिक संबंधों के साथ उद्यमों को प्रमुखता देते हुए पुर्तगाल और भारत बेहतर समकालीन विकास हेतु साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं।

नालंदा विश्व विद्यालय की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर 9 अक्तूबर 2015 को हस्ताक्षर कर पुर्तगाल इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला यूरोपीय देश और चौथा नॉन ईस्ट एशिया समिट (ईएएस) देश बन गया है।

पहले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सीटीटी कॉरियोज डी पुर्तगाल ने 21 जून, 2015 को स्मारक पोस्ट कार्ड जारी किया।

लिस्बन स्थित भारतीय दूतावास ने दोनों तरफ के व्यापार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नवंबर, 2015 में दो व्यापार सम्मेलन आयोजित किए थे। पुर्तगाल में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए दूतावास ने वर्ष भर अनेक कार्यक्रम भी आयोजित किए। 23 सितंबर 2015 को दूतावास द्वारा हिंदी दिवस का आयोजन किया गया था।

वर्ष 2015 के दौरान भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट वीज़ा (ई–टीवी) सुविधा का पुर्तगाल तक विस्तार किया था।

सैन मैरिनो

भारत और सैन मैरिनो के बीच सौहार्द पूर्ण संबंध हैं। दोनों देश अपने के पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए इच्छुक हैं जो कि सैन मेरिनो की जीडीपी में 50 प्रतिशत से भी अधिक का योगदान करता है। बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और मिट्टी के बरतनों का उद्योग यहां के उद्योग के अन्य मुख्य क्षेत्र हैं।

सैन मैरिनो ने दोहरा कराधान करार (डीटीएए) और द्विपक्षीय निवेश विस्तार तथा दोनों देशों के बीच कर से संबंधित सूचनाओं के आदान – प्रदान से संबंधित सुरक्षा करार (बीआईपीए) को मंजूरी दे दी है।

पर्यटन को बढ़ावा देने और लोगों का लोगों से संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से भारत ने वर्ष 2015 के दौरान सैन मैरिनो तक इलेक्ट्रॉनिक – टूरिस्ट वीज़ा विस्तार का प्रस्ताव किया था।

स्पेन

वर्ष 2015 भारत और स्पेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों में घनिष्ठता का साक्षी है। स्पेन के विदेश मंत्री, श्री जोस गार्सिया – मार्गलो द्वारा 27 अप्रैल, 2015 में भारत दौरे के समय राजनैतिक स्तर पर भी इस बात पर जोर दिया गया; विगत 43 वर्षों में यह अपने प्रकार का पहला दौरा था। इस दौरे के समय, भविष्य में सहयोग हेतु प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने के लिए दोनों देशों ने एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की थी। विदेश मंत्री ने स्पेन के विदेश मंत्री से मुलाकात की और व्यापार, शहरी विकास, अक्षय ऊर्जा, रक्षा सहयोग, आतंकवाद नियंत्रण, सुरक्षा और आपसी हितों से संबंधित क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की।

वर्ष के दौरान द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में भी मजबूती आई। जनवरी 2015 में स्पेन के रक्षा मंत्री, श्री पेड्रो मोरेंस के भारत दौरे के बाद, स्पेन के रक्षा सचिव, श्री पेड्रो आर्गुलेस सलवेरिया ने भी 27 और 28 सितंबर, 2015 तक भारत का दौरा किया। उन्होंने रक्षा मंत्री से भेंट की और 27 नवंबर 2015 को रक्षा सहयोग हेतु भारत स्पेन संयुक्त कार्यदल की पहली बैठक आयोजित की गई थी।

अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल है असैनिक परमाणु सहयोग करार हेतु समझौता वार्ता की पुनः शुरूआत और सितंबर 2015 में आयोजित उद्घाटनात्मक सुरक्षा नीति वार्ता। स्पेन–इंडियन काउंसिल फाउंडेशन ने दोनों देशों की सिविल सोसाइटियों के साथ अनेक वार्ताएं आयोजित की इस में शामिल था विश्व स्तरीय भू–आर्थिक, रक्षा एवं सुरक्षा चुनौतियों पर विचारक समूह का सम्मेलन, नेतृत्व उद्यमिता और सामाजिक प्रभाव जैसे मुद्दों पर पर महिला संवाद।

भारतीय निर्यात में हुई वृद्धि से पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में वर्ष, 2015 में वाणिज्यिक मंच पर द्विपक्षीय व्यापार आंकड़ों में वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल – अक्तूबर, 2015 के दौरान, 3.46 प्रतिशत की कमी के साथ स्पेन का भारत में निर्यात 697 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि 2.65 प्रतिशत की वृद्धि के साथ स्पेन में भारतीय निर्यात 1.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, इस प्रकार

कुल व्यापार लगभग 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

मैड्रिड में 13 – 15 अक्तूबर 2015 तक रसायन और फार्मास्यूटिकल उद्योग पर आयोजित सबसे बड़े व्यापार मेले में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और दवा संघटकों (सीपीएचआई वर्ल्डवाइड) के सम्मेलन में वाणिज्य सचिव ने उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। 273 कंपनियों द्वारा भारतीय फार्मा उद्योग के प्रतिनिधित्व के साथ इसमें हमारी व्यापक भागीदारी रही।

अप्रैल, 2015 में जारी संयुक्त समझौता विज्ञप्ति के अनुपालन में, दोनों देशों के बीच राजनैतिक संबंधों की स्थापना के 60 वर्षों के स्मरण में भारत और स्पेन ने वर्ष 2016 के लिए कार्यक्रमों का कैलेंडर तैयार करने हेतु अपने कोर ग्रुप का गठन किया। भारत और स्पेन की योजना है कि इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में कार्यक्रमों की श्रृंखला के रूप में समारोह के रूप में मनाया जाए।

स्पेन, 21 जून 2015 को आयोजित सबसे उत्साहपूर्ण समारोह, पहले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का भी गवाह बना।

नववर्ष संगीत समारोह में 9 जनवरी 2016 को डॉ. एल सुब्रमण्यम गायक समूह के साथ केस्टिला बाईलियोन के सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। भारत स्पेन राजनैतिक संबंध समारोहों की 60वीं वर्ष गांठ के लिए आधिकारिक लोगो को 26 जनवरी 2016 को पहली बार प्रदर्शित किया गया था।

यूनाइटेड किंगडम

भारत के यूनाइटेड किंगडम के साथ अद्वितीय संबंध हैं और 12–14 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री की यूनाइटेड किंगडम यात्रा से 11 वर्ष पुरानी कार्यनीतिक साझेदारी में काफी सुधार हुआ। वर्ष 2006 के बाद एक भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा किया गया पहला आधिकारिक द्विपक्षीय दौरा था। यह साझेदारी के सभी महत्वपूर्ण घटकों को शामिल करते हुए यह प्रधानमंत्री का मैत्रीपूर्ण दौरा कार्यक्रम था जिसमें यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कैमरुन के साथ चर्चा, यूनाइटेड किंगडम की महारानी, सांसदों और बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों के साथ विचार विमर्श, लंदन शहर को संबोधन और व्यावसायिकों के साथ विचार विमर्श शामिल था।

इस दौरे के दौरान, दोनों नेताओं ने भारत की अग्रणी विकास परियोजनाओं जैसे अवसंरचना निर्माण, स्मार्ट सिटीज, स्वच्छ भारत और सवच्छ ऊर्जा में प्रौद्योगिकी अंतरण और कौशल तथा बराबर भागीदारी के माध्यम से परमाणु, रक्षा तथा साइबर क्षेत्रों के साथ साथ गहन सुरक्षा सहयोग के लिए नवीन सहभागिता पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री कैमरुन ने आतंकवाद का मुकाबला करने और यूएनएससी की सदस्यता, बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण प्रणालियों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में महत्वपूर्ण मताधिकार के माध्यम से वैश्विक निर्णय लेने में भारत को शामिल करने के यूनाइटेड किंगडम के सहयोग को जारी रखने की पुनः पुष्टि की है।

इस दौरे के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा संबंध बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी विजन दस्तावेज की रूपरेखा बनाने; आर्थिक सहयोग, शहरी विकास, शिक्षा, कौशल विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय भागीदारी को गहन बनाने की पहलों को प्रमुखता देते हुए एक संयुक्त वक्तव्य; वैश्विक जोखिमों, और रक्षा, आतंकवाद का विरोध करने साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और संगठित अपराध से निपटने के लिए गहन सहयोग हेतु एक नवीन रक्षा और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा भागीदारी; विकासशील देशों की विकास संबंधी चुनौतियों में सहायता करने के लिए पारस्परिक सामर्थ्य बढ़ाने के लिए अविकसित देशों में सहयोग हेतु भागीदारी; और जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा ऊर्जा की वहनीय एवं सतत आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त वक्तव्य सहित 5 निष्कर्ष दस्तावेज जारी किए गए थे।

उच्चतम स्तर पर आदान प्रदान जारी रखने और भागीदारी को गति प्रदान करने के लिए भारत और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री स्तर पर द्विवार्षिक शिखर वार्ताएं आयोजित करने के लिए सहमत हुए हैं। रणनीतिक भागीदारी में यथेष्ट कदम बढ़ाने के लिए संपूर्ण परमाणु चक्र को चिन्हित करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के साथ एक असैनिक परमाणु सहयोग संबंधी एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस दौरे के दौरान असैनिक परमाणु सहयोग, ऊर्जा, सहयोग, एकीकृत औषधि, शासन में सुधार, परमाणु ऊर्जा भागीदारी हेतु भारत के वैश्विक केंद्र के साथ यूनाइटेड किंगडम का सहयोग, रेलवे में तकनीकी सहयोग, अविकसित देशों में सहयोग हेतु भागीदारी, भारत में यूनाइटेड किंगडम के निवेश हेतु फास्ट ट्रैक तंत्र की स्थापना, व्यवसाय सरलीकरण में सहयोग, कौशल विकास, फसल विज्ञान, जलवायु परिवर्तन, कृषि, रोगाणुरोधी प्रतिरोध और टीका विकास के क्षेत्रों में बारह करारों की घोषणा की गई थी।

प्रधानमंत्री के यूनाइटेड किंगडम के दौरे के दौरान इस क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण पहलों द्वारा सुदृढ़ भारत – यूनाइटेड किंगडम आर्थिक संबंधों को और अधिक सशक्त बनाया गया था। यह सहमति बनी थी कि भारतीय अवसंरचना परियोजनाओं, की पूंजी और विशेषज्ञता को लाभ पहुंचाने में विभिन्न माध्यमों से निवेशों

सिटी ऑफ लंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत सरकार ने लंदन में पहला सरकार पोषित बांड जारी करने के अपने इरादे की घोषणा की और एचडीएफसी, भारती एयरटेल, भारतीय स्टेट बैंक और यस बैंक सहित निजी क्षेत्र की कई हस्तियों ने सिटी ऑफ लंदन के माध्यम से धन जुटाने की अपनी योजनाओं की घोषणा की थी।

प्रधानमंत्री के यूनाइटेड किंगडम यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा पुनर्रारंभ भारत – यूके सीईओ मंच के उद्घाटन बैठक का आयोजन किया गया था। भारतीय और ब्रिटिश कंपनियों के बीच 9.3 बिलियन पाउंड से अधिक के वाणिज्यिक सौदों की घोषणा की गई थी। भारत में यूनाइटेड किंगडम के निवेशों को सरल बनाने के लिए एक फास्ट ट्रैक तंत्र की स्थापना करने और भारतीय अवसंरचना परियोजनाओं के लिए सिटी ऑफ लंदन के माध्यम से वैश्विक निवेशों को सुकर बनाने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश निधि (एनआईआईएफ) के तहत भारत यूनाइटेड किंगडम भागीदारी निधि स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। यूनाइटेड किंगडम ने इंदौर, पुणे और अमरावती में स्मार्ट शहरों के विकास में साझेदारी में अपने सहयोग की घोषणा की है।

वर्ष के दौरान, आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में उच्च स्तरीय आदान – प्रदान में द्विपक्षीय परिचर्चा का आयोजन करने के लिए मई 2015 में विद्युत, कोयला और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री द्वारा किया गया यूनाइटेड किंगडम का दौरा; यूनाइटेड किंगडम से पश्चिम बंगाल में निवेश आकृष्ट करने के लिए जुलाई 2015 में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री का यूनाइटेड किंगडम का दौरा;

प्रधानमंत्री डेविड कैमरन लंदन में भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत (12 नवंबर, 2015) करते हुए।

व्यापार, नवाचार और कौशल के लिए यूनाइटेड किंगडम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साजिद जाविद और यूनाइटेड किंगडम के व्यापार राज्य मंत्री लॉर्ड फ्रांसिस मॉड का सितंबर, 2015 में भारत का दौरा; भारतीय रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं और रेलवे सेक्टर में पारस्परिक सहयोग के क्षेत्रों में निवेश के बारे में विचार विमर्श करने हेतु अक्तूबर 2015 में यूनाइटेड किंगडम के रेल मंत्री का दौरा शामिल हैं।

कोटक महिंद्रा बैंक के श्री उदय कोटक और स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष सर जेरी ग्रिमस्टोन के नेतृत्व में 2 नवंबर 2015 को लंदन में भारत यूनाइटेड किंगडम वित्तीय भागीदारी (आईयूकेएफपी) वार्ता का आयोजन किया गया था। इन चर्चाओं जो भारत के कॉर्पोरेट बांड मार्केट के विकास पेंशन अवसंरचना और भारत के नए दीवालियापन नियमों में सुधार करने पर केंद्रित थीं, में सचिव, आर्थिक कार्य विभाग और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक ने भी भाग लिया।

हमारे रक्षा सचिव और यूके के स्थायी रक्षा सचिव की सह अध्यक्षता में रक्षा परामर्शी समूह (डीसीजी) द्वारा भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित किया जाता है। कार्यकारी संचालन समूह (ईएसजी) ने जुलाई 2015 और रक्षा उपकरण उप समूह (डीईएसजी) ने अक्तूबर 2015 में मुलाकात की, जो इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समानांतर मंच हैं।

प्रधानमंत्री के यूनाइटेड किंगडम दौरे के दौरान रणनीतिक हिस्सेदारी में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य से कदम आगे बढ़ाते हुए एक नई रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा भागीदारी की शुरूआत की गई थी। इसमें रक्षा प्रौद्योगिकियों, नए क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान और विकास तथा 'मेक इन इंडिया' के अंतर्गत देशेज रक्षा परियोजनाओं को शामिल करते हुए कार्य नीतिक क्षमताओं के अंतरण में सक्षम बनने के लिए रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी थी।

वर्ष के दौरान रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय आदान प्रदान में अग्रलिखित शामिल हैं: सितंबर 2015 में रक्षा और सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए हमारे रक्षा राज्य मंत्री द्वारा यूनाइटेड किंगडम का दौरा; जून, 2015 में हमारे थल सेनाध्यक्ष द्वारा यूनाइटेड किंगडम का दौरा; सलीसबरी मैदान प्रशिक्षण क्षेत्र में जून 2015 में भारतीय सेना के 16 कुमायूं रेजीमेंट और ब्रिटिश सेना के 1 राइफल्स के बीच संयुक्त अभ्यास 'अजेय योद्धा 2015'; जुलाई 2015 में रॉयल एयर फोर्स के साथ भारत यूके संयुक्त अभ्यास; जुलाई 2015 में भारतीय नौ सेना द्वारा जल यात्रा प्रशिक्षण पोत आईएनएस तरंगिनी से प्लाइमाउथ, यूनाइटेड किंगडम का दौरा; सितंबर 2015 में यूनाइटेड किंगडम के प्लाइमाउथ में समुद्र में रॉयल नौसैनिक पोत एचएमएस आयरन ड्यूक के साथ संयुक्त अभ्यास 'कोंकण' – 2015 में भारतीय नौ सेना जलपोत आईएनएस त्रिकंड की सहभागिता; और यूनाइटेड किंगडम में रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस सर्विसेज और प्वाइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में भारतीय अधिकारियों के प्रशिक्षण सहित शिक्षा सेवा अधिकारियों तथा राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, देहरादून और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन में ब्रिटिश अधिकारियों का प्रशिक्षण शामिल है।

दोनों देशों के शिक्षा मंत्रियों की अध्यक्षता वाले भारत यूनाइटेड किंगडम शिक्षा मंच द्वारा शिक्षा क्षेत्र में उच्च स्तरीय सहयोग को आगे बढ़ाया जाता है। अप्रैल 2006 में शुरू किए गए पारस्परिक लाभ के मुख्य सिद्धांत के बारे में दोनों सरकारों द्वारा समर्थित बहु–हितधारक भागीदारी कार्यक्रम यू के – भारत शिक्षा और अनुसंधान पहल (यूकेआईईआरआई) से इस क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाया जाता है। भारत और यूनाइटेड किंगडम दोनों से प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन पाउंड वार्षिक निवेश से अप्रैल 2016 से यूकेआईईआरआई के चरण 3 का क्रियान्वयन किया जाना है। अनुसंधान भागीदारी को गति प्रदान करने, कौशल विकास और नेतृत्व विकास पर यूकेआईईआरआई का मुख्य जोर होगा।

प्रधानमंत्री के यूनाइटेड किंगडम दौरे के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घोषणाओं में i) वर्ष 2016 को भारत यूके शिक्षा, अनुसंधान और नव प्रवर्तन वर्ष घोषित करना; ii) ज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत अगले दो वर्षों में 100 यूके एकेडमिक्स का भारतीय शैक्षिक संस्थानों में पढ़ाना; iii) 25000 यूके छात्रों को शिक्षा और इंटर्नशिप हेतु भारत का दौरा; तथा 1000 यूके के छात्रों को टीसीएस द्वारा भारत में आईटी में प्रशिक्षित किया जाना और iv) स्कूलों के बीच यथार्थ भागीदारी शामिल है। कौशलों में भागीदारी पर भी सहमति बनी जिसके अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम मुख्य क्षेत्रों में नए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करेगा जिसकी शुरूआत पुणे में स्व प्रेरण कौशल केंद्र शुरू करके होगी।

स्वास्थ्य सहयोग के क्षेत्र में अनुसंधान और इंटीग्रेटेड मेडिसिन की शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रधान मंत्री के दौरे के समय आयुष मंत्रालय और यूनाइटेड किंगडम के अग्रणी संस्थान लंदन हॉस्पिटल ऑफ इंटीग्रेटिड मेडिसन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण पहलों में; 1. भारत यूके संयुक्त वैक्सीन विकास सहयोग शुरू करना 2. जीनोमिक स्तर पर एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोधक संबंधी कार्यनीतिक दल की स्थापना 3. चंडीगढ़ में

किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल स्थापित करने के लिए किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल एनएचएस फाउंडेशन ट्रस्ट और इंडो यूके हेल्थ केयर प्रा. लि. के बीच करारों पर हस्ताक्षर किया जाना शामिल है। जैव – प्रौद्योगिकी विभाग और एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध संबंधी यूके सरकार की अनुसंधान परिषदों की पहल के भाग के रूप में वर्ष 2016 में लंदन में आयोजित होने वाली वैश्विक शिखर वार्ता में भारत और यूके भी अपनी वैज्ञानिक विशेषज्ञता का योगदान देने के लिए सहमत हुए।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी सहयोग भारत – यूके सहयोग का सर्वाधिक तेजी से बढ़ता घटक है। संयुक्त अनुसंधान, क्षमता निर्माण और भारत यूके एसएण्डटी सहयोग नेतृत्व स्थापन के लिए वर्ष 2014 में न्यूटन भाभा निधि की स्थापना की गई थी। वर्ष 2015 के दौरान लगभग ख72 मिलियन के निवेश से आज संयुक्त निवेश जो वर्ष 2008 में 1 मिलियन पाउंड से कम था। आज बढ़कर 200 मिलियन पाउंड से अधिक हो गया है। प्रधानमंत्री के यूनाइटेड किंगडम दौरे के समय यह घोषणा की गई थी कि यूनाइटेड किंगडम दिल्ली में आयोजित होने वाले प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2016 में भागीदार होगा। फसल विज्ञान, जलवायु परिवर्तन, कृषि अनुसंधान, वैक्सीन तैयार करने एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोधन के क्षेत्रों में सहयोग हेतु करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे। नए महत्वपूर्ण निवेशों में स्वच्छ ऊर्जा, जल सुरक्षा और कृषि नाइट्रोजन में यूके इंडिया आभासी केंद्र शामिल हैं।

उच्च स्तरीय आदान प्रदान में मई 2015 में माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री के नेतृत्व में जैव – प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधिमंडल का यूके का दौरा और ऊर्जा संबंधी द्विपक्षीय सहयोग के सुदृढ़ीकरण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन करार हेतु सामान्य आधार बढ़ाने के लिए सितंबर 2015 में यूके के ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन सचिव, अंबर रड का दौरा शामिल है।

भारत और यूनाइटेड किंगडम प्रतिवर्ष नियमित आधार पर बैठक करने वाले संयुक्त कार्य दलों के संस्थापित तंत्र के तहत आतंकवाद से निपटने और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग करते हैं। नई रक्षा और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा भागीदारी शुरू होने के साथ भारत और यूनाइटेड किंगडम आतंकवाद से निपटने और साइबर सुरक्षा में अपने सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर सहमत हुए। प्रधान मंत्री के यूके दौरे के समय दोनों नेताओं ने आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने और आईएसआईएस, अलकायदा, लश्कर–ए–तोयबा, हिजबुल मुजाहिद्दीन हक्कानी और संबद्ध दलों सहित आतंकी नेटवर्कों को बिच्छिन्न करने की अपनी प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि की। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद संबंधी सम्मेलन को जल्दी ही अंतिम रूप देने में सहयोग करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों पक्ष साइबर अपराध और साइबर फोरेंसिक सहयोग, टेलीकॉम परीक्षण और सुरक्षा प्रमाण ान, नया भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित करने और सीईआरटी – सीईआरटी समझौता ज्ञापन के शीघ्र निष्पादन संबंधी समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप देने के लिए कार्य करके साइबर सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत हुए।

भारत और यूनाइटेड किंगडम दीर्घकालीन ऐतिहासिक संबंधों और यूनाइटेड किंगडम में 1.5 मिलियन सशक्त भारतीय प्रवासियों द्वारा अभिलक्षित अद्वितीय सांस्कृतिक संबंधों के साझेदार हैं। यूनाइटेड किंगडम में 21 जून 2015 को भारत के उच्चायुक्त द्वारा लंदन में, भारत के महावाणिज्य दूतावास, एडिनबरा में और भारत के महा वाणिज्य दूतावास, बर्मिंघम में तथा अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं में प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया। योग के लाभों को प्रयोग द्वारा स्पष्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट क्रांसबेंच पीयर, लॉर्ड बिलिमोरिया ने 23 जून 2015 को यूनाइटेड किंगडम संसद में प्रथम वार्षिक संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोहों का नेतृत्व किया। प्रधान मंत्री कैमरून और यूनाइटेड किंगडम के विदेश एवं राष्ट्रमंडल कार्यालय मंत्री हयूगो स्वायर ने इस अवसर के समर्थन में संदेश भेजे।

यूके में भारतीय प्रवासियों ने ब्रिटिश जीवन और समाज के प्रति महत्वपूर्ण योगदान किया है और यह भारत–यूनाइटेड किंगडम संबंधों को आगे बढ़ाने में जीवंत पुल का काम करता है। प्रध ाान मंत्री ने प्रधान मंत्री डेविड कैमरून के साथ 13 नवंबर 2015 को वेम्बले स्टेडियम में भारतीय प्रवासी कार्यक्रम में 60,000 से अधिक लोगं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के दौरे के समय यह घोषणा की गई कि भारत की स्वतंत्रता की 70वीं वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में वर्ष 2017 को भारत – यूके सांस्कृतिक वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।

नवंबर 2015 में प्रधान मंत्री के यूके दौरे से उत्पन्न द्विपक्षीय सहयोग के आवेग को बनाए रखने के लिए यूके के व्यापार, नव प्रवर्तन और कौशल राज्य सचिव साजिद जाविद ने 9–11 दिसंबर 2015 तक भारत का दौरा किया। मंत्री साजिद जाविद और भारत की मानव संसाधन विकास मंत्री ने 'यूके–भारत शिक्षा, अनुसंधान और नव प्रवर्तन' के रूप में वर्ष 2016 की शुरूआत की। इस दौरे के समय ब्रिटिश मिडलैंड्स को नव प्रवर्तन और विनिर्माण हब के रूप में प्रवर्तित करने के लिए 9 दिसंबर 2015 को फिक्की के साथ साझेदारी में 'मिडलैंड्स इंजिन' पहल शुरू की गई थी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन और यूनाइटेड किंगडम

के विश्वविद्यालय और विज्ञान राज्य मंत्री जो जांनसन (जिन्होंने 9–11 दिसंबर 2015 तक नई दिल्ली, मुंबई और बंगलुरु का दौरा किया था) ने यूके के भारत के 2016 शिखर सम्मेलन और नॉलिज एक्सपो में साझेदार देश के रूप में भाग लेने की संयुक्त रूप से घोषणा की। जो जांनसन ने 2021 तक यूनाइटेड किंगडम के न्यूटन निधि में बढ़ोत्तरी करने और न्यूटन भाभा निधि के अंतर्गत नवीन अनुसंधान हिस्सेदारियों की भी घोषणा की।

संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ और नांटिगंम सिटी कौंसिल के बीच द्विपक्षीय व्यापार, नव प्रवर्तन और आर्थिक सहयोग को बढावा देने के लिए 11 दिसंबर 2015 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की बैठक (सीएचओजीएम)

विदेश मंत्री (ईएएम) ने 27–28 नवंबर 2015 को माल्टा में आयोजित राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक में (सीएचओजीएम) भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

■ ■

27–28 नवम्बर, 2015 को माल्टा में आयोजित राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की सामूहिक तस्वीर

8

अमेरिका

कनाडा

हाल के वर्षों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। वर्तमान द्विपक्षीय संबंध उच्च–स्तरीय कार्यकलापों पर आधारित हैं जिनमें राजनीतिक, सुरक्षा, व्यापार और आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री द्वारा अप्रैल, 2015 में की गई यात्रा से इन संबंधों में एक नई तेजी आई है।

कनाडा में 19 अक्टूबर 2015 को फेडरल चुनाव में लिबरल पार्टी की जीत के बाद प्रधानमंत्री ने 21 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री ट्रुडो से बात की और एक बधाई पत्र भेजा है। भारत यात्रा के लिए प्रधानमंत्री ट्रुडो को अमांत्रित करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि वे कनाडा में नए सरकार के साथ कार्य करने की उम्मीद रखते हैं।

प्रधानमंत्री की कनाडा यात्रा (14–16 अप्रैल 2015)

प्रधानमंत्री ने ओटावा, टोरंटो और वैंकूवर को कवर करते हुए 14–16 अप्रैल 2015 के बीच कनाडा का दौरा किया। किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने 42 वर्षों में कनाडा की यह पहली एकाकी यात्रा की थी। यात्रा के बाद "नया उत्साह : नए कदम" नाम से जारी संयुक्त बयान में दोनों नेताओं ने एक सामरिक साझेदारी के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार करने और अर्थव्यवस्था, व्यापार और निवेश, असैन्य परमाणु सहयोग, ऊर्जा, शिक्षा और कौशल विकास कृषि, रक्षा और सुरक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और अंतरिक्ष, संस्कृति एवं लोगों के साथ लोगों के संबंधों के लिए द्विपक्षीय सहयोग ठोस उपाय करने के लिए सहमति दर्शाई है।

प्रधानमंत्री ने कनाडा के राजनीतिक, व्यापार और शैक्षिक नेताओं सहित गवर्नर जनरल डेविड जॉनसन, प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर, ओंटारियो की प्रीमियर सुश्री कैथलीन वेन, सुश्री क्रिस्टी क्लार्क, ब्रिटिश कोलंबिया की प्रीमियर और लिबरल पार्टी के नेता, श्री जस्टिन ट्रुडो के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने कनिष्क एयर इंडिया के स्मारक स्थल टोरंटो में प्रधानमंत्री हार्पर के साथ संयुक्त रूप से पुष्पांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कनाडा के पेंशन फंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और अन्य निवेशकों के साथ बातचीत की और टोरंटो में भारतीय मूल के 10,000 लोगों की एक विशाल सभा को संबोधित किया।

यात्रा के प्रमुख परिणामों में कनाडा से यूरेनियम की खरीद पर एक समझौते, बाह्य अंतरिक्ष, रेलवे परिवहन, नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापनों और कौशल विकास पर 13 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया जाना भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री हार्पर ने 12 वीं सदी की मूर्ति 'पैरट लेडी' (बलुआ पत्थर की बनी हुई एक मोर के साथ एक महिला की मूर्ति) भेंट स्वरूप दिया।

कनाडा में भारतीय मूल (पीआईओ) के 12 लाख से अधिक व्यक्ति निवास करते हैं जो देश की आबादी का 3 प्रतिशत से अधिक है। लोगों से लोगों के बीच संबंधों का विस्तार करने के लिए कनाडा की अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री ने कनाडा के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक यात्रा उन्मुक्ति व्यवस्था की घोषणा की। कनाडा के नागरिकों के लिए 10 वर्षों की लंबी अवधि के वीजा की भी घोषणा की गई थी।

अन्य राजनीतिक दौरे

भारत की ओर से, किए गए दौरे हैं :

- श्री धर्मेंद्र प्रधान, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ने 3–6 जुलाई 2015 तक दूसरी भारत कनाडा ऊर्जा वार्ता के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
- श्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 21–27 अगस्त 2015 को कनाडा के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

कनाडा के मंत्रिस्तरीय दौरे हैं:

- वित्त मंत्री, ब्रिटिश कोलंबिया माइकल डी जोंग, ने 6–13 दिसंबर 2015 तक इंडिया (दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई) का दौरा किया।
- ओंटारियो की प्रधानमंत्री, सुश्री कैथलीन वेन ने 28 जनवरी –7 फ़रवरी 2016 तक भारत के लिए एक व्यापार मिशन का नेतृत्व किया और दिल्ली, अमृतसर, हैदराबाद, मुंबई का दौरा किया।

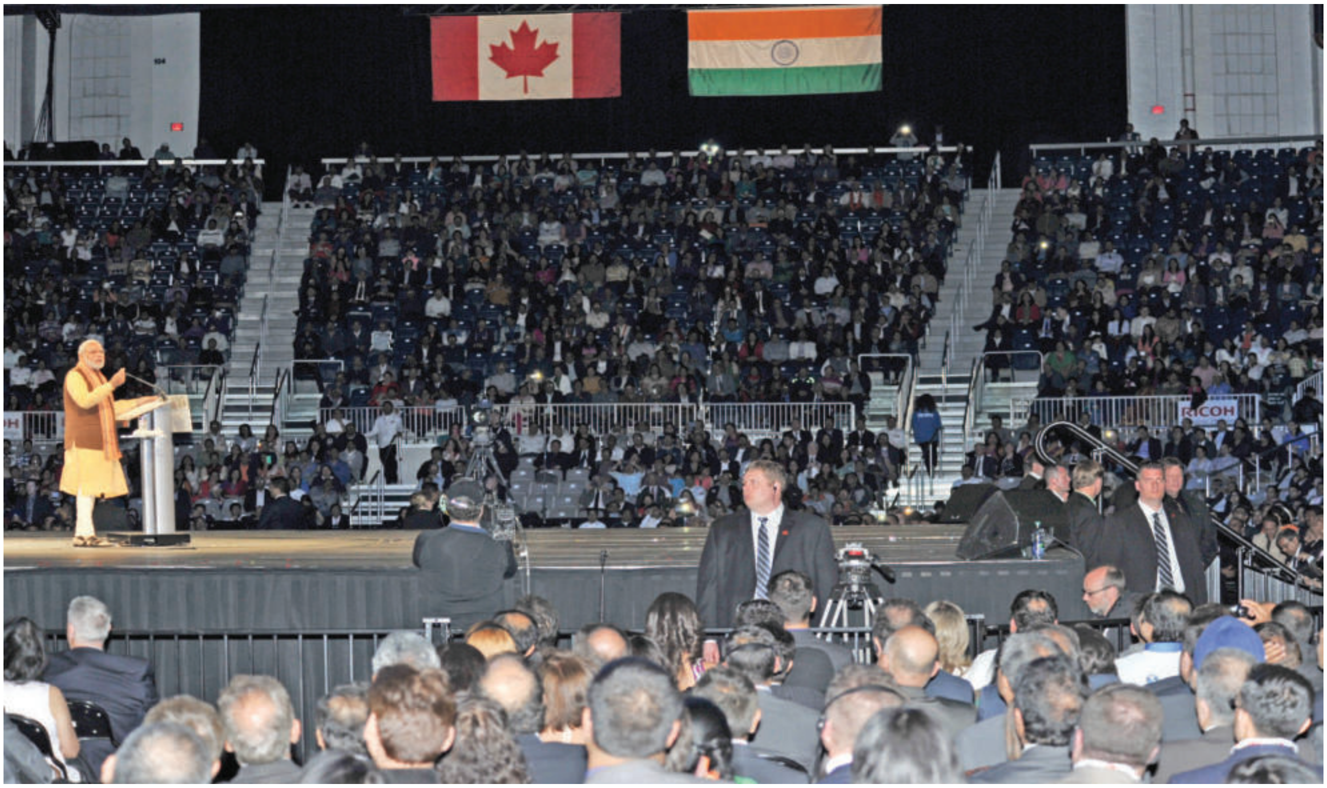

प्रधानमंत्री टोरंटो (15 अप्रैल 2015) में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए।

- प्रिंस एडवर्ड द्वीप के प्रीमियर, वेड मक्लाउचलान, ने 31 जनवरी – 7 फ़रवरी 2016 तक भारत के लिए एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
- लाइल स्टीवर्ट, कृषि मंत्री, कनाडा ने 14–20 फ़रवरी 2016 तक भारत का दौरा किया।

ऊर्जा

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कनाडा एक 'ऊर्जा महाशक्ति' है जहां यूरेनियम, प्राकृतिक गैस, तेल, कोयला, खनिज का बड़ा भंडार उपलब्ध है और जहां जल–विद्युत, खनन, नवीकरणीय ऊर्जा तथा परमाणु ऊर्जा की उन्नत प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं, ऊर्जा क्षेत्र पर हम मुख्य रूप से ध्यान देते रहे हैं।

कैलगरी, कनाडा में 5 जुलाई 2015 को दूसरी भारत कनाडा ऊर्जा वार्ता आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य (प्रभारी) मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान और कनाडा के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्राकृतिक संसाधन मंत्री श्री ग्रेग रिकफोर्ड ने किया। दोनों पक्षों की सरकारें ऊर्जा सहयोग को आगे बढ़ाने और सरकार से सरकार, व्यापार से व्यापार तथा नियामक से नियामक बातचीत से कार्रवाई उन्मुख तरीके से दो मार्गी व्यापार निवेश को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुईं।

इंडियन ऑयल ने प्रशांत उत्तर पश्चिम (पीएनडब्ल्यू), एलएनजी परियोजना, ब्रिटिश कोलंबिया में 10 प्रतिशत प्रतिभागिता हित का अधिग्रहण किया है।

असैनिक परमाणु सहयोग

प्रधानमंत्री की कनाडा यात्रा के दौरान, परमाणु ऊर्जा और मे. केमेको इंक. विभाग, कनाडा ने 2015–2020 के बीच भारत को यूरेनियम अयस्क सांद्र की 3000 मीट्रिक टन की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यूरेनियम की पहली खेप दिसंबर 2015 में भारत में पहुंची।

वियना में सितंबर 2015 में आयोजित आईएईए के आम सम्मेलन के अवसर पर कनाडा के परमाणु सुरक्षा आयोग और भारत के परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) के बीच नियामक सहयोग के लिए व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए थे।

असैनिक परमाणु सहयोग पर तीसरी भारत कनाडा संयुक्त समिति की बैठक 16 अक्टूबर 2015 को मुंबई में आयोजित की गई। बैठक में अन्य बातों के साथ परमाणु सहयोग समझौते और द्विपक्षीय उद्योगों में सहयोग की स्थिति पर चर्चा की गई। कैनेडियन न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज (ओसीआई), कनाडा में परमाणु उद्योग के लिए कनाडा के आपूर्तिकर्ताओं के एक संघ के भारतीय

परमाणु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 12.17 अक्टूबर 2015 के बीच भारत का दौरा किया।

वित्त, व्यापार और उद्योग

वर्ष 2014 में द्विपक्षीय व्यापार 4.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि का रहा। वर्ष 2014 में भारत में कनाडा के 789.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की तुलना में भारतीय एफडीआई 2781.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था। द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए दोनों पक्ष सक्रिय रूप से सीईपीए (व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता) और बीआईपीपीए (द्विपक्षीय निवेश संरक्षण और संवर्धन समझौते) पर बातचीत कर रहे हैं। सीईपीए वार्ता का नौवां दौर नई दिल्ली में 19–22 मार्च 2015 को आयोजित किया गया था। बीआईपीपीए वार्ता का अंतिम दौर 19–20 मई 2015 को आयोजित किया गया।

कनाडा के पेंशन फंड, विशेष रूप से जिसमें प्रबंधन के तहत 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है और जिसने पहले से ही भारत में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है, भारत को लंबी अवधि के निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य मानता है।

निवेश और व्यवसाय के रूप में हरियाणा को बढ़ावा देने और शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य तथा ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग की तलाश करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कनाडा का दौरा (21.27 अगस्त 2015) किया।

निवेश को बढ़ावा देने के लिए अधिकारी स्तर के तीन प्रतिनिधि मंडल 2015 में कनाडा गए। उनका नेतृत्व श्रीमती आराधना जौहरी, सचिव, विनिवेश विभाग, भारत सरकार (07–11 सितम्बर 2015) श्री जगमोहन सिंह, प्रधान सचिव उद्योग, तमिलनाडु (20–22 जुलाई 2015) और डॉ प्रेम एस मीणा, अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार (सितम्बर 2015) ने किया।

अक्टूबर 2015 में, एरिक डाजेनाइस, स्पेक्ट्रम के सहायक उपमंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार ने कनाडा, सेबिट इंडिया समारोह में भाग लेने के लिए बंगलौर का दौरा किया और मुंबई में कनाडा–भारत व्यापार परिषद की वार्षिक व्यापार शिखर बैठक में भाग लिया।

रक्षा

प्रधानमंत्री की कनाडा यात्रा के दौरान जारी संयुक्त वक्तव्य में संबंधित रक्षा स्टाफ कॉलेज प्रशिक्षण में ठंडी जलवायु युद्ध, शांति और भागीदारी में सहयोग की पहचान की गई। एक भारतीय सैन्य अधिकारी ने 01–05 फ़रवरी 2016 को वॉलकार्टियर, क्यूबेक में कनाडा की सेना के शीतकालीन प्रशिक्षण में भाग लिया।

14 जनवरी 2015 को भारत के डी आर डी ओ और कनाडा के रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद के बीच सहयोग के लिए एक मंशा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

भारत–कनाडा संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समिति (जेएसटीसीसी) की 5 वीं बैठक दिनांक 12 जून 2015 को ओटावा में आयोजित की गई थी। यह बैठक प्रो. आशुतोष शर्मा, सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा सुश्री क्रिस्टीन होगन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के उप मंत्री की सह–अध्यक्षता में हुई। जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य, पर्यावरण, मूल संरचना, नवाचार और उद्यमशीलता, ऊर्जा सुरक्षा और नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में की गई कार्य योजना और प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया दिया।

अंतरिक्ष

भारत और कनाडा के बीच 1990 के दशक के बाद से अंतरिक्ष के क्षेत्र में सफल सहकारिता और वाणिज्यिक संबंध जारी हैं, जो मुख्य रूप से अंतरिक्ष विज्ञान, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं और अंतरिक्ष मिशन के लिए समर्थन पर आधारित हैं। भारत ने 28 सितंबरए 2015 को अंतरिक्ष उड़ान प्रयोगशाला, टोरंटो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (एसएफएल, यूटीआईएएस), कनाडा के विश्वविद्यालय से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी–सी30) एनएलएस–14 (ईवी9) नामक एक नैनोसेटेलाइट का प्रक्षेपण किया।

कृषि

श्री आर के सिंहए संयुक्त सचिव, बीज और संस्कृति – अंतरराष्ट्रीय सहयोग ने 4–5 फ़रवरी 2016 तक कृषि पर चौथे भारत–कनाडा संयुक्त कार्य समूह के लिए ओटावा हेतु एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

लोगों का लोगों से संबंध

भारत कनाडा सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए 1 अगस्त 2015 में करार किया गया था।

2 नवंबर 2015 से टोरंटो से नई दिल्ली के लिए एयर कनाडा की सीधी उड़ानें फिर से शुरू की गई हैं।

कोमागता मारू शताब्दी समारोह वैंकूवर में 23–29 मई 2015 में आयोजित किया गया था। श्री प्रमोद जैनए संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय ने आयोजन में भाग लिया।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

ओटावा और मॉन्ट्रियल के भारत–कनाडा संघों के सहयोग से 21

जून 2015 में भारतीय उच्चायोगए ओटावा द्वारा ओटावा में प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया। इसमें ओटावा के मेयरए जिम वाटसन मुख्य अतिथि थे। सीजीआई वैंकूवर और टोरंटो में भी योग दिवस आयोजित किया गया था।

संयुक्त राज्य अमेरिका

भारत और अमेरिका के बीच सुदृढ रणनीतिक साझेदारी है जो साझा मूल्योंए समान सामरिक दृष्टिकोण तथा आर्थिक और प्रणालीगत समानताओं पर आधारित है। शिखर स्तरीय संबंधों और उच्च स्तरीय यात्राओं ने द्विपक्षीय संबंधों में गति को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया है। सितंबर 2015 की अमेरिका के प्रधानमंत्री की दूसरी यात्रा भारत की विकास संबंधी जरूरतों को मजबूती से भारत–अमेरिका साझेदारी के साथ संरेखित करने में सफल रही हैं। 2015 में रक्षा और आंतरिक सुरक्षाए व्यापार और निवेशए शिक्षाए विज्ञान और प्रौद्योगिकीए ऊर्जाए असैन्य परमाणु सहयोग, अंतरिक्ष, शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों से लोगों के संपर्क सहित अन्य क्षेत्रों को कवर करने के लिए भारत–अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग के लगभग सभी क्षेत्रों में सक्रिय कार्यकलाप हुए।

शिखर सम्मेलन सहभागिता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23–28 सितंबर 2015 में संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी दूसरी यात्रा की तथा न्यूयॉर्क और सैन जोसए कैलिफोर्निया राज्य का दौरा किया। सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री का पहला दौरा न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी का हुआ था जबकि जनवरी 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की नई दिल्ली यात्रा हुई।

प्रधानमंत्री ने 28 सितंबर 2015 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित कार्यकलापों के संदर्भ में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात की। इस यात्रा से प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच संबंध सुदृढ हुए और पिछले दो शिखर बैठकों के निर्णयों को मजबूती से लागू करने में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को स्वीकार किया गया।

प्रधानमंत्री ने वित्तीय क्षेत्र पर आधारित एक गोल मेज बैठक में भाग लियाय जिसमें मीडिया, प्रौद्योगिकी एवं संचार और शीर्ष फॉर्च्यून 500 के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी बातचीत की। उन्होंने अनेक प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने दृढ़ता से एक निवेश गंतव्य के रूप में भारत को प्रस्तुत किया और देश के लिए और अधिक निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों को रेखांकित किया। सीईओ ने आर्थिक सुधारों को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की और आगे किए जाने वाले कार्यों के संबंध में अपने सुझाव दिए ।

प्रधानमंत्री की सैन जोस यात्रा का आयोजन भारत–अमेरिकी प्रौद्योगिकी, निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा और मानव संसाधन साझेदारी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से किया गया था। हमारे अपने विकास की प्राथमिकताओं के लिए कैलिफोर्निया की प्रौद्योगिकी, उद्यमए पूंजी और लोगों से लोगों के बीच भारत के साथ संपर्क की सशक्त प्रासंगिकता है। वर्ष 1982 के बाद यह पहली बार हुआ है कि जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिका के पश्चिमी तट की यात्रा की थी।

प्रधानमंत्री ने सैन जोस में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, क्वालकॉम, सिस्को तथा एडोब सहित कई अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने गूगल मुख्यालय का दौरा भी किया और उन्होंने फेसबुक के मुख्यालय में एक टाउन हॉल बैठक में भाग लिया। इन सभी मुलाकातों में बेहतर प्रशासन और तेजी से सेवा प्रदान करने पर ध्यान दिया गया और इसमें डिजिटल प्रौद्योगिकी के महत्व पर चर्चा की गई कि वैश्विक आईटी कंपनियां सभी भारतीयों के जीवन पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव डालने के लिए भारत के साथ कैसे भागीदारी कर सकती हैं।

डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी समारोह में प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारियों / संस्थापकों / शीर्ष वैश्विक कंपनियों से समकक्ष व्यक्तियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लागू करने के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों के बारे में बताया। इसमें राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को जोर शोर से विस्तारित करना शामिल है जिससे 600,000 गांवों तक ब्रॉडबैंड लगाया जाएगा, देश में सार्वजनिक वाई–फाई हॉटस्पॉट के विस्तार और 500 रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक वाई–फाई आरंभ करने के लिए कार्य शुरू करने तथा गूगल के साथ साझेदारी और गांवों एवं कस्बों में सामान्य सेवा केन्द्रों की स्थापना करने की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त, कई अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों ने भारत में संलग्नता बढ़ाने के लिए अपनी योजनाओं की घोषणा की।

प्रधानमंत्री ने अमेरिकी वाणिज्य विभाग और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के सहयोग से अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र पर एक गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया। इसके प्रतिभागियों में अमेरिका के नीति निर्माता, शिक्षाविद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अक्षय ऊर्जा में निवेश करने वाले लोग शामिल थे। उन्होंने टेस्ला मोटर्स का भी दौरा किया। विकास के लिए हरित मार्ग का अनुसरण करने के लिए भारत के संकल्प को ध्यान में रखते हुए और भारत के ऊर्जा क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका बढ़ाने के लिए ये मुलाकातें भारत की जरूरतों तथा अमेरिका की क्षमताओं के बीच का संबंध अमेरिकी वार्ताकारों को बताने में सफल रही हैं।

प्रधानमंत्री ने नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ सॉफ्टवेयर एंड

प्रधानमंत्री सैन जोस (26 सितम्बर 2015) की अपनी यात्रा के दौरान सैन जोस के डिजिटल इंडिया डिनर में।

प्रधानमंत्री ने सैन जोस (27 सितंबर 2015) की अपनी यात्रा के दौरान फेसबुक के मुख्यालय का दौरा किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर न्यूयार्क में राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ मुलाकात की

सर्विस कम्पनीज (नैसकॉम) द्वारा समन्वित और टीआईई (द इंडस एन्त्रेप्रेनोयर्स) और आईआईएम अहमदाबाद के सीआईआईई ;नवाचार और उद्यमिता केन्द्र) के साथ आयोजित एक समारोह को भारत–अमेरिका स्टार्टअप कनेक्ट 2015 को संबोधित किया, जिसमें 36 स्टार्टअप ने भारत की ओर से प्रदर्शनी में भाग लिया। ये बातचीत भारत में स्टार्टअप क्रांति शुरू करने और सिलिकॉन वैली में पारिस्थितिकी तंत्र से लाभ पाने के उद्देश्य से की गई। प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने के लिए सात समझौता ज्ञापनों (एमओयू) / आशय का पत्रों (लोइस) पर हस्ताक्षर किए गए।

प्रधानमंत्री ने अप्रवासी भारतीयों के साथ भी बातचीत की। इस विचार के साथ कि 30 लाख मजबूत भारतीय अमेरिकी समुदाय समग्र द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं, व्यक्तियों का व्यक्तियों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था।

द्विपक्षीय स्तरीय अन्य शिखर वार्ताएं

प्रधानमंत्री ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस की यात्रा के दौरान कॉप–21 के मौके पर राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात की। जलवायु परिवर्तन के एजेंडे के अलावा, दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सामरिक साझेदारी को गहरा करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की।

राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 10 नवंबर, 2015 को प्रधानमंत्री को फोन पर दीवाली की बधाई संप्रेषित की, और जी–20 शिखर सम्मेलन तथा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, एवं पेरिस जलवायु सम्मेलन के आगे वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय सहयोग और प्रमुख क्षेत्रों में किए जा रहे संयुक्त प्रयासों की समीक्षा की। दोनों नेताओं के बीच सुरक्षित हॉटलाइन पर बात करने का यह पहला मौका था। प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच हॉटलाइन स्थापित करने का निर्णय जनवरी 2015 में राष्ट्रपति ओबामा की यात्रा के दौरान लिया गया था।

प्रधानमंत्री ने 8 दिसंबर 2015 को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने टेलीफोन पर बात की और दोनों नेताओं ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित रचनात्मक कार्यों के माध्यम से पेरिस सम्मेलन में विकासशील देशों की प्रगति में बाधा के बिना चर्चा के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने सैन बनारडिनो शूटिंग में लोगों की मौतों पर भी अपनी संवेदना व्यक्त की। 16 दिसंबर 2015 को राष्ट्रपति ओबामा ने फिर से फोन पर प्रधानमंत्री के साथ पेरिस में जलवायु समझौते को प्राप्त करने में उनके नेतृत्व के लिए उसे धन्यवाद करने के लिए बात की थी। प्रधानमंत्री ने यहां भी सान बर्नार्डिनो शूटिंग में हुए जीवन के नुकसान के लिए अपनी संवेदना व्यक्त की। राष्ट्रपति ओबामा ने 16 दिसंबर 2015 को फिर से फोन पर प्रधानमंत्री के साथ उनके नेतृत्व में पेरिस में जलवायु समझौते को प्राप्त करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

पहली सामरिक और वाणिज्यिक वार्ता

जनवरी 2015 में अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा की भारत यात्रा के दौरान, सामरिक और वाणिज्यिक वार्ता में द्विपक्षीय सामरिक वार्ता का विस्तार करने पर सहमति हुई। सामरिक और वाणिज्यिक वार्ता (एस एंड ईडी) पर पहली बैठक दिनांक 22 सितम्बर 2015 को वॉशिंगटन डीसी में आयोजित की गई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एस एंड सीडी के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। प्रतिनिधिमंडल में विद्युतए कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीयूष गोयल और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) निर्मला सीतारमण राज्य मंत्री शामिल थे। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री जॉन केरीए वाणिज्य सचिव प्रिट्जकर और ऊर्जा सचिव अर्नेस्ट मोनिज शामिल थे।

सामरिक सहित अन्य रक्षा और सुरक्षाय ऊर्जा और पर्यावरणय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व अंतरिक्षय स्वास्थ्यए शिक्षा और मानव विकासय तीसरे देश की संलग्नताय अर्थव्यवस्था और वित्तय व्यापार और निवेश आदि विभिन्न मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चाएँ आयोजित की गईं। एक संयुक्त वक्तव्य के साथ ही आतंकवाद से मुकाबला करने पर एक संयुक्त घोषणा जारी की गई थी।

भारत–अमेरिका ऊर्जा वार्ता (16–18 सितंबर 2015) की अधिकारी स्तरीय उप समूह की बैठकय स्वास्थ्य सचिव स्तर की भारत–अमेरिका वार्ता (17–18 सितम्बर, 2015); ऊर्जा मंत्रिस्तरीय भारत–अमेरिका वार्ता (21 सितंबर 2015); भारत–अमेरिका सीईओ फोरम (21 सितंबर 2015); जलवायु परिवर्तन पर सचिव स्तर की भारत–अमेरिका संयुक्त कार्य समूह (21 सितंबर 2015) की बैठकें एस एंड सीडी से पहले हुईं।

2015 में अन्य प्रमुख आदान प्रदान

2015 में दोनों ओर से अनेक उच्च स्तरीय दौरों का आयोजन किया गया। भारत के महत्वपूर्ण मंत्रिस्तरीय दौरों में शामिल हैं: परिवहन सचिव एंथनी फॉक्स (07–13 अप्रैल 2015); रक्षा सचिव एश्टन कार्टर (02–04 जून 2015); संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत और राष्ट्रपति ओबामा के मंत्रिमंडल की सदस्य सामन्था पावर (18–20 नवम्बर 2015)।

कांग्रेस सदस्य डेविड मैककिनले (रिपब्लिकन–वेस्ट वर्जीनिया) ने कांग्रेस की सदस्य मिशेल ग्रष्म (डेमोक्रेट, न्यू मैक्सिको) और कांग्रेसी ट्रेंट केली (रिपब्लिकन - मिसिसिप्पी) के साथ

16-18 अक्टूबर 2015 को भारत का दौरा किया। इसके अलावाए कांग्रेस के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल (श्री अमी बेरा (डी कैलिफोर्निया); श्री डेरेक किलमेर (डी–वाशिंगटन), श्री बिली लांग (आर–मिसौरी)य श्री जुआन वर्गास (डी कैलिफोर्निया)य श्री ब्रेंडन बॉयल (डी पेनसिलवेनिया) ने 18-23 जनवरी 2016 तक नई दिल्ली, आगरा, बेंगलुरु और मुंबई का दौरा किया। अन्य यात्राओं में शामिल हैंः हॉस्टन के महापौर अनीस पार्कर (23-24 अप्रैल 2015) मिशिगन ब्रायन केली के उपराज्यपाल (04-09 अक्तूबर 2015), और वर्जीनिया के गवर्नर टेरी मेकऔलिफे (16-21 नवम्बर 2015)।

भारत की ओर से हुए मंत्री स्तरीय दौरों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज (20–22 जून 2015 से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह के लिएए 21–22 सितम्बर 2015 से सामरिक और वाणिज्यिक वार्ता के लिएए 29 सितंबर – 2 अक्टूबर 2015 को पहली मंत्रिस्तरीय भारत–अमेरिका–जापान त्रिपक्षीय बैठक के लिए);

2. रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर (डॉ एश्टन कार्टर, अमेरिका के रक्षा सचिव के निमंत्रण पर 07–10 दिसम्बर 2015)।

3. वित्त मंत्री अरुण जेटली (17.19 अप्रैल 2015 के बीच अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष / विश्व बैंक की वसंत कालीन बैठक के लिएय 17-24 जून 2015 तक निवेश मिशन के लिएए 4-6 अक्टूबर 2015 तक निवेशकों की बैठक के लिए)

4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार) प्रकाश जावड़ेकरए (19–20 अप्रैल 2015 तक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मंच की बैठक के लिए)

5. बिजली, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीयूष गोयल ने न्यूयॉर्क में सभी के लिए संयुक्त राष्ट्र स्थायी ऊर्जा (एसई4ऑल) सम्मेलन के लिए और 19–22 मई 2015 तक वॉशिंगटन डीसी में द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेने के लिए; भारत – अमेरिकी ऊर्जा वार्ता तथा सामरिक और वाणिज्यिक वार्ता 21 – 22 सितम्बर 2015 एवं अमेरिकी विदेश मंत्री की मेजबानी में आयोजित जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा निवेश फोरम में भाग लेने के लिए 20 – 21 अक्तूबर 2015 तक।

6. वाणिज्य तथा उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) निर्मला सीतारमण ;सामरिक और वाणिज्यिक वार्ता 21 – 22 सितम्बर 2015; व्यापार नीति फोरम की बैठक 28–29 अक्तू. बर 2015 और फॉर्च्यून ग्लोबल फोरम में 3–4 नवम्बर 2015)

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 29 जून – 8 जुलाई 2015 एक व्यापार और निवेश मिशन पर अमेरिका का दौरा किया। इसी तरह, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक निवेश मिशन पर अगस्त 2015 में अमेरिका के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का भी नेतृत्व किया। इसके अलावा वहाँ दोनों ओर से कई सांसदों और वरिष्ठ अधिकारियों ने दौरा किया गया है।

सामरिक परामर्श

द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर राजनीतिक और सरकारी स्तर पर नियमित रूप से संपर्क किया गया है। अमेरिका के विदेश उप–मंत्री और विदेश सचिव के नेतृत्व में नया उच्च स्तरीय परामर्श शुरू करने के लिए सामरिक और वाणिज्यिक वार्ता का निर्णय लिया गया, जो 7 दिसंबर, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसके साथ ही सामरिक और वाणिज्यिक वार्ता के दौरानए अमरीकी विदेश विभाग और विदेश मंत्रालय के बीच एक नई कूटनीतिक साझेदारी की भी घोषणा की गई थी जिसमें एक नई नीति नियोजन वार्ता भी शामिल होगी। तदनुसार, पहली नीति नियोजन वार्ता 18 नवंबरए 2015 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

हवाई में 25–26 जून 2015 को कार्यात्मक स्तरीय भारत–जापान–अमेरिका त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70 वें सत्र के अवसर पर 29 सितंबर 2015 को भारत–अमेरिका–जापान त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराजए संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी और जापानी विदेश मंत्री फ्यूमियो किशिदा ने संबंधित प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया।

नई दिल्ली में 29 अप्रैल 2015 को विदेश सचिव, डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश कार्यालय राजनीतिक कार्य सचिव, वेंडी शर्मन की सह अध्यक्षता में परामर्श आयोजित किए गए।

नई दिल्ली में 29 अप्रैलए 2015 को भारत–अमेरिका पश्चिम एशिया वार्ता आयोजित की गई थी। दोनों पक्षों ने अफ्रीका को शामिल करते हुए सामरिक विचार–विमर्श का पहला दौर 29 अप्रैल 2015 को संपन्न किया।

भारत–अमेरिका वैश्विक मुद्दों के फोरम का आयोजन सुजाता मेहता सचिव (बहुपक्षीय और आर्थिक संबंध) और अमेरिका की राज्य अवर सचिव, नागरिक सुरक्षाए लोकतंत्र और मानवाधिकार, सारा सेवाल की सह–अध्यक्षता में 14 जनवरी, 2016 को नई दिल्ली में किया गया।

रक्षा

भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सामरिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण घटक रक्षा और सुरक्षा सहयोग है और यह दोनों देशों के बीच संलग्नता के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में विकसित हो गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर ने 2–4 जून

2015 तक भारत का दौरा किया और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने एक कैलेंडर वर्ष के अंदर मंत्रिस्तरीय यात्राओं के पारस्परिक आदान—प्रदान के तहत 7—10 दिसंबर 2015 तक अमेरिका का दौरा किया। रक्षा मंत्री श्री कार्टर ने नवंबर 2015 के शुरूआत में कुआलालंपुर में ए डी एम एम बैठक के मौके पर रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की।

अगले दस वर्षों के लिए रक्षा संबंधों का मार्गदर्शन करने के लिए जून 2015 में रक्षा मंत्री श्री कार्टर की भारत यात्रा के दौरान श्भारत—अमेरिका रक्षा संबंधों के लिए नई रूपरेखाश को नवीकृत किया गया।

रक्षा मंत्री की अमरीका यात्रा के दौरान दोनों पक्ष उन संभव सह विकास और उच्च प्रौद्योगिकी मदों की पहचान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो डी टी टी आई के रूपांतरकारी आशय को पूरा करते हैं। वह पहले भारतीय रक्षा मंत्री थे जो हवाई में अमेरिकी प्रशांत कमान के मुख्यालय का दौरा करने के लिए गए। उन्होंने रक्षा मंत्री श्री कार्टर के साथ उड़ान संचालन विमान वाहक पोत यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर (सीवीएन.69) पर सवार होकर इसका अवलोकन किया।

रक्षा क्षेत्र में सर्वोच्च नीति—स्तर परामर्शी तंत्र रक्षा नीति समूह (डीपीजी)ए अमेरिकी समकक्ष के साथ रक्षा मंत्री की सह अध्यक्षता में है। डीपीजी की अंतिम बैठक 17—18 नवम्बर 2015 को वाशिंगटन डीसी में आयोजित की गई थी। डीपीजी के उप समूहों, अर्थात् रक्षा खरीद और उत्पादन समूह (डीपीपीजीद्ध, वरिष्ठ प्रौद्योगिकी सुरक्षा समूह (एसटीएसजी), संयुक्त तकनीकी समूह (जेटीजी), सैन्य सहयोग समूह (एमसीजी) और कार्यकारी संचालन समूहों की (ईएसजी) वार्षिक बैठक होती हैं और ये डीपीजी को रिपोर्ट करते हैं। ये सभी बैठकें 2015 में आयोजित की गईं।

भारत और अमेरिका ने भारत—अमेरिका रक्षा प्रौद्योगिकी एवं व्यापार पहल (डीटीटीआईद्ध के तहत रक्षा प्रणाली के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को आसान बनाने और सह विकास तथा सह उत्पादन की संभावनाओं का पता लगाने का निर्णय लिया है। वॉशिंगटन डीसी में 16—18 नवंबर 2015 तक डीटीटीआई वार्ता के दो दौर आयोजित किए गए। दो डीटीआईआई परियोजनाओं अर्थात्, मोबाइल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड विद्युत स्रोत (एमएपीएस) और नई पीढ़ी सुरक्षात्मक समवेत (एनजीपीईद्ध के लिए परियोजना समझौते पर अगस्त 2015 में हस्ताक्षर किए गए। दो कार्यकारी समूहों की बैठक भी आयोजित की गई, जो डीटीटीआई के तहत गठित की गई हैं अर्थात् (पद्ध विमान वाहक प्रौद्योगिकी सहयोग पर कार्य समूह; अमेरिका में अगस्त 2015 में और फरवरी 2016 में भारत में) और (पपद्ध जेट इंजन प्रौद्योगिकी संयुक्त कार्य समूह; दिसंबर 2015 में बेंगलुरू में)।

नौसैनिक अभ्यास मालाबार बंगाल की खाड़ी में 14—19 अक्टूबर 2015 को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। पहली बार, जापान ने भारतीय तट पर आयोजित मालावार अभ्यास में भाग लिया। वाशिंगटन राज्य में हथियारों और उपकरणों को साझा करने की तकनीक, कार्यनीति और प्रक्रियाओं तथा परिचय द्वारा परस्पर कार्यक्षमता विकसित करने के लिए 09—23 सितम्बर 2015 से संयुक्त बेस लेविस मेकॉर्ड पर द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास 'युद्ध अभ्यास' आयोजित किया गया था। सिएटल में 17—30 जनवरी 2016 को द्विपक्षीय संयुक्त विशेष बलों का अभ्यास 'वज्र प्रहार' आयोजित किया जाएगा।

उच्च स्तर पर मिल से मिल विनिमयों के हिस्से के रूप में, स्टाफ समिति के प्रमुख और एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने अपने समकक्ष के एक निमंत्रण पर 18—23 मई 2015 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया। अमरीकी नौसेना सचिव रे मेबस ने 10—13 अप्रैल 2015 को भारत का दौरा किया। अमरीकी नौसेना कार्रवाइयों के प्रमुख एडमिरल जॉन एम रिचर्डसन, ने विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भाग लेने के लिए 02—06 फ़रवरी 2016 तक भारत का दौरा किया।

भारत की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में मृत अमेरिकी सैनिकों के अवशेष प्राप्त करने के लिए अमेरिकी सरकार के मानवीय मिशन को सहायता दी गई। हवाई में स्थित अमेरिकी युद्धवंदियों / युद्ध में गुम हुए की लेखांकन एजेंसी (डीपीएए) मिशन ने 27 सितंबर से 12 दिसंबर 2015 तक अरुणाचल प्रदेश में एक खोज और प्राप्ति अभियान चलाया।

आतंकवाद से निपटना और आंतरिक सुरक्षा

सितंबर 2015 में आयोजित सामरिक और वाणिज्यिक वार्ता में भारत और अमेरिका ने आतंकवाद का मुकाबला करने पर एक संयुक्त घोषणा का समर्थन किया, जिसमें दोनों पक्षों ने सभी प्रकार के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपनी प्रतिबद्ध ता की पुष्टि की। दोनों पक्षों ने इस बात को दोहराया कि अल—कायदा और उसके सहयोगी संगठनों, लश्कर—ए—तोयबा, जैश—ए—मोहम्मद, डी कंपनी, और हक्कानी नेटवर्क, तथा अन्य क्षेत्रीय गुटों जैसी संस्थाओं से स्पष्ट खतरा है जो दक्षिण एशिया की स्थिरता को कमजोर करना चाहते हैं और उन्होंने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की पहचान।

वाशिंगटन डीसी में 10—12 अगस्त 2015 को चौथी भारत—अमेरिका साइबर वार्ता का आयोजन किया गया। अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व अमेरिका के साइबर सुरक्षा समन्वयक और राष्ट्रपति के विशेष सहायक माइकल डैनियल ने और भारतीय पक्ष से उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अरविंद गुप्ता ने किया। दोनों प्रतिनिधियों ने

साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण, साइबर सुरक्षा अनुसंधान और विकास, साइबर अपराध का मुकाबला करने, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, और इंटरनेट शासन पर सहयोग में वृद्धि के लिए अनेक अवसरों की पहचान की है।

नई दिल्ली में 22–24 जुलाई 2015 को अमेरिका भारत आतंकवादी निर्धारण कार्यशाला आयोजित की गई थी।

भारत में 4 महानगरों – दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू और चेन्नई के पुलिस आयुक्तों को लेकर गृह मंत्रालय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने महानगर पुलिस व्यवस्था में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 16-20 नवम्बर 2015 को न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी का दौरा किया।

आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध

व्यापार में स्वस्थ विकास (वस्तुओं और सेवाओं में), निवेश और प्रौद्योगिकी साझेदारी के विस्तार से 2015 में भारत–अमेरिका व्यापार और वाणिज्यिक कार्यकलाप निरंतर जारी रहे।

2014-15 के दौरान अमेरिका को 42-45 बिलियन अमेरिकी डॉलर राशि का भारतीय सामान निर्यात किया गया (2013-14 में 39.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में) जो भारत के वैश्विक निर्यात का 13.67 प्रतिशत है। इसी अवधि के दौरान अमेरिका से भारत में 21.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर राशि का निर्यात (2013-14 में 22.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में) हुआ, जो भारत के वैश्विक निर्यात का 4.87 प्रतिशत है। भारत के पक्ष में अमेरिकी व्यापार का अधिशेष 20.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2013-14 में 16.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में) रहा। अमेरिका भारत के लिए वस्तुओं का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।

वर्ष 2013 के दौरान (नवीनतम वर्ष, जिसके लिए सेवा व्यापार पर पूरा डेटा उपलब्ध है), सेवा में द्विपक्षीय व्यापार कुल 66.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ जिसमें से भारत को अमेरिकी सेवाओं के निर्यात की राशि 34.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा अमेरिका को भारत की सेवाओं के निर्यात की राशि 31.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर रही।

अमेरिका का एफडीआई 2013–14 में 806 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ कर 2014–15 में 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया जो 126 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अमेरिका को भारत में छठा सबसे बड़ा निवेशक बनाता है। अप्रैलए 2000 से सितंबर 2015 तक भारत से अमेरिका में संचयी एफडीआई इक्विटी प्रवाह 14.6 बिलियन डॉलर का था।

भारत–अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 9वें दौर की बैठक वाशिंगटन डीसी में 29 अक्टूबर 2015 को आयोजित की गई। यह बैठक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) के राजदूत माइकल फ्रोमैन तथा वाणिज्यिक एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) निर्मला सीतारमन की सह–अध्यक्षता में हुई। व्यापार और निवेश के मुद्दों की एक सीमाए विशेष रूप से टीपीएफ एजेंडे के भाग के रूप में (i) कृषि (ii) सेवा (iii) विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, और (iv) बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में चर्चा की गई।

30 मार्च–1 अप्रैल, 2015 को नई दिल्ली में द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) पर अमेरिका के साथ वार्ता का 5वां दौर आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 दिसंबर 2015 को भारतीय द्विपक्षीय निवेश संधि के संशोधित मॉडल पाठ पर अपनी मंजूरी दे दी है।

अप्रैल 2015 में अमेरिका के परिवहन मंत्री एंथनी फ़ॉक्स के दौरे के दौरान, अमेरिका के संघीय उड्डयन प्रशासन (एफएए) के अंतरराष्ट्रीय उड्डयन सुरक्षा आकलन (आईएएसए) कार्यक्रम के तहत 1 रेटिंग श्रेणी में भारत के उन्नयन की घोषणा की गई। दौरे के दौरान रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन तथा पोत परिवहन और अमेरिका के परिवहन विभाग के बीच द्विपक्षीय परिवहन साझेदारी स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत–अमेरिका के मूल संरचना सहयोग मंच की दूसरी बैठक डिजिटल वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से 9 जुलाई, 2015 को आयोजित की गई। भारत–अमेरिका निवेश पहल की दूसरी बैठक नई दिल्ली में 4 नवंबर 2015 को आयोजित की गई जिसमें अनेक संभावित नीतिगत उपायों पर चर्चा की गई जिनसे भारत के पूंजी बाजार को और अधिक समृद्ध बनाया जा सकता है और ये भारत में अमेरिकी निवेश के लिए अधिक प्रेरक हो सकते हैं। अमेरिका के साथ सहयोग में अजमेरए इलाहाबाद और विशाखापत्तनम में तीन स्मार्ट शहरों के विकास में पर्याप्त प्रगति हुई। अमेरिकी वाणिज्य उप सचिवए ब्रूस एंड्रयूज ने एक बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में स्मार्ट सिटी पहल के तहत विशिष्ट परियोजनाओं की पहचान के लिए 07–10 फ़रवरी 2016 को दिल्लीए चेन्नई और मुंबई की यात्रा की।

भारत ने कर मामलों पर दोनों देशों के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में 9 जुलाई 2015 को अंतरराष्ट्रीय कर अनुपालन में सुधार लाने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते और अमेरिकी विदेशी खाते कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) के कार्यान्वयन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता 31 अगस्तए 2015 से प्रभाव में आया। इस समझौते के अनुपालन में, 18 सितंबर 2015 को कैलेंडर वर्ष 2014 के बाद से एफएटीसीए अनुकूल जानकारी का स्वतः आदान–प्रदान करने के लिए दोनों देशों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा समझौतों और अधिसूचनाओं (सीएए) पर हस्ताक्षर किए गए। भारत भी 3 जून 2015 को काले

धन के खतरे के खिलाफ लड़ने के लिए वित्तीय खातों की स्वतः जानकारी आदान–प्रदान (एनसीएए) पर बहुपक्षीय सक्षम प्राधिकारी समझौते में शामिल हो गया।

भारत और अमेरिका ने बाल्टीमोर में 21 अगस्त 2015 को संभावित द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा और समग्रता समझौते पर विचार–विमर्श किया।

सामरिक और वाणिज्यिक वार्ता से पहले भारत–अमेरिका सीईओ फोरम ने 21 सितंबर 2015 को बैठक की। यह पहली बार हुआ जब सीईओ फोरम को बातचीत के वाणिज्यिक ट्रैक से जोड़ा गया था। सीईओ फोरम ने अधिक से अधिक द्विपक्षीय व्यापार और दोनों एस एंड सीडी पर सरकारों को निवेश की सुविधा के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। एस एंड सीडी में इन सिफारिशों की समीक्षा की गई।

बेंगलुरू में 3.5 नवंबर 2015 को भारत–अमेरिका विमानन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अमेरिका–भारत शिखर सम्मेलन विमानन सहयोग कार्यक्रम (एसीपी) के सहयोग से अमेरिकी व्यापार एवं विकास एजेंसी और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सह–मेजबानी में की गई।

अमेरिकी कांग्रेस ने 19 दिसंबर 2015 को कानून पारित किया, जिसमें आईएमएफ के लंबे समय से लंबित कोटा सुधार को अनुमोदन दिया जाएगा जिससे भारत को मतदान के अधिक अधिकार मिलेंगे।

अमेरिकी अवर सचिव, अंतरराष्ट्रीय कार्य, कोषागार विभाग नेथन शीट्स ने द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय भागीदारी की उप कैबिनेट स्तरीय बैठक के लिए 6.8 जनवरी 2016 तक नई दिल्ली का दौरा किया। आर्थिक कार्य विभाग के सचिव श्री शक्तिकांत दास ने बैठक की सह–अध्यक्षता की।

ऊर्जा

मंत्रिस्तरीय भारत–अमेरिका ऊर्जा वार्ता का पहला दौर वाशिंगटन डीसी में 21 सितंबर 2015 को आयोजित किया गया। छः कार्य समूहों की बैठकें आयोजित की गई : क) कोयला, ख) नई प्रौद्योगिकी और अक्षय ऊर्जा, ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, घ) बिजली और ऊर्जा दक्षता, ड.) सतत विकास और च) भागीदारी स्वच्छ ऊर्जा उन्नत अनुसंधान (पेस–आर)। इसमें स्वच्छ ऊर्जा उन्नत अनुसंधान (पेस–आर) के लिए भागीदारी के तहत चौथी धारा के रूप में ग्रिड अनुप्रयोग हेतु स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के अलावा इसकी खोज के लिए सहमति हो गई थी।

मार्च 2014 के दौरान आयोजित ऊर्जा वार्ता के दौरान, दोनों सरकारों ने स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा अभिगम्यता को प्रोत्साहन देने की गतिविधियों (पीस) की एक योजना को अंतिम रूप दिया, जिसमें नवाचारी ऑफ ग्रिड स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के विकास को समर्थन देने हेतु एक नए ''पैस सैटर फंड'' के लिए 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि संयुक्त रूप से प्रदान करने का आशय घोषित किया गया। पैस सैटर फंड की स्थापना से संबद्ध समझौता ज्ञापन पर जून 2015 में हस्ताक्षर किए गए।

अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रायन डेसी के वरिष्ठ सलाहकार ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए 06.07 सितम्बर 2015 को भारत का दौरा किया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और यूएस के बीच द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति हो रही है। सामरिक और व्यावसायिक वार्ता के मौके पर; भारत – यूएस जलवायु अध्येतावृत्ति कार्यक्रम कार्यान्वयन में सहयोग हेतु 22 सितंबर 2015 को एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत; भारत और यूएस चार वर्ष की अवधि तक अध्येतावृत्ति कार्यक्रमों में 500,000 मिलियन यूएस डॉलर की सहायता प्रदान करेंगे और इसका प्रबंधन और कार्यान्वयन संयुक्त राज्य – भारतीय शैक्षिक संस्थान (यूएसआईईएफ) द्वारा किया जाएगा।

सेन जोस में 27 सितंबर 2015 को आयोजित भारत यूएस स्टार्ट अप कनेक्ट के दौरान, 1. एक दूसरे के पारिस्थितिक तंत्र का लाभ उठाकर, विज्ञान – आधारित उद्यमिता, अनुसंधान, शिक्षा और व्यापार में प्रगति लाने के लिए भारत – यूएस लाइफ साइंस सिस्टर इनोवेशन का विकास करने के उद्देश्य से सेंटर फॉर सेलुलर एण्ड मॉलिकुलर प्लेटफॉर्मस बैंगलुरू, और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट फॉर क्वांटिटेटिव बायोसाइंस (क्यूबी3) के मध्य समझौता ज्ञापन; और 2. भारत के डीबीटी स्टार कॉलेजों की प्रकाश लैब से फोल्ड स्कोप प्राप्त करने के लिए संयुक्त अनुसंधान की व्यवस्था की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और प्रकाश लैब, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बीच दो एमओयू / एलओआई पर हस्ताक्षर किए गए।

10 – 16 मई, 2015 को पिट्सबर्ग में आयोजित विश्व के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय कॉलेज पूर्व विज्ञान प्रतियोगिता, इंटेल अंतरराष्ट्रीय विज्ञान एवं अभियांत्रिकी मेला (इंटेल आईएसईएफ) में भाग लिया।

विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) के सचिव, प्रोफेसर टी. के. चंद्रशेखर ने 18 – 23 मई, 2015 को यूएस के लिए प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। यात्रा के दौरान विदेशी डॉक्टरेट फेलोशिप प्रोग्राम हेतु दौरे के समय एसईआरबी और यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और कार्नेगी. मेलन यूनिवर्सिटी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

मानसून पर समुद्री प्रभावों का पता लगाने, बंगाल की खाड़ी की सबसे ऊपरी परत पर विस्तृत आलेख पत्र तैयार करने के लिए भारतीय और यूएस वैज्ञानिकों ने बंगाल की खाड़ी में यूएस अनुसंधान पोत रोजर रिवेली और भारतीय अनुसंधान पोत सागर निधि पर अगस्त से सितंबर 2015 तक महीने भर समुद्र विज्ञान संबंधी अनुसंधान किया। अतीत में मानसून के स्वरूपों का पता लगाने और अतीत में जलवायु संबंधी स्थितियों के पुनः निर्माण में सहयोग के उद्देश्य से यूएस संयुक्त समुद्र – विज्ञान संस्थानों द्वारा संचालित ऑनबोर्ड अभ्यास जेओआईडीईएस प्रस्ताव के अनुपालन में भूगर्भ विज्ञान, मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय समुद्र अन्वेषण कार्यक्रम (आईओडीपी) के अंतर्गत; मई 2015 में द्विक्षीय वैज्ञानिक अभ्यास आईओडीपी 355 (अरब सागर) पूरा किया।

असैन्य परमाणु सहयोग

सितंबर 2014 में प्रधान मंत्री के यूएस दौरे के समय, दोनों देशों ने प्रशासनिक मामलों, दायित्वों, तकनीकी मुद्दों, और भारत में परमाणु पार्कों की स्थापना करने की सुविधा हेतु लाइसेंस प्रदान करने जैसे मुद्दों सहित कार्यान्वयन संबंधी सभी मामलों पर विचार विमर्श हेतु संपर्क समूह बनाने पर सहमति जताई थी। 24, नवंबर 2015 को वाशिंगटन डीसी में इस संबंध में सिविल परमाणु सहयोग संपर्क समूह की 5वीं बैठक का आयोजन किया गया।

मुंबई स्थित परमाणु ऊर्जा विभाग में 3–7 अगस्त, 2015 को भारत यूएस सिविल नाभिकीय ऊर्जा कार्यकारी समूह (सीएनईडब्ल्यूजी) की 7वीं बैठक आयोजित की गई। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) और यूएस परमाणु नियामक आयोग (एनआरसी) के बीच सहयोग हेतु 27 अक्तूबर 2015 को मुंबई में एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई।

अंतरिक्ष

वर्ष 2015 के दौरान भारत और यूएस ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के मामले में निरंतर प्रगति की। दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच सांस्थानिक सहयोग हेतु नासा मुख्यालय, वाशिगंटन डीसी में 12 – 14 अगस्त, 2015 को इसरो – नासा मार्स कार्यकारी समूह की बैठक हुई। इसके अतिरिक्त, सिविल स्पेस सहयोग हेतु इसरो मुख्यालय, बेंगलुरु में 23 – 24 सितंबर 2015 को भारत – यूएस संयुक्त कार्यकारी समूह की पांचवीं बैठक का आयोजन किया गया।

सितंबर, 2015 के दौरान यूएस – प्रौद्योगिकी रक्षा करार को 20 जुलाई 2019 तक 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया जिससे यूएस सरकार द्वारा शुरू की यूएस सेटेलाइट्स और यूएस घटकों वाली तीसरी भारतीय देशी सेटेलाइट्स की मंजूरी सुगम हो गई है। नई दिल्ली में 24 फरवरी, 2016 को दूसरी अंतरिक्ष सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर सहयोग के उद्देश्य से, भारत और यूएस ने 25 जून 2015 को निम्नलिखित तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए :

1. कैंसर अनुसंधान, निवारण, नियंत्रण और प्रबंधन हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान सं. स्थान, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर) जीव विज्ञान विभाग और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यूएस के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन।
2. पर्यावरण व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं आघात निवारण व नियंत्रण के लिए सहयोग हेतु रोग नियंत्रण एवं निवारण केंद्र (सीडीसी) यूएस और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर) के बीच समझौता ज्ञापन;
3. एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर), जैव प्रौद्योगिकी विभ. ाग, और यूएस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एण्ड इंफेक्सियस डिजीज (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ) के बीच आशय पत्र (एलओआई) पर समझौता।

स्वास्थ्य संबंधी पहली द्विपक्षीय वार्ता 17 – 18 सितंबर 2015 को वाशिंगटन डीसी में आयोजित की गई। यह वार्ता हाल में द्विपक्षीय स्वास्थ्य संबंधी पहल के अंतर्गत आयोजित की गई थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री भानु प्रताप शर्मा ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एण्ड ह्यूमन सर्विसेज के कार्यकारी उप सचिव श्री मेरी वेकफील्ड ने यूएस प्रतिनिधि मंडल का तथा का नेतृत्व किया। स्वास्थ्य वार्ता में कैंसर से लेकर, तम्बाकू नियंत्रण, मानसिक स्वास्थ्य, मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य, संचारी रोगों, परंपरागत औषधियों, विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंडा (जीएचएसए), सहित द्विपक्षीय स्वास्थ्य सहयोग हेतु पूंजी पर चर्चा की गई और जन स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए कुछ नए लक्ष्य निर्धारित किए गए।

आयुष मंत्रालय के सचिव; श्री निलंजन सान्याल ने 13 – 17 अप्रैल, 2015 को यूएस का दौरा किया और परंपरागत औषधि के क्षेत्र में सहयोग हेतु, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एण्ड ह्यूमन सर्विसेज, नेशनल सेंटर फॉर कम्पलीमेंटरी एण्ड इंटिग्रेटिव मेडिसिन (एनआईएच), नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट (एनसीआई – एनआईएच), खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) और यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया कन्वेंशन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की।

परंपरागत औषधि के क्षेत्र में सहयोग हेतु केंद्रीय आयुर्वेदिक शास्त्र अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएएस) (आयुष मंत्रालय की ऑल रिसर्च काउंसिल की ओर से) ने अक्तूबर 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ

मिसीसिपी, यूएस (नेशनल सेंटर फॉर नेचुरल प्रॉडक्ट्स रिसर्च की ओर से) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

शिक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 30 नवंबर 2015 को शैक्षिक नेटवर्क वैश्विक कार्यक्रम (जीआईएएन) की शुरूआत की जिसके अंतर्गत अन्य देशों से आने वाले अतिथि विद्वानों द्वारा अल्पकालिक अध्ययन और अनुसंधान कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा।

आईआईटी से आरंभ करते हुए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को तकनीकी सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से भारत यूएस जेडब्ल्यूजी की पहली बैठक दिनांक 5 जनवरी 2016 को गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की गई। इसके लिए, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा।

भारत में कौशल विकास के क्षेत्र में भागीदारी स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगमन (एनएसडीसी) ने तीन यूएस कम्युनिटी कॉलेजों अर्थात हडसन कम्युनिटी कॉलेज, अलामो कम्युनिटी कॉलेज और लोन स्टार्ट कम्युनिटी कॉलेज के साथ अप्रैल 2015 में समझौता ज्ञापन किया।

सांस्कृतिक प्रगति और प्रवासी संपर्क

यूनाइटेड स्टेट्स के अनेक शहरों में 21 जून 2015 को प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। पहले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोहों में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क का दौरा किया। पहले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की प्रशंसा और योग के बारे में जागरुकता लाने के लिए यूएस के अनेक नेताओं ने घोषणाएं की और बधाई संदेश भेजे।

प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मिशन और वाणिज्य दूतावास ने अनावरण कार्यक्रमों के रूप में श्री श्री रवि शंकर द्वारा दिनांक 29 अप्रैल 2015 को ''योग और ध्यान के माध्यम से शांति का विकास'' विषय पर व्याख्यान और 11 मई 2015 को सद्गुरू जग्गी वासुदेव के ''आधुनिक जीवन में योग का महत्व'' विषय पर व्याख्यान सहित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया

लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में 14 से 15 नवंबर 2015 को नौवें क्षेत्रीय प्रभावी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया। विदेश राज्य मंत्री डॉ. वी. के. सिंह (सेवा निवृत्त) ने इसमें भाग लिया।

कोंसुलर सहयोग

यूएस और भारत में सुरक्षा अधिकारियों द्वारा सुरक्षा जांच के बाद भारत के प्रतिष्ठित यात्रियों के यूएस में शीघ्र प्रवेश की सुविधा हेतु यूएस सरकार ने ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम (जीईपी) की सदस्यता का प्रस्ताव दिया। चर्चा का अंतिम दौर सितंबर 2015 में आयोजित किया गया।

भारत – यूएस कोंसुलर वार्ता के चौथे चरण का चौथा दौर 3 नवंबर, 2015 को वाशिगंटन डीसी में आयोजित किया गया।

लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देश

अर्जेंटीना

अर्जेंटीना के उप विदेश मंत्री, श्री इदुराडो जुएन और खनन मंत्री, जार्ज मायोरॉल ने वर्ष 2015 में भारत का दौरा किया। उन्होंने व्यापार; वाणिज्य, शिक्षण; संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के साथ अर्जेंटीना के सहयोग को और अधिक मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। भारतीय राज्यों और अन्य देशों में इनके समकक्ष राज्यों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों के रूप में, दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को शिक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए क्षेत्रीय कार्य योजना के अंतर्गत अर्जेंटीना से कई प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया।

भारत और अर्जेंटीना के द्विपक्षीय व्यावसायिक संबंधों में दो महत्वपूर्ण उपलब्धियों : अर्जेंटीना से फार्मा उत्पाद आयात करने वाले देशों की सूची में भारत को शामिल करने के लिए अनुबंध 2 में महत्वपूर्ण संशोधन और अर्जेंटीना के सेबों, नाशपातियों और श्रीफल के निर्यात हेतु भारत द्वारा साइटोसेनिटरी अनुमति जारी किए जाने से द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में मजबूती आई। अर्जेंटीना ने अक्टूबर 2015 में 6ठे भारत – एल ए सी कॉन्क्लेव में भी भाग लिया। भारत से फार्मा और रसायनों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तीन प्रोमोशनल काउंसिल्स, फॉमेक्साइल्स, कैमिक्साइल और लेदर एक्सपोर्ट काउंसिल ने ब्यूनस आयर्स में बी 2 बी प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त, शीर्ष व्यापार मंडलों के सहयोग से अर्जेंटीना के सभी भागों में मेक इन इंडिया कैम्पेन और ब्रांड इंडिया को बढ़ावा देने के लिए व्यापार सम्मेलनों का आयोजन किया गया।

सांस्कृतिक स्तर पर सभी प्रांतों जैसे कोटिनेट्स ब्यूनस आयर्स, जुजुए और मेंडोजा में भारतीय त्यौहारों / दिवसों का आयोजन किया गया। अर्जेंटीना के सभी 23 प्रांतों में पहले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया और ब्यूनस आयर्स की राजधानी में शहर / प्रांतीय सरकारों के सहयोग से इसका आयोजन किया गया।

बोलिविया

व्यापार प्रतिनिधि मंडलों के दौरे से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2014 – 15 में भारतीय निर्यात 70.838 मिलियन यू एस डॉलर का रहा जबकि इसी वर्ष आयात 3.56 मिलियन यूएस डॉलर का रहा। 15 अगस्त 2015 को बोलिविया को ई.टी.वी. के लिए पात्र देशों की सूची में शामिल

विदेश मंत्री ब्राजील के विदेश मंत्री श्री माउरो वियरा के साथ

गुयाना के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड रामोतार के साथ प्रधानमंत्री

कर लिया गया।

ला पेज़ के साथ–साथ कुछ अन्य शहरों में भी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2015 का आयोजन किया गया। जनवरी 2016 को आयोजित अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में बोलिविया ने सहयोगी देश के रूप में भाग लिया।

ब्राजील

संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक 19 नवंबर को दिल्ली में आयोजित की गई और माननीय विदेश मंत्री, श्रीमती सुषमा स्वराज और ब्राजील के विदेश मंत्री, श्री मोरो वीरा ने संयुक्त रूप से इसकी अध्यक्षता की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों पर विचार विमर्श किया और क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय सहयोग पर विचार साझा किए। दोनों मंत्रियों ने सहमति जताई कि विदेश कार्यालय परामर्श नियमित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए और एफओसी प्रणाली तंत्र को इस जेसीएम पर औपचारिक रूप से स्थापित किया गया।

द्विपक्षीय व्यापार 2015 में लगभग 7.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जिसमें कच्चे तेल और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में बड़ी गिरावट के कारण लगभग 30 प्रतिशत की कमी हुई। 2015 में व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था।

विशेष सचिव (एएमएस एण्ड सीपीवी), श्री आर. स्वामिनाथन ने ब्राजील का दौरा किया और 20 जुलाई 2015 को ब्राजीलिया में अपने समकक्ष श्री जोंस अल्फ्रेडो गेसा लाइमा, अंडर सेक्रेटरी जनरल के साथ द्विपक्षीय वार्ता की तथा अन्य बातों के साथ साथ, व्यापार और वाणिज्य, कृषि, पर्यावरण, नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग, अंतरिक्ष सुरक्षा, परंपरागत औषधि और क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय मुद्दों पर सहयोग हेतु विस्तार से चर्चा की।

2014 में प्रधान मंत्री के दौरे के समय हस्ताक्षरित करार के क्रियान्वयन में वाणिज्यदूत प्रणाली की पहली बैठक भी 21 जुलाई 2015 को आयोजित की गई। संधि के अनुसमर्थन विषय पर भी दोनों देशों के बीच विचार – विमर्श हुआ।

भारत ने अगस्त 2015 में आयोजित विश्व कौशल विकास साओ पाओलो प्रतियोगिता की 27 कौशल विकास श्रेणियों में भाग लिया। श्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली सरकार के उप मुख्य मंत्री एवं शिक्षा मंत्री, श्री शिबू बेबी जॉन, केरल के श्रम एवं कौशल विकास मंत्री के नेतृत्व में दो राज्य स्तरीय प्रतिनिधि मंडलों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। अन्य महत्वपूर्ण दौरों में शामिल हैं, लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए अक्टूबर 2015 में दिल्ली उच्च न्यायालय की जस्टिस श्रीमती दीपा शर्मा का साओ वाओलो का दौरा। ब्राजील एयरोस्पेस समूह एमब्रेयर के लिए एयर चीफ मार्शलए श्री अरूप राहा ने 26 अक्टूबर 2015 तक यात्रा की थी। मर्करीपर मिनिमाता परंपरा के अंतर्गत वित्त व्यवस्था करने वाले विशेषज्ञों के तदर्थ कार्यकारी समूह की बैठक में भाग लेने के लिए पर्यावरण; वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्रतिनिधिमंडल ने 26 – 29 अक्तूबर 2015 को साओ वाओलो का दौरा किया। सड़क सुरक्षा पर आयोजित द्वितीय वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, श्री नितिन गड़करी ने 17 – 19 नवंबर को ब्रासीलिया का दौरा किया। ब्राजील के राष्ट्रपति ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

ब्राजील के 12 बड़े शहरों में 21 जून 2015 को पहले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। ब्राजील के डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया।

चिली

अप्रैल – अक्तूबर 2015 के दौरान, 404.44 मिलियन यूएस डॉलर के भारतीय निर्यात और चिली से 1232.02 मिलियन के आयात के साथ भारत और चिली के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1636.46 मिलियन यूएस डॉलर रहा।

द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती लाने और पहले से ही अंतिम स्तर पर पहुंची चुकी दोनों देशों के बीच पीटीए विस्तार पर हो रही वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए माननीय श्री इडोरो फ्रेप, एशिया पैसिफिक क्षेत्र में विशेष मिशन के विशेष सचिव एवं पूर्ण अधिकार प्राप्त राजदूत और चिली के पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में चार सदस्यीय आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल ने 20 – 30 नवंबर को भारत का दौरा किया। दौरे के समय, एच.ई. फ्रेयी ने विदेश, वाणिज्य एवं उद्योग, टेक्स्टाइल्स और सूचना एवं संचार राज्य मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।

सैंटियागो के प्रतिष्ठित सेंट्रो कल्चरल ला मोनेडा (चिली के प्रेसिडेंसियल पैलेसे का सांस्कृतिक केंद्र) में 21 जून 2015 को पहले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाय) का आयोजन किया गया।

कोलम्बिया

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रभावित करता है। 82.41 प्रतिशत की गिरावट के साथ भारत में कोलम्बिया का निर्यात 415,38 मिलियन यूएस डॉलर रहा और मुख्य रूप से कच्चे तेल के निर्यात और इसकी कीमतों में गिरावट के कारण 2013–14 की इसी अवधि की तुलना में 2014–15 में 7.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ भारत ने कोलम्बिया में 909,72 मिलियन यूएस डॉलर का निर्यात किया। 2014–15 में व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा।

श्री धर्मेंद्र प्रधान, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री ने

व्यापार प्रतिनिधि मंडल के साथ 20 – 22 मई, 2015 को कोलम्बिया का दौरा किया; और कोलम्बिया के खनन एवं ऊर्जा मंत्री, श्री टॉमस गोन्जेलेज इस्ट्रेडा से मुलाकात की।

टेक्स प्रोसिल, कैपेक्सिल, स्ट्रेपीसी, एसीएमए, एण्ड टूर ऑपरेटरों द्वारा व्यापार संबंधी दौरों से कोलम्बिया के साथ व्यापार संबंधों में और मजबूती आई। कोलंबिया के बोगोटा, मेडेलीन, बैरेंकुइला, काली और पेस्टो में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया।

इक्वाडोर

भारत – इक्वाडोर संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (जेईटीसीओ) के गठन के लिए नई दिल्ली में एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए। जेईटीसीओ की पहली बैठक भारत में 2016 के आरंभ में आयोजित की जानी प्रस्तावित है।

विदेश राज्य मंत्री, जनरल (सेवानिवृत्त) वी. के. सिंह ने द्विपक्षीय परामर्श हेतु 25 – 27 मई 2015 को इक्वाडोर का दौरा किया। उन्होंने विदेश मंत्री, श्री रिचर्डो पैटिनो और उप विदेश मंत्री, श्री लियोनार्डो एरिजैगा के साथ बैठक की। बैठक में द्विपक्षीय; बहुपक्षीय और क्षेत्रीय हितों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई।

गुयाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान 24 सितंबर 2015 को गुयाना के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डेविड ग्रेंजर के साथ मुलाकात की। श्री आर स्वामीनाथनए विशेष सचिव (एम्स सीपीवी) ने जुलाई 2015 में गुयाना की सरकारी यात्रा की। इस यात्रा के दौरान पहली भारतीय–कैरीकॉम संयुक्त आयोग की बैठक गुयाना में 02 जून 2015 को की गई थी। आधारिक संरचना संबंधी परियोजनाओं जैसे, ईस्ट बैंक डेमेरारा–ईस्ट कोस्ट डेमेरारा वाइपास रोड और यात्री नौका के अतिरिक्त गुयाना में एक आईटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा हेतु 60 मिलियन यूएस डॉलर के रियायती ऋण की घोषणा के साथ भारत गुयाना को विकास संबंधी सहायता निरंतर प्रदान कर रहा है। गुयाना के जॉर्जटाउन में 21 जून 2015 को पहले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया, गुयाना के प्रधान मंत्री मोजेज नागमूतू मुख्य अतिथि के रूप में इसमें उपस्थित रहे।

मैक्सिको

न्यूयॉर्क में आयोजित 70वें यूएनजीए के अवसर पर प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मैक्सिको के राष्ट्रपति श्री इनरीक पेना नीटो के साथ बैठक के बाद, भारत और मैक्सिको के संबंधों में और मजबूती आई। इस बैठक के दौरान, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, एमटीसीआर में भारत की सदस्यता और संशोधित एवं विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता पर चर्चा की।

हाल के वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि प्रभावशाली रही है। मैक्सिको के कुल वैश्विक निर्यातों में भारत का आठवां स्थान है जबकि वैश्विक बाजार में भारत मैक्सिको का 14वां सबसे बड़ा हिस्सेदार है। वर्ष 2014–2015 में कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 6.25 मिलियन यूएस डॉलर दर्ज किया गया था। भारत में भी मैक्सिको का निवेश बढ़ रहा है।

पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल के साथ 18–19 मई 2015 तक मैक्सिको का दौरा किया और मैक्सिको के वाणिज्य एवं अर्थनीति मंत्री तथा ऊर्जा मंत्री के साथ मुलाकात की। भारत और मैक्सिको ऊर्जा भागीदारी को मजबूत बनाने पर सहमत हुए। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, कैरन, रिलायंस, अडानी, लार्सन एंड टूब्रो और फिक्की के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस व्यापार प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे।

मैक्सिको के अर्थ नीति उप मंत्री श्री फ्रांसिस्को डे रोसेंजवेग ने 8 – 9 अक्तूबर, 2015 को आयोजित सीआईआई भारत – एलएसी कान्क्लेव में भाग लिया। मैक्सिको शहर के फेडरल जिले की नगरीय सरकार के सहयोग से 21 जून 2015 को मैक्सिको में प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था।

सूरीनाम

पांचवीं जेसीएम के दौरान भारत ने सूरीनाम की लाइन ऑफ क्रेडिट के अनुसार 50 मिलियन यूएस डॉलर की घोषणा की और छह प्रस्तावों पर मंत्रालय द्वारा सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

13.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एचएएल मूल्य द्वारा उत्पादितए तीन चेतक हेलीकाप्टरों को 2015 मार्च में रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया। एचएएल के विशेषज्ञों / तकनीशियनों ने रखरखाव और प्रशिक्षण उद्देश्यों से 2015 में सूरीनाम का दो बार दौरा किया।

एलएसी के लिए सहायता अनुदान के अंतर्गत विदेश मंत्रालय ने पारामारिबो में एस लैंड्स हॉस्पिटल शवगृह के उन्नयन हेतु 3, 11, 567.21 यूएस डॉलर के अनुदान और सूरीनाम के प्राकृतिक संसाधन और इंजीनियरिंग अध्ययन संस्थान (एनएटीआईएन) के लिए सहायता हेतु 1,69,400 /– यूएस डॉलर धनराशि की स्वीकृति दी।

सूरीनाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अक्तूबर 2015 में छठवीं सीआईआई भारत – एलएसी कान्क्लेव में भाग लिया।

सूरीनाम में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने वर्ष 2015 में 29500 /– यूएस डॉलर की अनुदान राशि दी क्योंकि सूरीनाम के विभिन्न जिलों में 80 स्वैच्छिक हिंदी विद्यालय चल रहे हैं।

सूरीनाम के दो छात्र इस समय केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा में अध्ययन कर रहे हैं और दो छात्र आयुष छात्रवृत्ति के तहत भारत में बीएएमएस पाठ्यक्रम में अध्ययनरत है।

पराग्वे

भारत और पराग्वे के बीच स्नेहपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध है। अप्रैल 2015 में अमेरिका के विशेष सचिव (एएमएस एंड सीपीवी), श्री आर. स्वामीनाथन ने पराग्वे का दौरा किया जहां उन्होंने पराग्वे के विदेश मंत्री, प्रोटोकॉल के प्रेसीडेंसियल चीफ, कृषि और उद्योग मंत्रियों को द्विपक्षीय कृषि व्यापार को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देते हुए सहयोग के द्विपक्षीय मुद्दों के विस्तृत प्रभावशाली प्रदर्शन के बारे में विचार विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया। अगस्त 2015 में पराग्वे के उप विदेश मंत्री श्री आंस्कर कैबेलो ने फॉरेन ऑफिस कंसल्टेसंस के दूसरे चक्र के लिए भारत का दौरा किया। व्यापार और निवेश, कृषि, पर्यटन, तकनीकी सहयोग, एमईआरसीओएसयूआर और यूएनएससी सुधारों सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार – विमर्श किया गया। पराग्वे के खेल मंत्रालय के सहयोग से असंसियन में प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था।

पेरु

भारत ने 1 – 3 जुलाई 2015 को पराकास पेरु में ऑब्र्जवर स्टेट्स के साथ दसवें पैसिफिक अलायंस शिखर बैठक में भाग लिया। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने 6 – 11 अक्तूबर 2015 तक लीमा का दौर किया और विश्व बैंक समूह / आईएमएफ वार्षिक बैठकों एवं जी 24 तथा राष्ट्रमंडल वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। जनजातीय कार्य मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने 8 – 12 जून, 2015 तक लीमा का दौरा किया और पेरू के संस्कृति, शिक्षा और विकास एवं सामाजिक समावेश मंत्रालयों के साथ बैठकें कीं।

पेरू के लिए भारत का निर्यात वित्त वर्ष 2014–15 में 819.858 मिलियन अमेरिकी डॉलर था जबकि आयात की राशि 590.395 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।

उरूग्वे

उरूग्वे के विदेश मंत्री, श्री रोडोल्फोनिन नोवोओ ने द्विपक्षीय वार्ता और भारत – एलएसी कान्क्लेव में भाग लेने के लिए व्यावसायिक प्रतिनिधि मंडल के साथ 8 – 9 अक्तूबर 2015 को भारत का दौरा किया। श्री नोवोआ ने विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की और द्विपक्षीय व्यापार, पर्यटन और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य मंत्री के साथ चर्चा की। टाटा मोटर्स के सहयोग से उरूग्वे में प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था।

वेनेजुएला

वेनेजुएला, भारत में कच्चे तेल के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। भारत ने वर्ष 2014 – 15 में 12 बिलियन अमेरिकी डालर मूल्य के तेल का आयात किया। द्विपक्षीय व्यापार 2014 – 15 में 12.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने जकार्ता में आयोजित एशिया अफ्रीका शिखर सम्मेलन 2015 के दौरान 22 अप्रैल 2015 को कार्यकारी उप राष्ट्रपति श्री जॉर्ज एरियाजा से मुलाकात की। विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वी. के. सिंह ने 24 – 25 मई 2015 को कराकस का दौरा किया। उन्होंने उप राष्ट्रपति श्री जॉर्ज एरियाजा, विदेश मंत्री डॉ. डेल्सी रोड्रिज, तेल और खनन मंत्री श्री असद्रूबल चावेज और पीडीवीएसए के राष्ट्रपति श्री यूलोजियो डेल पिनो के साथ बैठकें आयोजित कीं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेंद्र प्रधान ने द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने के लिए 4 जून 2015 को वियना में तेल और खनन मंत्री श्री असद्रु बल चावेज से मुलाकात की। पीडीवीएसए के राष्ट्रपति श्री यूलोजियो डेलपिनो ने 15 – 16 जून 2015 को भारत का दौरा किया। उन्होंने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वी. के. सिंह से मुलाकात की। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 30 सितंबर 2015 को न्यूयॉर्क में यूएनजीए सत्र के बारे में विदेश मंत्री डॉ. डेल्सी रोड्रिज के साथ बैठक की थी।

सिमांन बोलिवर विश्वविद्यालय ने भारतीय दूतावास और आईटीईसी एलुमिनी के साथ मिलकर 4 जून 2015 को ''मेक इन इंडिया'' का आयोजन किया। प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाय) 21 जून 2015 को मनाया गया और इसमें लगभग 1000 प्रतिभागी शामिल हुए थे।

मध्य अमेरिका

बेलीज

विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ) वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त) की 28 मई 2015 को ग्वाटेमाला सिटी में बेलीज के विदेश मंत्री विल्फ्रेड इलरिंगटन के साथ एक सफल बैठक हुई, जहां उन्होंने भारत–एसआईसीए मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया।

कोस्टारिका

नई दिल्ली में 16 मार्च 2015 को द्वितीय एफओसी का आयोजन किया गया। विशेष सचिव (एएमएस और सीपीवी) श्री आर.

विदेश राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह (सेवानिवृत) वैनेजुएला की श्रीमती मारिया क्विजादा, विदेश मंत्री डेल्सी राडरेक्स और तेल एवं खनन मंत्री अस्द्रूबल चावेज के साथ

ग्वाटेमाला सीटी में सौर ट्रैफिक लाइटों के अधिष्ठापन के दौरान जनरल वी.के. सिंह (सेवानिवृत) का स्वागत

स्वामिनाथन ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल और विदेश मामलों के उप मंत्री श्री अले जांद्रो सोलानो ऑर्टिज ने कोस्टारिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस यात्रा के दौरान भारत और कोस्टारिका के विदेश सेवा संस्थानों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ) वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त) ने 21–22 जुलाई 2015 तक सैन जोसए कोस्टारिका का सरकारी दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने विदेश मंत्री, प्रथम उप – राष्ट्रपति और विदेश व्यापार मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। दोनों पक्षों ने भारत – कोस्टारिका द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण विस्तार पर विचार विमर्श किया। उन्होंने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों, भारत – सिका (मध्य अमेरिकी एकीकरण पद्धति) वार्ता से संबंधित मुद्दों और पिछले मंत्री पक्षीय अनुवर्तन पर भी विचार विमर्श किया। इस यात्रा के दौरान तकनीकी सहयोग संबंधी एक करार पर भी हस्ताक्षर किए गए।

कोस्टारिका के विदेश व्यापार मंत्री और द्वितीय उप राष्ट्रपति ने सीआईआई द्वारा 8 – 9 अक्तूबर, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित छठे भारतीय एलएसी कान्क्लेव में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया।

इस मिशन ने कोस्टारिका भारतीय संघ (सीआरआईए) के सहयोग से कला संग्रहालय में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जिसमें स्कूली बच्चों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया।

अल सल्वाडोर

माननीय विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वी. के. सिंह (सेवा निवृत्त) ने सैन सल्वाडोर, अल सल्वाडोर में कम्युनिटी ऑफ डेमोक्रेसीज़ (सीओडी) के 8वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22 – 24 जुलाई 2015 को अल सल्वाडोर का दौरा किया। सम्मेलन के मौके पर राज्य मंत्री ने सल्वाडोर के विदेश मंत्री ह्यूगो मार्टिनेज और उप राष्ट्रपति ऑस्कर ओर्टिज के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।

ग्वाटेमाला

माननीय विदेश राज्य मंत्री, राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वी. के. सिंह (सेवा निवृत्त) ने भारत – सिका मंत्रीस्तरीय बैठक और ग्वाटेमाला के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए 27–30 मई 2015 तक ग्वाटेमाला का दौरा किया। बैठक के दौरान भारत ने इन देशों में परियोजनाओं के लिए सिका देशों (प्रत्येक सिका देश के लिए 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट सीमा मौजूदा 100 आईटीईसी स्थानों को बढ़ाकर 200 किया और केवल सिका सचिवालय के लिए 10 छात्रवृत्तियां निर्धारित कीं। सिका क्षेत्र की गरीब महिलाओं, जो आगे चलकर सौर ऊर्जा से अपने गांवों का विद्युतीकरण कर सकती हैं, को प्रशिक्षित करने के लिए ग्वाटेमाला में बेयर फुट वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। इस यात्रा के दौरान राजनैतिक और सरकारी पास पोर्ट धारकों को वीजा आवश्यकताओं से छूट प्रदान करने के लिए ग्वाटे माला के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भेंट की गई सौर विद्युत ट्रैफिक सिग्नलिंग प्रणाली अवस्थापना परियोजना पूरी की गई और 29 मई 2015 को राज्य मंत्री की उपस्थिति में प्रचालित किया गया।

ग्वाटेमाला के विदेश उप मंत्री ने अक्तूबर 2015 में सीआईआई द्वारा आयोजित भारत – एलएसी कॉन्क्लेव में भाग लिया।

होंडुरास

प्रथम विदेश कार्यालय परामर्शों के आयोजन के साथ भारत और हौडुरस के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए। श्री आर स्वामीनाथनए विशेष सचिव (एएमएस और सीपीवी), भारत के विदेश मंत्रालय ने होंडुरास और भारत के बीच विदेश कार्यालय परामर्श के पहले दौर के लिए टेगुसिगलपा में 27 अप्रैल, 2015 को आयोजित विदेश मंत्रालय कार्यालय परामर्शों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। होंडुरास, राजदूत रॉबर्टो ओकोया मैड्रिड, विदेश मामलों के उप मंत्री ने हौडुरन प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर सहयोग भी शामिल है। विशेष सचिव (एएमएस एंड सीपीवी) ने होंडुरास के विदेश कार्य मंत्री, माननीय राजदूत अर्टुयूरो कोरेलेस अल्वारेज़ से मुलाकात की।

निकारागुआ

इस अवधि के दौरान द्विपक्षीय व्यापार में 92 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मामूली वृद्धि दर्ज की गई। भारत का निर्यात 0.83 मिलियन और आयात 91 मिलियन दर्ज किया गया। भारत ने फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोटिव, आईटी, कृषि, ऊर्जा और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में निकारागुआ की सहायता करने की प्रतिबद्धता जताई। वर्ष 2015 में 31.29 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण राशि पारेषण लाइनों और सब–स्टेशन परियोजना को अनुमोदित किया गया है।

विकास, उद्योग और व्यापार मंत्री श्री ओरियांडो सल्वाडोर सोलोर्जानों डेल्गाडिलो ने 8 – 9 अक्तूबर 2015 को नई दिल्ली में आयोजित 6ठी सीआईआई भारत – एलएसी कान्क्लेव में भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

निकारागुआ में भारतीय मिशन ने रुबेन डेरियो नेशनल थिएटर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (आईवीवाय) का आयोजन करने के लिए निकारागुआ में निवास कर रहे कुछ भारतीय परिवारों के साथ समन्वयन किया।

पनामा

एक्सपोकोमेर–2015 में भाग लेने के लिए 120 भारतीय कंपनियों ने मध्य अमेरिका की एक बड़ी वार्षिक वाणिज्यिक प्रदर्शनी, पनामा सिटी में 11–14 मार्च 2015 से पनामा चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर द्वारा आयोजित की। 35 से अधिक देशों ने प्रदर्शनी में भाग लिया।

पनामा डायमंड एक्सचेंज (पीडीई) ने विश्व के हीरा उद्योग, बहुमूल्य रत्नों और आभूषणों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को एक दूसरे से मिलाया। इस क्षेत्र के 17 देशों के 350 से अधिक खरीदारों और भारत, बेल्जियम तथा इजरायल के निर्यातकों ने व्यापारिक बैठकों में भाग लिया। चार भारतीय कंपनियों ने पनामा डायमंड एक्सचेंज में अपने कार्यालय शुरू किए हैं। पनामा के राष्ट्रपति इस इवेंट के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए।

पनामा में भारतीय मिशन ने स्थानीय योग संस्थानों की सक्रिय सहभागिता और प्रथम महिला, पनामा की मेयर एवं राष्ट्रीय संस्कृति संस्थान के कार्यालयों के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाय) का आयोजन किया।

कैरिबियन देश

एंटीगुआ एवं बरबुडा

श्री आर स्वामीनाथन, विशेष सचिव (एएमएस एंड सीपीवी) ने 24–25 जुलाई 2015 को एंटीगुआ एवं बरबुडा का सरकारी दौरा किया और एंटीगुआ एवं बरबुडा के प्रधानमंत्री माननीय गोस्टन ब्राउने विदेश एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की। आईटीईसी कार्यक्रम के तहत भारत में एंटीगुआ एवं बरबुडा के नागरिकों को प्रशिक्षण प्रदान करके इसे भारतीय विकास सहायता जारी रखी गई। सेंट जॉन्स एंटीगुआ में 21 जून 2015 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया विदेश और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री, चार्ल्स मैक्स फर्नाडीज इसके मुख्य अतिथि थे।

बारबाडोस

भारत और बारबाडोस के बीच प्रथम विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) 28 अप्रैल से 1 मई 2015 तक ब्रिजटाउन, बारबाडोस में आयोजित किया गया। श्री आर. स्वामीनाथन, विशेष सचिव (एएमएस एण्ड सीपीवी) ने 3 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल और सुश्री सिमोन रडर, स्थायी सचिव, विदेश मंत्रालय एवं विदेश व्यापार, बारबाडोस सरकार ने बारबाडोस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

भारत और बारबाडोस ने 6 अक्तूबर 2015 को वायु सेवा करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें दोनों देशों के बीच यात्रा आसान हो जाएगी।

कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका

हमारे द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत नवंबर 2015 में एक आईसीटी केंद्र स्थापित किया गया है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात एरिका के मद्देनजर मानवीय सहायता के रूप में डोमिनिका सरकार को 200,000 /– यूएस डॉलर की धन राशि उपलब्ध कराई गई थी।

संबंधित सरकारों के सहयोग से ग्रेनाडा और कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह पूर्वक मनाया गया था।

क्यूबा

क्यूबा के प्रथम उपराष्ट्रपति, मिगुएल डियाज–कैनल 23–25 मार्च 2015 से भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। इस एनएएम शिखर सम्मेलन के लिए अक्टूबर 1983 में तत्कालीन राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो की यात्रा भारत यात्रा के बाद यह क्यूबा की पहली उच्च स्तरीय यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान, क्यूबा के उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपतिए उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के गणमान्य अतिथि से मुलाकात की।

क्यूबा के ऊर्जा और खान उपमंत्री यूरी वियामोंटे लाजो ने 8 – 9 अक्तूबर 2015 को नई दिल्ली में आयोजित छठी सीआईआई इंडिया – एलएसी कॉन्क्लेव में भाग लिया। प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 – 22 जून 2015 को मनाया गया जिसमें लगभग 600 लोग शामिल हुए।

आयुष मंत्रालय की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल ने 21–25 जुलाई तक हवाना की यात्रा की और क्यूबा के विभिन्न संस्थानों के अतिरिक्त क्यूबा के प्राकृतिक और परंपरागत चिकित्सा विभाग तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। इस दौरे का उद्देश्य होम्योपैथी के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान करने की संभावनाओं का पता लगाना और क्यूबा के विश्वविद्यालयों में से एक में आयुर्वेद अथवा होम्योपैथी पीठ की स्थापना करने के बारे में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना था।

डोमिनिकन गणराज्य (डीआर)

विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ) वी के सिंह (सेवानिवृत्त) ने फरवरी 2015 में डीआर का दौरा किया। उन्होंने विदेश मंत्री नवारो से मुलाकात कीए एलएसी क्षेत्र के प्रति भारत की नीति पर एक भाषण दिया तथा व्यापार जगत के नेताओं के साथ बातचीत

की। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

18–21 अगस्त, 2015 को भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, डॉ नसीम जैदी ने पंटा काना, डोमिनिकन गणराज्य में आयोजित दूसरे ए–वेब महासभा और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया जहां दुनिया भर से लगभग 100 चुनावी निकायों के पैनल सदस्य एकत्र हुए।

हैती

हैती के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मैरी एल. फ्लोरेंस डुपरवाल ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आमंत्रण पर 25 – 29 अगस्त, 2015 को दिल्ली में थर्ड ग्लोबल कॉल टू एक्शन समिट में भाग लिया।

जमैका

किंगस्टन के प्रतिष्ठित नेशनल इंडोर स्पोर्ट्स सेंटर में 21 जून 2015 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। जमैका की खेल मंत्री सुश्री नीता हेडले ने इस समारोह को संबोधित किया।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तीन सदस्यों वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने समुद्री नियम संबंधी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुच्छेद 154 के अनुसरण में क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की समीक्षा के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के 21वें सत्र में भाग लेने के लिए जमैका का दौरा किया।

सेंट किट्स एण्ड नेविस

आईटीईसी कार्यक्रम के तहत भारत में यहां के नागरिकों को प्रशिक्षण देने सहित सेंट किट्स और नेविस को अन्य भारतीय विकास सहायता जारी रखी गई। सेंट किट्स एण्ड नेविस के राजधानी शहर बस्सेटेरे में 21 जून 2015 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।

त्रिनिदाद और टुबैगो

श्री आर. स्वामीनाथन, विशेष सचिव (एएमएस और सीपीवी) के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 3 – 6 जून 2015 तक त्रिनिदाद और टुबैगो का 3 दिवसीय दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने वहां के विदेश मंत्री, विंस्टन डूकरन और व्यापार, निवेश एवं संचार मंत्री वसंत भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया। भारतीय विदेश सेवा संस्थान तथा वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय (यूडब्ल्यूआई) के अंतरराष्ट्रीय संबंध संस्थान के बीच द्विपक्षीय सहयोग संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यूडब्ल्यूआई के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय भारतीय प्रवासी सम्मेलन 12 – 16 मई 2015 तक आयोजित किया गया । गुयाना, सुरीनाम, फिजी, यू. एस., यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और बारबाडोस के 50 से अधिक विद्वानों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

पूरे देश में 14 जून से शुरू करके 21 जून 2015 तक एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाय) का आयोजन किया गया जिसमें 500 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए और इसे सदन के स्पीकर ने इसे संबोधित किया। प्रतिष्ठित श्रोताओं में कानून मंत्री और अटॉर्नी जनरल माननीय वाडे मार्क भी उपस्थित थे।

सेंट लूसिया

प्रधानमंत्री ने 25 सितंबर 2015 को यूएनजीए के अवसर पर सेंट लूसिया के प्रधान मंत्री डॉ. केनी डी. एंथनी के साथ मुलाकात की और पारस्परिक हितों के द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की।

सेंट लूसिया सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, खेल और तकनीकी सहयोग के क्षेत्रों में भारत के साथ द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर करने में रुचि दिखाई है।

सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस

न्यूयॉर्क में 24 सितंबर 2015 को यूएनजीए बैठक के अवसर पर सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस के प्रधानमंत्री डॉ. रल्फ गोंसाल्विस ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध बनाने के बारे में वार्ता की और भारत तथा सेंट विसेंट और ग्रेनाडाइंस के बीच परंपरागत घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों पर संतोष व्यक्त किया।

बहामास

जून 2015 में भारत की मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने नसाउ में शिक्षा मंत्रियों के 19वें राष्ट्र मंडल सम्मेलन में भाग लेने के लिए बहामास में अपने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारतीय स्टेट बैंक, नसाउ द्वारा शिवानंद आश्रम और बहामास में भारतीय समुदाय के मुख्य सदस्यों की भागीदारी से 21 जून 2015 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया।

बहामास ने श्री जसोन लोवल मोर्टिमर को अपना अनिवासी उच्चायुक्त नियुक्त किया है जिन्होंने 30 अप्रैल 2015 को हमारे राष्ट्रपति के समक्ष अपने प्रत्यक्ष पत्र प्रस्तुत किया।

■ ■

संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और विधि और संधि प्रभाग

9

संयुक्त राष्ट्र में भारत

संयुक्त राष्ट्र महा सभा का 70वां सत्र

संयुक्त राष्ट्र महासभा (महासभा) का 70 वां सत्र न्यूयॉर्क में सितंबर 2015 में शुरू हुआ। माननीय प्रधानमंत्री (पीएम) श्री नरेन्द्र मोदी ने 24, 25 और 28 सितंबर 2015 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70 वें सत्र के उच्चस्तरीय खंड में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज (विदेश मंत्री) ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70 वें सत्र की सामान्य बहस में हिस्सा लेने के लिए 29 सितम्बर – 1 अक्तूबर 2015 को न्यूयॉर्क का दौरा किया।

प्रधानमंत्री ने 25 सितंबर, 2015 को सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को अपनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने जी –4 शिखर सम्मेलन (26 सितंबर 2015) की मेजबानी की और इस मौके पर (28 सितंबर 2015) शांति स्थापना पर शिखर बैठक के नेताओं के साथ इसमें भाग लिया। प्रधानमंत्री ने जॉर्डन नरेश, अमेरिका, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, गुयाना, मेक्सिको, फिलिस्तीन, श्रीलंका के राष्ट्रपति और स्वीडन, बांग्लादेश, भूटान, सेंट लुशिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन किया। प्रधानमंत्री ने सतत विकास शिखर सम्मेलन के अवसर पर 25 सितम्बर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव (यूएनएसजी) से मुलाकात की। उन्होंने यूएनएसजी में "भारत और

प्रधानमंत्री न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन (25 सितंबर, 2015) को संबोधित करते हुए

संयुक्त राष्ट्रः 70 साल" पर एक विशेष प्रकाशन प्रस्तुत किया, जिसमें 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के साथ भारत के संबंध में महत्वपूर्ण क्षणों को लेखबद्ध किया।

विदेश मंत्री ने 1 अक्तूबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस में अपने वक्तव्य में आतंकवाद सहित वैश्विक महत्व और सरोकार के मुद्दों पर को भारत के नजरिए पर प्रकाश डाला। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र की 70 वीं वर्षगांठ पर इसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए तत्काल जरूरत (यूएनएससी) को रेखांकित किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (सीसीआईटी) को अपनाने के लिए जल्द से जल्द अपील की।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70 वें सत्र के अवसर पर, बड़ी संख्या में आयोजित बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वार्ताओं का आयोजन किया गया जिसमें ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय बैठक और भारत–कैरीकॉम मंत्रिस्तरीय बैठकों की अध्यक्षता सहित भारत – सीईएलएसी, भारत–जीसीसी मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेना और सार्क विदेश मंत्रियों का दोपहर का भोज शामिल हैं। इसके अलावा, विदेश मंत्री ने यूनाइटेड किंगडम, मालदीव, सीरिया अन्य लोगों के अलावा श्रीलंका और नेपाल के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन किया। इन वार्ताओं/बैठकों के दौरान चर्चा में भारत के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंध तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक भागीदारी, व्यापार और निवेश तथा क्षेत्रीय एकीकरण के लिए एजेंडा 2030 शामिल था। विदेश मंत्री ने 29 सितंबर 2015 को न्यूयॉर्क में राष्ट्रमंडल के महासचिव से भी मुलाकात की।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70 वें सत्र में क्रमशः 19–25 अक्तूबर 2015 और 2–8 नवंबर 2015 की अवधि में संसद के 11 सांसदों के समूह ने भारत के गैर आधिकारिक दल के भाग के रूप में न्यूयॉर्क का दौरा किया। इनमें श्री कमलेश पासवान, भाजपा (राज्यसभा) श्री मनसुख एल मंदविया, भाजपा (राज्यसभा) श्री भर्तृहरि महताब, बीजेडी (राज्यसभा) श्री एस.पी. मुद्दहनुमेगौडा, कांग्रेस (राज्यसभा) श्री अभिषेक बनर्जी एआईटीसी (राज्यसभा) और श्रीमती विजिला सत्यानन्त, अन्नाद्रमुक (राज्यसभा) पहले बैच में शामिल थे। दूसरे बैच में प्रो. राम गोपाल यादव, एसपी (राज्यसभा) श्री रतन लाल कटारिया, बीजेपी (लोक सभा) श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, एनसीपी (लोक सभा) श्री राहुल कस्वां, बीजेपी (लोक सभा) और श्रीमती रीति पाठक, बीजेपी (लोक सभा) शामिल थे। इस यात्रा के दौरान, सांसदों ने कई संयुक्त राष्ट्र बैठकों/सम्मेलनों में भाग लिया और महासभा की बहस में राष्ट्रीय वक्तव्य दिए और सुरक्षा परिषद के काम करने के तरीकों और सुधार, आर्थिक और सामाजिक मामलों, अंतर्राष्ट्रीय कानून, निरस्त्रीकरण और अंतरिक्ष, टिकाऊ विकास, मानव अधिकारों और सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन के विभिन्न मुद्दों पर छह संयुक्त राष्ट्र महासभा समितियों में भाग लिया। सांसदों ने महासभा के अध्यक्ष, फील्ड समर्थन के लिए अपर महासचिव और न्यूयॉर्क में भारतीय अमरीकी संघ से भी मुलाकात की।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार

जी–4 शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में 26 सितंबर 2015 को आयोजित किया गया जो पहली ऐसी बैठक थी, जिसमें सभी जी –4 देशों का उच्चतम स्तर पर प्रतिनिधित्व था। शिखर सम्मेलन के दौरान अपने सम्बोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, ''जैसा कि मैंने संयुक्त राष्ट्र की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपने पत्र में लिखा है कि हम संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय से ही एक अलग मौलिक दुनिया में रहते हैं। इसके सदस्य देशों की संख्या में चार गुना वृद्धि हुई है। शांति और सुरक्षा के लिए खतरा और अधिक जटिल अप्रत्याशित और अपरिभाषित बन गया है। कई मायनों में, हमारा जीवन भूमंडलीकृत होता जा रहा है, किंतु हमारी पहचान के प्रति मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। हम एक डिजिटल युग में रहते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था बदल गई है, जिसमें वृद्धि के नए प्रेरक हैं, जो आर्थिक शक्ति में अधिक व्यापक रूप से फैले हैं और संपत्ति के अंतराल को बढ़ा रहे हैं। फिर भी, हमारे संस्थान, दृष्टिकोण, और मानसिकता अक्सर उस शताब्दी की कुशाग्रता को प्रदर्शित करते हैं, जिसे हमने पीछे छोड़ा दिया है, न कि वह शताब्दी जिसमें हम रहते हैं। यह विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए सच है। एक निश्चित समय सीमा के अंदर सुरक्षा परिषद में सुधार एक जरूरी और महत्वपूर्ण कार्य बन गया है। सुरक्षा परिषद में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों की वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रेरकों और सभी प्रमुख महाद्वीपों की आवाज़ को शामिल करना चाहिए। इससे अधिक विश्वसनीयता और वैधता आएगी और अधिक प्रतिनिधित्व होगा एवं 21 वीं सदी की चुनौतियों से निपटना अधिक प्रभावी हो जाएगा।''

प्रधान मंत्री ने यह कहकर अपना भाषण समाप्त किया कि 'दशकों के बाद, हम अंततः कुछ प्रगति देख रहे हैं। महासभा के 69 वें सत्र में पाठ के आधार पर वार्ता शुरू करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। यह संभव नहीं होता किंतु श्री सैम कुतेसा और एम्बेसडर कोर्ट्नी रत्तराय के सशक्त नेतृत्व के कारण ऐसा हो सका। हालांकि, यह सिर्फ पहला कदम है। हम यह लक्ष्य रखें कि 70वें सत्र के दौरान इस प्रक्रिया का युक्ति संगत निष्कर्ष निकाला जा सके। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बैठक इस दिशा में हमारे प्रयासों को एक बड़ा प्रोत्साहन देगी।''

शिखर सम्मेलन के अंत में जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्य में, जी–4 के नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70 वें सत्र के दौरान ठोस परिणामों को हासिल करने की दिशा में अपने प्रयासों को बढ़ाने में दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने अंतर सरकारी वार्ता (आईजीएन)

के दायरे में बातचीत के लिए आधार के रूप में दिनांक 31 जुलाई 2015 के अपने पत्र में 69 महासभा के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत पाठ का उपयोग करने के लिए महासभा निर्णय 69/560 को आम सहमति से स्वीकार किए जाने का स्वागत किया। मंत्रियों ने इस बात पर भी बल दिया कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता, स्थायी तथा अस्थायी दोनों, के विस्तार हेतु सदस्य राष्ट्रों के नेताओं ने इस बात पर बल दिया कि जी –4 देश एक विस्तारित और सुधार की गई परिषद् की स्थायी सदस्यता हेतु वैध उम्मीदवार हैं और एक दूसरे की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं।

विदेश मंत्री ने 1 अक्तूबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70 वें सत्र की आम बहस में कहा, ''यदि हमें वैश्विक शांति, सुरक्षा और विकास के संरक्षक के रूप में सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र का महत्व और इसकी वैधता बनाए रखनी है, तो इसमें सुधार इसकी सबसे जरूरी और उपयोगी आवश्यकता है। यह समय की मांग है। हमारे पास 2015 में ऐसी एक सुरक्षा परिषद कैसे हो सकती है जो अभी भी 1945 के भू–राजनीतिक संरचना को दर्शाती है। हमारी सुरक्षा परिषद ऐसी किस प्रकार हो सकती है जो अभी भी अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को एक स्थायी सदस्य के रूप में जगह नहीं देती है। सुरक्षा परिषद की रूपरेखा बनाने का निर्णय लेने में हमें और अधिक विकासशील देशों को शामिल करने की जरूरत है। और हमें पुरानी और गैर–पारदर्शी कार्य विधियों को हटाकर काम करने के तरीके को बदलने की जरूरत है। परिषद को अधिक वैधता और संतुलन प्रदान करने से इसकी विश्वसनीयता बहाल होगी और इसे हमारे समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए लैस किया जा सकेगा। हमें खुशी है कि पिछले एक वर्ष के दौरान माननीय श्री सैम कुटेसा और माननीय श्री कॉर्टने रत्तराय के नेतृत्व में हमने वह सब अर्जित किया है जो चर्चा के दो दशकों से अधिक समय में हम नहीं कर सके – बातचीत करने के लिए एक पाठ, जिसे सर्वसम्मति से निर्णय 69/560 के तहत आम सभा में सर्वसम्मति से अपनाया गया। यह पहली बार हुआ, लेकिन यह महत्वपूर्ण कदम है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस ऐतिहासिक 70 वें सत्र में कार्रवाई के लिए स्प्रिंगबोर्ड की तरह होना चाहिए।''

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70वें सत्र के प्रारंभ से पहले, जी –4 देशों से महानिदेशकों (ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान) ने 10 जुलाई 2015 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विचार / कार्यनीति का आदान–प्रदान करने के लिए ब्राजीलिया में मुलाकात की थी और संयुक्त राष्ट्र में चल रहे आईजीएन की स्थिति पर चर्चा की।

जलदस्युतारोधी कार्रवाई

भारत ने न्यूयॉर्क में 8 जुलाई 2015 को आयोजित सोमालिया के तट पर जलदस्युता पर संपर्क समूह (सीजीपीसीएस) की 18 वीं पूर्ण बैठक में भाग लिया। भारत के नजरिए से यह चोरी, उच्च जोखिम वाले क्षेत्र (एचआरए) विचार–विमर्श, निजी जहाजों पर सुरक्षा कंपनियों और निजी अनुबंधित सशस्त्र कार्मिक ऑन बोर्ड समुद्री सुरक्षा के विनियमन के महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक था। सीजीपीसीएस बैठक के अंत में जारी विज्ञप्ति में, तीन महीने के भीतर निर्देशांक सहित, वैश्विक शिपिंग और तेल उद्योग एचआरए की एक ठोस समीक्षा शुरू करने और सीजीपीसीएस के चेयर के समक्ष निष्कर्षों की रिपोर्ट करने के लिए सहमत हुए। बाद में, और समीक्षा के एक परिणाम के रूप में, 8 अक्तूबर 2015 को वैश्विक शिपिंग और तेल उद्योग द्वारा यह घोषणा की गई कि 1 दिसंबर 2015 से, जलदस्युता उच्च जोखिम वाले क्षेत्र की पूर्वी सीमा 780 ई (भारत के पश्चिमी समुद्र तट) को 650 ई देशांतर से संशोधित किया जाएगा।

शांति स्थापना

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में शांति स्थापना संबंधी मुद्दों पर अपनी सक्रिय भागीदारी जारी रखी जिसमें समापन व्यक्तव्य और शांति स्थापना पर विशेष समिति (70 वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति) के अंदर वाद–विवाद भी शामिल है।

प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में 28 सितंबर, 2015 को शांति स्थापना पर नेताओं की शिखर बैठक में भाग लिया। इस शिखर बैठक में, प्रधानमंत्री ने शांति कर्मियों, समर्थकों और प्रशिक्षण के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के लिए भारत के बढ़ाए गए योगदान की घोषणा की। उन्होंने निर्णय लेने की प्रक्रिया में योगदान देने वाले देशों की टुकडियों (टीसीसी) के लिए एक सशक्त आमंत्रण भी दिया। इसके अलावा, भारत ने अफ्रीका से शांति सैनिकों के लिए संयुक्त राष्ट्र मिशन में तकनीकी कर्मियों की तैनाती और महत्वपूर्ण समर्थक प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ, एक नए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत में 'तीन' महिला शांति सैनिकों के उच्च प्रतिनिधित्व सहित अतिरिक्त पुलिस इकाइयों, मौजूदा या नए कार्यों में 850 सैनिकों की एक अतिरिक्त बटालियन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता की है।

भारत ने इस दृष्टिकोण को बनाए रखा है कि यह महत्वपूर्ण है कि योगदान देने वाले देशों की सेना और पुलिस आज के बहुआयामी शांति अभियानों में जनादेश विकास में और निर्णय लेने की प्रक्रिया सहित मिशन योजना के सभी पहलुओं में पूरी तरह से शामिल रहे हैं। इस संबंध में भारत ने अक्तूबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा गठित और तिमोर–लेस्ते के पूर्व राष्ट्रपति, श्री जोस रामोस होर्ता के नेतृत्व में शांति संचालन पर उच्च स्तरीय स्वतंत्र पैनल (एचआईपीपीओ) की रिपोर्ट का स्वागत किया है। भारत से पैनल के सदस्यों में लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत गुहा (सेवानिवृत्त) शामिल थे। पैनल ने 5–7 फरवरी 2015 के दौरान भारत का दौरा किया है और विदेश मंत्री और रक्षा सचिव के साथ

मुलाकात की। भारत द्वारा संगत कार्यालयों के साथ संयुक्त राष्ट्र के प्रति सकारात्मक विचार की दिशा और एचआईपीपीओ रिपोर्ट के अंतिम कार्यान्वयन हेतु मिलकर कार्य किया जाएगा।

भारत अब तक संयुक्त राष्ट्र के 69 शांति अभियान प्रचालनों में से 48 मिशनों में 180,000 से अधिक सैनिकों की तुलना में समग्र योगदान के साथ संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए देशों में सैनिकों के योगदान के बीच मजबूत स्थिति (समग्र संदर्भ में) में रहा है। 31 अक्तूबर 2015 की स्थिति के अनुसार, भारत लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन पर पहली बार महिला गठित पुलिस इकाई सहित दस संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में तैनात 7796 कर्मियों के साथ तीसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (3662), दक्षिण सूडान (2,318), लेबनान (897), हैती (460), लाइबेरिया (253), और गोलान हाइट्स पर्याप्त भारतीय उपस्थिति के साथ सीरिया इजरायल सीमा (190) पर संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं। भारतीय सैनिकों और पुलिस कार्मिकों द्वारा चुनौतिपूर्ण परिस्थितियों में उच्चस्तरीय निष्पादन ने उन्हें दुनिया भर में उच्च सम्मान प्रदान किया है।

संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने 29 मई 2015 को एक सादे समारोह में 125 डैग हैम्बर्स जोल्ड पुरस्कार जीतने वाले संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, जिन्हें इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर एक संदेश भेजा जिसे समारोह के दौरान पढ़कर सुनाया गया। समारोह के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के मिशन द्वारा एक अनोखा प्रयास किया गया, जिसमें एक आभासी स्मृति दीवार बनाई गई और इसे उन 161 भारतीय शांति सैनिकों को समर्पित किया गया जिन्होंने अब तक संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। यह प्रयास अंततः न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के परिसर में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक स्मृति दीवार के निर्माण की शुरूआत है, जैसा कि भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

आतंकवाद

भारत ने 1267 अल कायदा प्रतिबंध समिति सहित यूएनएससी प्रतिबंध समिति एवं अलकायदा और तालिबान निगरानी दल के साथ नजदीकी से कार्य करते हुए सुनिश्चित किया कि प्रतिबंध की व्यवस्था में सदस्य राष्ट्रों द्वारा इसका कठोरतापूर्वक पालन किया जाए। इसके अलावा, भारत संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी निकायों जैसे काउंटर टेररिज्म कमिटी एग्जिक्यूटिव डायरेक्टरेट (सीटीईडी) के साथ कार्य करता है और इनकी कार्यशालाओं में नियमित रूप से भाग लेता है। सीटीईडी द्वारा 19 – 21 अक्तूबर 2015 के बीच बैंकॉक में न्यायाधीशों, अभियोजकों और पुलिस अधिकारियों के लिए दसवीं क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति की एक विशेष बैठक 28 जुलाई 2015 को मेड्रिड, स्पेन में विदेशी आतंकवादियों के आने पर रोक लगाने के लिए आयोजित की गई। भारत ने दोनों में हिस्सा लिया।

भारत सभी प्रयासों का पुरजोर समर्थन करता है, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्राधिकार के अंदर उन सभी प्रयासों का, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत बनाते हैं। इस संदर्भ में भारत ने कानूनी साधनों के विस्तार को बढ़ाने और आतंकवादियों के लिए सुरक्षित ठिकानों को नष्ट करने के प्रयास बढ़ाने, उनके वित्तीय समर्थन और सहायता नेटवर्कों को मिटाने एवं आतंकवादियों को न्याय के दायरे में लाने की जरूरत पर बल दिया। भारत सीसीआईटी के शीघ्र निष्कर्ष की ओर, यदि संभव होता है तो यूएनजीए के 70वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र की 6वीं समिति की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है।

प्रथम योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस

संयुक्त राष्ट्र में 21 जून 2015 को प्रथम योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस के समारोह की अध्यक्षता करने के लिए विदेश मंत्री ने 20–22 जून 2015 (रविवार) तक न्यूयॉर्क का दौरा किया। समारोह में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रवि शंकर द्वारा एक प्रदर्शन के साथ विशेष रूप से एक मुख्य व्याख्यान दिया। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को संकल्प ए / रेस / 69 / 131 को दिसंबर 2014 में अपनाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की थी, जो एक भारतीय प्रयास था और जिसे संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों की रिकॉर्ड संख्या द्वारा समर्थन दिया गया। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69 वें राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में भारतीय शांति सैनिकों की भूमिका पर लिपिबद्ध एक पुस्तक जारी की।

9वां अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की न्यासी परिषद में 2 अक्तूबर 2015 को भारत के स्थायी मिशन द्वारा एक विशेष समारोह में संयुक्त राष्ट्र अहिंसा का 9वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया। विदेश सचिव, डॉ. एस जयशंकर ने समारोह की अध्यक्षता की, जिसमें बांग्लादेश के वित्त मंत्री के अलावा 69वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष श्री मोजीन्स लिकेटोफ्ट और संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भाग लिया। समारोह के दौरान, विदेश सचिव ने

संयुक्त राष्ट्र, न्यूयार्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून सभा को संबोधित करते हुए

न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव

चरखा कातते हुए महात्मा गांधी का बड़े आकार का एक चित्र, महा सचिव को भेंट किया।

राष्ट्रमंडल

भारत राष्ट्रमंडल बजट के लिए चौथा सबसे बड़ा अंशदाता है और तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रमंडल कोष में पांचवां सबसे बड़ा अंशदाता रहा है। विदेश मंत्री ने 27 – 29 नवंबर 2015 को माल्टा में आयोजित राष्ट्र मंडल शासनाध्यक्षों की प्रमुखों की शासकीय बैठक (सीजीओजीएम) में भारतीय शिष्ट मंडल का नेतृत्व किया। उसके पहले, 25 और 26 नवंबर 2015 को माल्टा में विदेश राज्य मंत्रीए जनरल (डॉ) वी के सिंह (सेवानिवृत्त) (राज्यमंत्री) (वीकेएस) ने चोगम राष्ट्रमंडल विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया और राष्ट्रमंडल मंत्री स्तरीय कार्य समूह (सीएमएजी) की बैठक आयोजित की गई। चोगम 2015 के दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्र मंडल लघु राज्य व्यापार वित्त सुविधा में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अंशदान देने की घोषणा की। चोगम 2015 में जलवायु कार्य और रिट्रीट सत्र के अंत में एक वक्तव्य अपनाया गया।

सीएचओजीएम 2015 में, भारत को एक बार फिर से 2015–17 अवधि के लिए पुनर्गठित राष्ट्रमंडल मंत्री स्तरीय कार्य समूह (सीएमएजी) के सदस्य के रूप में नामित किया गया था।

गुट–निरपेक्ष आंदोलन (एनएएम)

संस्थापक सदस्य के रूप में, भारत ने गुट–निरपेक्ष आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है, क्योंकि इसने विकासशील देशों को सामूहिक रूप से राजनैतिक और आर्थिक मुद्दों के क्षेत्र में अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान किया है। शीत युद्ध के बाद के युग में, एन ए एम में निःसंदेह महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। फिर भी आंदोलन अत्यधिक संगत बना रहा, विशेष रूप से उन मुद्दों के संबंध में जहां दक्षिण के देशों के मध्य विचारों की समानता संभव होती है। अलजीयर्स (अलजीरिया) ने 26–29 मई, 2014 को आयोजित पिछली मध्यावधि एन ए एम मंत्रीमण्डलीय सम्मेलन और इसके बाद तेहराना, ईरान में अंतिम (16वें) एनएएम सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। अगला एन ए एम सम्मेलन 2016 में वेनेजुएला में होना निश्चित हुआ है।

लोकतांत्रिक पहल

(i) लोकतांत्रिक समुदाय : लोकतांत्रिक समुदाय पूरे विश्व में लोकतांत्रिक नियमों का समर्थन करने और लोकतांत्रिक व्यवहारों और संस्थाओं को सुदृढ़ करने के एक समान लक्ष्य की तलाश में सरकारों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र को एक साथ लाने के लिए राष्ट्रों का एक वैश्विक अंतर–सरकारी गठबंधन है। भारत लोकतांत्रिक समुदाय का एक सक्रिय सदस्य रहा है और यह इसके शासी परिषद का एक सदस्य भी है। शासी परिषद की बैठकें तिमाही आधार पर होती हैं। राज्य मंत्री (वीकेएस) ने 22–24 जुलाई 2015 को सान साल्वाडोर में सीओडी की 8वीं मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लिया। राज्य मंत्री ने समापन सत्र के अवसर पर भाषण दिया और उन्होंने 'लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नवीन साधन' नामक विषय के तहत विषय 'लोकतंत्र के लिए ई–लोकतंत्र, ई सरकार और घरेलू' पर सरकारों और नागरिक समाज संगठनों के बीच एक परस्पर इंटरएक्टिव वार्ता सत्र के पूर्ण अधिवेशन में भी भाग लिया। सीओडी के 8 वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का विषय 'लोकतंत्र और विकास' था। भारत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के मौके पर 17वीं शासी परिषद की बैठक के दौरान शासन और प्रभावशीलता पर सीओडी कार्य समूह में सदस्य के रूप में शामिल हुआ। राज्य मंत्री (वीकेएस) ने स्लोवाकिया के उप प्रधानमंत्री, मंगोलिया के विदेश मंत्री, लिथुआनिया और जापान के उप विदेश मंत्रियों और सीओडी के महासचिव के साथ द्विपक्षीय विचार–विमर्श किया। राज्य मंत्री (वीकेएस) ने अल साल्वाडोर के उप राष्ट्रपति को भी निमंत्रण दिया और अल सल्वाडोर के विदेश मंत्री से मुलाकात की।

(ii) बाली लोकतंत्र फोरमः इंडोनेशिया के बाली में 'लोकतंत्र और प्रभावी लोक प्रशासन' विषय पर 10–11 अक्तूबर, 2015 को 8वां बाली लोकतंत्र फोरम (बीडीएफ सात) की बैठक आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में भारत के राजदूत ने इंडोनेशिया में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत ने इस बात का उल्लेख किया कि एक समावेशी प्रतिनिधित्वमूलक और अनुकूल लोकतांत्रिक भावना ही उसकी सांस्कृतिक धरोहर है और यह कि स्त्री–पुरूष समानात तथा महिला सशक्तिकरण प्राथमिकता वाले क्षेत्र है।

(iii) संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि (यू एन डी ई एफ) : भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच भागीदारी के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि (यू एन डी ई एफ) की शुरूआत की गई थी और 14 सितंबर 2005 को न्यूयॉर्क में शुरू किया गया था। वर्तमान में भारत यू एन डी ई एफ का दूसरा सबसे बड़ा अंशदाता है, जिसने 2014–15 में 200,000 अमेरिकी डॉलर सहित नवंबर 2015 तक 31.76 मिलियन अमेरिकी डॉलर की समग्र राशि का अंशदान दिया है। भारत इसे लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं के संवर्धन के लिए एक प्रभावी तंत्र मानता है और सर्वोच्च शासी निकाय के सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में यू एन डी ई एफ में एक अहम भूमिका निभाता है। यूएनडीईएफ वर्तमान में, उन परियोजनाओं को समर्थन देती है जो नागरिक समाज की आवाज को मजबूत बनाने, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सभी समूहों की भागीदारी प्रोत्साहित करती हैं। अपनी स्थापना के बाद से, यूएनडीईएफ ने छः मुख्य क्षेत्रों अर्थात, सामुदायिक विकास, कानून और मानव अधिकार के नियम, लोकतंत्रीकरण के लिए उपकरण, महिलाएं, युवाएं, और मीडिया में 110 से अधिक देशों में लगभग 500 परियोजनाओं का

वित्तपोषण किया है।

चुनाव

भारत ने मानवाधिकार परिषद (एचआरसी) और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) सहित 30 से अधिक संयुक्त राष्ट्र निकायों में प्रतिनिधित्व किया है। 2015 में, भारत को 2016–2019 अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव पुनर्वास कार्यक्रम की संचालन परिषद (यूएन–अधिवास), 2016–2018 अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (यूएन–डब्लूएफपी) के कार्यकारी बोर्ड, 2016–2022 अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल), 2016–2017 अवधि के लिए शांति स्थापना आयोग (पीबीसी) संगठन समिति, 2016–2018 अवधि के लिए श्रेणी बी के तहत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद और अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (आईओसी) की कार्यकारी परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया था

यू–एन मानवाधिकार परिषद (एचआरसी)

जनवरी 2015 में मानवाधिकार परिषद (एचआरसी) के एक सदस्य के रूप में भारत ने लगातार दूसरी बार तीन वर्ष का कार्यकाल शुरू किया था। भारत ने 2015 में आयोजित परिषद् के तीन नियमित सत्रों तथा आतंकवादी समूह बोको हरम पर 23वें विशेष सत्र के कार्य और कार्रवाईयों पर एक संतुलित तथा व्यावहारिक मार्ग अपनाया। भारत ने उनमें से कुछ संकल्पों को आकार देने में रचनात्मक भागीदारी की जिन्हें वर्ष के दौरान एचआरसी द्वारा अपनाया गया। एचआरसी, विभिन्न विषय वस्तु मुद्दों पर ध्यान देने के अलावा सीरिया पर देश विशिष्ट संकल्पों को अपनाकर देश विशिष्ट परिस्थितियों पर, कोरिया जनवादी गणराज्य (डीपीआरके), म्यांमार, ईरान और श्रीलंका, और फिलिस्तिन पर केंद्रित रहा। भारत ने 42 देशों में से 20 की समीक्षा के दौरान वक्तव्य देकर एचआरसी की सार्व भौमिक अवधि समीक्षा (यूपीआर) में भी रचनात्मक रूप से योगदान दिया, जिन पर इस वर्ष विचार किया गया। इसके अलावा, भारत ने कुवैत, मालदीव और साओ टोम तथा प्रिंसीपी के यूपीआर के लिए ट्रॉएका के सदस्य के रूप में कार्य किया।

महत्वपूर्ण संधि निकायों के सदस्यों और मानवाधिकार तंत्र के रूप में विशिष्टता के साथ तीन प्रख्यात भारतीयों ने सेवा जारी रखी है जिसमें राजदूत दिलीप लाहिरी (उपाध्यक्ष, नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति – सीईआरडी), राजदूत चंद्रशेखर दासगुप्ता (उपाध्यक्ष, आर्थिक समिति सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार – आईसीईएससीआर) और श्री किशोर सिंह ;शिक्षा के अधिकार पर विशेष दूत) भी शामिल है।

अंतर–संसदीय संघ (आईपीयू)

लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने भारतीय संसदीय प्रतिनिमंडल का नेतृत्व किया, जिसमें लोक सभा तथा राज्य सभा के सदस्यों सहित भारतीय संसद का शिष्ट मंडल शामिल था, जिन्होंने जेनेवा में 10–16 अक्तूबर, 2014 तक अंतर–संसदीय संघ (आईपीयू) के 131वीं आईपीयू सभा में भाग लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने "न्यायपूर्ण स्मार्ट और अधिक मानवीय प्रवास के लिए नैतिक और आर्थिक अनिवार्यता" विषय पर आईपीयू महासभा को संबोधित किया। भारतीय संसदीय प्रतिनिमंडल ने आईपीयू सभा के चारों खंडों, पैनल चर्चा, विभिन्न मुद्दों पर आईपीयू समिति के सत्रों, आपातकालीन सत्रों और पूर्व तथा पश्च–सभा सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया। श्री नागेन्द्र सिंह, माननीय सांसद को औपचारिक रूप से सतत विकास पर स्थायी समिति के एशिया–प्रशांत समूह की एक ब्यूरो के सदस्य, वित्त और व्यापार के रूप में समर्थन दिया गया है। श्री आर. के. सिंह, माननीय सांसद, शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थायी समिति के ब्यूरो में पहले से ही हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)

भारत ने 19 वर्ष के अंतराल के बाद विश्व स्वास्थ्य सभा (डब्ल्यूएचए), विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, श्री जगत प्रकाश नड्डा (एचएफएम) ने 18 – 26 मई 2015 को जेनेवा में आयोजित 68वें डब्ल्यूएचए के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिन्हें सर्वसम्मति से सभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। डब्ल्यूएचओ की भारत की प्रतिबद्धता के एक प्रतिबिंब के रूप में, प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी के तौर पर, एचएफएम ने विभिन्न डब्ल्यूएचओ कार्यक्रमों और कोषों के लिए 2.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर अतिरिक्त स्वैच्छिक अंशदान की घोषणा की।

भारत ने एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर पहली वैश्विक कार्य योजनाए वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर पहले डब्ल्यूएचए संकल्प के साथ ही पोलियोए ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान और वैश्विक कार्यनीति पर प्रस्तावों सहित 68 डब्ल्यूएचए के प्रमुख परिणामों में से कुछ में और सार्वजनिक स्वास्थ्य नवाचार और बौद्धिक संपदा पर योजना की कार्रवाई में सक्रिय रूप से योगदान दिया।

भारत ने नवंबर 2015 में आयोजित चौथी बैठक में घटिया, नकली, झूठे लेबल, ग़लत और नकली (एसएसएफएफसी) चिकित्सा उत्पादों और डब्ल्यूएचओ प्रशासन सुधार पर आयोजित बैठकों में सदस्य राष्ट्र तंत्र में एक सक्रिय भूमिका निभाना जारी रखा – जो अराजकीय तत्वों के साथ वार्ता कार्यढांचा रूपरेखा के जुड़ाव और डब्ल्यूएचओ की आपात क्षमताओं को मजबूत करने के मद्देनजर इबोला संकट के लिए शुरू किए गए सुधारों पर आयोजित की गई थीं।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई. एल. ओ.)

श्री बंडारू दत्तात्रेय, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (राज्यमंत्री) ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) के 104 वें सत्र के लिए सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिसे 01.13 जून 2015 को जेनेवा में आयोजित किया गया था। भारत की ओर से आईएलसी के प्रमुख नियोक्ता और कार्यकर्ता समूहों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इसके अलावा, गुजरात, तेलंगाना और मध्य प्रदेश राज्यों के श्रम मंत्रियों ने आईएलसी में भाग लिया। 104वें आईएलसीके महत्वपूर्ण परिणामों में से एक परिणाम 'औपचारिक से अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव' विषय पर की गई सिफारिश को स्वीकार किया जाना था, जिसमें भारत ने एक रचनात्मक भूमिका निभाई है। भारत ने सक्रिय रूप से विभिन्न तकनीकी समितियों की चर्चाओं में भी भाग लिया। भारत को सर्वसम्मति से सम्मेलन के दौरान आयोजित एएसपीएजी की मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान एशिया–प्रशांत क्षेत्रीय समूह के क्षेत्रीय समन्वयक के रूप में निर्वाचित किया गया था।

भारत ने नवंबर 2015 में आयोजित आईएलओ की शासी निकाय के 325वें सत्र में भाग लिया और कई विषयक मुद्दों के साथ ही देश में विशिष्ट शिकायतों पर एएसपीएजी समन्वयक के रूप में समूह पक्षों को देखा। भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन से संबंधित आईएलओ की जारी सुधार प्रक्रिया सहित पर्यवेक्षी तंत्र की समीक्षा और आईएलओ के मानक समीक्षा तंत्र से जुड़ा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर)

सचिव (एम एंड ई) तथा जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर), सुश्री सुजाता मेहता ने 26 अगस्त 2015 को आयोजित भारत सरकार के बीच 5वें उच्च स्तरीय द्विपक्षीय परामर्श का नेतृत्व किया, जहां शरणार्थियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। यूएनएचसीआर ने विशेष रूप से शरणार्थियों को बेहतर ढंग संभालने के लिए भारत की सराहना की और शहरी शरणार्थियों सहित भारत के शरणार्थी संरक्षण के उपाय को अन्य देशों द्वारा अपनाने के लिए एक रोल मॉडल के रूप में करार दिया।

भारत ने 5.9 अक्तूबरए 2015 को जिनेवा में हुए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग ;यूएनएचसीआर) की कार्यकारिणी समिति के 65वें सत्र में भाग लिया और विकासशील देशों के योगदान की दक्षता, समाधान के स्थानीयकरण, नकदी आधारित प्रोत्साहन के उपयोग में वृद्धि, और इसे स्वीकार करने पर बल दिया है जिन्होंने आज के लगभग 80% शरणार्थियों को संभाला। अफगानिस्तान के उच्चस्तरीय घटक (एचएलएस) पर भारत का सामाजिक और बुनियादी रूपरेखा निर्माणए अफगानिस्तान के लोगों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर सार्थक बनाने की दिशा में अफगान शरणार्थियों के पुनर्वास और वापसी के लिए अनुकूल वातावरण की दिशा में योगदान देने के उद्देश्य से विकास सहयोग पर प्रकाश डाला।

अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (आईएचएल)

भारत रेड क्रॉस के 32 वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और रेड क्रीसेंट के लिए दिसंबर 2015 में सशस्त्र संघर्ष के पीड़ितों के लिए कानूनी सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए स्विट्जरलैंड और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस (आईसी आर सी) समिति द्वारा आयोजित बैठकों के आयोजन में सक्रिय रूप से संलग्न रहा है।

एच. आई. वी./एड्स (यूएनएड्स) पर साझा संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम

भारत ने एचआईवी / एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम (यूएनएड्स) की कार्यक्रम समन्वय बोर्ड (पीसीबी) की बैठकों में एक सक्रिय भूमिका निभाना जारी रखा जिन्होंने 2015 में यूएनएड्स फास्ट ट्रैक कार्यनीति 2016–2021 और यूएनआईएडीएस एकीकृत बजट जवाबदेही ढांचा (यूबीआरएएफ) 2016–2021 पर विचार किया और अपनाया। वर्ष 2030 तक एड्स महामारी समाप्त करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है और सस्ती तथा गुणवत्ता वाली रेट्रो वायरल रोधी दवा सफलतापूर्वक प्रदान करने पर बल देने के भारत के सुझाव को फास्ट ट्रैक की अंतिम रणनीति में शामिल किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन (आईओएम)

भारत आईओएम–संयुक्त राष्ट्र के संबंधों; प्रवास अभिशासन ढांचाए 2016 के लिए कार्यक्रम और बजट से संबंधित वार्ता में सक्रिय रूप से व्यस्त है और आईओएम की दक्षता में आगे सुधार और अपने मूल अधिदेश का पालन करते हुए प्रमुख प्रवास एजेंसी के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखने की जरूरत पर बल दिया गया है। आईओएम को लगातार मौजूदा शरणार्थी संबंधी चुनौतियों पर प्रवास के आर्थिक और सामाजिक आयाम की प्रधानता सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने के लिए अनुस्मरण कराया गया था।

भारत ने जिनेवा में 24–27 नवम्बर 2015 को रचनात्मक रूप से आयोजित आईओएम की 106 परिषद सत्र के विचार–विमर्श में भाग लिया। यह सत्र आईओएम–संयुक्त राष्ट्र संबंध और प्रवासन अभिशासन ढांचे के प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए उल्लेखनीय था। आईओएम में सुरक्षित, सम्मानजनक और क्रमबद्ध प्रवास से संबंधित संधारणीय विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए इनकी जांच करने और विभिन्न कार्यनीतियों के सुझाव और रूपरेखाओं देने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

प्रवास तथा विकास पर वैश्विक मंच (जीएफएमडी)

भारत ने इस्तांबुल में 14–16 अक्तूबर 2015 को प्रवासन और विकास (जीएफएमडीद्ध के विश्व मंच की 8वीं वार्षिक बैठक में प्रवासन से जुड़े विकासात्मक आयामों का उल्लेख किया। भारत ने प्रेषक और गंतव्य देशों के लिए एक विजय की स्थिति की दिशा में एक अनुकूल माहौल बनाने और प्रवास की वास्तविक क्षमता का दोहन करने के लिए समर्थन का नेतृत्व किया। भारत के फ्लैगशिप कार्यक्रमों, विशेषकर जन धन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रवासी मजदूरों को प्रस्तावित सुरक्षा उपायों, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं की सफलता को स्वीकार किया और सराहा गया।

भारत ने कुछ विकसित देशों द्वारा प्रवर्धित अवधारणा दूर की है जिसमें प्रेषण को उनके विदेशी विकास सहायता (ओडीए) प्रतिबद्ध ताओं के लिए एक विकल्प के रूप में चित्रित किया गया है। भारत ने इस आवश्यकता पर बल दिया है कि प्रेषण को व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय के रूप में लिया जाए और इसका ओडीए से कोई संबंध नहीं है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कार्यनीति (यूएनआईएसडीआर)

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून 2015 को आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाइ रूपरेखा का समर्थन किया जो सेंडाइ, जापान में 14–18 मार्च 2015 के बीच आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तीसरी संयुक्त राष्ट्र के विश्व सम्मेलन के परिणाम के रूप में आयोजित किया गया था। भारत ने मूल्यवान जानकारी देकर, समान विचारधारा वाले समूहों के साथ साझा पक्षों का खुलासा करके, समान सरोकारों तथा हितों वाले देशों के साथ सामरिक मुद्दों पर परामर्श करके बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत ने 17–19 नवंबर 2015 को दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण एशिया भागीदारी (आईएपी) की बैठक के लिए दूसरी अंतर्राष्ट्रीय कार्यनीति की मेजबानी की जिसमें एशिया–प्रशांत क्षेत्र से मंत्रियों और 100 से अधिक नीति निर्माताओं और चिकित्सकों ने भाग लिया। भारत ने क्षमता निर्माण और समर्थन के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण सेंडाइ ढांचे के कार्यान्वयन का समर्थन करने की दिशा में यूएनआईएसडीआर के लिए 1 मिलियन अमेरिका डॉलर के अंशदान की घोषणा की।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी)

भारत ने व्यापार एवं विकास बोर्ड की यूएनसीटीएडी की बैठकों में, एक वर्षीय तथा बहुवर्षीय विशेषज्ञ बैठकों में अपनी भागीदारी जारी रखी। अंकटाड के सभी देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों के लाभ के लिए व्यापार और विकास के क्षेत्र में एक यथार्थवादी नीति विश्लेषण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने सितंबर 2015 में आयोजित व्यापार और विकास बोर्ड की बैठक के 62 वें सत्र में भाग लिया, जहां उसने उच्च स्तरीय खंड पर चर्चा में भाग लिया, जिसमें दो विषयों अर्थात् संप्रभु बाह्य ऋण के प्रबंधन के लिए और व्यापार सर्व विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में महिलाओं की भूमिका पर बहुपक्षीय प्रक्रियाओं पर चर्चा की गई।

संयुक्त राष्ट्र विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा विकास आयोग (यूएन– सीएसटीडी)

संयुक्त राष्ट्र विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा विकास आयोग संयुक्त राष्ट्र विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा विकास आयोग के सदस्य के रूप में भारत ने मई 2015 में जेनेवा में आयोजित 18 वें सत्र में भाग लिया। भारत नेः एक शीर्षक ”सतत विकास लक्ष्यों के लिए सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों से संधारणीय विकास लक्ष्यों की ओर बदलाव का प्रबंधनः विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका”, और अन्य शीर्षक ”डब्ल्यूएसआईएस के परिणामों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा” नामक दो मंत्रिमंडलीय गोल मेज बैठकों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ)

जिनेवा में 25 मई–12 जून 2015 को 17वां विश्व मौसम विज्ञान महा सम्मेलन हुआ। माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री, श्री वाय. एस. चौधरी ने महासम्मेलन के भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत ने डब्ल्यूएमओ की कार्यकारी समिति के एक सदस्य के रूप में 2015 के दौरान डब्ल्यूएमओ में प्रामाणिक और संस्थागत घटनाक्रम के विकास में सक्रिय भूमिका जारी रखी।

संयुक्त राष्ट्र एशिया तथा प्रशांत आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यू एन ई एस सी ए पी)

बैंकॉक में 28–29 मई 2015 को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) में 71वें वार्षिक आयोग सत्र में श्रीमती निर्मला सीतारमण, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री (प्रभारी) ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। श्रीमती सीतारमण ने आयोग सत्र के विषय” सतत विकास के तीन आयामों का संतुलनः समेकन से कार्यान्वयन तक” पर देश की ओर से एक वक्तव्य दिया और उसी विषय पर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। आयोग सत्र के दौरान, भारत को इंचियोन में विकास सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (एपीसीआईसीटी) एशियाई और प्रशांत प्रशिक्षण केंद्र की शासी परिषद और बीजिंग में सतत कृषि यंत्रीकरण केंद्र (सीएसएएम) के लिए पुनः निर्वाचित किया गया।

विकास के लिए वित्त पोषण

अदीस अबाबा, इथियोपिया में 13–16 जुलाई 2015 को आयोजित विकास के लिए वित्त पोषण पर वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा ने तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। सम्मेलन के महत्वपूर्ण परिणामों में एक प्रौद्योगिकी सरलीकरण तंत्र और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक तंत्र शामिल थे और विकास सम्मेलन के वित्त पोषण के कार्यान्वयन के परिण ााम और 2015 के पश्चात विकास एजेंडा के कार्यान्वयन के साध ान की समीक्षा शामिल थे। सम्मेलन में स्वीकृत परिणाम दस्तावेज "अदीस अबाबा कार्रवाई एजेंडा (एएए)" में 1992 रियो घोषणा के सिद्धांतों की पुनः पुष्टि की गई और 2015 के बाद के विकास हेतु वित्त पोषण के लिए एक वैश्विक रूपरेखा के प्रदान की है।

संयुक्त राष्ट्र संधारणीय विकास शिखर सम्मेलन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 सितंबर, 2015 को संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। शिखर सम्मेलन में सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा अपनाया गया। नया एजेंडा गरीबी उपशमन और अगले 15 वर्षों के लिए संधारणीय विकास हेतु एक वैश्विक रूपरेखा है।

2030 एजेंडा सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) का उत्तरवर्ती है और इसमें 17 एसडीजी और 169 लक्ष्य शामिल हैं। एजेंडा बाध्यकारी नहीं है और इसके लक्ष्य आकांक्षी हैं, जो भारत जैसे विकासशील देशों के संधारणीय विकास के लिए अपने स्वयं के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए नीति स्थान और लचीलापन प्रदान करता है। एजेंडा में संधारणीय विकास और आर्थिक विकासए सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देने के साथ इसके संतुलित पर्यावरण संरक्षण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है। यह साझाए लेकिन अलग–अलग जिम्मेदारी वाले सिद्धांत की पुष्टि करता है। इसमें कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाने और संधारणीय विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनः प्रवलित करने के लिए भी एक समर्पित लक्ष्य है।

जलवायु परिवर्तन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन (सीओपी 21) (यूएनएफसीसीसी) के 21 वें सत्र के उच्चस्तरीय नेतृत्व खंड में भाग लिया, जहाँ उन्होंने जलवायु परिवर्तन वार्ता से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत की स्थिति का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने संयुक्त रूप से सौर प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए दो कटिबंधों के भीतर आने वाले 119 सौर समृद्ध देशों को एक साथ लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारंभ किया।

प्रधानमंत्री ने अमेरिका की पहल शमिशन अभिनव" के शुभारंभ के अवसर पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाए फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद और बिल गेट्स के साथ इसमें भाग लियाए जिसके साथ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को साफ करने के लिए इसका किफायती उपयोग की सुविधा होने की उम्मीद है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कॉप 21 के लिए 29 नवंबर, 12 दिसंबर 2015 तक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। कॉप 21 में 12 दिसंबर 2015 की पूर्ण बैठक में यूएनएफसीसीसी के मौलिक सिद्धांतों को बरकरार रखते हुए पेरिस समझौते के पाठ को अपनाया गया है। इसमें भारत के मुख्य सरोकारों और शमन / उत्सर्जन में कमीए अनुकूलनए वित्तए प्रौद्योगिकीए क्षमता निर्माण और कार्रवाई और समर्थन की पारदर्शिता से संबंधित "डरबन मंच" के सभी तत्वों पर हितों को भी ध्यान में रखा जाता है।

सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे (यूनेस्को)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन की 70 वीं वर्षगांठ के अवसर परपेरिस में 10 अप्रैल 2015 को यूनेस्को के मुख्यालय का दौरा किया। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यूनेस्को की पहली यात्रा थी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर संगठन के साथ भारत के संबंधों के महत्व पर जोर देने के लिए किया।

यूनेस्को की महासभा का 38 वां सत्र 03–18 नवम्बर, 2015 के बीच आयोजित किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्री सुश्री स्मृति जुबिन ईरानी ने 16–17 नवम्बर 2015 को लीडर्स श्फोरम सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 196वें सत्र का आयोजन 8–23 अप्रैल 2015 के बीच किया गया। भारत के कार्यकारी बोर्ड के प्रतिनिधि, डॉ कर्ण सिंह ने कार्यकारी बोर्ड सत्र में भाग लिया और समापन तर्क वितर्क में राष्ट्रीय वक्तव्य दिया।

मानव संसाधन विकास मंत्री सुश्री स्मृति जुबिन ईरानी ने 21 मई 2015 को इंचियोन दक्षिण कोरिया में विश्व शिक्षा फोरम में भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। अगले 15 वर्षों में शिक्षा के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टि – फोरम इंचियोन की घोषणा पारित की थी। देशों और वैश्विक शिक्षा के लिए समुदाय का एक एकलए शिक्षा एजेंडा – शिक्षा 2030 जो कि समग्र, महत्वाकांक्षी, समावेशी और आकांक्षा जगाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा 2030 कार्रवाई के लिए रूपरेखा (एफएफए) को स्वीकार किया गया और यूनेस्को के 38 वें महा सम्मेलन के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक, 4 नवंबर 2015 को आयोजित की गई थी। उच्च स्तरीय बैठक में 70 से अधिक मंत्रियों, सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों, नागरिक

प्रधानमंत्री पेरिस, फ्रांस में 30 नवंबर 2015 को कॉप 21 शिखर सम्मेलन के मौके पर संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा से मुलाकात करते हुए।

प्रधानमंत्री ने पेरिस, फ्रांस में, 30 नवंबर, 2015 को कॉप 21 में नवाचार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति (यूएसए) श्री बराक ओबामा, फ्रांस के राष्ट्रपति श्री फ्रांसवा ओलांद और श्री बिल गेट्स भी इसमें मौजूद हैं।

समाज, क्षेत्रीय संगठन, शिक्षण पेशा, शिक्षा, युवाओं और निजी क्षेत्र ने भाग लिया। एफएफए शिक्षा पर सतत विकास लक्ष्य (एमडीजी) लक्ष्य 4 के कार्यान्वयन हेतु देशों को मार्गदर्शन प्रदान करता है। मई 2015 में इंचियोन, कोरिया गणराज्य में विश्व शिक्षा फोरम में एफएफए के आवश्यक घटकों पर सहमति हुई।

विश्व विरासत सम्मेलन

विश्व धरोहर समिति के सदस्य और वाइस चेयर के रूप में, भारत ने 28 जून से 8 जुलाई 2015 तक बॉन (जर्मनी) में 39 वें विश्व धरोहर समिति के सत्र को आयोजित करने में एक महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका निभाई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने विश्व धरोहर कन्वेंशन के परिचालन दिशानिर्देश में महत्वपूर्ण संशोधनों को अपनाने में भी काफी योगदान दिया जो नामांकन के मूल्यांकन की सभी प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता और परामर्श / संवाद को बढ़ावा देने से संबंधित हैं। नामीबिया, विंडहोक में 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2015 के बीच आयोजित अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति की सुरक्षा पर अंतर सरकारी समिति के 10 वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

खाद्य और कृषि संगठन सम्मेलन (एफएओ)

श्री राधा मोहन सिंह, माननीय कृषि मंत्री ने जून 2015 में आयोजित एफएओ सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। एफएओ परिषद और एफएओ कार्यक्रम समिति, डब्लूएफपी कार्यकारी बोर्ड और आईएफएडी कार्यकारी बोर्ड के लिए भारत को सर्वसम्मति से चुना गया। भारत ने आईएफएडी मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता ग्रहण की।

संयुक्त राष्ट्र स्वापक द्रव्य और अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी)

दोहा, कतर में अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय विषय पर संयुक्त राष्ट्र के तेरहवें महा सम्मेलन का 12–19 अप्रैल 2015 तक आयोजन किया गया। श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा, विधि और न्याय मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था।

यूनिडो

भारत यूनिडो के औद्योगिक विकास बोर्ड (आईडीबी) और कार्यक्रम और बजट समिति (पीबीसी) का सदस्य बना हुआ है।

ईसीओएसओसी के विशेष समारोह की 70 वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष कार्यक्रम

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी 2016 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) की 70 वीं वर्षगांठ के अवसर पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित एक विशेष समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में एक विशेष वीडियो भाषण दिया। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के एक संस्थापक के रूप में दृष्टि विकास के महत्व पर जोर दिया और उनका ध्यान गरीबी उपशमन पर रहा क्योंकि यह 21 वीं सदी के सबसे बड़े अधूरे काम के रूप में प्रतिध्वनित होता है, विशेष रूप से विकासशील देश के प्रतिनिधिमंडलों के लिए। प्रधानमंत्री के संबोधन से संयुक्त राष्ट्र के साथ भारत का ऐतिहासिक जुड़ाव, बहुपक्षवाद के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और सर्वाधिक गरीब व्यक्ति की सेवा में संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली हेतु एक सक्रिय भूमिका पर जोर दिया गया। 2030 एजेंडे का अपने आपको ऊर्जावान बनाने तथा और अधिक कारगर बनाने में उपयोग करने हेतु प्रधान मंत्री द्वारा यूएन प्रणाली में किए गए आह्वान के प्रति बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली।

विधि और संधि प्रभाग

संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय कानून

संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति (विधिक)

छठी समिति जो महासभा में विधिक मुद्दों पर विचार करने के लिए प्राथमिक मंच है, विचार–विमर्श और अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित मुद्दों पर सिफारिश करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों को एक अवसर प्रदान करता है।

अक्तूबर और नवंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्तरवें सत्र में छठी समिति के समक्ष अन्य विषयों में से, आतंकवाद और संबंधित मुद्दे चर्चा के विषय बने हुए हैं। सामान्य बहस मेंए सदस्य देश दृढ़ता से अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की निंदा करते हैं। उन्होंने नोट किया कि जहाँ भी आतंकवादी गतिविधियां की गई, जिसके द्वारा या जिसके खिलाफ की गई, जिसका प्रयोजन / कारण या विचार कुछ भी हो, इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। सदस्य राष्ट्रों द्वारा आतंकवादियों को और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषणए योजनाए तैयारी को सुविधाजनक बनाने के प्रयास का समर्थन, सहयोग करने वालों को सुरक्षित आश्रय देने से मना किया जाना चाहिए तथा उनके प्रत्यर्पण या अभियोजन में सहयोग करना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आई एस आई एल / आई एस आई एस (इस्लामिक स्टेट) और विदेशी आतंकवादी सेनानियों से उत्पन्न बढ़ते खतरे पर गहरी चिंता व्यक्त कीए जो अपने निवास या राष्ट्रीयता के देशों से संघर्ष वाले क्षेत्रों में अपराध, योजना या आतंकवादी कृत्यों में भागीदारी या सहायता प्रदान करने या आतंकवादी प्रशिक्षण प्राप्त करने के उद्देश्यार्थ यात्रा करते हैं।

व्यावहारिक सुरक्षा उपायों के अलावाए सदस्य देशों ने आगे

आतंकवादी गतिविधियों और उनके साथी अपराधियों से निपटने के लिए कानूनी व्यवस्था को मजबूत बनाने के महत्व को स्वीकार किया। राज्यों का आह्वान किया गया कि वे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद (सीसीआईटी) पर व्यापक सम्मेलन समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करें। छठी समिति ने पुनः कार्य समूह के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए सीसीआईटी की स्थापना की। छठी समिति ने मसौदा सीसीआईटी से संबंधित लंबित मुद्दों पर कार्य समूह की सिफारिश का जायजा लिया और मसौदा अभिसमय की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए महासभा के इकत्तरवें सत्र में एक कार्य समूह की स्थापना की।

छठी समिति के कार्य समूह ने अंतर–सत्रीय अवधि के दौरान सभी सदस्य राष्ट्रों को उनके प्रयासों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। राष्ट्रों से बकाया मुद्दों पर मतभेदों को दूर करने के लिए और प्रारूप को अंतिम रूप देने की कोशिश करने के सीसीआईटी अंतर–सत्रीय अनौपचारिक परामर्श / बैठकें आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70 वें सत्र में छठी समिति द्वारा विचार किए गए अन्य विषयोंध्मुद्दे इस प्रकार हैंः– राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शासन के कानूनय संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों और मिशन पर विशेषज्ञों की आपराधिक जवाबदेही; सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र; शिक्षण, अध्ययन, प्रचार–प्रसार और व्यापक मूल्य निरूपण में सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम; संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में विशेष समिति और संगठन की भूमिका के सुदृढ़ीकरण पर रिपोर्ट।

छठी समिति ने भी विचार किया और अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर बहस की जिसमें निम्न विषय शामिल हैं – विदेशी आपराधिक अधिकार क्षेत्र से राज्य के अधिकारियों को उन्मुक्तिय संधियों की व्याख्या करने के संबंध में उत्तरोत्तर करार तथा अभ्यास; सर्वाधिक वरीय राष्ट्र शर्तय संधियों के अनंतिम आवेदन; प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून की पहचानय सशस्त्र संघर्ष के संबंध में पर्यावरण का संरक्षणय वातावरण का संरक्षणय मानवता के विरुद्ध अपराधय और अनुल्लंघनीय आदर्श (जुस कोजेंस)।

विधि और संधि प्रभाग ने छठी समिति द्वारा तैयार किए इन सभी विषयों / मुद्दों पर विवरण और विचार की प्रासंगिक बहस में भाग लिया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने छठी समिति की रिपोर्ट के आधार पर इन विषयों / मुद्दों पर प्रस्तावों को अपनाने के लिए 14 दिसंबर 2015 की तारीख तय की।

अंतर्राष्ट्रीय कानून सप्ताह

संयुक्त राष्ट्र महासभा "अंतर्राष्ट्रीय कानून सप्ताह" के 70 वें सत्र के मुख्य भाग के दौरान 29 अक्तूबर – 4 नवम्बर 2015 तक विधि और संधि प्रभाग के निदेशक और प्रमुख, डॉ विष्णु दत्त शर्मा ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय कानून सप्ताह के दौरान आयोजित की जाने वाली छठी समिति (कानून) की बैठक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित गतिविधियों और घटनाओं में शामिल हैं :

- अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर कार्य समूह, जिसमें, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और आतंकवाद को रोकने से संबंधित अन्य मुद्दों पर प्रस्तावित व्यापक अभिसमय के पाठ से संबंधित लंबित मुद्दों पर चर्चा की गई।

- अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के विभिन्न विषयों पर आईएलसी के कार्य की जांच की गई थी और भारतीय वक्तव्यों के लिए टिप्पणियां तैयार की गईं।

- कानूनी सलाहकारों की बैठकए जो इस वर्ष कनाडा में समन्वित की गई और जिसमें वैश्वीकरण के युग में कांसुली संबंध से जुड़े विषयोंय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण पर चर्चा की गई।

- अप्रैल 2015 में बीजिंग, चीन में आयोजित एएएलसीओ की बैठक और कार्यक्रमों में एशियाई अफ्रीकी कानूनी सला. हकार संगठन (एएएलसीओ) के 54 वें वार्षिक सत्र का जायजा लिया गया। एएएलसीओ ने संघर्ष समाधान, शांति और सुरक्षा, आतंकवाद और प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर केंद्रित पैनल प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय विवाद अधिनिर्णय प्रक्रिया पर एक अनौपचारिक बातचीत भी आयोजित की गई।

- स्विट्जरलैंडए आईसी आर सी और ब्रिटेन के कानूनी सला. हकारों के साथ द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई थी जिन्होंने मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून से संबंधित मुद्दों पर संक्षिप्त चर्चा की। रूस के कानूनी विभाग के निदेशक ने आम सरोकार के मामलों पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से वार्षिक बैठकों की संभावना का पता लगाने के लिए ब्रिक्स देशों के कानूनी सलाहकारों की एक अनौपचारिक बैठक का आयोजन किया।

महासागरों और समुद्र के कानून

महासागरों और समुद्र के कानून से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न मंचों पर चर्चा की गई, जिसमें संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून पर अभिसमय, 1982 के सदस्य देशों की बैठक; अनौपचारिक परामर्श प्रक्रिया; राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर कार्य समूह; समुद्री पर्यावरण के आकलन के

लिए नियमित प्रक्रिया; महाद्वीपीय मग्नतट की सीमा आयोग; और अंतर्राष्ट्रीय सीबैड प्राधिकरण की बैठकें भी शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 6–10 अप्रैल 2016 को महासागरों पर संयुक्त राष्ट्र अनौपचारिक परामर्श प्रक्रिया और समुद्री कानून (यूएनसीएलओएस) की सोलहवीं बैठक आयोजित की गई जिसमें विचार विमर्श के विषय महासागर और संधारणीय विकास : संधारणीय, अर्थात्, पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक के तीन आयामों का एकीकरण" था।

नई विकास कार्यसूची जिसका शीर्षक : "हमारी दुनिया को बदलनाः संधारणीय विकास के लिए 2030 कार्यसूची" को 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया। यह कार्यसूची अन्य बातों के साथ–साथ 17 संधारणीय विकास लक्ष्यों और लक्ष्य 14 जिसमें उल्लेख है कि "संधारणीय विकास के लिए महासागरों, समुद्रों तथा समुद्री संसाधनों का संरक्षण करें तथा ईष्टतम उपयोग करें", सहित उनके संबद्ध लक्ष्यों पर आधारित है। इसमें स्वीकार किया गया है कि महासागरों और समुद्र सहित सामाजिक और आर्थिक विकास इस ग्रह के प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन पर निर्भर करता है।

विधि और संधि प्रभाग ने सक्रिय रूप से भाग लिया और विभिन्न कानूनी पहलुओं पर योगदान दिया जो समुद्री कानून संबंधी बैठकों के दौरान सामने आए थे।

अंतर्राष्ट्रीय सीबैड प्राधिकरण (आईएसए) का इक्कीसवां वार्षिक सत्र 13.24 जुलाई 2015 को किंग्सटन, जमैका में आयोजित किया गया था। श्री एम कोटेश्वर रावए काउंसलर (एलए)ए पीएमआईए न्यूयॉर्क को सत्र के दौरान आईएसए की वित्त समिति के लिए चुना गया, जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल से भी जुड़े हुए थे।

यू एन चार्टर पर विशेष समिति

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की विशेष समिति हर वर्ष न्यूयार्क में बैठक करती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति में इसके प्रतिवेदनों पर विचार किया जाता है। विशेष समिति की अंतिम बैठक फरवरी 2015 में आयोजित की गई थी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द और सुरक्षा को बनाए रखने के प्रश्न, चार्टर के अध्याय सात के अंतर्गत स्वीकृतियों के अनुप्रयोगों से प्रभावित तीसरी दुनिया के देशों को सहायता पहुंचाने के संबंध में चार्टर के प्रावधानों के कार्यान्वयन के प्रश्न और संयुक्त राष्ट्र के अंगों के बीच संबंधों से जुड़े मुद्दों से संबंधित मुख्य प्रस्तावों पर विचार किया गया।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने दृढ़तापूर्वक कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द और सुरक्षा को बनाए रखना सर्वोपरि है। प्रतिनिधिमंडल ने नोट किया है कि सुरक्षा परिषद का प्रमुख कर्तव्य सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों की ओर से अपने कर्तव्य निर्वहन के तौर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में स्वीकृतियां केवल एक महत्वपूर्ण साधन हो सकती हैं जब वे चार्टर के प्रावधानों के अनुसरण में एक अंतिम उपाय के तौर पर अन्य सभी उपायों के खत्म होने के बाद जारी और अनुप्रयुक्त की गई हों। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के अंगों, विशेषकर महासभा और सुरक्षा परिषद के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने और जांच करने के लिए किए गए प्रयासों हेतु समर्थन व्यक्त किया गया। इस संबंध में हमने 24 सितंबर 2012 को राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तरों पर रूल ऑफ लॉ पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महासभा द्वारा स्वीकार की गई घोषणा की ओर ध्यान दिलाया गया, जो कि सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन करने के लगातार प्रयासों की महत्ता पर जोर देता है।

विशेष समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए, छठी समिति ने महासभा से सिफारिश की है कि विशेष समिति की अगली बैठक में इसकी कार्यसूची के विषयों/मुद्दों पर विचार जारी है, जो 16–24 फरवरी 2016 के बीच आयोजित की जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कारोबार कानून आयोग (यू एन सी आई टी आर ए एल)

विधि और संधि प्रभाग ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कारोबार कानून आयोग (यू एन सी आई टी आर ए एल) तथा इसके कार्य समूह की बैठकों में हिस्सा लिया।

कार्य समूह 2 (मध्यस्थता एवं सुलह) ने वियना में 7–11 सितंबर 2015 तक आयोजित अपनी बैठक के दौरान सचिवालय द्वारा तैयार दस्तावेजों के आधार पर प्रासंगिक मुद्दों की पहचान करने के लिए निपटान समझौते को लागू करने पर विचार–विमर्श किया।

कार्य समूह 6 (सुरक्षा हित) ने 12–16 अक्टूबर 2015 तक वियना में आयोजित, अपने 28 वें सत्र में, 2012 के 45 वें सत्र में लिए गए निर्णय के अनुसार सुरक्षित लेनदेन (मसौदा मॉडल कानून) पर एक मॉडल कानून की तैयारी पर कार्य जारी रखा।

यूएनसीआईटीआरएएल के कार्य समूह 4 (इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स) ने 9–13 नवम्बर 2015 के दौरान वियना में आयोजित अपने 52 वें सत्र में मसौदा इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरणीय रिकॉर्ड संबंधी मॉडल कानून पर विचार किया। एक मॉडल कानून की तैयारी के अंतिम चरण में हैए अतः कार्य समूह ने भविष्य में लिए जाने वाले विषयों के बारे में चर्चा की, जिसमें पहचान प्रबंधन और विश्वास सेवाएंए क्लाउड कंप्यूटिंग और मोबाइल वाणिज्य शामिल हैं। यह निर्णय लिया गया कि अभिनिर्धारित विषयों पर और भविष्य के सत्र में चर्चा के लिए बुनियादी मसौदे तैयार करने के लिए वार्तालाप का संचालन करने का निर्णय लिया गया।

एशियाई–अफ्रीका विधिक परामर्शदात्री संगठन (ए ए एल सी ओ)

एशियाई–अफ्रीका विधिक परामर्शदात्री संगठन (ए ए एल सी ओ) के 54वें वार्षिक सत्र का आयोजन बीजिंग, चीन के लोकतांत्रिक गणतंत्र में 13 – 17 अप्रैल 2015 के बीच किया गया था। इसमें आल्को के 40 सदस्यों सहित भारत ने सत्र में भाग लिया।

वर्ष 2015, संयुक्त राष्ट्र चार्टर को स्वीकृत किए जाने की 70वीं वर्षगांठ होने के कारण इस एएएलसीओ सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। स्मरण रहे कि एएएलसीओ ऐतिहासिक बांडुंग सम्मेलन का परिणाम था।

सत्र के दौरान, जिन मदों पर विचार विमर्श किए गए, उनमें समुद्र का कानून, फिलिस्तिनियों की स्वदेश वापसी, हिंसक चरमपंथी गतिविधियां और आतंकवाद (कानूनी पक्ष); पर्यावरण और सतत विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार कानून आयोग के कार्य पर रिपोर्ट। उपरोक्त विषयों पर चर्चा के अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग'' और ''साइबर स्पेस में अंतर्राष्ट्रीय कानून'' के विचाराधीन चुने गए विषयों पर आधे दिन के विशेष सत्र आयोजित किए गए। ''बांगडुम सम्मेलन की 60वीं वर्षगांठ समोराह'' पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। ''संयुक्त राष्ट्र चार्टर और युद्ध पश्चात् अंतर्राष्ट्रीय आदेश'' पर चर्चा के लिए समानांतर कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

भारत ने 54वें एएएलसीओ सत्र के दौरान सभी कार्य सूची मदों और चर्चा किए गए विषयों पर वक्तव्य दिए।

निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून पर हेग सम्मेलन (एचसीसीएच)

विधि और संधि प्रभाग ने हेग में आयोजित सम्मेलन में सामान्य कार्य और नीति परिषद् की बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें भारत सहित 64 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 180 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

परिषद्, ने अन्य कार्यों के अलावा सदस्य देशों के वाणिज्यिक संविदाओं में कानूनी विकल्प संबंधी सिद्धांतों पर विचार किया, जिन्हें 2014 में परिषद् द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अंतिम रूप दिया गया। परिषद् ने बच्चों की स्थिति से जुड़े मुद्दों सहित अंतर्राष्ट्रीय सरोगेट मां की व्यवस्थाओं से उत्पन्न मुद्दों पर स्थायी ब्यूरो द्वारा किए गए कार्य की सराहना कि और निर्णय लिया कि इस क्षेत्र में कार्य को आगे बढ़ाने की व्यवहार्यता तलाशने के लिए एक विशेषज्ञ समूह की बैठक बुलाई जाए।

8 – 12 जून 2015 तक 1993 हेग अंतर देशीय दत्तक ग्रहण अभिसमय के व्यावहारिक प्रचालन की समीक्षा हेतु एक बैठक बुलाई गई। इसमें 74 राष्ट्रों और 19 अंतर सरकारी तथा अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों सहित निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून पर हेग सम्मेलन के सदस्यों, अभिसमय के संविदाकार राष्ट्रों, गैर संविदाकार राष्ट्रों के प्रतिनिधियों एवं इच्छुक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया, जो अभिसमय में शामिल होने की संभावना सक्रिय रूप से तलाश रहे हैं। भारत की नोडल प्राधिकरण, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा), के प्रतिनिधि और विधि तथा संधि प्रभाग के प्रतिनिधियों ने विचार विमर्शों में हिस्सा लिया। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया कि पिछले 20 वर्षों में अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण का परिदृश्य बदला है और आज की जरूरत है कि गैर कानूनी प्रथाओं के मुद्दे को संबोधित करने और उत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए राष्ट्रों के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ाया जाए। आयोग की इस बैठक में इनके अनुप्रयोग पर कुछ सिफारिशें की गई – अभिसमय के सहायक सिद्धांत, काफला पर चर्चा, जो 1996 हेग अभिसमय के व्यावहारिक प्रचालन पर अगले विशेष आयोग की बैठक में बाल सुरक्षा उपाय के रूप में लिया गया है, और कार्य सूची में चौथे ''सीमांत पार परिवारों के कानूनी मुद्दों पर माल्टा न्यायिक सम्मेलन'' की कार्यसूची में अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के मुद्दे को शामिल करना''।

वर्ष 2014 में आयोजित विशेष आयोग बैठक की सिफारिशों के अनुपालन में विदेशी साक्ष्य लेने के लिए वीडियो लिंक और अन्य आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर 2 – 4 दिसंबर 2015 के बीच हेग सम्मेलन के तहत एक बैठक आयोजित की गई। प्रतिभागियों ने अपने राज्यों में साक्ष्य अभिसमय और अन्य अंतर्राष्ट्रीय / क्षेत्रीय साधनों के तहत वीडियो लिंक द्वारा साक्ष्य लेने के विषय में अपने राज्यों के अनुभव प्रस्तुत किए। भारत ने वीडियो लिंक द्वारा विदेशी साक्ष्य लेने के विषय में अपनी कानूनी स्थिति साझा की।

अंतर्राष्ट्रीय विवाद अधिनिर्णय में भारत का सहयोग

26 जून 2015 को इटली ने संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (यूएनसीएलओएस) के **अनुबंध–VII** के तहत एक मध्यस्थता ट्रिब्यूनल के गठन से पहले भारत के प्रति कार्रवाई स्थापित करने के दावे को अधिसूचित किया। यह 15 फरवरी 2015 को हुई एंरिका लेक्सी की घटना से संबंधित है जो भारत के केरल में 20.5 नोटिकल मील की दूरी पर हुई थी और इसमें इटली के झण्डे वाले एक तेल टैंकर एमवी एंरिका लैक्सि के शामिल होने के परिणाम स्वरूप दो भारतीय मछुआरों की मौत हो गई थी, जब इटली के नौ सैनिक कार्मिक ऑन बोर्ड, मिसी मिलानो लाटोरे और सलवेटोर गिरोने पर मछुआरों को मार गिराने की आशंका जताई गई थी, इन्हें भारतीय कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा नजर बंद किया गया था और यह मामला भारतीय अदालत में लंबित है।

इटली में मध्यस्थता ट्रिब्यूनल, का गठन लंबित होने के कारण इटली ने भारत को इस घटना पर किसी प्रकार के क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करने और उन समुद्री नाविकों की स्वतंत्रता, सुरक्षा और आवागमन पर प्रतिबंध हटाने के लिए अनुदेश हेतु अनंतिम उपाय निर्दिष्ट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून ट्रिब्यूनल (आईटीएलओएस) के पास अनुरोध किया है, ताकि जो नाविक भारत में हैं वे यात्रा कर सके और इटली में बने रहे तथा उन्हें अन्य नाविक (जो इटली में है) को **अनुबंध**–VII ट्रिब्यूनल के सामने कार्रवाई की पूरी अवधि के दौरान इटली में बने रहने की अनुमति दी जाए। आईटीएलओएस ने 10 और 11 अगस्त 2015 को **अनुबंध**–VII ट्रिब्यूनल का गठन होने तक अनंतिम उपाय हेतु इटली के अनुरोध से संबंधित मामले की सुनवाई की।

आईटीएलओएस ने 24 अगस्त 2015 को अपना आदेश दिया है, जिसमें अनुदेश दिया गया है कि इटली और भारत दोनों ही अपनी अदालती कार्रवाईयां रद्द करें और नई कार्रवाईयां शुरू करने पर संयम रखें एवं इटली के नाविकों को यह अनुमति देने के लिए याचिका अस्वीकार कर दी है कि जो नाविक भारत में हैं, वे यात्रा करें और इटली में बने रहें।

परिणामतः **अनुबंध**–VII मध्यस्थ न्यायाधिकरण पांच सदस्यों को लेकर गठन किया गया है अर्थात, प्रो फ्रांसेस्को फ्रैंकियोनी (इटली), न्यायाधीश श्री पी चंद्रशेखर राव (भारत), न्यायाधीश रॉबिन्सन (जमैका), न्यायाधीश गोलिटसिन (रूस) और न्यायाधीश पालिक (कोरिया गणराज्य)। यह मध्यस्थ न्यायाधिकरण अब गुण–दोष के आधार पर इस घटना के क्षेत्राधिकार के मुद्दों पर विचार करेगी।

परमाणु शस्त्र की हौड़ रोकने से संबंधित वार्ताओं से जुड़े दायित्व और परमाणु निःशस्त्रीकरण (मार्शल द्वीप बनाम भारत) : यह नोट किया जाए कि मार्शल द्वीप ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) के सामने भारत सहित नौ देशों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। अन्य देश हैं ब्रिटेन, पाकिस्तान, इजरायल, फ्रांस, चीन, अमरीका, रूस और उत्तरी कोरिया। भारत ने आईसीजे में काउंटर मेमोरियल जमा किया है और यह मामला मार्च 2016 में मौखिक कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

हेग में 18 – 26 नवंबर 2015 के बीच अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत (आईसीसी) के राज्य पक्षकार सभा (एएसपी) का 14वां सत्र आयोजित किया गया, जिसमें भारत ने एक प्रेक्षक के रूप में हिस्सा लिया, क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत की स्थापना के संविधि का पक्षकार नहीं है। एक निर्णय के अनुसार एएसपी को विधान के अनुच्छेद 124 को हटाकर इसे आईसीसी का दर्जा देते हुए एक संशोधन किया गया। इस अनुच्छेद में एक परिवर्तनकारी प्रावधान है, जिससे एक राज्य को विधान में पक्षकार बनने पर यह घोषित करना होता है कि वह अपने क्षेत्राधिकार में या अपने नागरिकों द्वारा सात वर्ष की अवधि के लिए युद्ध संबंधी अपराध पर अदालत के क्षेत्राधिकार को स्वीकार नहीं करता है।

संधि वार्ताएं

विधि और संधि प्रभाग ने पेरिस में 30 नवंबर – 12 दिसंबर 2015 के बीच ''2015 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, कॉप 21'' पर वार्ता में भाग लिया। इसके परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से निपटने के लिए ''जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय के तहत पेरिस करार'' को सफलता पूर्वक संपन्न करके इसे स्वीकार किया है।

विधि और संधि प्रभाग ने 8–10 दिसंबर 2015 के बीच जिनेवा में आयोजित रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट के 32 वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के नियमों की अनुपालना पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्यार्थ मानवीय मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया।

विधि और संधि प्रभाग ने बिम्सटेक मुक्त व्यापार क्षेत्र पर ऑस्ट्रेलियाए थाईलैंड और समझौते की रूपरेखा के साथ मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता में भाग लिया और कई दोहरे कराध ाान बचाव समझौते की बातचीत में योगदान दिया है तथा चीन तुर्कमेनिस्तानए सेशल्सए कुवैत और कोरिया के साथ किए जाने वाले करारों में से कुछ अंतिम चरण में हैं।

अनेक राजनयिक मिशनों और कौंसुली केंद्र के लाभकारी व्यवसाय / रोजगार व्यवस्था पर चर्चा की गई और जर्मनी, बेल्जियम, पुर्तगाल, स्विस फेडरल काउंसिल, मलेशिया, स्पेन, आयरलैंड, फ्रांस, फिनलैंड, मॉरीशस और पोलैंड के साथ करारों को अंतिम रूप दिया जा रहा है/निष्पन्न किए गए हैं।

विधि और संधि प्रभाग ने प्रत्यर्पण संधि, आपराधिक मामलोंए सिविल और वाणिज्यिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता और बाहरी देशों के साथ सजायाफ्ता व्यक्तियों के हस्तांतरण में पारस्परिक कानूनी सहायता संबंधी समझौता निष्पन्न करने के लिए विभिन्न द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लिया। भारत और चिली के बीच आजादी से पूर्व प्रत्यर्पण संधि को अप्रैल, 2015 में सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। भारत और बांग्लादेशए दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि को अधिसूचित करने की प्रक्रिया आंतरिक कानूनी प्रक्रियाओं के पूरे होने के बाद शुरू की गई। भारत और उज्बेकिस्तान, क्यूबाए जॉर्डन, इटली, कोलंबिया, मोजाम्बिक, बेलारूस, पेरू और ओमान के बीच परस्पर कानूनी सहायता पर बातचीत की गई / वर्ष 2015 के दौरान अंतिम रूप दिया गया। विधि और संधि प्रभाग ने सिविल और आपराधिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रत्यर्पण अनुरोध और अन्य अनुरोध की जांच कीए स्वदेशी साथ ही विदेशी न्यायालय से जानकारी प्राप्त की और उस पर कानूनी सलाह दी।

विधि और संधि प्रभाग ने 28 मई से 7 जून 2015 तक सोफिया, बुल्गारिया में आयोजित अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री समिति (ए टीसीएम) की XXXVIII बैठक में भाग लिया। इस बैठक में भारत सहित 30 परामर्शदात्री दलों और 12 अन्य गैर परामर्शी संपर्क दलों और अन्य पर्यवेक्षक संगठनों ने भाग लिया। एटीसीएम का कार्य अलग–अलग समूहों के बीच आयोजित किया गयाए अर्थात् (क) अंटार्कटिका की पर्यावरण संरक्षण (सीईपी) समिति (ख) कानूनी और संस्थागत मामलों पर कार्य समूहए (ग) पर्यटन और गैर–सरकारी कार्यों पर कार्य समूह और (घ) परिचालन मामलों पर कार्य समूह। एटीसीएम के पूर्ण सत्र में इन्हें अपनाए जाने से पहले कानूनी और संस्थागत कार्य समूह ने पहले सीईपी और अन्य कार्य समूह द्वारा अपनाए गए परिणाम प्रस्तावों को पुनरीक्षित किया। इसके अलावाए कानूनी और संस्थागत कार्य समूह के तीन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की अर्थात्ए (क) अंटार्कटिक प्रणाली का संचालनय (ख) दायित्वः एटीसीएम निर्णय 4 (2010) का कार्यान्वयन और (ग) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के ध्रुवीय संहिता।

विधि और संधि प्रभाग ने पेरिस में सांस्कृतिक संपदा के स्वामित्व के अवैध आयात, निर्यात और हस्तांतरण के निषेध तथा इस पर रोक लगाने के साधन, 1970 यूनेस्को पर यूनेस्को कन्वेंशन की सहायक समिति के तीसरे सत्र में भी भाग लिया।

ऑनलाइन संधि डेटाबेस

कानून और संधि प्रभाग ने 2014 के दौरान लिंक भारतीय संधि डेटाबेस के तहत विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर एक विशिष्ट वेब मॉड्यूल का शुभारंभ किया और अब वर्ष 1950 से 2015 तक की अवधि के लिए भारत गणराज्य की सरकार द्वारा विदेशों के साथ निष्पन्न संधियां/करार/समझौता ज्ञापन और अन्य महत्वपूर्ण मामले की जानकारी उपलब्ध हैं। कानून और संधि प्रभाग के प्रयास से सार्वजनिक क्षेत्र में यह डेटाबेस नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

संधियों की परीक्षा / पुनरीक्षण

कानून और संधि प्रभाग ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों/समझौतों और दिए गए कानूनी राय के लिए संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित मुद्दों की जांच की। इसने संधियों, समझौतों, रक्षा सहयोग, रेलवे, सार्क, स्वास्थ्य, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन सहित, बाह्य अंतरिक्ष के मुद्दों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह) और बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक), अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी /स्वापक द्रव्यों से संबंधित समझौतों; गोपनीयता के समझौतों; जल वैज्ञानिक आंकड़ों को साझा करने; गैस और ऊर्जा; सांस्कृतिक सहयोग के द्विपक्षीय समझौतों, दृश्य श्रव्य, सड़क परिवहन, व्यापार और निवेश, परियोजनाओं, शिक्षा, पर्यटन, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण; हाइड्रोग्राफी, ट्विनिंग / सिस्टर शहर समझौते और सीमा शुल्क सहयोग आदि का भी पुनरीक्षण किया।

भारत ने वर्ष 2015 के दौरान कई बहुपक्षीय/द्विपक्षीय संधि/ बाहर के देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए/ पुष्टि की। एक व्यापक सूची **परिशिष्ट–I** में दी गई है। वर्ष 2015 के दौरान जारी पूर्ण शक्ति दस्तावेजनों की सूची **परिशिष्ट–II** में दी गई है और वर्ष 2015 के दौरान तैयार अनुसमर्थन दस्तावेजों की सूची **परिशिष्ट–III** में दी गई है।

■ ■

10

निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले

वर्ष 2015–16 में भारत ने वैश्विक एवं निष्पक्ष परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुसरण में निरस्त्रीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले से संबंधित विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय भूमिका निभाना जारी रखा जिसका उद्देश्य सामान्य एवं संपूर्ण निरस्त्रीकरण का लक्ष्य हासिल करना था। इन मुद्दों पर भारत का पक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा हितों और विभिन्न पारंपरिक तथा गैर–पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ अपने घनिष्ठ विनियोजन की परंपरा द्वारा अभिप्रेरित थे।

भारत न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र की प्रथम समिति, संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग, जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन, जिनेवा में जैविक तथा टॉक्सिन हथियार कन्वेन्शन (बीटीडब्ल्यूसी), द हेग में रसायनिक हथियार कन्वेन्शन, जिनेवा में कतिपय पारंपरिक हथियार कन्वेन्शन, न्यूयार्क में लघु शस्त्रों तथा हल्के हथियारों से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम की बैठकों में सक्रिय भूमिका निभाता रहा।

संयुक्त राष्ट्र महा सभा

वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा में भारत ने वैश्विक, गैर पक्षपातपूर्ण तथा सत्यापनीय परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

वर्ष 2015 की प्रथम समिति में गुट निरपेक्ष आंदोलन के एक सक्रिय सदस्य के रूप में भारत ने इस समूह के संकल्प 'परमाणु निरस्त्रीकरण संबंधी आम सभा के वर्ष 2013 में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक पर अनुवर्ती कार्रवाई' का समर्थन किया। इस संकल्प में अन्य बातों के साथ–साथ परमाणु हथियार कन्वेन्शन से संबंधित निरस्त्रीकरण सम्मेलन में तत्काल बातचीत शुरू करने का आग्रह किया, 26 सितंबर को परमाणु हथियारों की पूर्ण समाप्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने तथा इसे बढ़ावा देने का स्वागत किया और वर्ष 2018 तक संयुक्त राष्ट्र द्वारा परमाणु निरस्त्रीकरण से संबंधित उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने संबंधी निर्णय को पुनः स्मरण किया गया।

वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र की प्रथम समिति की बैठक में परमाणु हथियारों से संबंधित सामान्य तथा विषयपरक परिचर्चा के दौरान निरस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया और इस दिशा में भारत द्वारा प्रस्तावित कई उपायों को दोहराया। परमाणु निरस्त्रीकरण संबंधी प्रतिबद्धता के साथ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी हितों का तारतम्य स्थापित करते हुए भारत ने एक बहुपक्षीय निष्पक्ष तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्यापनीय संधि पर आयोजित सम्मेलन में इस पर बातचीत हेतु अपने समर्थन को भी पुनः दोहराया जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरणों के लिए सामग्री तैयार करने पर प्रतिबंध लगाना है।

भारत के वर्ष 2002 के संकल्प जिसका शीर्षक 'व्यापक विनाश के हथियारों को हासिल करने से आतंकवादियों को रोकने संबंधी उपाय' है, को एक मत से पुनः अपनाया गया जिसे वर्ष 2015 में 91 देशों द्वारा सहप्रायोजित किया गया था। इसमें इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर सतत् मतैक्य को रेखांकित किया गया। इस संकल्प ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों द्वारा व्यापक विनाश के हथियारों को हासिल करने से आतंकवादियों को रोकने के उद्देश्यार्थ उपाय करने के लिए तथा इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करने को कहा।

'परमाणु हथियारों के प्रयोग पर रोक लगाने संबंधी कन्वेन्शन' से संबंधित भारत के संकल्प के तहत किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियारों के उपयोग अथवा उपयोग किए जाने के खतरों से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन पर बातचीत शुरू करने के लिए निरस्त्रीकरण सम्मेलन का पुनः आह्वान किया गया है। परमाणु हथियारों के मानवीय प्रभावों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हो रही वर्तमान परिचर्चा के संबंध में इस संकल्प की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। यह उस आस्था को दर्शाता है कि परमाणु हथियारों के उपयोगों पर रोक लगाने के निमित्त एक बहुपक्षीय, वैश्विक तथा कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज से निरस्त्रीकरण सम्मेलन में परमाणु हथियार पर रोक लगाने संबंधी बातचीत के लिए एक सौहार्दपूर्ण माहौल सृजित करने में मदद मिलेगी। 39 देशों के सहप्रायोजन के साथ इस संकल्प को प्रथम समिति द्वारा बहुमत से स्वीकार किया गया। भारत के तृतीय संकल्प ष्परमाणु खतरे को कम करनाष के तहत परमाणु सिद्धांतों की समीक्षा करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया और साथ ही परमाणु हथियारों का जानबूझकर अथवा दुर्घटनावश किए गए प्रयोग के जोखिम को कम करने के लिए तत्काल किए जाने वाले उपायों का उल्लेख किया गया है जिनमें डी अलर्टिंग तथा डी टार्गेटिंग जैसे उपाय शामिल हैं। इस संकल्प को भी बहुमत

से स्वीकार कर लिया गया जिसमें सहप्रायोजक देशों की संख्या बढ़कर 34 हो गई। प्रथम समिति ने 'अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा निरस्त्रीकरण के संदर्भ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका' विषय पर भारत द्वारा प्रस्तावित प्रारूप निर्णय को भी स्वीकार कर लिया।

संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग (यूएनडीसी)

वर्ष 2015 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग के महत्वपूर्ण सत्र का आयोजन 6–24 अप्रैल, 2015 तक किया गया। आयोग द्वारा अपने 2015–17 चक्र के लिए अपनाए गए एजेंडे के अनुसार आयोग ने परमाणु निरस्त्रीकरण और पारंपरिक हथियारों के क्षेत्र में विश्वास सृजन उपायों से संबंधित अपने 2 एजेंडा मदों पर विचार–विमर्श किया। सिफारिशों पर मतैक्य हासिल करने में मदद के उद्देश्यार्थ भारत ने आयोग की विचार–विमर्श प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। भारत ने बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण एजेंडे को आगे ले जाने, विशेषतः यूएनडीसी के वैश्विक स्वरूप का उल्लेख करते हुए संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण तंत्र के विशिष्ट विचार–विमर्श तंत्र के रूप में यू एन डी सी के कार्यों के महत्व को दोहराया।

निस्त्रीकरण सम्मेलन (सीडी)

वर्ष भर निरस्त्रीकरण सम्मेलन में विभिन्न विचार–विमर्शों के दौरान भारत ने कार्य योजना को स्वीकार करते हुए निरस्त्रीकरण सम्मेलन में उल्लेखनीय कार्य शुरू करने की आवश्यकता पर निरंतर बल दिया और इस संबंध में अनौपचारिक कार्य समूह द्वारा किए जा रहे कार्यों में सक्रिय हिस्सेदारी की। भारत ने निरस्त्रीकरण सम्मेलन एजेंडे से संबंधित सभी मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण साझा किया जिनमें परमाणु निरस्त्रीकरण, विखंडनीय सामग्री नियंत्रण संधि, बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ पर रोक, और नकारात्मक सुरक्षा आश्वासनों जैसे 4 महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। यह गौर किया जाए कि भारत इन सभी 4 महत्वपूर्ण एजेंडा मदों पर निरस्त्रीकरण सम्मेलन में आयोजित सुनियोजित अनौपचारिक परिचर्चा में एक सक्रिय साझेदार था। भारत ने निरस्त्रीकरण सम्मेलन को विश्व स्तरीय बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण विचार–विमर्श के एक मात्र मंच के रूप में दिए गए महत्व का पुनः उल्लेख किया। इसने परमाणु निरस्त्रीकरण को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा दिए गए महत्व को भी रेखांकित किया। भारत ने एक निष्पक्ष तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से सत्यापनीय विखंडनीय सामग्री नियंत्रण संधि पर बातचीत हेतु अपने समर्थन की भी घोषणा की। भारत ने अपना यह दृढ़ विश्वास भी व्यक्त किया कि इस सम्मेलन के पास सदस्यता, विश्वसनीयता तथा अपने अधिदेश के निर्वहन हेतु कार्य विधि नियमावली मौजूद है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी)

वर्ष 2015 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विभिन्न निकायों के साथ परमाणु अप्रसार तथा आतंकवाद विरोध के संबंध में सक्रिय रूप से समन्वय किया। इस संदर्भ में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1540 (2004) के अनुसरण में स्थापित सुरक्षा परिषद समिति के साथ समन्वय करता रहा है जो अन्य बातों के साथ–साथ राष्ट्रों को इस बाबत बाध्य करता है कि वह अराजकीय तत्वों द्वारा परमाणु, रासायनिक अथवा जैविक हथियारों तथा उनकी आपूर्ति प्रणालियों के विकास, प्रापण, विनिर्माण, हासिल करने, परिवहन, अंतरण अथवा इसके प्रयोग से बचे।

इसके अलावा भारत ने सुरक्षा परिषद संकल्प संख्या 1373 (2001) और 1624 (2005) के अनसुरण में स्थापित सुरक्षा परिषद आतंकवाद रोधी समिति के साथ घनिष्ठ समन्वय किया है, जो सीमाओं के भीतर तथा एक देश से दूसरे देश में आतंकवादी कृत्यों को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रों की क्षमता को और संबल प्रदान करने का कार्य करती है।

कतिपय पारंपरिक हथियार कन्वेन्शन (सीसीडब्ल्यू)

कतिपय पारंपरिक हथियार कन्वेन्शन से संबंधित उच्च संविदाकारी पक्षकारों की वार्षिक बैठक, जिसका आयोजन जिनेवा में 12–13 नवंबर, 2015 तक आयोजित किया गया था, में भारत ने कतिपय पारंपरिक हथियार कन्वेन्शन को संयुक्त राष्ट्र कार्यढ़ाचे के भीतर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून से संबंधित एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में अपना समर्थन दिया जिसके तहत कुछ पारंपरिक हथियारों के सभी मुख्य प्रयोक्ता तथा निर्माता साथ आते हैं। भारत ने वर्ष 2016 में कतिपय पारंपरिक हथियार कन्वेन्शन में घातक स्वायत हथियार प्रणालियों से संबंधित मुद्दों पर निरंतर चर्चा का समर्थन किया, जो कि पूर्व सम्मत अधिदेश पर आधारित था। 11 नवंबर, 2015 को आयोजित संशोधित प्रतोकॉल–II (एपी–II) के 17वें वार्षिक सम्मेलन में भारत ने एपी–II में सन्निहित दृष्टिकोण के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया और मानवरोधी बारूदी सुरंगों को समाप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत ने एपी–II के तहत आईईडी के संबंध में निरंतर कार्य हेतु अपना समर्थन भी व्यक्त किया। 9–10 नवंबर, 2015 को आयोजित प्रोतोकॉल–V के 9वें वार्षिक सम्मेलन में भारत ने सभी मुद्दों पर हुई चर्चा में अपना योगदान दिया जिनमें जेनेरिक रोकथाम उपाय, युद्ध में विस्फोटक अवशेषों से संबंधित सूचनाओं की रिकार्डिंग तथा पारेषण, सहयोग एवं सहायता और युद्ध में शिकार हुए लोगों की सहायता शामिल है। भारत ने प्रोतोकॉल–ट और एपी–ष्ष के विशेषज्ञों की अप्रैल 2015 में आयोजित बैठकों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत ने जिनेवा में 30 नवंबर से 4 दिसंबर, 2015 तक आयोजित व्यक्तिरोधी बारूदी सुरंग कन्वेन्शन (ओटावा कन्वेन्शन) में शामिल राष्ट्रीय पक्षकारों की 14वीं बैठक में एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में भाग लिया।

जैविक जहरीला हथियार कन्वेन्शन (बीटीडब्ल्यूसी)

भारत ने दिनाकं 10–14 अगस्त, 2015 तक आयोजित जैविक जहरीला हथियार कन्वेन्शन से संबंधित विशेषज्ञों की वार्षिक बैठक और दिनांक 14–18 दिसंबर, 2015 तक आयोजित पक्षकार राष्ट्रों की बैठक में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विशेषज्ञों की वर्ष 2015 में

आयोजित बैठक में भारत ने जैविक जहरीला हथियार कन्वेन्शन को प्रथम बहुपक्षीय, निष्पक्ष संधि के रूप में उसके द्वारा दिए गए महत्व को पुनः दोहराया जिसके तहत विनाश के हथियारों की संपूर्ण श्रेणी को प्रतिबंधित किया गया। भारत ने इस कन्वेन्शन की कारगरता में सुधार करने, इसके क्रियान्वयन को सशक्त करने, और इसे वैश्विक रूप प्रदान करने हेतु प्रयासों का समर्थन किया। बीटीडब्ल्यूसी बैठकों में 7वें समीक्षा सम्मेलन में यथानिर्णीत तीन एजेंडा मदों (सहयोग एवं सहायता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास की समीक्षा तथा राष्ट्रीय क्रियान्वयन) और द्विवार्षिकी एजेंडा मद (अनुच्छेद–III के तहत सहायता एवं सहयोग) पर विस्तार से चर्चा की गई। वर्ष 2016 में आयोजित होने वाले आठवें समीक्षा सम्मेलन की तैयार में अपने योगदान के तौर पर भारत ने फ्रांस के साथ एक कार्यपत्र (working paper) प्रस्तुत किया है जिसमें बीडब्ल्यूसी के अनुच्छेद–VII के तहत सहायता संबंधी डाटाबेस स्थापित करने का प्रस्ताव है और बीडब्ल्यूसी के अनुच्छेद–III के सशक्त क्रियान्वयन हेतु संयुक्त राज्य अमरीका के साथ भी एक कार्यपत्र प्रस्तुत किया।

रासायनिक हथियार कन्वेन्शन (सीडब्ल्यूसी)

रासायनिक हथियार निषेध संगठन (ओपीसीडब्ल्यू) की कार्यकारी परिषद के एक सदस्य के रूप में भारत ने विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयों के निरूपण, मसौदा तैयार करने, विचार–विमर्श तथा इन्हें स्वीकार किए जाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विगत वर्षों की ही तरह रासायनिक हथियारों को नष्ट करने, उद्योग निरीक्षण, राष्ट्रीय क्रियान्वयन एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व सहायता से संबंधित मुद्दों पर कार्यकारी परिषद के नियमित सत्रों (7–10 जुलाई, 2015) तथा (6–9 अक्तूबर, 2015), कार्यकारी परिषद की अनेक विशेष बैठकों और पक्षकार राष्ट्रों के सम्मेलन (30 नवम्बर–4 दिसम्बर, 2015) के दौरान सक्रिय भूमिका निभाना जारी रखा।

भारत ने ओपीसीडब्ल्यू के महानिदेशक (डीजी) श्री अहमत उजूक्कू की 2–5 सितंबर, 2015 तक की भारत यात्रा की मेजबानी की। महानिदेशक महोदय ने रासायनिक हथियार निरस्त्रीकरण व्यवस्था के प्रति भारत की उच्च स्तरीय प्रतिबद्धता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं क्षमता निर्माण तंत्रों में अभिवृद्धि के उद्देश्यार्थ ओपीसीडब्ल्यू के प्रशिक्षण एवं सहायता कार्यकलापों में इसके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया। अपनी यात्रा के दौरान, महानिदेशक महोदय ने नई दिल्ली स्थित रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए) और मुम्बई स्थित रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईसीटी) में विचारकों, शिक्षाविदों, छात्रों तथा उद्योग प्रतिनिधियों को सम्बोधित किया। भारतीय राष्ट्रिक श्री हामिद अली राव को जुलाई 2015 में ओपीसीडब्ल्यू का महानिदेशक नियुक्त किया गया।

लघु अस्त्र एवं हल्के हथियार

लघु अस्त्र एवं हल्के हथियारों से जुड़े सभी प्रकार के अवैध कारोबार की रोकथाम करने, इससे निपटने तथा इन्हें समूल नष्ट करने के लिए जुलाई 2001 में स्वीकृत संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के तहत इसके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए व्यापक पैमाने पर राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक उपाय मौजूद हैं। भारत ने न्यूयार्क में 1–5 जून, 2015 तक आयोजित सरकारी विशेषज्ञों की द्वितीय बहुद्देशीय बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य राष्ट्रों ने कार्रवाई कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय अनुरेखण उपकरण की वैधता की एकमत से पुनः अभिपुष्टि की। विशेष मुद्दों एवं विषयों से जुड़ी मुख्य क्रियान्वयन चुनौतियों और अवसरों पर भी चर्चा की गई जिसमें भारत ने सक्रिय हिस्सेदारी की।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई ए ई ए)

भारत ने 13–18 सितंबर, 2015 तक वियना में आयोजित आई ए ई ए महा सम्मेलन के 59वें सत्र में हिस्सा लिया। भारतीय शिष्टमण्डल ने अमरीका, रूस, फ्रांस, बांग्लादेश, ब्रिटेन, अर्जेन्टिना तथा श्रीलंका के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें कीं। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बी ए आर सी) ने महा सम्मेलन सप्ताह के दौरान एक प्रदर्शनी भी आयोजित की।

असैन्य परमाणु सहयोग

प्रधान मंत्री की फ्रांस यात्रा (9–12 अप्रैल, 2015) के दौरान जैतापुर परमाणु विद्युत परियोजना की स्थानीकरण को बढ़ाकर तथा वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार करके लागत में कमी करने के उद्देश्यार्थ मैसर्स लार्सन एंड टूब्रो और मैसर्स अरेवा के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मैसर्स एन पी सी आई एल और मैसर्स अरेवा के बीच पूर्व–इंजीनियरी करार पर भी हस्ताक्षर किए गए।

प्रधान मंत्री की कनाडा यात्रा (14–16 अप्रैल, 2015) के दौरान भारत की ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए यूरेनियम की दीर्घावधिक आपूर्ति के लिए भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) और कनाडा के मैसर्स कैमेको के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। भारत–कनाडा परमाणु सहयोग करार के तहत संयुक्त समिति की तीसरी बैठक 16 अक्तूबर, 2015 को मुम्बई में आयोजित की गई। उसी समय ओवरसीज कनाडियाई परमाणु उद्योग शिष्टमण्डल ने नई दिल्ली/मुम्बई की यात्रा की।

प्रधान मंत्री की मंगोलिया यात्रा (17 मई, 2015) के दौरान, भाभाट्रान–ᐧᐧ टेली थेरेपी यूनिट के साथ–साथ एक रेडियोथेरेपी सिमुलेटर उपहार स्वरूप प्रदान करने के लिए टाटा मेमोरियल सेन्टर ऑफ इंडिया और नेशनल कैंसर सेंटर ऑफ मंगोलिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्वक उपयोग में सहयोग के लिए भारत और श्रीलंका के बीच एक करार 2 जून, 2015 को लागू हुआ। उम्मीद है कि इस करार से परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में ज्ञान एवं विशेषज्ञता का आदान–प्रदान करने, संसाधन बांटने, क्षमता निर्माण तथा कार्मिकों के प्रशिक्षण में सहयोग करना सुविधाजनक हो पाएगा।

प्रधानमंत्री की कजाखस्तान यात्रा (7–8 जुलाई, 2015) के दौरान प्राकृतिक यूरेनियम सान्द्र की बिक्री एवं खरीद के लिए भारत गणराज्य के परमाणु ऊर्जा विभाग और जेएसपी नेशनल एटॉमिक कम्पनी 'कज एटॅम प्रॉम' के बीच एक दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए।

प्रधानमंत्री की ब्रिटेन यात्रा (12 नवम्बर, 2015) के दौरान परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग हेतु भारत सरकार और ग्रेट ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम तथा उत्तरी आयरलैंड की सरकार के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। भारत के ग्लॅबल सेन्टर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप (जीसीएनईपी) के सहयोग से संयुक्त प्रशिक्षण तथा अनुभव बांटने के लिए यू.के. तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए भारत सरकार और ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच करार संबंधित आंतरिक प्रक्रियाएं पूरी कर लिए जाने के बाद 13 नवम्बर, 2015 को लागू हुआ। यह करार अन्य बातों के साथ–साथ सहयोग को बढ़ावा देगा जिससे ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए यूरेनियम के दीर्घकालिक आपूर्तिकर्ता की भूमिका अदा कर सकता है।

भारत और अमरीका ने संपर्क समूह तंत्र के तहत अपनी द्विपक्षीय असैन्य परमाणु सहयोग संबंधी बातचीत जारी रखी है। संपर्क समूह की पांचवीं बैठक नवम्बर 2015 में आयोजित की गई। अमरीका–भारत कारोबार परिषद (यूएसआईबीसी) परमाणु ऊर्जा संस्थान (एनईआई) परमाणु व्यापार मिशन ने दिसम्बर 2015 में नई दिल्ली/मुम्बई का दौरा किया।

जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा (12 दिसंबर, 2015) के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग करार से संबंधित एक ज्ञापन का आदान–प्रदान किया जिसके अनुसार दोनों पक्षों ने पुष्टि की कि वे परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमत हुए हैं।

प्रधान मंत्री जी की रूस यात्रा (24 दिसंबर, 2015) के दौरान दोनों पक्षों ने भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग तथा रूसी राज्य परमाणु ऊर्जा सहयोग ष्रोसाटोमष के बीच ष्रूस द्वारा अभिकल्पित नाभिकीय रिएक्टर इकाइयों का भारत में निर्माण किए जानेष से संबंधति एक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिसम्ब 2014 के असैन्य सहयोग हेतु भारत–रूस रणनीतिक दृष्टिकोण के तहत परिकल्पित भावी सहयोग योजना के अनुरूप रूस द्वारा निर्मित नाभिकीय संयंत्रों का निर्माण क्रमिक रूप से भारत में करना है।

फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा (25 जनवरी, 2016) के दौरान दोनों नेताओं ने जैतापुर में छह नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टरों के निर्माण हेतु वर्ष 2016 के अंत तक तकनीकी–वाणिज्यिक वार्ताएं संपन्न करने के लिए अपनी औद्योगिक कंपनियों को प्रोत्साहित किया। उस प्रक्रिया में परियोजना की लागत प्रभावित, फ्रांस की ओर से रियायती वित्त पोषण, प्रौद्योगिकी अंतरण में सहयोग तथा भारत सरकार की में इन इन्डिया पहल के अनुसरण में बड़े तथा महत्वपूर्ण पुर्जों का कम लागत में भारत में निर्माण करने पर विशेष बल दिया जाएगा। दोनों पक्षों ने 2016 में जैतापुर नाभिकीय ऊर्जा परियोजना पर चर्चाओं में तेजी लाने के लिए सहयोग की योजना बनाने पर भी अपनी सहमति व्यक्त की। वर्ष 2017 के आरंभ में परियोजना का कार्यान्वयन शुरू करना दोनों का साझा उद्देश्य है। दोनों पक्षों ने जैतापुर में छह ई पी आर इकाइयों का निर्माण करने के लिए ई डी एफ तथा एन पी सी आई एल के बीच एक संशोधित समझौता ज्ञापन की पहल की।

एक वित्तीय जोखिम प्रबंधन तंत्र, जिसे भारत परमाणु बीमा पूल (आई एन आई पी) का नाम दिया गया है, का औपचारिक उद्घाटन जुलाई 2015 में किया गया, जिसमें जीआईसीआईई एक प्रधान अंशदाता है। उम्मीद है कि यह पूल शीघ्र ही अपना वाणिज्यिक कार्यकलाप प्रारंभ करेगा। उम्मीद है कि यह तंत्र परमाणु क्षति अधिनियम 2010 हेतु भारत के असैन्य दायित्व संबंधी चिंताओं को दूर करेगा।

परमाणु सुरक्षा

भारत ने परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन से संबंधित विलनियस, लिथुआनिया (जुलाई 2015) तथा अलमाती,, कजाखस्तान (दिसंबर 2015) तथा स्टॉकहोम, स्वीडन (फरवरी 2016) में आयोजित तैयारी बैठकों में हिस्सा लिया। इसके अलावा भारत ने लिओन, फ्रांस (अप्रैल 2015) तथा न्यूयार्क (मई 2015) में आयोजित प्रारूपन समूह की बैठकों में भी हिस्सा लिया। भारत ने एन एस एस कार्ययोजनाओं/शिखर सम्मेलन परिणामों को अंतिम रूप देने में सक्रिय योगदान किया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एन एस एस प्रक्रिया को संगत संगठनों, मुख्यतः आई ए ई ए में उचित तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। प्रधान मंत्री जी ने वाशिंगटन में आयोजित शिखर सम्मेलन (31 मार्च– 01 अप्रैल, 2016) में भाग लिया।

एशिया में बातचीत तथा विश्वास सृजन उपायों पर सम्मेलन (सी आई सी ए)

एशिया में बातचीत तथा विश्वास सृजन उपायों पर सम्मेलन (सी आई सी ए) एशियाई क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा प्रगति को बढ़ावा देने हेतु वार्ता एवं सहयोग का एक 26 सदस्यीय क्षेत्रीय मंच है। वर्ष 2015 में, भारत ने बीजिंग में 24–26 अगस्त, 2015 तक आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की समिति (एस ओ सी) की बैठकों में हिस्सा लिया। भारत ने मतैक्य तथा एशियाई वास्तविकताओं से प्रेरित कदम–दर–कदम दृष्टिकोण पर आधारित मौजूदा क्षेत्रों में विश्वास सृजन उपायों को और मजबूती प्रदान करके इन्हें क्रियान्वित करने हेतु अपने समर्थन का उल्लेख किया। भारत दो विश्वास सृजन उपायों अर्थात्, परिवहन गलियारों की सुरक्षित एवं प्रभावी प्रणालियों का विकास और ऊर्जा सुरक्षा का समन्वय कर रहा है।

आसियान क्षेत्रीय मंच (ए आर एफ) और इससे संबंधित मंच

एशिया–प्रशांत क्षेत्र में राजनैतिक सुरक्षा तथा आर्थिक क्षेत्रों में अधिक से अधिक भागीदारी करके भारत ने आसियान–प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाए रखी। विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त) ने कुआलालम्पुर में 6 अगस्त, 2015 को आयोजित 22वीं ए आर एफ मंत्रिस्तरीय बैठक में भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया। आसियान के नेतृत्व वाले क्षेत्रीय सुरक्षा तंत्रों के बीच समन्वयन एवं अनुपूरकताओं सहित क्षेत्रीय निरोधात्क राजनय क्षमताएं विकसित करने के उद्देश्यार्थ अधिकाधिक पहल करने पर सर्वसम्मति बनी। दक्षिण चीन समुद्र के मुद्दे पर जो इस क्षेत्र के विभिन्न राजनैतिक एवं सुरक्षा से जुड़े मंचों पर चर्चा के दौरान एक विवादास्पद विषय के रूप में उभरा है, भारत ने नौकायन, वायुक्षेत्र से गुजरने तथा निर्वाध कारोबार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की आवश्यकता का उल्लेख किया। भारत ने ए आर एफ के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक, आपदा राहत, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोध तथा अंतर्राष्ट्रीय अपराध, परमाणु अप्रसार तथा निरस्त्रीकरण संबंधी अंतर–सत्रीय समूह बैठकों, रक्षा विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थानों के प्रमुखों की बैठकों और ए आर एफ रक्षा अधिकारी वार्ता और विभिन्न सहयोग कार्यकलापों तथा सेमिनारों में हिस्सा लिया। भारत ने केदाह तथा पर्लिस, मलेशिया में 24–28 मई, 2015 तक आयोजित ए आर एफ आपदा राहत अभ्यास (एआरएफ डायरेक्स 2015) में भी हिस्सा लिया।

कुआलालम्पुर में 3 नवम्बर, 2015 को आयोजित तीसरी एडीएमएम प्लस बैठक में भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर ने किया। भारत ने एच ए डी आर, सैन्य औषध, समुद्री सुरक्षा, शांति रक्षा ऑपरेशन आतंकवादरोध से संबंधित आसियान रक्षा मंत्री बैठक प्लस (एडीएमएम प्लस) विशेषज्ञ कार्यसमूह में भी हिस्सा लिया और वर्ष 2014–17 तक के वर्तमान चक्र में 'ह्यूमेनिटेरियन माइन एक्शन' विषय पर विशेषज्ञ कार्यसमूह की सह अध्यक्षता की।

भारत वर्ष 2016 में सी बी एम/निवारक राजनय पर एआरएफ अंतर–सत्रीय समूह (आई एस जी) की बैठक की लाओस–पीडीआर के साथ मिलकर सह–अध्यक्षता करेगा जो ए आर एफ कार्यढांचे के भीतर तीसरा कार्यसाधक क्लियरिंग हाउस है।

समुद्री मामले

भारत ने नवम्बर 2015 में नई दिल्ली में आयोजित प्रारंभिक भारत–ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता की मेजबानी की। द्वितीय द्विपक्षीय समुद्री वार्ता का आयोजन जापान के साथ टोक्यो में (अक्तूबर 2015) किया गया। इस कार्य के दौरान समुद्री सुरक्षा से संबंधित व्यापक मुद्दों पर चर्चा की गई।

भारत ने मलक्का तथा सिंगापुर (एस ओ एम एस) जलडमरूमध्य से संबंधित सहयोग मंचों पर सक्रिय भागीदारी की। नौकायन कोष में एस ओ एम एस सहायता के रूप में पहली बार 50,000 अमरीकी डॉलर (पचास हजार) का अंशदान किया गया।

निर्यात नियंत्रण

भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एन एस जी) और तीन अन्य बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण अर्थात प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एम टी सी आर), ऑस्ट्रेलिया समूह और वासेनार व्यवस्था (डब्ल्यू ए) और साथ ही इन चार व्यवस्थाओं के अलग–अलग सदस्यों के साथ जुड़ा है जिसका उद्देश्य इन व्यवस्थाओं में हमारी सदस्यता के मुद्दे को आगे बढ़ाना है। इन व्यवस्थाओं में हमारी सदस्यता से उम्मीद है कि, अन्य बातों के साथ–साथ, भारत के लिए दोहरे–उपयोग तथा उच्च प्रौद्योगिकी मदों की सुलभता आसान होगी और साथ ही इससे वैश्विक अप्रसार संबंधी प्रयास मजबूत होंगे।

एम टी सी आर के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने जून 2015 में नई दिल्ली का दौरा किया। भारत ने एमटीसीआर की सदस्यता के लिए जून 2015 में अपना औपचारिक आवेदन प्रस्तुत किया। इस आवेदन को काफी समर्थन मिला है और यह एम टी सी आर के विचाराधीन है। एन एस जी के अध्यक्ष ने एन एस जी तथा परमाणु कारोबार पर बातचीत के लिए अक्तूबर 2015 में भारत का दौरा किया। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री से भी मुलाकात की। इस वर्ष के दौरान भारतीय विशेषज्ञों ने वियना में जून 2015 में आयोजित वास्सेनार व्यवस्था के तकनीकी विशेषज्ञों की बैठक और जून 2015 में पर्थ में गैर–सदस्यों के लिए ऑस्ट्रेलिया समूह वार्ता में हिस्सा लिया। निर्यात नियंत्रण संबंधी द्विपक्षीय वार्ताएं जर्मनी, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ आयोजित की गई। भारत–जर्मनी उच्च प्रौद्योगिकी सहभागिता समूह (एच टी पी जी) से जुड़े एक कार्य–समूह की बैठक सितम्बर 2015 में आयोजित की गई।

नाभिकीय क्षति के लिए पूरक मुआवजे पर कन्वेंशन (सी एस सी), 1997

4 फरवरी, 2016 को भारत ने वर्ष 1997 में पारित तथा 27 अक्तूबर, 2010 को भारत द्वारा हस्ताक्षरित नाभिकीय क्षति के लिए पूरक मुआवजे से संबद्ध कन्वेंशन के अनुसमर्थन दस्तावेजों को आई ए ई ए में जमा कराया। यह भारत में असैन्य नाभिकीय दायित्व से संबंधित मुद्दों का समाधान करने की दिशा में एक निर्णायक कदम था जिसमें फरवरी 2015 में असैन्य नाभिकीय दायित्व पर पूर्व में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जारी किए गए तथा बाद में भारत नाभिकीय बीमा पूल (आई एन आई पी) का शुभारंभ किया गया।

■ ■

बहुपक्षीय आर्थिक संबंध

11

ऊफा, रूस में ब्रिक्स सम्मेलन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऊफा, रूस में 8–9 जुलाई 2015 के दौरान 7वें ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। ब्रिक्स सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का विषय थारू शब्रिक्स भागीदारी – वैश्विक विकास का एक शक्तिशाली कारक"। नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुधार, आईएमएफ सुधार, विश्व व्यापार संगठनए जी–20, क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रमों, आतंकवाद, नए विकास बैंक (एनडीबी), ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (सीआरए), आईसीटी पर सहयोग और इंट्रा–ब्रिक्स सहयोग से संबंधित अन्य मुद्दों सहित कई व्यापक मुद्दों पर चर्चा की। नेताओं ने सम्मेलन में ऊफा घोषणा और कार्य योजना पारित की।

7वें ब्रिक्स सम्मेलन के मुख्य परिणामों में सांस्कृतिक सहयोग पर एक करार, संयुक्त ब्रिक्स वेबसाइट के सृजन पर एक समझौता ज्ञापन और एनडीबी के साथ सहयोग पर अंतर ब्रिक्स बैंक तंत्र के तहत एक समझौता ज्ञापन शामिल हैं। सम्मेलन में नेताओं ने ब्रिक्स आर्थिक सहभागिता रणनीति भी पारित की जिसमें व्यापार, निवेशए वित्तए विनिर्माण, ऊर्जा, कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, आईसीटी आदि के क्षेत्रों में सहयोग शामिल है।

प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में पहल करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को 21वीं शताब्दी में प्रासंगिक रहने के लिए समय पर सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने ब्रिक्स देशों से आह्वान किया कि आतंकवाद से संबंधित प्राथमिक सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विभिन्न समितियों में मिलकर कार्य करें और उन्होंने किसी प्रकार के भेदभाव के बिना आतंकवाद के प्रायोजकों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विश्व स्तर पर सस्ती नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करने के लिए एक ब्रिक्स ऊर्जा क्षमता प्रौद्योगिकी कार्यक्रम की स्थापना का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी प्रस्ताव किया कि एनडीबी द्वारा वित्त पोषित पहली परियोजना स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

रूस ने 9 जुलाई 2015 को ब्रिक्स–आउटरीच सत्र की भी मेजबानी की जिसमें यूरेशियन आर्थिक संघ और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) दस आमंत्रित देशों के नेताओं, सदस्यों तथा पर्यवेक्षकों–अफगानिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस, ईरान, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने भाग लिया। ब्रिक्स आउटरीच सत्र में, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और अवसंरचना विकास साझा हित के क्षेत्रों के रूप में उभरा जहां ब्रिक्स देश मध्य एशियाई देशों के साथ मिलकर इस क्षेत्र के समावेशी और सतत विकास के लिए कार्य कर सकते हैं।

जी 20 सम्मेलन के अवसर पर ब्रिक्स नेताओं की बैठक

प्रधानमंत्री ने 10वें जी20 सम्मेलन के अवसर पर ही 15 नवम्बर 2015 को अंतालयाए तुर्की में ब्रिक्स के नेताओं के साथ एक बैठक की। यह बैठक वर्तमान ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में रूस के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित की गई। एजेंडा में आर्थिक भागीदारी के लिए ब्रिक्स कार्यनीति, नए विकास बैंक और आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था सहित जी–20 सम्मेलन की कार्यसूची और इंट्रा–ब्रिक्स मुद्दों पर विचारों का विनिमय शामिल है। नेताओं ने मिस्र में एक रूसी वाणिज्यिक विमान की दुर्घटना की वजह से जान हानि के संबंध में रूस के प्रति समर्थन और एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने पेरिस में आतंकवादी हमले को ध्यान में रखते हुए जी–20 सम्मेलन की पूर्व संध्या पर 13 नवंबर 2015 को फ्रांस के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया और आतंकवाद का मुकाबला करने में एक साथ कार्य करने का संकल्प लिया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि आतंकवाद से लड़ना ब्रिक्स के लिए एक प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि ब्रिक्स की भारतीय अध्यक्षता फरवरी–दिसंबर 2016 के दौरान, का विषय "उत्तरदायी, समावेशी और सामूहिक समाधान" का निर्माण होगा। प्रधान मंत्री ने नए विकास बैंक संस्थान (एनडीबीआई) की स्थापना का भी प्रस्ताव किया। बैठक के बाद एक मीडिया टिप्पणी भी जारी की गई।

प्रधानमंत्री ने ऊफ़ा, रूस (9 जुलाई 2015) में 7वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

प्रधानमंत्री तुर्की में 15 नवंबर, 2015 को जी –20 शिखर सम्मेलन 2015 के मौके पर अन्य ब्रिक्स नेताओं के साथ

ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक

विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70 वें सत्र के अवसर पर 29 सितंबर 2015 को न्यूयॉर्क में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक का आयोजन किया। मंत्रियों ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दोंए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय परिदृश्यए संयुक्त राष्ट्र महासभा और इंट्रा–ब्रिक्स सहयोग के एजेंडे के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के उपरांत एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। मंत्री स्तरीय बैठक से पूर्व रूस की मेजबानी में ब्रिक्स के शेरपाओं की बैठक हुई।

आईबीएसए वार्तामंच

25 सितंबर 2015 को आईबीएसए (भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका) वार्ता मंच बैठक (वरिष्ठ अधिकारियों) के केंद्रीय बिंदु न्यूयार्क में मिले। जून 2003 में आईबीएसए की स्थापना के बाद यह उनकी 25वीं बैठक थी। उन्होंने दक्षिण–दक्षिण सहयोग के बढ़ते महत्व के मद्देनजर आईबीएसए की निरंतर प्रासंगिकता की पुष्टि की। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने सूक्ष्म वित्त पोषणए उपग्रहों पर आधारित अनुप्रयोगों, स्मार्ट शहरों और संयुक्त अंटार्कटिका अभियान के क्षेत्र में भारत द्वारा प्रस्तावित आईबीएसए सहयोग के लिए नई पहल का स्वागत किया।

विदेश मंत्रियों के समूह पंद्रह (जी –15) की बैठक

जी–15 के विदेश मंत्रियों की 38वीं बैठक न्यूयॉर्क में 1 अक्टूबर 2015 को आयोजित की गई थी। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के लिए श्रीलंका के स्थायी प्रतिनिधि ने अपने विदेश मंत्री की ओर से बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यालय से एक अधिकारी ने भारत के प्रतिनिधित्व किया था। देश की ओर से अपने वक्तव्य में भारत ने इस बात पर जोर दिया कि जी–15 अपने दक्षिण–दक्षिण सहयोग गतिविधियों को मजबूत करके स्वयं को सशक्त बनाए और विशेष रूप से 2015 के पश्चात विकास एजेंडा लागू करने के लिए सतत विकास के मुद्दों पर वैश्विक नीति निर्माण के लिए एक मंच के रूप में उभरें हैं।

10वां जी20 सम्मेलन

प्रधानमंत्री ने 15–16 नवम्बर 2015 को अंतालयाए तुर्की में 10वें जी20 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। सम्मेलन के एजेंडे में आतंकवादए शरणार्थी संकट, जलवायु परिवर्तन, 10वें विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, वैश्विक अर्थव्यवस्था, विकास और रोजगार तथा निवेश कार्यनीतियों, उन्नत लचीलापन, वित्तीय विनियमन, अंतरराष्ट्रीय करए भ्रष्टाचार–रोध, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधार और ऊर्जा शामिल थे। जी –20 नेताओं ने एक विज्ञप्ति और सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर एक सामूहिक वक्तव्य जारी किया।

प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन में विकास और जलवायु परिवर्तन पर अग्रणी पहल की। उन्होंने सम्मेलन में कई नए विचार प्रस्तुत किए। आतंकवाद के विरुद्ध पहल करते हुए प्रधानमंत्री ने लक्षित प्रतिबंधों तथा प्रभावी आतंकवाद–रोधी वित्त पोषण के माध्यम से आतंकवाद वित्त पोषण के विरुद्ध सहयोग सशक्त करने का आह्वान किया। उन्होंने बिना किसी देरी के अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध एक व्यापक अभिसमय पारित करने का आग्रह किया। उन्होंने आतंकवादियों को हथियारों की आपूर्ति रोकने, आतंकवादी आवागमन बाधित करने और रोकने तथा आतंकवाद के वित्त पोषण को अपराध घोषित करने के लिए जोरदार प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया के उपयोग को न्यूनतम करने के लिए आपसी सहायता पर बल दिया। उन्होंने उग्रवाद के खिलाफ एक सामाजिक आंदोलन के लिए धार्मिक नेताओंए विचारकों और राय निर्माताओं को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया और विशेष रूप से युवाओं को संबोधित किया। निजी क्षेत्र में पारदर्शिता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान जी–20 कार्य का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जी–20 भ्रष्टाचार से निपटने के कार्य को प्राथमिकता दें। मूल देश में अवैध धन की वापसी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने अत्यधिक बैंकिंग गोपनीयता और जटिल कानूनी और नियामक ढांचे संबंधी बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता पर अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया।

2014 में पिछले जी –20 सम्मेलन में ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में निर्धारित लक्ष्य जी–20 के सामूहिक सकल घरेलू उत्पाद को 2013 की अपेक्षा 2018 तक अतिरिक्त दो प्रतिशत तक बढाने के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने यह सुझाव दिया कि जी–20 ऐसी समर्थन प्रणाली का निर्माण करें जो अधिकतम विकास क्षमता वाले देशों पर केंद्रित हों और विकास को बढ़ावा देने के लिए देश की कार्यनीतियों को सुविधाजनक बनाने तथा विशेष बाधाओं को दूर करने में उनकी सहायता कर सकें।

व्यापार और ऊर्जा पर पहल करते हुए प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि दोहा दौरे द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए और बाली पैकेज के सभी कारकों को लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि क्षेत्रीय व्यापार करारों से वैश्विक व्यापार व्यवस्था विखंडन न हो। उन्होंने स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ाने का आह्वान किया ताकि इसकी लागत में कमी की जा सके तथा इसे किफायती और सुलभ बनाया जा सके। उन्होंने ऊर्जा के

15 नवम्बर, 2015 को तुर्की में आयोजित समावेशी विकास पर जी–20 शिखर सम्मेलन कार्य सत्र में प्रधानमंत्री

पोडांग, इन्डोनेशिया में 15वीं आईओआरए मंत्रिपरिषद बैठक

लिए वैश्विक शासन संरचना में प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अधिक से अधिक अधिकार देने का आह्वान किया।

आईओआरए मंत्रिपरिषद की 15वीं बैठक

विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ) वी के सिंह (सेवानिवृत्त) ने 23 अक्टूबर 2015 को पाडांग में इंडोनेशिया की मेजबानी में आईओआरए मंत्रिपरिषद 'हिंद महासागर रिम संघ, की 15वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस बैठक में 2015–17 अवधि के लिए ऑस्ट्रेलिया ने एसोसिएशन की अध्यक्षता ग्रहण की। दक्षिण अफ्रीका ने 2015–17 के लिए इंडोनेशिया से उपाध्यक्ष का पद ग्रहण किया।

बैठक में आईओआरए के 21वें सदस्य के रूप में सोमालिया का स्वागत किया गया। जर्मनी आईओआरए का 7वां वार्ता भागीदार बन गया हैय अन्य वार्ता भागीदारों में चीनए मिस्रए फ्रांसए जापानए ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं।

बैठक में पाडांग विज्ञप्तिए आईओआरए समुद्री सहयोग घोषणा और आईओआरए समन्वय पर एक तदर्थ समिति की स्थापना का निर्णय पारित किया गया।

बैठक में भारत के इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से स्वागत किया गया कि आईओआरए ट्रोइका ख्वर्तमान (इंडोनेशिया)ए विगत (ऑस्ट्रेलिया) और भावी (दक्षिण अफ्रीका) अध्यक्षों, आपसी हित के मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर आसियान के अध्यक्ष के साथ वार्षिक बैठकों का संस्थाकरण करें। विदेश राज्य मंत्री ने सुझाव दिया कि दस्युताए तस्करी और अंतरराष्ट्रीय अपराध और प्राकृतिक आपदाओं के गैर परंपरागत सुरक्षा खतरों की चुनौतियों के एक क्षेत्रीय व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उन्होंने आईओआरए सचिवालय के लिए लैपटॉप और फोटोकॉपियर उपलब्ध कराने के मामले में आईओआरए विशेष निधि और तकनीकी सहायता के लिए 100,000 अमेरिका डॉलर के योगदान की घोषणा की।

■ ■

12

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) और बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक)

भारत अपने भूगोलए अर्थव्यवस्थाए अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा और इस क्षेत्र के लिए प्रतिबद्धता के कारण सार्क में प्रमुख है। सार्क के लिए भी इसका योगदान लाभदायक है। भारत ने सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए सार्क संस्थानों को कुल मिलाकर 530 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का योगदान दिया गया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने काठमांडू (नवंबरए 2014) में 18वें सार्क शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से कई एक पक्षीय प्रस्ताव रखे हैं। इन घोषणाओं के कार्यान्वयन का कार्य प्रगति पर है और निम्नलिखित अनुसार कई लक्ष्य प्राप्त किए जा चुके हैंः–

18वें सार्क शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा हैः

("हम भारत में कारोबार करने में आसानी की बात करते हैं। चलो हम अपने क्षेत्र में इसका विस्तार करें। मैं यह सुनिश्चित करने का आश्वासन देता हूं कि सीमा पर हमारी सुविधाओं में तेजी आएगी, व्यापार मन्दा नहीं होगा... भारत अब सार्क के लिए 3–5 वर्ष के लिए व्यापार वीजा देगा।')

उपर्युक्त घोषणा के अनुसरण मेंए सार्क देशों के व्यावसायियों के लिए 3–5 वर्ष के दीर्घावधिक व्यापार वीजा जारी किए जा रहे हैं।

("भारत पोलियो मुक्त देश के अनुवीक्षण एवं निगरानी का समर्थन करेगा")

अफगानिस्तान से स्वास्थ्य अधिकारियों / विशेषज्ञों ने 22 नवंबरए 2015 को भारत के उप–राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस (एसएनआईडी) में भाग लिया ताकि वे भारत में अपनाई जाने वाली सर्वोत्त प्रणालियों को सीख सकें तथा उनका पालन कर सकें।

("नई दिल्ली में दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय का सपना साकार हो गया। सही अर्थों में दक्षिण एशियाई बनने के लिए इसमें प्रत्येक सार्क देश से कम से कम एक विश्वविद्यालय की भागीदारी होनी चाहिए।")

दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय ने प्रत्येक सार्क देश में कम से कम एक विश्वविद्यालय के साथ सहभागिता स्थापित की है।

("स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ... चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने वाले लोगों के लिएए भारत रोगी और एक परिचर के लिए तत्काल चिकित्सा वीजा प्रदान करेगा।")

सार्क देशों में स्थित हमारे मिशनों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर रोगियों और परिचर के लिए चिकित्सा वीजा जारी किए जा रहे हैं।

"हम पड़ोसियों के रूप में अच्छे और बुरे समय में समान रूप से एक साथ होना चाहिए ... जैसे हम दुनिया भर के संघर्षों और आपदाओं में फंसे भारतीयों की सहायता करते हैं वैसे ही हम अपने सभी दक्षिण एशियाई नागरिकों की सहायता करेंगे।"

आवश्यकतानुसार अपेक्षित सहायता दी जा रही है।

काठमांडू (नवंबर 2014) में 18वें सार्क शिखर सम्मेलन में ऊर्जा सहयोग (विद्युत) पर सार्क अवसंरचना करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस करार से सार्क क्षेत्र के अंदर सीमा पार विद्युत व्यापार सुविधाजनक बनाने के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार होगा। भारत ने 31 जुलाई 2015 को करार का अनुसमर्थन किया।

अप्रैल–नवंबर, 2015 के दौरान, सार्क प्रभाग ने भारत में निम्नलिखित सार्क कार्यकलाप आयोजित किए :–

- क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण अध्ययन (चरण–।।) की सिफारिशों को प्राथमिकता देने के लिए गोवा में 14–15 अप्रैल 2015 के दौरान वाणिज्य और वित्त मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की विशेष सार्क बैठक।

- नोएडा (उत्तर प्रदेश) में 5–9 अक्टूबर 2015 के दौरान स्वास्थ्य और जनसांख्यिकीय आंकड़े, एनएसएसटीए पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- नई दिल्ली में 23–24 जून 2015 के दौरान जूटए कपड़ा और चमड़ा पर क्षेत्रीय तकनीकी समिति की चौथी बैठक।
- नोएडा (उत्तर प्रदेश) में 02–06 नवम्बर 2015 से फसल प्राक्कलन एनएसएसटीए में मॉडल के उपयोग पर कार्यशाला।
- नई दिल्ली में 15–16 सितम्बर 2015 के दौरान "तृतीयक पक्ष मूल्यांकन एवं प्रत्यायन का महत्व" विषय पर सार्क देशों के विनियामकों के लिए सार्क – फिसिकलिस्क – टेक्नीक बुंदेसंस्टल्ट (पीटीबी) दो– दिवसीय सुग्राहीकरण कार्यक्रम।
- नई दिल्ली में 23–24 अप्रैल 2015 के दौरान दोहरे कराधान परिहार और कर मामलों में आपसी प्रशासनिक सहायता पर सार्क सक्षम अधिकारियों की चौथी बैठक।
- नई दिल्ली में 8 अप्रैल 2015 को सार्क स्वास्थ्य मंत्रियों की पांचवीं बैठक।
- नई दिल्ली में 7 अप्रैल 2015 को एचआईवी / एड्स पर विशेषज्ञ समूह की सातवीं बैठक।
- नई दिल्ली में 6 अप्रैल 2015 को स्वास्थ्य और जनसंख्या कार्यकलापों पर तकनीकी समिति की पांचवीं बैठक।
- नई दिल्ली में 25–26 नवम्बर 2015 के दौरान पर्यटन पर सार्क कार्यकारी समूह की 5वीं बैठक।
- नई दिल्ली में 27 नवंबरए 2015 को आपदा प्रबंधन क्षेत्र में सदस्य राज्यों के बीच आपदा जोखिम कमी–अनुभव साझा करने पर कार्यशाला।
- नई दिल्ली में 19–20 नवम्बर 2015 के दौरान सार्क आपदा प्रबंधन केंद्रए नई दिल्ली के समापन की कार्यवाही को पूरा करने के लिए समिति की बैठक।
- नई दिल्ली में 1–2 नवम्बर 2015 के दौरान सार्क सदस्य राज्यों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और डेटा प्रबंधन के परीक्षा पश्चात पहलुओं पर कार्यशाला।

उपरोक्त के अलावा, भारत ने प्रतिभागियों को आपदा का सामना करने की योजनाओं और सार्क देशों की क्षमताओं के बारे में चर्चा करने के लिए एक अवसर प्रदान करने हेतु 23–26 नवम्बर 2015 को नई दिल्ली से दक्षिण एशियाई वार्षिक आपदा प्रबंधन अभ्यास (एसएएडीएमईएक्स) का आयोजन किया। यह एक बहुराष्ट्रीय आपदा राहत संचालन और समन्वय के विविध सामरिक मुद्दों का समाधान करने के लिए लक्ष्य हेतु एक व्यावहारिकए यथार्थवादी अभ्यास था।

पड़ोस के देशों को अपने नए दृष्टिकोण के भाग के रूप में 2004 के बाद से सार्क में भारत का सक्रिय रुख संगठन को घोषणात्मक से कार्यान्वयन मोड में क्रमिक एवं अपरिहार्य परिवर्तन को सुनिश्चित करने में एक सुधारात्मक कारक रहा है, अपनी आंकलित दायित्वों से अधिक दायित्वों का विषम तथा गैर–प्रतिदेय तरीके से निर्वहन के भारत की प्रतिबद्धता की क्षेत्र के भीतर सराहना हुई है।

बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक)

अप्रैल–दिसंबर 2015 की अवधि के दौरान भारत ने बिम्सटेक के सभी सदस्य राज्यों के लिए सामान्य महत्व के विषयों अर्थात् परिवहन एवं संचारए व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकीए ऊर्जाए कृषि, जन स्वास्थ्य, आतंकवाद से निपटने और अंतरराष्ट्रीय अपराध और जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया।

समीक्षाधीन वर्ष मेंए आतंकवाद (एसजी–सीएफटी) के वित्तपोषण के विरुद्ध बिम्सटेक उप–समूह की बैठक थिम्पूए भूटान में 27–28 मई 2015 के दौरान आयोजित की गई थी। बैठक में एस जी–सी एफ टी वेबपेज के प्रकाशन के लिए फीडबैक प्राप्त करने का निर्णय लिया जिसे एक सुरक्षित माध्यमसे संबंधित सदस्य राज्यों के बीच साझा किया जाएगा। इसके अलावाए इस बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि बिम्सटेक सचिवालय द्वारा कार्यभार ग्रहण करने तक अग्रणी देश के रूप में थाईलैंड का एंटी मनी लांडरिंग कार्यालय (एएमएलओ) के साथ बिम्सटेक एसजी सीएफएम वेबपेज का प्रबंधन करेगा। बैठक के दौरान भारत ने "आतंक वित्त"य निधियों का सीमा पार प्रवाह" पर एक प्रस्तुति दी जिसमें आतंक वित्त पद्धति की स्रोतों और माध्यमों, भारत के अपने अनुभव और विशेष मामले के अध्ययन, आतंक वित्त का प्रभाव और आतंक वित्त रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की व्याख्या की गई थी। बैठक में सहमति हुई कि मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए एक अनिवार्य तत्व है। इस दृष्टि से, बिम्सटेक सचिवालय सदस्य देशों की आवश्यकताओं और प्रस्तावों के आधार पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के एक वार्षिक कैलेंडर तैयार करेगा।

पारंपरिक चिकित्सा में राष्ट्रीय समन्वय केन्द्रों का बिम्सटेक नेटवर्क स्थापित किया गया है, जिनमें थाईलैंड ने तीन बैठकों की मेजबानी की है, पिछली बैठक नॉन्थबुरी, थाईलैंड में 20–22 जुलाई 2015 को आयोजित की गई जिसमें श्पारंपरिक चिकित्सा

में राष्ट्रीय समन्वय केन्द्रों के बिम्सटेक नेटवर्कश के तहत अगले एसओएम के लिए प्रस्तुत करने के लिए एक श्पारंपरिक चिकित्सा पर बिम्सटेक टास्क फोर्सश की स्थापना के लिए विचारार्थ विषयों पर विचार–विमर्श किया गया था।

बिम्सटेक–प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा (टीटीएफ) की स्थापना पर तीसरे बिम्सटेक विशेषज्ञ समूह की बैठक 25–26 अगस्त 2015 के दौरान कोलंबो में आयोजित की गई थी। दो दिवसीय बैठक में मूल रूप से शामिल एजेंडे में कोलंबो में बिम्सटेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा की स्थापना पर संस्था ज्ञापन (एमओए) मसौदे को अंतिम रूप देना शामिल था। मसौदे में भारत और म्यांमार द्वारा कुछ संशोधन किए गये थे और बिम्सटेक के सचिवालय ने सदस्य राज्यों को संशोधित मसौदा परिचालित किया थाए ताकि भारत तथा म्यांमार द्वारा की टिप्पणियों पर उनकी सहमति प्राप्त की जाएगी।

बिम्सटेक व्यापार वार्ता समिति (टीएनसी) की 20वीं बैठक 07–09 सितम्बर 2015 से खॉन केन, थाईलैंड में आयोजित की गई थी। टीएनसी ने वस्तु व्यापार करार पर विचार–विमर्श किया। संबंधित कार्यसमूहों में निम्नलिखित पर समानांतर रूप से विचार–विमर्श किया गया थाः उत्पत्ति के नियमय सेवा व्यापारय निवेशय और कानूनी विशेषज्ञ। 20वीं टीएनसी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भारत बिम्सटेक सदस्य राज्यों के विचारार्थ सीमा शुल्क सहयोग पर प्रोतोकालका मसौदा परिचालित करेगा तथा उत्पाद विशेष नियमावली को अद्यतित करेगा क्योंकि बैठक में भारत ने सूचित किया था कि पीएसआर के तहत 147 प्रशुल्क लाइनों पर 2011 में सहमति हुई थी और व्यापार के क्षेत्र में हाल के घटनाक्रम को देखते हुए एक बार फिर से पीएसआर पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है और भारत निकट भविष्य में आयोजित होने वाले बिम्सटेक टीएनसी की अगली (21वीं) बैठक में पीएसआर पर अपने विचार प्रस्तुत करेगा।

राजदूत – स्तर पर बिम्सटेक कार्य समूह (बीडब्ल्यूजी) की 144वीं बैठक 14 सितंबर 2015 को आयोजित की गई थी जिसमें ढाका में हमारे उच्चायुक्त ने भाग लिया था और भारत ने बीडब्ल्यूजी से पहले सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर इसका अद्यतन विवरण प्रस्तुत किया था। इसी प्रकार उसके थोडे समय के बाद 145वीं बीडब्ल्यूजी 20 अक्टूबर 2015 को आयोजित की गई थीए जिसमें अद्यतन विवरण पर चर्चा की गई।

आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर बिम्सटेक अभिसमय के मसौदे को अंतिम रूप देने में प्रगति हुई और यह अगले बिम्सटेक मंत्रिस्तरीय बैठक में हस्ताक्षर के लिए तैयार है। आतंकवाद.रोध और अंतरराष्ट्रीय अपराध पर बिम्सटेक संयुक्त कार्य समूह की 7वीं बैठक 4–5 अगस्त 2015 के दौरान बैंकॉक में आयोजित की गई थीए भारत ने विधिक एवं विधिक प्रवर्तन मुद्दों के क्षेत्रमें अग्रणी के रूप में प्रतिबद्धता व्यक्त की कि वह नई दिल्ली में 17–18 दिसंबर 2015 को आयोजित विधिक एवं विधिक प्रवर्तन मुद्दों पर बिम्सटेक उप–समूह की छठी बैठक के अनुसार सजायाफ्ता व्यक्तियों के प्रत्यर्पण संबंधी अभिसमय पर विचार–विमर्श करने के लिए उप–समूह की बैठक आयोजित करेगा। तदनुसार कानूनी और कानून प्रवर्तन मुद्दों पर बिम्सटेक उप–समूह की 6वीं बैठक 17–18 दिसंबर 2015 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी जिसमें सजायाफ्ता व्यक्तियों के प्रत्यर्पण पर बिम्स्टेक अभिसमय पर विचार विमर्श किया गया था। इसके अलावाए अगले उप–समूह की बैठक 2016 में आयोजित की जाएगी।

■ ■

विकास सहयोग

13

विकास सहभागिता प्रशासन (डीपीए)

विकास सहभागिता भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह विकास सहयोग दो मुख्य स्तंभों पर आधारित है, पहला, विकास सहयोग, जिसमें साझेदारी करने के विचार से अर्थात पारस्परिक लाभ के लिए कार्य करना है और दूसरा, साझेदार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं पर आधारित विकास सहयोग है।

हाल के वर्षों में, विकास सहयोग कार्यक्रमों में भौगोलिक प्रसार और क्षेत्रीय कवरेज दोनों में, बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है। डीपीए का उद्देश्य भारत की विकास सहायता के मुख्य पहलुओं को पूरा करने में शामिल प्रक्रियाओं को सुचारू बनाना तथा उनका संवर्धन करना है, उदाहरण के लिए आईटीईसी तथा अन्य योजनाओं के तहत क्षमता विकास कार्यक्रम, ऋण और अनुदान सहायता परियोजनाएं। डीपीए मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय प्रभागों के घनिष्ठ समन्वयन से कार्य करता है, जो भारत के विकास सहायता पहल के तहत शामिल परियोजनाओं को वरीयता प्रदान करने तथा उनके चयन के लिए सहभागी देशों के साथ मुख्य वार्ताकार के रूप में कार्य करना जारी रखा।

डीपीए में तीन प्रभाग हैं। डीपीए–I वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) के अंतर्गत ऋण श्रंखला वाली परियोजनाओं की देखभाल करता है। कार्य संचालन नियमावली के तहत बांग्लादेश, नेपाल और भूटान विदेश मंत्रालय के दायरे में हैं। डीपीए–I इन देशों से संबंधित एलओसी के तौर–तरीकों से संबंधित कार्रवाई भी करता है। डीपीए–II रक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण से संबंधित कार्य करता है। और एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सहकारी और आर्थिक, सामाजिक विकास के लिए कोलम्बो योजना के भारतीय तकनीकी व आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के तहत नागरिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा, भागीदार देशों से अनुरोध पर विभिन्न विषयों में विशेष पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा यह मानवीय सहायता भी प्रदान करता है। डीपीए–III भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और अन्य एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय से सहायता कार्यक्रमों को तेजी से और कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के विचार से अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका में परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य करता है।

डीपीए विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं को संभालने के लिए आवश्यक प्रागामी विशेषज्ञता विकसित कर रहा है, जिसका उद्देश्य परियोजना मूल्यांकन, क्रियान्वयन और निगरानी के विभिन्न चरणों के माध्यम से परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करना है।

ऋण श्रृंखला (एलओसी)

हाल के वर्षों में कम विकसित और विकासशील देशों को रियायती दरों पर ऋण श्रंखला भारत की विकास सहायता के एक मुख्य उपाय के रूप में उभरा है। ऋण श्रंखला अफ्रीका, एशिया और लातिन अमेरिका में भारत की विकास सहायता नीति का एक महत्वपूर्ण घटक रहा और जिसका मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय सहायता को बढ़ावा देना है। एलओसी ने ऋण लेने वाले देशों को भारत से माल और सेवाएं आयात करने तथा अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं के अनुसार अवसंरचना विकास और क्षमता विकास के लिए परियोजनाएं लेने के योग्य बनाया है।

भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) के अन्तर्गत विभिन्न देशों को भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली ऋण श्रंखला के दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है। यह 2015–16 से 2019–20 तक लागू रहेंगे। संशोधित दिशानिर्देशों के तहत विकासशील देशों को दिए जाने वाले ऋण और अधिक आसान शर्तों पर दिए जाते हैं और ऋण–श्रंखला के कारगर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त निरिक्षण प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

इन वर्षों में 226 एलओसी में कुल 16,898,23 मिलियन अमरिकी डॉलर आबंटित किए गए हैं, जिसमें से 8,705,21 मिलियन अमरिकी डॉलर अफ्रीकी देशों के लिए आबंटित किए गए थे और 8,193.02 मिलियन अमेरिकी डॉलर गैर–अफ्रीकी देशों को स्वीकृत किए गए थे। 1 अप्रैल – 30 नवंबर, 2015 की अवधि के दौरान 2279 मिलियन अमरिकी डॉलर की राशि की एलओसी स्वीकृत की गई थी। इसमें से इस अवधि के दौरान अफ्रीका के लिए आबंटन 279 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और अन्य देशों के लिए आबंटन 2000 मिलियन अमरिकी डॉलर है। इसी अवधि के दौरान 564.99 मिलियन अमरिकी डॉलर की कुल राशि के लिए सात एलओसी करारों पर हस्ताक्षर किया गए थे।

बांग्लादेश के लिए 2010 में 1 बिलियन अमरिकी डॉलर के रियायती दरों पर ऋण प्रदान किया गया था। इसमें से 200 मिलियन अमरिकी डॉलर को 2012 में बंगलादेश सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार परियोजनाओं में उपयोग हेतु अनुदान में परिवर्तित कर दिया गया था। आपूर्ति तथा अवसंरचना परियोजनाओं सहित 15 परियोजनाओं को कवर करने हेतु शेष 800 मिलियन अमरिकी डॉलर की राशि को बढ़ाकर 862 मिलियन अमरिकी डॉलर कर दिया गया। आपूर्ति परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। रेल पुलों, नई रेल लाइनों आदि के निर्माण की अवसंरचना परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। जून 2015 में, भारत सरकार ने बिजली, रेलवे, सड़क परिवहन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जहाजरानी, स्वास्थ्य और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रों जैसे विभिन्न सामाजिक और अवसंरचना विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए बांग्लादेश को 2 बिलियन अमरिकी डॉलर के दूसरी ऋण श्रृंखला की घोषणा की। एलओसी परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी बंगलादेश सरकार और अन्य संबंधित पक्षों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से की जाती है।

नेपाल को जल विद्युत, सिंचाई और अन्य विभिन्न अवसंरचनात्मक विकास परियोजनाओं के लिए 1000 मिलियन अमरिकी डॉलर की एलओसी प्रदान की इसमें से नेपाल में भूकंप पश्चात पुनर्निर्माण कार्य के लिए 450 मिलियन अमरिकी डॉलर के एक आबंटन और 300 मिलियन अमरिकी डॉलर के एक अतिरिक्त एलओसी, सहित कुल 750 मिलियन अमरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता दी गई है। यह 2007 और 2010 में क्रमशः 100 मिलियन अमरिकी डॉलर और 250 मिलियन अमरिकी डॉलर की दो एलओसी के अलावा है। सड़क परियोजनाएं, ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं, विद्युत पारेषण और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन अमरिकी डॉलर की एलओसी का पूर्णतः उपयोग किया गया है। विद्युत पारेषण और सड़क परियोजनाओं के लिए 250 मिलियन अमरिकी डॉलर की ऋण श्रृंखला पर कार्रवाई की जा रही है और इस एलओसी के अंतर्गत 19 सड़क परियोजना के लिए 69.37 मिलियन अमरिकी डॉलर की कुल राशि अनुमोदित कर दी गई है।

निर्माणाधीन परियोजनाओं की निगरानी के तौर पर समीक्षा मिशनों के अधिकारियों ने नेपाल, बंगलादेश और म्यांमार का दौरा किया। भारतीय मिशनों और आयात–निर्यात बैंक, भारत सरकार एलओसी के ऋण बैंक से भी प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की गई।

पड़ोसी देशों में अनुदान सहायता प्राप्त विकास परियोजनाएं

पड़ोसी देशों में अनुदान सहायता से विकास परियोजनाएं

अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम मोहम्मद अशरफ गनी के साथ सहित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने काबुल में 25 दिसंबर 2015 को नए अफगान संसद भवन का उद्घाटन किया। भारत–अफगानिस्तान विकास सहयोग के तहत संसद भवन का निर्माण किया गया था।

कार्यान्वयन की जा रही हैं जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने 25 दिसम्बर 2015 को अफगानी संसद भवन परियोजना का उद्‌घाटन किया।

हेरात प्रांत में सलमा बांध के पुनर्निर्माण में काफी प्रगति हुई है। दोशी में 220/20 केवी सब–स्टेशन जुलाई 2015 में चालू किया गया है और 31 दिसंबर 2015 को चरिकर में ऐसे ही सब–स्टेशन का उद्‌घाटन किया गया है। काबुल में इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय बाल अस्पताल के लिए अधिकांश चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति और कमीशनिंग पूरी हो चुकी है और शेष उपकरण भी प्रदान कर दिए जाएंगे। काबुल में स्टॉर पैलेस का पुनरूद्धार कार्य सही तरीके से चल रहा है जो महल को अपने मूल वैभव में लाएगा।

कंधार में अफगानिस्तान राष्ट्रीय कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एएनएएसटीयू) के छात्रों को, भारत–अफगानिस्तान के विकास सहयोग की एक पहल पर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), नई दिल्ली में प्रशिक्षित किया गया और कक्षाएं भी टेली–टीचिंग माध्यम से आयोजित की जा रही है। पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों तथा प्रयोगशालाओं के लिए उपकरणों की आपूर्ति के माध्यम से एएनएसटीयू को भी सहायता दी जा रही है। अफगान अधिकारियों को खनन की विभिन्न शाखाओं में भारतीय खनन विद्यालय, धनवाद मे प्रशिक्षित करने के बाद अफगान खनन संस्थान की स्थापना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है। इसी तरह बसों की आपूर्ति और संबद्ध बुनियादी संरचना वाले डिपो और अन्य आवश्यकताओं के विकास के लिए भी डीपीआर तैयार की जा रही है।

अफगानिस्तान के साथ भारत की विकास साझेदारी का एक अन्य क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सहयोग भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) द्वारा कार्यान्वित अफगान नागरिकों के लिए सालाना 1000 विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति और 614 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के लिए छात्रवृत्ति भी शामिल है। लघु विकास परियोजना (एस डी पी) सभी प्रांतों में समुदाय आधारित परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें कृषि क्षेत्र में जोखिम भरे सीमावर्ती क्षेत्रों, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य शामिल हैं जिसका स्थानीय स्वामित्व और प्रबंधन के साथ सामुदायिक जीवन और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर सीधा प्रभाव पड़ता है और जिसे अपनाया जा रहा है।

म्यांमार में आर्थिक विकास बढ़ाने और विकास की गति तेज करने को बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने की अनेक सीमा पार परियोजनाएं आयोजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (जो भारत के पूर्वी समुद्र बोर्ड पर बंदरगाहों के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और म्यांमार में सितवे बंदरगाह, और उसके बाद मिजोरम में भारत–म्यांमार सीमा के लिए) शामिल हैंय भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच त्रिपक्षीय राजमार्ग जिसमें भारत तामू – क्याइगोन – कलेवा खंड में पुलों का निर्माण और कलेवा–यारगी खंड में 120 किलोमीटर सड़क का उन्नयन किया जा रहा है। कार्यान्वयन के तहत अन्य सड़क परियोजना में रिह–टेडिम सड़क भी शामिल है। कृषि उपज और गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा (एसीएआरई) और एक चावल जैव उद्यान के लिए एक उन्नत केंद्र नाय पी ताव में स्थापित किया जा रहा है। म्यांमार सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एमआईआईटी), मांडले में एक विश्व स्तरीय आईटी संस्थान की स्थापना की प्रगति जारी है और सॉफ्टवेयर विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीईएसडी) और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (बी टेक) पाठ्‌यक्रम 2015 में शुरू किया गया है। यांगून बाल अस्पताल और सितवे जनरल अस्पताल के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति और कमिशनिंग की जा रही है। भूमि–अभिलेख विभाग, कृषि और सिंचाई मंत्रालय, म्यांमार के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर की आपूर्ति, भाषा प्रयोगशालाओं की स्थापना और यांगून और नाय पी ताव में एक ई–संसाधन केन्द्र जैसी परियोजनाओं को इस वर्ष पूरा किया गया।

भारत और नेपाल के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए भारत–नेपाल सीमा पर समेकित चेक पोस्ट और सीमा पार रेलवे लिंक पर की निर्माण परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। काठमांडू में 200 बिस्तरों वाले आपातकालीन और ट्रॉमा सेंटर के लिए शेष चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति जारी है जिसका उद्‌घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2014 में किया गया था।

श्रीलंका के साथ भारत की विकास हिस्सेदारी परामर्शदात्री दृष्टिकोण पर आधारित है जो श्रीलंका सरकार की प्राथमिताओं पर आधारित होता है। बहु–क्षेत्रीय हिस्सेदारी में जाफना सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण और तिरूकथेश्वरम मंदिर का जीर्णोद्धार शामिल है। डिकोया में 150 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण कार्य 2014 में पूरा किया गया।

भारत एक बड़ी आवासीय परियोजना जिसमें 50,000 भवनों का निर्माण किया जाना शामिल है, के माध्यम से श्रीलंका में आतंरिक रूप से विस्थापित लोगों (आई डी पी) की पुर्नस्थापना में सहयोग कर रहा है। 17 जनवरी, 2012 को भारत और श्रीलंका सरकारों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें परियोजना के प्रति भारत की प्रतिबद्धता अभिपुष्ट की गई है। वर्ष 2012 में 1000 भवनों के निर्माण की प्रायोगिक परियोजना पूरी हुई थी। उत्तरी पूर्वी प्रान्तों में स्वामित्व–प्रेरित प्रक्रिया के अन्तर्गत 45,000 भवनों के निर्माण और मरम्मत के दूसरे चरण का कार्य इस समय जारी है। वर्ष 2013 के अन्त तक 10,250 भवनों का निर्माण कार्य हुआ। अन्य 16,000 भवनों का निर्माण कार्य वर्ष 2014 के अन्त तक पूरा हुआ और शेष कार्य चल रहा है। स्वामित्व आधारित मॉडल में उनके भवनों के निर्माण में लाभार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जाता है तथा निधियां निर्माण के चार परिभाषित चरणों में समापन से संबद्ध चार किस्तों में उनके बैंक खाते में भेजी जाती हैं। परियोजना की गति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है।

पौधारोपण क्षेत्र में नियोजित भारतीय मूल के तमिलों के लिए मध्य/उवा प्रान्तों में एजेंसी चालित मॉडल के अन्तर्गत परियोजना का तीसरा चरण अर्थात 4000 भवनों का निर्माण कार्य भी श्रीलंका सरकार द्वारा भूमि की पहचान की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात शुरू हो चुका है। 1,134 घरों के लिए भूमि का आबंटन पूरा हो चुका है और इन घरों का निर्माण स्वामित्व आधारित मॉडल के तहत किया जा रहा है। शेष 2866 घरों के निर्माण के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा इन घरों के लिए भूमि के आबंटन पर किया जाएगा।

मालदीव में विकास परियोजनाओंए अर्थात् इंदिरा गांधी स्मारक अस्पताल, सुरक्षा और कानून प्रवर्तन अध्ययन संस्थान (आईएसएलईएस), संयुक्त प्रशिक्षण संस्थान और माले में रक्षा मंत्रालय भवन के नवीनीकरण का कार्य विचार/कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

अफ्रीका में विकास परियोजना

अफ्रीका के साथ भारत की भागीदारी ने सहयोग की एक गतिशील और सामरिक भागीदारी का रूप ले लिया है जो, विकास के अनुभवों को बांटे जाने और अफ्रीकी देशों की प्राथमिकताओं और जरूरतों पर आधारित है। विकासात्मक हिस्सेदारी के माध्यम से क्षमता निर्माण में अफ्रीकी देशों के साथ संपर्क और आर्थिक विकास में योगदान में पिछले दशक में पर्याप्त वृद्धि हुई है। आईएएफएस–।। के तहत द्विपक्षीय सहयोग के भाग के रूप में मेडागास्कर और अल्जीरिया में ग्रामीण विकास (सीजीएआरडी) में भू–सूचना अनुप्रयोग पर केंद्रों की स्थापना और जिम्बाब्वे कोटे डी आइवर और मालावी में ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना कार्यान्वयन के अधीन हैं।

तीसरे भारत–अफ्रीका मंच सम्मेलन (आईएएफएस–।।।) के दौरानए अगले पांच वर्षों में विकास परियोजनाओं के लिए ऋण श्रंखला में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सहायता अनुदान की पेशकश की गई थी। इसमें 100 मिलियन डॉलर के भारत–अफ्रीका विकास कोष और 10 मिलियन डॉलर का भारत–अफ्रीका स्वास्थ्य कोष अनुदान भी शामिल है। इसमें अगले पांच वर्षों के लिए भारत में 50,000 छात्रवृत्तियां शामिल होगी और अखिल अफ्रीका ई–नेटवर्क और कौशल, प्रशिक्षण तथा अध्ययन के संस्थानों का विस्तार किया जाएगा।

अनुदान सहायता के तहत अफ्रीका के देशों के लिए महत्वपूर्ण सहायता में मलावी क लिए 34 ट्रैक्टर एवं दवाओं की दो खेप, नामीबिया में अस्पतालों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण तथा टमाटर उत्पादन तथा प्रसंस्करण संबंधी प्रायोगिक शोध परियोजना के लिए 2.088 मिलियन अमरिकी डॉलर दिया जाना शामिल है। ब्लैक लायन अस्पताल, इथियोपिया में एक सीटी स्कैन मशीन आपूर्ति की गई और इसे सफलतापूर्वक स्थापित किया गया और अस्पताल के कर्मचारियों को उपकरण का प्रशिक्षण दिया गया। और इसे सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। इसके अलावाए एंबुलेंस वाहनों की आपूर्ति के लिए सहायता अनुदान के रूप में अफ्रीका के कई अन्य देशों को राशि भी दी गई है।

अन्य विकास परियोजनाएं

भारत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में प्राचीन सांस्कृतिक विरासत स्मारकों के संरक्षण के लिए अपनी सहायता और अनुभव प्रदान कर रहा है जिनमें कंबोडिया में ता प्रोम, वियतनाम में मायसोन और लाओ पीडीआर में वाट फोउ शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता के विभिन्न केन्द्रों की स्थापना के रूप में और भागीदार देशों जैसे पेरू, पनामा, कोस्टारीका और डोमिनिका राष्ट्रमंडल को प्रशिक्षण देने के रूप में साझा किया जा रहा है। वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं जैसे ग्वाटेमाला शहर के एक प्रतिष्ठित क्षेत्र में उच्च दृश्यता सौर संचालित यातायात सिग्नल प्रणाली और आर्मेनिया में दूरदराज के अस्पतालों को जोड़ने के लिए टेलीमेडिसिन नेटवर्क को कार्यान्वित किया गया है।

तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी, एससीएएपी तथा कोलम्बो योजना के तहत तकनीकी सहयोग योजना) के माध्यम से क्षमता निर्माण

वर्ष 2015–16 में क्षमता निर्माण भारत के विकास सहभागिता कार्यक्रम का एक मुख्य घटक बना रहा। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आई टी ई सी) कार्यक्रम, अफ्रीका कार्यक्रम हेतु विशेष राष्ट्रमंडलीय सहायता (एस सी ए ए पी) तथा कोलम्बो योजना के तहत तकनीकी सहयोग योजना (टी सी ओ) तथा नए–नए क्षेत्रों में नई सहयोगी संस्थाओं और कार्यप्रणालियों को शामिल करने से उनका कार्यक्षेत्र और उनकी पहुंच निरंतर सुदृढ़ होती रही।

वर्ष 2015–16 के दौरान देश भर में फैली संस्थाओं में विभिन्न अल्पावधिक और मध्यावधि पाठ्यक्रमों हेतु 161 सहयोगी देशों (सहयोगी देशों की सूची परिशिष्ट 4 में दी है) के लिए आई टी ई सीध्एस सी ए ए पी कार्यक्रम के तहत 8360 नागरिक छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित नागरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यापिक और विविध रेंज में कार्य कर रहे व्यवसायिकों के लिए लगभग 284 पाठ्यक्रमों का आयोजन पैनल के 47 संस्थानों के साथ विभिन्न कौशल और विषयों में जैसे आईटी और दूरसंचार, वित्त एवं लेखा, लेखा परीक्षा, बैंकिंग, शिक्षा, योजना एवं प्रशासन, संसदीय कार्य, अपराध अभिलेख, वस्त्र, ग्रामीण विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, उपकरण डिजाइन, एसएमई और उद्यमिता विकास आदि किया गया। (विदेश मंत्रालय के आईटीईसी और एससीएएपी कार्यक्रमों के तहत नागरिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों की सूची **परिशिष्ट**–V पर है)।

पिछले वर्षों की भांति ही नागरिक एवं रक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में भारतीय संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों ने बड़ी संख्या में सहभागियों

को आकर्षित किया है। नया और पूर्णतः उपयोक्ता अनुकूल आईटेक वेब पोर्टल 2015–16 से ही कार्य कर रहा है जिसका उद्देश्य आइटैक/एससीएएपी सहभागियों, मिशनों/केंद्रों तथा भागीदार संस्थानों के लिए पैनल के संस्थानों एवं अनुमोदित पाठ्यक्रमों इत्यादि की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। विकास भागीदारी के क्षेत्र में आइटेक ने महत्वपूर्ण ब्रांड का दर्जा हासिल कर लिया है। वेब पोर्टल एवं अन्य सामाजिक नेटवर्किंग माध्यमों के जरिए तथा मुख्यालय, विदेश स्थित मिशनों एवं आइटेक संस्थानों द्वारा पूर्व छात्रों क नेटवर्क से बढ़ाया गया है।

एशिया और प्रशांत महासागर में सहकारी और आर्थिक सामाजिक विकास के लिए कोलम्बो योजना की तकनीकी सहयोग योजना के अंतर्गत 500 अन्य छात्रवृत्तियां भी प्रदान की गई थीं। इसके तहत प्रशिक्षण में निम्नलिखित शामिल थे–मानव संसाधन विकास लेखापरीक्षा और लेखे, वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी, टेक्सटाइल, वित्तीय प्रबंधन, बीमा इत्यादि। भारत की प्रमुख प्रशिक्षण संस्थाओं अर्थात एनएडीटी नागपुर, एल बी एस एन ए ए–मसूरी, आई जी एन एफ ए–देहरादून, एन ए ए ए–शिमला और एन ए सी ई एन, फरीदाबाद में इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष भूटान के दस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारत–भूटान की रॉयल यूनिवर्सिटी से संबद्ध विभिन्न महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं को प्रतिनियुक्ति पर भेजता रहा है तथा मनीला स्थित कोलम्बो प्लान स्टाफ कॉलेज रक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम (सी पी एस सी) में समर्थन हेतु भारतीय शिक्षक प्रदान करता रहा है। वर्ष 2015–16 की अवधि के लिए कोलंबो योजना परिषदए श्रीलंका को 17,400 अमेरिकी डॉलर का सहायता अनुदान दिया गया है।

रक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम

2015–16 के दौरान, सहभागी देशों को 2058 रक्षा प्रशिक्षण स्लॉट आबंटित किए गए थे। ये पाठ्यक्रम सामान्य एवं विशिष्ट, दोनों स्वरूप के थे जिनमें सुरक्षा एवं सामरिक अध्ययन, रक्षा प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग, समुद्री जलविज्ञान, काउंटर इन्सर्ज़ेंसी और वन युद्धकला तथा साथ ही तीनों सेवाओ के युवा अधिकारियों के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम भी शामिल थे। नेशनल डिफेंस कॉलेज, (एन डी सी) नई दिल्ली तथा डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, (डी एस एस सी) वेलिंगटन जैसे अग्रणी संस्थानों में चलाए गए पाठ्यक्रम बहुत लोकप्रिय हुए और इसने स्व वित्तपोषण आधार पर विकसित देशों के अधिकारियों को आकर्षित किया।

विशेष पाठ्यक्रम

नियमित पाठ्यक्रमों के अलावाए आईटीईसी / एससीएएपी भागीदार देशों की कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित विशेष पाठ्यक्रमों को नीचे वर्णित क्षेत्रों में आयोजित / अनुसूचित किया गया हैः

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर)ए चेन्नई में 80 बांग्लादेशी शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम।

- राष्ट्रीय अभिशासन केंद्र मसूरी में बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र, मसूरी में बांग्लादेश के उप आयुक्तों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली और लेखा परीक्षा केंद्र (आईसीआईएसए), नोएडा में भूटान के लेखा परीक्षा अधिकारियों के लिए विशेष पाठ्यक्रम।
- नेशनल एकेडमी ऑफ सेंट्रल एक्साइस एंड नारको. टिक्स (एनएसीईएन), फरीदाबाद में मंगोल सीमा शुल्क अधिकारियों के लिए विशेष पाठ्यक्रम।
- अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (ईएफएलयू), हैद. राबाद में कोलंबिया के शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।
- लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधनए नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में चुनाव प्रबंधन पर विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।
- नैनो साइंस और इंजीनियरिंग (सीईएनएसई)ए आईआईएससीए बैंगलोर के लिए केंद्र में नैनो निर्माण प्रौद्योगिकियों पर विशेष प्रशिक्षण।
- राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर)ए चंडीगढ़ में अंग्रेजी भाषा (मूलभूत और मध्यवर्ती स्तर) में मंगोलियाई शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम।

विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति

आई टी ई सी कार्यक्रम के तहत विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति विकासशील देशों के साथ भारतीय सुविज्ञता के आदान–प्रदान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय साबित हुआ है। 2015–16 के दौरान फोरेंसिक साइंस आयुर्वेद, चावल उत्पादन के क्षेत्र में तथा सरकारों के सलाहकारों तथा राज्य के परामर्शकों के रूप में सहभागी देशों में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 37 विशेषज्ञों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया। रक्षा प्रशिक्षण दलों को भी सहभागी देशों में प्रतिनियुक्त किया गया।

आपदा राहत

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित देशों को भारत सरकार द्वारा मानवीय आधार पर सहायता प्रदान की गई। सीरिया, फिलीपीन्स, जॉर्डन और लेबनोन के लिए नकद सहायता दी गई थी। इसके अतिरिक्त यमन के लिए दवाओं की आपूर्ति की गई और नेपाली सेना के लिए एरियल रोपवे की आपूर्ति की गई।

■ ■

14 निवेश तथा प्रौद्योगिकी संवर्धन

देश की विदेश नीति के आर्थिक कूटनीति आयाम को उपयुक्त दिशा देने के प्रयासों के भाग के रूप में निवेश और प्रौद्योगिकी संवर्धन (आईटीपी) प्रभाग द्वारा वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान अनेक पहलें की गईं। हमारा प्रयास विदेश मंत्रालय, केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, वाणिज्यिक संघों तथा विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना था, ताकि भारत के निर्यातों की पहुंच बढ़ायी जाए, विदेश में भारतीय उद्यमों के लिए नये अवसर सृजित किए जाए, निकटस्थ पड़ोस के साथ भारत के कार्यकलापों को बढ़ाया जाए, अधिक निवेश आकर्षित किया जाए, पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए तथा भारत को एक आकर्षक वाणिज्यिक गंतव्य बनाया जा सके।

भारतीय मिशनों/केंद्र, व्यापार संघों और थिंक टैंक संस्थानों, और राज्य औद्योगिक विकास निगमों, भारतीय व्यावसायिक घरानों और भारत में विदेशी राजनयिक मिशनों के साथ घनिष्ठ संपर्क करके आईटीपी प्रभाग ने सरकार के विकास के एजेंडे को अग्रेषित किया और सुनिश्चित किया कि देश के लिए सर्वोत्तम संभव आर्थिक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए सरकार के सुधार संबंधी एजेंडे तथा देश की विदेश नीति की सतत तथा समन्वित तरीके से जानकारी दी जाए।

आईटीपी प्रभाग की पहुंच और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए प्रभाग को एक मैट्रिक्स संरचना के रूप में पुनर्गठित किया गया है। विदेशी निवेशकों और भारतीय हितधारकों के बीच बातचीत की सुविधा के लिए एकल बिंदु संपर्क (एसपीओसी) बनाया गया है। सुविधा के लिए एसपीओसी को देश, भारतीय राज्य और स्वतंत्र क्षेत्र सौंपे गए हैं। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विदेशी निवेशकों और सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय के मुद्दों पर मैट्रिक्स संरचना पहले से ही प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।

अपने प्रत्यापन के देशों के साथ आर्थिक कार्यकलाप गहन करने में 187 मिशनों/केंद्रों को सक्षम बनाने के लिए आईटीपी प्रभाग ने अपनी "बाजार विस्तार गतिविधियां" बजट के तहत लगभग 4.5 करोड़ रुपए का वित्तपोषण किया है। इस कोष का उपयोग कैटालॉग प्रदर्शनी तथा क्रेता/विक्रेता मिलन आयोजित करने, बाजार अध्ययन हेतु परामर्शों की सहायता लेने, विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने वाले भारतीय उद्यमों के हितों को बढ़ावा देने के लिए समर्थन कार्य करने में किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभाग ने भारतीय मिशनों / केंद्रों की विशिष्ट व्यापार और निवेश संवर्धन गतिविधियों के साथ–साथ ही भारत में सर्वोच्च व्यावसायिक परिसंघों की अन्य आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए लगभग 1.65 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को आगे बढ़ाया है।

वित्तीय सेवा

वित्तीय मोर्चे पर आईटीपी प्रभाग ने वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की अंतर्विभागीय समिति (आईसीसी) में अपनी सदस्यता के माध्यम से लीबिया जैसे चुनौतीपूर्ण देशों में भारतीय उद्यमों द्वारा चलायी जा रही परियोजनाओं के लिए दी गई बैंक गारंटी का सम्मान करने, नीदरलैंड के एबीएन एमरो बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी खोलने और भारत में जे पी मार्गन चेज बैंक की तीन अतिरिक्त शाखाएं खोलने के संबंध में निर्णय लेने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आईटीपी प्रभाग ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के 342 मामलों पर कार्रवाई की (दिसंबर, 2015 तक) और उनमें से 238 मामलों का अनुमोदन जारी किया, जबकि शेष को विशिष्ट टिप्पणियों/प्रश्नों के साथ वापस कर दिया। आईटीपी और आर्थिक कार्य विभाग पेंशन तथा संप्रभु धन कोष से बेहतर निवेश आकर्षित करने संबंधी प्रयासों का भी समन्वय कर रहे हैं।

निवेश सुविधा

निवेश के मोर्चे पर, बोर्ड ऑफ इनवेस्ट इंडिया में अपनी सदस्यता के माध्यम से आईटीपी प्रभाग औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के साथ अपनी गतिविधियों का नजदीकी से समन्वय करता है। 25 सितंबर, 2014 को "मेक इन इंडिया" पहल की वैश्विक शुरूआत को भारतीय मिशनों/ केंद्रों के माध्यम से आईटीपी प्रभाग द्वारा सहायता की गई। आईटीपी प्रभाग भारत में आए निवेशकों को प्रत्यक्ष सेवाएं भी प्रदान कर रहा है तथा केंद्र एवं राज्यों में मंत्रालयों के साथ उनके कार्यकलाप को सुविधाजनक बनाता है। कनाडा (पावर, पेंशन फंडए बांड बाजार), चीन (रियल एस्टेट, सौर, दूरसंचार, बिजली, संसाधन), जर्मनी (विनिर्माण – इलेक्ट्रिकल),

कोरिया (शहरी विकास, रेलवे, विमानन), ताइवान (विनिर्माण – इलेक्ट्रॉनिक्स), जापान (मूल संरचना), रूस (टेलीकॉम, बैंकिंग, स्मार्ट सिटी) और संयुक्त राज्य अमेरिका (बैंकिंगए कृषि, जैव प्रौद्योगिकी) से 50 से अधिक विदेशी निवेश के प्रतिनिधिमंडलों को अप्रैल 2015 से जनवरी 2016 तक की अवधि के दौरान सहायता दी गई है। आईटीपी प्रभाग द्वारा की गई प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई के फलस्वरूप जियोमी ने आंध्र प्रदेश में एक मोबाइल फोन निर्माण संयंत्र में निवेश किया; हरियाणा के औद्योगिक नगर में 10 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता वांडा समूह से ली तथा अनेक परियोजनाओं को आगे बढ़ाया। आईटीपी प्रभाग ने दिल्ली में राजनयिक समुदाय के लिए "समुद्री भारत सम्मेलन– 2016" हेतु एक कर्टन रेज़र आयोजन में जहाजरानी मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य किया। आईटीपी प्रभाग 13 से 18 फरवरी 2015 को मुंबई में "मेक इन इंडिया वीक" के आयोजन में डीआईपीपी के साथ निकटता से कार्य किया। आईटीपी प्रभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, कॉनकॉर, और बीईएल में संभावित विनिवेश के उद्देश्य से कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में रोड शो का आयोजन करने में विनिवेश विभाग के साथ कार्य किया।

आर्थिक और व्यापार संवर्धन

आर्थिक और व्यापार संवर्धन मोर्चे पर वाणिज्य और उद्योग विभाग के साथ आईटीपी प्रभाग ने दक्षिण अमेरिका और कैरेबियाई देशों में भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई कार्यनीति पर कार्य किया। आईटीपी प्रभाग वाणिज्य मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ भुगतान तंत्र की संभावना का पता लगा रहा जिससे वेनेजुएला को निर्यात करने वाले भारतीय निर्यातक कच्चे तेल की खरीद कर के अपना भुगतान प्राप्त कर सकेंगे। बढ़ते अधिशेष के एक परिणाम के रूप में घरेलू चीनी की कीमतों में कमी की भरपाई के लिए, आईटीपी प्रभाग कृषि और सार्वजनिक वितरण विभाग और विदेश में भारतीय मिशनों / केंद्रों के साथ घनिष्ठ समन्वय के माध्यम से चीनी निर्यात के लिए नए बाजारों की पहचान करने में सफल रहा। यह प्रभाग वाणिज्य विभाग के साथ देश में दालों के आयात के लिए बाजारों की पहचान करने की दिशा में कार्य कर रहा है। राजस्व विभाग, आर्थिक कार्य विभाग और वाणिज्य विभाग के साथ आईटीपी प्रभाग को पिछले कई वर्षों में भारत द्वारा संपन्न सभी मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा गठित कार्य समूह के एक सदस्य के रूप में तैयार किया गया है। प्रभाग द्वारा लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध को तोड़ने और दोनों पक्षों के लिए लाभकारी परिणाम सुनिश्चित करके विदेशी संस्थाओं और भारतीय कारोबार के बीच व्यापार विवादों को हल करने के लिए सक्रिय हस्तक्षेप किया गया है। आईटीपी प्रभाग द्वारा समय से हस्तक्षेप किये जाने के कारण मैक्सिको के सिनेपोलिस ने केरल में मल्टीप्लेक्स का प्रचालन आरंभ करने संबंधी लंबित अनुमोदन प्राप्त कर लिया और भारतीय सीमा–शुल्क के साथ घनिष्ठ समन्वय करके हेरात स्थित हमारे केंद्र को अफगानिस्तान द्वारा भारत में केसर निर्यात करने संबंधी मामले का समाधान करने में मदद की।

बहुपक्षीय – वित्त

बहुपक्षीय मोर्चे परए आर्थिक कार्य विभाग के साथ आईटीपी प्रभाग को एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) की स्थापना के लिए वार्ता में शामिल किया गया था। बीजिंग में 29 जून 2015 को आयोजित एक विशेष मंत्रिस्तरीय बैठक (एसएमएम) में भावी संस्थापक सदस्य (पीएफएम) देशों में से प्रत्येक के प्रतिनिधियों ने इसपर हस्ताक्षर किए और समझौते के अनुच्छेद जमा किए। एआईआईबी के मुख्य वार्ताकारों की बैठकों के 8 दौरों के पश्चात श्री जिन लिक्यून को एआईआईबी, जिसका मुख्यालय बीजिंग में होगा, के नामित राष्ट्रपति के रूप में चयनित किया गया है। एआईआईबी की संस्था के अंतर्नियमों को नवंबर 2015 में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद अनुसमर्थन दस्तावेज 15 जनवरी 2016 को एआईआईबी सचिवालय के पास जमा किये गये थे। एआईआईबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पहली बैठक 16 जनवरी 2016 को बीजिंग में की गई। भारत एआईआईबी के निदेशक मंडल के लिए चुना गया है। एआईआईबी के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में भारत की 8.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सदस्यता मूल्य पर कुल 83,673 शेयरों की सदस्यता होगी। भारत बैंक में वाइस प्रेसिडेंट पद के कई पदों के लिए उम्मीदवारों को नामांकित करने की प्रक्रिया में है।

उद्योग आउटरीच

उद्योग के मोर्चे पर, आईटीपी प्रभाग द्वारा निम्नलिखित समारोह का वित्त पोषण और सह आयोजन किया :

- 07–09 मई 2015 : नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला संघ के साथ "भारत–अफ्रीकी महिला उद्यमिता" सम्मेलन
- 1 मई 2015 : नई दिल्ली में "भारतः भावी विश्व स्वास्थ्य रक्षा केंद्र" पर सम्मेलन
- 23–24 सितम्बर 2015 : नई दिल्ली में "ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया फोरम (जीआईआईएफ)" सम्मेलनय
- 05–06 अक्तूबर, 2016 : बेंगलुरू में फिक्की के साथ "सेकेंड इंडिया – सेंट्रल यूरोप बिजनेस फोरम (आईसीईबीएफ)";
- 20 नवंबर, 2015 : नई दिल्ली में एसोचैम के साथ "अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सम्मेलन";
- 23–24 नवंबर 2015 : कोलकाता में सेंटर फॉर स्टडीज इन

इंटरनेशनल रिलेशन्स एंड डेवलपमेंट (सीएसआईआरडी) के साथ "11वीं कोलकाता–2–कुनमिंग फोरम"

- 27–29 नवंबर 2015ः भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (आईएएफएस– III) की तर्ज पर, आईटीपी प्रभाग द्वारा 27 नवंबरए 2015 को एक्जिम बैंक के साथ "फोकस अफ्रीका" संगोष्ठी, 27–29 नवंबर 2015 से "व्यापार प्रदर्शनी" और 28 नवंबर 2015 को सीआईआई, फिक्की, एसोचैम और पीएचडीसीसीआई के साथ "इंडिया अफ्रीका बिजनेस फोरम" समन्वित की गई।
- 16 दिसंबर 2015ः नई दिल्ली में – ''स्टार्ट अप इंडिया 2015''।
- 9–10 फरवरी, 2016ः नई दिल्ली में ''8वां वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन''।

नागरिक उड्डयन

नागरिक उड्डयन के मोर्चे परए आईटीपी प्रभाग ने द्विपक्षीय हवाई सेवा वार्ता पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य किया। हवाई सेवा करारों पर (एएसए) मंगोलिया (17 मई 2015), न्यूजीलैंड (26 मई 2015), सेशल्स (26 अगस्त 2015), जर्मनी (5 अक्टूबर 2015), बारबाडोस (6 अक्टूबर 2015), और कोरिया गणराज्य (15 अक्टूबर 2015) के साथ हस्ताक्षर किए गए। कई असफल प्रयासों के बाद कोरिया गणराज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाना आर्थिक संबंधों और लोगों से लोगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की दोनों पक्षों की इच्छा को दर्शाता है। दोनों देशों के लिए क्षमता पात्रता प्रति सप्ताह मौजूदा छह सेवाओं से बढ़ा कर प्रति सप्ताह 19 सेवाओं की कर दी गई है। दक्षिण कोरियाई विमान अतिरिक्त केंद्रों के रूप में बेंगलुरु और चेन्नई के लिए उड़ान भर सकते हैंए जबकि भारतीय विमान दक्षिण कोरिया के माध्यम से टोक्यो और लॉस एंजिल्स के अलावा वैंकूवर और सिएटल के लिए उड़ान भरने में सक्षम होंगे। तुर्की में 19–21 अक्टूबर 2015 को अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन वार्ता (आईसीएएन) में संपन्न समझौता ज्ञापनों पर आठ देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए – फिनलैंड, कजाखस्तान, केन्या, स्वीडन, नार्वे, डेनमार्क, ओमान और इथियोपियाय सर्बिया, ग्रीस,यूरोपीय आयोग के साथ क्रमशः "कार्यवृत्त पर सहमत" हुएय और ब्रुनेई दारुस्सलाम, और कतर के साथ "चर्चाओं का रिकार्ड" पर सहमति बनी।

व्यवसाय करने की सरलता

व्यवसाय करने में सरलता लाने के मोर्चे परए आईटीपी प्रभाग द्वारा भारत के शीर्ष निवेश राष्ट्रों – यूएसए, सिंगापुर, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, चीन, दक्षिण कोरिया, और नीदरलैंड के बीच व्यापक सर्वेक्षण किया गया है। सूचनाएं यूएसआईबीसी, एएमसीएचएएम, केओटीआरए, केएआईडीएएनआरईएन, जेट्रो, फिनप्रो और नई दिल्ली में स्थित विदेशी दूतावासों / उच्चायोगों के आर्थिक एवं वाणिज्यिक अधिकारियों सहित विदेशी व्यापार मंडलों द्वारा भेजा गए साक्षात्कार, प्रस्तुतियों और लिखित प्रस्तुतियाँ के माध्यम से प्राप्त हुई थी। वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों / विभागों द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए सर्वेक्षण के निष्कर्षों को एकत्र किया जा रहा है। आर्थिक कार्य विभाग के साथ गहन परामर्श मेंए शाखा कार्यालय (बीओ) / संपर्क कार्यालयों (एलओ) / परियोजना कार्यालय (पीओ) की स्थापना के लिए आवेदन पत्र और जारी करने संबंधी मंजूरी पर कार्रवाई को कारगर बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए। दिसंबर 2015 तकए आईटीपी प्रभाग द्वारा कुल 31 बीओ / एलओ / पीओ मामलों पर कार्रवाई की गई और मंजूरी दी गई। पर्यटन मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ घनिष्ठ समन्वय करके आईटीपी प्रभाग ने चीनी फिल्म निर्माण दल "लॉस्ट इन इंडिया" और "डे टांग क्यूंजांग" के लिए समय से अनुमोदन प्राप्त कर लिया।

भारतीय मिशनों के लिए ज्ञान का समर्थन

आईटीपी प्रभाग ने भारतीय मिशनों / पोस्ट के लिए ज्ञान का समर्थन प्रदान करने के प्रयासों के भाग के रूप में दुनिया भर में भारत सरकार के सभी फ्लैगशिप कार्यक्रमों की जानकारी पहुंचाने के लिए सभी प्रस्तुतियां और रिपोर्टें तैयार की हैं। प्रभाग विदेश स्थित भारतीय मिशनों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रेषण के लिए जारी करता है और साप्ताहिक और मासिक आर्थिक न्यूज़लेटर प्रदान करके भारतीय मिशन / पोस्ट की आउटरीच गतिविधियों का समर्थन करता है। आईटीपी भारत व्यापार से संबंधित जानकारी के एकल स्रोत के रूप में हमारे मिशनों / केंद्रों की बेहतर सहायता के लिए अपनी वेबसाइट indiainbusiness.nic.in में सुधार करने की प्रक्रिया में है। प्रभाग भारत में व्यापार वातावरण का सर्वेक्षण किए जाने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंसल्टेंसी फर्मों की सहायता से कार्य करता है। नवंबर 2015 में, डीआईपीपी के साथ आईटीपी प्रभाग ने इंडिया अट्रेक्टिवनेस सर्वेक्षण 2015 लाने के लिए अर्न्स्ट एंड यंग के साथ कार्य किया जिसमें निवेश गंतव्य के रूप में दुनिया में नंबर 1 स्थान भारत का रहा। प्रकाशन के बाद से न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, शंघाई, और टोक्यो में भारतीय वाणिज्य दूतावास के सहयोग से रोड शो चलाये गये हैं।

■ ■

ऊर्जा सुरक्षा

15

ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग की स्थापना विदेश मंत्रालय में वर्ष 2009 में की गई थी और यह भारत की ऊर्जा कूटनीति का समन्वय करता है तथा विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मंचों में सरकार की अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संबंधी कार्यों के लिए नोडल बिन्दु के रूप में कार्य करता है। यह राजनयिक कदमों के माध्यम से सरकार के ऊर्जा और संसाधन मंत्रालयों (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, कोयला और खान), की अंतरराष्ट्रीय कार्रवाइयों का समर्थन करता है। यह ऊर्जा से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे कि अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए), ऊर्जा सक्षमता और सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय भागीदारी (आईपीईईसी), अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच (आईईएफ), अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए), स्वच्छ ऊर्जा मंत्रालय (सीईएम) इत्यादि तथा जी–20, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, आईबीएसए इत्यादि में ऊर्जा से संबंधित मामलों पर भारत के संपर्क का कार्य करता है। यह परिकल्पना की जाती है कि यह कृषि एवं उर्वरक जैसे मंत्रालयों के समन्वय से खाद्य सुरक्षा के मामलों का संचालन करेगा।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संगठनों के साथ बैठकों में भागीदारी

ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग ने निम्नलिखित बैठकों / सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी के साथ कार्य किया :

- हनोवर मेसी मेला 2015 का आयोजन 14–16 अप्रैल 2015 के दौरान किया गया था। इस मेले में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक निवेश गंतव्य के रूप में भारत को प्रदर्शित किया गया।
- विद्युत, कोयला तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने 19–20 मई 2015 के दौरान न्यूयॉर्क में आयोजित सभी मंचों के लिए दूसरे संयुक्त राष्ट्र सतत ऊर्जा के सलाहकार बोर्ड की बैठक में भाग लिया।
- मेरिडा, मेक्सिको में 24–26 मई 2015 के दौरान इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिसिएंसी कॉर्पोरेशन (आईपीईईसी) की 11वीं नीति समिति (पीओसीओ) की बैठक आयोजित की गई। विभिन्न कार्य समूहों द्वारा की गई बैठक में जी–20 ऊर्जा क्षमता कार्य योजना और आईपीईईसी गतिविधियों को मजबूत बनाया गया और इसके प्रभाव की समीक्षा की गई। इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिसिएंसी कॉर्पोरेशन (आईपीईईसी) की 13वीं कार्यकारिणी समिति (एक्स्को) बैठक 16–18 सितम्बर 2015 के दौरान पेरिस में आयोजित की गई थी। जी 20 ऊर्जा दक्षता कार्य योजना और अन्य कार्य समूह प्रस्तुतियों पर एक्स्को–13 ने विचार–विमर्श किया।
- 2015 के दौरान तुर्की की अध्यक्षता में जी 20 ऊर्जा स्थिरता कार्य समूह की बैठक तुर्की में आयोजित की गई। बैठकों में ऊर्जा तक पहुंच, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, बाजार में पारदर्शिता और अक्षम जीवाश्म ईंधन सब्सिडी के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- मेरिडा, मेक्सिको में 26–28 मई 2015 के दौरान छठी स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इसमें उन्नत शुभारंभ के लिए सहमति हो गई थी, सीईएम के तहत कार्य के दूसरे चरण में "सीईएम 2.0." के रूप में संदर्भित मंत्रियों द्वारा एक नई सीईएम संचालन समिति बनाई गई जो सबसे बड़े संभावित प्रभाव के क्षेत्रों में प्रयासों को प्राथमिकता देने के लिए पूरे वर्ष नेतृत्व और सामरिक मार्गदर्शन के दौर प्रदान करेगा। भारत संचालन समिति के संस्थापक सदस्यों में से एक है।
- छठी ओपेक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी 3–4 जून 2015 के दौरान वियनाए आस्ट्रिया में आयोजित की गई। इस बैठक के के दौरान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस ने महा सचिवए ओपेक तथा अपने समकक्षों के साथ तेल एवं गैस क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा करने के लिए अलग से द्विपक्षीय बैठकें की। ओपेक के साथ उच्च स्तरीय वार्ता आरंभ करने का निर्णय लिया गया।
- क्रमशः 10–11 जून 2015 और 23–24 नवम्बर 2015 के दौरान अबू धाबी में अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए) की परिषद की 9वीं और 10वीं बैठक आयोजित की गई।
- उप–सहारा अफ्रीका में ऊर्जा उपलब्धता पर जी 20 के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक और सम्मेलन इस्तांबुल, तुर्की में 1–2 अक्टूबर 2015 को आयोजित किया गया। बैठक में समावेशी

ऊर्जा सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया और जी 20 ऊर्जा के सिद्धांतों पर सहमति व्यक्त की गई।

- आईईए मंत्रिस्तरीय बैठक 17–18 नवम्बर 2015 के दौरान पेरिस में आयोजित की गई।
- 15–19 जनवरी 2016 के दौरान अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी महासभा के छठे सत्र का आयोजन किया गया। ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल में भाग लिया।
- चीन में 28 जनवरी 2016 को चीन की अध्यक्षता में जी 20 ऊर्जा स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई।

द्विपक्षीय ऊर्जा बैठकें

- माननीय राज्य मंत्री (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस) के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने हाइड्रोकार्बन और कोयले के क्षेत्र में और अधिक सहयोग पर चर्चा के लिए 09–10 अप्रैल 2015 के दौरान मापुटो, मोजाम्बिक दौरा किया।
- एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने तेल एवं गैस क्षेत्र में व्यापार और निवेश से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर ईरान के साथ द्विपक्षीय विचार विमर्श के लिए 18–19 अप्रैल 2015 और 28 जुलाई 2015 के दौरान तेहरानए ईरान का दौरा किया।
- चौथा अंतरराष्ट्रीय एलएनजी निर्माता–उपभोक्ता सम्मेलन 16 सितंबर 2015 को टोक्यो में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में एलएनजी उत्पादन और खपत से संबंधित मौजूदा चुनौतियों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया गया।
- भारत – जापान ऊर्जा वार्ता 11–14 जनवरी 2016 के दौरान टोक्यो में आयोजित की गई। माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विद्युत, कोयला और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया गया था।

तापी गैस पाइपलाइन परियोजना

- परियोजना की संचालन समिति की 22वीं बैठक (एससीएम) 6 अगस्त 2015 को अश्गाबातए तुर्कमेनिस्तान में आयोजित की गई थी। माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)ए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस द्वारा भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया गया था।
- परियोजना की संचालन समिति की 23वीं बैठक (एससीएम) और तकनीकी कार्य समूह (टीडब्ल्यूजी) की 30वीं बैठक 23–24 अक्टूबर 2015 के दौरान अश्गाबातए तुर्कमेनिस्तान में आयोजित की गई। बैठक की मुख्य विशेषताओं में पक्षकारों द्वारा तापी लि. में शेयरों की संगत प्रतिशतता की घोषणा करना तथा इस परियोजना के लिए शेयरधारकों के करार शामिल हैं।

इंटरनेशनल सौर एलायंस (आईएसए)

सीओपी 21 के अतिरिक्त समय में 121 सौर संसाधन समृद्ध देशों के बीच आपसी सहयोग के लिए एक मंच, इंटरनेशनल सौर एलायंस (आईएसए)ए का शुभारंभ भारत के माननीय प्रधानमंत्री और फ्रांस के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था। इस शुभारंभ समारोह में 31 राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों और 35 अन्य उच्च स्तर के गणमान्य व्यक्तियोंए संयुक्त राष्ट्र महासचिव और उद्योगए गैर सरकारी संगठनों और मीडिया के 600 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने इस गठबंधन की सफल शुरुआत करने में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) का दृढ़ता से समर्थन किया। भावी सदस्य देशों और कोर ग्रुप के सदस्यों के आवासीय राजनयिक मिशनों के प्रतिनिधियों के साथ आवश्यक सहायता के बारे में सूचना साझा सत्रों के आयोजन में एमएनआरई को आवश्यक सहयोग दिया गया थाय 100 से अधिक देशों में स्थित हमारे मिशनों के माध्यम से तीव्रता से अनुवर्ती कार्रवाई करने; आईएसए में शामिल होने की पुष्टि करने के लिए और आईएसए शुभारंभ समारोह आयोजित करने के साथ ही 1 दिसंबरए 2015 को आईएसए की अंतरराष्ट्रीय संचालन समिति की उद्घाटन बैठक के आयोजन की पुष्टि की गई । विदेश मंत्रालय इस पहलकदमी से संबंधित कार्य में योगदान देता रहेगा।

इंटरनेशनल सौर एलायंस (आईएससी) के अंतरराष्ट्रीय संचालन समिति (आईएसए) की दूसरी बैठक 18 जनवरी 2016 को अबु धाबीए संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की गई।

अन्य बैठकें

- ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग द्वारा "अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता" विषय पर 15 जुलाई 2015 को अनौपचारिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों सहित ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् एनटीपीसीए पीजीसीआईएलए ईईएसएल ने भाग लिया। इस समूह ने इन क्षेत्रों और संबंधित अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति और प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर चर्चा की।
- वेनेजुएला और कोलंबिया में स्थित तेल क्षेत्र निवेश में आपातकालीन बचाव योजना की बैठक 16 जून 2015 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयए नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक के दौरान संपत्ति तथा कार्मिक दोनों के मामले में इन देशों में ओएनजीसी को पेश आ रही विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा की गई।

राज्य प्रभाग

16

माननीय प्रधानमंत्री के नीतिपरक दृष्टिकोण के तहत, भारत के विकास के लिए नियंत्रक के तौर पर राज्यों की भूमिका को मूर्ति रूप देने के लिए अक्टूबर 2014 में विदेश मंत्रालय में राज्य प्रभाग बनाया गया है। यह सहयोगी संघवाद के सिद्धांत को बढ़ावा देता है और इसका लक्ष्य राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के बाह्य संबंधों को और गहरा बनाना है। सहयोग के क्षेत्रों का व्यापक विस्तार है तथा इसमें आर्थिक सहयोग, शैक्षणिक संबंधों, निवेश, पर्यटन, तकनीकी का हस्तांतरण, निर्यात, संस्कृति, लोगों का लोगों से संपर्क और समुदाय द्वारा नियंत्रित मुद्दें शामिल हैं। यह प्रभाग विदेश मंत्रालय तथा विदेश स्थित हमारे दूतावासों तथा कौंसुलावासों के साथ राज्यों की सुविधा, केंद्र बिंदु तथा परिचय हेतु नई संस्थागत अवसंरचना को विकसित करने की प्रक्रिया में है। मई, 2015 में माननीय प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान भारत चीन राज्य/ प्रांतीय नेतृत्व मंच का शुभारंभ इस प्रभाग की मुख्य उपलब्धियों में से एक रही। आवासीय राजनयिकों को राज्य सरकारों के साथ परिचित करवाने तथा राज्यों से वरिष्ठ भारतीय राजनयिकों के अभिगम के लिए शुरू की गई "मीट द स्टेट्स" जैसी नई पहलों ने परस्पर प्रक्रिया को सुदृढ़ किया है। इस प्रभाग ने संकट के दौरान भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के लिए आपरेशन राहत के माध्यम से यमन से लोगों को निकालने के लिए तथा आपरेशन मैत्री के माध्यम से नेपाल भूकंप के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों तथा विदेश स्थित मिशनों के साथ सफलतापूर्वक समन्वय किया है।

राज्य प्रभाग सभी भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों द्वारा "राज्य विशेषज्ञता" की नई पहल के लिए नोडल विभाग है। इस पहल के तहत अधिकारियों को दो राज्यों में विशेषज्ञता हासिल करनी होती है। भारत के राज्यों तथा भारतीय राजनय के बाह्य अभिगम के बीच इंटरफेस होने के कारण, राज्य प्रभाग विकास के लिए राजनय के प्रतिमान को प्रोत्साहन देता है।

वर्ष 2015 में राज्य प्रभाग से संबंधित गतिविधियां निम्नानुसार हैं :

1. सिस्टर सिटी और सिस्टर प्रांत करार

क. 15 मई 2015 को माननीय प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान, राज्य प्रभाग ने **कर्नाटक–सिचुआन** के बीच सिस्टर राज्य करार को अंतिम रूप दिया और हस्ताक्षर किए जाने का समन्वय किया तथा तीन सिस्टर सिटी करारों पर हस्ताक्षर किए जाने का भी समन्वय किया है, जो नामतः इस प्रकार हैं–

- **चेन्नई – चोंगकिंग**
- **हैदराबाद – किंगदाओ,**
- **औरंगाबाद–दुन्हुयांग**

ख. माननीय प्रधानमंत्री की 2015 के दौरान क्योटो, जापान की यात्रा के दौरान, राज्य प्रभाग ने **क्योटो–वाराणसी भ. ागीदार शहर** करार पर हस्ताक्षर करने में सहायता प्रदान की। क्योटो के मेयर श्री दैसाकु काडोकावा और जापान में भारत की राजदूत श्रीमती दीपा गोपालन वाधवा दोनों देशों के नेताओं की उपस्थिति में करार पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य "जापानी विशेषज्ञता और तकनीकी आहरण" के द्वारा जल प्रबंधन, सीवेज प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन तथा शहरी परिवहन के क्षेत्र में सहयोग का संवर्धन करना है।

ग. **वाराणसी को एक स्मार्ट विरासत शहर के रूप में विकसित** करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के विभागों और वाराणसी के शहर अधिकारियों के बीच 7–9 जुलाई 2015 और 16–17 नवम्बर 2015 के बीच वाराणसी में आयोजित परामर्शदात्री बैठकों में राज्य प्रभाग ने विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया।

2. राज्य और प्रांतीय नेता मंच

15 मई 2015 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान, राज्य प्रभाग ने ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल, **बीजिंग में चीन के साथ भारत के पहले राज्य / प्रांतीय नेता,** मंच की सफल शुरूआत के समन्वय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मंच का उद्देश्य दोनों देशों के बीच उप–राष्ट्रीय सहयोग को गहरा करना है। प्रभाग ने गुजरात और महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्रियों की भागीदारी की भी सुविधा प्रदान की। चेन्नई और अहमदाबाद के मेयरों और अधिकारियों ने भी नेता मंच में भाग लिया।

3. मानवीय क्रिया कलाप

क. संकट की घड़ी में, राज्य प्रभाग ने दृढ़ता के साथ प्रतिक्रिया दी। इसने **यमन (ऑपरेशन राहत) और नेपाल (ऑपरेशन मैत्री)** में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राहत एवं बचाव अभियान में सफलतापूर्वक अपनी भूमिका निभाई। इसने यमन और नेपाल से भारतीयों की निकासी के लिए राजनयिक मिशनों और उन्हें अपने–अपने राज्यों में सुरक्षित और निरापद रूप से उन्हें वापस भेजने के लिए वहां के राजनयिक मिशनों एवं यहां के निवासी आयुक्तों के बीच सेतु के रूप में कार्य किया। इसमें संबंधित देशों से पीड़ितों के शवों को वापस लाना और उनके परिवारों को सौंपना भी शामिल था।

ख. राज्य प्रभाग जिन्हें अगस्त 2015 में मलेशिया में उनके नियोक्ता द्वारा हिरासत में लिए गए **13 कामगारों की स्वदेश वापसी को** सुविधाजनक बनाने में उत्तराखंड सरकार और क्वालालंपुर स्थित हमारे मिशन के साथ संपर्क स्थापित किया।

ग. राज्य प्रभाग ने आंध्र प्रदेश के **6 मछुआरों की 13 अगस्त 2015** को बांग्लादेश से रिहाई और उनके गृह नगर में उनकी वापसी का समन्वय किया।

घ. राज्य प्रभाग के प्रतिनिधि ने **मोहम्मद रमजान** से संबंधित मुद्दे पर गौर करने के लिए तथा **उनके घोषित गृह देश, पाकिस्तान में उनकी वापसी** की सुविधा के लिए 27 नवंबर 2015 को भोपाल का दौरा किया। मोहम्मद रमजान एक लड़का है, जो कथित तौर पर कराची, पाकिस्तान का रहने वाला है। वह पिछले दो वर्षों से आरामबाग, भोपाल की एक गैर–सरकारी संस्था द्वारा चलाए जा रहे आश्रय 'उम्मीद' में रह रहा है।

ड. राज्य प्रभाग ने **सुश्री गीता,** एक भारतीय नागरिक जो अपना रास्ता भटक गई थी और वर्षों पूर्व पाकिस्तान में प्रवेश कर गई थी, उसकी वापसी के लिए पीएआई प्रभाग के साथ मिलकर कार्य किया, पाकिस्तान की ओर से इदी फाउंडेशन, कराची नामक गैर सरकारी संगठन के सदस्यों की मेजबानी की जो पाकिस्तान में उस लड़की का देखरेख कर रही थी।

4. राज्य सरकारों के गणमान्य व्यक्तियों की विदेश यात्रा को सुगमता प्रदान करना

क. राज्य प्रभाग ने **पंजाब के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुखबीर सिंह बादल की जुलाई 2015 में पोलैंड और हंगरी की यात्रा** के लिए सुविधा प्रदान की। विशेष तौर पर कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य के क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करना महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। प्रगतिशील पंजाब निवेश शिखर सम्मेलन के लिए पोलैंड को भागीदार देश के रूप में घोषित किया गया। इसे 28–29 अक्टूबर 2015 के बीच मोहाली, पंजाब में आयोजित किया गया। प्रभाग ने 28 अगस्त –3 सितंबर 2015 तक पंजाब के माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की कोरिया गणराज्य की यात्रा की सुविधा प्रदान की। प्रभाग ने 22–30 अगस्त 2015 तक पंजाब उद्योग एवं वाणिज्य माननीय मंत्री श्री मदन मोहन मित्तल की चीन यात्रा के लिए भी सुविधा प्रदान की।

ख. राज्य प्रभाग ने **हरियाणा राज्य से एक 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल** की 16–25 अगस्त 2015 तक **संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा** यात्रा के लिए सुविधा प्रदान की थी। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी अध्यक्षता की थी तथा इसमें हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, मुख्य सचिव और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। हरियाणा को निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने के लिए यह यात्रा की गई थी। राज्य प्रभाग ने 17–25 जनवरी 2016 के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री को सिंगापुर यात्रा को सुगतमा प्रदान की।

ग. राज्य प्रभाग ने निवेश भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए और शहरी विकास एवं शिक्षा से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए **पश्चिम बंगाल** की माननीय मुख्यमंत्री **श्रीमती ममता बनर्जी** की जुलाई 2015 में **ब्रिटेन** यात्रा के लिए सुविधा प्रदान की थी।

घ. राज्य प्रभाग ने **महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र से एक 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का "महाराष्ट्र राज्य निवेश प्रोत्साहन संगोष्ठी" में भाग लेने के लिए 8–13 सितंबर 2015 तक जापान जाने के लिए यात्रा** का समन्वय किया था। इसका उद्देश्य राज्य में निवेश वृद्धि करना और वाटयार्न में भारतीय संविधान के वास्तुकार भारत रत्न डॉ बी. आर. अम्बेडकर की प्रतिमा के अनावरण करना था।

ड. राज्य प्रभाग ने 8–15 सितंबर 2015 तक **डालियान, चीन में** स्विट्जरलैंड **आधारित विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) शिखर सम्मेलन** में भाग लेने के लिए **तेलंगाना के** 16 सदस्यीय **प्रतिनिधिमंडल** की चीन यात्रा की व्यवस्था की थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव ने इस प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता की थी। प्रतिनिधिमंडल ने नए विकास बैंक (एनडीबी), शंघाई का दौरा किया और चीनी निवेशकों के साथ बातचीत की। बीजिंग में, उन्होंने चीन रेल

निगम, वांडा समूह (रियल एस्टेट) और शीर्ष चीनी कंपनियों में से कुछ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। मुख्यमंत्री ने सूज़ो का दौरा किया और सूज़ो औद्योगिक पार्क के उद्योगपतियों के साथ बैठक की थी।

च. राज्य प्रभाग ने 29 सितंबर – 6 अक्टूबर 2015 तक मध्य प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री शिव राज सिंह चौहान की जापान और कोरिया की यात्रा की व्यवस्था की थी। राज्य प्रभाग ने 12–15 जनवरी 2016 तक मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की सिंगापुर की यात्रा की व्यवस्था की।

छ. राज्य प्रभाग ने 17–23 अगस्त 2015 तक कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्योग तथा पर्यटन मंत्री श्री आर. वी. देशपांडे के नेतृत्व में **कर्नाटक के एक प्रतिनिधिमंडल** ने मेक्सिको और पेरू **यात्रा** को सुविधाजनक बनाने के लिए मिशनों के साथ संबंध स्थापित किया था। इस यात्रा का उद्देश्य **श्इन्वेस्ट कर्नाटकश 2015** को बढ़ावा देना और उद्योग एवं पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा करना।

5. प्रभाग के अभिगम कार्यक्रम

क. राज्य प्रभाग ने 23 जून 2015 को राज्यों के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सरलीकरण पर **चार शाखा सचिवालयों और 16 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों के प्रमुखों** के लिए एक **उन्मुखीकरण कार्यशाला** का आयोजन किया था। कार्यशाला में राज्यों से संबंधित आर्थिक सहयोग, प्रवासी भारतीयों से संबंधित मामलों आदि से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। विशेष सचिव (एएमएस और सीपीवी) ने भी कार्यशाला को संबोधित किया।

ख. प्रभाग ने 31 जुलाई 2015 को **मुख्य सचिव के नेतृत्व में तेलंगाना के वरिष्ठ अधिकारियों तथा दक्षिण कोरिया के दूतावास के प्रतिनिधियों और मुख्य महानिदेशक, भारत और दक्षिण एशिया, कोटरा (कोरिया व्यापार केन्द्र)** के बीच एक बैठक का आयोजन किया था।

ग. राज्य प्रभाग ने **इंटरनेशनल चैंबर आफ कामर्स बीजिंग का प्रतिनिधित्व करते हुए चीन के 19 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों**, और हरियाणा के कार्मिकों के बीच 10 सितंबर, 2015 को एक बैठक का आयोजन किया जिसे राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।

घ. राज्य प्रभाग ने **सचिव (पूर्व) की अध्यक्षता में 24 सितंबर, 2015** को एक बैठक का आयोजन किया था जिसमें **आंध्र प्रदेश के** 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल तथा विभिन्न देशों के वरिष्ठ राजनयिकों ने भाग लिया था। इस प्रतिनिधिमंडल में आवासीय आयुक्त, प्रमुख सचिव (शिक्षा), कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल थे तथा माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री गंता श्रीनिवास राव ने इसका नेतृत्व किया। इस प्रतिनिधिमंडल ने **ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका, सिंगापुर, जापान और चीन** के शिक्षा से संबंधित मामलों से जुड़े कई वरिष्ठ राजनयिकों के साथ मुलाकात की। यह बातचीत आंध्र प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अवसर तथा छात्र एवं संकाय आदान–प्रदान तथा सहयोगात्मक अनुसंधान के क्षेत्रों में विदेश स्थित प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के साथ संभावित सहयोग पर केंद्रित थी।

ङ राज्य प्रभाग ने अपनी पहल – **"मीटिंग द स्टेट्स"** के तहत 1 अक्टूबर, 2015 को राजनयिक मिशनों के साथ तेलंगाना राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, श्री के. टी. रामा राव के साथ एक विचार–विमर्श का आयोजन किया था। यह बैठक माननीय विदेश राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में हुई थी। इस बातचीत का उद्देश्य तेलंगाना में आर्थिक सहयोग और निवेश के लिए अवसरों को प्रस्तुत करना था।

च. **माननीय विदेश मंत्री** के निर्देश पर राज्य प्रभाग ने आसियान–एमएल प्रभाग के साथ समन्वय करते हुए पूर्वोत्तर राज्यों के गवर्नरों के लिए **माननीय विदेश मंत्री** द्वारा एक ब्रीफिंग सत्र का आयोजन किया। इस बैठक में अरुणाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री जे. पी. राजखोवा, असम और नागालैंड के राज्यपाल श्री पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य, मणिपुर और मेघालय के राज्यपाल श्री वी शण्मुगनाथन, मिजोरम के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा और सिक्किम के राज्यपाल श्री श्रीनिवास पटियाला ने भाग लिया। माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज की अध्यक्षता में 6 अक्टूबर 2015 को इस बैठक का आयोजन किया गया। ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) और वरिष्ठ अधिकारी ने भी भाग लिया, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष जोर देने के साथ भारत की "पूर्वोन्मुखी नीति'' के सभी व्यापक पहलू शामिल थे तथा सीमा पार व्यापार एवं सीमा पार संपर्क परियोजनाओं पर चर्चा की गई जो आसियान देशों अर्थात म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस पीडीआर और वियतनाम को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ सकेंगे।

छ. राज्य प्रभाग ने ऑटोमोटिव अनुसंधान एवं विकास तथा विनिर्माण, सामग्री, एयरोस्पेस और रक्षा, कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण, बुनियादी संरचना और ऑटोमोटिव

डिजाइन और प्रौद्योगिकी पर ध्यान देने के साथ आवक और जावक दोनों निवेश के अवसरों के लिए प्रेरित करने हेतु मिशिगन के उपराज्यपाल माननीय ब्रायन कैली के नेतृत्व में एक 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और पंजाब की राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एसीएमए) आंध्र प्रदेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफएपीसीसीआई) के प्रतिनिधियों की 9 अक्टूबर 2015 को एक बैठक का आयोजन किया।

ज. राज्य प्रभाग ने 21 अक्टूबर 2015 को श्री मासायुकी, मत्सुशिता, कंसाई इकॉनॉमिक फेडरेशन (कानकैरेन), जापान की अध्यक्षता में 23 सदस्यीय कानकैरेन प्रतिनिधिमंडल के लिए एक बैठक की मेजबानी की थी। नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, आपदा प्रबंधन, पर्यटन, शिक्षा और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग और कम कार्बन समाज के साथ स्मार्ट शहरों के निर्माण पर ध्यान देने के साथ **जापान और भारत** में व्यापार के अवसरों की खोज एवं विस्तार करना इस यात्रा का उद्देश्य था। संयुक्त सचिव (राज्य) ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी।

झ. राज्य प्रभाग ने **मणिपुर संगाई महोत्सव** में भागीदारी प्राप्त करने के संदर्भ में चुनिंदा देशों के **राजनयिक प्रतिनिधियों के साथ मणिपुर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों** के लिए 23 अक्टूबर 2015 को एक बैठक की मेजबानी की थी।

ञ राज्य प्रभाग ने **"पंजाब निवेश बैठक"** में भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान देने के लिए उच्च स्तर पर राज्य के गणमान्य व्यक्तियों के साथ विदेशी राजनयिकों की बैठकों में सहायता की थी।

ट. राज्य प्रभाग ने 6 नवम्बर 2015 को जेएनबी में **'खाड़ी देशों में महिला घरेलू श्रमिकों'** पर एक बैठक का आयोजन किया था। नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक में तेलंगाना के माननीय पंचायती राज और आईटी मंत्री श्री के. टी. रामा राव, आंध्र प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री श्री आर किशोर बाबू और तेलंगाना सरकार के विशेष प्रतिनिधि श्री रामचंद्रन तेजवाथ ने भाग लिया था। इस बैठक में सचिव, भारतीय प्रवासी कार्य मंत्रालय (एमओआईए), संयुक्त सचिव (एमओ. आईए), सचिव (आईटी), तेलंगाना, संयुक्त सचिव (पीएआई व राज्य), संयुक्त सचिव (कौंसुलर पासपोर्ट और वीजा), संयुक्त सचिव (खाड़ी), संयुक्त सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), आंध्र प्रदेश सरकार, निवासी आयुक्त (आरसी) तेलंगाना और आर सी आंध्र प्रदेश, विदेश मंत्री के निजी सचिव, विदेश मंत्री के अपर निजी सचिव और विदेश मंत्रालय के अन्य अधि ाकारियों ने भाग लिया। भारत वापस लौटने वाले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की 'महिला घरेलू श्रमिकों' ने भी इसमें भाग लिया था।

ठ. राज्य प्रभाग ने 17 नवंबर, 2015 को एक बैठक का आयोजन किया जिसमें **नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी)** के प्रतिनिधियों और **विदेश मंत्रालय के अधिकारियों** ने भाग लिया। एनडीएमसी के कुछ जमीनी श्रमिकों के चुने गए सफाई कर्मचारियों तथा बेलदारों (डिगर) के एक दल को अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के विषय में सीखने के लिए विदेशी एक्सपोजर दौरे के तहत टोक्यो तथा सिओल जाने हेतु इस बैठक का आयोजन किया गया।

6. विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की भारत यात्रा की व्यवस्था

क. राज्य प्रभाग ने 14 –16 जुलाई 2015 तक **एइची प्रान्त, जापान के गवर्नर श्री हिदेयकी ओहमुरा की** गुजरात और राजस्थान की यात्रा के दौरान बैठकों की व्यवस्था की थी। प्रभाग के प्रतिनिधि ने जयपुर (राजस्थान) की बैठक में भाग लिया।

ख. राज्य प्रभाग ने **यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल के काउंसलर, सुश्री ऐनी मरकल** की यात्रा में सहायता की **जिन्होंने** अगस्त 2015 में **बिहार (पटना और बोधगया) में लिए एक यूरोपीय संघ टीम के नेतृत्व किया था तथा** मुख्य सचिव, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और साथ में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुखों से मुलाकात की थी। राज्य प्रभाग ने पाई प्रभाग और केरल सरकार के समन्वय से 3 जनवरी 2016 को तिरुवनंतपुरम, केरल में साउथ एशियन फुटबाल फेडरेशन (एसएएफएफ) चैम्पियनशिप में भारत और अफगानिस्तान के बीच फाइनल मैच देखने के लिए मंत्रियों, संसद के सदस्यों और राजनयिकों सहित **अफगानिस्तान से आए 100 से अधिक सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल की** से जुड़ी व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण किया।

घ. राज्य प्रभाग मार्च में आयोजित **असम, मणिपुर और सिक्किम में नॉर्डिक राजदूतों की यात्रा का आयोजन करने** में शामिल है।

ङ राज्य प्रभाग 03–05 फ़रवरी 2016 से बेंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित **"इनवेस्ट कर्नाटक – 2016"** और 13–18 फ़रवरी 2016 से मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित **"मेक इन इंडिया समिट"** में विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की यात्राओं का आयोजन करने में भी शामिल था।

7. विविध

क. राज्य प्रभाग ने **"स्वच्छ भारत अभियान"** और **"गंगा संरक्षण योजना"** पर हुई बैठकों में, जिनमें विभिन्न मंत्रालयों के संयुक्त सचिव शामिल हुए थे, उनमें विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया।

ख. राज्य प्रभाग के प्रतिनिधियों ने विशाखापत्तनम में 10 अगस्त 2015 को **जियोमी के श्मेक इन इंडियाश मोबाइल फोन के उद्घाटन समारोह** में भाग लिया था।

ग. राज्य प्रभाग ने **"महात्मा की यादें"** विषय पर एक यात्रा प्रदर्शनी के संदर्भ में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुए समारोह में 20 अक्टूबर 2015 को जयपुर में विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया था।

घ. राज्य प्रभाग ने **मणिपुर संगाई महोत्सव 2015** के एक भव्य वार्षिक पर्यटन और सांस्कृतिक घटना में विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें मणिपुर में एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने के उद्देश्य से दुनिया भर के लिए मणिपुर की समृद्ध परंपरा और संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता था।

ङ राज्य प्रभाग के प्रतिनिधि ने **20–21 जनवरी 2016 को विज्ञान भवन में आयोजित सहकारी संघवाद पर सम्मेलन** में भाग लिया, और कई राज्य सरकार के गणमान्य व्यक्तियों के साथ इस पर विचार–विमर्श किया कि वे प्रभाग से क्या उम्मीद करते हैं और अधिकाधिक सहभागिता और सक्रिय रूप से समर्थन के लिए राज्यों को कैसे प्रेरित किया जाए।

■ ■

17 आतंकवाद का सामना

वर्ष के दौरान दुनिया के विभिन्न भागों में हुई आतंकवाद से संबंधित घटनाओं के मद्देनजर हुई विभिन्न उच्च स्तरीय द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों में आतंकवाद के मुद्दे का प्रमुखता से उल्लेख किया गया। ऐसी सभी बातचीतों के दौरान भारत ने दृढ़ता से हर प्रकार के आतंकवाद की निंदा की और वैश्विक स्तर पर इस गंभीर खतरे का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

भारत ने विभिन्न भागीदार देशों के साथ आतंकवाद का सामना करने पर संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी–सीटी) के माध्यम से सुनियोजित विचार–विमर्श करना जारी रखा। वर्ष 2015–16 के दौरान भारत ने रूस, बिम्सटेक, यूरोपीय संघ, नीदरलैंड, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, चीन, जापान, फ्रांस और मिस्र के साथ आतंकवाद का सामना (सीटी) करने हेतु संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठकों का आयोजन किया।

वैश्विक आतंकवाद विरोधी मंच (जीसीटीएफ), जो 2011 में स्थापित किया गया था, के एक संस्थापक सदस्य के रूप में भारत नियमित रूप से सभी जीसीटीएफ बैठकों में भाग लेता है। विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) सत्र के पार्श्व में सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में आयोजित सी जी टी एफ समन्वय समिति की बैठक, मंत्री स्तरीय बैठक और नेताओं के शिखर सम्मेलन में वरिष्ठ स्तर पर भागीदारी की।

भारत ने नवंबर 2015 में आयोजित ब्रिक्स और जी –20 सम्मेलन में आतंकवाद की समस्या के बारे में गंभीर चिंताएं व्यक्त कीं। इसके अलावा, विभिन्न उच्च स्तरीय आदान–प्रदान के दौरान, इसने 1996 में संयुक्त राष्ट्र में भारत द्वारा प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (सीसीआईटी) के अंतर्गत इस समस्या का समाधान करने के लिए एक संयुक्त कार्रवाई के महत्व पर भी बल दिया।

■ ■

वैश्विक साइबर मुद्दे

18

'डिजिटल इंडिया' को प्राप्त करने की दृष्टि से और साइबर मुद्दों पर महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की भागीदारी बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए, विदेश मंत्रालय (एमईए) वैश्विक साइबर मुद्दों पर भारत के लिए एक नेतृत्व की भूमिका प्राप्त करने के लिए सक्रियता से कार्रवाई कर रहा है। विदेश मंत्रालय का वैश्विक साइबर मुद्दा प्रभाग वैश्विक साइबर मुद्दों से संबंधित सभी मामलों पर कार्रवाई करता है।

भारत ने साइबर मुद्दों पर वैश्विक समुदाय के साथ व्यापक बातचीत करने के अपने प्रयासों को जारी रखा है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने 16–17 अप्रैल 2015 के दौरान हेग में संपन्न साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन (जीसीसीएस) 2015 में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत साइबर विशेषज्ञता पर वैश्विक मंच (जीएफसीई) का संस्थापक सदस्य बन गया जो जीसीसीएस के दौरान शुरू किया गया था। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने चौथी भारत–अमेरिकी साइबर वार्ता (10–12 अगस्त 2015) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। यूरोपीय संघ (21 मई 2015), ऑस्ट्रेलिया (24 अगस्त 2015) और जर्मनी (9 अक्टूबर 2015) के साथ द्विपक्षीय साइबर संवाद आयोजित किया गया।

डबलिन में 18–22 अक्टूबर 2015 को आयोजित आईसीएएनएन 54 में भारत ने जोयो पेसोया, ब्राजील में 10–13 नवंबर 2015 को आयोजित 10वें इंटरनेट गवर्नेंस फोरम में भी भाग लिया।

भारत विश्व सूचना संस्था शिखर सम्मेलन की 10 वर्षीय समीक्षा में सक्रिय रूप से शामिल रहा है, जो जून 2015 में आरंभ की गई थी और न्यूयॉर्क में 15–16 दिसंबर 2015 को एक उच्च स्तरीय बैठक में इसका समापन हुआ। विदेश मंत्रालय के सचिव (डीईआईटीवाई) के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस आयोजन में भाग लिया।

■ ■

19 सीमा प्रकोष्ठ

सीमा प्रकोष्ठ ने बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान के साथ चल रही वार्ता और भारत की बाहरी सीमाओं के प्रबंधन सहित विदेश मंत्रालय (एमईए) के भीतर संबंधित क्षेत्रीय प्रभागों के लिए सीमा से संबंधित मामलों पर मानचित्रण सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करना जारी रखा। यह अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित में उपलब्ध मानचित्रण पट्टी / मूल मानचित्र का संग्रह और डिजिटलीकरण में सहायता करता है। सीमा प्रकोष्ठ भारतीय सर्वेक्षण और सैन्य सर्वेक्षण (एमओजीएस–जीएस) के साथ गहन समन्वय करके भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सभी पहलुओं एवं भारत की बाह्य सीमाओं से संबंधित मानचित्र पृष्ठों के प्रकाशन की जांच करता है। प्रकोष्ठ संयुक्त सीमा सर्वेक्षण कार्य, सीमा स्तंभों के रखरखाव / मरम्मत / निर्माण और भारतीय प्रदेशों में किसी भी अतिक्रमण और डेटाबेस के रखरखाव की रिपोर्टों पर भारतीय सर्वेक्षण एवं राज्य सरकारों के साथ संपर्क भी स्थापित करता है। सीमा प्रकोष्ठ समुद्री सीमाए विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) और महाद्वीपीय मग्नतट–भूमि के चित्रण से संबंधित जानकारी के संग्रह और डिजिटलीकरण में सहायता प्रदान करता है। यह रक्षा मंत्रालय के साथ समन्वय करके प्रतिबंधित तथा गुप्त मानचित्र प्रपत्र की सुरक्षा करता है और नौसेना जल सर्वेक्षण कार्यालय और संबंधित विभागों और मंत्रालयों के साथ संपर्क बनाए रखता है। सीमा प्रकोष्ठ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित सभी मानचित्र / दस्तावेज / सूचना का रख–रखाव करता है।

2015–16 के दौरान, सीमा प्रकोष्ठ ने बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय भूमि एवं समुद्री सीमा पर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय / अंतर–मंत्रालयी बैठकों में भाग लिया।

सीमा प्रकोष्ठ ने भूमि सीमा समझौते (एलबीए) 1974 के प्रोटोकॉल 2011 के अनुसमर्थन में सहायता प्रदान की हैए और प्रतिकूल कब्जे वाली भूमि क्षेत्रों और परिक्षेत्रों के तत्कालीन गैर–सीमांकन खंडों के बकाया मुद्दों को हल किया। भारत–बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा के 30 पट्टी मानचित्रों को अंतिम रूप दिया गया और ढाका, बांग्लादेश में 30 जुलाई 2015 को दोनों देशों के पूर्णाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

■ ■

नीति नियोजन एवं अनुसंधान प्रभाग

20

वर्ष 2014–15 के दौरान विदेश मंत्रालय (एमईए) में नीति नियोजन और अनुसंधान प्रभाग का एक महत्वपूर्ण पुनरुद्धार देखा गया। प्रभाग को मानव और वित्तीय संसाधनों का आबंटन बढ़ाने के माध्यम से मजबूत बनाया गया था और अपने अधिदेश को पुनर्गठित और सक्षम बनाने के लिए सुव्यवस्थित किया गया था, ताकि यह अपनी उस परिकल्पित भूमिका का निष्पादन कर सके, जिसकी परिकल्पना कई दशक पहले इसकी स्थापना के साथ की गई थी।

प्रभाग के नए सिरे से परिभाषित अधिदेश के महत्वपूर्ण तत्व इस प्रकार हैं:

(i) हमारी प्रमुख विदेश नीति के लक्ष्यों का सतत और भविष्योन्मुखी विश्लेषण करना और मंत्रालय के लिए जारी मुद्दों / नीतियों पर अनुसंधान आधारित संभावनाएं प्रदान करना। इसमें गृह कार्य या अनुसंधान संगठनों और सरकार के बाहर से थिंक टैंक की सेवाओं का उपयोग करना शामिल है।

(ii) विदेश नीति तैयार करने के लिए विचारों और दृष्टिकोण प्राप्त करने हेतु भारतीय थिंक टैंक के लिए सक्रिय आउटरीच और अनुसंधान के प्रकार पर उन्हें मार्गदर्शित करने के लिए उन लोगों के साथ संबंध स्थापित करना, जो मंत्रालय के लिए उपयोगी होंगे।

(iii) भारत में ऐसे प्लेटफार्मों, जहां दुनिया भर के प्रमुख सामरिक विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के बीच समकालीन विदेश नीति के मुद्दों पर विचार–विमर्श किए जा सकते हैं, को विकसित करने के उद्देश्य से प्रमुख थिंक टैंक और शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी करके सम्मेलनों का आयोजन करना।

(iv) दीर्घकालिक सामरिक योजना और प्राथमिकताओं पर विचारों के आदान–प्रदान के लिए हमारे महत्वपूर्ण राजनयिक सहयोगियों के साथ नीति नियोजन पर संस्थागत संवादों का विकास।

(v) भारत के नजरिए को पेश करने के लिए भारत तथा विदेशों में महत्वपूर्ण कूटनीतिक सम्मेलनों में भारत की भागीदारी सुनिश्चित करना तथा उक्त सम्मेलनों में विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के बीच आदान–प्रदान से लाभ उठाना।

वर्ष के दौरान, प्रभाग के लिए संसाधनों के आबंटन को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इसमें शामिल हैः

(i) पीपी एंड आर प्रभाग के अंतर्गत मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले वित्तीय संसाधनों को मजबूत बनानाए जो थिंक टैंक और संगोष्ठियों और सम्मेलनों के आयोजन के साथ ही सामयिक अध्ययन (परिशिष्ट VI) करने के लिए वित्तीय सहायता से संबंधित थे। इस प्रयोजन के लिए अगले वित्त वर्ष के दौरान एक उच्चतर आबंटन अनुमोदन के अध्यधीन प्रस्तावित है।

(ii) मंत्रालय के संसाधन पूल में से अतिरिक्त मानव संसाधनों की तैनाती करना।

(iii) अन्य मंत्रालयों से विशेषज्ञों को शामिल करने के लिए कदम उठाना। अब तक भारतीय सेना के एक अधिकारी और आर्थिक पृष्ठभूमि के साथ एक अन्य को शामिल किया गया है।

(iv) प्रभाग में सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए शैक्षिक तथा थिंक टैंक समुदाय से अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर विशेषज्ञों की भर्ती करना। अब तक, इस तरह के दो विशेषज्ञों ने मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण किया है और दो अन्य के शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है।

वर्ष के दौरान, प्रभाग ने भारत की विदेश नीति के विशिष्ट पहलुओं पर अनेक शोध पत्र और नीति संक्षेप तैयार किए हैं। इनमें वे सभी क्षेत्र शामिल हैं जिनमें मौजूदा नीति के पुनःअंशांकन की आवश्यकता होती है और जहां वैश्विक स्तर पर नए घटनाक्रम पर नीति प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। ऐसा करने में, प्रभाग ने हमारी नीति के रुख तैयार करने में अपनी विशेषज्ञता की तलाश

के लिए सरकार के अन्य संगत शाखाओं के साथ और प्रतिष्ठित अनुसंधान संगठनों और थिंक टैंक के साथ सहयोग किया है।

प्रमुख समकालीन विदेश नीति के मुद्दों पर विचार–विमर्श और अभिव्यक्ति के लिए मंच तैयार करने के लिएए प्रभाग ने देश में प्रमुख थिंक टैंक के साथ साझेदारी करके वार्षिक आधार पर भारत में प्रमुख विदेश नीति सम्मेलनों का आयोजन करने के लिए प्रस्तावों की पहल की। इस तरह का पहला सम्मेलन 1–3 मार्चए 2016 को ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ साझेदारी करके ”रायसीना वार्ता” नामक सम्मेलन आयोजित किया गया। ऐसे ही, 16–17 अप्रैल, 2016 को मुंबई में गेटवे हाउस के साथ ”भारत वार्ता का प्रवेश द्वार” शीर्षक से एक और ऐसी बातचीत आयोजित करने की प्रक्रिया की शुरूआत की गई है। इस तरह के अनेक सम्मेलन आने वाले वर्ष में आयोजित किए जाएंगे। विदेश नीति के मुद्दों के लिए समर्पित अनेक सेमिनारों तथा सम्मेलनों में योगदान दिया था। महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और द्विपक्षीय या एकतरफा ट्रैक 1.5 और ट्रैक 2 संवाद में प्रभाग ने सीधे भाग लिया या संबंधित एजेंसियों की भागीदारी सुनिश्चित की है।

नीति नियोजन और प्राथमिकताओं पर दृष्टिकोणों के आदान–प्रदान की दृष्टि से महत्वपूर्ण राजनयिक सहयोगियों के साथ संपर्कों को विकसित करने के प्रयास के भाग के रूप में, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल के विदेश कार्यालयों में समकक्षों के साथ विचार विमर्श आयोजित किया गया। वर्ष के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी के साथ औपचारिक नीति नियोजन संवाद की घोषणा की गई और क्रमशः नवंबर 2015 और फरवरी 2016 में ऐसे संवादों के पहले दौर आयोजित किए गए। इससे पहले ब्रिक्स देशों के नीति नियोजन विभागों के साथ संयुक्त विमर्शों के पहले दौर का आयोजन भी मई 2015 में किया गया। अन्य प्रमुख सहयोगियों के साथ इसी तरह के संवाद शुरू करने और मौजूदा संवादों को पुनर्जीवित के प्रयास अगले वर्ष के दौरान जारी रहेंगे।

विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के बीच व्यापक थिंक टैंक और सामरिक मंडलियों में अनुसंधान और विश्लेषण का प्रसार करने के लिएए प्रभाग ने हमारे मंत्रालय और विदेशों मिशनों में कार्य कर रहे अधिकारियों को विदेश नीति के समकालीन मुद्दों पर प्रासंगिक शोध पत्र और लेख के प्रसार के लिए एक वेब आधारित पोर्टल का विकास किया। मंत्रालय के हित के क्षेत्रों में चल रही संगोष्ठियों और सम्मेलनों की कार्यवाहियों पर उन्हें अद्यतन जानकारी देने के लिए भी इस पोर्टल का उपयोग किया जाता है। इस पोर्टल के माध्यम से हित के विषयों पर पीपी एंड आर प्रभाग द्वारा तैयार की गई स्थिति रिपोर्ट और मुद्दों के सार का भी प्रचार–प्रसार किया जाता है।

■ ■

प्रोटोकॉल

21

वर्ष 2015 में, विदेश मंत्रालय के प्रोटोकॉल प्रभाग ने राष्ट्राध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, शासनाध्यक्ष तथा विदेश मंत्री के स्तर पर आगमन/प्रस्थान के 57 दौरों का समन्वय किया।

इसके अलावा, प्रोटोकॉल प्रभाग ने 19–21 अगस्त 2015 के दौरान भारत – प्रशांत द्वीपसमूह सहयोग शिखर सम्मेलन के दूसरे मंच का समन्वय किया जिसमें प्रशांत द्वीप समूह के 14 राष्ट्राध्यक्षों तथा शासनाध्यक्षों ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसके अलावाए 26–30 अक्टूबर 2015 के दौरान 54 देशों का तीसरा भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें 41 राष्ट्राध्यक्षों तथा शासनाध्यक्षों ने भाग लिया और अन्यों का प्रतिनिधित्व निचले स्तर पर किया गया था।

संदर्भ–अधीन अवधि के दौरान, इक्वेटोरियल गिनी ने नई दिल्ली में अपना दूतावास खोला; बांग्लादेश ने गुवाहाटी में अपना उप उच्चायोग खोलाय श्रीलंका ने कोलकाता में वाणिज्य दूतावास और नॉर्वे ने मुंबई में अपने वाणिज्य दूतावास खोला । 29 मिशन प्रमुखों ने राष्ट्रपति जी को अपने विवरण प्रस्तुत किए। पांच मानद वाणिज्य दूतावास चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और नई दिल्ली शहरों में खोले गए। राजनयिक मिशनों / अंतरराष्ट्रीय संगठनों में 51 नए पद सृजित किए गए।

यात्राओं का कैलेंडर

राष्ट्र प्रमुख / सरकार प्रमुख / उप राष्ट्रपति तथा समकक्ष द्वारा राजकीय यात्राएं

क्र. सं.	गणमान्य अतिथि	तिथियां
1	अफगानिस्तान के राष्ट्रपति	27–29 अप्रैल, 2015
2	तंजानिया के राष्ट्रपति	17–20 जून, 2015
3	मोजाम्बिक के राष्ट्रपति	4–7 अगस्त, 2015
4	सेशेल्स के राष्ट्रपति	25–27 अगस्त, 2015

राष्ट्र प्रमुख/सरकार प्रमुख/उप राष्ट्रपति तथा समकक्ष द्वारा आधिकारिक/कार्य संबंधी यात्राएं

क्र. सं.	गणमान्य अतिथि	तिथियां
1	नीदरलैंड के प्रधानमंत्री	5–7 जून, 2015
2	बांग्लादेश की प्रधानमंत्री	19 अगस्त 2015
3	अफगानिस्तान के उप राष्ट्रपति	2–4 अक्टूबर, 2015
4	जर्मनी के चांसलर	04–05 अक्टूबर, 2015
5	कोस्टा रिका के उप राष्ट्रपति	07–13 अक्टूबर, 2015
6	चीन के उप राष्ट्रपति	03–07 नवम्बर, 2015
7	भूटान के प्रधानमंत्री	13–17 नवम्बर, 2015
8	मॉरीशस के राष्ट्रपति	6–9 दिसम्बर, 2015
9	जापान के प्रधानमंत्री	11–13 दिसम्बर, 2015

राष्ट्र प्रमुख / सरकार प्रमुख / उप राष्ट्रपति तथा समकक्ष द्वारा निजी और ट्रांजिट यात्राएं

क्र. सं.	गणमान्य अतिथि	तिथियां
1	श्रीलंका के प्रधानमंत्री	18 अप्रैल 2015
2	मॉरीशस के राष्ट्रपति	18–24 अप्रैल, 2015
3	अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति	04–08 अगस्त, 2015

विदेश मंत्री और समकक्ष द्वारा आधिकारिक यात्रा

क्र. सं.	गणमान्य अतिथि	तिथियां
1	डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके द्धके विदेश मंत्री	12–14 अप्रैल, 2015
2	बेलारूस के विदेश मंत्री	14–16 अप्रैल, 2015
3	ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री	12–16 अप्रैल, 2015
4	स्पेन के विदेश मंत्री	26–28 अप्रैल, 2015
5	ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री	11–15 मई, 2015
6	कांगो के विदेश मंत्री	13–16 मई, 2015
7	नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री	14–19 जुलाई, 2015
8	म्यांमार के विदेश मंत्री	14–18 जुलाई, 2015
9	लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री	09–10 अगस्त, 2015
10	ईरान के विदेश मंत्री	13–14 अगस्त, 2015
11	संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के अध्यक्ष	28–31 अगस्त, 2015
12	संयुक्त अरब अमीरात (यूईए) के विदेश मंत्री	02–03 सितम्बर, 2015
13	उरुग्वे के विदेश मंत्री	06–11 अक्टूबर, 2015
14	फिलीपींस के विदेश मंत्री	13–15 अक्टूबर, 2015
15	सिंगापुर के विदेश मंत्री	13 अक्टूबर 2015
16	नेपाल के उप प्रधानमंत्री	17–19 अक्टूबर, 2015
17	नॉर्वे के विदेश मंत्री	02–04 नवम्बर, 2015
18	ब्राजील के विदेश मंत्री	18–19 नवम्बर, 2015
19	फ्रांस के विदेश मंत्री	20–21 नवम्बर, 2015
20	मालदीव के विदेश मंत्री	20–22 नवम्बर, 2015
21	नेपाल के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री	30 नवम्बर – 2 दिसम्बर, 2015
22	आयरलैंड के विदेश मंत्री	08–10 दिसम्बर, 2015
23	आसियान के महासचिव	08–12 दिसम्बर, 2015

भारत के राष्ट्रपति / उप राष्ट्रपति / प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं

क्र. सं.	गणमान्य अतिथि	तिथियां
1.	प्रधानमंत्री की फ्रांस, जर्मनी, कनाडा की यात्रा	9–17 अप्रैल, 2015
2.	राष्ट्रपति की मास्को यात्रा	7–10 मई, 2015
3.	प्रधानमंत्री की चीन, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया की यात्रा	13–19 मई, 2015
4.	राष्ट्रपति की स्वीडन और बेलारूस की यात्रा	31 मई – 4 जून, 2015
5.	प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा	6–7 जून, 2015
6.	प्रधानमंत्री की उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान, ऊफ़ा, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान की यात्रा	6–13 जुलाई, 2015
7.	प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा	16–17 अगस्त, 2015
8.	उपराष्ट्रपति की कंबोडिया और लियोस की यात्रा	12–18 सितम्बर, 2015
9.	प्रधानमंत्री की आयरलैंड, यूएसए की यात्रा	23–29 सितम्बर, 2015
10.	राष्ट्रपति की जोर्डन, फिलिस्तीन, इसराइल की यात्रा	10–15 अक्टूबर, 2015
11.	उप राष्ट्रपति की इंडोनेशिया की यात्रा	1–5 नवम्बर, 2015
12.	प्रधानमंत्री की ब्रिटेन और तुर्की की यात्रा	12–15 नवम्बर, 2015
13.	प्रधानमंत्री की मलेशिया और सिंगापुर की यात्रा	20–24 नवम्बर, 2015
14.	प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा	29 नवंबर से 1 दिसंबर, 2015
15.	उपराष्ट्रपति की तुर्कमेनिस्तान की यात्रा	11–13 दिसम्बर, 2015
16.	प्रधानमंत्री की रूस, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की यात्रा	23–25 दिसम्बर, 2015

विदेश मंत्री की विदेश यात्राएं

1.	अश्गाबातए तुर्कमेनिस्तान	7–9 अप्रैल, 2015
2.	जकार्ताए इंडोनेशिया	21–25 अप्रैल, 2015
3.	प्रिटोरियाए दक्षिण अफ्रीका	18–20 मई, 2015
4.	न्यूयार्कए यूएसए	20–22 जून, 2015
5.	काठमांडूए नेपाल	24–25 जून, 2015
6.	बैंकाकए थाईलैंड	27–29 जून, 2015
7.	मिस्र और जर्मनी	23–27 अगस्त, 2015
8.	वाशिंगटनए यूएसए	21–23 सितम्बर, 2015
9.	न्यूयार्कए यूएसए	29 सितम्बर – 2 अक्टूबर, 2015
10.	मालदीव	10–11 अक्टूबर, 2015
11.	मास्को	19–21 अक्टूबर, 2015
12.	माल्टा	26–29 नवम्बर, 2015
13.	इस्लामाबाद	08–09 दिसम्बर, 2015
14.	इजराइल और फिलिस्तीन	16–19 जनवरी, 2016
15.	बहरीन	23–24 जनवरी, 2016

22 कौंसुली, पासपोर्ट एवं वीजा सेवाएं

मंत्रालय का कौंसुली, पासपोर्ट एवं वीजा प्रभाग (सीपीवी) केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (सीपीओ) और पासपोर्ट कार्यालयों के अपने नेटवर्क एवं पासपोर्ट सेवा केन्द्रों के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करता है; और विदेश स्थित भारतीय मिशनों एवं केन्द्रों के माध्यम से आप्रवासी भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों को कौंसुली, वीजा एवं पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करता है।

पासपोर्ट सेवाएं

हाल के वर्षों में पासपोर्ट जारी करना विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सबसे उल्लेखनीय वैधानिक एवं नागरिक–केंद्रित सेवा के रूप में उभरा है। तद्नुसार मंत्रालय ने देश में पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने में कई गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार किए हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन और 37 पासपोर्ट कार्यालयों के अपने अखिल भारतीय नेटवर्क, सीपीवी प्रभाग (केवल राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट) तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन द्वारा भारतीय पासपोर्ट (तिब्बती शरणार्थियों के लिए पहचान प्रमाण पत्र, भारत वापसी के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र, जम्मू और कश्मीर में पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्र और नियंत्रण रेखा यात्रा अनुमति जैसे अन्य यात्रा दस्तावेजों सहित) जारी किए जाते हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) विधि में चलाए जा रहे 77 पासपोर्ट सेवा केन्द्र (पीएसके) के अलावा, मंत्रालय ने अगरतला, आइजोल, गंगटोक, इम्फाल, कालाबुर्जी, करीमनगर, दरभंगा और शिलांग में 8 अतिरिक्त पासपोर्ट सेवा केन्द्र की स्थापना की है, जो मुख्यतः पूर्वोत्तर के पासपोर्ट आवेदकों को विस्तारित पहुंच प्रदान करता है। नागरिकों की सुविधा के लिए 10 और पासपोर्ट सेवा केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे वर्ष 2016 के दौरान पासपोर्ट सेवा केन्द्रों की संख्या 95 हो जाएगी। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए 183 भारतीय मिशनों / केन्द्रों द्वारा कौंसुली दस्तावेजों के सत्यापन के अतिरिक्त पासपोर्टए ओसीआई कार्ड, ईसी एवं अन्य विविध कौंसुली सेवाएं प्रदान की जाती है।

पासपोर्ट सेवाओं में अपार वृद्धि

पिछले पांच वर्षों में, पासपोर्ट से संबंधित सेवाओं के कार्यक्षेत्र और इसकी मात्रा दोनों में अपार विस्तार हुआ है। 37 पासपोर्ट कार्यालयों, मुख्यालयों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव के कार्यालय को पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्रों सहित पासपोर्ट सेवाओं से संबंधित 1.03 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए थे और 1.06 करोड़ पासपोर्ट तथा इससे संबंधित दस्तावेज जारी किए गए थे (2547 राजनयिक पासपोर्ट, 27138 सरकारी पासपोर्ट, 4,01,781 पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्र (पीसीसी), 4605 अभ्यर्पण प्रमाणपत्र (एससी) 3852 पहचान प्रमाणपत्र (आईसी) और 4623 नियंत्रण रेखा (एलओसी) अनुमति आवेदनों सहित), जो वर्ष 2014 की तुलना में आवेदन पत्रों में 19 प्रतिशत तथा सेवाओं के संदर्भ में 24 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। विदेश में स्थित 183 भारतीय मिशनों / केंद्रों ने लगभग 14 लाख पासपोर्ट जारी किए जिसमें ईसी एवं अन्य पासपोर्ट से संबंधित विविध सेवाएं शामिल हैं। इस प्रकार भारत सरकार ने पूरे वर्ष में कुल मिलाकर 1.20 करोड़ पासपोर्ट और पासपोर्ट से संबंधित अन्य सेवाएं प्रदान कीं। यह अपने आप में सर्वाधिक है और वर्ष 2010 से यह 100 प्रतिशत वृद्धि है। 31 दिसंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार 6,32,99,804 नागरिकों के पास वैध पासपोर्ट (वर्ष 2014 में 5.70 करोड़ और वर्ष 2013 में 5.19 करोड़ से अधिक) थे। भारत आज वैश्विक पासपोर्ट जारी करने के मामले में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर आ गया है।

पासपोर्ट शुल्क के संबंध में सरकार राजस्व में तीव्र वृद्धि हुई है : वर्ष 2011–12 के बाद से 110 प्रतिशत वृद्धि हुई है। सभी पासपोर्ट सेवाओं से दिसम्बर 2015 तक कुल 1,630,90,66,204 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। 2011–2012 में 1,030.58 करोड़ रुपए और 2014–15 में 2167.07 करोड़ रुपए की तुलना में (सभी पासपोर्ट सेवाओं से 2015–16 में 2300 करोड़ रुपए का कुल राजस्व अर्जित होने की उम्मीद है) वित्तीय वर्ष, 2015–16 के दौरान केंद्रीय पासपोर्ट संगठन को 902.70 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी।

केंद्रीय पासपोर्ट संगठन

केंद्रीय पासपोर्ट कार्यालय का गठन मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में 1959 में किया गया था जिसके अध्यक्ष संयुक्त सचिव और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी होते हैं जो पासपोर्ट

अधिनियम, 1967 के तहत अपीलीय प्राधिकारी तथा प्रत्यायोजित वित्तीय शक्ति नियमावली, 1978 के तहत विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। 31 दिसंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय पासपोर्ट संगठन की कुल स्वीकृत संख्या 2697 थी। इसके अतिरिक्त पासपोर्ट सेवा परियोजना की परियोजना प्रबंधन इकाई (पी एम यू) को संचालित करने की दृष्टि से वर्ष 2007 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार 15 तकनीकी और 6 सहायक स्टाफ सहित 21 पद सृजित किए गए थे।

मंत्रालय ने सी पी ओ संवर्ग का पुनर्गठन एवं विस्तार करते हुए सी पी ओ कार्मिकों की सेवा शर्तों में सुधार करने के लिए इस मंशा से कई कदम उठाए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उपलब्ध रिक्त पदों को तीव्र पदोन्नति द्वारा भरा जाए। मंत्रालय ने पूर्व निरधारित एवं परस्पर सहमत मानकों पर आधारित व्यक्तिगत निष्पाद को वित्तीय रूप से प्रोत्साहित करने के लिए 21 मार्च, 2013 को एक संशोधित उत्पादकतायुक्त प्रोत्साहन योजना (पी एल आई एस) को अधिसूचित किया है। यह भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अनोखी योजना है। सी पी ओ कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई योग्य सेवाओं की पहचान करने तथा इस प्रकार देश में शासन में सुधार के प्रति योगदान करने की दृष्टि से पासपोर्ट सेवा पुरस्कार शुरू किए गए हैं। प्रतिवर्ष पासपोर्ट अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान पासपोर्ट कार्यालय के चयनित कर्मचारियों को पुरस्कार दिए जाते हैं।

वर्ष 2015 में, 442 अधिकारियों की पदोन्नति के लिए 8 डीपीसी आयोजित की गई : 23 फरवरी 2015 को 171 अधीक्षकों से पीजीओ के लिए डी पी सी 19 मार्च 2015 को एमएसीपी योजना के लिए 21 अधिकारियों (आशुलिपिक, यूडीसी, एलडीसी व कार्यालय सहायक) हेतु डीपीसी, 24 फरवरी 2015 को सहायक से अधीक्षक (पूरक) के लिए डीपीसी, 22 मई 2015 को 35 यूडीसी से सहायक के लिए डीपीसी, एक आशुलिपिक ग्रेड II से I के लिए डीपीसी, 84 यूडीसी से सहायक के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति, 27 अक्टूबर 2015 को 35 सहायक से अधीक्षक के लिए डीपीसी, 27 अक्टूबर 2015 को 45 अधीक्षक से पीजीओ के लिए डीपीसी और 19 नवम्बर 2015 को 2 एलडीसी से यूडीसी के लिए डीपीसी।

कर्मचारी चयन आयोग ने भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली है और 92 सहायकों और 550 निम्न श्रेणी लिपिक की नियुक्ति हेतु फाइलें पहले से ही भेज दी हैं। मंत्रालय ने इन उम्मीदवारों को नियुक्ति के प्रस्ताव जारी कर दिए हैं।

भौतिक अवसंरचना

37 पासपोर्ट कार्यालयों में से 18 स्वयं के भवनों से प्रचालनरत हैं, 4 भारत सरकार के भवनों से कार्य कर रहे हैं और शेष 15 किराए के भवनों से कार्य कर रहे हैं। सभी पासपोर्ट कार्यालयों को अपने भवनों में स्थानांतरित करने से संबंधित मंत्रालय की नीति के अनुरुप आधुनिक भवनों के निर्माण हेतु भूभाग खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्रालय ने अब तक 8 जगहों अर्थात श्रीनगर, अमृतसर, देहरादून, मुंबई, पुणे, भोपाल, गुवाहाटी एवं जालंधर में भू–खण्ड अधिग्रहित किए हैं। नए पीओ भवन मुंबई का निर्माण पूरा हो चुका है और मंत्रालय संबंधित अधिकारियों के अनुमोदन के बाद इस पर अपना आधिपत्य प्राप्त कर लेगा। विदेश मंत्री ने 26 मई 2015 को भोपाल में पासपोर्ट भवन की आधारशिला रखी। जालंधर और अमृतसर में निर्माण कार्य प्रगति पर है। पासपोर्ट कार्यालय कोलकाता के लिए भूमि खरीदने की मंजूरी दे दी गई है और शीघ्र ही भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। पासपोर्ट कार्यालयए रांची के लिए राज्य सरकार की ओर से भूमि खरीद की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

पासपोर्ट सेवा परियोजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन

पासपोर्ट सेवा कार्यक्रमए एक महत्वाकांक्षी मिशन मोड परियोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोड में तथा सेवा प्रदाता टाटा कंसलटेंसी सर्विस (टीसीएस) के साथ मिलकर राष्ट्रीय ई–शासन योजना के भाग के रूप में सफलतापूर्वक चल रहा है। पासपोर्ट और संबंधित सेवाओं के आवेदन वर्ष 2015 में 1 करोड़ की संख्या पार कर चुके हैं, जो विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वैधानिक और नागरिक–केन्द्रित सेवाओं के रूप में उभर रहा है। वर्ष 2011–12 के दौरान राष्ट्र भर में सफलतापूर्वक प्रारंभ करने के बाद यह योजना 14 जूनए 2012 से वर्तमान में प्रचालन और रख–रखाव चरण पर है तथा इसने अपने सफलतापूर्वक प्रचालन के साढ़े तीन साल पूरे कर लिए हैं।

पूरे देश में 37 पासपोर्ट कार्यालयों के विस्तृत भाग के रूप में सर्वश्रेष्ठ सुविधाओं सहित 77 पासपोर्ट सेवा केन्द्रों (पीएसके) की स्थापना की गई हैं, जिससे पासपोर्ट आवेदकों को व्यापक पहुंच प्रदान की जा सके। सभी पी एस के में प्रत्येक दिन लगभग 50,000 नागरिक आते हैं। टोल फ्री नंबर (1800–258–1800) का इस्तेमाल करते हुए एक 24 x 7 राष्ट्रीय कॉल सेंटर खोला गया है जो 17 भाषाओं में समयोजित स्थिति और अद्यतन जानकारी प्रदान करता है। कॉल सेंटर में प्रतिदिन 20,000 से अधिक कॉल आती हैं। http://passportindia.gov.in पोर्टल पर भी समायोजित अद्यतन जानकारी प्रदान की जाती है जिसे नियमित रूप से अध्यतित किया जाता है। यह परियोजना, आवेदक की निजी जानकारी के सत्यापन के लिए राज्य / संघ राज्य क्षेत्र पुलिस प्रणाली, पोस्टल डिलीवरी के लिए भारतीय पोस्ट और पासपोर्ट बुकलेट की आपूर्ति व्यवस्था के लिए आई एस पी नासिक के साथ एकीकृत की गई है। इस प्रणाली को अगस्त 2015 के बाद से

आधार कार्ड डेटाबेस के साथ भी देश भर में एकीकृत किया गया है। यह परियोजना 183 मिशनों और केन्द्रों के साथ–साथ आप्रवास प्राधिकरणों को भी समुचित अद्यतन जानकारी प्रदान करता है। जैसे ही पासपोर्ट प्रेषित किया जाता है, आवेदक को एक एस एम एस / ई–मेल एलर्ट भेज दिया जाता है।

पासपोर्ट इंडिया पोर्टल

पासपोर्ट सेवाओं पर विस्तृत और नई जानकारी प्रदान करने, मिलने का समय निश्चित करने की प्रक्रिया, दस्तावेजों, स्थिति की जानकारी तथा अन्य संबंधित मामलों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल passportindia.gov.in बनाया गया है जिसे किसी भी समय और कहीं भी देखा जा सकता है। इस पोर्टल को अधिक सरल और प्रयोक्ता अनुकूल बनाने के लिए निरंतर मॉनीटर और अद्यतन किया जाता है। यह पोर्टल द्विभाषी है जिसमें हिंदी में भी जानकारी प्रधान रूप से दिखाई जाती है। यह समय–समय पर हुए पासपोर्ट सेवा संबंधी सार्वजनिक सूचनाएं, सलाह तथा प्रेस विज्ञप्ति से अद्यतन रहता है। जून 2015 में एक अधिक प्रयोक्ता अनुकूल पोर्टल जारी किया गया। पोर्टल पर प्रति दिन 2 करोड़ से अधिक हिट किए जाते हैं। पासपोर्ट आवेदकों को प्रति दिन 1 लाख से अधिक एसएमएस भेजे जाते हैं।

सेवाएं प्रदान करने में किए गए उल्लेखनीय सुधार

पासपोर्ट सेवा परियोजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप, देश भर में पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। जनवरी–दिसंबर, 2015 के दौरान देश भर में 38 प्रतिशत सामान्य पासपोर्ट 03 दिनों के अंदर, 74 प्रतिशत 07 दिनों में; 91 प्रतिशत 14 दिनों में 94 प्रतिशत 21 दिनों में और 95 प्रतिशत 30 दिनों में जारी किए गए (पुलिस सत्यापन के लिए समय के अलावा)। आज अखिल भारतीय आधार पर, एक महीने में पुलिस सत्यापन सहित 68 प्रतिशत सामान्य पासपोर्ट जारी किए जाते हैं, जो वर्ष 2014 में 46 प्रतिशत था। तत्काल पासपोर्ट के मामलों में 34 प्रतिशत आवेदन जमा करने के दिन 65 प्रतिशत 01 दिन के अंदर, 87 प्रतिशत 03 दिनों के अंदर जारी किए गए। तत्काल श्रेणी के आवेदनों की संख्या वर्ष 2013 में कुल आवेदनों के 8 प्रतिशत की तुलना में अब 5 प्रतिशत है।

31 दिसंबर 2015 की स्थिति के अनुसारए प्रति दिन 60,000 से अधिक नियुक्ति स्लॉट जारी किए गए। यह पिछले वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत की वृद्धि है। पूरे देश के सभी पासपोर्ट कार्यालय में किसी भी पासपोर्ट सेवा केन्द्र में मुलाकात का समय अब 1–7 दिनों के अंदर उपलब्ध है।

आवेदनों की संख्या

- पासपोर्ट आवेदन प्राप्त करने की संख्या और प्रदान की गई सेवाओं के आधार पर सर्वोच्च 05 राज्य उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, तामिलनाडु और गुजरात थे जो कुल आवेदनों का 51 प्रतिशत से भी अधिक था।
- प्राप्त आवेदनों की संख्या और प्रदान की गई सेवाओं के आधार पर सर्वोच्च 06 पासपोर्ट कार्यालय थे : लखनऊ (9.48 लाख), हैदराबाद (7.60 लाख), बैंगलोर (6.33 लाख), कोलकाता (6.13), अहमदाबाद (5.66 लाख) और दिल्ली (5.06 लाख)।
- प्राप्त आवेदनों की संख्या और प्रदान की गई सेवाओं के आधार पर प्रमुख 5 जिले (दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, बैंगलुरू और चेन्नई महानगरों को छोड़कर); मल्लापुरम, पुणे, थाने, अहमदाबाद तथा कोजीकोड थे।
- उत्तर प्रदेश ने पासपोर्ट सेवाओं के मामले में पहली बार नंबर 1 राज्य के रूप में उभरकर (13.37 लाख) इतिहास रचा
- पहली बार, 4 राज्य पासपोर्ट लखपति राज्य बन गए हैं; उत्तर प्रदेश (13.37 लाख), महाराष्ट्र (11.87 लाख), केरल (11.44 लाख) और तमिलनाडु (10.08 लाख)

पुलिस सत्यापन

पासपोर्ट को समय पर जारी करने में पुलिस सत्यापन की अहम भूमिका होती है। पुलिस सत्यापन में तेजी लाने के लिए मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्यों के पुलिस विभागों के साथ निकट संपर्क में है। पुलिस सत्यापन को पूरा करने में लगने वाले दिनों का अखिल भारतीय औसत 34 (2014 में 42 और 2013 में 49 था) तक घट गई है और लगभग 61 प्रतिशत पुलिस सत्यापन अपेक्षित 21 दिनों की समय सीमा में पूरा हो जाता है, जो पिछले वर्ष से लगभग 24 प्रतिशत तथा 15 दिनों का सुधार दर्शाता है। इसमें पिछले वर्ष से 22.5 प्रतिशत वृद्धि के साथ पीएसपी प्रणाली में 87.02 लाख से अधिक पुलिस सत्यापन रिपोर्ट जमा की गई थी।

कुछ राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने लगातार पुलिस सत्यापन कार्रवाई का समय कम रखना कायम रखा है। उदाहरण के रूप में, नई प्रणाली के तहत, तेलंगाना ने औसतन 08 दिनों में पुलिस सत्यापन पूरा किए इसके बाद आंध्र प्रदेश (12 दिन), चंडीगढ़ (12 दिन), गोवा (12 दिन), दिल्ली (14 दिन), हरियाणा (15 दिन), गुजरात और पंजाब (17 दिन), उत्तर प्रदेश (20 दिन) और राजस्थान (21 दिन) रहे। हैदराबाद के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए 9 दिनों में पुलिस सत्यापन को पूरा किया जिसके बाद गोवा (12 दिन) विशाखापट्नम (12 दिन),

दिल्ली (15 दिन) तथा जलंधर (16 दिन) रहे। मंत्रालय द्वारा किए जा रहे लगातार प्रयासों के फलस्वरूप ज्यादा से ज्यादा जिले वांछित जिला पुलिस मुख्यालय सत्यापन मॉडल को अपना रहे हैं। अभी तक 731 पुलिस जिलों में से 683 ने 98.29 प्रतिशत पुलिस सत्यापन मात्रा को संभालते हुए नई प्रणाली को अपनाया है और वे जिला मॉडल पर कार्य कर रहे हैं।

मंत्रालय सेवा प्रदाता की सहायता से एक एनरॉइड उपधारित 'एम पासपोर्ट पुलिस एप' पर कार्य कर रहा है' जिसमें पासपोर्ट आवेदकों की निजी जानकारी तथा फोटोग्राफ ग्रहण करने की क्षमता होगी और जो इसे संबंधित हितधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतरित करेगा। यह एप पुलिस द्वारा स्थल पर जाकर किए गए सत्यापन की प्रामाणिकता को सुनिश्चित करते हुए 'गूगल मैप' के आधार पर आवेदक के आवास स्थान की पहुंच को भी ग्रहण करेगा। विकास एवं परीक्षण के बाद यह एप वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक प्रयोग हेतु उपलब्ध होगा।

न्यूनतम शासन अधिकतम सुशासन को साकार करने के लिए प्रकियाओं का कार्यात्मक वृद्धि करण/ सरलीकरण

- मार्च 2013 में एण्ड्रायड प्लैटफार्म पर शुरू हुए, एम–पासपोर्ट सेवा मोबाइल एप को अब विण्डोज और एप्पल आई ओ एस प्लैटफार्म पर भी उपलब्ध कराया गया है। प्रति दिन 15000 मोबाइल एप्लीकेशन हिट्स के साथ 31 दिसंबर, 2015 तक 13.7 लाख मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किए गए।
- अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी बचत पुस्तिका के अतिरिक्त अनुसूचित निजी क्षेत्र के भारतीय बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जारी फोटो बचत पुस्तिका को भी अब पासपोर्ट सेवा प्रदान करने के प्रयोजन हेतु पते और पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य किया जाएगा।
- परित्यक्त / अनाथ बच्चों को पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने के लिएए जन्म प्रमाण पत्र की स्वीकृति की आवश्यकताओं का उदारीकरण किया गया है।
- पासपोर्ट आवेदन पत्र के लिए सरकारी अधिकारियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता को भी उदार बनाया गया है।
- पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को अधिक सरल, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए आवेदक द्वारा जमा की गई आधार संख्या को एक पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में प्रमाणित करने के लिए यूआईडीएआई के ऑनलाइन एकीकरण को इस वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक आरंभ किया गया।
- नागरिकों की भावनाओं को समझने और सोशल मीडिया से निकलती जानकारी प्राप्त करने के लिए पासपोर्ट सेवा में ट्विटर, फेसबुक, फ्लिपकार्ट तथा यूट्यूब से इनपुट्स प्राप्त करने का प्रावधान है। प्रत्येक पासपोर्ट अधिकारी और सीपीवीए मुख्यालय के पास ट्विटर / फेसबुक का एकाउंट होता है और इसके बारे में नियमित रूप से शिकायतों को दूर किया जा सकता है।
- स्नातक छात्रों के लिए 'पासपोर्ट सेवामित्र' के तौर पर कार्य करने के लिए 4–8 सप्ताह एक गैर परिलब्धि की इंटर्नशिप योजना 8 जून 2015 से आरंभ की गई ताकि वे पासपोर्ट सेवा द्वारा ई–शासन, नागरिक केन्द्रित और सेवा उन्मुख अनुभव ले सकें। 22 इंटर्न ने अपनी इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूर्ण की है।
- माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुपालन में मंत्रालय ने'' 18 अगस्त 2015 को, पासपोर्ट प्रक्रिया के सरलीकरण, समरूप पुलिस सत्यापन और तकनीकी सुधार पर कार्यशाला'' आयोजित की। विदेश राज्य मंत्री, जनरल (डॉ) वी के सिंह (सेवानिवृत्त) द्वारा कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। कार्यशाला में मुख्य प्रतिभागियों में गृह मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, डीएआरपीजी, डाक विभाग, यूआईडीएआई, पुलिस महानिदेशक / 8 राज्यों से उनके प्रतिनिधिए संबंधित पासपोर्ट अधिकारी और सेवाप्रदाता प्रतिनिधि शामिल थे। अधिक प्रभावी एवं सुव्यवस्थित पासपोर्ट सेवा प्रदान करना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस कार्यशाला में तीव्र पुलिस सत्यापन की आवश्यकता आधार/यूआईडीएआई, आईवीईआरटी, सीसीटीएनएस, एनपीओ/एनआरआईसी तथा पैन कार्ड जैसे विभिन्न डाटाबेसों का पासपोर्ट सेवा प्रणाली के साथ एकीकरण, डाकघरों के माध्यम से पासपोर्ट आवेदनों का ऑनलाइन भरा जाना पासपोर्ट आवेदकों के सत्यापन में डाकिए की भूमिका तथा सामान्य सेवा केन्द्रों के व्यापक प्रसार पर विचार किया गया। तकनीकी और प्रक्रिया में सुधार अर्थात् एम–पासपोर्ट पुलिस एप, डिजि लॉकर, ई–साइन, ई–पासपोर्ट, उन्नत पासपोर्ट निजीकरण समाधान और विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों पासपोर्ट सेवा प्रणाली के साथ एकीकरण की भी चर्चा की गई थी।

पासपोर्ट मेला

पासपोर्ट सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 2015 की अवधि में पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा समय –समय पर सप्ताहांत/अवकाश के दिनों में 397 पासपोर्ट मेलों का आयोजन किया गया। इन मेलों में बढ़ाई गई कार्यविधि के दौरान 12.56 लाख पासपोर्ट आवेदनों पर सेवा प्रदान की गई थी।

पासपोर्ट सेवा शिविर

पासपोर्टों की बढ़ती मांग को पूरा करने और पी एस के से दूर रहने वाले व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से कई स्थानों पर पासपोर्ट सेवा शिविरों को आयोजित किया गया। देश भर में विभिन्न स्थानों पर अगरतला (त्रिपुरा), कोहिमा (नागालैंड), राजौरी (जम्मू–कश्मीर), श्री गंगानगर (राजस्थान), भुज (गुजरात), संबलपुर (ओडिशा), लक्षद्वीप, दमन एवं दीव और पुडुचेरी सहित, कश्मीर (लेह) से कन्याकुमारी (तमिलनाडु) तक देश के विभिन्न स्थानों पर वर्ष 2015 के दौरान 124 पासपोर्ट सेवा शिविर आयोजित किए गए। यह आईटी द्वारा संचालित सार्वजनिक सेवाओं को करीबी रूप से प्रदान करने का एक और नागरिक–केन्द्रित उपाय है जिसमें 51,000 से अधिक आवेदन प्राप्त किए गए हैं।

सामान्य सेवा केंद्र

विशेषतः दूरस्थ ग्रामीणों इलाकों में, डिजिटल डिवाइड की इस चुनौती का समाधान करने की दृष्टि से मंत्रालय ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रवर्तित मैसर्स सी एस सी इ–गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर 19 मार्च, 2014 को नागरिक केन्द्रित सेवाएं घर तक सुलभ कराने के उद्देश्य से एक लाख से अधिक सामान्य सेवा केन्द्रों (सी एस सी एस) के विशाल नेटवर्क के माध्यम से पासपोर्ट से संबंधित सेवा आवेदन ऑन लाइन भरने की शुरूआत की। इस पहल ने देश में डिजिटल डिवाइड को बड़े पैमाने पर कम किया है। पासपोर्ट संबंधी सेवाओं को उनके सेवा समुच्च के भाग के रूप में जोड़ा गया है। सी एस सी के माध्यम से पासपोर्ट आवेदन फार्म को भरने एवं अपलोड करने तथा प्रयोज्य शुल्क का भुगतान (डेबिट, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अथवा एस बी आई इंटरनेट बैंकिंग / चालान के माध्यम से) 100 रुपए से कम के सामान्य शुल्क पर पी एस के में मुलाकात के समय लेने को सुविधाजनक बनाया जाता है। पूरे सप्ताह तथा सप्ताहंत के दौरान सी एस सी के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध हैं। अप्रैल 2014 में सेवा की शुरुआत के बाद से 1,56,272 आवेदकों ने इन सेवाओं का इस्तेमाल किया है। विगत वर्ष के दौरान 1,19,000 आवेदनों को इन सीएससी पर ऑनलाइन जमा किया गया था।

विदेशों में पासपोर्ट सेवाएं

वर्ष 2015 के दौरान विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों ने 13.85 लाख पासपोर्ट एवं अन्य संबंधित सेवाएं प्रदान की हैं। दो देश मुख्यतः यू ए ई और सऊदी अरब ने विदेशों में कुल 35.11 प्रतिशत सेवाओं का योगदान दिया है (स्थानवार, दुबई, आबुधाबी, रियाद, जेद्दा, कुवैत, मस्कट, दोहा, बहरीन में 55.76 प्रतिशत सेवाएं दी गई)। पासपोर्ट सेवा के दृष्टिकोण से मुख्य 10 देश थे : यू ए ई, सऊदी अरब, अमेरिका, दोहा, कुवैत, मस्कट, सिंगापुर, कनाडा, यू.के. और बहरीन। उन्होंने संयुक्त रूप से विदेशों में कुल 77 प्रतिशत पासपोर्ट सेवाओं का योगदान दिया।

पुरस्कार तथा मान्यता :

इस परियोजना को सरकार में उच्चतम स्तर पर मान्यता मिली है। इसका दृष्टांत अध्ययन किया गया है और इसे अनेक पुरस्कार मिले हैं :

(i) 30 जनवरी 2015 को, पीएसपी को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, पीजी तथा पेंशन मंत्रालय (जनवरी 2015) द्वारा नागरिक केन्द्रित सेवा प्रदान करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ई–शासन वर्ष 2014.2015 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (गोल्ड अवार्ड) से सम्मानित किया गया।

(ii) 14 फरवरी 2015 को पीएसपी ने 'नागरिक सेवा वितरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन' श्रेणी के अंतर्गत एक्सप्रेस समूह ई–शासन पुरस्कार जीता।

(iii) 25 मार्च 2015 को पीएसपी ने वेब के माध्यम से ई–शासन प्रयासों में उत्कृष्टता के लिए 'नागरिक केन्द्रित सेवाओं' के तहत उत्कृष्ट सामग्री श्रेणी में पासपोर्ट सेवा पोर्टल के लिए वेब रत्न प्लेटिनम पुरस्कार जीता।

(iv) 20 मई 2015 को पासपोर्ट सेवा परियोजना (पीएसपी) ने तीनों व्यापक मान्यता प्राप्त आईएसओ मानकों अर्थात् आईएसओ 9001:2008, 20000:2011 और 27001:2013 के अंतर्गत प्रथम मिशन मोड ई–शासन परियोजना बनने की अनोखी विशिष्टिता अर्जित की।

(v) 18 अगस्त, 2015 में, श्री मुक्तेश कुमार परदेशी और श्री गोलोक लालकृष्ण सिमली ने सीआईओ लीडर व्यापार प्रभाव पुरस्कार 2015 प्राप्त किया।

(vi) 18 दिसंबर 2015 में पासपोर्ट सेवा परियोजना ने ज्वेल्स ऑफ इंडिया अवार्ड 2015 प्राप्त किया।

पासपोर्ट सेवा को तिहरा आईएसओ प्रमाणन दिया गया

पासपोर्ट सेवा दिवस और पासपोर्ट अधिकारी सम्मेलन

24 जून 2015 को विदेश सचिव ने पासपोर्ट अधिकारियों के तीन दिवसीय सम्मेलन और तीसरे पासपोर्ट सेवा दिवस का उद्घाटन किया, जो 24–26 जून 2015 के दौरान आयोजित किया गया था। सम्मेलन 2015 की कार्यसूची में पिछले वर्ष के दौरान पासपोर्ट सेवा प्रचालनों की समीक्षा और 2015–16 के दौरान अर्जित किए जाने वाले उद्देश्यों / लक्ष्यों को तय करना था। समापन समारोह का संबोधन विदेश मंत्री, श्रीमती सुषमा स्वराज ने दिया जिसमें जनरल (डॉ.) वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त), विदेश राज्य मंत्री उपस्थित थे। समारोह के दौरान पुलिस सत्यापन के लिए 'पासपोर्ट सेवा ई–बुक' और 'एम–पासपोर्ट पुलिस' मोबाइल एप्लीकेशन आरंभ किए। अपने कर्तव्यों के प्रति सच्ची निष्ठा दिखाने एवं नागरिकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले अधिकारियों को पासपोर्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए गए।

लोक शिकायत निवारण तंत्र

पासपोर्ट सेवा परियोजना (पीएसपी) के तहत मंत्रालय ने एक मजबूत लोक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित की है जिसमें बहुभाषीय राष्ट्रीय कॉल सेंटर सहित टॉल फ्री नंबर (1800–258–1800) है, जो 17 भाषाओं में 24×7 के आधार पर प्रचालित है। यह शिकायतों का निपटान तथा नागरिक फीडबैक सहित पासपोर्ट से संबंधित विभिन्न सेवाओं के बारे में सूचना के प्रसार का कार्य देखता है तथा यह फिलहाल केंद्रीय प्रणाली प्लेटफार्म पर कार्य करता है। वर्तमान में यह प्रतिदिन 20,000 कॉल का निपटान करता है (इसमें से 48 प्रतिशत हिंदी में तथा 23 प्रतिशत अंग्रेजी में)। पीएसपी के भाग के रूप में, एक पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पोर्टल (www.passportindia.gov.in) की रचना की गई है, जो अपडेशन के साथ सभी पासपोर्ट से संबंधित सेवाओं पर व्यापक और नवीनतम जानकारी, समय–समय पर जारी परामर्श/परिपत्र सहित विभिन्न नागरिक अनुकूल उपायों पर प्रदान करता है। इस पोर्टल में एक ई–मेल आधारित सहायता डेस्क भी है, जिसमें सुझाव और शिकायतों को दर्ज किया जा सकता है। नागरिक इस पोर्टल के माध्यम से अपने पासपोर्ट आवेदन / शिकायत की स्थिति की ऑनलाइन निगरानी कर सकते हैं।

संयुक्त सचिव (पासपोर्ट सेवा परियोजना) तथा मुख्य पासपोर्ट अधिकारी की निगरानी में सी पी वी प्रभाग में एक लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, जिन्हें मंत्रालय के लिए लोक शिकायत निदेशक के तौर पर भी नियुक्त किया गया है। यह आम जनता की ओर से दूरभाष, ई–मेल तथा डाक द्वारा प्राप्त

पासपोर्ट सेवा दिवस 2015 के अवसर पर पासपोर्ट सेवा ई–पुस्तक का लोकार्पण

शिकायतों का निपटान करता है और राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय मंत्रीमंडल सचिवालय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा संसद सचिवालय जैसे विभिन्न सरकारी कार्यालयों से प्राप्त संदर्भों का भी निपटान करता है। इसके अलावा, सभी पासपोर्ट कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन *(www.pgportal.gov.in)* मंत्रालय की वेबसाइट के केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण तथा निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएम) के माध्यम से लोक शिकायतों का निवारण करते हैं। वर्ष 2015 के दौरान 35,351 लोक शिकायत याचिका (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, शिकायतों / पूछताछ तथा सीपीजीआरएएम से संबंधित 16,605 ई–मेल डाक, फैक्स सहित) प्राप्त हुई थी, जिसमें से 34,475 मामलों का निपटान कर दिया गया है। उनके आवेदनों पर आगे की कार्रवाई के लिए निर्देशों सहित उनकी अद्यतन स्थिति दर्शाते हुए वेबसाइट पर पोस्ट कर दी जाती है, जिसे लोगों द्वारा उनके हित के लिए आसानी से देखा जा सकता है। पिछले 03 वर्षों के दौरान शिकायतों/फरियादों की संख्या में तेजी से कमी आई है।

सभी पासपोर्ट कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के वेबसाइट के केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण तथा निगरानी प्रणाली के माध्यम से लोक शिकायतों का निपटान करते हैं। आवेदकों की सहायता तथा उनकी शिकायतों का तीव्रता से निवारण करने के लिए पासपोर्ट कार्यालयों और पासपोर्ट सेवा केन्द्र में सूचना तथा सुविधा पटल, लोक शिकायत प्रकोष्ठ तथा हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। पासपोर्ट कार्यालयों तथा पासपोर्ट सेवा केन्द्रों में महत्वपूर्ण स्थानों पर शिकायत / सुझाव पेटियां संस्थापित की गई हैं। लोक शिकायत अधिकारी के नाम, पता तथा फोन नं. भी पासपोर्ट कार्यालय/पी एस के तथा पासपोर्ट कार्यालयों की वेबसाइटों में दर्शाए गए हैं। समय–सीमा के अंतर्गत नागरिकों से किसी शिकायत के विषय में पूछताछ करने तथा उसके निवारण के लिए सभी पासपोर्ट कार्यालयों में लोक शिकायत निवारण तंत्र है।

प्रधानमंत्री ने सरकार की महत्वाकांक्षी बहुउद्देश्यीय और बहुविध मंच, प्रगति (उन्मुख प्रशासन और समय पर क्रियान्वयन) के संबंध में 24 जून 2015 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में प्रणाली की पुनः इंजीनियरिंग और मजबूतीकरण के लिए सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से प्राप्त लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

पासपोर्ट अदालत एवं मेला

पासपोर्ट आवेदकों के शिकायतों के निवारण के लिए पासपोर्ट कार्यालय नियमित रूप से पासपोर्ट अदालतों का आयोजन करते हैं। वर्ष 2015 में आवेदकों के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से ये अदालतें, लगभग 7,000 पुराने तथा जटिल मामलों को सुलझाने में काफी सहायक रही हैं।

नागरिकों द्वारा मुलाकात का समय लेने में होने वाली समस्याओं को निपटाने के उद्देश्य से पासपोर्ट सेवाओं की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा समय–समय पर सप्ताहांत पासपोर्ट मेलों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2015 में विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा सप्ताहांत / अवकाश के दौरान समय–समय पर 397 पासपोर्ट मेलों (2014 में 384 मेलों की तुलना में) का आयोजन किया गया था, जिसमें 2.54 लाख पासपोर्ट आवेदनों पर कार्रवाई की गई।

हज यात्री : विशेष अभियान

यह मामला संतुष्टि का है कि, वर्ष 2015 में भावी हज यात्रियों को पासपोर्ट जारी करना सुचारू ढंग से पूरा किया गया था। 1,25,000 आवेदनों के आबंटित हज कोटा की तुलना में निर्धारित समय सीमा तक हज समिति ने लगभग 3 लाख आवेदन प्राप्त किए थे। सभी पासपोर्ट कार्यालयों को यह निर्देश जारी किए गए थे कि भावी हज आवेदकों के पासपोर्ट आवेदनों को उच्च प्राथमिकता दी जाए तथा नोडल अधिकारी की नियुक्ति करके; सहायता पटल शुरू करके, ऐसे आवेदकों के लिए मुलाकात के समय का स्लॉट आरक्षित करके उन्हें पासपोर्ट जारी करने के लिए शीघ्र अपेक्षित सहायता प्रदान की जाए तथा ऐसे नागरिकों से प्राप्त अनुरोधों/शिकायत याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई की जाए।

पासपोर्ट कार्यालयों का निरीक्षण

विभिन्न राज्यों के पासपोर्ट कार्यालयों का नियमित तौर पर निरीक्षण किया जाता है। इसके अलावा, इन कार्यालयों का सतर्कता निरीक्षण भी नियमित आधार पर किया जाता है। पासपोर्ट सेवा केन्द्र का भी गैर–तकनीकी सेवा स्तर के करारों (एसएलए) के तहत भी नियमित आधार पर निरीक्षण किया जाता है। वर्ष 2015 के दौरान, 35 से अधिक नियमित निरीक्षण / सतर्कता निरीक्षण / एसएलए निरीक्षण किए गए।

सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई)

आरटीआई के तहत आवेदकों को सूचना प्रदान करने के लिए प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय में एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। सीपीवी प्रभाग में भी एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। संयुक्त सचिव (पीएसपी) तथा सीपीवी सभी पासपोर्ट कार्यालयों तथा सीपीवी प्रभाग के संदर्भ में प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं। इस प्रभाग द्वारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 2015 की अवधि के दौरान कुल 7101 ऑनलाइन तथा डाक से प्राप्त आर टी आई आवेदनों का निपटान किया गया। (इसमें से 5893 आवेदनों को उनकी ओर से कार्रवाई के लिए आरपीओ को

भेजे गए तथा सीपीवी प्रभाग से 1208 आवेदनों का उत्तर दिया गया था) इसी अवधि के दौरान, 9995 डाक तथा ऑनलाइन प्रथम अपील प्राप्त किए गए थे तथा उनका निपटान भी कर दिया गया था।

अपील (पासपोर्ट अधिनियम की धारा 11 के तहत)

पी आई ए के निर्णयों के विरुद्ध अपील प्रभावित व्यक्तियों को पासपोर्ट अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रदत्त सांविधिक अधिकार है। वर्ष 2015 में, अप्रैल, अगस्त और अक्तूबर 2015 माहों में 3 अपील सत्र आयोजित हुए, जिसमें 105 अपीलकर्ताओं ने इन कार्यवाहियों में हिस्सा लिया। सुनवाई के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसरण में 140 सकारण आदेश जारी किए गए।

यात्रा दस्तावेज तैयार करना तथा इसे वैयक्तिक बनाना :

सभी भारतीय यात्रा दस्तावेज इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक द्वारा तैयार किए जाते हैं। भारतीय पासपोर्टों की समग्र गुणवत्ता, कार्यात्मकता तथा सुरक्षा में सुधार करने की दृष्टि से कई उपाय किए गए हैं। सभी पासपोर्ट कार्यालयों, मुख्यालय तथा विदेश स्थित चुनिंदा मिशनों/केन्द्रों में मशीन आधारित पठनीय पासपोर्ट प्रिंटर्स प्रदान किए गए हैं। मंत्रालय वर्तमान में "अगली पीढ़ी स्वचालित मशीन पठनीय पासपोर्ट निजीकरण प्रिंटर", की खरीद के लिए निविदा जारी करने के चरण में है जो अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) के विनिर्देशों के अनुसार है और पूरी तरह से ई–पासपोर्ट के निजीकरण का समर्थन करेगा।

विदेशों में स्थित 160 मिशनों/केन्द्रों और सहायक सचिव (पासपोर्ट) का कार्यालय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर के लिए मशीन पठनीय पासपोर्ट (एमआरपी) जिसमें अस्पष्ट छवि सुरक्षा फीचर शामिल हो, सीपीवी, नई दिल्ली प्रभाग के केन्द्रीय भारतीय पासपोर्ट मुद्रण प्रणाली (सीआईपीपीएस) में मुद्रित करवाए जाते हैं। सी आई पी पी एस ने 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसंबरए 2015 की अवधि के दौरान 1,78,101 पासपोर्ट मुद्रित करवाए (इनमें अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिए 4392 पासपोर्ट शामिल है)।

मशीन रीडेबल ट्रेवल डॉक्यूमेंट में बायोमेट्रिक डेटा शामिल करने के लिए आईसीएओ सिफारिशों के अनुरूप भारत में अपने मौजूदा पासपोर्ट को ई–पासपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में अद्यतन करने का भी निर्णय लिया है। ई–पासपोर्ट के माध्यम से फर्जी विधि तथा दस्तावेज में छेड़छाड़ के विरुद्ध अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। ई–पासपोर्ट के निर्माण के लिए इंडियन सिक्योरिटी प्रेस (आईएसपी) नासिक ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टेक्टलेस इनलेज के प्रापण हेतु एक वैश्विक पी क्यू बी की शुरूआत की है।

अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ)

भारत ने अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) के मशीन रीडेबल ट्रेवल डॉक्यूमेंट (एमआरटीडी) संबंधी तकनीकी सलाहकार समूह (टीएजी) के सदस्य के रूप में कार्य किया है और एमआरटीडी पर आईसीएओ दिशानिर्देशों को क्रियान्वित करता रहा है। आईसीएओ ने दस्तावेज 9303 के संबंध में नागर विमान सुरक्षा में सुधार लाने के लिए आईसीएओ के कार्यनीतिक उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक यात्रा दस्तावेजों हेतु, वैश्विक रूप से इन्टरऑपरेबल ई–पासपोर्ट सत्यापन स्कीम को बढ़ावा देने के लिए लागत साझेदारी आधार पर आईसीएओ पब्लिक की डायरेक्टी (पीकेडी) स्थापित की है। पीकेडी बोर्ड सदस्यों को पीकेडी सहभागी देशों द्वारा नामित किया जाता है और आईसीएओ परिषद् द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। भारत को फरवरी 2009 में आईसीएओ पीकेडी में प्रवेश मिला। संयुक्त सचिव (पीएसवी) एवं सीपीओ ने पीकेडी बोर्ड की 22वीं बैठक और एमआरटीडीएस, बायोमेट्रिक्स तथा सुरक्षा मानकों पर 10वीं संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी में 13–16 अक्तूबर 2015 की अवधि में भाग लिया। मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा 13–18 अप्रैल, 2015 की अवधि में सिंगापुर में आयोजित द्विवार्षिक व्यापार समारोह प्रथम 'इंटरपोल वर्ल्ड' में, 4–5 मार्च 2015 की अवधि के दौरान वैलिंगटन में 21वें पीकेडी बोर्ड की बैठक और 9–11 जून 2015 के बीच लंदन में नौवें सुरक्षा दस्तावेज विश्व (एसडीडब्ल्यू) सम्मेलन और प्रदर्शनी में प्रतिनिधित्व किया गया।

जनता को सूचित करने के उद्देश्य से एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया था कि अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) ने सभी नॉन मशीन रीडेबल पासपोर्ट (एमआरपीएस) को वैश्विक रूप से चरणबद्ध करने के लिए 24 नवंबर, 2015 की समय–सीमा निर्धारित की है। भारत सरकार ने 2001 से मशीन रीडेबल पासपोर्ट जारी करना प्रारंभ किया है। सभी नए भारतीय पासपोर्ट आईसीएओ–अनुपालनकारी एमआपी पासपोर्ट है। आईसीएओ द्वारा निर्धारित किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी पासपोर्ट मशीन– रीडेबल पासपोर्ट जारी करते हैं।

वैश्विक प्रविष्टि कार्यक्रम (जीईपी)

वैश्विक प्रविष्टि एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में आगमन पर पूर्व अनुमोदित, कम जोखिम वाले यात्रियों के लिए शीघ्र अनापत्ति अनुमति देता है। भारत ने 27 सितंबर 2013 को जारी भारत–अमेरिका संयुक्त वक्तव्य में अमेरिका के वैश्विक प्रविष्टि कार्यक्रम में भागीदारी के अमेरिका के प्रस्ताव का स्वागत किया। इस संबंध में, एक द्विपक्षीय भारत–अमेरिका बैठक सितंबर 2015 में वाशिंगटन में आयोजित की गई थी।

डिजिटल बनाने की परियोजना

भारतीय मिशनों/केन्द्रों में पासपोर्ट, वीजा, ओसीआई और पीआईओ आवेदनों के लिए ''इमेज पुनःप्राप्त करने वाले डेटाबेस का सृजन'' की परियोजना जून, 2012 में 3 विक्रेताओं के एक पैनल को दी गई थी। प्रथम चरण में कांसुलर दस्तावेजों को डिजिटल करने का कार्य 5 और द्वितीय चरण में अन्य 27 मिशनों / केन्द्रों में शुरू किया गया जिनमें से 26 मिशनों / केन्द्रों का कार्य पूर्ण हो गया है और वर्तमान कार्य 4 मिशन / पोस्ट में कार्याधीन है। 31 दिसंबर, 2015 तक लगभग 21 करोड़ वाणिज्य दूत दस्तावेजों को डिजिटल किया गया है।

आरपीओ/पीएसके में संसदीय समिति का दौरा

पासपोर्ट सेवाओं के संबंध में संसद के गहन रुचि की काफी संख्या में पीक्यू, और कई संसदीय समितियों द्वारा जांच एवं निरीक्षण/अध्ययन यात्राओं द्वारा पुष्टि की गई।

(क) राजभाषा संसदीय समिति की पहली उप–समिति ने विदेश मंत्रालय और उसके कार्यालय में राजभाषा के कार्यान्वयन पर समीक्षा के लिए प सपोर्ट कार्यालय गोवा (13 जनवरी 2015), रायपुर (19 फरवरी 2015) देहरादून (20 फरवरी 2015) सूरत (21 मार्च 2015) दिल्ली (23 मार्च 2015), गुवाहाटी (16 अप्रैल 2015) चंडीगढ़ (11 जून 2015), श्रीनगर (17 जून 2015) कोलकाता (13 जुलाई 2015), लखनऊ (15 जुलाई 2015), मुंबई (18 सितम्बर 2015), (24 सितंबर 2015) हैदराबाद का दौरा किया।

(ख) विदेश मंत्रालय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 06–10 जुलाई 2015 की अवधि के दौरान तिरुवनंतपुरम, गोवा और श्रीनगर में पासपोर्ट कार्यालयों का अध्ययन दौरा किया।

(ग) विदेश मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति के अधीन "पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली और भारतीय नागरिकों के लिए ई–पासपोर्ट परियोजना के कार्यान्वयन का प्रदर्शन" के विषय पर 30 जुलाई 2015 को अपनी बैठक का आयोजन किया।

सार्वजनिक आउटरीच

अपनी आउटरीच के विस्तार प्रदान करने के भाग के रूप में, सीपीवी प्रभाग एक अर्ध–वार्षिक सरकारी समाचार 'पासपोर्ट पत्रिका' निकल रहा है। कई पासपोर्ट कार्यालय में मीडिया रोड शो भी आयोजित किए गए जिसमें मीडिया को पासपोर्ट सेवाओं में सुधार के बारे में सूचित किया गया था।

वीजा

विदेश स्थित मिशनों / केन्द्रों द्वारा वीजा जारी करना

विदेश स्थित भारतीय मिशनों / केन्द्रों ने वर्ष 2015 में (5,17,413 ई–पर्यटक वीजा और 3,14,026 ओसीआई कार्ड सहित) में 4.79 मिलियन वीजा जारी किए हैं। मिशनों / केन्द्रों द्वारा वीजा जारी करने की प्रक्रिया को और सरल किया गया है, जिसमें जारी करने की प्रणाली को कम्प्यूकरीकृत करना और वीजा सेवाओं को आउटसोर्स करना जो 2006 में शुरू हुआ, शामिल है।

वीजा जारी करने की प्रक्रिया से जुड़े सुरक्षा माहौल को बढ़ाने के लिए सरकार ने वर्ष 2012 में भारत की यात्रा करने के लिए वीजा चाहने वाले विदेशियों के लिए आईवीएफआरटी (आप्रवासन, वीजा तथा विदेशियों का पंजीकरण एवं ट्रैकिंग) परियोजना के एक भाग के रूप में बायोमेट्रिक नामांकन प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। बायोमैट्रिक नामांकन प्रक्रिया में दस अंगुलियों के निशान तथा चेहरे की बायोमैट्रिक शामिल है। आईवीएफआरटी योजना 31 दिसंबर, 2015 को 163 भारतीय मिशनों/केन्द्रों में आरंभ की गई है, जिसमें से 77 मिशनों/केन्द्रों में बायोमेट्रिक्स नामांकन प्रक्रियाओं कार्यान्वित की जा रही है। इन प्रक्रियाओं में केवल 5 वर्षों में एक बार बायोमैट्रिक डेटा कैप्चर करने की परिकल्पना की गई है। बायोमैट्रिक नामांकन प्रक्रिया के साथ आईवीएफआरटी योजना के क्रियान्वयन से भारत आने वाले वास्तविक विदेशी सैलानियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के अलावा वीजा जारी तंत्र के सुरक्षा पहलुओं से जुड़े माहौल में सुधार होगा।

सी पी वी प्रभाग द्वारा वीजा जारी किया जाना

सी पी वी प्रभाग ने फरवरी से दिसंबर 2015 तक की अवधि के दौरान (केंद्रीकृत विदेशी पंजीकरण कार्यालय (सीएफआरओ) की एक नई ऑनलाइन प्रणाली को फरवरी 2015 में शुरू किया गया है) विदेशी राजनयिक तथा आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को 5561 वीजा जारी किए। सी पी वी प्रभाग ने वर्ष 2015 के दौरान स्थानांतरण तथा सरकारी कार्य से भारतीय मिशनों/केन्द्रों में कार्यभार ग्रहण करने जाने वाले भारतीय सरकारी अधिकारियों को 8870 वीजा नोट भी जारी किए।

भारतीय मिशनों / केन्द्रों द्वारा वीजा / कौंसुली/ पासपोर्ट कार्यों को आउटसोर्स किया जाना

मंत्रालय ने वर्ष 2006–07 के दौरान विदेश स्थित भारतीय मिशनों तथा केन्द्रों में वीजा सेवाओं की आउटसोर्सिंग शुरू की। तदुपरांत पासपोर्ट तथा कौंसुली सेवाओं का भी आउटसोर्स किया गया। वर्तमान स्थिति के अनुसार विदेश स्थित 67 भारतीय मिशनों / केन्द्रों ने पासपोर्ट / वीजा / वाणिज्य दूत सेवाओं तथा संग्रहण कार्य की आउटसोर्सिंग की है। आउटसोर्स करने का उद्देश्य आम

जनता को वीजा, पासपोर्ट तथा वाणिज्य दूत सेवाएं तत्काल एवं कारगर ढंग से उपलब्ध कराना है और इन सेवाओं के वितरण के लिए एक प्रदर्शन और सुलभ स्थान प्रदान किए गए।

ई–पर्यटक वीजा (ईटीवी)

टीवीओए– ईटीए योजना 27 नवंबर 2014 को शुरू किया गया था। इसे 15 अप्रैल 2015 से ई–पर्यटक वीजा (ईटीवी) का नया नाम दिया गया था। शुरू में यह 43 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध था और बाद में अधिक देशों के लिए बढ़ा दिया गया था। 31 दिसंबर 2015 की स्थिति के अनुसारए ई–टीवी योजना 113 देशों / क्षेत्रों के पासपोर्ट धारकों के लिए उपलब्ध है :

वित्त मंत्री ने 28 फरवरी 2015 को अपने बजट भाषण में घोषणा की है, कि इस योजना को एक वर्ष के अंदर 150 देशों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तदनुसार, ई–टीवी योजना अधिक से अधिक देशों में चरणबद्ध तरीके से सुविधा प्रदान करने के लिए विस्तार किया जा रहा है। वर्ष 2015 में कुल 5,17,413 ई–पर्यटक वीजा जारी किए गए थे।

विदेशी मिशनों के लिए वीजा का ऑनलाइन प्रसंस्करण (सीएफआरओ)

इससे पहले, सरकारी और राजनयिक वीजा आवेदकों को वीजा आवेदन सीपीवी प्रभाग में वास्तविक रूप में प्रस्तुत करने होते थे। सीएफआरओ प्रणाली द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रणाली का प्रसंसाधन और एकीकरण किया जाता है तथा इसके बाद विदेशियों के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा प्रयुक्त प्रणाली के साथ विदेशी मिशन के सदस्यों को शामिल किया जाता है। वर्ष 2015 में आरंभ इस प्रणाली के अंतर्गत विदेशी राजनयिक और उनके आश्रित अब http://indianvisaonline.gov.in /visa/ पर वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपनी तस्वीरें तथा अन्य सहायक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। जमा किए गए आवेदनों की संवीक्षा, सत्यापन और बीजा प्रदान करने का कार्य तीन स्तरों पर किया जाता है। सफलतापूर्वक आवेदनों को जमा करने की पावती ऑनलाइन दी जाती है और वीज़ा प्रदान करने की कार्रवाई की जाती है। जब वीज़ा तैयार हो जाता है तो ई–मेल या एसएमएस द्वारा एक संदेश भेजा जाता है। विदेशियों (राजनयिकों और गैर राजनयिकों) से संबंधित सभी डेटा अब आसान पहुंच/पुनः प्राप्ति के लिए एक ही डेटाबेस पर उपलब्ध हैं।

वीजा में छूट संबंधी करार

भारत ने 63 देशों के साथ वीजा में छूट संबंधी करार संपन्न किए हैं जिसके तहत राजनयिक / सरकारी पासपोर्टधारकों को वीजा की अपेक्षाओं से छूट दी जाती है। वर्ष 2015 में, वीजा छूट समझौतों पर अल्बानिया (27 नवम्बर 2015), क्यूबा (23 मार्च 2015), ग्वाटेमाला (28 मई 2015), मोरक्को (17 नवम्बर 2015), मोजाम्बिक (6 अगस्त 2015), पोलैंड (5 अक्टूबर 2015), श्रीलंका (14 मार्च 2015) स्वीडन (1 जून 2015) और ट्यूनीशिया (30 अप्रैल 2015) के साथ हस्ताक्षर किए गए थे। अन्य देशों के साथ इसी तरह के समझौते पर बातचीत चल रही है। एक वीजा सरलीकरण समझौते पर 18 दिसंबर 2015 को ईरान के साथ हस्ताक्षर किए गए थे।

साक्ष्यांकन और अपोस्टिल कन्वेंशन परियोजना

इस मंत्रालय के सी पी वी प्रभाग में साक्ष्यांकन प्रकोष्ठ बाहर के देशों में व्यक्तिगत तथा वाणिज्यिक प्रयोग के लिए लोगों के शैक्षिक, वाणिज्यिक तथा व्यक्तिगत दस्तावेजों के अभिप्रमाणन के लिए साक्ष्यांकन सेवाएं प्रदान करता रहा है। इसके अलावा भारतीय व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी विदेशों में निर्यात और साथ ही अन्य कारोबारी गतिविधियों के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा साक्ष्यांकित वाणिज्यिक दस्तावेजों की भी आवश्यकता होती है। अभिप्रमाणन दो प्रकार का होता है; सामान्य साक्ष्यांकन तथा अपोस्टिल प्रमाणन। अपोस्टिल प्रमाणन उन देशों में प्रयोग किए जाने वाले दस्तावेजों का किया जाता है जो हेग अपोस्टिल कन्वेंशन के सदस्य हैं।

यद्यपि सामान्य साक्ष्यांकन निःशुल्क है, अपोस्टिल स्टिकर लगाने के लिए मामलेवार पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से 50 रुपए प्रति दस्तावेज / प्रति पृष्ठ शुल्क लिया जाता है। विदेश मंत्रालय द्वारा साक्ष्यांकन / अपोस्टिल प्रमाणन के लिए दस्तावेजों के संग्रहण तथा आपूर्ति का कार्य जुलाई 2012 से दो वर्ष की अवधि के लिए 05 कंपनियों को आउटसोर्स किया गया है। ये कंपनियां प्रति दस्तावेज 22 रुपए (व्यक्तिगत), 18 रुपए (शैक्षिक) और 16 रुपए (वाणिज्य) का सेवा शुल्क लेती है।

जनवरी से दिसंबर 2015 की अवधि के लिए सी पी वी प्रभाग के साक्ष्यांकन प्रकोष्ठ ने 3,53,646 व्यक्तिगत दस्तावेजों और 1,74,878 वाणिज्यिक दस्तावेजों का साक्ष्यांकन किया और अपोस्टिल सदस्य देशों में प्रयोग के लिए 4,36,601, दस्तावेजों का अपोस्टिल प्रमाणन किया। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता तथा गुवाहाटी में चार विदेश मंत्रालय शाखा सचिवालय ने 34,724 दस्तावेजों का साक्ष्यांकन / अपोस्टल प्रमाणन किया गया। विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए कौंसुली दस्तावेजों का साक्ष्यांकन भारतीय मिशन / केन्द्र द्वारा भी किया जाता है।

कौंसुली मामले

प्रत्यर्पण तथा विधिक सहायता

विदेश मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद तथा संगठित अपराध की रोकथाम सहित वित्तीय धोखाधड़ी तथा मादक द्रव्यों की तस्करी से निपटने के लिए एक कानूनी तथा संस्थागत कार्य रूपरेखा की व्यवस्था करने हेतु द्विपक्षीय कौंसुली करारों पर बातचीत

करने के लिए विभिन्न देशों के साथ सक्रिय रूप से वार्ता करता रहा है। इन करारों में प्रत्यर्पण संधि, आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता संधि, असैनिक तथा वाणिज्यिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता संधि और सजा प्राप्त व्यक्तियों के स्थानांतरण संबंधी करार शामिल हैं

जनवरी से दिसम्बर 2015 के बीच की अवधि के दौरान भारत सरकार और थाइलैंड अधिराज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि के अनुसमर्थन दस्तावेज का 29 जून 2015 को माननीय विदेश मंत्री के दौरे के समय बैंकॉक में आदान प्रदान किया गया और भारत गणराज्य की सरकार तथा फिलिपिन्स गणराज्य सरकार के बीच प्रत्यर्पण संधि के अनुसमर्थन दस्तावेज का आदान प्रदान 14 अक्तूबर 2015 को नई दिल्ली में सचिव, विदेशी कार्य विभाग, फिलीपिन्स गणराज्य के दौरे के अवसर पर किया गया। भारत तथा ब्राजील के बीच 10 अप्रैल, 2008 को हस्ताक्षरित प्रत्यर्पण संधि के अनुसमर्थन दस्तावेजों का 21 जुलाई, 2015 को ब्राजील में हुई द्विपक्षीय कौंसुली वार्ता के उद्घाटन सत्र के दौरान आदान–प्रदान किया गया था। भारत और चीली के बीच स्वतंत्रता पूर्व प्रत्यर्पण संधि 1897 में ग्रेट ब्रिटेन और चिली द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जिन पर मई 2015 माह के दौरान प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 के तहत अधिसूचना जारी की गई।

वर्ष 2015 के दौरान भारत के पांच (5) प्रत्यर्पण अनुरोध (ब्रिटेन 2 और संयुक्त राज्य अमेरिका 2; चिली 1) प्राप्त हुए और सात (7) प्रत्यर्पण अनुरोध (हांगकांग 1; मॉरिशस 1; मोरक्को 1; स्पेन 1, संयुक्त राज्य अमेरिका 1 और यूएई 1) भेजे गए। इसके अलावा, भारत को यूएई से स्थानीय अभियोजन पक्ष के लिए 24 अनुरोध प्राप्त हुआ। भारत ने तीन (विदेशी देशों के लिए) 3 भगोड़ों का (ऑस्ट्रेलिया 1 और संयुक्त राज्य अमेरिका 2) प्रत्यर्पण किया और अन्य देशों से (ऑस्ट्रेलिया 1; बांग्लादेश 1; इंडोनेशिया 1; मोरक्को 1; मॉरिशस 1; थाईलैंड 2 और यूएसए 2) नौ (9) भगोड़ों को भारत को प्रत्यर्पित/निर्वासित किया गया।

प्रत्यर्पण वार्ता ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन और यूएई के साथ आयोजित की गई, जहां नीति और कार्यान्वयन मुद्दों के बकाया मामलों की समीक्षा के साथ–साथ चर्चा की गई।

कौंसुली मुद्दे

विश्व भर में 183 देशों में लगभग 28 मिलियन प्रवासी भारतीय रहते हैं। इनमें से लगभग 5 मिलियन लोग भारतीय पासपोर्ट धारी हैं। इन भारतीय नागरिकों में से अधिकांश अस्थायी प्रवासी है जिनमें महिला कामगार भी शामिल हैं और इनमें से 90 प्रतिशत कामगार खाड़ी क्षेत्रों में काम करते हैं। ये भारतीय कामगार अपने तथा भारत में अपने परिजनों के बेहतर जीवनयापन के लिए विदेश जाते हैं। हालांकि, एक बार विदेश पहुंचने पर उनके सामने कई प्रकार की समस्याएं आती हैं क्योंकि विदेश में काम करने तथा वहां के रहन–सहन की स्थिति उनकी उम्मीदों के अनुसार नहीं भी हो सकती है।

सी पी वी प्रभाग में कौंसुली अनुभाग का मुख्य सरोकार विदेशों में रहकर काम करने वाले भारतीय नागरिकों की देखभाल से संबंधित है। उपर्युक्त के अलावा कौंसुली प्रभाग भारत में गिरफ्तार किए गए विदेशियों तथा विदेशी मूल के लोगों की मौत के मामलों को देखता है जिनमें भारत में विदेशी राजनयिक मिशनों को कौंसुली सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान शामिल हैं। कौंसुली अनुभाग लापता भारतीय नागरिकों का पता लगाने तथा उनके कल्याण के लिए भी आम जनता की सहायता प्रदान करता है। कौंसुली अनुभाग द्वारा भारतीय मूल के लोगों द्वारा भारतीय बच्चों को गोद लेने, मृत भारतीय कामगारों के परिजनों को बकाया वेतनों तथा मृत्यु क्षतिपूर्ति के भुगतान, भारतीय कर्मी दलों के सदस्यों की गिरफ्तारी तथा भारतीय जहाजों को कब्जे में लिए जाने के संबंध में पोत परिवहन मंत्रालय के साथ संपर्क करने, विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 के तहत भारतीय नागरिकों के विवाह तथा तलाक संबंधी मामले, विदेशों में भारतीय नागरिकों के जन्म तथा मृत्यु के पंजीकरण संबंधी मुद्दे निपटाए जाते हैं।

विदेशों में भारतीय मिशन/केन्द्र विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदायों को समग्र रूप से समुदाय के अस्तित्व को प्रभावित करने वाले विभिन्न मामलों में निष्पक्ष तरीके से सलाह देते हैं तथा उनका मार्गदर्शन करते हैं। विदेशों में भारतीय नागरिकों के हित तथा कल्याण के संरक्षण हेतु भारत सरकार ने कई सदस्य देशों के साथ कौंसुली मामलों पर विभिन्न द्विपक्षीय कार्यसमूहों का गठन किया है। इसके अलावा, भारतीय मिशन/केन्द्र विभिन्न कौंसुली सेवाएं जैसे दस्तावेजों का साक्ष्यांकन, भारतीय नागरिकों के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण, भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर को भारत वापस भेजने की व्यवस्था करने, भारतीय नागरिकों के विवाह सम्पन्न कराने/पंजीकरण कराने, विदेशी जेलों में बंद भारतीय नागरिकों को कौंसुली सेवाएं सुलभ करवाने, भारतीय नागरिकों को भारतीय न्यायालय से सम्मन भेजने आदि कार्य करते हैं।

मदद कौंसुली शिकायत निगरानी प्रणाली

'सुशासन' की पहल के अनुसरण में विदेश मंत्रालय के विदेशी कौंसुली सहायता की आवश्यकता से भारतीयों के लिए मदद का हाथ बढ़ाने हेतु ''मदद'' नाम के एक वेब पोर्टल (ऑनलाइन वाणिज्य दूत शिकायत प्रबंधन प्रणाली) का शुभारंभ किया। विदेश स्थित सभी भारतीय मिशन और पोस्ट तथा विदेश मंत्रालय की चेन्नईए गुवाहाटी, हैदराबाद और कोलकाता में शाखा सचिवालय, कौंसुली संबंधी शिकायत पर नज़र रखने और अनुवर्तन के लिए इस पोर्टल के साथ जोड़े गए हैं। यह पोर्टल आधिकारिक तौर पर 21 फ़रवरी 2015 को शुरू किया गया था। मदद ऑनलाइन पोर्टल ऑनलाइन अग्रेषण, ट्रैकिंग और वृद्धि के माध्यम से कौंसुली शिकायतों से निपटने के लिए मौजूदा प्रक्रियाओं पर एक गुणात्मक सुधार का प्रतिनिधित्व करता है। यह पूरी शिकायत से निपटने की प्रक्रिया के बाद सार्वजनिक और प्रभावी ट्रैकिंग के सदस्यों द्वारा

शिकायतों के प्रत्यक्ष पंजीकरण की अनुमति देता है। मदद में कई अभिनव सुविधाओं को शामिल किया है जैसे विभिन्न शिकायतों पर कार्य करने हेतु लचीली संरचना आसान पुनर्प्राप्ति और संदर्भ के लिए एक प्रकार की शिकायतों, को जोड़ना और ऑनलाइन फाइलिंग करना प्राथमिकता में स्वतः वृद्धि एवं विस्तार, आसान आकलन और निगरानी के लिए, कलर–कोडेड डैश बोर्ड प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की मौजूदा सुविधाओं के साथ जोड़कर शिकायत करने वाले अशिक्षित लोगों को सहायता देने के लिए कॉल सेंटर के साथ संपर्क की अनुमति देना। मदद के लिए एक मोबाइल एप भी बनाया गया है

इसके अलावा, शिकायतकर्ताओं को इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने में सहायता के लिए गुड़गांव में प्रवासी कामगार संसाधन केंद्र (एडब्ल्यूआरसी) और दुबई में भारतीय कामगार संसाधन केंद्र (आईडब्ल्यूआरसी) को प्राधिकृत किया गया है। 31 दिसम्बर 2015 के अनुसार, मदद पोर्टल पर 4793 शिकायतों को पंजीकृत किया गया है, जिसमें से 3988 शिकायतों का समाधान किया गया है।

मदद पोर्टल की उपयोगिता एवं पहुंच को बढ़ाने के लिए कई नए मॉड्यूलों को इसमें शामिल किया जा रहा है। इनमें शामिल हैं :

(i) कैदियों का मॉड्यूल
(ii) भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) मॉड्यूल
(iii) सीपीसी वापसी मॉड्यूल
(iv) छात्र मॉड्यूल

इसके अलावा, राष्ट्रीयता सत्यापन के लिए विदेश मंत्रालय के द्वारा हमारे विदेश स्थित मिशनों / केन्द्रों और राज्य पुलिस प्राधिकरणों से जोड़ने के लिए एक अलग मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है।

द्विपक्षीय कौंसुली बैठकें

इस अवधि के दौरान निम्नलिखित देशों के साथ द्विपक्षीय कौंसुली वार्ताएं हुई : ऑस्ट्रेलिया (21 अक्टूबर 2015), ब्राजील (21 जुलाई 2015), चीन (19 अगस्त 2015), चेक गणराज्य (1 जून 2015), दक्षिण अफ्रीका (27 मार्च 2015), रूस (18 नवम्बर 2015), तुर्कमेनिस्तान (19 मई 2015) और संयुक्त राज्य अमेरिका (3 नवम्बर 2015)। इन बैठकों के दौरान कौंसुली, वीजा तथा पासपोर्ट संबंधी मामलों पर विचार–विमर्श किया गया।

माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा मदद का शुभारंभ

23 प्रवासी भारतीय कार्य

भारत, डायस्पोरा और प्रवास : एक अवलोकन

भारत के पास अनुमानतः 25 मिलियन का एक सशक्त प्रवासी भारतीय समुदाय है। इसकी प्रवासी आबादी के महत्व को देखते हुए इसके डायस्पोरा के साथ एक सतत और परस्पर लाभकारी संबद्धता के लिए एक संस्थागत ढांचा बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

भारतीय डायस्पोरा, जिसमें भारतीय मूल के लोग और अनिवासी भारतीय शामिल हैं, का निर्माण वाणिज्यवाद के कारण सैंकड़ों वर्षों से हो रहे प्रवास के अनेक दौर, उपनिवेशकाल में अनुबंधित मजदूरों की भर्ती, उत्तर औपनिवेशिक काल में अतिथि कार्य कार्यक्रमों; 20 वीं सदी में विकसित देशों में भारतीय पेशेवरों के प्रवास के कारण, ईसीआर देशों में अर्द्धकुशल भारतीय मजदूरों; और विदेशों में उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों में लगे भारतीय छात्रों के परिणामस्वरूप हुआ है।

इन प्रवासी प्रवाहों के परिणामस्वरूप भारतीय डायस्पोरा के विशाल समुदाय का निर्माण हुआ है जिसमें पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व एशिया, दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमरीका के उत्तरी भाग और करीबियाई द्वीपों में बसे भारतीय मूल के लोग शामिल हैं। भारतीय मूल के लोगों के ये अलग–अलग समुदाय और विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक मिल कर एक विशाल भारतीय डायस्पोरा का निर्माण करते हैं।

पिछले वर्ष में सरकार ने विदेशों में भारतीय डायस्पोरा के साथ नए संपर्क स्थापित करने के अपने दृष्टिकोण को जारी रखा। प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री के विदेश दौरों से विदेशी भारतीय समुदाय तक पहुंचने, भारत में जारी विकास और आर्थिक पहलों के बारे मे उन्हें जानकारी देने और भारत के विकास की कहानी में अपना योगदान देने के लिए उन्हें आमंत्रित करने का अवसर मिला है। भारतीय डायस्पोरा ने भारत में चल रहे प्रमुख कार्यक्रमों जैसे स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, मेक इन इंडिया और स्टार्ट अप इंडिया आदि के बारे में रूचि और उत्साह दर्शाया है।

विदेश मंत्रालय के साथ विलय

माननीय प्रधानमंत्री के अनुमोदन से प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय का विदेश मंत्रालय के साथ विलय कर दिया गया । भारतीय डायस्पोरा से संबंधित जारी कार्य में न्यूनतम व्यवधान हो, यह सुनिश्चित करते हुए दो मंत्रालयों का आसानी से विलय किया गया। यह विलय सरकार के न्यूनतम सरकार अधिकतम सुशासन के लक्ष्य के अनुरूप है। यह एक प्रशासनिक निर्णय है जोकि सुशासन की दिशा में एक अच्छा कदम है। इससे विदेश मंत्रालय भी भारतीय डायस्पोरा, विशेष रूप से विदेशी भारतीय कामगारों के लिए विभिन्न नीतियों, स्कीमों और कार्यक्रमों का बेहतर कार्यान्वयन कर सकेगा।

भारतीय डायस्पोरा के साथ संबद्धता

मंत्रालय अनेक कार्यक्रमों, उत्सवों और स्कीमों का आयोजन करता है जिससे यह दुनिया भर में फैले प्रवासी भारतीय समुदाय तक पहुंचता है। प्रवासी भारतीय समुदाय, खासतौर पर व्यथित भारतीयों और प्रवासी कामगारों के विभिन्न कमजोर और असुरक्षित वर्गों के कल्याण और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है।

प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी)

भारत को इसके विशाल प्रवासी समुदाय के साथ जोड़ने और उनके ज्ञान, विशेषज्ञता और कौशल को एक साझा मंच पर लाने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है जो कि डायस्पोरा से संपर्क का एक प्रमुख कार्यक्रम है और वर्ष 2003 से यह 7 से 9 जनवरी के बीच हर वर्ष मनाया जाता है। अब तक 14 पीबीडी मनाए गए हैं :

वर्ष	तारीख	स्थल
2003	9–11 जनवरी 2003	नई दिल्ली
2004	9–11 जनवरी 2004	नई दिल्ली
2005	7–9 जनवरी 2005	मुंबई

2006	7—9 जनवरी 2006	हैदराबाद
2007	7—9 जनवरी 2007	नई दिल्ली
2008	7—9 जनवरी 2008	नई दिल्ली
2009	7—9 जनवरी 2009	चेन्नई
2010	7—9 जनवरी 2010	नई दिल्ली
2011	7—9 जनवरी 2011	नई दिल्ली
2012	7—9 जनवरी 2012	जयपुर
2013	7—9 जनवरी 2013	कोची
2014	7—9 जनवरी 2014	नई दिल्ली
2015	7—9 जनवरी 2015	गांधीनगर
2016	9 जनवरी 2016	नई दिल्ली

पीबीडी में नया उत्साह भरने के लिए इस वर्ष से दो वर्षों में एक बार पीबीडी कनवेंशन का आयोजन किया जाएगा। बीच के वर्षो में हर महीने छोटे और अपेक्षाकृत अधिक संवादपरक पीबीडी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे ताकि हम अधिक संवादपरक तरीके से डायस्पोरा तक पहुंच सकें और उनके हित और सरोकार से संबंधित मुद्दों पर उनकी राय जान सकें।

तदनुसार 9 जनवरी 2016 को नई दिल्ली में 14 वां पीबीडी भारतीय मिशनों द्वारा दुनियाभर में एक संवादमूलक कार्यक्रम के रूप में मनाया गया। विदेश मंत्री ने माननीय विदेश राज्य मंत्री और सेवानिवृत्त माननीया प्रीति पटेल, यूनाइटेड किंगडम के रोजगार राज्य मंत्री और भारत में स्थित प्रमुख डायस्पोरा देशों के एचओएम सहित विशिष्ट अतिथियों और आमंत्रित व्यक्तियों की उपस्थिति में मुख्य बातों पर केंद्रित अभिभाषण दिया। विदेश मंत्री ने डायस्पोरा को भारत की सामाजिक और विकास प्रक्रिया में भाग लेने और भारत में अपने मूल स्थान के साथ अपने संबंध को नई ऊर्जा देने के लिए आमंत्रित किया। सेवानिवृत्त मान. प्रीति पटेल, यूनाइटेड किंगडम के रोजगार राज्य मंत्री जो कि विशिष्ट अतिथि थीं, ने यू.के. में भारतीय डायस्पोरा के योगदान को रेखांकित किया।

मुख्य संबोधन के बाद विदेश मंत्री ने लंदन, दुबई, क्वालालंपुर, पोर्ट लुई और सिंगापुर में भारतीय डायस्पोरा के साथ वीडियो कानफ्रेंस के जरिए बातचीत की। कई भारतीय मिशनों ने 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया और अपने संबंधित कार्यक्षेत्रों में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की।

प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार

प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार (पीबीएसए) भारत सरकार द्वारा अनिवासी भारतीयों, भारतीय मूल के लोगों या अनिवासी भारतीयों अथवा भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा स्थापित या चलाए जा रहे संगठन या संस्था जिसने निम्नलिखित में से किसी एक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है, को दिया जानेवाला सर्वोच्च्य सम्मान है:

(क) भारत के बारे में विदेशों में बेहतर समझ ;

(ख) भारत के लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप में समर्थन;

(ग) भारत, प्रवासी भारतीय समुदाय और उनके निवास के देश के साथ निकट संबंध का निर्माण ;

(घ) भारत अथवा विदेशों में सामाजिक और मानवीय कार्य;

(ड) स्थानीय भारतीय समुदाय का कल्याण ;

(च) परमार्थ और उदारतापूर्ण कार्य ;

(छ) अपने क्षेत्र में ख्याति या उत्कृष्ट कार्य, जिससे उसके निवास के देश में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है; अथवा

(ज) कौशल में उत्कृष्टता जिससे उस देश में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी हो (गैर पेशेवर कामगारों के लिए)।

पीबीएसए भारत के राष्ट्रपति द्वारा पीबीडी कनवेंशन के समापन पर दिया जाता है। अब तक 179 प्रवासी भारतीय सम्मान दिए जा चुके हैं। अगला पीबीएस पुरस्कार जनवरी 2017 में भारत में पीबीडी कनवेंशन में दिया जाएगा।

क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस

यह मंत्रालय उन देशों में क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करता है जहां डायस्पोरा आबादी काफी अधिक है और इसका मकसद उस डायस्पोरा से संपर्क स्थापित करना होता है जो भारत में पीबीडी में भाग लेने में सक्षम नहीं हैं। न्यूयार्क, सिंगापुर, द हेग, डर्बन, टोरंटो, मॉरीशस , सिडनी, लंदन और लॉस एंजिल्स में अब तक नौ आरपीबीडी आयोजित किए गए हैं।

नौंवा आरपीबीडी 14—15 नवंबर 2015 के दौरान लॉस एंजिल्स में मनाया गया जिसमें माननीय प्रवासी भारतीय कार्य राज्य मंत्री जनरल वी.के.सिंह भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे। इस समारोह का विषय था "भारतीय डायस्पोरा—भारत और अमेरिका के संबंधों में नए प्रतिमान को परिभाषित करना" । इस समारोह में लगभग 1,100 व्यक्तियों ने भाग लिया जिसमें डायस्पोरा के सदस्य, राज्य सरकार के अधिकारी, मीडिया, प्रतिष्ठित व्यक्ति आदि शामिल थे। इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना (एक मंत्री के नेतृत्व में), हरियाणा, झारखंड और केरल राज्यों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे।

आरपीबीडी के पूर्व 14 नवंबर 2015 को इंडियन डायस्पोरा बिजनेस सम्मेलन का आयोजन ओवरसीज इंडियन फैसिलेटशन सेंटर द्वारा किया गया था। महानिदेशक, सीआईआई के नेतृत्व में भारत से 35 सदस्यीय व्यवसाय शिष्टमंडल ने इस सम्मेलन में भाग लिया और बी2बी और बी2जी बैठकें की। ओआईएफसी ने 14 नवंबर 2015 को तीन पैनेल परिचर्चाएं भी आयोजित की जिसमें काफी अच्छी उपस्थिति थी।

भारत को जानो कार्यक्रम

भारत को जानो कार्यक्रम (केआईपी) का उद्देश्य 18—26 आयु वर्ग के भारतीय डायस्पोरा को देश द्वारा किए गए विकास और प्राप्त

उपलब्धियों के बारे में परिचित कराना और उन्हें अपने पूर्वजों की धरती के करीब लाना है। केआईपी भारतीय मूल के छात्रों और युवा प्रोफेशनल्स को भारत का भ्रमण करने, अपने विचारों, उम्मीदों और अनुभवों को साझा करने और समकालीन भारत के साथ निकटता से जुड़ने का अनोखा मंच प्रदान करता है। मंत्रालय ने अब तक 1053 प्रवासी भारतीय युवाओ की भागीदारी से 34 केआईपी का आयोजन किया है।

प्रतिभागियों का चयन विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों/पोस्ट्स से प्राप्त नामांकनों के आधार पर किया जाता है। उन्हें आतिथ्; प्रदान किया जाता है और अपने संबंधित दशों से भारत आने जाने के इकानॉमि क्लास के हवाई किराये के 90 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाती है।

33 वां केआईपी 29 जून से 19 जुलाई 2015 तक आयोजित किया गया जिसमें गोवा साझेदार राज्य था। इसमें फिजी, फ्रांस, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, त्रिनिदाद और टोबेगो के 38 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 34 वां केआईपी 17 अगस्त से 6 सितंबर 2015 तक आयोजित किया गया जिसमें पंजाब साझेदार राज्य था। कनाडा, फिजी, फ्रांस, इजराइल, मलेशिया, मॉरीशस, म्यांमार, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका ट्रिनिडाड़ और टोबेगो के 32 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

भारत अध्ययन कार्यक्रम

भारत अध्ययन कार्यक्रम प्रवासी युवाओं को भारत के इतिहास, विरासत, कला, संस्कृति, सामाजिक–राजनीतिक, आर्थिक विकास आदि की जानकारी प्राप्त करने हेतु एक भारतीय विश्वविद्यालय में अल्पावधि पाठ्यक्रम के लिए सक्षम बनाता है। भारत अध्ययन कार्यक्रम का उद्देश्य शैक्षिक अभिमुखीकरण और अनुसंधान है। रहनेए खाने–पीने और स्थानीय परिवहन की लागत तथा पाठ्यक्रम की फीस और इकॅानोमी क्लास के विमान भाडे का 90 प्रतिशत का खर्चा भारत सरकार वहन करेगी। चौथे भारत अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन 20 जनवरी से 20 फरवरी 2016 के दौरान सिम्बोसिस अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, पुणे में किया गया। फ्रांस, इजराइल, मलेशिया, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका (डर्बन), श्री लंका (कैण्डी), त्रिनिडाड और टोबेगो से 13 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया।

डायस्पोरा बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम

डायस्पोरा बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम की शुरूआत शैक्षणिक वर्ष 2006–07 में की गई थी ताकि भारतीय मूल के व्यक्तियों/अनिवासी भारतीय छात्रों को इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी, मानविकी/उदारीकृत कला, वाणिज्य, प्रबन्धन, पत्रकारिता, होटल प्रबंधन, कृषि/पशु पालन आदि में पूर्व स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रति वर्ष 4000 अमेरिकन डॉलर तक की 100 छात्रवृत्तियां प्रदान की जा सकें। स्कीम को एजुकेशनल कन्सलटेंट्स इंडिया लि. (एडसिल) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और यह भारतीय डायस्पोरा की पर्याप्त संख्या वाले 40 देशों में स्थित अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों/प्रवासी भारतीय नागरिकों के लिए खुली है। स्कीम की शुरूआत से अब तक कुल 770 उम्मीदवारों ने छात्रवृत्ति का लाभ उठाया है। जैसा कि, डायस्पोरा बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम में संशोधन किया जा रहा है अतः वर्ष 2015–16 के लिए एक वर्ष तक स्कीम बंद है। प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के बाद संशोधित स्कीम को कार्यान्वित किया जाएगा।

मूल निवास स्थान की खोज

मंत्रालय अक्तूबर, 2008 से 'मूल निवास स्थान की खोज' नामक एक स्कीम चला रहा है ताकि भारतीय मूल के लोगों की भारत में मूल स्थान की खोज करने में सहायता की जा सके। भारतीय मूल के जो लोग भारत में अपने मूल स्थान की खोज करना चाहते हैंए उन्हें 30000 रू. की फीस के साथ अपने निवास के देश में भारतीय मिशन/पोस्ट की मार्फत एक निर्धारित फार्म में आवेदन करना होता है। भारत में खोजे गए मूल निवास से जुड़े ब्यौरे अर्थात निकटवर्ती जीवित सम्बन्धी (सम्बन्धियों) का नाम; उनके पूर्वजों (पैतृक और मातृ पक्ष) का मूल स्थान और एक सम्भावित परिवार श्रृंखला से सम्बन्धित ब्यौरे आवेदक को उपलब्ध कराये जाते हैं। यदि प्रयास सफल नहीं होता है तो भारतीय मिशन आवेदक को 20,000 रूपये वापस करने के लिए प्राधिकृत है।

भारत को जानिए क्विज

प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2015 के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 'भारत को जानिए' शीर्षक वाले एक ऑनलाइन क्विज का आयोजन किया जाएगा ताकि प्रवासी बच्चों और युवाओं में भारत के बारे में जानकारी को बढ़ाया जा सके। प्रवासी भारतीय युवाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ इस मंत्रालय द्वारा इस क्विज की शुरूआत की गई। 14 दिसम्बर 2015 को क्वालिफाइंग राउण्ड खत्म हुआ। अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्तियों की प्रत्येक श्रेणी से 10–10 फाइनालिस्टों को नई दिल्ली में अंतिम चरण के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्तियों की प्रत्येक श्रेणी से 3–3 विजेताओं को मैडल और प्रमाण–पत्र से सम्मानित किया जाएगा। सभी फाइनालिस्टों को भारत को जानिए यात्रा पर ले जाया जाएगा ताकि उन्हें भारत के इतिहास, संस्कृति, आर्थिक और अन्य पहलूओं से परिचित करवाया जा सके।

प्रवासी भारतीय केन्द्र

भारतीय डायस्पोरा की क्रमागत उन्नति और उसकी उपलब्धियों की स्मृति के लिए प्रवासी भारतीय केन्द्र की स्थापना 95 करोड़ रू. की

अनुमानित लागत से चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में की जा रही है। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को टर्नकी कंसलटेंट एवं प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है। यह केन्द्र आने वाले समय में सभी प्रवासी भारतीयों के साथ और उनके बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विषयों पर परस्पर चर्चा करने का केन्द्र बिन्दु बनेगा। यह एक अनुसंधान और प्रलेखन केन्द्र के रूप में भी कार्य करेगा और इसमें एक स्थायी प्रदर्शनी होगी।

केन्द्र में अन्यों के अलावा पुस्तकालय/अनुसंधान केन्द्र, बैठक कक्ष, भारतीय संस्कृति केन्द, 350 सीटों की क्षमता वाला सभागार, स्थायी प्रदर्शनी स्थल, सभी सेवाओं से युक्त अतिथिगृह, बैंक्वेट हॉल और एक रेस्टोरेंट होंगे। यह परियोजना 1 मई, 2011 को शुरू हुई थी और वर्ष 2016 में इसके पूरा होने की संभावना है।

प्रवासी भारतीय नागरिकता (ओसीआई) स्कीम

भारतीय मूल के व्यक्तियों को उनकी मूल भूमि से जोड़ने के लिए सरकार की गहन वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करके प्रवासी भारतीय नागरिकता (ओसीआई) स्कीम को अगस्त 2005 में शुरू किया गया । ओसीआई स्कीम गृह मंत्रालय द्वारा संचालित है।

स्कीम, भारतीय मूल के सभी लोगों (पीआईओई), जो 26 जनवरी 1950 को अथवा उसके बाद भारत के नागरिक थे अथवा जो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बनने के पात्र थे और जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर अन्य देशों के नागरिक थे, को प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) के रूप में पंजीकृत करने का प्रावधान करती है। स्कीम भारतीय मूल के लोगों को प्रवासी भारतीय नागरिकता दस्तावेज, जिनमें प्रवासी भारतीय नागरिकता प्रमाण–पत्र और यूनिवर्सल वीजा स्टीकर शामिल हैं, जारी करने का प्रावधान करती है। यह स्कीम जनवरी 2006 से संचालन में है। जनवरी 2016 के अंत तक 20 लाख से अधिक भारतीय मूल के लोगों को ओसीआई के रूप में पंजीकृत किया गया था।

एक पंजीकृत प्रवासी भारतीय नागरिक को भारत भ्रमण के लिए बहु–आयामी प्रवेश, बहु–प्रयोजन, दीर्घावधि वीजा दिया जाता है और भारत में कितने भी समय तक ठहरने के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय में पंजीकरण कराने से छूट दी जाती है। ओसीआई कार्ड धारकों को उपलब्ध अन्य लाभों में शामिल हैं :– भारतीय बच्चों को अंतर्देशीय दत्तक बनाने के मामले में अनिवासी भारतीयों के बराबर समानता, घरेलू हवाई यात्रा भाड़ों में प्रभारों के मामले में अनिवासी भारतीयों के बराबर समानता, चॉर्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में कार्य करने के मामले में अनिवासी भारतीयों के बराबर समानता। यह कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा 22 जुलाई, 2014 को अधिसूचित ओसीआई व्यावसायिक अकाउंटेंट के नामांकन हेतु स्कीम में उल्लिखित शर्तों के आधार पर मान्य होगा। तथापि, प्रवासी भारतीय नागरिकता 'दोहरी नागरिकता' नहीं है। प्रवासी भारतीय नागरिकता में राजनीतिक अधिकार नहीं दिये जाते। प्रवासी भारतीय नागरिकता स्कीम से सम्बन्धित विस्तृत निर्देश और प्रक्रियाएं गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। नया पासपोर्ट जारी करने, व्यक्तिगत ब्यौरों अर्थात राष्ट्रीयता, नाम, पते/व्यवसाय आदि में परिवर्तन और ओसीआई पंजीकरण प्रमाण–पत्र/वीजा के खो जाने/नष्ट हो जाने के मामलों में, ओसीआई दस्तावेजों की अनुलिपि जारी करने से संबंधित अब एक ऑनलाइन ओसीआई विविध सेवा उपलब्ध है।

संसद द्वारा 10 मार्च, 2015 को एक नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2015 जारी किया गया है जिसके तहत 6 जनवरी, 2015 से मौजूदा पीआईओ कार्ड धारकों को प्रवासी भारतीय नागरिकता कार्ड धारक माना जाएगा। यह संशोधन अनिवासी भारतीयों के विदेशी नागरिकता वाले नाबालिग बच्चों और अनिवासी भारतीय/प्रवासी भारतीय नागरिकता कार्ड धारकों से संबंधित विदेशी पति/पत्नियों को प्रवासी भारतीय नागरिकता कार्ड प्राप्त करने का पात्र बनाता है। इसके अलावा चौथी पीढ़ी तक के भारतीय मूल के व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय नागरिकता पंजीकरण के लिए अनुमोदित किया गया है।

अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को मतदान का अधिकार

प्रवासी भारतीय पासपोर्ट धारकों को मतदान का अधिकार देने के लिए लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम, 2010 पारित किया गया। इस सम्बंध में 3 फरवरी, 2011 को अधिसूचना जारी की गई जो विदेशों में रह रहे भारतीयों को पासपोर्ट पर अंकित भारत में आवासीय पते के अनुसार मतदाता सूची में अपना नाम डलवाने का अधिकार देती है। विदेशों में रह रहे मतदाताओं को निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन सम्बंधित पंजीयन अधिकारी (आरओ) को भेजने की आवश्यकता है। नियमों के मुताबिक, आवेदकों को स्व–अभिप्रमाणित दस्तावेज भेजने की अनुमति है। भारतीय चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया की शुरूआत की है जो प्रवासी मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक मतपत्र के माध्यम से विदेश स्थित अपने निवास स्थान से ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देती है।

प्रवासी भारतीयों का भारत विकास प्रतिष्ठान

प्रवासी भारतीयों का भारत विकास प्रतिष्ठान (आईडीएफ –ओआई) एक गैर लाभकारी ट्रस्ट है जिसकी स्थापना प्रवासी भारतीयों को भारत में सामाजिक और विकास परियोजनाओं के साथ संबद्ध करने के लिए की गई है। इस ट्रस्ट को विदेशी योगदान विनियम अधिनियम (एफसीआरए) 2010 के प्रावधानों से छूट है।

आईडीएफ–ओआई बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा शासित है जिसकी अध्यक्षा श्रीमती सुषमा स्वराज, माननीय विदेश और प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री हैं। बोर्ड के अन्य सदस्यों में प्रख्यात प्रवासी भारतीय और जाने–माने भारतीय जिनकी रूचि परोपकार में है ; गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और नीति आयोग से भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

आईडीएफ–ओआई के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज् जिसकी क्रमशः मई और दिसंबर 2015 में दो बैठकें हुईं, ने आईडीएफ–ओआई को नया अधिदेश दिया जिसके तहत आईडीएफ–ओआई अब प्रवासी भारतीयों से प्राप्त योगदान को सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों– राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता मिशन; स्वच्छ भारत मिशन, और राज्य सरकार की प्रमुख सामाजिक और विकास परियोजनाओं में लगा रहा है।

आईडीएफ–ओआई ने संयुक्त अरब अमीरात में 15–16 अक्तूबर 2015 को एक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया जिसका नेतृत्व सचिव, एमओआईए और उपाध्यक्ष, आईडीएफ–ओआई द्वारा किया गया और भारतीय समुदाय को आईडीएफ–ओआई के माध्यम से भारत को अपना योगदान देने के लिए आमंत्रित किया गया। आईडीएफ–ओआई ने लॉस एंजिल्स, यूएसए में 14–15 नवंबर 2015 को क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस में भाग लिया और 15 नवंबर 2015 को एक प्रस्तुतीकरण दिया।

प्रवासी भारतीय सुविधा केंद्र

प्रवासी भारतीय सुविधा केंद्र (ओआईएफसी) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की साझेदारी में वर्ष 2007 में स्थापित एक गैर लाभकारी ट्रस्ट है जिसका उद्देश्य भारत के साथ भारतीय डायस्पोरा के आर्थिक और ज्ञान संबंधी संपर्क को बढ़ाना है। इसके साझेदार के रूप में राज्य सरकारों और ज्ञानक्षेत्र विशेषज्ञों के नेटवर्क द्वारा समर्थित ओआईएफसी प्रवासी भारतीय व्यवसाय और निवेश संबंधी सूचना प्रदान करता है; डायस्पोरा संपर्क सम्मेलनों (बी2बी और बी2जी बैठकों का आयोजन करता है। ओआईएफसी प्रख्यात प्रवासी भारतीयों, सरकार के वरिष्ठ नीति निर्माताओं और उद्योग प्रमुखों की परिषद द्वारा शासित है।

भारतीय डायस्पोरा खासतौर पर युवा प्रवासी भारतीयों के साथ अग्रसक्रिय और स्थायी संबंध स्थापित करने के लिए ओआईएफसी ने निम्नलिखित इंडिया कनेक्ट पहल और कार्यक्रम आरंभ किए है :

- **बिजनेस कनेक्ट** : प्रवासी भारतीयों के नेतृत्व में व्यवसाय शिष्टमंडलों के भारत दौरे को सुगम बनाना और उन्हें भारत में व्यवसाय साझेदारों और हितधारकों के साथ कनेक्ट करना।
- **इंडिया कार्पोरेट इंटर्नशिप्स** : विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रबंधन, इंजीनियरिंग , विज्ञान और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में पढ़ रहे भारतीय मूल/वंशज के छात्रों को अवसर प्रदान करने के लिए समर 2016 से 23 भारतीय कार्पोरेट्स में 60 से अधिक अल्पकालिक प्रशिक्षण।
- **इंडिया फेलोज् प्रोग्राम** : 'भारत में व्यवसाय किस प्रकार किया जाए', इस बारे में इंडियन स्कूल आफ बिजनेस के सहयोग से युवा डायस्पोरा उद्यमियों के लिए समर 2016 से एक वर्ष का एक उपयुक्त अनुबंध करता है।
- **भारतीय डायस्पोरा व्यवसाय सम्मेलन,17 अक्तूबर 2015, दुबई, यूएई** : ओआईएफसी के संरक्षण में भारत से 16 सदस्यों के एकबिजनेंस शिष्ट मंडल ने भारतीय मूल/एनआरआई व्यवसायियों और निवेशकों के साथ व्यवसाय बेठक में भाग लिया।

14–15 नवम्बर, 2015 को लॉस एंजिल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस के एक भाग के रूप में, प्रवासी भारतीय सुविधा केन्द्र ने भारत के 31 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया जिसमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, केरल और तेलंगाना की राज्य सरकारें शामिल थी, उन्होंने तीन पैनल विचार–विमर्श में भाग लिया और भारतीय मूल के व्यापार और निवेशक समुदाय के साथ बी2बी और बी2जी बैठके की।

उत्प्रवास में रुझान

वर्ष 2015 के दौरान, लगभग 7.81 लाख कामगारों ने उत्प्रवास स्वीकृति प्राप्त करने के बाद भारत से उत्प्रवास किया। इनमें से लगभग 3.06 लाख कामगार सऊदी अरब में, लगभग 2.25 लाख कामगार यूएई में, लगभग 0.59 लाख कतर में, लगभग 0.85 लाख ओमान में तथा लगभग 0.21 लाख मलेशिया में गए। उत्प्रवासियों की संख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और केरल प्रमुख स्रोत राज्य थे, जहां से उत्प्रवास हुआ।

उत्प्रवासित कामगारों की संख्या (संख्या लाख में)

		वर्ष-2015
1	सउदी अरब	3.06
2	यू.ए.ई.	2.25
3	कतर	0.59
4	ओमान	0.85
5	मलेशिया	0.21
6	अन्य	0.85
	कुल	**7.81**

उत्प्रवास संरक्षी कार्यालयों द्वारा प्रदान की गई उत्प्रवास स्वीकृतियों की वर्ष वार अवस्थिति निम्नानुसार है :–

वर्ष	2010	2011	2012	2013	2014	2015
उत्प्रवास संरक्षी द्वारा प्रदान की गई उत्प्रवास स्वीकृतियों की संख्या (लाख में)	6.41	6.27	7.47	8.17	8.05	7.81

भारतीय नागरिकों का विदेशी रोजगार

उत्प्रवास अधिनियम, 1983 जो 30 दिसम्बर, 1983 को प्रभावी हुआ था, में भारत के सर्वोच्च न्यायालय और इसके 20.03.1979 के फैसले और आदेश (कांगा बनाम भारतीय संघ और अन्य) द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिकाएं निहित हैं और यह प्रवासी रोजगार के लिए भारतीय कामगारों के उत्प्रवास के संबंध में विनियमनकारी संरचना प्रदान करता है और उनके हितों को सुरक्षित रखता है और उनके संरक्षण और कल्याण को सुनिश्चित करता है।

उत्प्रवास से संबंधित संचालनात्मक मामलें, उत्प्रवासियों के उत्प्रवास सेवा प्रावधान और उत्प्रवास अधिनियम, 1983 को लागू करना उत्प्रवास महासंरक्षी (पीजीई) द्वारा उत्प्रवास संरक्षी के 10 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। उत्प्रवास महासंरक्षी, उत्प्रवास अधिनियम के अन्तर्गत उत्प्रवासी कामगारों जो ईसीआर श्रेणी में आते हैं, के संरक्षण और कल्याण के लिए उत्तरदायी सांविधिक प्राधिकारी हैं।

उत्प्रवास महासंरक्षी, उत्प्रवास अधिनियम, 1983 को प्रशासित करते हैं। वह चंडीगढ़, चैन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, राय बरेली और तिरूवंनतपुरम में स्थित उत्प्रवास संरक्षियों के 10 क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रशासित करते हैं। राय बरेली कार्यालय वर्ष 2013 में खोला गया था।

ई–माइग्रेट : एक ई–गवर्नेंस परियोजना

ई–माइग्रेट एक ई–गवर्नेंस परियोजना है जो रोजगार के उद्देश्य से अधिसूचित देशों को जाने वाले ईसीआर श्रेणी के उत्प्रवासियों के उत्प्रवास को सुविधाजनक बनाती है। एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ई–माइग्रेट, सुप्रवाही और कुशल उत्प्रवास को सक्षम बनाती है जो पंजीकृत किए जा रहे ईसीआर श्रेणी के कामगारों के पासपोर्ट ब्यौरों के सत्यापन हेतु पासपोर्ट सेवा परियोजना से एकीकृत की गई है। यह उत्प्रवासियों, मिशनों, भर्ती एजेंटों, विदेशी नियोक्ताओं और बीमा एजेंसियों के संबंध में एक व्यापक और ऑनलाइन डाटाबेस प्रदान करती है।

उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (धारा 10) के अंतर्गत यह आवश्यक है कि जो व्यक्ति काम की श्रेणियों के लिए विदेशों में रोजगार के लिए भारतीय नागरिकों की भर्ती करना चाहते हैं, उन्हें स्वयं को पंजीकरण प्राधिकरण, अर्थात उत्प्रवास महासंरक्षी (पीजीई) के पास पंजीकृत कराना होगा। पंजीकरण के लिए निर्धारित शुल्क नियम (7) (2) के अंतर्गत 25,000/–रुपये है। आरंभ में पंजीकरण प्रमाण–पत्र 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है। भर्ती एजेंट के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन हेतु फॉर्म उत्प्रवास महासंरक्षी के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है और इसे वेबसाइट **emigrate.gov.in** से डाउनलोड भी किया जा सकता है। पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रदान करने हेतु योग्य पाये जाने पर आवेदक को 50 लाख रूपये की बैंक गारंटी जमा करानी होती है। पंजीकरण प्रमाण–पत्र को जारी करने और इसका नवीकरण करने हेतु जमा की जाने वाली बैंक गारंटी को विदेश मंत्रालय और प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों पर 20 लाख रू. से बढ़ाकर 50 लाख रू. कर दिया गया है।

प्रवर्तन और शिकायत निवारण

प्रवासी भारतीय कामगारों के शोषण के बारे में शिकायतें मिलती रहती हैं जो मजदूरी न दिए जाने/देर से दिए जाने, कामगारों की संविदाओं में एकतरफा बदलाव तथा मनमाने तरीके से नौकरियाँ बदलने इत्यादि के बारे में होती हैं। ऐसे मामलों में, उत्प्रवासी महासंरक्षी (पीजीई) संबंधित भर्ती एजेंट (यदि कामगार की भर्ती एजेंट द्वारा की गई हो तो) से उनके ही खर्चे पर इन कामगारों को स्वदेश वापस भिजवाने के लिए कहता है। यदि भर्ती एजेंट ऐसा नहीं करता है तो उसका पंजीकरण निलम्बित/रद्द करने और उसकी बैंक गारंटी जब्त करने के लिए कार्रवाई शुरू की जाती है, ताकि उस राशि में से स्वदेश वापसी का खर्च वहन किया जा सके। विदेश स्थित भारतीय मिशन और कांसुलेट भी शिकायतों पर संबंधित विदेशी नियोक्ता/प्रायोजक या विदेशी सरकार के साथ विचार–विमर्श करके ऐसे मामलों का समाधान करते हैं।

उत्प्रवासियों का संरक्षण एवं कल्याण

सभी उत्प्रवासी कामगारों में घरेलू नौकरानियां और अप्रशिक्षित कामगार बहुत ही संवेदनशील श्रेणियों में आते हैं। उनके शोषण को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

(क) ईसीआर पासपोर्टो पर ईसीआर देशों में उत्प्रवास करने वाली सभी महिला उत्प्रवासियों के संबंध में 30 वर्ष की आयु सीमा को अनिवार्य बनाया गया है चाहे उनके रोजगार का स्वरूप/श्रेणी कुछ भी हो।

(ख) यदि कोई विदेशी नियोक्ता किसी कामगार को सीधे रूप में भर्ती करता है तो उसके द्वारा 2500 डालर सिक्यूरिटी के रूप में जमा करवाना अपेक्षित है।

(ग) सभी ईसीआर देशों के मामले में सभी महिलाओं और

अप्रशिक्षित श्रेणी के कामगारों के संबंध में दूतावास से अनुप्रमाणन अनिवार्य किया गया है।

(घ) उत्प्रवास (संशोधन) नियमों के अंतर्गत उत्प्रवासी कामगार के हितों की सुरक्षा के लिए भर्ती एजेन्टों को कुछ विशेष कर्त्तव्य और दायित्व सौंपे गए हैं उन्हें कुछ बुनियादी सुविधाओं का रखरखाव भी करना होगा।

(ङ) उत्प्रवासियों के हितों की सुरक्षा करने के उद्देश्य से नियमों के तहत विदेशी नियोक्ताओं के लिए कुछ विशेष कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं।

(च) जून 2015 से विदेशी नियोक्ता का ई–माइग्रेट प्रणाली में पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।

प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई)

प्रवासी भारतीय बीमा योजना मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक बीमा स्कीम है जिसके अंतर्गत प्रवासी भारतीय बीमा योजना नीति 2008 के तहत कवरेज और लाभ निम्नानुसार हैं :

i) प्रवासी भारतीय बीमा योजना के तहत अधिकतम बीमा राशि जिसके लिए बीमा किया जाएगा, 10 लाख रू. है।

ii) हास्पीटेलाइजेशन (मैडिकल व्यय) जिनके तहत चोट लगने या घायल होने/बीमारी/रोग/विकृत बीमारी कवर होंगी, इस प्रायोजनार्थ बीमा राशि 75000 रू. है।

iii) स्वदेश वापसी में मैडिकल रूप से अनफिट होने को भी कवर किया है, हवाई जहाज द्वारा एक तरफा इक्नामी क्लास हवाई शुल्क की पूर्ति।

iv) भारत में पारिवारिक हास्पीटेलाइजेशन हेतु 50,000 रू. का प्रावधान।

v) मेटरनिटी के लिए 25000 रू.।

vi) अटेन्डेंट के लिए एक तरफा इक्नामी क्लास का हवाई शुल्क।

vii) विधिक व्यय : 30,000 रू. ।

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना (एम जी पी एस वाई)

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना ई.सी.आर देशों में काम कर रहे ई.सी.आर पासपोर्ट धारक अकुशल और अर्धकुशल प्रवासी भारतीय कामगारों के लिए एक विशेष रूप से तैयार की गई सामाजिक सुरक्षा स्कीम है। महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना प्रवासी भारतीय कामगारों को निम्नलिखित के लिए प्रोत्साहित करती है और सक्षम बनाती है :–

(क) भारत में वापसी और पुनर्वास के लिए बचत करने,

(ख) उनकी पेंशन के लिए बचत करने,

(ग) प्रवासी रोजगार की अवधि के दौरान कंपलीमेंटरी जीवन बीमा कवर प्राप्त करने के लिए।

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना बाजार में तीन मौजूदा स्कीमों की पेशकश करती है जो कि निम्नानुसार हैं :–

(क) राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (एन. पी. एस) लाइट (एनपीएस–लाइट को बंद कर दिया गया है और इसके स्थान पर 1 जून, 2015 को अटल पेंशन योजना शुरू की गई है)

(ख) यू.टी.आई की मासिक आय योजना (म्युचुअल फंड) और

(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम की आम आदमी बीमा योजना

श्रम पर द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन

भारतीय कामगारों की बेहतर सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सउदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान, मलेशिया और बहरीन के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

समय–समय पर उठने वाले श्रम विवादों की समीक्षा और उनके समाधान को संयुक्त कार्य दल की नियमित बैठकों द्वारा सुविधाजनक बनाया जाता है। कतर के साथ संयुक्त कार्य दल की तीसरी बैठक का आयोजन दिनांक 17–18 अगस्त, 2015 को हुआ। बहरीन के साथ दूसरी संयुक्त कार्य दल बैठक का आयोजन दिनांक 15–16 अप्रैल, 2015 के दौरान हुआ। सउदी अरब अधिराज्य के साथ दूसरी संयुक्त कार्य दल की बैठक का आयोजन दिनांक 12–13 अक्तूबर, 2015 के दौरान हुआ।

विदेश स्थित भारतीय नागरिकों का कल्याण और संरक्षण

भारतीय समुदाय कल्याण कोष

भारतीय मिशनों/पोस्टों में भारतीय समुदाय कल्याण कोष की स्थापना की गई है ताकि मिशन मीन्स टेस्टेड बेसिस पर व्यथित प्रवासी भारतीय नागरिकों के यथास्थान कल्याण कार्यकलापों के लिए मिशन द्वारा उपगत आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए उन्हें सक्षम बनाया जाए। भारतीय समुदाय कल्याण कोष के अंतर्गत, हाउसहोल्ड/घरेलू क्षेत्रों में व्यथित प्रवासी भारतीय कामगारों तथा अकुशल श्रमिकों को आवास और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराने, आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना, प्रारंभिक कानूनी सहायता प्रदान करने, जरूरतमंद असहाय प्रवासी भारतीयों को हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करने, मृतक प्रवासी भारतीयों के पार्थिव शरीर को विमान द्वारा भारत लाने या स्थानीय दाह संस्कार/दफन जैसी आकस्मिकताओं पर होने वाले व्यय को वहन करने, मेजबान देश में गैरकानूनी रूप से रूकने के

लिए भारतीय नागरिकों के मामलें में जुर्माने की अदायगी करना जहां कामगार प्रथम दृष्टया दोषी न हो, जेल में/करावास केन्द्रों में बंद भारतीय नागरिकों की रिहाई हेतु छोटे अर्थदंड/जुर्माने का भुगतान करने आदि से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।

असहाय भारतीयों का देश प्रत्यावर्तन

मार्च–अप्रैल 2015 के दौरान लगभग 4012 भारतीयों को यमन से देश वापस लाया गया। व्यापक और सुसमन्वित प्रत्यावर्तन आपरेशन खासतौर पर भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए सरकार की शीघ्र और अग्रसक्रिय कार्रवाई की सराहना की गई।

आईसीडब्ल्यूएफ ने भारतीय पर्वतारोही श्री मल्ली मस्तान बाबू के अवशेषों की खोज और प्राप्ति को सक्षम बनाया जो चिली और अर्जेंटीना के बीच पर्वत श्रृंखला में खो गए। सेशेल्स से 19 भारतीय मछुआरों को भारत में प्रत्यावर्तित किया गया।

प्रवासी कामगार संसाधन केंद्र

आप्रवासियों और इच्छुक आप्रवासियों को सूचना प्रदान करने और विदेश में नियोजन के लिए वैध कार्य परमिट/ वीजा प्राप्त करने की अपेक्षाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने 2008 में प्रवासी कामगार संसाधन केंद्र (ओडब्ल्यूआरसी) स्थापित किया ताकि इच्छुक प्रवासियों और प्रवासी कामगारों को विदेशों में नियोजन के सभी पहलूओं की जानकारी दी जा सके।

ओडब्ल्यूआरसी आप्रवास संबंधी सूचना का प्रसार करता है; विदेशों में रोजगार और भारतीयों को पेश आने वाली समस्याओं संबंधी शिकायतों को दर्ज और कार्रवाई करता है।

ओडब्ल्यूआरसी आप्रवासियों और उनके परिवारों को वर्ष के सभी दिनों के दौरान 24 घंटे हेल्पलाइन (1800 11 3090) पर 11 भाषाओं (हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, मलयालम, तेलगू, तमिल, बंगाली, गुजराती, उड़िया, मराठी और पंजाबी) में निःशुल्क आवश्यकता आधारित सूचना प्रदान करता है। कामगार दुनिया में कहीं से भी 91–11–40503090 पर हेल्पलाइन की सुविधा ले सकते हैं। 2015 में ओडब्ल्यूआरसी को इच्छुक प्रवासियों और परेशानी में फंसे भारतीयों से 62,175 कॉल्स प्राप्त हुए।

प्रवासी संसाधन केंद्र

मंत्रालय ने डायस्पोरा भेजने वाले प्रमुख राज्यों में वॉक इन परामर्श केंद्रों के रूप में इच्छुक प्रवासियों और प्रवासी भारतीय कामगारों को विधिक और विनियामक अपेक्षाओं, प्रलेखन और प्रक्रियाओं, नीतियों, और विदेशों में काम करने में आनेवाली समस्याओं आदि सहित विदेशों में नियोजन के सभी पहलूओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए प्रवासी संसाधन केंद्र (एमआरसी) स्थापित किया है। एमआरसी पांच स्थानों यथा कोची, हैदराबाद, गुड़गांव, चेन्नई और लखनऊ में स्थापित किए गए हैं। जून 2015 में मंत्रालय और तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में प्रवासी संसाधन केंद्र (एमआरसी) स्थापित किया। 10 फरवरी 2015 को लखनऊ में एमआरसी का उद्घाटन किया गया।

एनआरआई पतियों द्वारा छोड़ी/ तलाकशुदा भारतीय महिलाएं

अपने विदेशी पतियों द्वारा छोड़ी गई भारतीय महिलाओं को विधिक/वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालय ने 2007 में एक स्कीम की शुरुआत की। यह यूएसए, यूके, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और कुछ खाड़ी देशों में भारतीय मिशनों/पोस्टों के पैनेल पर भारतीय महिला संगठनों/भारतीय समुदाय संघों और एनजीओ के माध्यम से पीड़ित भारतीय महिलाओं को परामर्शी और विधिक सेवाएं प्रदान करता है।

सामाजिक सुरक्षा करार

यह मंत्रालय प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा के लिए विदेशी सरकारों और कंपनी के साथ पारस्परिक आधार पर सामाजिक सुरक्षा करार करता है। इन करारों से कामगारों को निम्नलिखित रूप में सहायता मिलती है :

- अल्पकालिक संविदाओं के मामले में सामाजिक सुरक्षा योगदान से छूट प्रदान करना
- पुनः गृह देश में वापसी या किसी तीसरे देश में बसने की स्थिति में पेंशन भेजने की सुविधा
- अंशदान अवधियों को जोड़ना

ये करार कंपनियों के लिए भी लाभकारी साबित होते हैं क्योंकि अपने कर्मचारियों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा योगदान से छूट से उनकी लागत कम हो जाती है।

2015–16 में एसएसए के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस प्रकार थे :

1. नॉर्वे के साथ एसएसए 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ।
2. 23–25 मार्च : भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने एसएसए की प्रशासनिक व्यवस्था पर बातचीत के लिए कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया।
3. 4–5 जून 2015 : भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने साइप्रस के साथ प्रथम दौर की चर्चा के लिए साइप्रस का दौरा किया।
4. 1 जुलाई 2015 : आस्ट्रिया के साथ एसएसए लागू हुआ।
5. 27–29 जुलाई 2015 को एक आस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल ने एसएसए के फार्म और प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए भारत का दौरा किया।

6. 1 अगस्त 2015 : कनाडा के साथ एसएसए लागू हुआ।
7. 21 अगस्त 2015 : भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रस्तावित टोटलाइजेशन करार के बारे में यूएस एसएसए के साथ चर्चा के लिए वाशिंगटन, यूएसए का दौरा किया।
8. 1 जनवरी 2016 : आस्ट्रेलिया के साथ एसएसए लागू हुआ।
9. 18–20 दिसंबर 2015 : एसएसए के कार्यान्वयन के लिए फार्म और प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने के लिए 7वें दौर की बातचीत के लिए जापान के साथ भारत में चर्चा हुई।

इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन–रिसर्च थिंक टैंक

इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन (आईसीएम) की स्थापना मंत्रालय द्वारा 'अंतर्राष्ट्रीय प्रवास' से संबंधित सभी मामलों पर शोध विचारमंच के रूप में गैर लाभकारी सोसाइटी के रूप में की गई थी। यह केंद्र क्षमता वृद्धि के लिए व्यक्तियों, संस्थाओं और सरकारों के साथ साझेदारी करता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और इसके शासन में अच्छी रियायतों का पथप्रदर्शन करता है।

आईसीएम की शासी परिषद के प्रमुख सचिव, एमओआईए हैं और अन्य सदस्यों में आर्थिक विभाग, विदेश मंत्रालय , श्रम और रोजगार मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव और तीन राज्य सरकारों के सचिव और प्रवास के मुद्दों से संबंधित विशेषज्ञ शामिल हैं।

आईसीएम की शासी परिषद की पांचवीं और छठी बैठकें क्रमशः मई और दिसंबर 2015 में नई दिल्ली में हुई। शासी परिषद ने निदेश दिया कि आईसीएम प्रमुख मुद्दों जैसे वैश्विक श्रम बाजारों का अध्ययन; प्रवासी रोजगार के लिए मानक रोजगार ठेका; और महिला घरेलू क्षेत्र की कामगारों के प्रवास पर शोध और नीतिगत जानकारी देना जारी रख सकता है।

2015–16 में आईसीएम ने प्रवासी कामगारों के नियोजन, कल्याण और संरक्षण जैसे मुद्दों पर अध्ययन किया जैसे :

क) भारतीय समुदाय कल्याण निधि(आईसीडब्ल्यूएफ)

ख) सरकार द्वारा हस्ताक्षरित सामाजिक सुरक्षा करारों (एसएसए) के प्रभाव आकलन पर प्रारंभिक रिपोर्ट

ग. श्रमिक प्रवासियों पर अंतर्राष्ट्रीय कनवेंशन और भारत के लिए उनकी प्रासंगिकता

घ. फिलिप्पींस द्वारा प्रवास प्रबंधन की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां

ङ. विदेशों में भारतीयों की मृत्यु/चोट के मामले में क्षतिपूर्ति के दावे दाखिल करने के लिए प्रक्रियाओं के संकलन से प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय को सूचना के प्रसार में मदद मिली

च. म्यांमार में भारतीय प्रवासी : उभरती प्रवृत्तियां और चुनौतियां

छ. खाड़ी देशों में प्रवास, सामाजिक विप्रेषण और धर्म : केरल के इसाइयों की बदलती गतिकी।

आईसीएम ने 23 से 24 मार्च 2015 में माइग्रैंट्स इन कंट्रीज् इन क्राइसिस इनिशिएटिव–दक्षिण पूर्व, दक्षिण और दक्षिणपूर्व रीजनल कंसल्टेशन और 4 से 5 नवंबर 2015 में कोलंबो में कोलंबो प्रोसेस (सीपी) की तीसरी वरिष्ठ अधिकारी बैठक में भाग लिया।

बजट और वित्तीय समीक्षा

2014–15 के लिए मंत्रालय का संशोधित बजट (आरई) 94 करोड़ रु. था। वर्ष 2015–16 के लिए 118.17 करोड़ रु. के बजट अनुमान का अनुमोदन किया गया है। विस्तृत बजट आवंटन और संशोधित अनुमान सारणी क में दिए गए हैं। विगत पांच वर्षों के दौरान व्यय की व्यापक प्रवृत्ति चित्र क में बार डायग्राम में दर्शाई गई है।

कौशल विकास के लिए योजना स्कीम

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) में विदेशों में रोजगार के लिए कौशल विकास हेतु एक नई योजना शुरू की गई। व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने 7 जून 2013 को इस योजना स्कीम पर विचार करके कुल परियोजना लागत 137 करोड़ रु. की परियोजना लागत से अनुमोदित किया। इस स्कीम का पुनः नामकरण प्रवासी कौशल विकास योजना किया गया है। 2015–16 के बजट अनुमान में 20 करोड़ रु. का वित्तीय प्रावधान किया गया है।

जेंडर बजट

निम्नलिखित विचारणीय विषय के साथ जेंडर बजट प्रकोष्ठ का गठन किया गया था :

(i) महिलाओं के लिए लाभकारी विशिष्ट योजनाएं बनाना

(ii) विभाग के मौजूदा कार्यक्रमों और स्कीमों के जरिए महिलाओं को मिल रहे लाभ का आकलन करना।

(iii) विभाग के निष्पादन बजट में महिलाओं के लिए लाभ के लिए स्पष्ट रूप से स्कीम वार प्रावधान और वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना

(iv) हर वर्ष विस्तृत अनुदान मांग के लिए जानकारी प्रदान करना।

नो इंडिया कार्यक्रम (केआईपी) के महिला प्रतिभागियों पर व्यय इस कार्यक्रम के लिए आवंटित कुल बजट का 51 प्रतिशत रहा है।

तालिका क

विषय शीर्षवार योजना और गैर योजना संशोधित अनुमान 2015–16 और बजट अनुमान 2016–17

(करोड़ रू. में)

शीर्ष	मौजूदा शीर्ष	बजट अनुमान (2015–16)		वास्तविक (2015–16 (31.12.2015 तक)		संशोधित अनुमान (2015–16)		बजट अनुमान (2016–17)	
		गैर–योजना	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना	योजना
	राजस्व खंड								
2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं (प्रमुख शीर्ष)								
00.090	सचिवालय (लघु शीर्ष)								
34	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय								
01	स्थापना (विस्तृत शीर्ष)								
34.01.01	वेतन								
	प्रभार								
	पारित	6.10		4.77		6.10		8.00	
34.01.02	मजदूरी	0.00		0.00		0.00		0.00	
34.01.03	ओवरटाइम भत्ता	0.03		0.00		0.03		0.04	
34.01.06	चिकित्सा उपचार	0.25		0.17		0.25		0.27	
34.01.11	घरेलू यात्रा व्यय	1.00		0.04		0.10		0.10	
34.01.12	विदेश यात्रा व्यय	1.00		0.20		0.36		0.75	
34.01.13	कार्यालय व्यय								
	प्रभार								
	पारित	3.00		1.46		2.10		2.00	
34.01.14	किराया, दर, कर	4.00		2.76		3.45		4.00	
34.01.16	प्रकाशन	0.25		0.01		0.01		0.05	
34.01.17	बैंकिंग नकदी लेनदेन कर	0.00		0.00		0.00		0.00	
34.01.26	विज्ञापन और प्रचार	1.38		0.00		0.01		0.75	
34.01.27	लघु कार्य	0.80		0.34		0.60		1.00	
34.01.28	व्यावसायिक सेवाएँ	0.17		0.08		0.17		0.25	
34.99	सूचना प्रौद्योगिकी								
34.99.13	कार्यालय व्यय	1.40		0.25		0.57		0.50	
	कुल सचिवालय								
	प्रभार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पारित	19.38	0.00	10.08		13.75	0.00	17.71	0.00

(करोड़ रू. में)

शीर्ष	मौजूदा शीर्ष	बजट अनुमान (2015–16)		वास्तविक (2015–16 (31.12.2015 तक)		संशोधित अनुमान (2015–16)		बजट अनुमान (2016–17)	
		गैर–योजना	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना	योजना
40	उत्प्रवास महासंरक्षी								
40.01	स्थापना (विस्तृत शीर्ष)								
40.01.01	वेतन	2.70		2.04		2.90		3.70	
40.01.02	मजदूरी	0.02		0.04		0.05		0.05	
40.01.03	ओवरटाइम भत्ता	0.00		0.00		0.00		0.00	
40.01.06	चिकित्सा भत्ता	0.02		0.00		0.04		0.06	
40.01.11	घरेलू यात्रा व्यय	0.10		0.05		0.10		0.10	
40.01.12	विदेश यात्रा व्यय	0.00		0.00		0.00		0.00	
40.01.13	कार्यालय व्यय	1.50		0.61		1.00		1.00	
40.01.14	किराया, दर, कर	0.62		0.56		1.27		1.30	
40.01.16	प्रकाशन	0.00		0.00		0.00		0.00	
40.01.26	विज्ञापन और प्रचार	0.00		0.00		0.00		0.00	
40.01.27	लघु कार्य	0.05		0.00		0.05		0.05	
40.01.28	व्यावसायिक सेवाएँ	0.14		0.24		0.40		0.50	
40.99	सूचना प्रौद्योगिकी								
40.99.13	कार्यालय व्यय	6.15		5.04		6.05		9.00	
	कुल पीजीई	**11.30**	**0.00**	**8.58**	**0.00**	**11.86**	**0.00**	**15.76**	**0.00**
	प्रभार					0.00			
	पारित	**11.30**	**0.00**	**8.58**	**0.00**	**11.86**	**0.00**	**15.76**	**0.00**
00.800	अन्य व्यय (लघु शीर्ष)								
07	सेमिनारों और अध्ययनों के आयोजन पर व्यय								
07.00.20	अन्य प्रशासनिक व्यय	0.00		0.00		0.00		0.00	
	कुल–अन्य व्यय	**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
	कुल–सचिवालय सामान्य सेवाए	**30.68**	**0.00**	**18.66**	**0.00**	**25.61**	**0.00**	**33.47**	**0.00**
	प्रभार	0.00				0.00		0.00	
	पारित	30.68	0.00	18.66	0.00	25.61	0.00	33.47	0.00
2061	**विदेश (मुख्य शीर्ष)**								

(करोड़ रू. में)

शीर्ष	मौजूदा शीर्ष	बजट अनुमान (2015–16)		वास्तविक (2015–16 (31.12.2015 तक)		संशोधित अनुमान (2015–16)		बजट अनुमान (2016–17)	
		गैर–योजना	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना	योजना
00.104	अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन / बैठके (लघु शीर्ष)								
01	अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन / बैठके								
01.00.20	अन्य प्रशासनिक व्यय	0.76		0.00		0.05		0.05	
	कुल–अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन / बैठक	**0.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.05**	**0.00**	**0.05**	**0.00**
00.106	मनोरंजन प्रभार (लघु शीर्ष)								
01	गणमान्य व्यक्तियों का मनोरंजन								
01.00.20	अन्य प्रशासनिक व्यय	0.23		0.00		0.01		0.01	
	कुल – गणमान्य व्यक्तियों का मनोरंजन	**0.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.01**	**0.00**
	कुल – मनोरंजन प्रभार	**0.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.06**	**0.00**	**0.06**	**0.00**
00.800	अन्य व्यय (लघु शीर्ष)								
03	अन्य योजनाएं (उप शीर्ष)								
00.03	अन्य मदे								
03.03.31	अनुदान सहायता सामान्य (विषय शीर्ष)	0.76		0.00		1.00		1.00	
03.03.50	अन्य प्रभार (विषय शीर्ष)	1.50		1.23		1.00		0.50	
03.04	भारत की विदेशी नागरिकता (विस्तृत शीर्ष)								
03.04.50	अन्य प्रभार (विषय शीर्ष)	0.50		0.58		2.30		1.50	
03.05	भारत जानों कार्यक्रम								
03.05.50	अन्य प्रभार (विषय शीर्ष)	8.00		1.23		1.94		1.50	
03.06	डायस्पोरा बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना (विस्तृत शीर्ष)								
03.06.50	अन्य प्रभार (विषय शीर्ष)	6.50		6.47		6.50		6.00	
03.07	प्रवासी भारतीयों के साथ सांस्कृतिक संबंधों का संवर्धन (विस्तृत शीर्ष)								

(करोड़ रू. में)

शीर्ष	मौजूदा शीर्ष	बजट अनुमान (2015–16)		वास्तविक (2015–16 (31.12.2015 तक)		संशोधित अनुमान (2015–16)		बजट अनुमान (2016–17)	
		गैर–योजना	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना	योजना
03.07.50	अन्य प्रभार (विषय शीर्ष)	9.50		0.13		0.70		2.00	
03.08	जागरूकता अभियान / मीडिया योजना (विस्तृत शीर्ष)								
03.08.50	अन्य प्रभार (विषय शीर्ष)	9.50		0.00		1.00		5.54	
03.09	भारत विकास प्रतिष्ठान (विस्तृत शीर्ष)								
03.09.50	अन्य प्रभार (विषय शीर्ष)	0.85		0.66		0.66		1.00	
03.10	प्रवासी भारतीय सुविधा केंद्र (विस्तृत शीर्ष)								
03.10.50	अन्य प्रभार (विषय शीर्ष)	1.30		0.00		0.00		1.50	
03.11	प्रवासी कामगार स्रोत केंद्र ;विस्तृत शीर्ष)								
03.11.50	अन्य प्रभार (विषय शीर्ष)	1.20		0.63		1.19		1.30	
03.13	श्रम गतिशीलता भागीदारी (विस्तृत शीर्ष)								
03.13.50	अन्य प्रभार (विषय शीर्ष)	0.04		0.00		0.00		0.01	
03.20	उत्प्रवासी कामगारों का प्रस्थान पूर्व अभिमुखीकरण और कौशल उन्नयन (विस्तृत शीर्ष)								
03.20.50	अन्य प्रभार (विषय शीर्ष)	0.50		0.00		0.00		0.01	
03.22	प्रवासी भारतीय केंद्र (विस्तृत शीर्ष)								
03.22.50	अन्य प्रभार (विषय शीर्ष)	3.69		3.01		3.69		3.20	
03.24	भारतीय प्रवासी रोजगार परिषद (विस्तृत शीर्ष)								
03.24.50	अन्य प्रभार (विषय शीर्ष)	3.04		0.00		0.00		0.10	
03.25	एनआरआई शादियों में समस्याओं का सामना कर रही महिलाओं को कानूनी सहायता (विस्तृत शीर्ष)								
03.25.50	अन्य प्रभार (विषय शीर्ष)	0.10		0.00		0.27		0.25	

									(करोड़ रू. में)
शीर्ष	मौजूदा शीर्ष	बजट अनुमान (2015–16)		वास्तविक (2015–16 (31.12.2015 तक)		संशोधित अनुमान (2015–16)		बजट अनुमान (2016–17)	
		गैर–योजना	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना	योजना
03.30	स्वर्ण प्रवास योजना								
03.30.50	अन्य प्रभार (विषय शीर्ष)	0.00	20.00	0.00	1.27		3.00	0.00	(SPA)
	कुल–अन्य योजनाएं	**46.98**	**13.94**	**20.00**	**1.27**	**20.25**	**3.00**	**25.41**	**0.00**
15	प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन								
15.00.50	अन्य प्रभार	7.53		12.21		13.33		5.00	
	कुल–अन्य योजनाएं	**54.51**	**20.00**	**26.15**	**1.27**	**33.58**	**3.00**	**30.41**	
	कुल – विदेश कार्य (मुख्य शीर्ष)	**55.50**	**20.00**	**26.15**	**1.27**	**33.64**	**3.00**	**30.47**	**0.00**
	प्रभार					0.00			
	पारित	55.50	20.00	26.15	1.27	33.64		30.47	
	कुल – राजस्व खंड	**86.18**	**20.00**	**44.81**	**1.27**	**59.25**	**3.00**	**63.94**	**0.00**
	प्रभार					0.00			
	पारित	86.18	20.00	44.81	1.27	59.25		63.94	0.00
	पूँजीगत खंड								
4059	**लोक कार्यों परः पूँजीगत परिव्यय (मुख्य शीर्ष)**								
60	अन्य इमारतों (उप मुख्य शीर्ष)								
60.051	निर्माण (लघु शीर्ष)								
23	प्रवासी भारतीय केन्द्र								
23.00.53	प्रमुख कार्य	12.00		11.75		12.00		7.50	
24	पीजीई / पीओई के लिए इमारतों का निर्माण/ खरीद								
24.00	प्रमुख कार्य								
24.00.53	प्रमुख कार्य	0.00		0.00		0.00		0.00	
	लोक कार्यों पर कुल – पूंजीगत परिव्यय	**12.00**	**0.00**	**11.75**	**0.00**	**12.00**	**0.00**	**7.50**	**0.00**
	कुल – पूंजीगत खंड	**12.00**	**0.00**	**11.75**	**0.00**	**12.00**	**0.00**	**7.50**	**0.00**
	कुल – अनुदान संख्या 70	**98.18**	**20.00**	**56.56**	**1.27**	**71.25**	**3.00**	**71.44**	**0.00**
	प्रभार	0.00				0.00		0.00	
	पारित	**98.18**	**20.00**	**56.56**	**1.27**	**71.25**	**3.00**	**71.44**	**0.00**

रेखा–चित्र . ख

विषय शीर्षवार योजना और गैर योजना संशोधित अनुमान 2015–16 और बजट अनुमान 2016–17

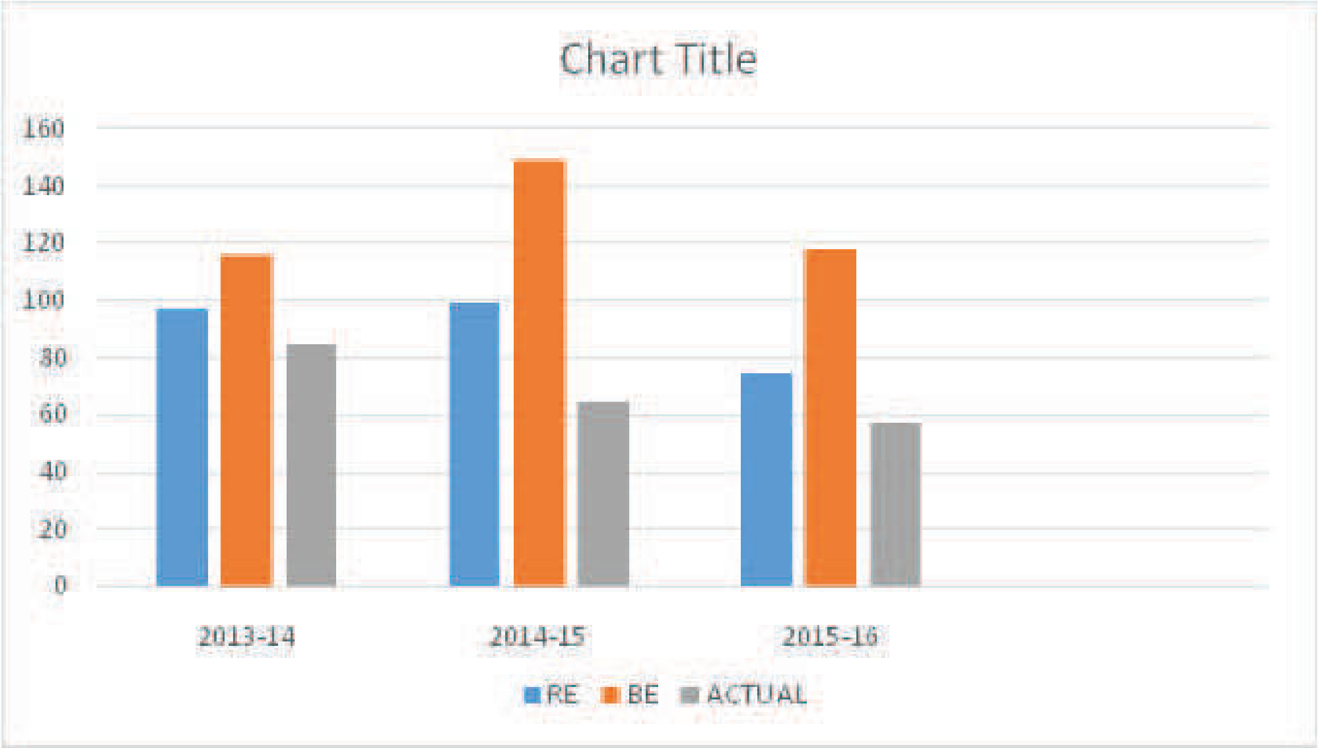

प्रशासन तथा स्थापना

24

प्रशासन प्रभाग द्वारा मुख्यालय तथा विदेश स्थित 183 भारतीय मिशनों/ केंद्रों में मंत्रालय की जरूरतों को पूरा करने के लिए जनशक्ति संसाधन के बेहतर उपयोग का प्रयास जारी है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह प्रभाग काडर प्रबंधन का कार्य देखता है, जिसमें अन्यों के अतिरिक्त भर्ती, प्रशिक्षण, तैनाती/स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति तथा कैरियर उन्नयन शामिल है। इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग कार्मिकों संबंधी सभी संगत नियमों और अधिनियमों के निरूपण, संशोधन और सुधार का कार्य भी देखता है। यह प्रभाग विदेश स्थित नए मिशनों/केंद्रों की स्थापना के लिए अनुमोदन भी प्राप्त करता है।

सुशासन के लिए सर्वोत्तम विधि अपनाने और इसे विकसित करने के लिए अपनी पहल के भाग के रूप में मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय की ई–समीक्षा–डिजिटल प्लेटफार्म विकसित किया है, जिसमें समय–समय पर मंत्रालय में लिए गए विभिन्न नीतिगत निर्णयों के बारे में वास्तविक जानकारी इक्ट्ठा करने की व्यवस्था है और यह मुख्यालय और मिशन/केंद्र के बीच एक ऑनलाइन इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। उपलब्ध मानव संसाधन का इष्टम उपयोग करने के लिए, मंत्रालय के दिल्ली स्थित कार्यालयों और मंत्रालय के दिल्ली से बाहर के संबद्ध कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली स्थापित कर दी गयी है।

वर्तमान में मंत्रालय में 4054 संस्वीकृत पद हैं (परिशिष्ट IX)। इन पदों पर तैनात कार्मिकों को भारत तथा विदेश स्थित 183 मिशनों/केंद्रों में तैनात किया जाता है। इसमें भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस), भारतीय विदेश सेवा, ब्रांच 'ख' (आईएफएस 'बी'), दुभाषिया संवर्ग, विधि एवं संधि संवर्ग और पुस्तकालय संवर्ग शामिल हैं, परंतु इसमें समूह 'घ' तथा बाह्य संवर्ग पद शामिल नहीं है।

मंत्रालय के विभिन्न समूहों की 01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च, 2016 तक सीधी भर्ती (डीआर), विभागीय पदोन्नति (डीपीपी) तथा सीमित विभागीय परीक्षा (एलडीई) के माध्यम से भर्ती की गई थी (परिशिष्ट X)।

विदेश मंत्रालय के 183 मिशन/केंद्र हैं, जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, जहां अधिकारियों के प्रशिक्षण और भाषाई कौशल के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप सेवा में विदेशी भाषा कौशल वाले अधिकारियों का एक पूल तैयार हो गया, जिससे अधिकारीगण अपनी राजनयिक जिम्मेदारी अधिक प्रभावी रूप से पूरी करने में समर्थ हो गए (परिशिष्ट XI)।

मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों को पर्याप्त अवसर सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार के नियमों के अनुरूप अपने कार्मिकों के बीच विकलांग व्यक्तियों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व होने की नीति अपनाना जारी रखा गया।

सतर्कता एकक

''सुशासन के उपकरण के रूप में निवारक सतर्कता'' विषय पर 27 अक्टूबर, 2015 से 01 नवम्बर, 2015 तक सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाया गया। विदेश स्थित सभी भारतीय मिशन/केंद्रों तथा विदेश मंत्रालय के विभिन्न विभागों ने केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित शपथ ली।

मंत्रालय में अपने पोर्टल पर सतर्कता मामलों को ऑनलाइन दायर करने की सुविधा है। इस ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से मंत्रालय, विदेश स्थित राजनयिक मिशनों/केंद्रों, भारत स्थित पासपोर्ट कार्यालयों, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, अनुसंधान और सूचना प्रणाली, विश्व मामलों की भारतीय परिषद से संबंधित सतर्कता शिकायतें दायर की जा सकेंगी।

विदेश मंत्रालय ने 01 जनवरी, 2013 से 50 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक मूल्य की सभी अधिप्राप्तियों/ परियोजनाओं के लिए मंत्रालय और भावी बोली लगाने वालों/विक्रेताओं के बीच पूर्व संविदा इंटीग्रिटी समझौता पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव किया है। यह विदेश सेवा संस्थान, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद तथा विश्व मामलों की भारतीय परिषद सहित मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त निकायों पर लागू होगा।

यह इंटीग्रिटी पैक्ट दो स्वतंत्र बाहरी अनुवीक्षकों (आईईएम) के एक पैनल के माध्यम से कार्यान्वित होगा, जिन्हें मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से नियुक्त किया जाएगा।

मंत्रालय द्वारा उच्च सत्यनिष्ठा और ख्याति वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति आईईएम के रूप में नियुक्त किए जाएंगे।

वर्ष 2015–16 के लिए मंत्रालय में सीएनवी प्रभाग के सतर्कता एकक द्वारा संचालित मामलों का विवरण निम्नानुसार हैः–

31 मार्च, 2015 को लंबित मामलों की संख्या	:	83
01 अप्रैल, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 तक की अवधि के दौरान जांच हेतु प्राप्त मामलों की संख्या	:	55
31 दिसंबर, 2015 तक प्राप्त मामलों की कुल संख्या	:	138
01 अप्रैल, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 तक की अवधि के दौरान औपचारिक जुर्माना लगाकर बंद किए गए मामलों की संख्या	:	5
01 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 तक की अवधि के दौरान मृत्यु, वीआरएस आदि के कारण, बिना जुर्माने के बंद हुए मामलों की संख्या	:	37
01 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 तक की अवधि के दौरान बंद किए गए मामलों की कुल संख्या	:	42
31 दिसंबर, 2015 को लंबित मामलों की संख्या	:	96

कल्याण

कल्याण प्रभाग विदेश मंत्रालय के सभी कर्मचारियों के सामान्य कल्याण का कार्य देखता है। इस वर्ष के दौरान विदेश मंत्रालय ने अपने 08 कर्मचारियों को खोया है, जिनके लिए प्रभाग द्वारा सभी प्रकार की सहायता दी गई तथा कर्मचारी लाभ निधि से अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया। एक्सटर्नल अफेयर्स स्पाउस एसोसिएशन (ईएएसए) ने भी कल्याण अनुभाग के माध्यम से प्रभावित बच्चों को 9 छात्रवृत्तियां प्रदान की।

इस वर्ष 61 बच्चों को इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया गया था। इंजीनियरिंग सीटों के लिए एक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उम्मीदवारों का चयन किया गया तथा पहली बार विदेश मंत्रालय के इंट्रानेट के माध्यम से प्रासंगिक जानकारी परिचालित की गई। विदेश मंत्रालय के अधिकारी के एक बच्चे को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों में आबंटित 60 सीटों में से 53 पर बच्चों को प्रवेश दिया गया।

इस वर्ष के दौरान अनुकंपा के आधार पर लंबे समय से लंबित एमटीएस के 08 पद और एलडीसी के एक पद पर भर्ती की गई।

कल्याण विभाग द्वारा सांप्रदायिक सद्भाव और सशस्त्र बल झंडा दिवस हेतु निधि जुटाने का अभियान शुरू किया गया था। विदेश स्थित दो भारतीय मिशनों/केंद्रों को मनोरंजन क्लबों की स्थापना के लिए भी सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा, कल्याण प्रभाग द्वारा विभिन्न सार्वजनिक/निजी स्कूलों में मिशन से मुख्यालय में लौटने वाले अधिकारियों और कर्मचारी सदस्यों को सहायता देने गैस कनेक्शन, राशन कार्ड, टेलीफोन कनेक्शन आदि की सुविधा प्रदान करने तथा चिकित्सा आपात स्थिति में अपेक्षित आवश्यक सहायता देने से संबंधित दिनचर्या के मामलों को निपटाया गया, चाहे संबंधित अधिकारी/कर्मचारी विदेश स्थित मिशनों अथवा मुख्यालय में कार्यरत हों।

प्रभाग ने उनकी शिकायतों को समझने और समाधान करने के लिए विभिन्न स्टाफ एसोसिएशनों के साथ नियमित रूप से बैठकों की अध्यक्षता की।

स्थापना

स्थापना प्रभाग मंत्रालय के कार्यालय और आवासीय परिसर के रख–रखाव तथा अनुरक्षण, मंत्रालय के कार्यालयों के लिए आवास और कार्यालय के लिए स्थान का आबंटन, कार्यालय उपस्कर तथा फर्नीचर की खरीद और आपूर्ति संबंधी कार्य देखता है। यह विदेश स्थित मिशनों और केंद्रों में तैनात अधिकारियों के लिए भत्तों और विशेष अनुदान; कार्यालय वाहन और विशेष अधिप्रापण वस्तुओं की खरीद और आपूर्ति के साथ ही साथ विदेश स्थित हमारे मिशनों और केंद्रों के लिए आवासीय व्यवस्था और चांसरी किराए पर लेने की व्यवस्था से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करता है।

हाल ही में जुलाई 2015 में सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किए गए सर्वेक्षण में, जवाहरलाल नेहरू भवन सर्वोत्तम कार्यालय भवन के रूप में दर्ज किया गया था और राजधानी में 49 सरकारी भवनों में से स्वच्छ भारत अभियान (एसबीए) रेटिंग में सबसे ऊपर रहा है जिसकी साफ–सफाई की पूरी तरह जांच की गई थी। इस भवन को प्रकृति के अनुकूल बनाने और इसे और खूबसूरत दिखने लायक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

रखरखाव, हरियाली और बागवानी के संबंध में अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान करके चाणक्यपुरी, के जी मार्ग, गोल मार्केट और द्वारका स्थित मंत्रालय के आवासीय परिसरों में रहने की स्थिति में सुधार किया गया है। के जी मार्ग और गोल मार्केट आवासीय परिसरों की समग्र स्थिति में सुधार करने के लिए सिविल कार्य पूरा कर लिया गया है।

कार्मिकों को 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत सफाई पर ध्यान देने तथा अपने आस–पास की सफाई में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने की आवश्यकता पर बल देने की दृष्टि से पिछले एक वर्ष के दौरान मंत्रालय के साथ–साथ विदेश स्थित हमारे मिशनों और केंद्रों में कई कदम उठाए गए थे। विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों/केंद्रों ने भी सफाई अभियान में प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्रों और आगंतुक कक्षों, प्रतीक्षा लॉबी, आदि पर विशेष ध्यान देने के साथ साफ–सफाई का स्तर बढ़ाने के लिए सफाई अभियान

में बढ़–चढ़कर भाग लिया। सरकारी कर्मचारियों के बीच स्वस्थ स्वच्छता प्रथाओं के संबंध में एक सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन देखा गया है।

परियोजनाएं

तोरण द्वार परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने के अलावा, रिपोर्ट की अवधि के दौरान, प्रभाग ने सियोल, तेल अबीब और वैंकूवर में अधिग्रहण हेतु प्रस्तावों के साथ अधिग्रहण प्रस्तावों पर कार्रवाई करना जारी रखा। प्रभाग ने जेद्दा और काबुल में अधिग्रहण प्रस्तावों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना जारी रखा है ये प्रस्ताव चरण में और संबंधित विदेशी कार्यालयों से अंतिम मंजूरी के लिये प्रतीक्षित है। माले और बैंकॉक में अधिग्रहीत भूखंडों पर निर्माण परियोजनाओं की दिशा में भी प्रगति हुई।

सिडनी चांसरी में नवीयन परियोजना पूरा हो गई थी और मई 2015 में चांसरी को कब्जे में ले लिया गया था। कुआलालंपुर, डबलिन, कोलंबो, पेरिस स्थित सांस्कृतिक केंद्र और भारतीय दूतावास, वाशिंगटन में सांस्कृतिक विंग में नवीकरण से संबंधित प्रमुख परियोजनाएं विभिन्न चरणों में हैं, इन परियोजनाओं के लिए सलाहकार की नियुक्ति से लेकर वास्तुकलात्मक आरेख की तैयारी और वास्तविक नवीकरण का काम जारी है।

प्रभाग ने विभिन्न निर्माण/पुनः विकास परियोजनाओं की प्रगति की नजदीकी से निगरानी जारी रखी है, ताकि उन्हें समय पर प्रारंभ/पूरा किया जा सके। विदेश स्थित परियोजनाओं में अदीस अबाबा में,बहरीन, बेलग्रेड, बैंकॉक, बर्लिन, ब्रुनेई, कैनबरा, दार–एस–सलाम, ढाका, दोहा, इस्लामाबाद, गेबरोन, जकार्ता, काबुल, काठमांडू, खार्तूम, लंदन, माले, मास्को, निकोसिया, पोर्ट लुई (चांसरी और विश्व हिंदी सचिवालय), पोर्ट ऑफ स्पेन, सैंटियागो, शंघाई, सिंगापुर (दो भूखंडों के पुनर्विकास), ताशकन्द, वॉरसॉ, वेलिंगटन, कुआलालंपुर, डबलिन और कोलंबो और पेरिस स्थित चांसरी और/या आवासों का निर्माण और पुनर्विकास कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरण में हैं और रिपोर्ट की अवधि के दौरान परामर्शदाता की नियुक्ति से लेकर वास्तुकलात्मक आरेख और वास्तविक निर्माण/नवीयन का काम जारी है।

ठोस प्रयासों के माध्यम से, प्रभाग शंघाई में परामर्श / डिजाइन का चयन करने में सक्षम रहा है और दार–एस–सलाम और बहरीन में उच्चायोग के लिए चांसरी और आवास का निर्माण कार्य समय पर पूरा होने के कगार पर है।

प्रभाग ने वैश्विक संपदा प्रबंधन पोर्टल के शुभारंभ करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति की है।

■ ■

25 सूचना का अधिकार और मुख्य जनसूचना अधिकारी का कार्यालय

वर्ष 2015 के दौरान, मंत्रालय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए प्रयासरत है। स्वप्रकटीकरण के बारे में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों के अनुसार आरटीआई आवेदन/ अपील / जवाबों तथा मासिक आरटीआई आंकड़ों को सार्वजनिक डोमेन पर अपलोड करने का कार्य किया गया है। आरटीआई आवेदनों की ऑनलाइन स्वीकृति एवं निपटान की प्रणाली 17 अगस्त 2015 से प्रभावी आरटीआई वेब पोर्टल के साथ संरेखित करके विदेश स्थित सभी 183 मिशनों /केंद्रों में कार्यान्वित किया गया है।

01 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 के दौरान मंत्रालय में आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने हेतु कुल 2825 आवेदन प्राप्त हुए थे और उनका संतोषजनक ढंग से निपटान कर दिया गया है। आवेदनों में सामान्य रूप से विदेशी संबंध, प्रशासनिक मामले, हज यात्रा, द्विपक्षीय यात्राएं और उन पर हुए व्यय जैसे विषय शामिल थे। कोंसुलर, पासपोर्ट और वीजा (सीपीवी) प्रभाग, विदेश स्थित मिशन और केंद्र, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद तथा वैश्विक मामलों की भारतीय परिषद इस अधिनियम के अंतर्गत स्वतंत्र लोक प्राधिकरण के रूप में अपने रिकॉर्ड का रख–रखाव करते हैं।

मंत्रालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के बारे में बेहतर समझ विकसित करने के उद्देश्य से मुख्य जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को आवेदनों पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने में सक्षम बनाने के लिए, आरटीआई अधिनियम, 2005 के एक विशेषज्ञ के साथ परस्पर संवादात्मक सत्र आयोजित किए गए।

संबंधित मुख्य जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और आरटीआई प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की सभी सुनवाइयों के दौरान उपस्थित होते रहे हैं। और मंत्रालय को सीआईसी से कोई प्रतिकूल निर्णय / टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। सीआईसी में यथापेक्षित तिमाही रिटर्न समयानुसार दायर की गई हैं।

■ ■

ई–गवर्नेंस तथा सूचना प्रौद्योगिकी

26

ई–गवर्नेंस और सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग (ईजी एंड आईटी) मुख्यालय और विदेश स्थित मिशनों / केंद्रों में आईटी अवसंरचना की खरीद, अनुरक्षण और रखरखाव के लिए मंत्रालय को आईटी से संबंधित समर्थन प्रदान करता है। साथ ही ईजी एंड आईटी प्रभाग एनआईसी और डीईआईटीवाई के साथ समन्वय करके ई–शासन अनुप्रयोगों के प्रणाली अध्ययन, विकास, परीक्षण और रखरखाव करके मुख्यालय व विदेश स्थित मिशनों / केंद्रों में विभिन्न ई–शासन अनुप्रयोगों के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय को समर्थन देता है।

ईजी एंड आईटी प्रभाग मंत्रालय और विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों / केंद्रों में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विभिन्न घटकों को लागू करने के लिए कदम उठा रहा है। ई–क्रांति की चार मिशन मोड परियोजनाएं (डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का चौथा स्तंभ) अर्थात् ई–कार्यालय, ई–प्रापण, आईवीएफआरटी (आप्रवास, वीजा, विदेशियों के पंजीकरण, ट्रैकिंग) और पासपोर्ट सेवा परियोजना (पीएसपी)ए मंत्रालय और विदेश स्थित मिशनों/ केंद्रों में वर्तमान में प्रचालित हैं। ई–कार्यालय सॉफ्टवेयर पहले से ही मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों में कार्यान्वित किया गया है। मंत्रालय में ई–कार्यालय के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। मंत्रालय में सरकारी खरीदों को अधिक पारदर्शी और कारगर बनाने के उद्देश्य से मंत्रालय में ई–प्रोक्योरमेंट अनुप्रयोग को मार्च 2013 से लागू किया गया है। मंत्रालय में 1 अप्रैल 2015 के बाद से 5 लाख रुपए और उससे अधिक मूल्य की सभी निविदा प्रक्रियाओं के लिए बोलियों को ऑनलाइन आमंत्रित करने की प्रक्रिया (निविदा प्रक्रिया में) लागू की गई है। मंत्रालय ई–सेवाओं जैसे पासपोर्ट और ऑनलाइन वीजा सेवाओं के रूप में ई–प्रवास, ई–ताल (इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन और एकत्रीकरण पटल) और आधार / यूआईडीएआई के साथ एकीकृत किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा 163 भारतीय मिशनों / केंद्रों में आईवीएफआरटी (अप्रवास, वीजा, विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैकिंग) का ऑनलाइन वीजा घटक कार्यान्वित हो गया है जबकि 76 मिशनों / केंद्रों में बायोमेट्रिक इनरॉलमेंट कार्यान्वित किया गया है।

मार्च 2015 के बाद से ई–गवर्नेंस अनुप्रयोग, विदेश मंत्रालय की ई–समीक्षाए विभिन्न स्तरों पर मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी के लिए एक वास्तविक समय ऑनलाइन प्रणाली, मुख्यालय और विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों / केंद्रों विदेश में कार्यान्वित की गई है। अन्य ई–गवर्नेंस अनुप्रयोग जैसे एईबीएएस (आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली), ई–विजिटर और प्रगति (प्रो–एक्टिव गवर्नेंस और समय पर कार्यान्वयन) भी मंत्रालय में कार्यान्वित किए गए हैं। मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए कंप्यूटर डीडीओ सॉफ्टवेयर मुख्यालय में लगाया गया और 2005 के बाद से विदेश स्थित सभी मिशनों / केंद्रों के लिए एकीकृत मिशन लेखा सॉफ्टवेयर (आईएमएएस) मंत्रालय में कार्यान्वित किया गया है। इससे मंत्रालय और विदेश स्थित सभी 180 मिशनों / केंद्रों की लेखा पद्धति में एकरूपता लाई गई है। आईएमएएस सॉफ्टवेयर का अगला संस्करण, जो वेब आधारित है, मंत्रालय में विकसित किया जा रहा है।

प्रौद्योगिक आधार पर 31 दिसंबरए 2015 को विदेश सचिव द्वारा ऑनलाइन ई–राजनीतिक मंजूरी पोर्टल (http://epolclearance.gov.in) का शुभारंभ किया गया था। इस प्रणाली में राजनीतिक मंजूरी के लिए आवेदनों की ऑनलाइन जमा करने की सुविधा हैए आवेदकों द्वारा संबंधित प्रभागों के लिए समर्थन दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा प्रदान की गई है, ऑनलाइन आवेदन संबंधित प्रभागों को अग्रेषित करने और प्रभागों द्वारा इस पर कार्रवाई किए जाने के बाद, राजनीतिक मंजूरी प्रदान की जाती है, जिसे इस प्रणाली द्वारा एक ही स्थान से आवेदकों को सीधे भेजा जाएगा। यह ऑनलाइन पोर्टल ईजी एंड आईटी प्रभागए विदेश कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है और एनआईसी द्वारा जीआई क्लाउड पर समन्वित किया जा रहा है। पोर्टल 1 जनवरी 2016 से शुरू हो गया।

मंत्रालय ने फ़िशिंग साइटों और मैलवेयर अनुलग्नकों के लिए लिंक युक्त ईमेल के रूप में साइबर सुरक्षा के खतरों के बारे में प्रयोक्ताओं को सचेत करना जारी रखा। साइबर सुरक्षा खतरों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मंत्रालय के अधिकारियों और मुख्यालय के कर्मचारियों और विदेशों में तैनाती के लिए जाने वाले अधिकारियों के लिए साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण पर विशेष जोर जोर दिया गया है।

■■

संसद और समन्वय प्रभाग

संसद प्रभाग

मंत्रालय का संसद प्रभाग संसद से संबद्ध है तथा संसद से संबंधित सभी कार्यों के लिए विदेश मंत्रालय का एक नोडल बिंदु है। इस कार्य में संसद प्रश्नों के उत्तर, संसदीय आश्वासनों की पूर्ति, ध्यानाकर्षण नोटिस एवं प्रस्ताव, अपनी ओर से दिए जाने वाले वक्तव्य, विदेश नीति पर बहस/ अल्पावधिक चर्चा, विधायी कार्य, संसद में रिपोर्ट तथा दस्तावेज इत्यादि प्रस्तुत करने के संदर्भ में विदेश मंत्रालय के सभी प्रभागों के साथ संपर्क स्थापित करना शामिल है। संसद सत्र प्रारंभ होने से पहले यह अनुभाग प्रधानमंत्री कार्यालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के लिए आगामी सत्र के दौरान संसद में उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर सारांश भी संकलित करता है। यह प्रभाग विदेश मामलों पर परामर्शदात्री समिति की बैठकों तथा विदेश मामलों पर संसदीय स्थायी समिति से संबंधित कार्य और अन्य संसदीय समितियों के साथ विदेश मंत्रालय की चर्चा का समन्वय भी करता है।

परामर्शदात्री समिति की बैठकें:

विदेश मंत्री (ईएएम) ने 2015 में विदेश मामलों और प्रवासी भारतीय कार्य से संबंधित परामर्शदात्री समिति की चार बैठकों की अध्यक्षता की:

(क) 15 जून 2015 को पहली बैठक आयोजित की गई थी। राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा विदेशों में रोजगार भर्ती से संबंधित प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की कार्यसूची मदों, विदेशों में रोजगार के लिए भर्ती एजेंसियों की नियुक्ति की वर्तमान प्रणालीए खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों के सामने आने वाली समस्याओं पर विदेश मंत्रालय की कार्यसूची मद और कल्याणकारी उपायों पर चर्चाएँ आयोजित की गईं।

(ख) 'विदेशों में रोजगार और भर्ती एजेंसियों की भूमिका से संबंधित मुद्दे' विषय पर दूसरी बैठक 8 अक्टूबर 2015 को आयोजित की गई थी।

(ग) 'प्रधानमंत्री के हाल के विदेश दौरे के परिणामः रूस और मध्य एशियाई देशों, यूएई, आयरलैंड, संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राज्य अमेरिका'' संबंधी कार्यसूची मद पर परामर्शदात्री समिति की 2015 की तीसरी बैठक 02 नवंबर 2015 को आयोजित की गई थी; और

(घ) ''नेपाल की स्थिति'' संबंधी कार्यसूची मद पर चौथी बैठक 21 नवंबर 2015 को आयोजित की गई थी।

विदेश मामलों की स्थायी समिति की बैठकें:

अप्रैल–नवंबर 2015 की अवधि के दौरान विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति के साथ मंत्रालय की निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गई:

(क) मौखिक ब्रीफिंग :

i) 2014 के बाद अफगानिस्तान के साथ भारत की संबद्धता और पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों तथा भारत की भूमिका पर विदेश सचिव द्वारा विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति की मौखिक ब्रीफिंग 12 मईए 2015 को आयोजित की गई थी।

ii) ''पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली और भारतीय नागरिकों के लिए ई–पासपोर्ट परियोजना के कार्यान्वयन के निष्पादन'' विषय पर विदेश मामलों की स्थायी समिति की एक मौखिक ब्रीफिंग 30 जुलाई 2015 को आयोजित की गई थी। विदेश सचिव ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

iii) ''संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों और जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों के बारे में भारत की प्रतिबद्धताएं'' विषय पर विदेश मंत्रालय द्वारा 5 नवंबर, 2015 को विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति की एक मौखिक ब्रीफिंग आयोजित की गई थी। विदेश सचिव ने भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वरिष्ठ प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए।

iv) ''नेपाल में हाल के घटनाक्रम और भारत के लिए इसके निहितार्थ'' विषय पर 29 दिसंबर 2015 को विदेश मामलों की स्थायी समिति की एक ब्रीफिंग बैठक आयोजित की गई।

(ख) मौखिक साक्ष्यः

i) विदेश सचिव ने 'काडर, सेवाकालीन कैरियर इंट्री और सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं अभिविन्यास हेतु संघ लोक सेवा आयोग की अलग से परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता सहित आईएफएस काडर की भर्ती संरचना और क्षमता–निर्माणश विषय पर 18 जूनए 2015 को विदेश मामलों संबंधी संसदीय स्थायी समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया।

ii) विदेश मामलों संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 'काडर, सेवाकालीन कैरियर इंट्री और सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं अभिविन्यास हेतु संघ लोक सेवा आयोग की अलग से परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता सहित आईएफएस काडर की भर्ती संरचना और क्षमता निर्माण विषय परश 16 दिसंबरए 2015 को विदेश मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया। यह इस विषय पर समिति द्वारा ली गई चौथी बैठक थी।

संसद की अन्य समितियों की बैठकें:

अप्रैल–नवंबर 2015 की अवधि के दौरान अन्य संसदीय समितियों के साथ मंत्रालय के प्रतिनिधियों की निम्नलिखित सुनवाइयां हुईं:

(क) मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एण्ड ए जी) की 2010–11 की रिपोर्ट सं–9 से समिति द्वारा चयन किए गए विषयों पर लोक लेखा समिति की उप समिति–V (2014–15) के समक्ष 23 अप्रैल, 2015 को इसकी बैठक में मौखिक साक्ष्य दिया। अपर सचिव (प्रशासन) ने विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया।

(ख) विश्व मामलों की भारतीय परिषद अधिनियम, 2001, व्यापक विनाश के हथियार और उनकी सुपुर्दगी प्रणाली (गैर–कानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 और नालन्दा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 के विशेष संदर्भ में विदेश मंत्रालय द्वारा प्रशासित संसद के अधिनियमों के तहत नियम/विनियम तैयार करने की स्थिति के संबंध में 1 जून, 2015 को राज्यसभा के अधीनस्थ विधायन समिति के साथ विदेश मंत्रालय की सुनवाई हुई। विदेश सचिव ने इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

(ग) लोकसभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति ने 21 जुलाई और 31 अगस्त, 2015 को 13वीं लोकसभा के तीसरे सत्र से 16वीं लोकसभा के तीसरे सत्र तक लंबित आश्वासनों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया। विदेश सचिव ने मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

(घ) लोक लेखा समित ने वर्ष 2014 की सी एण्ड ए जी रिपोर्ट संख्या–16, संघ सरकार के आधार पर विदेश मंत्रालय द्वारा वैश्विक संपदा प्रबंधन की लेखा परीक्षा निष्पादन की जांच के संबंध में 19 अगस्त, 2015 को विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों/बहुपक्षीय/द्विपक्षीय संधियों अथवा करारों का प्रावधान तैयार करने/इसे अनुमोदित करने में विधि एवं न्याय मंत्रालय की भूमिका विषय की जांच करने के संबंध में कार्मिक लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति के साथ 28 सितंबरए 2015 को विदेश मंत्रालय की सुनवाई हुई। अपर सचिव (प्रशासन) ने विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

संसद के बजट सत्र 2015 के दौरान विदेश मंत्रालय ने भारत–बांग्लादेश भू–सीमा करार से संबंधित विधेयक पेश किया, जिसे संविधान (100वां संशोधन) विधेयक, 2015 कहा गया। इस विधेयक पर विचार किया गया और राज्यसभा में 6 मई और 11 मई, 2015 को तथा लोकसभा में 7 मई, 2015 को इसे पारित किया गया।

समन्वय प्रभाग

समन्वय प्रभाग राज्यपालों, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, केंद्रीय मंत्रियों तथा राज्य सरकारों के मंत्रियों, संसद सदस्यों, राज्य विधानसभा सदस्यों, न्यायपालिका के सदस्यों, सरकारी अधिकारियों आदि की विदेश यात्रा हेतु राजनीतिक दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रदान करने संबंधी सभी प्रस्तावों पर कार्रवाई करता है। राजनीतिक अनापत्ति विदेश मंत्रालय द्वारा दी जाती है और यह अनापत्ति सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों, प्रस्तावित दौरों/बैठकों के राजनीतिक तथा कार्यात्मक औचित्य तथा संबंधित भारतीय मिशनों/केंद्रों की अनुशंसाओं पर विचार करने के बाद दी जाती है। अप्रैल 2015–जनवरी 2016 के दौरान समन्वय अनुभाग ने ऐसी यात्राओं के लिए 1966 राजनीतिक अनापत्ति प्रदान की।

प्रभाग विदेशी अनिर्धारित सैन्य उड़ानों तथा विदेशी नौसैनिक जहाजों की यात्रा हेतु राजनयिक अनापत्ति प्रदान करने से संबंधित कार्य का भी संचालन करता है। अप्रैल 2015–जनवरी 2016 के दौरान अनुभाग ने विदेशी अनिर्धारित सैन्य उड़ानों के लिए 416

अनापत्तियां और विदेशी नौसैनिक जहाजों की यात्राओं हेतु 46 अनापत्तियां जारी कीं।

समन्वय प्रभाग ने विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भारतीय स्पोर्टस टीमों और खिलाड़ियों की भागीदारी तथा जनवरी 2016 में विदेशी खिलाड़ियों और टीमों की यात्राओं हेतु अनुमोदन को प्रक्रियाबद्ध किया।

प्रभाग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनार, कार्यशालाओं आदि के आयोजन के लिए, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (1885) के तहत एमेच्योर डब्ल्यू/टी लाइसेंस प्रदान करने, नाम/प्रतीक पंजीकरण के लिए मंजूरी और विदेशों में स्थित भारत–विदेशी सांस्कृतिक दोस्ती और सांस्कृतिक संस्थाओं को सहायता अनुदान देने के लिए भी अनापत्ति प्रदान के लिए अनुरोध की जांच करता है। अप्रैल 2015–जनवरी 2016 के दौरान, प्रभाग भारत में 710 सम्मेलनों/संगोष्ठियों आदि के लिए मंजूरी जारी की गई। इसके अलावा, प्रशिक्षण/अनुसंधान के लिए विदेशी विद्वानों के आगामी दौरे के लिए 88 अनुरोध को प्रक्रियाबद्ध किया गया।

समन्वय प्रभाग विदेशी नागरिकों को पद्म पुरस्कार देने से संबंधित कार्य का समन्वय करता है। विदेश स्थित समन्वय प्रभाग द्वारा भारतीय मिशनों/केन्द्रों से नामांकन प्राप्त किए जाते हैं और मंत्रालय की सिफारिशें गृह मंत्रालय को संसूचित की जाती हैं।

समन्वय अनुभाग द्वारा आतंकवाद विरोध दिवस (21 मई), सद्भावना दिवस (20 अगस्त), कौमी एकता दिवस (19–25 नवंबर) और संविधान दिवस (26 नवंबर) भी मनाया जाता है।

समन्वय प्रभाग ने शिकायत निवारण कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं की समीक्षा विषय पर प्रधानमंत्री के मासिक प्रगति वीडियो कांफ्रेंस में मंत्रालय की भागीदारी का भी समन्वय किया। इसने मंत्रिमंडल सचिवालय की ई–समीक्षा वेबसाइट के संबंध में मंत्रालय के उत्तर का भी समन्वय किया। समन्वय प्रभाग ने मंत्रिमंडल की टिप्पणी के मसौदे तथा संसद से संबंधित कार्य पर मंत्रालय की इनपुट को भी प्रक्रियाबद्ध किया जहां पर ये इन्पुट्स मंत्रालय में कई प्रभागों से एकत्र किया जाना अपेक्षित था।

शिक्षा

शिक्षा अनुभाग द्वारा 57 मित्र पड़ोसी और विकासशील देशों से भारत में विभिन्न केंद्रीय संस्थानों/कॉलेजों में मेडिसिन एवं बैचलर ऑफ सर्जरी (एमबीबीएस), बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस), बी इंजीनियरिंग, बी फार्मेसी पाठ्यक्रम के स्नातक के लिए मांगे गए आवेदनों के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन इस मंत्रालय के आबंटित सीटों के प्रति स्व वित्त पोषण योजना में विदेशी छात्रों के चयन, नामांकन, दाखिले के विषय में कार्य किया जाता है। वैकल्पिक प्रशिक्षण/प्रेक्षकता/अनुसंधान सहित इंजीनियरिंग, चिकित्सा, नर्सिंग और अन्य तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में संस्थाओं में पहले से ही भारत में अध्ययनरत विदेशी छात्रों के संबंध में सरकार में राजनीतिक मंजूरी के मामलों पर भारत सरकार की नोडल मंत्रालयों से संपर्क करने पर भी कार्रवाई की जाती है।

अप्रैल–नवंबर 2015 की अवधि के दौरान नामित सीटों के चयन के लिए शिक्षा अनुभाग में संसाधित/प्राप्त किए गए विदेशी नागरिकों के आवेदनों के संबंध में विवरण नीचे दिए गए हैं।

i) मिशनों/केंद्रों से नामांकन/चयन हेतु 33 एमबीबीएस सीटों के लिए 58 आवेदन प्राप्त हुए थे और 2 बीडीएस सीटों के लिए नामांकन/चयन के लिए दो आवेदन प्राप्त हुए थे।

ii) बी. इंजीनियरिंग सीटों के विषय में नामांकन/चयन हेतु 87 आवेदन और बी. फार्मेसी सीटों के लिए पांच आवेदन प्राप्त हुए थे।

iii) चिकित्सा विज्ञान संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी में पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए 5 सीटों के संबंध में नामांकन/चयन के लिए 17 आवेदन प्राप्त हुए थे।

अनुभाग ने अप्रैल–नवंबर 2015 के दौरान, विदेशी छात्रों/नागरिकों के वैकल्पिक प्रशिक्षण/प्रेक्षकता/अनुसंधान/उनके परीक्षा में शामिल होने आदि के लिए 290 मामलों के लिए राजनीतिक मंजूरी का कार्य संभाला।

■ ■

विदेश प्रचार एवं लोक कूटनीतिक प्रभाग

28

सरकार की परिवर्तनकारी कूटनीति के एक वर्ष की विभिन्न गतिविधियों को विदेश प्रचार और लोक कूटनीति प्रभाग (एक्सपीडी) के माध्यम से परिलक्षित किया गया। प्रभाग ने अपने निर्धारित अधिदेश के अनुसार प्रभावी ढंग से विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय मामलों के मुद्दों पर भारत की स्थिति स्पष्ट करना जारी रखा। इसे वीवीआईपी दौरे के प्रेस कवरेज मीडिया से नियमित रूप से और विशेष ब्रीफिंग, समय पर जारी प्रेस वक्तव्यों और विज्ञप्तियों के साथ–साथ भारतीय और विदेशी पत्रकारों के लिए परिचय दौरा की सुविधा के माध्यम से प्राप्त किया गया था। इस प्रभाग ने विशेषकर विभिन्न सामाजिक मीडिया मंचों के साथ–साथ 'भारत की कहानी' के अद्वितीय पहलुओं पर फिल्मों और प्रकाशनों के माध्यम से अपने लोक राजनय पहलकदमियों का प्रसार किया है। इन प्रयासों ने मंत्रालय और सरकार की विदेश नीति के बारे में दुनिया में भारत के कद में वृद्धि करते हुए ठोस परिणामों के लिए अग्रणी और प्रभावी रूप से जागरूकता पैदा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रेस कवरेज

एक्सपीडी प्रभाग ने राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की विदेश यात्राओं के दौरान उपयुक्त मीडिया कवरेज सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित मीडिया केन्द्रों की स्थापना और संचालन, मीडिया ब्रीफिंग के आयोजन और इसके उपयुक्त मीडिया कवरेज सुनिश्चित करने सहित मीडिया के जाने की लॉजिस्टिकल व्यवस्था की।

प्रभाग ने वैश्विक नेताओं और अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के भारत दौरों की उपयुक्त मीडिया कवरेज में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

शिखर वार्ताएं / सम्मेलन और आउटरीच कवरेज

प्रभाग ने जयपुर में (अगस्त, 2015) भारत–प्रशांत द्वीप देशों के फोरम (एफआईपीआईसी) का शिखर सम्मेलन, भोपाल में (सितंबर 2015) 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन और (अक्टूबर 2015) में तीसरा भारत–अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन और (फरवरी 2016) को 8वीं दिल्ली वार्ता के कवरेज की सफलतापूर्वक व्यवस्था की। एक्सपीडी प्रभाग ने 9 जनवरी 2016 को प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन किया।

सरकार के प्रयास प्रचारित करना

(क) मई 2015 में सरकार का पहला वर्ष के पूरा होने पर, प्रभाग ने 'परिवर्तनकारी कूटनीति' शीर्षक से एक विस्तृत पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें विदेश नीति की गतिविधियों में मुख्य उपलब्धियों की रूपरेखा दी गई है। यह एक छोटे से वीडियो के साथ है, जिसमें मुख्य बातों को शामिल किया गया। विदेश मंत्री ने एक व्यापक पत्रकार सम्मेलन के दौरान पुस्तिका का शुभारंभ किया जिसमें उन्होंने सरकार की विदेश नीति पहल पर विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए।

(ख) संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को योग अंतरराष्ट्रीय दिवस (आईडीवाई) के रूप में घोषणा करने के फलस्वरूप, एक्सपी प्रभाग ने लाइव स्ट्रीमिंग घटनाओं और वास्तविक समय में सामाजिक मीडिया अद्यतन के साथ 192 देशों में दुनिया भर में आयोजन समारोह का समन्वय किया। पूर्व से पश्चिम तक गतिविधियों का शुभारंभ भारत में मुख्य समारोह के साथ किया गया जिसमें संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय और टाइम्स स्क्वायरए न्यूयॉर्क विशेष थे। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर एक विशेष आईडीवाई पेज स्थापित किया गया था जिसमें तस्वीरें एकत्र की गईं और आयोजनों को दर्शाया दिया।

(ग) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में, भारत के संविधान के निर्माण के लिए उनके योगदान को दर्शाते हुए एक्स पी प्रभाग ने एक विशेष पेज बनाया। उनके लेखन और भाषणों का एक संग्रह विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। इसके अलावा, डॉ. अम्बेडकर के जीवन पर 2 प्रसिद्ध फिल्में और श्याम बेनेगल द्वारा भारत के संविधान पर बनी 10 डीवीडी का एक सेट विदेशों में हमारे मिशनों/केंद्रों में स्क्रीनिंग के लिए भेजा गया था। डॉ अम्बेडकर पर 23 किताबें विदेशों में हमारे मिशनों/केंद्रों के उपयोग के लिए भी चयनित किया गया।

(घ) एक्सपी प्रभाग द्वारा 2015 के दौरान विदेश नीति के मोर्चे पर विभिन्न उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के लिए **'डिप्लोमेसी फॉर डेवलपमेंट : फ्रॉम एस्पिरेशंस टू अचीवमेंट्स'** शीर्षक से एक पुस्तिका निकाली गई, तथा लगभग 13 महत्वपूर्ण विषयों में विकास और राष्ट्रीय पुनरुत्थान में कूटनीति के अंतरंग ब्योरे का प्रदर्शन भी किया किया।

(ङ) प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान की उपलब्धियों और भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन की उपलब्धियों और महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डालने के लिए विशेष ई–पुस्तकों का सृजन किया गया है। इन्हें हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया, जो यह समझनू में इसके अमूल्य संसाधन सिद्ध हुए कि यात्रा और दस्तावेज़ के परिणामों को कैसे समझा जाए।

(च) भारतीय युवाओं के बीच भारतीय विदेश नीति के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से, एक्सपीडी प्रभाग ने भारत की विदेश नीति से संबंधित सात विषयों पर अपने सभी 25 क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के माध्यम से एक अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। नई दिल्ली में 10 दिसंबर 2016 को माननीय विदेश मंत्री ने प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए।

एक्सपीडी प्रभाग विदेश मंत्रालय और मीडिया के बीच संपर्ककर्ता के रूप में कार्य करता है। मीडिया के साथ जानकारी साझा करने के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं या महत्वपूर्ण राजनयिक चुनौतियों के साथ–साथ वीवीआईपी दौरों पर विशेष ब्रीफिंग सहित नियमित प्रेस ब्रीफिंग आयोजित किए गए। वास्तविक समय के आधार पर सूचना का तेजी से और समय पर प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करने के लिए एसएमएस अलर्ट, यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग, भाषणों की होस्टिंग, वेबसाइट के साउंड क्लाउड पेज पर ब्रीफिंग जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल जारी है।

डिजिटल आउटरीच

चूँकि एक्सपीडी प्रभाग सामाजिक और डिजिटल मीडिया आउटरीच के लिए मंत्रालय का नोडल प्रभाग है, इसलिए सूचना के प्रसार के प्रयासों को बढ़ाने के लिए नई सुविधाओं को लगातार जोड़ा जा रहा है। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट जिसे 2015 में वेब रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था, भारत सरकार के मानकों के अनुसार बनाई गई है और मंत्रालय की गतिविधियों के बारे में जानकारी और संसाधनों की एक गतिशील स्रोत बनी हुई है। मंत्रालय की फ्रेंचए स्पेनिश और अरबी वेबसाइटों को भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। एक्सपीडी प्रभाग यह भी सुनिश्चित करता है कि कांउसलर, पासपोर्ट और वीजा प्रभाग द्वारा नए प्रयासों का पर्याप्त रूप से प्रचार किया जाए और इस कार्य के लिए एक समर्पित पृष्ठ है जिसे लगातार अद्यतन किया जाता है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म

एकसमान डिजिटल पहचान कायम करने के बाद, विदेश मंत्रालय (एमईए) की सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। केवल मंत्रालय की कुल फॉलोइंग, विदेश स्थित मिशनों और पोस्ट को छोड़कर, लगभग 3.8 मिलियन है। इसके परिणामस्वरूप, ट्विटर पर इसके पोस्ट की औसत मासिक पहुंच 17.5 मिलियन से अधिक है, जबकि फेसबुक पर मासिक पहुंच 15 मिलियन से ऊपर है।

(क) भारतीय कूटनीति फेसबुक पेज और विदेश मंत्रालय भारत फेसबुक पेज के फॉलोवर्स में काफी वृद्धि हुई है और आज इनकी संख्या क्रमशः 8,17,513 और 11,91,214 तक जा पहुँची है।

(ख) उनके इनर सर्कल के लिए विदेश मंत्रालय के भारत जी + पेज से जुड़ने वाले लोगों की संख्या में तेजी से विस्तार हो रहा है और आंकड़ा 7,83,768 पार कर चुका है। इसी तरह, भारतीय कूटनीति ट्विटर अकाउंट (@IndianDiplomacy) और आधिकारिक प्रवक्ता ट्विटर अकाउंट (@MEAIndia) दोनों के फोलोवर्स की संख्या कुल मिलाकर 10,32,930 है। इन प्लेटफार्मों को भारत और भारत की विदेश नीति पर ट्वीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

(ग) भारतीय राजनय यू ट्यूब चैनल (www.youtube.com/user/Indiandiplomacy) पर प्रभाग द्वारा जारी किए गए संपूर्ण वृत्तचित्रों तथा फिल्मों के दर्शकों की संख्या भी बढ़कर 63,81,147 तक पहुँच गई है।

(घ) फ़्लिकर अकाउंट (http://www.flickr.com/photos/meaindia) मंत्रालय के सभी प्रमुख आयोजनों की तस्वीरों के एक उपयोगी और लोकप्रिय ऑनलाइन रिपोजिटरी के रूप में लगातार सेवाएं दे रहा है।

विदेश नीति में सोशल मीडिया की भूमिका का विस्तार करने के अपने पहल के हिस्से के रूप में, मंत्रालय ने मेजबान देशों की स्थानीय आबादी के साथ–साथ भारतीय समुदाय के साथ सीधा संवाद करने तथा ऑनलाइन स्पेस में प्रवेश करने के लिए विदेशों में स्थित हमारे मिशनों व केंद्रों को तैयार कर लिया है।

आज दुनिया भर में लगभग 149 भारतीय मिशनों की फेसबुक पर उपस्थिति (95 प्रतिशत) है। फेसबुक के साथ कार्य करते हुए, मंत्रालय ने इनमें से अधिकांश अकाउंट को सत्यापित किया है और एक शीर्षक के तहत उन्हें मानकीकृत किया हैए उदाहरण के लिएए 'अमेरिका में भारत', 'आयरलैंड में भारत'। इन अकाउंटों का उपयोग नियमित रूप से भारत के बारे में सॉफ्ट स्टोरी, निवेश के चैनलों, दूतावास की गतिविधियों के बारे में जानकारी डालने और प्रमुख कार्यक्रमों जैसे कि 'मेक इन इंडिया' और ''डिजिटल इंडिया'' में भागीदारी के लिए किया जाता है।। 90 से अधिक मिशन और पोस्ट ट्विटर पर भी सक्रिय हैं। मंत्रालय ट्विटर पर इनके नामों के मानकीकरण करने और साथ ही प्रामाणिक रूप में खातों को सत्यापित करने के लिए काम कर रहा है।

दृश्य आउटरीच – फिल्म और वृत्तचित्र

विदेश में भारत की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने के उद्देश्य से प्रभाग लघु फिल्मों को तैयार करता है जो विदेशी टीवी चैनलों पर स्क्रीनिंग और प्रसारण के लिए विदेश स्थित भारतीय मिशनों को भेजी जाती हैं। अवधि के दौरान पंद्रह वृत्तचित्र फिल्में पूरी की गईं जिसमें शामिल हैं–नवरोजः द न्यूडे,– ओशन ऑफ मेलोडी पार्ट 1 और 2, अंदर और बाहर एक ही समय मेंः साझा इतिहासः भारत में फ्रांस फ्रांस में भारत, भारतः बुद्ध भूमि पर बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव (वेसक), योगः प्रकृति के साथ सद्भाव, कालीमिर्च सफेद कालीमिर्चः खाइयों की कहानियां, जापान में भारतीय देवताओं की पूजाए ऑपरेशन राहत, मूनस्ट्रक, अदूर : फ्रेम्स में एक यात्राए पद्म भूषण साइचिरो मिसुमीः भारत–जापान का वास्तुकार संबंधए भारत गंतव्य, नव रसायनविद् – विशाल भारतीय जुगाड़, एकमात्र लक्ष्य।

21 जून 2015 को पहले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, प्रभाग ने – ''योगः प्रकृति के साथ सद्भाव'' जारी की जिसे चार टीवी चैनलों पर प्रसारित किया गया था। फिल्म छह विदेशी भाषाओं में डब की गई थी।

प्रभाग ने एक ट्यूनीशियाई फिल्म निर्माता द्वारा निर्मित एक अरबी फिल्म 'जीरो' का प्रीमियर किया जो अंक ''शून्य (0)'' के बारे में है जिसका प्रारंभ भारत से हुआ है ।

भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (आईएएफएस) के लिए दो फिल्मों ''भारत–अफ्रीका भागीदारी के लिए प्रगति श और ''एकमात्र लक्ष्य'' को विशेष रूप से जारी किया गया।

प्रभाग ने एनडीटीवी के साथ एक नए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है और क्रमशः एनडीटीवी, डीडी नेशनल, डीडी इंडिया और डीडी भारती पर अपने वृत्तचित्र के प्रसारण के लिए डीडी भारती के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। डिस्कवरी चैनल ने तीन महीने की अवधि के लिए एक्सपीडी के वृत्तचित्र में से एक ''जय हो'' का प्रसारण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया।

इस अवधि के दौरान वृत्तचित्र फिल्में '6 की शक्ति", 'जलसा – रिकार्ड बनाती भारतीय महिलाएं", 'भारत की समुद्री कथा" ''भारतीय महिला (स्त्री शक्ति)", 'एक समग्र संस्कृति–भारत की हिंदी फिल्म उद्योग में प्रवास" पर्यावरण और सतत विकास पर श्भारत का दृष्टिकोण", ''अंतरराष्ट्रीय योग दिवस" और ''एक भारतीय संदर्श से जलवायु परिवर्तन के आसपास बहस" भी जारी की गई।

सार्वजनिक पहुँच

2010 में अपनी स्थापना के बाद से विशिष्ट व्याख्यान श्रृंखला के शीर्ष के तहत प्रभाग के सार्वजनिक आउटरीच पहल कालगातार विस्तार हुआ है। इस व्याख्यान श्रृंखला ने देश भर के अनेक प्रमुख शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं के अलावा 38 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को भी अपने दायरे में ले लिया है। इस कार्यक्रम में अब तक देश भर में 50 से अधिक संस्थानों को भारत विदेश नीति के बारे में समान्य जनता विशेष रूप से युवाओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शामिल किया गया। इस व्याख्यान श्रृंखला में बढ़ती रुचि भारत भर की कई अन्य संस्थाओं से प्राप्त अनुरोधों की बढ़ती संख्या और आयोजित व्याख्यान की संख्या कई गुना बढ़ने से स्पष्ट है। केवल इसी वर्ष में, 45 व्याख्यानों का आयोजन पहले ही किया जा चुका है।

भारत संदर्श, मंत्रालय की प्रमुख पत्रिका अब 2 और अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में उपलब्ध है अर्थात चीनी और जापानी। भारत संदर्श अब 16 भाषाओं में उपलब्ध हैं–पुर्तगाली, रूसी, सिंहली हिन्दी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इंडोनेशियाई, इतालवी, पश्तो, फारसी, जर्मन, स्पेनिश, तमिल, चीनी और जापानी। इसे www. indiaperspectives.in पर ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और यह मैगजेटर और आईएसएसयूयू के माध्यम से कई डिजिटल प्लेटफार्मों पर उपलब्ध है।

इस अवधि के दौरान अनेक कॉफी टेबल पुस्तकों को जारी किया गया जिनमें प्रथम विश्व युद्ध, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस और तीसरे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के समारोह में भारत की भूमिका शामिल हैं। इनमें उन कुछेक प्रमुख सॉफ्ट पावर संभावनाओं और भागीदारी को प्रतिबिंबित किया गया है जिसमें मंत्रालय ने भागीदारी की है। इस अवधि के दौरान 35वीं पुस्तक समिति में चयनित पुस्तकों को विदेश स्थित भारतीय मिशनों को भेजा गया था।

एक्सपीडी प्रभाग और नेशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी) के बीच 25 चीनी क्लासिक पुस्तकों का अनुवाद हिन्दी में करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए थे। इस अवधि के दौरान कम से कम एक क्लासिक पुस्तक का अनुवाद होने की उम्मीद है।

परिचय दौरे

मित्र देशों के बीच भारत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और मीडिया आदान–प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए, एक्सपीडी प्रभाग ने विदेशी और भारतीय पत्रकारों के परिचय दौरों का आयोजन किया। इस अवधि के दौरान भूटान, बेलारूस, थाईलैंड, अफगानिस्तान, वियतनाम, प्रशांत द्वीप देशों, मध्य एशियाई देशों और अफ्रीकी देशों से पत्रकारों का दौरा आयोजित किया गया।

द्विपक्षीय मीडिया फोरम

तीसरा भारत–अफ्रीका संपादक मंच का आयोजन नई दिल्ली में 25 अक्तूबर, 2015 को आयोजित किया गया और इसमें अफ्रीकी देशों के साथ–साथ वरिष्ठ भारतीय पत्रकारों ने भाग लिया। माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने इस मंच का उद्घाटन किया।

■ ■

29

विदेश सेवा संस्थान

प्रशिक्षु अधिकारी

विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई) ने भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के 2013 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों (ओटी) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। 2013 बैच के पच्चीस आईएफएस अधिकारी प्रशिक्षुओं ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया और 04 जून, 2015 को एफएसआई में उनका विदाई समारोह आयोजित किया गया। विदेश मंत्री, श्रीमती सुषमा स्वराज इस आयोजन की मुख्य अतिथि थीं। इस अवसर पर, 2013 बैच के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु अधिकारी के लिए विदेश मंत्रालय का स्वर्ण पदक, सर्वोत्तम शोध प्रबंध के लिए राजदूत बिमल सान्याल स्मृति मेडल और सर्वोत्तम खिलाड़ी ट्रोफी से योग्य प्रशिक्षु अधिकारी को पुरस्कृत किया गया।

2014 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने दिसंबर, 2014 में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक राष्ट्रीय अकादमी (एलबीएसएनएए) में अपना फाउंडेशन कोर्स पूरा करने के बाद नौ–महीने का दीर्घावधिक प्रशिक्षण पूरा किया, जो सितंबर 2015 में समाप्त हुआ। इस प्रशिक्षण में अंतरराष्ट्रीय संबंध और विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय कानून रक्षा एवं सुरक्षा, व्यापार और आर्थिक राजनय, हाइड्रो डिप्लोमेसी, मीडिया संबंध, सांस्कृतिक राजनय, सूचना का अधिकार, सामाजिक विकास, अल्पसंख्यक और मानव अधिकार मामले आदि जैसे विषय शामिल हैं। इस कार्यक्रम में प्रशासन, स्थापना, लेखा, प्रोटोकॉल, कॉन्सुलर मामले, प्रतिवेदन कौशल, राजभाषा नीति, विदेश प्रचार, लोक राजनय, प्रतिनिधित्व कौशल तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत पर मॉड्यूल भी शामिल है।

प्रशिक्षण, अंतः क्रियात्मक व्याख्यान, सामूहिक चर्चा, दृष्टांत अध्ययन, भूमिका का निर्वहन तथा अनुकरण और सृजनात्मक सोच को विकसित करने के लिए विषयात्मक मामलों पर प्रस्तुतिकरण के माध्यम से दिया जाता है। प्रभावी संवाद कौशल विकसित करने के लिए सार्वजनिक संबोधन और कॉन्सुलर कार्य पर विशेष मॉड्यूल भी इसमें शामिल थे। प्रबंधन और आर्थिक मामलों पर प्रवीणता विकसित करने के लिए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से एक सप्ताह का पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। 'जलवायु परिवर्तन वार्ता' विषय पर दो दिवसीय मॉड्यूल प्रशिक्षु अधिकारी 'प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा रहे, जिसे विज्ञान और पर्यावरण केंद्र द्वारा आयोजित किया गया। उनके कामकाज और जिम्मेदारियों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण मॉड्यूल कैबिनेट सचिवालय द्वारा आयोजित किया गया था।

प्रशिक्षुओं अधिकारी को विदेश स्थित भारतीय मिशनों के कार्य से परिचित कराने हेतु उन्हें सात अलग–अलग समूहों में दो सप्ताह की अवधि के लिए पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान और बांग्लादेश स्थित भारतीय मिशनों में भेजा गया।

प्रशिक्षु अधिकारियों को भारतीय थल सेना, नौसेना, वायु सेना के साथ कार्य करने तथा इसके बाद देश की सम्पन्न सांस्कृतिक विरासत, विविधता, तथा आर्थिक और पर्यटन संभावनाओं का नजदीकी से परिचय कराने हेतु तीन सप्ताह के 'भारत दर्शन' के लिए भेजा गया।

2015 की शुरुआत के साथ, एफएसआई ने सरकार के निर्देश के तहत, प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण के भाग के रूप में राज्य विशेषज्ञता कार्यक्रम शुरू किया है। इस प्रकार, सामान्य जिले के साथ जोड़ने के स्थान पर, प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों की एक महीने तक राज्य परिचय यात्रा/ जिले के साथ जुड़ाव शामिल किया गया। इसमें प्रशिक्षु अधिकारियों को राज्यों की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटन और राज्य के आर्थिक स्थिति, सामान्य जन स्तर पर प्रशासन तथा कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी और जिला प्रशासन के बारे में सीखने का अवसर मिला। वापसी पर, प्रशिक्षु अधिकारियों ने राज्य विशेषज्ञता पर अपना शोध प्रस्तुत किया। उन्होंने एफएसआई संकाय की उपस्थिति में भारत दर्शन पर एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी। एफएसआई द्वारा प्रशिक्षु अधिकारियों के भारत दर्शन के दौरान ली गई तस्वीरों की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिनका प्रसिद्ध फोटोग्राफर और बौद्ध विद्वान श्री बेनाय बहल द्वारा निर्णय किया गया। सितंबर 2015 में एफएसआई में अपना प्रशिक्षण पूरा होने पर 2014 को बैच में मंत्रालय में डेस्क अटैचमेंट पर तैनात किया गया।

4 जून 2015 को आयोजित 2013 बैच के विदाई समारोह के दौरान 2013 और 2014 के भारतीय विदेश सेवा बैच के अधिकारी

वर्ष 2015 बैच के आई एफ एस प्रशिक्षु अधिकारियों ने एल बी एस एन ए ए मसूरी में फाउंडेशन कोर्स पूरा किया। एफ एस आई में 33 प्रशिक्षु अधिकारियों ने (2015 बैच के 32 तथा 2014 बैच के 1) 21 दिसंबर 2015 से अपना प्रशिक्षण आरंभ किया।

मध्य–कैरियर प्रशिक्षण :

एफ एस आई ने 1999 और 2000 बैच के ग्रेड– IV अधिकारियों (निदेशक–स्तर) के लिए तीन सप्ताह का एफ एस आई, आईआईएम, अहमदाबाद और राज्य विशेषज्ञता दौरे में समान रूप से वितरित अवधि का 30 नवंबर से 18 दिसंबर, 2015 तक मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमसीटीपी) फेज–II आयोजित किया।

एम सी टी पी–। (कैरियर के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम फैज–।) का एक लचीला कार्यक्रम उन अधिकारियों के लिए है जो कि अपनी पहली बार की विदेशी तैनाती पूरी करके मुख्यालय वापस आते हैं। (आम तौर पर, उनकी बेल्ट के अंतर्गत 5 से 8 वर्षों की सेवा) विदेश मंत्रालय के प्रशासन के भी विचाराधीन है। इसमें भाग लेने वाले अधिकारियों से अपेक्षा होगी कि अधिकारी इस प्रशिक्षण को अपनी गति और सुविधा के अनुसार पूरा कर सकें।

अन्य प्रशिक्षण मॉड्यूलः

अधिकारियों के व्यापक परिचय और विचारों के विस्तार हेतु आईएफएस, प्रशिक्षु अधिकारियों, विदेश मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों के साथ साथ यूएस/डीएस स्तर के आईएफएस अधिकारियों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें व्यापार और आर्थिक कूटनीति, मीडिया प्रबंधन, हाइड्रो कूटनीति के विषय और अन्य अनेक विषय शामिल थे। विदेश में तैनात किए गए अधिकारियों की सुविधा के लिए वार्ता / व्याख्यान, वेबिनार द्वारा साझा किया गया जिनमें से अनेक इनमें भी शामिल हुए।

अंतर सेवा प्रशिक्षण

मंत्रिमंडल सचिवालय के अधिकारियों के लिए अप्रैल 2015 में विदेश नीति पर एक अभिविन्यास कैप्सूल आयोजित किया गया। विदेश स्थित मिशनों में भारतीय वाणिज्यिक प्रतिनिधि के लिए भी आर्थिक और वाणिज्यिक प्रशिक्षण पर एक अभिविन्यास कैप्सूल 11–12 जून 2015 को आयोजित किया गया था। कुछ विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने भी कैप्सूल में भाग लिया।

भारतीय विदेश सेवा के ग्रुप 'ख' के लिए प्रशिक्षण

अनुभाग अधिकारियों/निजी सचिवों, सहायकों / वैयक्तिक सहायकों तथा लिपिकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पुर्ननिर्मित किया गया। भारत सरकार के नियमों तथा कार्यालय प्रक्रिया तथा विदेश मंत्रालय के विशिष्ट विषय जैसे आई एफ एस (पी एल सी ए) नियम, आई एम ए एस (एकीकृत मिशन लेखा प्रणाली), प्रोटोकाल, आर्थिक एवं वाणिज्यिक कार्य, कॉन्सुलर, पासपोर्ट तथा वीजा कार्य आदि के मौजूदा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अलावा, सूचना का अधिकार (आरटीआई), व्यक्तित्व विकास और मूल कंप्यूटर और आई टी कौशल, हिंदी का उपयोग, वेबसाइट प्रबंधन, वित्त एवं बजट कार्य, विदेश मंत्रालय सिंहावलोकन, विदेश नीति, व्यापार

संवर्धन, सांस्कृतिक राजनय, मीडिया हैंडलिंग, वी वी आई पी यात्राएं आदि के क्षेत्रों में नया प्रशिक्षण कैप्सूल प्रारंभ किया गया। विदेश मंत्रालय के एम टी एस स्टाफ और ड्राइवरों के लिए पहली बार दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

विदेश स्थित समकक्ष विदेशी राजदूतावास / राजनयिक संस्थानों के साथ संयोजन

संकायाध्यक्ष, एफएसआई ने 23–28 अगस्त 2015 के बीच प्रांतीय एफएओ पर बातचीत के लिए हांगकांग और शंघाई तथा चीनी विदेश मंत्रालय के कार्यालय से बातचीत के लिए बीजिंग का भी दौरा किया। संकायाध्यक्ष ने 42वीं वार्षिक संकायाध्यक्ष की बैठक और राजनयिक अकादमियों के निदेशकों और अंतरराष्ट्रीय संबंध संस्थानों द्वारा आयोजित राजनयिक प्रशिक्षण पर इंटरनेशनल फोरम में भाग लेने के 23–25 सितम्बर 2015 के बीच पोलैंड का भी दौरा किया।

नेपाल सरकार के विदेश मंत्रालय के सलाहकार, महामहिम श्री शंभू राम शिमखाडा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 7 जुलाई 2015 को एफएसआई का दौरा किया। आसियान देशों के छात्रों के 110 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल और सिंगापुर के विदेश सेवा के अधिकारियों के एक 34 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने क्रमशः 11 और 14 सितंबर, 2015 को एफएसआई का दौरा किया। इसके बाद, आसियान देशों के छात्रों के एक 96 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 30 अक्टूबर 2015 को एफएसआई का दौरा किया। वर्ष के दौरान अफगानिस्तान, आर्मीनिया, सोमालिया, इंडोनेशिया, स्पेन और चेक गणराज्य सहित नई दिल्ली में स्थित कई राजदूतों ने एफएसआई संकायाध्यक्ष के साथ मुलाकात की। सुश्री किरण परवेज, संयुक्त राज्य विदेश सेवा संस्थान में नवीन दक्षिण और मध्य एशिया के अध्यक्ष, ने दो विदेश सेवा संस्थानों के बीच सहयोग के तौर–तरीकों पर नवंबर 2015 में संकायाध्यक्ष और एफएसआई के अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत की।

एफएसआई ने वर्ष 2015 के माध्यम से विदेशी राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का भी आयोजन किया जो नीचे सूचीबद्ध हैं:

विदेशी राजनयिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

- विदेशी राजनयिकों के लिए 59वें व्यावसायिक पाठ्यक्रम 23 मार्च से 17 अप्रैल 2015 को आयोजित किया गया था, जिसमें 26 विदेशी राजनयिकों ने भाग लिया था य
- प्रशांत द्वीप के देशों के राजनयिकों के लिए नादी (फिजी) और पलाउ दो स्थानों में विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम क्रमशः 4.8 और 11.15 मई 2015 को आयोजित किया गया था और फिजी, कुक आइलैंड्स, किरिबाती, टोंगा, तुवालु, नौरू, समोआ, वानुअतु, पापुआ न्यू गिनिया, पलाऊ, माइक्रोनेशिया संघीय राज्य और मार्शल द्वीप के 26 राजनयिकों ने इसमें भाग लिया। दो सेवानिवृत्त राजदूतों और एफएसआई के अतिथि संकाय सदस्यों ने इन विदेशी राजनयिकों को प्रशिक्षित करने के लिए नाडी और पलाउ की यात्रा कीय
- विदेशी राजनयिकों के लिए 5 अगस्त से 4 सितम्बर 2015 के बीच 60वें व्यावसायिक पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें 27 विदेशी राजनयिकों ने भाग लिया था
- सोमाली राजनयिकों के लिए 16 सितंबर से 16 अक्टूबर 2015 को एक विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें 20 सोमाली राजनयिकों ने भाग लिया।
- दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के राजनयिकों के लिए 9 वां विशेष पाठ्यक्रम 18 नवंबर

सोमाली राजनयिकों के लिए एफएसआई में विशेष पाठ्यक्रम (16 सितम्बर – 16 अक्टूबर 2015)

से 18 दिसंबर 2015 को आयोजित किया गया जिसमें कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआरए म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम से 19 राजनयिकों ने भाग लिया।

वर्ष 2015 के दौरान एफएसआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए:

- 17 मई 2015 को मंगोलिया के विदेश मंत्रालय की राजनयिक अकादमीय
- 5 जून 2015 को अंतरराष्ट्रीय संबंध संस्थान (आईआईआर) वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालयए सेंट अगस्टीन, त्रिनिदाद गणराज्य और टोबैगोय
- 11 जुलाई 2015 को तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्रालय के अंतरराष्ट्रीय संबंध संस्थानय
- 11 अक्तूबर 2015 को मालदीव विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय, मालदीव गणराज्य सरकार; और
- 11 अक्तूबर 2015 को जार्डन राजनय संस्थानए विदेश मंत्रालय और जॉर्डन हेशमिट किंगडम के प्रवासी।

स्वच्छ भारत अभियान :

2014 में प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किए व्यापक स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ते हुए, एफएसआई ने वर्ष 2015 के दौरान अपने परिसर और आस–पड़ोस की साफ–सफाई सुनिश्चित करने का प्रयास जारी रखा है। एफएसआई ने भी अपनी प्रशिक्षण विषय वस्तु के भाग के रूप में इस संदेश को शामिल किया गया है। आवधिक स्वच्छता तथा जागरूकता अभियानों के आयोजन सहित कार्य योजनाओं पर विचार विमर्श के लिए बेर सराय में स्वच्छ भारत समिति की स्थापना की गई है।

■ ■

30

नालंदा प्रभाग

नालंदा विश्वविद्यालय ने वर्ष के दौरान एक अंतरराष्ट्रीय पहचान स्थापित करते हुए एक अकादमिक उत्कृष्टता संस्थान के रूप में अपनी यात्रा की अच्छी शुरूआत की। ऐतिहासिक अध्ययन स्कूल और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण अध्ययन स्कूल में शिक्षण राजगीर, बिहार में पट्टे पर लिए गए परिसर में सितंबर 2014 में शुरू किया गया और शैक्षणिक वर्ष 2015–16 के दौरान छात्रों की कुल संख्या 62 तक पहुँच गई है।

आगे, विश्वविद्यालय की बौद्ध अध्ययन, स्कूल में शिक्षण प्रारंभ करने की योजना है। दर्शन और तुलनात्मक धर्मों के विषय में अध्यापन बाद में शुरू की जाएगी। विश्वविद्यालय में 2450 छात्रों और 500 संकाय सदस्यों के साथ वर्ष 2021–22 तक पूरी तरह चालू होने पर अध्ययन के कुल सात सदनों की परिकल्पना की गई है। भारत सरकार ने 2021–22 तक इसकी स्थापना के चरण के दौरान राजधानी और नालंदा विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय के लिए 2727 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की।

नालंदा विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप को सुदृढ़ करने के लिए, विदेश मंत्रालय पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) के सदस्य देशों और अन्य देशों से सहयोग लेकर काम कर रहा है। इंडोनेशिया 14 मार्च 2015 को नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला 12वां ईएएस देश बना, जबकि थाईलैंड ने 29 जून 2015 को इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। गैर ईएएस देशों में से श्रीलंका ने 16 फरवरी 2015 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जबकि 9 अक्टूबर 2015 को पुर्तगाल इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला यूरोपीय देश बना। अब तक कुल 17, ईएएस और गैर–ईएएस देशों ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के कानूनों / विनियमों की अधिसूचना की प्रक्रिया को 10 जून 2015 को विश्वविद्यालय के पहले अध्यादेश के साथ आगे बढ़ाया गया था।

राजगीर, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया पर पुरजोर ढंग से विचार किया जा रहा है और उम्मीद है कि अनुबंध प्राप्त होते ही स्थल पर निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा। निर्माण कार्य साढ़े तीन साल के अंदर पूरा होने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय ने मैसर्स आरएसपी आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स, सिंगापुर एवं मैसर्स वास्तुशिल्प कंसल्टेंट्स के साथ सिंगापुर के लोगों द्वारा 10 मिलियन सिंगापुर डॉलर से अधिक राशि के दान से विश्वविद्यालय पुस्तकालय के निर्माण हेतु एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए।

वर्ष 2015 के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पर हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों का विवरण।

क्र. सं.	समझौते का शीर्षक	हस्ताक्षर की तिथि	प्रवेश के लागू होने की तिथि
1	भारत गणराज्य और श्रीलंका गणराज्य के बीच नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पर समझौता ज्ञापन।	16 फरवरी 2015	16 फरवरी 2015
2	भारत गणराज्य और इंडोनेशिया गणराज्य के बीच नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पर समझौता ज्ञापन।	14 मार्च 2015	14 मार्च 2015
3	भारत गणराज्य और थाईलैंड की शाही सरकार के बीच नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पर समझौता ज्ञापन	29 जून 2015	29 जून 2015
4	भारत गणराज्य और पुर्तगाली गणराज्य के बीच नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पर समझौता ज्ञापन	9 अक्टूबर 2015	9 अक्टूबर 2015

31 राजभाषा नीति का कार्यान्वयन और विदेशों में हिंदी का प्रचार–प्रसार

मंत्रालय का मिशनों/केंद्रों के माध्यम से विदेशों में हिंदी के प्रचार–प्रसार का एक सुनियोजित कार्यक्रम है। इस योजना के अंतर्गत हिंदी पाठ्य–पुस्तकों, साहित्यिक और बाल पुस्तकों, हिंदी पत्रिकाओं, हिंदी शिक्षण कंपैक्ट डिस्क (सीडी), कंप्यूटरों और हिंदी में कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर, शब्दकोश आदि सहित हिंदी शिक्षण सामग्री, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य गैर–सरकारी संगठनों (एन जी ओ) को भेजी जाती है। मंत्रालय विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों के माध्यम से हिंदी से संबधित क्रियाकलापों के लिए विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक संस्थानों को सहयोग प्रदान करता है।

मंत्रालय द्वारा हर तीन वर्ष में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाता है। माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज की अध्यक्षता में मंत्रालय द्वारा 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल, मध्य प्रदेश में 10–12 सितंबर, 2015 को आयोजित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। सम्मेलन के उद्घाटन और समापन समारोहों में विदेशी प्रतिनिधियों की एक बड़ी संख्या सहित 7000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। सम्मेलन का मुख्य विषय ''हिंदी जगतः विस्तार एवं संभावना'' था। मुख्य विषय के आधार पर, बारह उप विषयों पर समानांतर चर्चाएं आयोजित की गईं। विश्व हिंदी सम्मेलन के अलावा, मंत्रालय द्वारा हिंदी के प्रचार–प्रसार और विदेशों में भारतीय संस्कृति में शामिल स्थानीय आयोजकों के सहयोग से विदेश स्थित हमारे मिशनों के माध्यम से क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है।

हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए भारत और मॉरीशस के बीच एक द्विपक्षीय करार के तहत मॉरीशस

भोपाल, मध्य प्रदेश में 10–12 सितंबर, 2015 को आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज तथा अन्य गणमान्य हस्तियां।

10 सितंबर, 2015 को आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी स्मारक डाक टिकट जारी करते हुए।

10 सितंबर, 2015 को आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के अवसर पर विराजमान शिष्टमंडल।

में एक विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की गई है। सचिवालय का कार्य विदेश मंत्रालय तथा मॉरीशस सरकार में उनके समकक्षी के सहयोग से किया जाता है।

मंत्रालय विदेशी विद्यार्थियों को केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा में हिंदी अध्ययन करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने से संबंधित कार्य में सहयोग प्रदान करता है। प्रति वर्ष 100 छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रावधान है।

भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को मंत्रालय लगातार उच्च प्राथमिकता देता रहा है। मंत्रालय में हिंदी दिवस के अवसर पर 'हिंदी पखवाड़े' का आयोजन किया गया था। हिंदी दिवस 2015 के अवसर पर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों और साथ ही विदेश स्थित हमारे मिशनों द्वारा विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। इन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों के लिए विशेष अनुदान स्वीकृत किए गए थे। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मुख्यालय के साथ–साथ विदेश स्थित हमारे मिशनों/केंद्रों में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विदेश मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय में एक हिंदी सलाहकार समिति कार्य कर रही है।

संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के आधार पर, विदेश स्थित भारतीय मिशनों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जा रहा है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन में, मंत्रालय राजभाषा विभाग के सहयोग से सरकारी कार्यों में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने हेतु विदेश स्थित भारतीय मिशनों और भारत स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण करता है।

मंत्रालय के तहत आने वाले देहरादूनए रायपुर और शिमला के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों को इस वर्ष से राजभाषा नियमए 1976 के उप नियम 10 (4) के तहत अधिसूचित किया गया है। इस नियम के तहत केवल उन्हीं कार्यालयों को अधिसूचित किया जाता है जहां न्यूनतम 80 प्रतिशत कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाध ाक ज्ञान है।

■ ■

32 भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई सी सी आर) की स्थापना 09 अप्रैल, 1950 को भारत के विदेशी सांस्कृतिक संबंधों को सूत्रबद्ध करने से संबंधित नीतियों का प्रतिपादन और कार्यक्रमों कार्यान्वयन करने से भारत तथा अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों एवं पारस्परिक समझ को बढ़ाने और सुदृढ़ करने और संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध स्थापित करने और विकसित करने तथा इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे उपायों को करने के उद्देश्य से की गई थी। वर्ष 2015 में भा सां सं प ने विदेशों में भारत के प्रति बेहतर समझ बनाने के लिए अनेक व्यापक कार्यक्रमों का आयोजन किया। आई सी सी आर के कार्यकलापों को मुख्यतः इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है; शैक्षिक तथा बौद्धिक; कला तथा संस्कृति एवं अन्य कार्यकलाप।

शैक्षिक तथा बौद्धिक

आई सी सी आर कला और संस्कृति, मानविकी सहित विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों यथा इंजीनियरी, फॉर्मेसी, अकाउन्टेंसी, व्यापार प्रशासन तथा प्रबंधन हेतु विदेशी छात्रों को स्नातक पूर्व, स्नातकोत्तर तथा डॉक्टरल कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत छात्रवृत्तियां प्रदान करती है। शैक्षिक एवं बौद्धिक कार्यकलापों के भाग के रूप में भारत में अध्ययन करने के लिए आई सी सी आर द्वारा विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत 3339 छात्रवृत्ति स्लॉटों की पेशकश की गई।

आई सी सी आर विभिन्न कल्याणकारी उपायों, विशिष्ट भारतीय विद्वानों द्वारा व्याख्यानों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन शिविरों का आयोजन करती है ताकि विदेशी छात्रवृत्तिधारकों को भारत को जानने तथा इसकी समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत तथा इस देश की औद्योगिक और वैज्ञानिक क्षमताओं से परिचित होने का अवसर मिल सके। इन कल्याणकारी कार्यकलापों के एक भाग के रूप में, परिषद ने मई–जून 2015 के दौरान 12 ग्रीष्मकालीन शिविर एवं दिसम्बर 215 से फरवरी 2016 के दौरान 12 शीतकालीन शिविर आयोजित किए। मौलाना आजाद की जन्म शताब्दि के अवसर पर परिषद ने अनेक इच्छुक छात्रों और पूर्व छात्रों के लाभार्थ क्षेत्रीय कार्यालयों और विदेश स्थित कुछेक मिशनों में नवंबर 2015 में अंतरर्राष्ट्रीय छात्र समारोह आयोजित किया।

आई सी सी आर विदेश स्थित भारतीय मिशनों को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहा है कि वे आई सी सी आर पूर्व छात्र समूह स्थापित करें और इस प्रकार के अनेक समूह पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।

आई सी सी आर ने विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के परामर्श से अनेक विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय अध्ययन पीठ स्थापित किए हैं। इन पीठों का उद्देश्य यह है कि विदेशी छात्रों को भारत के बारे में शिक्षित करने के अलावा वे एक धुरी का काम करें जिसके इर्द–गिर्द विदेशों में स्थित शिक्षा संस्थानों में भारतीय अध्ययनों का विकास हो सके।।

30 नवंबर, 2015 तक इस प्रकार की प्रचालन पीठों की संख्या 70 है जिनमें स्कूल स्तरीय हिंदी अध्यापकों के 10 पद शामिल हैं। कुल 70 पीठों में से 27 भारतीय भाषाओं के अध्यापन के लिए (20 हिंदी पीठ जिनमें 10 प्रोफेसर स्तरीय तथा 10 अध्यापक स्तरीय) हैं, 04 संस्कृत पीठ, 02 तमिल पीठ और 01 बंगाली पीठ हैं जबकि शेष पीठ भारत से संबद्ध विषयों से संबंधित हैं।

इसके अलावा, 21 पीठों के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) का नवीकरण किया जाना है। विदेशी विश्वविद्यालयों में नए पीठों की स्थापना के लिए 15 नए प्रस्ताव हैं। अप्रैल 2015 से नवंबर 2015 की अवधि के दौरान, 11 नए पीठों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन नए पीठों का ब्यौरा इस प्रकार है– (ऑस्ट्रेलिया मुर्डोक यूनिवर्सिटी, पर्थ और मोनाश यूनिवर्सिटी, मेलबोर्न में 2), चीन (फुडान यूनिवर्सिटी, शंघाई) में 1, हांग कांग (द चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांग कांग) में 1, इथियोपिया (अदीस अबाबा यूनिवर्सिटी, अदीस अबाबा) में 1, नैरोबी (यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी) में 1, रोमानिया (यूनिवर्सिटी ऑफ बुखारेस्ट, बुखारेस्ट) में 1, स्पेन (वेलेडोलिड यूनिवर्सिटी, वेलेडोलिड) में 1, रूस (कजान यूनिवर्सिटी, कजान) में 1, ब्रिटेन (सेंट जेम्स स्कूल, लंदन) में 1 तथा लेबनान (लेबनान अमेरिकन यूनिवर्सिटी, बेरूत), में 1। इन

पीठों के शैक्षणिक वर्ष 2015–16 और 2016–17 में आरंभ होने की संभावना है।

विदेशी विश्व विद्यालयों में भा सां सं प के 70 पीठों का संचालन कर रहा है जिनमें भाषाओं एवं भारतीय अध्ययन के अन्य पहलुओं को शामिल किया गया है। विदेशों में पीठों के अलावा, आई सी सी आर भारत में भी दो पीठों अर्थात दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) पीठ और नेल्सन मंडेला का संचालन करती है और इन पीठों के लिए विद्वानों को विदेशों से भारत में आमंत्रित किया जाता है। अफ्रीकी विद्वानों को नेल्सन मंडेला पीठ के लिए आमंत्रित किया जाता है जो स्थायी रूप से जे एन यू में स्थित है, जबकि सार्क देशों के विद्वान सार्क पीठ के लिए आमंत्रित किए जाते हैं जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में बारी–बारी से स्थापित की जाती है।

वर्ष 2015 में भा सां सं प ने 19 सम्मेलनों/संगोष्ठियों का आयोजन किया जिनमें भारती के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा राष्ट्रपति भवन में उद्घाटित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारत विज्ञान सम्मेलन, 2015 तथा आजाद भवन में माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा उद्घाटित अंतर्राष्ट्रीय रोमा सम्मेलन, 2016 शामिल है। सम्मेलनों /सेमिनारों की एक विस्तृत सूची परिशिष्ट XII में है।

परिषद ने भारत, कंबोडिया और वियतनाम में आयोजित आठ सम्मेलनों/संगोष्ठियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की।

भा सां सं प ने वर्ष 2015 में 3 पुरस्कार स्थापित किए, नामतः विशिष्ट भारत विज्ञान पुरस्कार, विश्व संस्कृत पुरस्कार तथा विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार। विशिष्ट भारत विज्ञानी पुरस्कार 2016 एक जर्मन विद्वान प्रो. हेनरिक फ्रेहर वॉन स्टीटेनरोन को भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखजी द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक सम्मान समारोह में प्रदान किया गया। विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा 3 विजेताओं को प्रदान किया गया जिनमें आसियान महासचिव वियतनाम के महामहिम श्री ली लुओग मिन्ह, इथोपिया के महिला, बाल एवं युवा मामले मंत्री महामहिम सुश्री जेनेबु तादेस बोल्टसदिक तथा फ्रांस की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सुश्री मिलेना साल्विन शामिल है।

आई सी सी आर ऐसे अंतरर्राष्ट्रीय विद्वानों को वरिष्ठ तथा कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति प्रदान करती है जो विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर संस्कृति और सामाजिक विज्ञानों में विशेषज्ञता हासिल करते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 4 विद्वान (ब्रिटेन से दो, रूस और चेक गणराज्य में से एक–एक) आईसीसीआर के वरिष्ठ अध्येताओं के रूप में विभिन्न विश्वविद्यालयों में शामिल हुए तथा दो विद्वान (नेपाल और रूस से एक–एक) आईसीसीआर कनिष्ठ अध्येताओं के रूप में शामिल हुए।

"विशिष्ट आगंतुक कार्यक्रम" के अंतर्गत आईसीसीआर ने लातविया, ट्यूनीशिया, नेपाल, त्रिनिदाद एवं टोबैगो और नामीबिया से प्रतिष्ठित व्यक्तियों की भारत यात्रा की मेजबानी की।

अपने जावक आगंतुक कार्यक्रम के तहत, परिषद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अज़रबैजान, स्पेन, थाईलैंड, मॉरीशस, भूटान और ब्रिटेन में संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि के लिए 24 प्रतिभागियों की यात्रा का प्रायोजन किया/यात्रा अनुदान दिया।

शिक्षाविद आगंतुक कार्यक्रम के अंतर्गत परिषद ने 04 उत्कृष्ट शिक्षाविदों/ विद्वानों को पोलैंड, अर्जेंटिना, इंडोनेशिया और तंजानिया से आमंत्रित किया।

कला और संस्कृति

विदेशों में भा सां सं प के 35 पूर्णकालिक सांस्कृतिक केन्द्रों और एक उप केन्द्र ने नृत्य, संगीत, नाटक, योग, हिंदी भाषा, संवाद, प्रदर्शनियों, सम्मेलनों एवं संगोष्ठियों के द्वारा भारत की मृदु शक्ति (Soft Power) को बढ़ावा दिया। भा सां सं प ने बुसान तथा सिडनी में 2 नए सांस्कृतिक केंद्र खोले। परिषद ने विभिन्न देशों में राष्ट्रीय नेताओं की आवक्ष प्रतिमाएं/प्रतिमाएं भी भेजी। भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों के लिए लगातार बातचीत और मार्गदर्शन के माध्यम से आई सी सी आर अपने द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की संख्या के साथ–साथ उनके आकार तथा विविधता को बढ़ाने में भी सफल रही है।

21 जून 2015 को पहले अंतरर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, परिषद ने योग के ज्ञान का प्रसार करने के लिए आयुष मंत्रालय के सहयोग से विभिन्न देशों के लिए 30 भारतीय अस्थायी योग शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की। विदेशों में भारतीय योग की शिक्षाओं को संस्थागत रूप प्रदान करने के लिए भा सां सं प ने चीन के युनान मिंजु विश्वविद्यालय, कुनमिंग में भारत–चीन योग विद्यालय तथा आश्गाबत में भारत–तुर्कमेनिस्तान योग एवं पारंपरित औषध केंद्र की स्थापना की।

अप्रैल 2015 से नवंबर 2015 की अवधि के दौरान, आईसीसीआर और भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, बुसान के बीच 21 जून, 2015 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए जिसके अनुसार तीन वित्तीय वर्षों के लिए आईसीसी, बुसान के व्यय हेतु आई सी सी आर द्वारा 50,000 अमेरिकी डॉलर या व्यय के 25 प्रतिशत तक (इनमें से जो भी कम हो) वित्तीय सहायता दी जाएगी। योग के दो सहायक प्रोफेसरों (पुरुष एक और महिला प्रत्येक एक) की तैनाती करके योग कॉलेज खोलने के लिए आईसीसीआर और

युन्नान मिंजु यूनिवर्सिटी, कुनमिंग, चीन के बीच अन्य समझौता ज्ञापन पर 15 मई, 2015 को हस्ताक्षर किए गए। अशगाबत में भारत–तुर्कमेनिस्तान योग और पारंपरिक चिकित्सा केंद्र में दो योग शिक्षकों (पुरुष एक और महिला एक) तैनात किए गए थे। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा रूस की यात्रा के दौरान इस क्रेंद्र का उद्‌घाटन किया गया। परिषद विदेशों में उन स्थानों पर विभिन्न भारतीय मिशनों में शिक्षकों की तैनाती का कार्य कर रहा है जहां आई सी सी आर का भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र नहीं है। हनोई (वियतनाम) और नैरोबी (केन्या) में पूर्ण भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना के प्रस्ताव पर तत्परतापूर्वक विचार किया जा रहा है।

आई सी सी आर ने 120 भारतीय सांस्कृतिक समूहों/कलाकारों को महत्वपूर्ण अंतरर्राष्ट्रीय समारोहों के साथ–साथ 91 देशों में अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए यात्रा का प्रायोजन किया/यात्रा अनुदान दिया। इसके अलावा, परिषद प्रमुख महोत्सवों का आयोजन करके विदेश में भारतीय संस्कृति के भिन्न–भिन्न रूपों को उजागर कर रही है। अपने रूसी समकक्षी सहित भारत के माननीय राष्ट्रपति ने मास्को में 10 मई 2015 को ''नमस्ते रूस'' का उद्‌घाटन किया। उद्‌घाटन समारोह में सुश्री कुमुदिनी लखिया की कदम्ब मंडली द्वारा विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इसने भा सां सं प के अनेक प्रतिष्ठित महोत्सवों सहित अन्य कार्यक्रमों में 53 विदेशी मंडलियों की प्रस्तुतियों का आयोजन किया।

ज्ञान प्रवाह विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा एक संस्कृत नाटक ''कर्णाभरम'' 29 जून, 2015 का मंचन थाईलैंड में किया गया जो चालू वित्तीय वर्ष की विशेषता थी क्योंकि संस्कृत नाटक शायद ही पहले कभी विदेश में मंचित किए गए थे। श्री राम भारतीय कला केंद्र (एसबीकेके) के रामायण समूह ने अंतरर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन के दौरान रामायण प्रस्तुत करने के लिए मॉरीशस का दौरा किया।

आई सी सी आर ने अपनी ओर से विभिन्न देशों में 18 प्रदर्शनियां भी भेजी जिनमें फोटोग्राफी, चित्रकला और वस्त्रों सहित विभिन्न आयामों का प्रदर्शन किया गया था।

भारत से 10 महिला कलाकारों के एक समूह ने शंघाई, चीन में 24–30 अक्टूबर, 2015 से आयोजित मैत्री || – महिला कलाकार रेजीडेंसी में भाग लिया। रेजीडेंसी का उद्‌घाटन समारोह 2014 में जयपुर, भारत में आयोजित किया गया था।

नवंबर 2014 में जयपुर में आयोजित भारत – चीन महिला 'कलाकार रेजीडेंसी के दौरान कलाकारों द्वारा 'मैत्री' प्रदर्शनी बैंगलोर, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, गोवा, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलांग, पुणे और मुंबई में की गई थी।

क्षितिज श्रृंखला के अंतर्गत आई सी सी आर ने अपनी आजाद भवन कला दीर्घा में चित्रकला और मूर्तिकला पर 4 प्रदर्शनियों का आयोजन किया। विवरण परिशिष्ट XIII में संलग्न हैं।

अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्पर्कों को बढ़ावा देने के लिए आई सी सी आर ने विदेशी सहभागिता से 16–18 अक्तूबर, 2015 के दौरान दिल्ली में डी आई ए एफ के सहयोग से अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। इनमें महत्वपूर्ण है, दूसरे ''अंतरर्राष्ट्रीय लोक नृत्य और संगीत महोत्सव'' का आयोजन जिसमें ब्रिटेन, स्पेन, किर्गिस्तान, रूस, इजरायल, मॉरीशस, हंगरी, श्रीलंका और भारत से समूहों की भागीदारी रही। समारोह का उद्‌घाटन श्रीमती नजमा हेपतुल्ला, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री द्वारा किया गया। इसके अलावा दिल्ली में प्रदर्शन के अलावा इन समूहों ने भारत के दस अन्य शहरों में भी अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ''भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन'' 24 अक्टूबर से 5 नवंबर 2015 को दिल्ली में आयोजित किया गया जिसमें भारतीय सांस्कृतिक समूहों के अलावा इथोपिया, घाना, युगांडा, जांबिया, मिस्र और बोलीविया से सांस्कृतिक समूहों ने 29 अक्टूबर 2015 को राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शन किया और गुवाहाटी, वडोदरा और दिल्ली में भी प्रदर्शन किया; नई दिल्ली में 16–31 अक्तूबर 2015 तक 'दिल्ली अंतरर्राष्ट्रीय कला समारोह, 2014' के आयोजन के लिए आई सी सी आर ने 'फोरम ऑफ आर्ट बियोण्ड बार्डर्स' (एफ ए बी बी) तथा प्रसिद्ध फाउंडेशन दिल्ली के साथ सहयोग किया जिसमें मिस्र, ताइवान, पुर्तगाल, किर्गिज़स्तान, इजरायल, तुर्की, इंडोनेशिया, मैक्सिको, चीन और ब्रिटेन के समूहों ने भाग लिया; दूसरा ''अंतरर्राष्ट्रीय भक्ति महोत्सव'' 07–09 दिसम्बर, 2015 तक दिल्ली में आयोजित किया गया और भारत, बांग्लादेश, भूटान और मॉरीशस से आए भक्ति मंडलियों ने न केवल दिल्ली में बल्कि अहमदाबाद, पुणे, जम्मू, चंडीगढ़, देहरादून और नोएडा में भी कला मंचन किया।

उपर्युक्त समारोहों के अलावा, आई सी सी आर ने जून 2015 में दिल्ली और कोलकाता में मलेशिया के श्री रामली इब्राहिम के नेतृत्व में 10 सदस्यीय ओडिसी समूह 'सूत्र फाउंडेशन' की मेजबानी की।

नई दिल्ली के आजाद भवन सभागार में भारतीय कलाकारों/समूहों द्वारा प्रस्तुत 'क्षितिज श्रृंखला' के अंतर्गत आई सी सी आर द्वारा दस सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन किया गया। ''क्षितिज श्रृंखला'' कार्यक्रमों का आयोजन परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भी किया जाता है।

हिंदी को बढ़ावा देने तथा इसका प्रचार–प्रसार करने के लिए परिषद भारत तथा विदेशों में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करती है जैसे – सम्मेलन और पुस्तकों का लोकार्पण आदि। हिंदी भाषा के प्रचार के लिए परिषद विदेश स्थित अपने सांस्कृतिक

केन्द्रों, मिशनों और विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिंदी अध्यापक/प्रोफेसर नियुक्त करती है। यह विदेश स्थित भारतीय मिशनों तथा सांस्कृतिक केन्द्रों को हिंदी पुस्तकें, शब्दकोश तथा अपनी पत्रिका "गगनांचल" की प्रतियां भेजती हैं। अप्रैल से नवंबर 2015 की अवधि के दौरान जून 2015 में परिषद में हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई थी। फादर कामिल बुल्के, जो एक बेल्जियम नागरिक तथा हिंदी के विद्वान थे, पर एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी जिसका शीर्षक था "फादर कामिल बुल्के : भारतीयता के प्रकाशपुंज"। परिषद ने जून 2015 में अंतरर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रकाशित हिन्दी पत्रिका "गगनांचल" खंड 38 अंक 3 का विशेष अंक प्रकाशित किया। भोपाल में 10–12 सितम्बर 2015 तक आयोजित "10वें विश्व हिंदी सम्मेलन" के अवसर पर "गगनांचल" खंड 38 अंक 4–5 का विशेष अंक और एक स्मारिका का प्रकाशन किया गया। काव्य–रसधारा आईसीसीआर द्वारा सितंबर 2015 के दौरान "हिन्दी पखवाड़ा" का आयोजन किया गया था जिसमें हिंदी कार्यशाला और हिंदी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, दिल्ली के वरिष्ठ नागरिक परिषद के सहयोग से परिषद ने 5 नवंबर 2015 को अपने सभागार में काव्य सम्मेलन का आयोजन किया।

2015 के दौरान, विदेश मंत्रालय की ओर से आईसीसीआर ने कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और मलेशिया को महात्मा गांधी की तीन प्रतिमाएं और किर्गिस्तान, हैती (हवाना) और नीदरलैंड को तीन मूर्तियां, तजाकिस्तान और अर्जेंटीना को रवींद्रनाथ टैगोर की दो प्रतिमाएं तथा सिंगापुर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा भेजी।

पुस्तकालय और प्रकाशन

मौलाना अबुल कलाम आजाद, परिषद के संस्थापक अध्यक्ष द्वारा संग्रहित पुस्तकों और पांडुलिपियों की विरासत आईसीसीआर लाइब्रेरी का प्रमुख भाग है। पांडुलिपियों और मौलाना आजाद की व्यक्तिगत पुस्तकों की सूची तीन भाषाओं अरबी, उर्दू और फारसी में पुस्तक के रूप में मुद्रित की गई। विगत दशकों में, पुस्तकालय के आकार में कई गुना वृद्धि हुई है और वर्तमान में 50,000 से अधिक पुस्तकें हैं। आईसीसीआर ने ब्रिटिश काउंसिल पुस्तकालय का प्रशासन और भारत में विदेशी सांस्कृतिक केन्द्र की गतिविधियों का समन्वय करना जारी रखा। पुस्तकालय अध्येतावृत्ति कार्यक्रम पुस्तकालय संसाधनों के उपयोग को अधिकतम करने के उद्देश्य से 2002 में प्रारंभ किया गया।

आई सी सी आर पांच विभिन्न भाषाओं में 'इंडियन होराइजन' (अंग्रेजी–त्रैमासिक), 'गगनांचल' (हिंदी–द्विमासिक), 'पेपल्स डीला इंडिया' (स्पेनिश–छमाही), 'रांकोंत्र आवेक लेन्द' (फ्रेंच–छमाही), तथा 'तकाफट–उल–हिंदी' (अरबी–तिमाही) का प्रकाशन भारत तथा विदेशों में वितरण के लिए प्रकाशन करती है।

■ ■

33

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्ल्यूए) ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप, संयुक्त राज्य अमरिका, लातिन अमरिका, में राजनीतिक और आर्थिक विकास के अनुसंधान और अध्ययन को उच्च प्राथमिकता देना जारी रखा तथा व्यापक वैश्विक भू–रणनीतिक वातावरण का विश्लेषण किया। इस निष्कर्ष को सप्रू हाउस पेपर, संक्षिप्त अंक, संक्षिप्त नीति और दृष्टिकोण के रूप में प्रचारित किया गया था जो आईसीडब्ल्यूए वेबसाइट पर डाला गया था। इसके अलावा, आईसीडब्ल्यू, ने हिंदी में अपनी अकादमिक उत्पादन का अनुवाद शुरू कर दिया और इसे अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किया है। अप्रैल 2015 के बाद से इन्होंने दो पुस्तकें हिंदी में प्रकाशित की (अनुवाद), एक मोनोग्राफ और एक सप्रू हाउस पेपर। आईसीडब्ल्यूए वेबसाइट को और अधिक प्रयोक्ता अनुकूल बनाने के लिए सुधार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आईसीडब्ल्यूए ने आम जनता के लिए अपने पुस्तकालय खोल दिए हैं और सदस्यता के नियमों को सरल किया गया है।

आईसीडब्ल्यूए ने भारी संख्या में समारोहों, व्याख्यानों, सम्मेलनों और आउटरीच कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। पुस्तकालय में सुधार किया गया था और नई पुस्तकें प्राप्त की गई। आईसीडब्ल्यूए के प्रचालन के लिए सेवा विनियमों का विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा अधिसूचित आईसीडब्ल्यूए संचालन नियम के आधार पर मसौदा तैयार किया गया था। राजदूत नलिन सूरी ने जुलाई 2015 में आईसीडब्ल्यूए के नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है।

अनुसंधान

आईसीडब्ल्यूए अनुसंधान संकाय में वर्तमान में निदेशक (अनुसंधान) और 20 अनुसंधान अध्येता शामिल हैं। पांच अनुसंधान इंटर्न कम अवधि के लिए भर्ती किए गए थे। इसमें ऑस्ट्रेलिया से, एक छात्र डॉ एलन ब्लूम फील्ड शामिल है।

पिछले आठ महीनों में, अनुसंधान शिक्षक और विद्वान राजनीतिक, सुरक्षा और दुनिया भर में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आर्थिक प्रचालन एवं घटनाक्रमों पर अध्ययन और अनुसंधान में लगे हुए थे। और उन्होंने व्यापक वैश्विक भू–रणनीतिक और आर्थिक वातावरण का विश्लेषण किया है। उन्होंने इस अवधि के दौरान 2 सप्रू हाउस पत्रों, 1 मोनोग्राफ, 11 पुस्तकों, 24 संक्षिप्त मुद्दे, 13 नीति संक्षिप और 24 दृष्टिकोण के आईसीडब्ल्यूए प्रकाशनों के अलावा मीडिया और अन्य शैक्षिक पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित करके परिणामों को प्रचारित किया।

अपने आउटरीच पहल के भाग के रूप मेंए आईसीडब्ल्यूए ने विदेश नीति के मुद्दों पर सुविधा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बुक अनुसंधान अनुदान, सप्रू हाउस कागज अनुदान और सम्मेलन अनुदान संस्थापित किया। इसके अलावाए विदेश नीति जागरूकता कार्यक्रम के तहत हिंदी में कार्यक्रमों को चलाकर हिंदी को प्रोत्साहन दिया गया है और अब तक ऐसे आठ समारोह का आयोजन किया गया है।

यद्यपि आईसीडब्ल्यूए की आंतरिक अनुसंधान क्षमता को तेजी से निर्मित किया जा रहा है, मुख्य क्षेत्रों अथवा देशों अथवा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मामलों में भारत के संबंधों पर विशिष्ट क्षेत्रों अथवा परियोजनाओं पर अनुसंधान करने के लिए विदेश नीति के जाने–माने विद्वानों तथा पूर्व में अभ्यास करने वालों को नियुक्त किया जा रहा है। आईसीडब्ल्यूए ने कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन भी किया। इसके अलावा, आईसीडब्ल्यूए ने अपने विद्वानों के लिए सम्मेलन संबंधी यात्रा का समर्थन किया और चार आरएफ को विदेश में सम्मेलन में भाग लेने के लिए यात्रा अनुदान दिया।

24 जुलाई, 2015 को स्थापित चीन पर दूसरे कोर समूह ने पांडुलिपि का निर्माण का कार्य पूरा कर लिया है जो अब प्रकाशित की जा रही है। पाकिस्तान पर कोर समूह की सात बैठकें हो चुकी हैं और पुस्तक अब प्रकाशित हो गई है। आईसीडब्ल्यूए ने समकालीन वैश्विक / द्विपक्षीय महत्व के विषय पर परियोजनाएं शुरू कर दी हैं की तथा ऐसी छह रिपोर्ट विदेश मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई है।

उपयुक्ता अनुसार, अध्ययन और नीति सिफारिशें, विदेश मंत्रालय के पास भेज दी गई थी। आईसीडब्ल्यूए विदेश मंत्रालय को सम्मेलन सारांश रिपोर्ट भी उपलब्ध करा रहा है।

प्रकाशन

नीचे दी गई जानकारी के अनुसार इस अवधि के दौरान आईसीडब्ल्यूए के विभिन्न प्रकाशनों को नियमित तौर पर निकाला गया :

1. आईसीडब्ल्यूए की पत्रिका 'भारत त्रैमासिक' को 2015–16 की अवधि के दौरान नियमित रूप से निकाला गया था –
   - i) भारत त्रैमासिक (अंतरराष्ट्रीय मामलों पर एक पत्रिका), खंड–71 अंक 2 जून 2015
   - ii) भारत त्रैमासिक (अंतरराष्ट्रीय मामलों पर एक पत्रिका), खंड–71 अंक 3 सितंबर, 2015
   - iii) भारत त्रैमासिक (अंतरराष्ट्रीय मामलों पर एक पत्रिका), खंड–71 अंक 4, दिसंबर, 2015
2. 2015–16 की अवधि के दौरान प्रकाशित आईसीडब्ल्यूए की पुस्तकें (पांडुलिपि)
   - i) बीसीआईएम इकोनॉमिक कोरिडोरः द रोड अहेड – राजीव के भाटिया व राहुल मिश्रा द्वारा संपादित
   - ii) म्यांमार में परिवर्तन (हिन्दी में) – राजीव के भाटिया द्वारा
   - iii) ट्रांसिशन्स एंड इंटरडेपेंडेन्सः इंडिया एंड इटस नेबर्स – पंकज झा एवं स्मिता तिवारी द्वारा संपादित
   - iv) इनसाइट्स इनटु एवोलूशन ऑफ़ कंटेम्परेरी पाकिस्तान – सतीश चंद्र और स्मिता तिवारी द्वारा संपादित
   - v) इंडिया इन ग्लोबल अफेयर्सः पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम सप्रू हाउस –राजीव के भाटिया द्वारा
   - vi) इंडिया एंड सदर्न अफ्रीकाः फोर्जिंग अहेड थ्रू पार्टनरशिप –परमजीत सिंह सहाय द्वारा संपादित
   - vii) इंडिया एंड द ओशिनियाः एक्सप्लोरिंग विस्टास फॉर कोऑपरेशन–पंकज के झा द्वारा
   - viii) द पीकॉक एंड द गरुड़ः एन ओवरव्यू ऑफ़ इंडिया–इंडोनेशिया रिलेशंस – राजीव के भाटिया व राहुल मिश्रा द्वारा संपादित
   - ix) कनाडा–इंडियाः पार्टनर्स इन प्रोग्रेस– प्रेम के. बुधवार द्वारा
3. 2015–16 की अवधि के दौरान निकाले गए आईसीडब्ल्यूए के 'सप्रू हाउस पेपर्स' और 'अन्य प्रकाशन'
   - i) भारत की इजरायल नीति का बदलता स्वरूप (हिन्दी में) – डॉ अनूप कुमार गुप्ता
   - ii) ओरल हिस्ट्री रिकॉर्ड ऑफ़ एम्बेसडर ए.पी वेंकटेस्वरन खंड. 3 –कृष्णा एस. राणा
   - iii) आईसीडब्ल्यूए न्यूज़लेटर (अंग्रेजी + हिंदी) – आईसीडब्ल्यूए

4. मोनोग्राफ (हिन्दी में)

''हिमालय के सीमावर्ती देशों में चीन की घुसपैठ और भारतीय चुनौती''. डॉ. सतीश कुमार द्वारा

प्रक्रियाधीन पुस्तक परियोजनाओं की सूची

- अथर जफर, अनुसंधान अध्येताए आईसीडब्ल्यूए द्वारा सप्रू हाउस पत्र शीर्षक "पीएम मोदी विजिट रीइंविगोरेट्स टाइस विद् सेंट्रल एशिया"
- हिन्दी में भारत और रूस
- लेखक संजीव कुमारए अनुसंधान अध्येताए आईसीडब्ल्यूए द्वारा "राइज ऑफ़ नेबरहुड इन चाइनीज फॉरेन पालिसी''
- राजदूत ए.एन राम की ओरल हिस्ट्री परियोजना जिसका राजदूत. गजानन वाकांकर द्वार साक्षात्कार लिया गया
- राजदूत जी एस अय्यर द्वारा ए चाइना प्राइमरः एन इंट्रोडक्शन टु ए कल्चर एंड नेबर" शीर्षक मोनोग्राफी
- चाइना एंड द यूरेशियाई रिजन : राजदूत. सी वी रंगनाथन और संजीव कुमार, अनुसंधान अध्येता, आईसीडब्ल्यूए द्वारा संपादित

आउटरीच कार्यक्रम

आईसीडब्ल्यूए के आउटरीच कार्यक्रमों में कई भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त सम्मेलन और सेमिनार और देश भर में थिंक टैंक शामिल है। इसी तरह, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कई देशों में सम्मेलन, सेमिनार और व्याख्यान में भाग लेना शामिल हैं।

1 अप्रैल 2015 से 30 नवंबरए 2015 तक की अवधि के दौरानए आयोजित समारोहों की कुल संख्या इस प्रकार हैंः

i.	व्याख्यान	-	07
ii.	सेमिनार / सम्मेलन	-	09
iii.	द्विपक्षीय सामरिक वार्ता	-	13

iv.	पैनल चर्चा / पृष्ठभूमि वार्ता	-	04
v.	पुस्तक विमोचन / रिलीज / चर्चा समारोह	-	04
	कुल		37

(क) भारत में आउटरीच कार्यक्रमः

क) दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, द्वारा गोरखपुर में 29 मई, 2015 को हिंदी में आयोजित विदेश नीति के बारे में जागरूकता कार्यक्रम

ख) बैंगलोर में 13 जून 2015 को *'चाइनिज ग्रोइंग जियोपोलिटिकल रीच एंड इंटेरसेक्शन ऑफ़ इंटरेंस्ट विद् इंडिया'* पर आईसीडब्ल्यूए–एशिया केंद्रए बैंगलोर (आईसीडब्ल्यूए) समझौता ज्ञापन भागीदारी) संयुक्त संगोष्ठी।

ग) सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा सिक्किम में 25–26 जूनए 2015 को आयोजित *'इंडियाज नार्थ–ईस्ट एंड बियॉन्डः चैलेंजेज एंड ऑपर्चुनिटीस'* पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन।

घ) अटल बिहारी वाजपेयी **हिन्दी** विश्वविद्यालय द्वारा भोपाल में 28 जुलाई 2015 को हिंदी में आयोजित विदेश नीति के बारे में जागरूकता कार्यक्रम।

ड) जीडीसी मेमोरियल कॉलेज द्वारा भिवानी में 19–20 सितम्बर, 2015 को **हिंदी** में आयोजित विदेश नीति के बारे में जागरूकता कार्यक्रम।

च) रावेनशॉ विश्वविद्यालय द्वारा कटक, उड़ीसा में 30–31 अक्टूबर, 2015 को आयोजित *रीवाइटलाइजेंशन रिलेशंस विद् 'एक्सटेंड निबरहूड': न्यू ऑपर्चुनिटीस एंड फ्यूचर डिरेक्शंस फॉर इंडियास फॉरेन पालिसी'* विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन ।

छ) तुर्की भाषा और साहित्य कार्यक्रम, मानविकी और भाषा के संकाय, जामिया मिलिया इस्लामिया (जेंएमआई) विश्वविद्यालय द्वारा जेएमआई, नई दिल्ली में 1–3 नवम्बर, 2015 को आयोजित 'इंडो–तुर्किक रिलेशंसः पर्सपेक्टिव्स एंड इट्स कंटेम्परारी रेलवेंस' पर तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन।

ज) रक्षा अध्ययन विभाग, मेरठ कॉलेज द्वारा मेरठ में 28–29 नवम्बर, 2015 को आयोजित 'इंडिया–. चीन रिलेशंसः कनफ्लिक्ट और को–ऑपरेशन' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी।

झ) आईसीडब्ल्यूएआई द्वारा 5–6 दिसम्बर, 2015 को आर्थिक रूप से समर्थित आउटरीच कार्यक्रम 'एशियाई कंफ्लुएंसः यंग स्कॉलर्स फोरम'

ञ) यूएस कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी के साथ 18 जनवरी, 2016 को 'इंडिया–यूएस" साझेदारी पर गोलमेज

ट) 28–29 जनवरी, 2016 को 'इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसीः प्रोब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स इन नार्थ ईस्ट इंडियाश पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी

(ख) भारत के बाहर आउटरीच कार्यक्रमः

आईसीडब्ल्यू, ने निम्नलिखित विदेशी विचारकों के साथ सम्मेलन / संगोष्ठी आयोजित कीः

क) 'इंडिया–.इजिप्ट डायलागः प्रेजेंट रियलिटीस एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स' पर 19–23 अप्रैल 2015 को अपने समझौता ज्ञापन के साझेदार,विदेश कार्यों मिस्र परिषद (इसीएफए) के साथ दूसरी वार्ता आयोजित करने के लिए आईसीडब्ल्यूए के प्रतिनिधिमंडल की काइरो यात्रा।
स्थानः काहिरा, मिस्र

ख) *''सिक्स्थ इंडिया–यूरोपियन यूनियन इंस्टिट्यूट फॉर सेक्टरिटीएस स्टडीज (यूएस) फोरम''* 'आईसीडब्ल्यूएआई के समझौता ज्ञापन भागीदार, ईयूआईएसएसए द्वारा 11–12 मई 2015 को ब्रसेल्स में मेजबानी की गई।
आईसीडब्ल्यूए–एसडब्ल्यूपी वार्ता
जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड सिक्योरिटी अफेयर (एसडब्ल्यूपी) के साथ एक दिवसीय वार्ता)
बर्लिन, 13 मई 2015
स्थानः ब्रसेल्स और बर्लिन

ग) सूंग चिंग लिंग फाउंडेशन, के साथ 25–27 नवंबर, 2015 को *'एक्सपेक्ट' फ्यूचरफ्रॉम ट्रेडिशनः चीन–इंडिया फ्रेंडली एक्सचैंजेस एंड म्यूच्यूअल लर्निंग'* पर चीन–भारत मैत्री गोलमेज
स्थानः बीजिंग, चीन

(ग) आयोजित महत्वपूर्ण व्याख्यान –

महामहिम श्री मोहम्मद अशरफ घानी, अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य के राष्ट्रपति, द्वारा 28 अप्रैल 2015 को *'द रिबर्थ ऑफ़ द एशियाई कॉन्टिनेंटल इकॉनमीः रीजनल को–ऑपरेशन एंड अफ़ग़ानिस्तान को–ऑपरेटिव एडवांटेज"* पर सोलहवां सप्रू हाउस व्याख्यान

ख) महामहिम श्री असलोव सिरोजीदिन मुहरीदेनोविच, ताजिकिस्तान गणराज्य के विदेश मंत्री द्वारा 12 मई 2015 को *"तजाकिस्तान फॉरेनपॉलिसी एंड रिजनल सिक्योरिटी चेलेंजीस"* पर सत्रहवां सप्रू हाउस व्याख्यान

ग) न्यायमूर्ति एंटोनियो टी कार्पियो, वरिष्ठ एसोसिएट न्यायाधीश, फिलीपींस सुप्रीम कोर्ट द्वारा 6 अगस्त 2015 को *'द साउथ चीन सी डिस्प्यूट'* पर अठारहवां सप्रू हाउस व्याख्यान

घ) महामहिम श्री जेम्स एलिक्स मिशेल, सेशेल्स गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा 27 अगस्त 2015 को *'मेरीटाइम सिक्योरिटी फॉर द ब्लू इकॉनमी'* पर उन्नीसवां सप्रू हाउस व्याख्यान

ड) महामहिम श्री मोगेंस लिकेटोफ्ट 70वें सत्र के निर्वाचित अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनसीए) 31 अगस्त 2015 को *"यूएन एएट 70"* पर भाषण

च) राजदूत सामन्था पोवेर, संयुक्त राष्ट्र के स्थायी अमेरिकी प्रतिनिधि द्वारा 20 नवंबर 2015 को *''टुवर्ड मोर इफेक्टिव पीसकीपिंग इन द 21स्ट सेंचुरी''*, पर व्याख्यान

छ) महामहिम डॉ मिलान ब्रेगलेज, स्लोवेनिया की संसद के अध्यक्ष का 26 नवंबर 2015 को *'स्लोवेनिया डिकेड इन द यूरोपियन यूनियन – ए लुक बैक एंड ओपर्चुनिटीएस फॉर द फ्यूचर"* पर बीसवां सप्रू हाउस व्याख्यान

ज) महामहिम श्री रणजीत राय, नेपाल में भारत के राजदूत द्वारा 11 जनवरी 2016 को 'द करंट सिचुएशन इन नेपाल' पर वार्ता

(घ) महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन –

क) *'इंडिया–अफ्रीका इन द 21स्ट सेंचुरीः स्केल एंड स्कोप ऑफ़ कम्प्रेहेंसिव पार्टनरशिप'* पर 15–16 अक्टूबर, 2015 को पूर्व भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (आईएएफएस) –III सम्मेलन

(ङ) महत्वपूर्ण द्विपक्षीय और रणनीतिक वार्ता का आयोजन –

क) भारत–न्यूजीलैंड वार्ता श्रृंखला

9 अप्रैल 2015 को *"एशिया–प्रशांत क्षेत्र में न्यूजीलैंड की भूमिका"* पर सुश्री एंड्रिया स्मिथ, विदेश मामलों, न्यूजीलैंड के उप सचिव के साथ गोलमेज चर्चा

ख) *'वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ऑफ़ चीन'* पर 25 मई 2015 को गोलमेज चर्चा

ग) आईसीडब्ल्यूए– एमआईएसआईएस द्विपक्षीय वार्ता, 17 जून 2015

म्यांमार सामरिक और अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान (एमआईएसआईएस) के सहयोग से,

घ) विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर भारत–प्रशांत द्वीप समूह सहयोग के लिए मंच (एफआईपीआईएस) का दूसरा शिखर सम्मेलन के लिए प्रशांत द्वीप देशों से प्रतिनिधियों के सम्मान में 21 अगस्त 2015 को आईसीडब्ल्यूए द्वारा आयोजित मध्याह्न भोज बैठक

स्थानः होटल आईटीसी राजपूताना, जयपुर

ड) आईसीडब्ल्यूए ऑस्ट्रेलियाई इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर (एआईआईए) द्विपक्षीय वार्ताए 15 सितंबर 2015

च) आईसीडब्ल्यूए– एआईआईए – (जापान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर (जेआईआईए) के साथ त्रिपक्षीय वार्ताए 16 सितंबर, 2015

छ) आईसीडब्ल्यूए – जेआईआईए द्विपक्षीय वार्ता, 17 सितंबर 2015

ज) 'इंटरनेशनल डे ऑफ़ सॉलिडेरिटी विद् द पलेस्तीनिअन पीपल' पर 30 नवंबर, 2015 को मनाना गया समारोह

झ) 2 दिसंबर 2015 को आईसीडब्ल्यूए के अनुसंधान संकाय और पर जेएनयू के एचआरडीसी वैश्विक अध्ययन कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों के बीच विचार विमर्श

(च) महत्वपूर्ण पुस्तक का विमोचन / लोकार्पण कार्यक्रमों का आयोजन –

क) पुस्तक का विमोचन : "लैटीन अमेरिका, द कैरेबियन एंड इंडिया : प्रोमिस एंड चैलेंज" (एक आईसीडब्ल्यू, प्रकाशन, लेखक राजदूत दीपक भोजवानी), 9 अप्रैल 2015

ख) पुस्तक की लोकार्पण : "चीन कन्फ्यूशियस इन द शेडोस" (एक आईसीडब्ल्यू, प्रकाशन, लेखिका सुश्री पूनम सूरी)

1 मई, 2015 को भारत के उप राष्ट्रपति और वैश्विक मामलों पर भारतीय परिषद के अध्यक्ष माननीय श्री एम हामिद अंसारी द्वारा

ग) राजदूत राजीव भाटिया की पुस्तक का विमोचन–'इंडिया–म्यांमार रिलेशंसः चेंजिग कौंटूर'–22 सितंबर, 2015 को भारत के उप राष्ट्रपति तथा वैश्विक मामलों पर भारतीय परिषद क अध्यक्ष माननीय श्री एम हामिद अंसारी द्वारा।

घ) लेखक डॉ पंकज झाए निदेशक (अनुसंधान), आईसीडब्ल्यूए की पुस्तक 'इंडिया एंड द ओशिनिया' पर 20 जनवरी 2016 को पुस्तक चर्चा

(छ) परिषद में महत्वपूर्ण विदेशी गणमान्य व्यक्तियों का दौरा

1. महामहिम श्री मोहम्मद अशरफ घानी, अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य के राष्ट्रपति, 28 अप्रैल 2015
2. महामहिम श्री असलोव सिरोजीद्दिन मुहरीदिनोविच, ताजिकिस्तान गणराज्य के विदेश मंत्री द्वारा, 12 मई 2015

3. महामहिम श्री जेम्स एलिक्स मिशेल, सेशेल्स गणराज्य के राष्ट्रपति, 27 अगस्त 2015
4. महामहिम श्री मोगेंस लायकेटोफ्ट, 70वें सत्र के निर्वाचित अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) द्वारा, 31 अगस्त 2015
5. राजदूत सामन्था पोवेर, संयुक्त राष्ट्र के लिए स्थायी यूएस प्रतिनिधि, 20 नवम्बर 2015

एशिया प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग परिषद (सीएससीएपी)

आईसीडब्ल्यूए द्वारा 2001 के बाद से एशिया प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग परिषद सचिवालय (सीएससीएपी) भारत समिति के सचिवालय की मेजबानी की गई है।

सीएससीएपी एशिया प्रशांत सुरक्षा मामलों पर एक समावेशी गैर सरकारी प्रक्रिया है। 1 अप्रैल 2015 से 30 नवम्बर 2015 की अवधि के दौरान परिषद ने निम्नलिखित कार्यक्रमों का समन्वय किया:

1. कुआलालम्पुर में 6–7 अप्रैल, 2015 को हुई एशिया प्रशांत क्षेत्र में निरस्त्रीकरण के अप्रसार पर पहली सीएससीएपी अध्ययन समूह बैठक
2. कुआलालम्पुर में 27–29 अप्रैल, 2015 को हुई निवारक राजनय पर पहली सीएससीएपी अध्ययन समूह बैठक
3. कुआलालंपुर में 1–3 जून, 2015 को हुई सीएससीएपी की 29वीं एशिया प्रशांत गोलमेज बैठक
4. कुआलालम्पुर में 4 जून 2015 को हुई सीएससीएपी की 43वीं संचालन समिति की बैठक
5. बीजिंग, चीन में 14–16 जूनए 2015 को हुई ऊर्जा सुरक्षा पर सीएससीएपी अध्ययन समूह की दूसरी बैठक
6. कुआलालम्पुर में 18–20 जून 2015 को हुई वैमानिकी और समुद्री खोज के सामंजस्य (एसएआर) पर सीएससीएपी अध्ययन समूह की पहली बैठक
7. बीजिंग, चीन में 13–22 सितम्बरए 2015 को हुई युवा विद्वानों पर दूसरी कार्यशाला बैठक।
8. नोम पेन्ह, कंबोडिया में 23–25 सितम्बरए 2015 को हुई महाद्वीपीय दक्षिण पूर्व एशिया में सामरिक व्यापार पर नियंत्रण पर सीएससीएपी कार्यशाला
9. सिंगापुर में 15–16 अक्टूबर, 2015 को हुई परमाणु ऊर्जा विशेषज्ञ समूह की बैठक पर सीएससीएपी अध्ययन समूह बैठक
10. उलानबातर, मंगोलिया में 20–21 अक्टूबरए 2015 को हुई सीएससीएपी की 44वीं संचालन समिति बैठक
11. उलान बातार, मंगोलिया में 21–22 अक्टूबरए 2015 को हुआ सीएससीएपी की 10वां आमसभा सम्मेलन
12. सिंगापुर में 26–27 अक्टूबरए 2015 को हुई ऊर्जा सुरक्षा पर तीसरा सीएससीएपी अध्ययन समूह बैठक

आईसीडब्ल्यूए पुस्तकालय

सप्रू हाउस पुस्तकालय, 1955 में अपनी स्थापना के बाद से, भारतीय और विदेशी विद्वानों के लिए एक प्रमुख संसाधन केंद्र के रूप में उभरा है। इनमें लगभग 143,000 किताबें, पत्रिकाएं, नक्शे, और संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के दस्तावेज हैं। संपूर्ण संग्रह एक डिजिटल सूचकांक के माध्यम से सुलभ है और ऑन लाइन सार्वजनिक उपयोग सूची के माध्यम से खोजा जा सकता है। सप्रू हाउस पुस्तकालय का एक बड़ा भागए डिजिटल स्वरूप में आईसीडब्ल्यूए पत्रिका के संपूर्ण संग्रह के रूप में – भारत तिमाही के अनुसंधान विद्वानों के लिए सुलभ है। उच्च स्तरीय साइबर पुस्तकालय से संपन्न, सप्रू हाउस पुस्तकालय अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ जुड़ा है जो आईसीडब्ल्यूए विद्वानों के लिए पहुंच प्रदान करता है।

पुस्तकालय का लक्ष्य दक्षिण एशिया पर विशेष ध्यान देते हुए भारतीय विदेश नीति के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान सामग्री और दस्तावेजों का एक व्यापक भंडारण है। यह हमारे अनुसंधान परियोजनाओं के बढ़ते हुए दायरों की मांगों को पूरा करने के लिए और इसकी सुविधाओं के उन्नयन के लिए प्रयास करता है।

प्रसार

आईसीडब्ल्यूए ने सबसे बड़े संभावित वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने तथा राष्ट्रीय और वैश्विक कार्य क्षेत्र में भारत की चिंताओं और आकांक्षाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसके परिणाम और गतिविधियों की व्यापक प्रचार–प्रसार करने की एक नीति शुरू की। प्रकाशन अलर्ट के प्रचार के साथ ही वेबसाइट के सुधार की एक प्रणाली: *www.icwa.in* और महत्वपूर्ण घटनाओं में से वैश्विक वेबकास्टिंग आईसीडब्ल्यू, के अधिदेश को प्राप्त करने में मददगार है। आईसीडब्ल्यूए ने एक व्यापक वैश्विक दर्शकों के लिए परिषद के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए अपने प्रचार ब्रोशर को अद्यतन और पुनःमुद्रित किया है।

■ ■

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली

34

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस) नई दिल्ली में स्थित एक स्वायत्त नीति अनुसंधान संस्थान है जो व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान देने के साथ अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों में विशेषज्ञता प्राप्त है। आरआईएस की कल्पना वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक मुद्दों पर विकासशील देशों के बीच प्रभावी नीति वार्ता और क्षमता–निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में की गई है।

आरआईएस का कार्य कार्यक्रम दक्षिण–दक्षिण सहयोग (एसएससी) को बढ़ावा देने और विभिन्न मंचों पर बहुपक्षीय वार्ताओं में विकासशील देशों के साथ सहयोग करने पर केंद्रित है। आरआईएस कई क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पहल की पूरी अंतर–सरकारी प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। आरआईएस अपने थिंक टैंक के गहन नेटवर्क के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों और विकास भागीदारी कैनवास पर अनुकूल नीति को बढ़ाना चाहता है।

वर्ष 2015 में आरआईएस के कार्य कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं नीचे प्रस्तुत हैं:

नीतिगत वार्ताएं, सम्मेलन और क्षमता निर्माण कार्यक्रम:

खुली नवोन्मेष रूपरेखा में एनआईएस के निदान और एसटीआई कार्यनीतियों के विकास पर तीसरा एशिया–प्रशांत एनआईएस फोरम

आर आई एस ने बैंकाक, थाईलैंड में खुली नवोन्मेष रूपरेखा में राष्ट्रीय नवोन्मेष प्रणाली (एनआईएस) के निदान और एसटीआई कार्यनीतियों के विकास पर तीसरे एशिया–प्रशांत एनआईएस फोरम का आयोजन करने के लिए 8 और 9 अप्रैल 2015 को संयुक्त राष्ट्र एशिया और प्रशांत आर्थिक और सामाजिक आयोग (ईएससीएपी), नई दिल्ली, भारत और राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति कार्यालय (एसटीआई), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, थाईलैंड के एशियाई और प्रशांत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र (एपीसीटीटी) के साथ सहयोग किया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक और डॉ रवि श्रीनिवास, परामर्शदाता, ने इसमें भाग लिया।

यूएनडीपी के दक्षिण–दक्षिण सहयोग कार्यनीति पर संवाद सत्र

आरआईएस ने नई दिल्ली में 14 अप्रैल 2015 को सुश्री जियोजून ग्रेस वैग, नीति और कार्यक्रम समर्थन संबंधी दक्षिण–दक्षिण और त्रिपक्षीय सहयोग ब्यूरो (बीपीपीएस), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), न्यूयॉर्क के साथ यूएनडीपी के दक्षिण–दक्षिण सहयोग कार्यनीति पर एक संवाद सत्र का आयोजन किया। चर्चा में बैंकॉक के सुश्री नेन कोलिन्स, एसएससी विशेषज्ञ, यूएनडीपी क्षेत्रीय केंद्र और सुश्री मोमिन जान, कार्यक्रम अधिकारी, यूएनडीपी इण्डिया कंट्री ऑफिस आरआईएस संकाय में शामिल हुए।

एपीईसी और भारत पर रिपोर्ट जारी करना

फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के साथ संयुक्त रूप से आरआईएस में आसियान–भारत केन्द्र (एआईसी) द्वारा, नई दिल्ली में 21 मई, 2015 को आरआईएस के उपाध्यक्ष राजदूत वी. एस. शेषाद्री, उपाध्यक्ष द्वारा लिखित रिपोर्ट 'एपीईसी और भारतः एक मूल्यांकन' के लिए आरंभिक समारोह का आयोजन किया। राजदूत अनिल वाधवा, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालयए भारत सरकार ने रिपोर्ट जारी की और मुख्य वक्ता के रूप में टिप्पणी की। राजदूत श्याम सरनए अध्यक्षए आरआईएस ने विशेष टिप्पणी की। राजदूत वी. एस. शेषाद्री ने रिपोर्ट के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया और उसके बाद खुली चर्चा की गई। डॉ. प्रबीर डेए समन्वयकए आरआईएस में एआईसी, ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

ऑस्ट्रेलिया और भारतः एक शांतिपूर्ण और समृद्ध एशियाई आर्थिक क्रम की दिशा में

दो प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलियाई सार्वजनिक नीति टिप्पणीकारों अर्थात श्री रोवन कैलीक, द ऑस्ट्रेलियन न्यूजपेपर के एशिया–प्रशांत संपादक और श्री टॉम स्विट्जर, प्राध्यापक, राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंध और रिसर्च एसोसिएट, यूनाइटेड स्टेट्स अध्ययन

केन्द्र, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, ने 'ऑस्ट्रेलिया और भारतः एक शांतिपूर्ण और समृद्ध एशियाई आर्थिक क्रम की दिशा में' पर एक गोलमेज चर्चा करने के लिए 26 मई 2015 को आरआईएस का दौरा किया। आरआईएस सेए प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक और प्रो राम उपेंद्र दास ने इसमें भाग लिया।

भारत 2050 पर पैनल चर्चाः सतत समृद्धि के लिए एक रोडमैप

आरआईएस ने नई दिल्ली में 29 मई 2015 को 'भारत 2050ः सतत समृद्धि के लिए एक रोडमैप' पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया। प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। राजदूत श्याम सरन, अध्यक्ष, आरआईएस ने परिचयात्मक टिप्पणी की। डॉ. रामगोपाल अग्रवाल, अध्यक्ष, ''पहले इंडिया फाउंडेशन, नई दिल्ली'' ने अपनी पुस्तक 'भारत 2050ः सतत समृद्धि के लिए एक रोडमैप' पर एक प्रस्तुतीकरण दिया। इसमें प्रो मुचकुंद दुबे, अध्यक्ष, सामाजिक विकास परिषद (सीएसडी); प्रो बी.बी. भट्टाचार्य, पूर्व कुलपति, जेएनयूय श्री मनीष सिंघल, सहायक महासचिव, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की); तथा डॉ सैकत सिन्हा रॉय, एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता के पैनल सदस्य शामिल हैं।

भारत–मध्य एशिया आर्थिक सहयोग पर संगोष्ठी

सामाजिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के साथ संयुक्त रूप से आरआईएस ने नई दिल्ली में 11–12 जून 2015 को 'भारत–मध्य एशिया आर्थिक सहयोग की दिशा में' पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। राजदूत श्याम सरनए अध्यक्षए आरआईएस ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। डॉ. ऐश नारायण राय, निदेशक, सामाजिक विज्ञान संस्थान, ने विशेष टिप्पणियां की। श्री नवतेज सिंह सरना, सचिव (पश्चिम), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने मुख्य भाषण दिया। महामहिम श्री मिर्जा शरीफ असोमुद्दीनवाइक जैलोलोव, भारत में तजाकिस्तान के राजदूत; श्री एवगेनी केबलुकोव, मंत्री के सलाहकार, किर्गिज गणराज्य; श्री सरदार शिहियेव, प्रथम सचिव, परामर्शदाता, तुर्कमेनिस्तान; और श्री गैरत तैरोव, व्यापार और आर्थिक परामर्शदाता, उज़्बेकिस्तान ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस सेमिनार के दौरान निम्नलिखित विषयों पर सत्र चले : व्यापार और निवेश संबंधों, क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय रूपरेखा की भूमिका, नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के सहयोग के अवसरों, उद्यमशीलता भागीदारी का विकास और आर्थिक विकास के लिए एजेंडा। आरआईएस से, प्रो. एस. के. मोहंती और प्रो. राम उपेंद्र दास ने इसमें भाग लिया।

दक्षिण एशिया विकास और सहयोग रिपोर्ट 2015 का शुभारंभ

आरआईएस ने 25 जून 2015 को नई दिल्ली में अपने प्रमुख प्रकाशन 'दक्षिण एशिया विकास और सहयोग रिपोर्ट 2015' (एसएडीसीआर) का शुभारंभ किया। श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु, माननीय रेल मंत्री, भारत सरकार ने रिपोर्ट जारी की। प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। राजदूत श्याम सरन, अध्यक्ष ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। प्रो दीपक नायर, अवकाश प्राप्त अर्थशास्त्र प्रोफेसर, जेएनयू, नई दिल्ली तथा सह अध्यक्ष, दक्षिण एशिया नीति अध्ययन केंद्र (एसएसीईपीएस); डॉ. ए. एम. गोंदाने, संयुक्त सचिव (सार्क), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार; तथा महामहिम श्री सैदा मोहम्मद अब्दाली, भारत में अफगानिस्तान के इस्लामी गणराज्य के राजदूत ने भी उद्घाटन सत्र में विशेष टिप्पणी की। प्रो राम उपेंद्र दास ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

कार्यक्रम के दौरान 'दक्षिण एशिया में आर्थिक विकास के लिए आर्थिक सहयोग' और 'सार्क से पहले नई चुनौतियां' सत्र चले। महामहिम राजदूत ल्योनपो डैगो त्शेरिंग, भारत में भूटान के पूर्व राजदूत ने समापन सत्र की अध्यक्षता की। डॉ. कविता ए. शर्मा, अध्यक्ष, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और राजदूत जयंत प्रसाद पैनल के सदस्य थे। श्री अरविंद मेहता, संयुक्त सचिव (सार्क), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने समापन भाषण दिया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। समारोह में वरिष्ठ राजनयिकों, सरकारी अधिकारियों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, उद्योग प्रतिनिधियों और मीडिया ने भाग लिया।

भारत–अफ्रीका आर्थिक व्यवस्था पर चर्चा की बैठक

आरआईएस ने 12 जून 2015 को नई दिल्ली में भारत–अफ्रीका आर्थिक व्यवस्था (आईएईए) पर चर्चा बैठक का आयोजन किया। राजदूत श्याम सरन, अध्यक्ष, आरआईएस ने बैठक की अध्यक्षता की। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। बैठक में मुख्य वक्ताओं में निम्नलिखित शामिल थेः श्री सैयद अकबरुद्दीन, संयुक्त सचिव और मुख्य समन्वयक (आईएएफएस), विदेश मंत्रालय, भारत सरकारय श्री अमित शुक्ला, अवर सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार; श्री रोहित मिश्रा, अवर सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार; और प्रो. एस. के. मोहंती, आरआईएस।

थिंक टैंक के आसियान–भारत नेटवर्क का चौथा गोलमेज सम्मेलन (एआईएनटीटी)

आरआईएस पर आसियान–भारत केन्द्र (एआईसी), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के साथ संयुक्त रूप सेय विदेश मंत्रालय, मलेशिया; आसियान सचिवालय, तथा सामरिक और अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान (आईएसआईएस) मलेशिया ने कुआलालंपुर में 7–8 अगस्त 2015 को ''आसियान–इंडियाः स्ट्रेंथेनिंग द टाइस डैट बाइंड'' विषय पर थिंक टैंक के आसियान–भारत नेटवर्क (एआईएनटीटी) का चौथा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। टैन श्री रस्तम मोहम्मद ईसा, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामरिक और अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान (आईएसआईएस) मलेशिया ने टिप्पणियों का स्वागत किया। माननीय डेटो सेरी रीजल मेरिकन नैना मेरिकन, विदेश मामलों के उप मंत्री, मलेशिया ने मुख्य भाषण दिया।

जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह, विदेश राज्य मंत्री, भारत सरकार ने उद्घाटन भाषण दिया। राजदूत अनिल वाधवा, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और राजदूत वी. एस. शेषाद्री, उपाध्यक्ष, आरआईएस ने विशेष टिप्पणी की। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस और एआईसी ने समापन भाषण दिया। गोलमेज सम्मेलन में 'आसियान–भारत आर्थिक संबंधः अवसर और चुनौतियां, पर एआईसी / आरआईएस ने तीसरी एआईएनटीटी गोलमेज पर कार्यवाही की तथा 'आसियान–भारतः पोस्ट–2015 एजेंडा को आकार देने' पर 7वीं दिल्ली वार्ता की आईडीएस, कार्यवाही भी जारी की। गोलमेज सम्मेलन के पहले सत्र में समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद सहित अंतरराष्ट्रीय अपराध जैसे गैर–पारंपरिक सुरक्षा खतरों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। राजदूत वी. एस. शेषाद्री ने इस सत्र की अध्यक्षता की। दूसरे सत्र में मौजूदा और उभरते क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना का संबोधन किया गया और उन चुनौतियों पर चर्चा की जिसका इस क्षेत्र में आने वाले देशों को सामना करना पड़ रहा है। सुश्री इलिना नूर ने इस सत्र की अध्यक्षता की। तीसरे सत्र में क्षेत्रीय आर्थिक संरचना जैसे आसियान आर्थिक समुदाय (एईसी), क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी), और आगे के रास्ता के रूप में संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। इसकी अध्यक्षता डॉ. राजीव कुमार, कुलपति, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, पुणे और वरिष्ठ अध्येता, नीति अनुसंधान केंद्र (सीपीआर) ने की। चौथे सत्र में प्रो. प्रबीर डे, समन्वयक, एआईसी की अध्यक्षता में आसियान और भारत के बीच अतीत और वर्तमान के सांस्कृतिक संबंधों पर चर्चा हुई और संबंधों को मजबूत करने की दिशा में सुझाव दिया। टैन श्री डेटो अजीत सिंह, सलाहकार (इंडिया बिजनेस), आईजेएम कॉर्पोरेशन बेरहाद और पूर्व महासचिव, आसियान सचिवालय ने 'पोस्ट–2015 आसियान का एजेंडा और आगे के रास्ते' पर पांचवें सत्र की अध्यक्षता की। गोलमेज सम्मेलन प्रो. प्रबीर डे और टैन श्री रस्तम मोहम्मद ईसा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुआ।

हिंद महासागर में ब्लू अर्थव्यवस्था की संभावनाओं पर आई ओ आर ए ब्लू इकोनामी वार्ता

आरआईएस ने 17–18 अगस्त 2015 को गोवा में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ), नई दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से, नई दिल्ली में "हिंद महासागर में ब्लू इकोनामी की संभावनाओं" पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस के स्वागत भाषण के साथ सम्मेलन शुरू हुआ। श्री समीर सरन, उपाध्यक्ष, ओआरएफ और श्री आलोक

क्वालाम्पुर में 'आसियान – भारत : आपस में जोड़ने वाले संबंधों को प्रगाढ़ बनाना' विषय पर 7 से 8 अगस्त 2015 को आयोजित आसियान – भारत विचारक नेटवर्क की चौथी गोलमेज बैठक में प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस और एआईसी; राजदूत अनिल वाधवा, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार; माननीय डेटो सेरी रिजाल मेरिकन नैना मेरिकन, विदेश मामले के उप मंत्री, मलेशिया; तान श्री रस्तम मोहम्मद ईसा, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामरिक और अंतरराष्ट्रीय अध्ययन मलेशिया संस्थान; जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह, विदेश राज्य मंत्री, भारत सरकार; और राजदूत वी. एस. शेषाद्री, उपाध्यक्ष, आरआईएस और एआईसी ने भाग लिया।

डिमरीए निदेशक (एमईआर), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने विशेष टिप्पणी की। प्रोफेसर वी. एन. अत्री, अध्यक्ष, हिंद महासागर रिम अध्ययन, आई ओ आर ए ने मुख्य भाषण दिया। इसमें ब्लू इकोनामी, मत्स्यपालन और जलीय कृषि, अक्षय महासागर ऊर्जा, बंदरगाह, जहाजरानी, विनिर्माण और अन्य क्षेत्रों, और समुद्रतल गवेषण और खनिज के लिए एक व्यापक लेखा रूप रेखा विकसित करने पर सत्र थे।

विकास हेतु वित्तियन पर विचार विमर्श

अदीस अबाबा में विकास के लिए वित्तपोषण (एफएफडी 3) पर तीसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन से पहले, भारतीय विकास सहयोग के लिए फोरम और भारत में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से आरआईएस ने विकास के लिए वित्त पोषण पर विचार–विमर्श का आयोजन किया। 8 जुलाई 2015 को नई दिल्ली में प्रथम परामर्श सत्र आयोजित किया गया था, जिसमें प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। राजदूत श्याम सरन, अध्यक्ष ने इस परामर्श सत्र की अध्यक्षता की। डॉ. आदर्श सवैका, निदेशक, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक प्रभाग, विदेश मंत्रालयए भारत सरकार; प्रो दीपक नैयर, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर एमेरिटस, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली; और डॉ अकमल हुसैन, अर्थशास्त्र के विशिष्ट प्रोफेसर, फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज, लाहौर पैनल के मुख्य सदस्य थे। श्री जयंत सिन्हा, वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में एफएफडी 3 के मौके पर 14 जुलाई 2015 को अदीस अबाबा में दूसरा परामर्श सत्र आयोजित किया गया। राजदूत संजय वर्मा, इथियोपिया और जिबूती में भारत के राजदूत ने स्वागत भाषण दिया। प्रो मिलिंद चक्रवर्ती, विजिटिंग फेलो, आरआईएस; डॉ मैनुएल मोंटेस, वरिष्ठ सलाहकार, वित्त एवं विकास, दक्षिण सेंटर, जिनेवा; श्री अमिताभ बिहार, कार्यकारी निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय संघ; और श्री डैनी श्री स्कंदराज, महासचिव, सिविक्स शिक्षाविदों और नागरिक समाज ने विचार प्रस्तुत किए। डॉ सब्यसाची साहाए सहायक प्रोफेसरए आरआईएस धन्यवाद ज्ञापन विस्तारित किया।

आसियान–भारत प्रख्यात व्यक्ति' व्याख्यान

17 जुलाई 2015 को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और आसियान सचिवालय के साथ संयुक्त रूप से आसियान–भारत प्रख्यात व्यक्ति व्याख्यान श्रृंखला, आसियान भारत केंद्र (एआईसी) के भाग के रूप आरआईएस में महामहिम श्री इवान गार्सिया, विदेश अवर सचिव, फिलीपींस द्वारा एक व्याख्यान का आयोजन किया। राजदूत अनिल वाधवा, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने विशेष भाषण दिया। प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस और एआईसी ने स्वागत भाषण दिया। राजदूत श्याम सरन, अध्यक्ष, आरआईएस ने उद्घाटन भाषण दिया।

आसियान – भारत सांस्कृतिक संपर्कों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

23–24 जुलाई 2015 को नई दिल्ली में "आसियान–भारत सांस्कृतिक संबंध : ऐतिहासिक और समकालीन आयाम'' पर आसियान–भारत केन्द्र (एआईसी), आरआईएस ने, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और सांस्कृतिक मामलों की भारतीय परिषद (आईसीसीआर) की सरकार के साथ सहयोग में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। राजदूत अनिल वाधवा, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने मुख्य भाषण दिया। प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस और एआईसी ने स्वागत भाषण दिया। प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस और एआईसी ने स्वागत भाषण दिया। राजदूत श्याम सरन, अध्यक्ष, आरआईएस और एआईसी ने उद्घाटन भाषण दिया। लोकेश चंद्र, अध्यक्ष, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर), नई दिल्ली में उद्घाटन भाषण दिया। सम्मेलन के विभिन्न सत्र पर चर्चा की : (1) दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापार और समुद्री संबंध; (2) निरंतरता और परिवर्तन; (3) धर्मों और अनुष्ठानों का प्रतिनिधित्व; (4) मूलपाठ परंपराओं और प्रसारण; (5) पवित्र भौगोलिक और मान्यताओं का स्थानीकरण; (6) कलात्मक अभिव्यक्ति से विकसित : आधुनिकता के लिए परंपरा; और (7) हमारे अपने इतिहास लेखन : परिवर्तित विधियां। विश्व के विभिन्न भागों से आए प्रतिष्ठित विद्वानों ने सम्मेलन में भाग लिया। एआईसी के समन्वयक प्रो. प्रबीर डे ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

चिकित्सा उपकरणों नीति पर गोलमेज सम्मेलन

10 अगस्त 2015 को मसौदा राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरणों की नीति, 2015 पर टिप्पणी / सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन है। गोलमेज के उद्देश्य मसौदा नीति को समन्वित प्रतिक्रिया की सुविधा के लिए किया गया था। प्रो सचिन चतुर्वेदीए महानिदेशक ने स्वागत भाषण दिया। श्री टी सी जेम्स, सलाहकार, आरआईएस ने मसौदा नीति पर प्रस्तुत किया। श्री लालकृष्ण एम गोपा कुमार, थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क; डॉ रेजी के. जोसेफ, आईएसआईडी; डॉ अमित सेनगुप्ता, इंटरनेशनल पीपुल्स हेल्थ विश्वविद्यालयय डॉ जितेंद्र कुमार शर्मा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केन्द्र, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, श्री जाकिर थॉमस, पूर्व निदेशक, ओएसडीडी मंत्रालय; डॉ सरोजिनी एन बी; डॉ देबप्रिया दत्ता, निदेशक, भारत–फ्रांस उन्नत अनुसंधान की अभिवृद्धि केंद्र, और डॉ सब्यसाची साहा, सहायक प्रोफेसर ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।

सीएलएमवी के साथ भारतीय आर्थिक एकीकरण कार्यनीति पर रिपोर्ट का शुभारंभ

14 अगस्त 2015 को नई दिल्ली में सीएलएमवी के साथ सुश्री रीता टेयोटिया, वाणिज्य सचिव, भारत सरकार ने भारतीय आर्थिक एकीकरण कार्यनीति पर रिपोर्ट का शुभारंभ किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रिपोर्ट निकाली गई। राजदूत श्याम सरन, अध्यक्ष, आरआईएस, नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता की। श्री रवि कपूर, संयुक्त सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने तर्क और रिपोर्ट की उत्पत्ति प्रस्तुत की। महामहिम श्री टन सिंह थान, भारत में वियतनाम के राजदूत ने विशेष टिप्पणी की। राम उपेंद्र दास, आरआईएस, इस रिपोर्ट के लेखक ने व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए धन्यवाद ज्ञापन दिया।

एक क्षेत्र, एक ही रास्ता

विश्व आर्थिक एवं राजनीति संस्थान (आईडब्ल्यूईपी) चीन के सामाजिक विज्ञान अकादमी ने एक क्षेत्र, एक ही रास्ता तथा बीजिंग चीन में 25–26 अगस्त, 2015 को बी सी आई एम के क्षेत्रीय अंतर संपर्क सम्मेलन का आयोजन किया। आरआईएस इस इंटरकनेक्शन सम्मेलन के सह–आयोजक थे। कार्यक्रम झांग युयान, निदेशक, आईडब्ल्यूईपी द्वारा उद्घाटन और स्वागत की टिप्पणी के साथ शुरू हुआ। बांग्लादेश–भारत–चीन म्यांमार आर्थिक कोरीडोर (बीसीआईएम–ईसी) 'एक क्षेत्र, एक ही रास्ता' के स्वप्न को प्राप्त करने के पूरक है। आरआईएस से प्रो एस के से मोहंती ने ''एशिया में एक क्षेत्रीय विकास उपरिकेंद्र का उभार : 'एक क्षेत्र, एक ही रास्ता' की नीति के साथ बीसीआईएम की संभावना'' सम्मेलन में भाग लिया और एक प्रस्तुति दी।

विकास और पद 2015 एजेंडा के लिए वित्तपोषण

श्री जयंत सिन्हा, वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार ने मुख्य भाषण दिया। प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस द्वारा स्वागत टिप्पणी दी गई। राजदूत श्याम सरन, अध्यक्ष आरआईएस ने अध्यक्ष – टिप्पणी दी और सुश्री सुजाता मेहता, सचिव (एम एंड एम), एमईए ने विशेष टिप्पणी दी। सुश्री निशा अग्रवाल, ऑक्सफेम इंडिया और डॉ भास्कर चटर्जी, महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय निगमित कार्य संस्थान, निगमित कार्य मंत्रालय के अन्य पैनल के सदस्य थे।

भारत – कोरिया सीईपीए : प्रगति का मूल्यांकन

नई दिल्ली में 8 सितंबर, 2015 पर 'भारत–कोरिया सीईपीएः प्रगति का मूल्यांकन' राजदूत अनिल वाधवा, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने रिपोर्ट जारी की। प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत टिप्पणी दी। राजदूत श्याम सरन अध्यक्ष, आरआईएस और एआईसी ने आरंभिक टिप्पणी की। श्री अमिताभ कांत, सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विशेष टिप्पणी की और उल्लेख किया कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत पर समझौते के उन्नयन के लिए यह रिपोर्ट सरकार को मदद करेगी। राजदूत वी.एस. शेषाद्री, उपाध्यक्ष, आरआईएस और एआईसी, अध्ययन के प्रमुख अन्वेषक ने उनकी प्रस्तुति दी। श्री एस आर तायलए कोरिया गणराज्य के लिए भारत के पूर्व राजदूत ने भारत–कोरिया सीईपीए में महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत किया।

भारत–अफ्रीका भागीदारी पर राष्ट्रीय परामर्श

'भारत–अफ्रीका भागीदारीः प्राथमिकताएं और संभावनाएं ''नई दिल्ली में 16 सितंबर, 2015 को तीसरे भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन से पहले आरआईएस ने रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए), भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और ब्रूकिंग्स भारत के साथ, एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया। श्री नवतेज सरना, सचिव (पश्चिम), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने उद्घाटन भाषण दिया। राजदूत राजीव भाटिया ने मुख्य भाषण दिया। डॉ डब्ल्यूपीएस सिद्धू, वरिष्ठ अध्येता, ब्रूकिंग्स भारत, नई दिल्ली और श्री प्रणव कुमार मुख्य – अंतरराष्ट्रीय नीति और व्यापार, सीआईआई द्वारा भी टिप्पणियां की गई। डॉ रुचिता बेरी, वरिष्ठ अनुसंधान सहायक और समन्वयक, अफ्रीका, और संयुक्त राष्ट्र एलएसी केंद्र, आईडीएसए ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। परामर्श के विभिन्न सत्रों (i) भारत–अफ्रीका भागीदारी और वैश्विक संदर्भ; (ii) व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों; (iii) ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और समुद्री सुरक्षा; तथा (iv) लोगों से लोगों का संपर्क : शिक्षा, नागरिक समाज और सामाजिक क्षेत्र पर विचार–विमर्श किया। उन्होंने राजदूत डॉ हसन ई. ईएल तालिब, अनिवासी राजदूत श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और मालदीव, दूतावास सूडान गणराज्य, नई दिल्ली, प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस और श्री प्रणव कुमार, प्रमुख – अंतरराष्ट्रीय नीति और व्यापार, सीआईआई द्वारा भी संबोधन किया गया। डॉ डब्ल्यूपीएस सिद्धू, वरिष्ठ अध्येता, ब्रूकिंग्स – भारत ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

सतत विकास लक्ष्यों पर परामर्श (एसडीजी)

आरआईएस ने नीति आयोग, भारत सरकार के सहयोग से; भारत में संयुक्त राष्ट्रय एफडीआईसी; और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) के साथ मिलकर 9 सितंबर 2015 को नई दिल्ली में 9 एमडीजी पर हितधारकों के साथ एक दिन के लंबे समय का विचार–विमर्श आयोजित किया है, जो 25–27 सितंबर 2015 को न्यूयार्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र से पूर्व थी। प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत

भाषण दिया। भारत में संयुक्त राष्ट्र निवासी समन्वयक और यूएनडीपी स्थानीय प्रतिनिधि, श्री यूरी अफनासिव अतिथियों का स्वागत किया। सुश्री सिंधुश्री खुल्लर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग ने उद्‌घाटन भाषण दिया। अम्ब श्याम सरन, अध्यक्ष, आरआईएस ने अध्यक्ष टिप्पणी की। श्री पुनीत अग्रवाल, संयुक्त सचिव (यूएनईएस), विदेश मंत्रालय ने विशेष टिप्पणी की। प्रो अनुराधा चिनॉय, एफडीआईसी के अध्यक्ष और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय अध्ययन स्कूल में डीन ने उद्‌घाटन सत्र में समापन भाषण दिया। इस परामर्श में आरआईएस ने एसडीजी पर अपनी पत्रिका एशियाई जैव प्रौद्योगिकी और विकास की समीक्षा (एबीडीआर) का विशेष अंक भी जारी किया गया। संस्थान ने एसडीजी को समर्पित एक नया वेब पेज का अनावरण किया। परामर्श के तकनीकी सत्र पर चर्चा की (i) स्वास्थ्य, कृषि और पोषण सुरक्षा और मानव विकास पर एमडीजी; (ii) विज्ञान, अभिनव और प्रौद्योगिकी तक पहुँच; (iii) एमडीजीः समावेशी विकास, लिंग और स्थिरता; (iv) एसडीजीः ऊर्जा और पर्यावरण; (vi) एसडीजी : उद्योग, नागरिक समाज और मीडिया की भूमिका; तथा (v) एसडीजी : कार्यान्वयन मुद्दों, निगरानी, राज्यों और वैश्विक प्रतिबद्धताओं की भूमिका।

आरआईएस में वियतनाम समाजवादी गणराज्य की राजनीति की राष्ट्रीय अकादमी का प्रत्यायोजन

सहायक प्रो डॉ थ्रिन्ह डुक थाओ, राज्य और विधि संस्थान, हो ची मिन्ह राष्ट्रीय राजनीति अकादमी (एचएनएपी) के निदेशक ने एक सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए, 15 सितंबर, 2015 को भविष्य शैक्षिक सहयोग के लिए एक संवादात्मक सत्र के लिए आरआईएस का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे : डॉ गुयेन थी तुयेत माई, वरिष्ठ व्याख्याता, नेतृत्व संस्थान और सार्वजनिक नीति, एचएनएपी; डॉ गुयेन थी फुओंग लैन, अर्थव्यवस्था संस्थान के व्याख्याता, एचएनएपी; श्री गुयेन वान डुओंग, एमए, अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रभार में एचएनएपी के उपाध्य के पीएस, श्री डो खुओंग मान्ह लिन्ह, एमए, भारतीय अध्ययन केंद्र के विशेषज्ञ; और सुश्री यु वैन अन्ह अन्हए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के विशेषज्ञ, एनएचएपी।

यूएनडीपी, न्यूयॉर्क में एनईएसटी बैठक

22 सितंबर 2015 को न्यूयॉर्क में यूएनडीपी कार्यालय में दक्षिण–दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग पर आरआईएस ने नीति और कार्यक्रम के समर्थन के लिए यूएनडीपी ब्यूरो के सहयोग से एक परामर्श का आयोजन किया जिसमें दक्षिणी थिंक टैंक (घोंसला) के नेटवर्क के भविष्य के कार्य कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा की गई। डॉ जियोजन अनुग्रह वैंग, नेतृत्व सलाहकार, यूएनडीपी ने आरंभिक टिप्पणी की। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने विशेष टिप्पणी की। पैनल के अन्य लोग में शामिल थे : डॉ वांग विहुआन, निदेशक, अनुसंधान अंतरराष्ट्रीय विकास केंद्र (आरसीआईडी), चीन कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू); श्री जेसु वेलाजक्वेज कैस्टिलो, संयुक्त राष्ट्र के मेक्सिको के स्थायी मिशन के प्रतिनिधि; सुश्री एंजेला ट्रेन्टन–म्बोंडे, वरिष्ठ सलाहकार, यूएनएड्स; डॉ थॉमस फ्यूस, जर्मन विकास संस्थान; और प्रो मैनुएल मोंटेस, ए दक्षिण केंद्र।

संयुक्त राष्ट्र महासभा, न्यूयॉर्क के मौके पर आरआईएस के आयोजन

आरआईएस ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के पार्श्व, दो समारोहों का आयोजन किया। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा पर प्रथम समारोह : दक्षिणी परिपेक्ष्य का आयोजन संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 21 सितम्बर 2015 को संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केंद्र, न्यूयार्क विश्वविद्यालय के साथ आयोजित किया गया। बैठक संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के सहयोग से संयोजित की गई थी। डॉ सब्यसाची साहा, सहायक प्रोफेसर, आरआईएस द्वारा स्वागत टिप्पणी दी गई। प्रो सचिन चतुर्वेदी, अशोक कुमार मुखर्जी, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने आरंभिक टिप्पणी की। प्रो अरविंद पनगढ़िया, उपाध्यक्ष, नीति आयोग ने मुख्य भाषण दिया। सुश्री हेलेन क्लार्क, प्रशासक, यूएनडीपी ने विशेष भाषण दिया। समारोह में राजदूत मचारिया कमाउ, संयुक्त राष्ट्र में केन्या के स्थायी प्रतिनिधि; एसडीजी पर ओपन कार्य समूह के राजदूत डेविड डोनोग्वे, संयुक्त राष्ट्र और सुविधा प्रदाताओं के लिए आयरलैंड के स्थायी प्रतिनिधि उपस्थित थे। संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र के अन्य अधिकारियों, प्रमुख शिक्षाविदों, नागरिक समाज के सदस्यों और मीडिया, दक्षिणी देशों से वरिष्ठ राजनयिकों और नीति निर्माताओं, स्थायी प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों ने भाग लिया। पहली पैनल चर्चा ''2030 एजेंडे : विकासशील देशों के लिए इसका क्या मतलब है'' पर थी। पैनल के लोगों में प्रो कार्लोस कोरिया, दक्षिण सेंटर, जिनेवा; सुश्री सारा एफ क्लिफ, निदेशक, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय केंद्र; श्री यूरी अफनेसिव, संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वयक और भारत में यूएनडीपी स्थानीय प्रतिनिधि तथा सुश्री मिन्ह–गुरु फाम, वरिष्ठ नीति निदेशक, संयुक्त राष्ट्र संघ शामिल थे। दूसरी पैनल चर्चा थी : ''2030 एजेंडा : एक बढ़ते दक्षिण के लिए चुनौतियां और अवसर''। यह श्री अमिताभ बिहार, कार्यकारी निदेशक, भारत के लिए राष्ट्रीय संघ द्वारा संचालित किया गया था। इस सत्र में पैनल के लोग शामिल थे – प्रो संजय रेड्डी, सामाजिक अनुसंधान के लिए नए स्कूल, न्यू यॉर्क, राजदूत कार्लोस सर्जियो

सोब्राल ड्यूरेटे, संयुक्त राष्ट्र में ब्राजील के उप स्थायी प्रतिनिधि; डॉ समीर सरन, उपराष्ट्रपति, ओआरएफ, नई दिल्ली; और डॉ डब्ल्यूपीएस सिद्धू, वरिष्ठ अध्येता, ब्रूकिंग्स भारत, नई दिल्ली।

प्रौद्योगिकी के लिए संस्थागत संरचना और विकास और उपयोग पर परामर्श :

22 सितंबर 2015 को न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय मिडटाउन सेंटर में 'संस्थागत संरचना और विकास और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर परामर्श' अंतरराष्ट्रीय सहयोग, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय पर केंद्र सरकार के सहयोग से आरआईएस द्वारा दूसरी पक्ष समारोह का आयोजन किया गया। पहला सत्र संस्थागत संरचना और विकास पर था। यह डॉ डब्ल्यूपीएस सिद्धू, वरिष्ठ अध्येता, ब्रूकिंग्स इंडिया द्वारा संचालित किया गया। वक्ताओं में शामिल थे – डॉ थॉमस फ्यूस, जर्मन विकास संस्थान; डॉ सारा हार्न, अंतरराष्ट्रीय सहयोग केंद्र, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय; डॉ रीनेता जियानिनी, वरिष्ठ शोधकर्ता, इंस्टीट्यूटो इगारेपे; और प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस। दूसरा सत्र टीएफएम संस्थागत पर था : आईपी और प्रौद्योगिकी के लिए पहुंच। इस सत्र में पैनल के लोग थे श्री अमित नारंग, वाणिज्य दूत, भारत संयुक्त राष्ट्र के स्थायी मिशन; डॉ डेविस ओश्कॉनर, संयुक्त राष्ट्र डीईएसए; और प्रो कार्लोस कोरिया, दक्षिण केंद्र, श्री समीर सरन, उपाध्यक्ष, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली।

आसियान इंडिया एयर कनेक्टिविटी पर गोलमेज सम्मेलन

आरआईएस में एआईसी नई दिल्ली ने 28 सितंबर, 2015 को "आसियान इंडिया एयर कनेक्टिविटी" एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। प्रो प्रबीर डे, समन्वयक, एआईसी राजदूत अनिल वाधवा, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने मुख्य भाषण दिया। राजदूत श्याम सरन, अध्यक्ष, आरआईएस ने उद्घाटन पर भाषण दिया। श्री अनिल श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (एटी), नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) ने विशेष भाषण दिया। डॉ सनत कौल, अध्यक्ष, विमानन, एयरोस्पेस एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनल फाउंडेशन (आईएफएडी), नई दिल्ली द्वारा 'भारत और दक्षिण पूर्व तथा पूर्व एशिया के बीच वायु परिवहन' पर गोलमेज सम्मेलन के पहले सत्र की अध्यक्षता की गई। सुश्री पूजा कपूर, संयुक्त सचिव (एएमएल), विदेश मंत्रालय ने विशेष भाषण दिया। प्रो प्रबीर डे, आरआईएस तथा समन्वयक एआईसीए 'भारत हवाई संपर्क आसियान' अध्ययन पर एक प्रस्तुति पेश की। डॉ शेफाली जुनेजा, निदेशक, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) ने विशेष टिप्पणी की। श्री सतेंद्र सिंह, पूर्व महानिदेशक, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए), नई दिल्ली द्वारा 'आसियान–भारत खुला आकाशः अवसर और चुनौतियां' पर दूसरे सत्र की अध्यक्षता की गई। सम्मेलन डॉ दुराइराज कुमारसामी, सलाहकार, एआईसी ने धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त किया।

कृषि में भारत–अफ्रीका सहयोग : अवसर और चुनौतियां

आरआईएस ने हैदराबाद में 6 अक्टूबर 2015 को भारत–अफ्रीका कृषि सहयोग पर एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। भारतीय और अफ्रीकी सरकारो के प्रतिनिधियों सहित प्रमुख हितधारकों; व्यापार और उद्योग; और अनुसंधान संस्थानों के बीच भारत–अफ्रीका बीज क्षेत्र के सहयोग में चुनौतियों और अवसरों पर हमारी अनुसंधान अध्ययन के निष्कर्षों का प्रसार करना सम्मेलन का उद्देश्य है।

भारतीय पी पी वी एवं एफ आर प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. आर. आर. हनिचाल ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की तथा भारतीय राष्ट्रीय वीज संघ (एनएसएआई) के अध्यक्ष तथा नूजीवीडू सीड्स के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने मुख्य अभिभाषण दिया। आई डी एस, ससेक्स के रिसर्च फेलो डॉ. दोमिनिक ग्लोवर ने टिप्पणी दी, एबीएनई, एनईपीएडी, बर्किना फासो निदेशक डॉ. दिरेन माकिंडे ने विशेष टिप्पणी दी तथा एग्री बायोटेक फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक डॉ. पाकी रेड्डी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रदान किया।

सम्मेलन में निम्नलिखित सत्र थेः कृषि क्षेत्र में भारत–अफ्रीका सहयोग, भारत–अफ्रीका बीज क्षेत्र पर आरआईएस/सीएबीई/ईआईएआर/आईडीएस अध्ययन, भारत तथा अफ्रीका के बीच बीज व्यापारः अवसर एवं चुनौतियों तथा भारत एवं अफ्रीका के बीच बीज क्षेत्र सहयोग में अंतर्राष्ट्रीय विनियामकों पर डायनामिक्स। आरआईएस ने आईडीएस (ससेक्स, यूके), ईआईएआर (अदिस अबाबा, इथोपिया) तथा सीएबीई (बैरोबी, केन्या) के साथ संयुक्त सहयोगी अनुसंधान पर कार्य किया है।

फिलीपींस के विदेश मंत्री महामहिम श्री अलबर्ट एफ. डेल रोजारियो द्वारा द्वितीय रिजाल–नेहरू व्याख्यान

'14 अक्टूबर 2015 को आरआईएस तथा विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में दूसरा रिज़ाल–नेहरू व्याख्यान का आयोजन किया। फिलीपींस के विदेश मंत्री महामहिम श्री अल्बर्ट एफ डेल रोसारियो ने फिलीपींस–भारत संबंधों के लिए आगे की राह : चुनौतियां और अवसर पर व्याख्यान दिया। सुश्री मोनिका मोहता, अपर सचिव (दक्षिण), विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार ने विशेष टिप्पणी प्रदान की। प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस तथा एआईसी ने स्वागत भाषण दिया। अध्यक्ष, आरआईएस तथा एआईसी राजदूत श्याम सरन, ने प्रारंभिक टिप्पणी दी। आरआईएस तथा समन्वयक, एआईसी प्रो प्रबीर डे, धन्यवाद ज्ञापन प्रदान किया।

ट्रांस–पैसिफिक सहभागिता टी पी पी पर पैनल विचार–विमर्श

16 अक्टूबर 2015 को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) पर आरआईएस ने नई दिल्ली में एक पैनल चर्चा का आयोजन किया। भारत सरकार के पूर्व वाणिज्य सचिव, ने चर्चा शुरू की। महानिदेशक, आईआईएस प्रो सचिन चतुर्वेदी, ने स्वागत टिप्पणी दी थी। प्रतिष्ठित पैनलिस्टों में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल थे : प्रो एस के मोहंती, आरआईएस; श्री बिपुल चटर्जी, उप कार्यकारी निदेशक, कहस इंटरनेशनल; तथा आरआईएस के श्री टी सी जेम्स।

भारत–अफ्रीका भागीदारीः भविष्य की दिशा

'भारत–अफ्रीका भागीदारीः भविष्य की दिशा'' पर 25–29 अक्तूबर, 2015 को तृतीय मंच शिखर सम्मेलन के रन अप में रक्षा अध्ययन तथा समीक्षा संस्थान, भारतीय उद्योग की ब्रूकिंग्स इंडिया एण्ड कॉनफेडरेशन के सहयोग से आरआईएस ने 20 अक्तूबर, 2015 को परामर्शी का आयोजन किया था।

सुश्री सुजाता मेहता, सचिव (एम एंड ईआर) विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने विशेष टिप्पणी प्रदान की। प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया।

इस अवसर पर, सुश्री सुजाता मेहता ने तीन विशेष प्रकाशनों का शुभारंभ किया था। इनमें आरआईएस द्वारा ''भारत–अफ्रीका भागीदारी सतत् विकास की दिशा''; आईडीएसए द्वारा ''भारत–अफ्रीका : अगले दशक के लिए भारत–अफ्रीका सामान्य सुरक्षा चुनौतियां" ब्रूकिंग्स द्वारा "भारत अफ्रीकाः एक सामरिक भागीदारी फोर्जिंग" शामिल है। आईडीएसए की डॉ रूचिका बेरी ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

भू–सामरिक संबंधों और भारत–अफ्रीका भागीदारी; पर इस परामर्श में व्यापार और निवेश, और क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य सत्र थे। श्री नवतेज सिंह सरना, सचिव (पश्चिम), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, समापन भाषण दिया था।

आसियान–भारत पर गोलमेज सम्मेलन : एकता और विकास एवं आसियान–भारत विकास एवं सहयोग रिपोर्ट 2015 की एकीकरण विज्ञप्ति

आरआईएस में एआईसी ने 27 अक्टूबर 2015 को नई दिल्ली में आसियान–भारत : एकीकरण विकास पर संयुक्त रूप से सीआईआई के साथ गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था। राजदूत अनिल वाधवा, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार ने मुख्य भाषण दिया था। उन्होंने एआईसी–आरआईएस 'आसियान–भारत विकास और सहयोग की रिपोर्ट 2015" शीर्षक पर रिपोर्ट जारी की थी। प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस और एआईसी ने स्वागत भाषण दिया था। राजदूत श्याम सरन, अध्यक्ष, आरआईएस और श्री श्रीकांत सोमानी, अध्यक्ष, सीआईआई (एनआर) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सोमानी सिरामिक्स लिमिटेड ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया था।

गोलमेज सम्मेलन के पहले सत्र 'आसियान–भारत सामरिक साझेदारी : प्रगति और विकास के आयाम' पर विचार–विमर्श किया गया था। इसका दूसरा सत्र नई 'वैश्विक वास्तुकला और क्षेत्रीय एकीकरण : एशिया के लिए चुनौतियां और अवसर' पर था।

लाइबेरिया गणराज्य की राष्ट्रपति माननीय मदाम एलेन जॉनसन सरलीफ, द्वारा भारत–अफ्रीका भागीदारी और सतत विकास पर विशेष अभिभाषण दिया था

आरआईएस ने 31 अक्तूबर 2015 को नई दिल्ली में लाइबेरिया गणराज्य की राष्ट्रपति माननीय मदाम एलेन जॉनसन सरलीफ, द्वारा भारत–अफ्रीका भागीदारी और सतत विकास पर विशेष भाषण का आयोजन किया गया था। महानिदेशक, आरआईएस प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र के निवासी समन्वयक और भारत में यूएनडीपी के रेसीडेंट स्थानीय प्रतिनिधि श्री यूरी अफनेसिव ने भारत में विशेष अभिभाषण दिया था। कोट डी आईवरी गणराज्य में भारत के राजदूत तथा साथ में लाइबेरिया गणराज्य तथा गिनी गणराज्य के स्वीकृत राजदूत श्री दिनेश भाटिया भी इस अवसर पर उपस्थित थे, जिन्होंने संगोष्ठी को संबंधित किया था। आरआईएस के प्रो. राम उपेंद्र दास ने धन्यवाद ज्ञापन दिया था।

समुद्री सुरक्षा और सहयोग पर ईएएस सम्मेलन

एआईसी ने नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के सहयोग से आरआईएस में 9 और 10 नवंबर, 2015 को नई दिल्ली में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर दो दिवसीय ईएएस सम्मेलन का आयोजन किया था। राजदूत अनिल वाधवाए सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय ने मुख्य भाषण दिया था।

प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस और एआईसी ने स्वागत भाषण दिया था। राजदूत वी एस शेषाद्री, उपाध्यक्ष, आरआईएस ने आरंभिक भाषण दिया। डॉ विजय सखुजा, निदेशक, एनएमएफ और श्री दीपक शेट्टी, महानिदेशक, नौवहन महानिदेशालय की ने विशेष टिप्पणियां प्रदान की। प्रो प्रबीर डे, समन्वयक, एआईसी ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

प्रथम सत्र समुद्री क्षेत्र पर ईएएस के परिप्रेक्ष्य में था। द्वितीय सत्र में एशिया–प्रशांत क्षेत्र में उभरते सुरक्षा वास्तुकला पर विचार–विमर्श किया गया था। तृतीय सत्र, समुद्री संपर्कः व्यापार

के लिए निर्माण पर था। चौथे सत्र में ब्लू इकोनॉमी और समुद्री संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई थी। पांचवां सत्र सागर में 'कॉमन पब्लिक गुड' के सहकारी वितरण पर था, तथा छठा सत्र आगे के उपायों पर था। प्रो प्रबीर डे ने समापन टिप्पणी और धन्यवाद ज्ञापन प्रदान किया था।

डब्ल्यूटीओ और एसडीजी पर सम्मेलन : नैरोबी मंत्रिस्तरीय के समक्ष मुद्दे

विश्व व्यापार संगठन अध्ययन केंद्र (आईआईएफटी), जर्मन विकास संस्थान, फिक्की और सीआईआई के साथ साझेदारी में आरआईएस ने नैरोबी मंत्रिस्तरीय के समक्ष महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया था। 23 और 24 नवंबर 2015 को नई दिल्ली में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। श्री सुधांशु पांडे, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने उद्घाटन भाषण दिया गया था। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, प्रोफेसर अभिजीत दास, प्रमुख, विश्व व्यापार संगठन अध्ययन केंद्र, नई दिल्ली ने स्वागत भाषण दिया था। श्री मानब मजूमदार, सहायक महासचिव (डब्ल्यूटीओ), फिक्कीय और श्री प्रणव कुमार, प्रमुख, अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति प्रभाग, सीआईआई ने भी इस अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत किए। जर्मन विकास संस्थान के श्री जोहानिस ब्लैंकेनबेच ने धन्यवाद ज्ञापन दिया था।

आरआईएस अनुसंधान के नए फ्रंटियर

आरआईएस ने वरिष्ठ शोधकर्ताओं के लिए एक नई संगोष्ठी श्रृंखला फ्रंटियर अनुसंधान संगोष्ठी श्रृंखला की शुरूआत की है जिसमें संस्थान के उभरती अनुसंधान कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी।

- प्रो राम उपेंद्र दास द्वारा 'यूरेशियाई एफटीए एंड इंडिया' पर श्रृंखला की पहली संगोष्ठी 28 अगस्त 2015 को आयोजित की गई थी।
- प्रो. एस. के. मोहंती ने आगामी आरआईएस विश्व व्यापार और विकास रिपोर्ट (डब्ल्यूटीडीआर) के लिए 28 सितम्बर 2015 को दूसरी संगोष्ठी की रूपरेखा प्रस्तुत की थी।

आर आई एस ब्रेकफास्ट संगोष्ठी श्रृंखला

आरआईएस ब्रेकफास्ट संगोष्ठी श्रृंखला का उद्देश्य उनके शोध के निष्कर्षों का प्रसार जारी कार्य पर चर्चा और विशेषज्ञों और साथियों से फीडबैक/प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए युवा संकाय सदस्यों और कैरियर की शीघ्र शुरूआत करने वाले शोधकर्ताओं के लिए एक मंच प्रदान करना है। शैक्षणिक और नीति की प्रासंगिकता के विषयों पर बात करने के लिए प्रख्यात विद्वानों को भी आमंत्रित किया गया था। इसी समय, अपने अनुभव और ज्ञान साझा करने के लिए इन सत्रों की पीठ में प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था। इन सत्रों को पारस्परिक बनाने के लिए कभी–कभी वरिष्ठ शोधकर्ताओं तथा नीति निर्धारकों को भी आमंत्रित किया गया था। इस श्रृंखला में आरआईएस के भाग के रूप में निम्नलिखित संगोष्ठियां आयोजित की गई है :

- प्रो राम उपेंद्र दास, आरआईएस द्वारा 'व्यापार सिद्धांत और अभ्यास के क्षेत्र में विकास' पर 7 अप्रैल 2015 को प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने इस संगोष्ठी की अध्यक्षता की थी।
- आरआईएस द्वारा 'चीनी उत्पादन में इथियोपिया के साथ भारतीय विकास सहयोगः श्री सुशील कुमार,, सलाहकार द्वारा एक आकलन में 5 मई 2015 को प्रो एस के मोहंती, आरआईएस ने इस संगोष्ठी की अध्यक्षता की थी।
- श्री सुनंदो बसुए रिसर्च एसोसिएट, आरआईएस द्वारा 'सीजीई मॉडलिंग और इसके अनुप्रयोग के लिए एक परिचय', पर 2 जून 2015 को प्रो एस मोहंती, आरआईएस की अध्यक्षता में इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया था।
- सुश्री रश्मि सिंह, परामर्शदाता, आरआईएस द्वारा 'वियतनाम – चीन ग्रेटर मेकांग उप–क्षेत्रीय फ्रेमवर्क सहयोग (जीएमएस)' पर 11 अगस्त 2015 को राजनयिक जयंत प्रसाद, अतिथि अध्येता, आरआईएस ने संगोष्ठी की अध्यक्षता की थी।
- सुश्री आस्था गुप्ता, अनुसंधान सहायक, आरआईएस द्वारा 'व्यापार नीति में उदारीकरण और भारत में व्यापार के साथ संबंध' पर 11 सितंबर 2015 को डॉ शाहिद अहमद, प्रमुख, अर्थशास्त्र विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, ने इस संगोष्ठी की अध्यक्षता की थी।

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम

- विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के आईटीईसी / एससीएएपी कार्यक्रम के तहत आरआईएस ने नई दिल्ली में 16–27 नवंबर 2015 के दौरान दक्षिण–दक्षिण सहयोग की समझ पर एक दो सप्ताह का क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया।
- व्यापार नीति और विश्लेषण पर कार्यशालाएं : आरआईएस ने आर्थिक, पर्यावरण और समाज केंद्र (सीईएसएस), म्यांमार के साथ संयुक्त रूप से नई दिल्ली में 9–13 जून 2015 दौरान आरआईएस में 'व्यापार नीति और विश्लेषण' पर चौथी कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को आईपीई वैश्विक, अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए विभाग–सहायता

ब्रिटेन (डीएफआईडी), ज्ञान भागीदारी कार्यक्रम और म्यांमार वाणिज्य मंत्रालय द्वारा समर्थित किया गया था। राजदूत श्याम सरन, अध्यक्ष, आरआईएस ने समापन भाषण दिया। प्रो प्रबीर डे ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। यंगून यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स, यंगून में ससेक्स विश्वविद्यालय, यूएनईएससीएपी, यंगून यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स, ट्रेड सिफ्ट और एशिया–प्रशांत अनुसंधान एवं प्रशिक्षण नेटवर्क (आर्टनेट) के सहयोग से 11–15 मई 2015 के दौरान आरआईएस द्वारा आर्थिक, पर्यावरण और समाज केंद्र (सीईएसएस), म्यांमार के साथ संयुक्त रूप से तीसरी कार्यशाला आयोजित की गई थी।

विश्व व्यापार और विकास रिपोर्ट का शुभारंभ

आरआईएस ने केआईसीसीए नैरोबी में साउथ सेंटर, जिनेवा और राष्ट्रमंडल सचिवालय के साथ साझेदारी में विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के मौके पर 17 दिसंबर 2015 को नैरोबी में 'व्यापार, विकास, विश्व व्यापार संगठन और मेगा एफटीए' पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया। इस अवसर पर "मेगा क्षेत्रीय, विश्व व्यापार संगठन और नए मुद्दों" विषय पर विश्व व्यापार और विकास रिपोर्ट (डब्ल्यूडीआर) के आरआईएस प्रमुख प्रकाशन भी जारी की गई थी और इस पर चर्चा की गई थी। श्रीमती सुचित्रा दुरई, केन्या गणराज्य के लिए भारतीय उच्चायुक्त ने पैनल चर्चा की अध्यक्षता की। प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस; प्रो एस के मोहंती, आरआईएस; डॉ कार्लोस कोरिया, विशेष सलाहकार, साउथ सेंटर, जिनेवा; डॉ मोहम्मद रिजक्वी, निदेशक, व्यापार प्रभाग, राष्ट्रमंडल सचिवालय, लंदन; सुश्री सान्या रीड स्मिथ, तीसरा वैश्विक नेटवर्क, जिनेवा, अन्य दूसरे प्रतिष्ठित वक्ताओं में शामिल थे।

दक्षिण–दक्षिण सहयोग के एक साधन के रूप में आईबीएसए न्यास निधि

आरआईएस नेः नई दिल्ली में 21 दिसंबर 2015 को सुश्री लौरा करीना गेटिरेज मटेमोरोस, रिसर्च स्कॉलर, अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोग एडॉ जोस मारिया लुइस मोरा रिसर्च इंस्टीट्यूट, मेक्सिको (और इंटर्नशिप स्कॉलर्स, आरआईएस) द्वारा 'दक्षिण–दक्षिण सहयोग के साधन के रूप में आईबीएसए न्यास निधि : उभरते देशों की परिप्रेक्ष्य' पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने उद्घाटन भाषण दिया। वैश्विक मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्ल्यूए) के पूर्व महानिदेशक राजदूत राजीव कुमार भाटिया, ने भारतीय विश्व कार्य परिषद (आईसीडब्ल्यूए) संगोष्ठी की अध्यक्षता की।

आसियान–भारत विशिष्ट व्यक्ति व्याख्यान

आसियान–भारत प्रख्यात व्यक्तियों के व्याख्यानों की श्रृंखला के भाग के रूप मेंए आरआईएस में एआईसी ने महामहिम श्री ली लुयोंग मिन्ह, महासचिव, आसियान द्वारा नई दिल्ली में 10 दिसंबर 2015 को "आसियान–भारतः शांति एवं समृद्धि के लिए भागीदारी" पर आसियान–भारत प्रख्यात व्यक्ति व्याख्यान का आयोजन किया। प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। राजदूत वी एस शेषाद्री, उपाध्यक्ष, आरआईएस ने टिप्पणियां खोली। राजदूत अनिल वाधवा, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने विशेष भाषण दिया। प्रो प्रबीर डे, समन्वयक, एआईसी ने सत्र का समापन किया और धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।

भारत में नैदानिक परीक्षण विनियम पर कार्यशाला

आरआईएस ने स्वास्थ्य अभियान मंच बनाम यूओआई में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और उनके प्रभाव के परिणामस्वरूप भारत में नैदानिक परीक्षण विनियम में हाल के बदलाव पर अध्ययन के भाग के रूप में अनुसंधान दल द्वारा किए गए सर्वेक्षण की जांच परिण ाामों को साझा करने और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 2 दिसंबर, 2015 को नई दिल्ली में 'भारत में नैदानिक परीक्षण नियमों' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। प्रो. एस के ब्रह्मचारी, पूर्व सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग तथा महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान (सीएसआईआर) परिषद द्वारा इस कार्यशाला का उद्घाटन किया गया था।

अभिनव वित्त नीति के माध्यम से एक स्वच्छ ऊर्जा मंच के निर्माण पर चर्चा हेतु बैठक

आरआईएस ने 18 दिसंबर, 2015 को नई दिल्ली में अभिनव वित्त नीति के माध्यम से एक स्वच्छ ऊर्जा मंच के निर्माण पर चर्चा हेतु बैठक का आयोजन किया। प्रो. राम उपेंद्र दास, आरआईएस द्वारा आरंभिक भाषण दिया गया। श्री जेफरी स्कहुब, ग्रीन कैपिटल के लिए गठबंधन के कार्यकारी निदेशक मुख्य वक्ता थे। डॉ नित्यानंद, अध्येता द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टेरी) और डॉ सब्यसाची साहाए आरआईएस ने चर्चा में भाग लिया था।

जयपुर में एफडीआईसी क्षेत्रीय परामर्श

एफडीआईसी–आरआईएस ने 22–23 दिसंबर 2015 को जयपुर में तीसरे क्षेत्रीय परामर्श का आयोजन किया। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने उद्घाटन सत्र में स्वागत भाषण दिया। श्री ए.के साहूए संयुक्त सचिव (डीपीए II), विदेश मंत्रालय ने उद्घाटन भाषण दिया। प्रोफेसर वी.एस. व्यासए अवकाश प्राप्त प्रोफेसर विकास अध्ययन संस्थान (आईडीएस), जयपुर ने मुख्य भाषण दिया। डॉ कौस्तुव बंदोपाध्याय, निदेशक, सीएसओ पर एफडीआईसी कार्य समूह के पीआरआई, और संयोजक ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

दो दिवसीय विचार–विमर्श के दौरान उभरे महत्वपूर्ण मुद्दे दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर एक भारतीय वर्णन के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे।

आर आई एस ब्रेकफास्ट संगोष्ठी श्रृंखला

2 दिसंबर 2015 को श्री प्रत्युश, अनुसंधान सहायक, आरआईएस द्वारा 'वैश्विक प्रणाली सिद्धांत माध्यम से वैश्विक विकास पर बहस की गई। प्रो ऐश नारायण राय' निदेशक, सामाजिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने इसकी अध्यक्षता की थी।

अन्य आयोजन :

- 6 जनवरी 2016 अगले दशक के लिए आईओआरए की बढ़ती मजबूती तथा रोडमैप पर पैनल चर्चा
- 11 जनवरी 2016 को येल विश्वविद्यालय से प्रो कवेः खोस्न्नूद द्वारा आरआईएस / एफडीआईसी संगोष्ठी।
- जनवरी 2016 के दौरान शिलांग / पटना और चेन्नई में एफडीआईसी क्षेत्रीय परामर्शी
- विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर भारत–अफ्रीका भागीदारी संगोष्ठीः 21 जनवरी 2016 को बीज क्षेत्र और कृषि उपकरण पर विशेष ध्यान दिया गया।
- पोषण हेतु 11 एवं 12 फरवरी, 2016 को कृषि और खाद्य प्रणाली पर वैश्विक पैनल द्वारा दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परामर्शी पर आर आई एस/पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन पर भारतीय सम्मेलन
- 22 और 23 फरवरी 2016 को एसडीजी स्थिति और प्रतिबद्ध ताओं पर आरआईएस / नीति आयोग परामर्शी

आरआईएस प्रकाशन

आरआईएस प्रकाशनों की सूची अनुबंध XIV पर दी गई है।

बजट

विदेश मंत्रालयए भारत सरकार ने आरआईएस को वर्ष 2015–16 के लिए 6.85 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता संस्वीकृत की है।

■ ■

35 विश्व मामलों की भारतीय परिषद

विदेश मंत्रालय का पुस्तकालय

विदेश मंत्रालय का पुस्तकालय मुख्यालय तथा विदेश स्थित भारतीय मिशनों एवं केंद्रों में कार्यरत विदेश मंत्रालय के अधिकारियों व कर्मचारियों के ज्ञानवर्धन के लिए पुस्तकालय के साथ–साथ संसाधन और सूचना केंद्र के रूप में सामान्य तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। पुस्तकालय वर्तमान में पटियाला हाउस के अपने पुराने परिसर में साथ ही जवाहर लाल नेहरू भवन में दोनों जगह से कार्य कर रहा है।

पुस्तकालय में एक लाख से ज्यादा पुस्तकें, मूल्यवान संसाधन सामग्री और मानचित्र, माइक्रो फिल्मों एवं सरकारी दस्तावेजों का बड़ा संग्रह मौजूद है। यह विदेश मंत्रालय में नीति आयोजना तथा अनुसंधान को समर्थन करने के लिए आधुनिक सुविधाओं से भी सुसज्जित है। विदेश मंत्रालय का पुस्तकालय लगभग 300 पत्रिकाएं/जर्नल्स तथा समाचार पत्र शीर्षक (ऑन–लाइन जर्नल्स और डेटाबेस सहित) मंगवाता/प्राप्त करता है और उसका रखरखाव करता है।

पुस्तकालय समिति पुस्तकालय के क्रियाकलापों का प्रबंधन करती है जिसमें पुस्तकों की खरीद और दैनिकी/पत्रिकाएं और डेटाबेस मंगवाना शामिल है। विदेश सचिव पुस्तकालय समिति का गठन/पुनर्गठन करते हैं। वर्तमान पुस्तकालय समिति में संयुक्त सचिव (पीपी एण्ड आर और जीसीआई) अध्यक्ष हैं तथा टेरिटोरियल प्रभागों के 3 से 4 निदेशक/उप सचिव इसके सदस्य तथा निदेशक (पुस्तकालय एवं सूचना) के रूप में सदस्य–सचिव हैं। अनुमोदन के आधार पर वेंडरों द्वारा प्रस्तुत पुस्तकों की पुस्तकालय समिति की बैठकों में प्रस्तुत करने से पहले पुस्तकालय के अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है। इस पुस्तकालय की पुस्तकों का चयन करने के लिए प्रत्येक वर्ष पुस्तकालय समिति की 4 से 6 बैठकें आयोजित की जाती हैं। रोज की जरूरत के हिसाब से प्राथमिकता आधार पर अनुरोधित/अनुशंसित पुस्तकें खरीदी जाती हैं। और अंतर–पुस्तकालय ऋण के माध्यम से भी पुस्तकें खरीदी जाती हैं अधिकारियों को आपूर्ति की जाती हैं।

पुस्तकालय सेवाएं न केवल विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और मंत्रालय के कर्मचारियों और विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों के लिए प्रदान की जाती हैं, बल्कि, अंतरराष्ट्रीय संबंधों एवं इससे जुड़े विषयों पर मूल्यवान एवं विशिष्ट संग्रह के कारण, हम नियमित रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय (पी एम ओ), राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति कार्यालय, वैश्विक मामलों की भारतीय परिषद (आई सी डब्लूय ए), भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई सी सी आर)ए राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय परिषद (एन एस सी एस), नेशनल डिफेंस कॉलेज (एन डी सी), विभिन्न अन्य मंत्रालयों तथा विभागों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के शोधकर्ताओं को भी पुस्तकालय की सेवाएं प्रदान करते हैं।

एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन साफ्टवेयर "लिबसिस" का इस्तेमाल करते हुए सभी प्रलेखन/ग्रंथ–संदर्भी सेवाएं तथा अन्य पुस्तकालय प्रचालन एवं सेवाएं कंप्यूटरीकृत कर दी गई हैं। ऑन लाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग (ओ पी ए सी) के माध्यम से सभी पुस्तकों एवं प्रलेखों तथा पुस्तकालय में प्राप्त पत्रिकाओं / दैनिकियों से प्राप्त चुनिंदा लेखों के बारे में जानकारी उपलब्ध है। हमने हाल ही में "वेब सेंट्रिक लिबसिस 7" से जोड़ते हुए पुस्तकालय प्रबंधन साफ्टवेयर को उन्नत बनाया है। विदेश मंत्रालय की वेबसाइटः http://mealib.nic.in पर इंटरनेट के माध्यम से भी पुस्तकालय संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

विदेश मामलों संबंधी डेटाबेस में पुस्तकालय में प्राप्त सभी नए प्रलेखों और पत्रिकाओं तथा दैनिकियों से प्राप्त चुनिंदा लेखों को नियमित आधार पर फीड किया जा रहा है। पुस्तकालय अपने उपभोक्ताओं को ऑन लाईन / वेब आधारित सेवाएं, ऑन लाइन जर्नल्स / पेरियोडिकल्स तथा डेटाबेस सेवाएं, ई–मेल सेवाएं, बुक एलर्ट एण्ड आर्टिकल एलर्ट सेवाएं तथा साथ ही सभी प्रकार की सर्वाधिक आधुनिक कंप्यूटरीकृत सेवाएं प्रदान कर रहा है। इन ऑन लाइन डेटाबेसों और दैनिकियों / पत्रिकाओं के बारे में यूजरनेम और पासवर्ड के जरिए इंटरनेट पर जानकारी हासिल की जा सकती है। ऐसे शीर्षकों की सूची नियमित रूप से मुख्यालय तथा विदेश स्थित भारतीय मिशनों और केंद्रों में भी परिचालित की जाती है और यह विदेश मंत्रालय की वेबसाइटः http://mealib.nic.in पर भी उपलब्ध है।

अपने उपभोक्ताओं को प्रलेखन, बिब्लियोग्राफिक, करेंट अवेयरनेस/एसडीआई और संदर्भ सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से पुस्तकालय नियमित आधार पर विभिन्न बुलेटिनें जैसे रीसेंट एडिशन्स, फॉरेन अफेयर्स डकुमेंटेशन बुलेटिन एवं क्रोनिकल ऑफ इवेन्ट जारी करता है। इसके अतिरिक्त, पुस्तकालय ने विभिन्न ऑनलाइन डेटाबेसेस/ आनलाइन सेवाओं जैसे ईआईयू ऑनलाइन सर्विसेस, बिजनेस मानीटर इंटरनेशनल, मार्केट लाइन एडवांटेज, प्रेस रीडर, जेएसटीओआर आर्काइवल डेटाबेस, प्रोक्वेस्ट एबीआई इंफोर्मा कंपलीट, प्रोक्वेस्ट – हिस्टोरिकल न्यूजपेपर आर्काइव्स, जेन्स ऑनलाइन सर्विसेस, केसिंग्स वर्ल्ड न्यूज आर्काइव्स, आदि के माध्यम से सेवाएं प्रदान करना प्रारंभ कर दिया है।

पुस्तकालय ने एनआईसी के सहयोग से विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट (1948 से 1998–99) तथा फोरेन अफेयर्स रिकार्ड (1955 से 1999) का फुल टेक्स्ट सीडी–आरओएम निकाला है।

विदेश मंत्रालय के पुस्तकालय में दुर्लभ पुस्तकों का बहुत अच्छा संग्रह है। कुछ चुनिंदा दुर्लभ पुस्तकों की सूची पहले ही तैयार और मुद्रित करा ली गई है। इन दुर्लभ पुस्तकों को जेएनबी स्थित एक पृथक दुर्लभ पुस्तक लाइब्रेरी में रखा गया है।

हमने हाल ही में 1947 से 2014 तकष्भारत की द्विपक्षीय संधियों एवं करारों तथा साथ ही संयुक्त घोषणापत्रों और विज्ञप्तियोंष्को प्रकाशित/पुनः मुद्रित करने के लिए एक परियोजना पूरी की है और इस प्रकाशन को 18 खंडों में शीघ्र ही जारी किए जाने की संभावना है।

विदेश मंत्राललय का पुस्तकालय दिल्ली के विभिन्न संस्थानों में अध्ययनरत पुस्तकालय विज्ञान के छात्रों को समय–समय पर व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। आईसीडब्ल्यूए के अनुरोध परए विदेश मंत्रालय पुस्तकालय के एक अधिकारी को हाल ही में आईसीडब्ल्यूए पुस्तकालय में पुस्तकालय और अपनी सेवाओं के उन्नयन के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है।

विदेश मंत्रालय का पुस्तकालय इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन (आईएलए), इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एण्ड इन्फार्मेशन सेंटर (आईएएसएलआईसी), इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन्स एण्ड इंस्टीट्यूशन्स (आईएफएलए) और स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन (एसएलए) का एक संस्थागत सदस्य है। निदेशक (पुस्तकालय एवं सूचना) तथा अन्य अधिकारियों ने समय–समय पर आई एल ए, आई ए एस एल आई सी, आई एफ एल ए, एस एल ए, आदि के अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सम्मेलनों / सेमिनारों / बैठकों में नियमित रूप से भाग लिया। डॉ एस एस ढाकाए निदेशक (पुस्तकालय एवं सूचना) का 2015–2017 तक की अवधि के लिए एसएलए (एशियाई अध्याय) के अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया है। वे आईएफएलए – जीआईओपीएस के एससी सदस्य और एशियाई लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। श्री संजय कुमार बिहानी, 2015–2017 तक की अवधि के लिए आईएफएलए – आरएससीएओ के सचिव और 2015–2019 के लिए आईएफएलए – जीआईओपीएस के एससी सदस्य के रूप में चुने गए हैं।

अभिलेखागार एवं अभिलेख प्रबंधन

विदेश मंत्रालय के अभिलेखागार और अभिलेख प्रबंधन प्रभाग अभिलेखागार और अभिलेख प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों को देखता है। 1 अप्रैल 2015 से 30 नवम्बर 2015 के बीच की अवधि के दौरान 2679 फाइलें संबंधित विभाग प्रमुखों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद मूल्यांकन के लिए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंप दी गई हैं। इनके अलावा, 2737 साधारण फाइलों को नष्ट कर दिया गया है और 5555 फ़ाइलों को गैर–गोपनीयता श्रेणी में रखने हेतु अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है। 282 रैकों वाले छह कम्पेक्टरों की सात रिकॉर्ड सॉर्टर द्वारा सफाई की गई थी तथा कम्पेक्टरों में कुल 26230 फ़ाइलें रखने की व्यवस्था है।

■ ■

36 वित्त और बजट

वर्ष 2015–16 के लिए विदेश मंत्रालय के लिए कुल बजट परिव्यय 14966.83 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2014–15 के लिए आबंटित बजट (14730.39 करोड़ रुपये) से 1.67 प्रतिशत अधिक था (परिशिष्ट XV)।

इस बजट का बड़ा भाग योजना और गैर–योजना निधि दोनों के माध्यम से अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए है।

योजना

विदेश मंत्रालय के बजट का योजना घटक अवसंरचना, जल विद्युत पावर प्रोजेक्ट्स, कृषि, उद्योग आदि के क्षेत्रों में कई बड़ी विकास परियोजाओं की जरूरतों को पूरा करता है जिन्हें भारत के पड़ोसी देशों जैसे भूटान, अफगानिस्तान और म्यांमार में चलाई जाती हैं।

भूटान इस योजना बजट शीर्ष से लाभ उठाने वालों में हमारा एक प्रधान लाभग्राही है। कई महत्वपूर्ण जल विद्युत पावर प्रोजेक्ट्स जैसे पुनातसांग्छु जल विद्युत परियोजना–I एवं II तथा मांग्देछु जल विद्युत परियोजना क्रियान्वित की जा रही हैं।

अफगानिस्तान भी योजना घटक निधि का दूसरा महत्वपूर्ण गंतव्य स्थान है। अफगानिस्तान में काबुल से पुले–ए–खुमरी तक डबल सर्किट पारेषण लाइन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इस परियोजना के अतिरिक्त घटक के रूप में अब दोशी और चारीकर में दो उप–केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है।

म्यांमार में कालादन मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना पर भी पर्याप्त प्रगति हुई है।

गैर–योजना

वित्तीय वर्ष 2015–16 में भारत के तकनीकी सहयोग कार्यक्रमों के प्रधान लाभग्राही भूटान (1200 करोड़ रुपए), बांग्लादेश (250 करोड़ रुपए), अफगानिस्तान (550 करोड़ रुपए), श्रीलंका (500 करोड़ रुपए), नेपाल (420 करोड़ रुपए), म्यांमार (120 करोड़ रुपए) तथा अफ्रीकी देश (200 करोड़ रुपए) थे। कुछ अन्य लाभग्राहियों में मालदीव, मंगोलिया, लातिन अमेरिकी, यूरेशिया और अन्य क्षेत्रों के देश शामिल हैं।

मंत्रालय को 31 सितंबर 2015 तक पासपोर्ट जारी करने, वीजा शुल्क और अन्य प्राप्तियों से 2079.59 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। राजस्व प्राप्तियां निम्नानुसार रहीं:

लघु शीर्ष	राजस्व प्राप्ति (करोड़) में)
पासपोर्ट	1110.83
वीजा शुल्क	757.10
अन्य	211.66
कुल	2079.59

वर्ष 2015–16 के बजट अनुमान के अनुसार बजट आबंटन का क्षेत्रवार विश्लेषण (परिशिष्ट XVI) दर्शाता है कि कुल 14966.83 करोड़ रुपए के आबंटन में से बजट का 60.85 प्रतिशत (9107.02 करोड़ रु.) तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के अंतर्गत परियोजनाओं पर और विदेशी सरकारों को ऋण एवं अग्रिम के रूप में 3398.80 करोड़ रु. व्यय किया गया था। मिशनों और केन्द्र को बजट का 15 प्रतिशत (2265.01 करोड़ रु.) आबंटित किया गया था। शेष आबंटन विशेष राजनयिक व्यय (11 प्रतिशत), पासपोर्ट एवं उत्प्रवासन (4 प्रतिशत), अंतरराष्ट्रीय संगठनों (3 प्रतिशत) और संस्थानों को अनुदान (1 प्रतिशत), पूंजीगत परिव्यय (2 प्रतिशत), विदेश मंत्रालय सचिवालय (2 प्रतिशत) तथा अन्यों (1 प्रतिशत) पर किया गया।

■ ■

परिशिष्ट

परिशिष्ट–I

वर्ष 2015 के दौरान अन्य देशों के साथ भारत द्वारा संपन्न किए गए अथवा नवीकृत संधियां / अभिसमय / करार : बहुपक्षीय

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
1.	अंतरराष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन पर अभिसमय के प्रोटोकॉल में संशोधन		16 अप्रैल 2015		रक्षा मंत्रालय
2.	जहाजों पर हानिकारक विरोधी दूषण प्रणाली का नियंत्रण पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 2001		25 मार्च 2015		जहाजरानी मंत्रालय
3.	ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था की स्थापना के लिए संधि	15 जुलाई 2014	25 मार्च 2015		वित्त मंत्रालय
4.	नए विकास बैंक पर करार	15 जुलाई 2014	25 मार्च 2015		वित्त मंत्रालय
5.	भारत गणराज्य और दक्षिण पूर्व एशियाई देश संघ के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग फ्रेमवर्क करार के तहत सेवाओं में व्यापार पर करार	12 नवंबर 2014	6 अप्रैल 2015		वाणिज्य मंत्रालय
6.	ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय की स्थापना पर समझौता ज्ञापन	18 नवंबर 2015		18 नवंबर 2015	विदेश मंत्रालय
7.	संयुक्त ब्रिक्स वेबसाइट के निर्माण पर समझौता ज्ञापन	9 जुलाई 2015		9 जुलाई 2015	विदेश मंत्रालय
8.	ब्रिक्स के बीच ऊर्जा की बचत और ऊर्जा दक्षता पर समझौता ज्ञापन	20 नवंबर 2015		20 नवंबर 2015	विदेश मंत्रालय
9.	संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर ब्रिक्स देशों की सरकार के बीच समझौता।	9 जुलाई 2015		9 जुलाई 2015	संस्कृति मंत्रालय
10.	बंग्लादेशए भूटानए भारत और नेपाल के बीच यात्री, व्यक्तिगत और कार्गो वाहनों के यातायात के नियमन के लिए मोटर वाहन करार	15 जून 2015	10 जुलाई 2015		सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
11.	भारत गणराज्य तथा दक्षिण–पूर्व एशियाई देश संघ के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग फ्रेमवर्क करार के तहत निवेश पर करार	12 नवंबर 2014	6 अप्रैल 2015		वाणिज्य मंत्रालय
12.	आईएलओ की समुद्री श्रम सम्मेलन, 2006	10 जुलाई 2015	9 अक्टूबर 2015		जहाजरानी मंत्रालय
13.	एशियाई मूल संरचना निवेश बैंक के समझौते के अनुच्छेद	29 जून 2015	16 दिसंबर 2015		वित्त मंत्रालय

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
14.	भारत गणराज्य और दक्षिण–पूर्व एशियाई देश संघ के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग फ्रेमवर्क समझौते के तहत सेवाओं में व्यापार पर करार	13 नवंबर 2014	6 अप्रैल 2015		वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

ख : द्विपक्षीय

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
1.	अफगानिस्तान के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और भारत गणराज्य के वस्त्र मंत्रालय के बीच कपड़ा, वस्त्र, निवेश, अनुपालन और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।	**अफ़ग़ानिस्तान**	7 जनवरी 2015	8 जनवरी 2016		वस्त्र मंत्रालय
2.	भारत गणराज्य की सरकार तथा अल्बानिया गणराज्य के मंत्रियों की परिषद के बीच राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकताओं की छूट पर करार	**अल्बानिया**	27 नवंबर 2015			विदेश मंत्रालय
3.	भारत और ऑस्ट्रेलिया के गणराज्य के बीच सामाजिक सुरक्षा करार	**ऑस्ट्रेलिया**	18 नवंबर 2014	9 अक्टूबर 2015		प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
4.	भारत सरकार और ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच सहयोग पर परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का समझौता।	**ऑस्ट्रेलिया**	5 सितंबर 2014	12 नवंबर 2015	13 नवंबर 2015	परमाणु ऊर्जा विभाग
5.	खेल में सहयोग पर भारत सरकार और ऑस्ट्रेलिया की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	**ऑस्ट्रेलिया**	5 सितंबर 2014		5 सितम्बर 2014	युवा एवं खेल मंत्रालय
6.	भारत गणराज्य और ऑस्ट्रेलिया की सरकार के बीच जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	**ऑस्ट्रेलिया**	5 सितंबर 2014		5 सितम्बरए 2014	जल संसाधन मंत्रालय
7.	राष्ट्रीय कौशल विकास निगमए भारत गणराज्य और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल के बीच तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	**ऑस्ट्रेलिया**	5 सितंबर 2014		5 सितम्बर 2014	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

जारी है.....

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
8.	भारतीय नौसेना के प्रतिनिधित्व द्वारा भारत गणराज्य तथा ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल की ओर से आव्रजन और सीमा सुरक्षा विभाग के प्रतिनिधित्व द्वारा ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल के बीच व्हाइट शिपिंग जानकारी साझा करने के रूप में तकनीकी व्यवस्था	**ऑस्ट्रेलिया**	2 अक्टूबर 2015		2 अक्टूबर 2015	जहाजरानी मंत्रालय
9.	भारत गणराज्य और ऑस्ट्रिया गणराज्य के बीच सामाजिक सुरक्षा पर समझौता	**ऑस्ट्रिया**	4 फ़रवरी 2013	2 अप्रैल 2013	1 जुलाई, 2015	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
10.	भारत गणराज्य सरकार और बहरीन की शाही सरकार के बीच जल संसाधन विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	**बहरीन**	22 फ़रवरी 2015		22 फ़रवरी 2015	जल संसाधन मंत्रालय
11.	भारत गणराज्य सरकार और बहरीन की शाही सरकार के बीच अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने, इसके अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध में परिवर्तन, शीली दवाओं, मादक और मनः प्रभावी पदार्थ और प्रि कर्सर रसायन की तस्करी में सहयोग पर करार		बहरीन	2 दिसंबर 2015		गृह मंत्रालय
12.	भारत गणराज्य सरकार तथा बंग्लादेश जनवादी गणराज्य सरकार के बीच भारत और बंग्लादेश के बीच भूमि सीमा और सीमांकन के संबंधित मामलों के संबंध में करार	**बंग्लादेश**	16 मई 1974	25 मई 2015		विदेश मंत्रालय
13.	भारत गणराज्य सरकार तथा बंग्लादेश जनवादी गणराज्य सरकार के बीच		जल संसाधन मंत्रालय	25 डंल 2015		विदेश मंत्रालय
14.	भारत – बंग्लादेश भूमि सीमा करार, 1974 और भूमि सीमा करार के 2011 प्रोटोकॉल के बारे में दस्तावेजों के अनुसमर्थन के विषय में आदान–प्रदान के लिए प्रोटोकॉल।	**बंग्लादेश**	6 जून 2015			विदेश मंत्रालय
15.	भारत गणराज्य के तटरक्षक बल और बंग्लादेश जनवादी गणराज्य के बंग्लादेश के तटरक्षकों के बीच समुद्र में अंतरराष्ट्रीय अवैध गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए तथा भारत तटरक्षक बल और बंग्लादेश तटरक्षक बल के बीच क्षेत्रीय सहयोग के विकास हेतु सहयोगात्मक संबंधों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन।	**बंग्लादेश**	6 जून 2015			रक्षा मंत्रालय

जारी है.....

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
16.	भारत और बंग्लादेश के बीच व्यापार समझौते	**बंग्लादेश**	6 जून 2015		1 अप्रैल 2015	वाणिज्य मंत्रालय
17.	भारतीय मानक ब्यूरो और बंग्लादेश के मानक और परीक्षण संस्थान के बीच मानकीकरण और अनुरूपता आकलन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता।	**बंग्लादेश**	6 जून 2015		6 जून, 2015	उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
18.	भारत गणराज्य सरकार और बंगलादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच भारत और बंग्लादेश में ढाका में गुवाहाटी के बीच यात्री बस सेवा का संचालन पर समझौते के मामले में प्रोटोकॉल		6 जून 2015	उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	6 जून, 2015	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
19.	वर्ष 2015–2017 के लिए भारत गणराज्य सरकार और बंगलादेश जनवादी गणराज्य सरकार के बीच सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम **(सीइपी)**।	**बंग्लादेश**	6 जून 2015		6 जून 2015	संस्कृति मंत्रालय
20.	भारत गणराज्य सरकार **(जीओआई)** तथा बंगलादेश जनवादी गणराज्य सरकार **(जीओर्बी)** के बीच भारत सरकार की ओर से बंग्लादेश सरकार को 2.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर की नई ऋण रेखा विस्तारित करने के लिए समझौता ज्ञापन	**बंग्लादेश**	6 जून 2015		6 जून 2015	विदेश मंत्रालय
21.	भारत गणराज्य सरकार के जहाजरानीए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा बंग्लादेश जनवादी गणराज्य सरकार के जहाजरानी मंत्रालय के बीच चिट्टागोंग और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग से संबंधित माल की आवाजाही के लिए समझौता ज्ञापन।	**बंग्लादेश**	6 जून 2015			जहाजरानी मंत्रालय
22.	भारत गणराज्य सरकार और बंग्लादेश जनवादी गणराज्य सरकार के बीच नकली नोटों का प्रचलन और तस्करी को रोकने के लिए तथा निपटने के लिए समझौता ज्ञापन	**बंग्लादेश**	6 जून 2015		6 जून 2015	वित्त मंत्रालय

जारी है.....

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
23.	भारत गणराज्य सरकार और बंग्लादेश जनवादी गणराज्य सरकार के बीच तथा मानव तस्करी विशेषकर महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार की रोकथाम; बचावए बचानेए स्वदेश वापसी और तस्करी के शिकार के पुनः एकीकरण के लिए द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता ज्ञापन	**बंग्लादेश**	6 जून 2015		6 जून 2015	गृह मंत्रालय
24.	भारत गणराज्य सरकार और बंग्लादेश जनवादी गणराज्य सरकार के बीच नकली नोटों का प्रचलन और तस्करी को रोकने के लिए तथा निपटने के लिए समझौता ज्ञापन	**बंग्लादेश**	6 जून 2015		6 जून 2015	वित्त मंत्रालय
25.	भारत गणराज्य सरकार और बंग्लादेश जनवादी गणराज्य सरकार के बीच बंग्लादेश में भारतीय आर्थिक क्षेत्र की स्थापना पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन।	**बंग्लादेश**	6 जून 2015		6 जून 2015	वाणिज्य मंत्रालय
26.	भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और बांग्लादेश जनवादी गणराज्य के पर्यावरण और वन विभाग के बीच दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन के तहत भारत सरकार से सहायता अनुदान से संबंधित भारत बंदोबस्ती **(आईईसीसी–एसए)** के तहत बांग्लादेश के चयनित क्षेत्रों में 70ए000 उन्नत कुक स्टोव **(आईसीएस)** की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन।	**बंग्लादेश**	6 जून 2015		6 जून 2015	विदेश मंत्रालय
27.	बंगाल की खाड़ी के समुद्र विज्ञान पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारत, और ढाका विश्वविद्यालय, बंग्लादेश के बीच संयुक्त अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन	**बंग्लादेश**	6 जून 2015			विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
28.	बांग्लादेश जनवादी गणराज्य और भारत गणराज्य के बीच शिक्षा सहयोग पर आशय का वक्तव्य।	**बंग्लादेश**		विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग		मानव संसाधन विकास मंत्रालय

जारी है......

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
29.	भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के अध्यक्ष की ओर से एलआईसी द्वारा बंग्लादेश में प्रचालन आरंभ करने के लिए बंग्लादेश के इंश्योरेंस डेवलपमेंट एण्ड रेगुलेटरी एथॉरिटी (आई.डी.आर.ए) को सहमति पत्र सौंपना	**बंग्लादेश**	6 जून 2015		मानव संसाधन विकास मंत्रालय	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
30.	भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और बांग्लादेश जनवादी गणराज्य के बीच दोनों देशों के बीच मोटर वाहन यात्री आवागमन के नियमन के लिए करार	**बंग्लादेश**	6 जून 2015	भारतीय जीवन बीमा निगम	6 श्रनदम 2015	भारतीय जीवन बीमा निगम
31.	भारत गणराज्य की सरकार और बांग्लादेश जनवादी गणराज्य के बीच तटीय जहाजरानी पर करार	**बंग्लादेश**	6 जून 2015			जहाजरानी मंत्रालय
32.	भारत गणराज्य सरकार और बारबाडोस सरकार के बीच हवाई सेवा करार	**बारबाडोस**	6 अक्टूबर 2015			नागर विमानन मंत्रालय
33.	भारत–बेलारूस सहयोग के लिए रोडमैप	**बेलारूस**	3 जून, 2015			
34.	भारत गणराज्य सरकार और बेलारूस जनवादी गणराज्य के बीच 27 सितम्बर 1997 को आय और संपत्ति (पूंजी) पर करों के संबंध में दोहरे कराधान और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम से बचाव हेतु करार में संशोधन के लिए प्रोटोकॉल	**बेलारूस**	3 जून, 2015	31 श्रनसल 2015	19 नवंबर 2015	वित्त मंत्रालय
35.	भारतीय मानक ब्यूरो और बेलारूस गणराज्य की मानकीकरण राज्य समिति के बीच मानकीकरण और जानकारी के समर्थन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	**बेलारूस**	3 जून, 2015			उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
36.	प्रसार भारती (पीबी) और बेलारूस गणराज्य की राष्ट्रीय राज्य टेलीविजन और रेडियो कंपनी (बेलेटेर रेडियो कंपनी) के बीच प्रसारण पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	**बेलारूस**	3 जून 2015			सूचना और प्रसारण मंत्रालय
37.	बेलारूस गणराज्य के वित्त मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता ज्ञापन	**बेलारूस**	3 जून 2015	सूचना और प्रसारण मंत्रालय		वित्त मंत्रालय

जारी है.......

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
38.	भारत गणराज्य सरकार और बेलारूस राज्य कंपनी के बीच प्रकाश उद्योग की वस्तुओं के विनिर्माण और विपणन **(कंपनी''बैलगप्रोम'')** के लिए समझौता ज्ञापन	**बेलारूस**	3 जून 2015			वस्त्र मंत्रालय
39.	भारत गणराज्य सरकार और ब्राजील सरकार के बीच की प्रत्यर्पण संधि	**ब्राजील**	16 अप्रैल 2008	14 अगस्त 2008	20 अगस्त 2015	विदेश मंत्रालय
40.	भारत गणराज्य सरकार और बुल्गारिया गणराज्य के बीच 2005–2017 की अवधि में विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में सहयोग के लिए कार्यक्रम		4 सितंबर 2015		4 सितंबर 2015	संस्कृति मंत्रालय
41.	भारत गणराज्य सरकार और बुल्गारिया गणराज्य के बीच 2005–2017 की अवधि में विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में सहयोग के कार्यक्रम के तहत आदान प्रदान के नियमन की वित्तीय और सामान्य शर्तें।	**बुल्गारिया**	4 सितंबर 2015			मानव संसाधन विकास मंत्रालय
42.	जवाहर लाल नेहरु पत्तन न्यास और एंटवर्प / फ्लैंडर प्रशिक्षण केंद्र के बीच समझौता ज्ञापन	**बेल्जियम**	12 फ़रवरी 2015			जहाजरानी मंत्रालय
43.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत गणराज्य तथा बेल्जियम के सक्षम प्राधिकारियों के बीच ऊर्जा के संघीय और क्षेत्रीय स्तर पर समझौता ज्ञापन, बेल्जियम सरकार	**बेल्जियम**			जहाजरानी मंत्रालय	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
44.	भारत गणराज्य सरकार और कंबोडिया शाही सरकार के बीच पर्यटन में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	**कंबोडिया**	16 सितम्बर 2015		16 सितम्बर 2015	पर्यटन मंत्रालय
45.	सॉफ्टवेयर विकास और प्रशिक्षण में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना पर समझौता ज्ञापन।	**कंबोडिया**			5 अगस्त 2015	विदेश मंत्रालय
46.	राष्ट्रीय डाक संस्थान, टेलीकॉम और आईसीटी, डाक और दूर संचार मंत्रालय, कंबोडिया की शाही सरकार और उन्नत अवकलन विकास केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत गणराज्य सरकार के बीच पारंपरिकए आभासी कक्षा और ई–लर्निंग तकनीकों का उपयोग करते हुए सीएलएमवी / आसियान में उन्नत आईटी प्रशिक्षण के लिए स्थायी आईटी बुनियादी रूपरेखा की स्थापना के लिए करार।	**कंबोडिया**	29 अप्रैल 2015		29 अप्रैल 2015	

जारी है......

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
47.	भारत गणराज्य सरकार और कंबोडिया की शाही सरकार के बीच त्वरित प्रभाव परियोजनाओं (क्यूआईपी) केकार्यान्वयन के लिए भारतीय अनुदान सहायता पर करार।	**कंबोडिया**	16 सितंबर 2015		16 सितंबर 2015	विदेश मंत्रालय
48.	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत गणराज्य और कनाडा के जन सुरक्षा और आपातकालीन तैयारी विभाग के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	**कनाडा**	26 मार्च 2015		26 मार्च 2015	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
49.	बाह्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तथा कनाडा अंतरिक्ष एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन	**कनाडा**	15 अप्रैल 2015		15 अप्रैल 2015	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
50.	रेल परिवहन में तकनीकी सहयोग पर कनाडा के परिवहन विभाग और रेल मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन	**कनाडा**	15 अप्रैल 2015			रेल मंत्रालय
51.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा ग्रांट चैलेंजिस तथा कनाडा के बीच रोग उन्मूलन और मस्तिष्क के बचाव के प्रयासों में डीबीटी – जीसीसी सहयोग के कार्यान्वयन हेतु आशय पत्र	**कनाडा**	15 अप्रैल 2015		15 अप्रैल 2015	जैव प्रौद्योगिकी विभागए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
52.	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) तथा सेनेका कॉलेज, टोरंटो के बीच विमानन – गैर तकनीकी और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के लिए कौशल विकास में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	**कनाडा**	15 अप्रैल 2015		15 अप्रैल 2015	राष्ट्रीय कौशल विकास संगठन
53.	राष्ट्रीय कौशल विकास संगठन सर सैंडफोर्ड फ्लेमिंग कॉलेज, लिंडसे के बीच जल क्षेत्र के लिए कौशल विकास में समझौता ज्ञापन	**कनाडा**	15 अप्रैल 2015		15 अप्रैल 2015	राष्ट्रीय कौशल विकास संगठन
54.	राष्ट्रीय कौशल विकास और एल्गोनक्विन कॉलेज, ओटावा के बीच मोटर वाहन तथा निर्माण के लिए कौशल विकास में समझौता ज्ञापन	**कनाडा**	15 अप्रैल 2015		15 अप्रैल 2015	राष्ट्रीय कौशल विकास संगठन

जारी है......

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
55.	खेल के क्षेत्र में कौशल विकास में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन–बो वैली कॉलेज, अलबर्टा कैमोसम कॉलेज, विक्टोरिया और एनएसडीसी) और राष्ट्रीय कौशल विकास संगठन और वैली कॉलेज, अलबर्टा तथा कैमोसम कॉलेजए विक्टोरिया, बी सी. के बीच	**कनाडा**	15 अप्रैल 2015		15 अप्रैल 2015	राष्ट्रीय कौशल विकास संगठन
56.	राष्ट्रीय कौशल विकास संगठन और कॉलेज ऑफ न्यू कैलेडोनियाए प्रिंस जॉर्ज बी सी के बीच हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र के लिए कौशल विकास में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	**कनाडा**	15 अप्रैल 2015		15 अप्रैल 2015	राष्ट्रीय कौशल विकास संगठन
57.	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और सदर्न अलबर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अलबर्टा के बीच हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र के लिए कौशल विकास में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	**कनाडा**	15 अप्रैल 2015		15 अप्रैल 2015	राष्ट्रीय कौशल विकास संगठन
58.	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और डरहम कॉलेज, टोरंटो के बीच मोटर वाहन और कृषि क्षेत्र में कौशल विकास हेतु सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	**कनाडा**	15 अप्रैल 2015		15 अप्रैल 2015	राष्ट्रीय कौशल विकास संगठन
59.	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और फानशेव कॉलेज, लंदन, ओंटारियो के बीच परिधान और कपड़ा क्षेत्र के लिए कौशल विकास में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	**कनाडा**	15 अप्रैल 2015		15 अप्रैल 2015	राष्ट्रीय कौशल विकास संगठन
60.	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कैनाडोर कॉलेजए नोर्थ बे, ओंटारियो के बीच विमानन क्षेत्र – तकनीकी के लिए कौशल विकास में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	**कनाडा**	15 अप्रैल 2015		15 अप्रैल 2015	राष्ट्रीय कौशल विकास संगठन
61.	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और कैमोसन कॉलेजए विक्टोरिया बीसी के बीच स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के लिए कौशल विकास में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	**कनाडा**	15 अप्रैल 2015		15 अप्रैल 2015	राष्ट्रीय कौशल विकास संगठन
62.	**क्षेत्र कौशल** आईटी, दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए समझौता ज्ञापन	**कनाडा**	15 अप्रैल 2015		15 अप्रैल 2015	राष्ट्रीय कौशल विकास संगठन

जारी है.......

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
63.	**क्षेत्र कौशल** ग्रीन जॉब्स के लिए समझौता ज्ञापन	**कनाडा**	15 अप्रैल 2015		15 अप्रैल 2015	राष्ट्रीय कौशल विकास संगठन
64.	कनाडा के कॉलेजों और संस्थानों के साथ कौशल विकास में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	**कनाडा**	15 अप्रैल 2015		15 अप्रैल 2015	राष्ट्रीय कौशल विकास संगठन
65.	यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड और चिली के बीच आजादी पूर्व प्रत्यर्पण संधि	**चिली**	26 जनवरी 1897		28 अप्रैल 2015	गृह मंत्रालय
66.	**2015–2016 के लिए** चिली की कृषि एवं पशुधन सेवा और कृषि एवं भारत के सहकारिता विभाग बीच **द्विपक्षीय तकनीकी सहयोग के लिए कार्य योजना।**	**चिली**	12 जून 2015		12 जून 2015	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
67.	2015–2020 इसरो और चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन (सीएनएसए) के बीच अंतरिक्ष सहयोग की रूपरेखा।	**चीन**	15 मई 2015		15 मई 2015	अंतरिक्ष विभाग
68.	भारत गणराज्य के सूचना और प्रसारण मंत्रालय और चीन के जनवादी गणराज्य के प्रेस, प्रकाशन, रेडियो, फिल्म और टेलीविजन के राज्य प्रशासन के बीच श्रव्य दृश्य सह उत्पादन पर करार	**चीन**	18 सितम्बर 2014	1 मई 2015		सूचना और प्रसारण मंत्रालय
69.	भारत गणराज्य की सरकार और चीन की जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच चेंगडू और चेन्नई में कंसुलेट जनरल की स्थापना और भारत गणराज्य के वाणिज्य महादूतावास के वाणिज्य जिले के विस्तार में जियांग्क्सी प्रांत को गुआंगज़ौ में शामिल करने के लिए प्रोटोकॉल।	**चीन**	15 मई 2015			विदेश मंत्रालय
70.	व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य के उद्यमिता और कौशल विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा चीन की जनवादी गणराज्य के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौता ज्ञापन।	**चीन**	15 मई 2015			कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

जारी है......

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
71.	भारत गणराज्य के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और चीन जनवादी गणराज्य के मानव संसाधनए सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के बीच अहमदाबाद/गांधीनगर गुजरात में महात्मा गांधी राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता संस्थान की स्थापना में सहयोग की कार्य योजना	**चीन**	15 मई 2015			मानव संसाधन विकास मंत्रालय
72.	भारत गणराज्य के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय और चीन जनवादी गणराज्य के वाणिज्य मंत्रालय के बीच व्यापार वार्ता में सहयोग के लिए सलाहकार तंत्र पर समझौता ज्ञापन (एमओयू)	**चीन**	15 मई 2015			वाणिज्य मंत्रालय
73.	भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के अंतरराष्ट्रीय विभाग के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन	**चीन**	15 मई 2015			विदेश मंत्रालय
74.	चीन जनवादी गणराज्य के राष्ट्रीय रेल प्रशासन और भारत गणराज्य के रेल मंत्रालय के बीच रेलवे क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर कार्य योजना (2015.2016)	**चीन**	15 मई 2015			रेल मंत्रालय
75.	भारत गणराज्य के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और चीन जनवादी गणराज्य के शिक्षा मंत्रालय के बीच शिक्षा के क्षेत्र में आदान.प्रदान कार्यक्रम।	**चीन**	15 मई 2015			मानव संसाधन विकास मंत्रालय
76.	भारत गणराज्य के खान मंत्रालय और चीन जनवादी गणराज्य के भूमि और संसाधन मंत्रालय के बीच खनन और खनिज क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	**चीन**	15 मई 2015			खान मंत्रालय
77.	भारत गणराज्य की निर्यात निरीक्षण परिषद, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और चीन जनवादी गणराज्य के गुणवत्ता पर्यवेक्षण, निरीक्षण, संगरोध, सामान्य प्रशासन के बीच भारतीय रेपसीड भोजन के आयात पर स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमन के लिए अंतिम प्रोटोकॉल।	**चीन**	15 मई 2015			वाणिज्य मंत्रालय

जारी है......

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
78.	दूरदर्शन और चीन के केंद्रीय टेलीविजन के बीच प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।	**चीन**	15 मई 2015			सूचना और प्रसारण मंत्रालय
79.	भारत गणराज्य के पर्यटन मंत्रालय और चीन जनवादी गणराज्य के राष्ट्रीय पर्यटन प्रशासन के बीच पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग पर करार	**चीन**	15 मई 2015			पर्यटन मंत्रालय
80.	भारत.चीन थिंक टैंक फोरम की स्थापना पर समझौता ज्ञापन (एमओयू)	**चीन**	15 मई 2015			मानव संसाधन विकास मंत्रालय
81.	भारत सरकार के नीति आयोग और विकास अनुसंधान केंद्रए चीन जनवादी गणराज्य की राज्य परिषद के बीच समझौता ज्ञापन	**चीन**	15 मई 2015			नीति आयोग
82.	भारत गणराज्य के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और चीन जनवादी गणराज्य के चीन भूकंप प्रशासन के बीच भूकंप विज्ञान और भूकंप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सहयोग के विषय में समझौता ज्ञापन	**चीन**	15 मई 2015			पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
83.	भारत गणराज्य के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और चीन जनवादी गणराज्य के राज्य समुद्रीय प्रशासन के बीच महासागर विज्ञान, महासागर प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, ध्रुवीय विज्ञान और हिमांक मंडल के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।	**चीन**	5 मई 2015			विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
84.	भारत गणराज्य के भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय और चीन जनवादी गणराज्य के चीनी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भूमि और संसाधन मंत्रालय के बीच भूविज्ञान में वैज्ञानिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन	**चीन**	15 मई 2015			खान मंत्रालय
85.	विदेश मंत्रालय, भारत गणराज्य और विदेशों के साथ मैत्री के लिए चीनी पीपुल्स एसोसिएशन के बीच राज्य/प्रांतीय नेता मंच की स्थापना पर समझौता ज्ञापन।	**चीन**	15 मई 2015			विदेश मंत्रालय
86.	भारत गणराज्य की कर्नाटक राज्य सरकार और चीन जनवादी गणराज्य के सिचुआन की प्रांतीय सरकार के बीच सिस्टर राज्य/प्रांत संबंधों की स्थापना पर समझौता।	**चीन**	15 मई 2015			विदेश मंत्रालय

जारी है......

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
87.	चेन्नई, भारत गणराज्य और चूंगचींग, चीन जनवादी गणराज्य के बीच सिस्टर सिटी संबंधों की स्थापना पर करार	**चीन**	15 मई 2015			शहरी विकास मंत्रालय
88.	हैदराबाद, भारत गणराज्य और किगडाओ, चीन जनवादी गणराज्य के बीच सिस्टर सिटी संबंधों की स्थापना पर करार	**चीन**	15 मई 2015			शहरी विकास मंत्रालय
89.	औरंगाबाद, भारत गणराज्य और डनहुआंग, चीन जनवादी गणराज्य के बीच सिस्टर सिटी संबंधों की स्थापना पर करार	**चीन**	15 मई 2015			शहरी विकास मंत्रालय
90.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और फूडान विश्वविद्यालय के बीच गांधीवादी और भारतीय अध्ययन के लिए एक केंद्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन	**चीन**	15 मई 2015			संस्कृति मंत्रालय
91.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और युन्नान मिंजु विश्वविद्यालय के बीच एक योग कॉलेज की स्थापना पर समझौता ज्ञापन	**चीन**	15 मई 2015			विदेश मंत्रालय
92.	विदेश सेवा संस्थान, भारत गणराज्य, विदेश मंत्रालय और विदेश सेवा संस्थान (मैनुअल मारिया डी पेराल्टा) कोस्टा रिका गणराज्य के विदेश एवं वर्शिप मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन।	**कोस्टा रिका**	16 मार्च 2015		16 मार्च 2015	विदेश मंत्रालय
93.	भारत गणराज्य और कोस्टा रिका गणराज्य के बीच तकनीकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन।	**कोस्टा रिका**	21 जुलाई 2015			विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
94.	भारत गणराज्य सरकार और क्रोएशिया गणराज्य सरकार के बीच दोहरे कराधान से बचाव और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए समझौता।	**क्रोएशिया**	12 फ़रवरी 2014	12 अगस्त 2014	6 फ़रवरी 2015	वित्त मंत्रालय
95.	क्यूबा गणराज्य सरकार और भारत गणराज्य सरकार के बीच राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकताओं की छूट पर करार	**क्यूबा**	23 मार्च 2015	1 मई 2015	7 जुलाई, 2015	विदेश मंत्रालय
96.	भारत और चेक गणराज्य के बीच आर्थिक सहयोग पर संयुक्त आयोग की 10 वें सत्र के प्रोटोकॉल	**चेक गणतंत्र**	28 जनवरी 2015			वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

जारी है......

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
97.	केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरणए पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत गणराज्य सरकार और प्राग चिड़ियाघर, चेक गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन।	**चेक गणतंत्र**	9 जनवरी 2015			केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, पर्यावरण और वन मंत्रालय
98.	साक्करबॉग चिड़ियाघरए गुजरात और प्राग चिड़ियाघर के बीच समझौता ज्ञापन (सामरिक भागीदारी)।	**चेक गणतंत्र**	12 जनवरी 2015			गुजरात सरकार
99.	भारत के भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय और चेक गणराज्य के व्यापार और उद्योग मंत्रालय के बीच भारी उद्योग क्षेत्र में सहयोग पर प्रोटोकॉल	**चेक गणतंत्र**	24 नवंबर 2015			भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय
100.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयए भारत सरकार और ऊर्जा और खान मंत्रालयए डोमिनिकन गणराज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	**डोमिनिकन गणराज्य**	17 फ़रवरी 2015		17 फ़रवरी 2015	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
101.	इक्वेडोर के साथ समझौता ज्ञापन के प्रावधान के तहत संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति (जेईटीसीओ)	**इक्वेडोर**				
102.	भारत गणराज्य सरकार और मिस्र अरब गणराज्य सरकार के बीच पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	**मिस्र**	24 अगस्त 2015			पर्यटन मंत्रालय
103.	भारत गणराज्य और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र (एनआरसी), मिस्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	**मिस्र**	24 अगस्त 2015			विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
104.	भारत गणराज्य सरकार के नागरिक विमानन मंत्रालय और इथियोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन	**इथियोपिया**	21 अक्टूबर 2015			नागर विमानन मंत्रालय
105.	भारत गणराज्य के नागरिक विमानन मंत्रालय और फिनलैंड की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	**फिनलैंड**	19 अक्टूबर 2015			नागर विमानन मंत्रालय

जारी है......

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
106.	राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) भारतए और राष्ट्रीय व्यावसायिक योग्यता आयोग (कमिशन नेशनल डी ला सर्टिफिकेशन प्रोफेशनल–सीएनसीपी) के बीच कौशल योग्यता के बारे में ज्ञान और सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन	**फ्रांस**				कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
107.	आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान केंद्रए आयुष मंत्रालय और यूनिवर्सिटी डी स्ट्रासबर्ग / यूनिस्ट्रा (फ्रांस) के बीच **आशय पत्र**	**फ्रांस**	9 अप्रैल 2015			आयुष मंत्रालय
108.	एजेंसी फ्रेंकाइस डे डेवलपमेंट (एएफडी) और भारत के बीच हुए गारंटी करार, **एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) का निधिकरण**	**फ्रांस**	9 अप्रैल 2015			विद्युत मंत्रालय
109.	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अरेवा एनपी एसएएसए पेरिसए फ्रांस के बीच महाराष्ट्र, भारत में जैतापुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 2 ईपीआर इकाइयों के निर्माण के लिए डिजाइनए इंजीनियरिंग और नियामक पहलुओं से संबंधित प्री इंजीनियरिंग कार्यों के लिए प्री इंजीनियरिंग करार।	**फ्रांस**	10 अप्रैल 2015			परमाणु ऊर्जा विभाग
110.	भारत गणराज्य के नवीन एवं नवीकरण ीय ऊर्जा मंत्रालय और फ्रांस गणराज्य के पारिस्थितिकीय, सतत विकास और ऊर्जा मंत्रालय के बीच नवीकरणीय ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	**फ्रांस**	10 अप्रैल 2015		10 अप्रैल 2015	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
111.	भारत गणराज्य के रेल मंत्रालय और फ्रांस के राष्ट्रीय रेलवे (एस एन सी एफ) के बीच ''सेमी हाई स्पीड रेल और स्टेशन नवीकरण'' में सहयोग पर प्रोटोकॉल।	**फ्रांस**	10 अप्रैल 2015			रेल मंत्रालय
112.	भारत गणराज्य सरकार के संस्कृति मंत्रालय और फ्रांस गणराज्य के संस्कृति और संचार मंत्रालय के बीच विरासत के क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था	**फ्रांस**	9 अप्रैल 2015		9 अप्रैल 2015	संस्कृति मंत्रालय

जारी है.......

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
113.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग (भारत) और पियरे एट मैरी क्यूरी यूनिवर्सिटी तथा सेंटर नेशनल डे ला रिसर्च साइंटिफिक के बीच भारत में राष्ट्रीय समुद्री जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के एक संस्थान की स्थापना पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन।	**फ्रांस**	10 अप्रैल 2015		10 अप्रैल 2015	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
114.	भारत गणराज्य सरकार और फ्रांस गणराज्य सरकार के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर आशय पत्र।	**फ्रांस**	9 अप्रैल 2015			पर्यटन मंत्रालय
115.	स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली और इकोले सुपिरियर डी श्आर्कीटेक्चर डे पेरिस ला विलेट के बीच समझौता ज्ञापन।	**फ्रांस**	9 अप्रैल 2015		9 अप्रैल 2015	
116.	युवा कार्य और खेल मंत्रालय, भारत गणराज्य और फ्रांसीसी शहरी संसाधनए युवा कार्य और खेल मंत्री के बीच खेल के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन।	**फ्रांस**	9 अप्रैल 2015		9 अप्रैल 2015	युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय
117.	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और इंस्टीट्यूट नेशनल डी रीचर्च आर्कियोलॉजिकल प्रिवेंटिव्स (आईएनआरएपी) के बीच आशय पत्र	**फ्रांस**	9 अप्रैल 2015		9 अप्रैल 2015	संस्कृति मंत्रालय
118.	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और सेंटर नेशनल डी एटुडेस स्पेशिसलेस (सीएनईएस) के बीच उष्णकटिबंधीय वातावरण को समर्पित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के चरण सी/ डी/ ई के बारे में और 'मेघा–ट्रॉपिक" के रूप में संदर्भित समझौता ज्ञापन का अनुशेष	**फ्रांस**	8 अप्रैल 2015			अंतरिक्ष विभाग
119.	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और सेंटर नेशनल डी एटुडेस स्पेशिसलेस के बीच अंतरिक्ष गतिविधियों में प्रबलित सहयोग के लिए कार्यक्रम	**फ्रांस**	10 अप्रैल 2015		10 अप्रैल 2015	अंतरिक्ष विभाग
120.	भारत सरकारए आयुष मंत्रालय की आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद और स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय, फ्रांस के बीच आशय पत्र	**फ्रांस**	9 अप्रैल 2015			आयुष मंत्रालय

जारी है......

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
121.	इसरोए फ्रांसीसी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी (सीएनईएस) और फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर एयरोस्पेस रिसर्च (ओ एन ई आर ए) के बीच भारतीय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में 'का' बैंड प्रचार पर प्रयोग के लिए उनके सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन ।	**फ्रांस**	8 अप्रैल 2015		8 अप्रैल 2015	अंतरिक्ष विभाग
122.	इंडियन हेरिटेज सिटीज़ नेटवर्क फाउंडेशन (आई एच सी एन) एसोसिएशन नेशनल एट विलेस ए स्केटर्स सॉवेगार्डेस (एएनवीपीएएच) के बीच समझौता ज्ञापन	**फ्रांस**	9 अप्रैल 2015			शहरी विकास मंत्रालय
123.	उदयपुर के महल और चेटेउ चैम्बोर्ड के बीच ट्विनिंग व्यवस्था	**फ्रांस**	10 अप्रैल 2015			शहरी विकास मंत्रालय
124.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत और फ्रांस वैज्ञानिक अनुसंधान राष्ट्रीय केंद्र (सी एन आर एस) के बीच के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	**फ्रांस**	10 अप्रैल 2015			विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
125.	परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए पुर्जो के निर्माण के स्थानीकरण के लिए लार्सन एंड टुब्रो और अरेवा के बीच समझौता ज्ञापन	**फ्रांस**	10 अप्रैल 2015			व्यवसायिक अनुबंध
126.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयए भारत गणराज्य और जर्मनी के संघीय गणराज्य के आर्थिक सहयोग और विकास संघीय मंत्रालय के बीच इंडो–जर्मन सौर ऊर्जा भागीदारी के संबंध में भारत–जर्मन विकास सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन।	**जर्मनी**	5 अक्टूबर 2015		5 अक्टूबर 2015	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
127.	जर्मनी की संघीय गणराज्य सरकार भारत गणराज्य सरकार के बीच एक राजनयिक मिशन या कौंसुलर पोस्ट के परिवार के सदस्यों के लिए लाभकारी व्यवसाय पर करार	**जर्मनी**	25 मार्च 2015			विदेश मंत्रालय
128.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), भारत और जर्मन शैक्षणिक विनिमय सेवा (डी ए.ए. डी), जर्मनी के बीच उच्च शिक्षा (आईजीपी) में इंडो–जर्मन भागीदारी पर समझौता ज्ञापन।	**जर्मनी**	5 अक्टूबर 2015		5 अक्टूबर 2015	मानव संसाधन विकास मंत्रालय

जारी है.......

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
129.	भारत सरकार के भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय और फ्रॉनहॉफर जेसेलशाफ्ट जूर फोर्डरबर्ग डेर एंजवेंडटन फोर्शुंग ई वी के बीच इसकी फ्रॉनहॉफर फर सिस्टम अंड इनोवेशन फोर्शुंग (आईएसआई), कार्ल्सरूहे को कानूनी इकाई के रूप में लेकर समझौता ज्ञापन।	**जर्मनी**	5 अक्टूबर 2015		5 अक्टूबर 2015	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय
130.	भारत में जर्मन कंपनियों के लिए एक फास्ट ट्रैक प्रणाली की स्थापना पर संयुक्त घोषणा।	**जर्मनी**	5 अक्टूबर 2015			
131.	भारत गणराज्य के रेल मंत्रालय और जर्मनी संघीय गणराज्य के परिवहन और डिजिटल मूलसंरचना संघीय मंत्रालय के बीच रेलवे के क्षेत्र में सहयोग के आगे विकास पर आशय का संयुक्त घोषणा।	**जर्मनी**	5 अक्टूबर 2015		5 अक्टूबर 2015	रेल मंत्रालय
132.	एक ओर भारत गणराज्य के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और दूसरी ओर, जर्मनी गणराज्य के शिक्षा और अनुसंधान संघीय मंत्रालय और आर्थिक सहयोग और विकास संघीय मंत्रालय के बीच कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त समझौता ज्ञापन।	**जर्मनी**	5 अक्टूबर 2015		5 अक्टूबर 2015	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
133.	भारत गणराज्य के गृह मंत्रालय और जर्मनी के संघीय गणराज्य के संघीय गृह मंत्रालय के बीच सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन।	**जर्मनी**	5 अक्टूबर 2015		5 अक्टूबर 2015	गृह मंत्रालय
134.	भारत गणराज्य के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और जर्मनी के संघीय गणराज्य के संघीय विदेश कार्यालय के बीच भारत में एक विदेशी भाषा के रूप में जर्मन भाषा के संवर्धन तथा जर्मनी में आधुनिक भारतीय भाषाओं के संवर्धन के बारे में आशय का संयुक्त घोषणा।	**जर्मनी**	5 अक्टूबर 2015		5 अक्टूबर 2015	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
135.	भारत सरकार और जर्मनी संघीय गणराज्य सरकार के बीच नई दिल्ली में 28.29 सितम्बर 2015 को आयोजित विकास सहयोग पर वार्ता का सारांश रिकार्ड।	**जर्मनी**	5 अक्टूबर 2015			

जारी है......

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
136.	भारत गणराज्य के नागरिक विमानन मंत्रालय तथा जर्मनी के संघीय गणराज्य के संघीय गृह मंत्रालय के बीच उड़ान सुरक्षा अधिकारियों के वाहन पर समझौता ज्ञापन।	**जर्मनी**	5 अक्टूबर 2015		5 अक्टूबर 2015	नागर विमानन मंत्रालय
137.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (भारत गणराज्य सरकार) और संघीय शिक्षा अनुसंधान मंत्रालय (जर्मनी संघीय गणराज्य सरकार) के बीच पर इंडो–जर्मन विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र (आईजीएसटीसी) के कार्यकाल के विस्तार पर संयुक्त घोषणा	**जर्मनी**	5 अक्टूबर 2015			विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
138.	भारत गणराज्य के गृह मंत्रालय और जर्मनी संघीय गणराज्य के संघीय गृह मंत्रालय के बीच आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर आशय की संयुक्त घोषणा।	**जर्मनी**	5 अक्टूबर 2015		5 अक्टूबर 2015	गृह मंत्रालय
139.	जर्मनी संघीय गणराज्य के आर्थिक सहयोग और विकास संघीय मंत्रालय और भारत गणराज्य के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच इंडो.जर्मन सौर ऊर्जा भागीदारी के संबंध में भारत.जर्मन विकास सहयोग पर आशय पत्र	**जर्मनी**	14 अप्रैल 2015		14 अप्रैल 2015	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)
140.	भारत गणराज्य के शहरी विकास मंत्रालय और जर्मनी के संघीय गणराज्य के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण भवन परमाणु सुरक्षा संघीय मंत्रालय के बीच स्थायी शहरीविकास के क्षेत्र में सहयोग पर आशय का संयुक्त घोषणा।	**जर्मनी**	16 अप्रैल 2016		16 अप्रैल 2016	शहरी विकास मंत्रालय (शहरी विविकास मंत्रालय)
141.	भारत गणराज्य के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और जर्मनी के संघीय गणराज्य के आर्थिक सहयोग और विकास संघीय मंत्रालय के बीच इंडो–जर्मन कौशल विकास परियोजना के बारे में इंडो–जर्मन विकास सहयोग पर आशय पत्र	**जर्मनी**	16 अप्रैल 2016		16 अप्रैल 2016	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
142.	जर्मनी संघीय गणराज्य सरकार और भारत गणराज्य सरकार के बीच भारत के कॉर्पोरेट कार्यपालकों और कनिष्ठ कार्यपालकों के उन्नत प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग को जारी रखने पर संयुक्त घोषणा।	**जर्मनी**	5 अक्टूबर 2015		5 अक्टूबर 2015	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

जारी है.....

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
143.	जोखिम मूल्यांकन संघीय संस्थान (एफआईआरए) और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के बीच खाद्य सुरक्षा में सहयोग पर आशय का संयुक्त वक्तव्य ।	**जर्मनी**	5 अक्टूबर 2015		5 अक्टूबर 2015	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
144.	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और उपभोक्ता संरक्षण और खाद्य सुरक्षा संघीय कार्यालय (बीवीएल) के बीच खाद्य सुरक्षा में सहयोग पर आशय का संयुक्त वक्तव्य	**जर्मनी**	5 अक्टूबर 2015		5 अक्टूबर 2015	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
145.	जर्मन एग्रीबिजनेस एलायंस और भारतीय कृषि कौशल परिषद (एएससीआई) के बीच कृषि अध्ययन में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।	**जर्मनी**	5 अक्टूबर 2015		5 अक्टूबर 2015	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
146.	भारत सरकार के कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण (एमओए और परिवार कल्याण) और जर्मनी के संघीय गणराज्य के उपभोक्ता संरक्षण और खाद्य सुरक्षा संघीय कार्यालय (बीवीएल) के बीच पौध संरक्षण उत्पादों पर आशय की संयुक्त घोषणा।	**जर्मनी**	5 अक्टूबर 2015		5 अक्टूबर 2015	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओए और परिवार कल्याण)
147.	भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालयए भारत सरकार और फ्राउनहोफर सोसायटी, जर्मनी के बीच विनिर्माण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।	**जर्मनी**	5 अक्टूबर 2015		5 अक्टूबर 2015	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय
148.	हेल्म्होल्ट्ज़ एसोसिएशन, जर्मनी और भारत गणराज्य के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, . पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन के बीच पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	**जर्मनी**	7 अप्रैल 2015		7 अप्रैल 2015	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
149.	भारत गणराज्य सरकार और ग्वाटेमाला गणराज्य सरकार के बीच राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की आवश्यकता से छूट पर करार	**ग्वाटेमाला**	28 मई 2015		9 अक्टूबर 2015	विदेश मंत्रालय
150.	सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण पर भारत गणराज्य सरकार और गवर्नमेंट ऑफ़ द होन्ग कोंग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ़ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ़ चीन के बीच करार।	**हॉन्गकॉन्ग**	20 जनवरी 2015		11 मार्च 2015	गृह मंत्रालय

जारी है.....

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
151.	इंडोनेशिया गणराज्य सरकार और भारत गणराज्य सरकार के बीच नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पर समझौता ज्ञापन।	**इंडोनेशिया**	14 मार्च 2015		14 मार्च 2015	विदेश मंत्रालय
152.	भारत गणराज्य के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा इंडोनेशिया गणराज्य के ऊर्जा एवं खनिज संसाधन मंत्रालय के बीच नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग पर समझौता ज्ञापन	**इंडोनेशिया**	2 नवंबर 2015		2 नवंबर 2015	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
153.	भारत गणराज्य सरकार और इंडोनेशिया गणराज्य सरकार के बीच संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन ।	**इंडोनेशिया**	2 नवंबर 2015		2 नवंबर 2015	संस्कृति मंत्रालय
154.	आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत गणराज्य सरकार और उडयन विश्वविद्यालय, बाली के बीच आयुर्वेद में एक शैक्षिक पीठ की स्थापना पर समझौता ज्ञापन।	**इंडोनेशिया**	4 नवंबर 2015		4 नवंबर 2015	आयुष मंत्रालय
155.	आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर टिप्पणियां का आदान प्रदान।	**इंडोनेशिया**	25 जनवरी 2011		3 अप्रैल 2014	गृह मंत्रालय
156.	प्रत्यर्पण संधि का आदान प्रदान।	**इंडोनेशिया**	25 जनवरी 2011			गृह मंत्रालय
157.	भारत गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय तथा इंडोनेशिया गणराज्य के शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के बीच वर्ष 2015.2018 के लिए सांस्कृतिक आदान.प्रदान कार्यक्रम के विषय में समझौता	**इंडोनेशिया**	2 नवंबर 2015		2 नवंबर 2015	संस्कृति मंत्रालय
158.	ईरान इस्लामी गणराज्य सरकार तथा भारत गणराज्य सरकार के बीच वीजा जारी करने की सुविधा प्रदान करने के लिए करार	**ईरान**	18 दिसंबर 2015	8 जनवरीए 2016		विदेश मंत्रालय
159.	भारत गणराज्य सरकार तथा ईरान इस्लामी गणराज्य सरकार के बीच चाबहार बंदरगाह के विकास की योजना में भारत की भागीदारी पर 6 मई 2015 को ऑर्डीबेहेस्ट 16, 1394 के अनुरूप समझौता ज्ञापन	**ईरान**	6 मई 2015			जहाजरानी मंत्रालय

जारी है.....

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
160.	भारत गणराज्य सरकार और इसराइल राष्ट्र सरकार के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर संधि	**इसराइल**	27 फ़रवरी 2014	25 अप्रैल 2014	1 मार्च 2015	गृह मंत्रालय
161.	भारत गणराज्य और इसराइल राष्ट्र के बीच आय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचाव और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए प्रोटोकॉल और अभिसमय में संशोधन पर प्रोटोकॉल	**इजराइल**	14 अक्टूबर 2015			वित्त मंत्रालय
162.	भारत गणराज्य सरकार तथा इसराइल राज्य सरकार के बीच वर्ष **2015.2018** के लिए सांस्कृतिक आदान.प्रदान कार्यक्रम	**इजराइल**	16 अक्टूबर 2015			संस्कृति मंत्रालय
163.	भारत के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय के बीच सूचना प्रौद्योगिकी सहयोग पर संयुक्त वक्तव्य	**जापान**	30 अप्रैल 2015			संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
164.	भारत गणराज्य सरकार और जापान सरकार के बीच रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के विषय में करार।	**जापान**	12 दिसंबर 2015		1 जनवरी 2016	रक्षा मंत्रालय
165.	भारत.प्रशांत क्षेत्र और दुनिया की शांति और समृद्धि के लिए मिलकर कार्य करने के लिए भारत और जापान विशेष सामरिक और वैश्विक भागीदारी।	**जापान**	12 दिसंबर 2015			
166.	भारत गणराज्य सरकार और जापान सरकार के बीच वर्गीकृत सैन्य जानकारी के संरक्षण के लिए सुरक्षा उपायों के विषय करार।	**जापान**	12 दिसंबर 2015		12 दिसंबर 2015	रक्षा मंत्रालय
167.	भारत गणराज्य सरकार और जापान की सरकार के बीच हाई स्पीड रेल पर सहयोग ज्ञापन	**जापान**	12 दिसंबर 2015			रेल मंत्रालय
168.	भारत गणराज्य सरकार और जापान की सरकार के बीच परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए करार के संबंध में ज्ञापन	**जापान**	12 दिसंबर 2015			परमाणु ऊर्जा विभाग

जारी है.....

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
169.	भारत गणराज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन और जापान के स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय के बीच चिकित्सा उत्पाद नियमन वार्ता तथा सहयोग रूपरेखा पर सहयोग ज्ञापन।	**जापान**	11 दिसंबर 2015		11 दिसंबर 2015	स्वास्थ्य मंत्रालय
170.	भारत गणराज्य सरकार और जापान की सरकार के बीच आय पर दोहरे कराधान से बचाव और करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए करार।	**जापान**	11 दिसंबर 2015			वित्त मंत्रालय
171.	नेशनल ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट फॉर पालिसी स्टडीज (ग्रिप), जापान और भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद (आईआईएम.ए), भारत के बीच शैक्षिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	**जापान**	9 दिसंबर 2015		9 दिसंबर 2015	
172.	भारत गणराज्य के रेल मंत्रालय और जापान के भूमि, मूलसंरचना, परिवहन और पर्यटन मंत्रालय के बीच रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर सहयोग ज्ञापन।	**जापान**	11 दिसंबर 2015		11 दिसंबर 2015	रेल मंत्रालय
173.	भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और जापान के कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन मंत्रालय के बीच वन और वानिकी क्षेत्र में सहयोग ज्ञापन	**जापान**	11 दिसंबर 2015		11 दिसंबर 2015	पर्यावरणए वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
174.	अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठनए भारत और जापान के रेलवे तकनीकी अनुसंधान संस्थान के बीच तकनीकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन	**जापान**	9 दिसंबर 2015		9 दिसंबर 2015	अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन
175.	आपसी समझ और सहकारी आधार पर ऊर्जा के क्षेत्र से संबंधित मुद्दों के विश्लेषण के लिए आशय का वक्तव्य	**जापान**	9 दिसंबर 2015		9 दिसंबर 2015	
176.	जापान की विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के बीच सामरिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम का आशय पत्र	**जापान**	11 दिसंबर 2015			विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
177.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागए भारत सरकार और जापान सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ़ साइंस के बीच एक युवा शोधकर्ता फैलोशिप प्रोग्राम स्थापित करने के लिए आशय पत्र।	**जापान**	11 दिसंबर 2015			विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

जारी है.....

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
178.	मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, भारत गणराज्य और जापान के शिक्षा, संस्कृति, खेलए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग ज्ञापन।	**जापान**	अक्टूबर 2015			मानव संसाधन और विकास मंत्रालय
179.	ग्रीन जॉब्स के लिए समझौता ज्ञापन पर क्षेत्र कौशल	**जॉर्डन**	11 अक्टूबर 2015			
180.	प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) और जॉर्डन समाचार एजेंसी (पेट्रा) के बीच समाचार के आदान–प्रदान पर सहयोग समझौता।	**जॉर्डन**	11 अक्टूबर 2015		11 अक्टूबर 2015	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
181.	भारत गणराज्य सरकार और जॉर्डन के हैशेमाइट किंगडम के बीच समुद्री परिवहन पर करार	**जॉर्डन**	11 अक्टूबर 2015			जहाजरानी मंत्रालय
182.	विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई), विदेश मंत्रालय, भारत गणराज्य और जॉर्डन इंस्टीट्यूट ऑफ़ डिप्लोमेसी (जेआईडी), विदेश मंत्रालय और जॉर्डन के हैशेमाइट किंगडम के प्रवासियों के बीच समझौता ज्ञापन	**जॉर्डन**	11 अक्टूबर 2015			विदेश मंत्रालय
183.	भारत गणराज्य के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और जॉर्डन के हैशेमाइट किंगडम के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग पर और समझौता ज्ञापन	**जॉर्डन**	11 अक्टूबर 2015		11 अक्टूबर 2015	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
184.	2015.17 के लिए सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम	**जॉर्डन**	11 अक्टूबर 2015			संस्कृति मंत्रालय
185.	भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और जॉर्डन स्टेंडर्ड एंड मेट्रोलोजी ऑर्गनाइजेशन (जेएसएसएमओ) के बीच मानकीकरण और अनुरूपता आकलन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	**जॉर्डन**	11 अक्टूबर 2015			भारतीय मानक ब्यूरो
186.	प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) और जॉर्डन समाचार एजेंसी (पेट्रा) के बीच समाचार के आदान प्रदान पर सहयोग समझौता।	**जॉर्डन**	11 अक्टूबर 2015		11 अक्टूबर 2015	सूचना और प्रसारण मंत्रालय

जारी है.....

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
187.	सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण पर भारत गणराज्य की सरकार और कजाकिस्तान गणतंत्र के बीच करार	**कजाखस्तान**	8 जुलाई 2015	10 अक्टूबर 2015		गृह मंत्रालय
188.	कजाकिस्तान गणराज्य सरकार और भारत गणराज्य सरकार के बीच रक्षा और सेना के तकनीकी सहयोग पर समझौता।	**कजाखस्तान**	8 जुलाई 2015	29 अक्टूबर 2015		रक्षा मंत्रालय
189.	वर्ष 2016.2017 के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), और काजाग्रोइनोवेशन्स जेएससी (केएआई), कजाखस्तान के बीच कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य योजना	**कज़ाकस्तान**	7 जुलाई 2015		7 जुलाई 2015	कृषि मंत्रालय
190.	भारत गणराज्य के रेल मंत्रालय और कज़ाकस्तान तेमिर जोली के बीच रेलवे के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन।	**कज़ाकस्तान**	8 जुलाई 2015		8 जुलाई 2015	रेल मंत्रालय
191.	युवा कार्य और खेल मंत्रालय, भारत गणराज्य और कजाखस्तान गणराज्य के संस्कृति और खेल मंत्रालय के बीच भौतिक संस्कृति और खेल के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।	**कजाखस्तान**	8 जुलाई 2015		8 जुलाई 2015	युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय
192.	भारत गणराज्य के नागरिक विमानन मंत्रालय और कजाकिस्तान की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	**कज़ाकस्तान**	19 अक्टूबर 2015			नागर विमानन मंत्रालय
193.	एलएलपी "कज़ाक्ड उपयोगिता प्रणाली" और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन	**कज़ाकस्तान**	7 जुलाई 2015		7 जुलाईए 2015	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)
194.	राष्ट्रीय निर्यात और निवेश एजेंसी "काजनेक्स इंवेट्स" जेएससी और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन	**कज़ाकस्तान**	7 जुलाई 2015		7 जुलाईए 2015	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)
195.	राष्ट्रीय निर्यात और निवेश एजेंसी "काजनेक्स इंवेस्ट" जेएससी और इनवेस्ट इंडिया" के बीच समझौता ज्ञापन।	**कज़ाकस्तान**	7 जुलाई 2015		7 जुलाई 2015	डीआईपीपी
196.	व्यापारए आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत–कजाकिस्तान अंतर सरकारी आयोग की 12 वीं बैठक के प्रोटोकॉल	**कज़ाकस्तान**	7 जुलाईए 2015			पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

जारी है.....

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
197.	भारत गणराज्य के नागरिक विमानन मंत्रालय और केन्या की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	**केन्या**	19 अक्टूबर 2015			नागर विमानन मंत्रालय
198.	भारत गणराज्य की सरकार और कोरिया गणराज्य की सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम से बचाव के लिए करार	**कोरिया**	18 मई 2015	22 जून 2015		वित्त मंत्रालय
199.	भारत गणराज्य सरकार और कोरिया गणराज्य की सरकार के बीच श्रव्य दृश्य सह.उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग पर करार	**कोरिया**	18 मई 2015	22 जून 2015		सूचना और प्रसारण मंत्रालय
200.	भारत गणराज्य की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कोरिया गणराज्य की राष्ट्रीय सुरक्षा के कार्यालय के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	**कोरिया**	18 मई 2015			गृह मंत्राल
201.	भारत गणराज्य के विद्युत मंत्रालय और कोरिया गणराज्य के व्यापार] उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय के बीच **इलेक्ट्रिक विद्युत विकास और नए ऊर्जा उद्योगों के क्षेत्र में सहयोग** के संबंध में समझौता ज्ञापन	**कोरिया**	18 मई 2015			विद्युत मंत्रालय
202.	भारत गणराज्य के युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय और कोरिया गणराज्य के लैंगिक समानता और परिवार मंत्रालय के बीच **युवा कार्यों में सहयोग** पर समझौता ज्ञापन	**कोरिया**	18 मई 2015			युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय
203.	भारत गणराज्य के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा कोरिया गणराज्य के भूमि, मूलसंरचना और परिवहन मंत्रालय के बीच **सड़क परिवहन और राजमार्ग के क्षेत्र में सहयोग की रूपरेखा**	**कोरिया**	18 मई 2015			सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
204.	भारत गणराज्य के जहाजरानी मंत्रालय तथा कोरिया गणराज्य के महासागर और मत्स्य मंत्रालय के बीच **समुद्री परिवहन और रसद** के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	**कोरिया**	18 मई 2015			जहाजरानी मंत्रालय

जारी है.....

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
206.	भारत गणराज्य के केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड तथा कोरिया गणराज्य के कोरिया सीमा शुल्क सेवा के बीच संबंधित अधिकृत आर्थिक प्रचालन कार्यक्रम के आपसी मान्यता से संबंधित व्यवस्था।	**कोरिया**	8 अक्टूबर 2015		8 अक्टूबर 2015	वित्त मंत्रालय
207.	भारत गणराज्य सरकार और किर्गिज गणराज्य सरकार के बीच रक्षा सहयोग पर करार	**किर्गिज गणराज्य**	12 जुलाई 2015	29 अक्टूबर 2015		रक्षा मंत्रालय
208.	भारतीय निर्वाचन आयोग तथा किर्गिज गणराज्य के केन्द्रीय निर्वाचन और जनमत संग्रह आयोग के बीच **चुनाव के क्षेत्र में** आपसी समझ और सहयोग पर समझौता ज्ञापन।	**किर्गिज गणराज्य**	12 जुलाई 2015		12 जुलाई 2015	निर्वाचन आयोग
209.	भारत गणराज्य सरकार तथा किर्गिज गणराज्य सरकार के बीच **संस्कृति, कला, युवा, खेल और मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग** पर करार।	**किर्गिज गणराज्य**	12 जुलाई 2015		12 जुलाई 2015	युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय
210.	भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) तथा किर्गिज गणराज्य के अर्थव्यवस्था मंत्रालय (मानवीकरण और माप विज्ञान / सीएसएम केन्द्र) के बीच समझौता ज्ञापन।	**किर्गिज गणराज्य**	12 जुलाई 2015		12 जुलाई 2015	उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
211.	**किर्गिज गणराज्य के साथ वस्त्र, कपड़े और फैशन उद्योग के क्षेत्र में सहयोग पर** समझौता ज्ञापन।	**किर्गिज गणराज्य**	17 मार्च 2015		17 मार्च 2015	वस्त्र मंत्रालय
212.	**व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग** पर भारत–किर्गिज़स्तान अंतर सरकारी आयोग के 7 वें सत्र का प्रोटोकॉल	**किर्गिज गणराज्य**	17 मार्च 2015		17 मार्च 2015	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
213.	भारत गणराज्य के वस्त्र मंत्रालय तथा किर्गिज गणराज्य के ऊर्जा और उद्योग मंत्रालय के बीच **वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में** सहयोग पर समझौता ज्ञापन।	**किर्गिज गणराज्य**	17 मार्च 2015	3 सितंबर 2015		वस्त्र मंत्रालय
214.	किर्गिज गणराज्य के ऊर्जा और उद्योग मंत्रालय तथा बीएचईएल कंपनी के बीच **जल विद्युत के क्षेत्र में सहयोग** पर समझौता ज्ञापन	**किर्गिज गणराज्य**	17 मार्च 2015		17 मार्च 2015	बीएचईएल

जारी है.....

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
215.	भारत गणराज्य सरकार और लाओ पीडीआर के बीच **त्वरित प्रभाव परियोजनाओं (क्यूआईपी) केकार्यान्वयन के लिए भारतीय अनुदान सहायता** पर करार	**लाओ पीडीआर**	18 सितंबर 2015		18 सितंबर 2015	विदेश मंत्रालय
216.	2015–2020 की अवधि के लिए भारत गणराज्य सरकार और मलेशिया सरकार के बीच **सांस्कृतिक आदान–प्रदान** कार्यक्रम।	**मलेशिया**	23 नवंबर 2015		23 नवंबर 2015	संस्कृति मंत्रालय
217.	भारत गणराज्य सरकार तथा मलेशिया सरकार के बीच **निष्पादन प्रबंधन, परियोजना वितरण और सरकार के कार्यक्रमों से संबंधित निगरानी और वितरण के क्षेत्र में सहयोग** पर समझौता ज्ञापन।	**मलेशिया**	23 नवंबर 2015		23 नवंबर 2015	
218.	विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय, भारत गणराज्य तथा मालदीव विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय, मालदीव गणराज्य की सरकार के बीच **आपसी सहयोग** पर समझौता ज्ञापन।	**मालदीव**	11 अक्टूबर 2015		11 अक्टूबर 2015	विदेश मंत्रालय
219.	भारत गणराज्य सरकार के युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय तथा मालदीव गणराज्य के युवा एवं खेल मंत्रालय के बीच **खेल एवं युवा कार्य में सहयोग पर** समझौता ज्ञापन	**मालदीव**	11 अक्टूबर 2015		11 अक्टूबर 2015	युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय
220.	वर्ष 2015–2018 के लिए भारत गणराज्य सरकार तथा मॉरीशस गणराज्य सरकार के बीच **सांस्कृतिक सहयोग के लिए कार्यक्रम**	**मॉरीशस**	11 मार्च 2015		11 मार्च 2015	संस्कृति मंत्रालय
221.	भारत गणराज्य सरकार तथा मॉरीशस गणराज्य सरकार के बीच **चिकित्सा और होम्योपैथी की पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग** पर समझौता ज्ञापन	**मॉरीशस**	11 मार्च 2015		11 मार्च 2015	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
222.	भारत गणराज्य सरकार तथा मॉरीशस गणराज्य सरकार के बीच **महासागर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग** पर समझौता ज्ञापन	**मॉरीशस**	11 मार्च 2015		11 मार्च 2015	वाणिज्य मंत्रालय

जारी है......

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
223.	भारत गणराज्य के कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय तथा मॉरीशस गणराज्य के कृषि उद्योग और खाद्य सुरक्षा मंत्रालय के बीच **भारत की ओर से ताजा आमों के आयात** के लिए प्रोटोकॉल	**मॉरीशस**	11 मार्च 2015		11 मार्च 2015	कृषि मंत्रालय
224.	**मॉरीशस के अगलेगा द्वीप पर समुद्र और वायु परिवहन सुविधाओं में सुधार के लिए** समझौता ज्ञापन।	**मॉरीशस**	11 मार्च 2015		11 मार्च 2015	विदेश मंत्रालय
225.	भारत गणराज्य सरकार और मंगोलिया सरकार के बीच **सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण** पर संधि	**मंगोलिया**	17 मई 2015	14 जुलाई 2015		गृह मंत्रालय
226.	भारत गणराज्य सरकार और मंगोलिया सरकार के बीच **वायु सेवा करार।**	**मंगोलिया**	17 मई 2015			नागरिक विमानन मंत्रालय
227.	भारत गणराज्य सरकार और मंगोलिया सरकार के बीच **पशु स्वास्थ्य और डेयरी के क्षेत्र में सहयोग** पर करार।	**मंगोलिया**	17 मई 2015			कृषि मंत्रालय
228.	भारत गणराज्य सरकार तथा मंगोलिया सरकार के बीच **चिकित्सा और होम्योपैथी की पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग** पर समझौता ज्ञापन	**मंगोलिया**	17 मई 2015			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
229.	भारत गणराज्य सरकार तथा मंगोलिया सरकार के बीच **मंगोलिया के रक्षा मंत्रालय में साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना** पर समझौता ज्ञापन	**मंगोलिया**	17 मई 2015			संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
230.	भारत गणराज्य सरकार तथा मंगोलिया सरकार के बीच **मंगोलिया में भारत–मंगोलिया मैत्री माध्यमिक विद्यालय की स्थापना** पर समझौता ज्ञापन	**मंगोलिया**	17 मई 2015			मानव संसाधन विकास मंत्रालय
231.	भारत गणराज्य सरकार तथा मंगोलिया सरकार के बीच **वर्ष 2015–2018 के लिए संस्कृति के क्षेत्र** में सहयोग पर सहयोग कार्यक्रम	**मंगोलिया**	17 मई 2015			संस्कृति मंत्रालय
232.	भारत गणराज्य की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद तथा मंगोलिया के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बीच **सहयोग के लिए** समझौता ज्ञापन	**मंगोलिया**	17 मई 2015			गृह मंत्रालय

जारी है.......

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
233.	भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय तथा मंगोलिया के विदेश मंत्रालय के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन	**मंगोलिया**	17 मई 2015			विदेश मंत्रालय
234.	भारत गणराज्य के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा मंगोलिया सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के बीच **नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग** पर समझौता ज्ञापन	**मंगोलिया**	17 मई 2015			नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
235.	भारत गणराज्य के गृह मंत्रालय तथा मंगोलिया के विधि मंत्रालय के बीच **सीमा चौकसी**, **पुलिस और निगरानी में सहयोग बढ़ाने के लिए** समझौता ज्ञापन	**मंगोलिया**	17 मई 2015			गृह मंत्रालय
236.	भारत के टाटा मेमोरियल सेंटर तथा मंगोलिया के नेशनल कैंसर सेंटर के बीच **रेडियोथेरेपी सिम्युलेटर सहित भाभाट्रोन –।। टेलीकोबॉल्ट यूनिट को उपहार देने** के लिए समझौता ज्ञापन	**मंगोलिया**	17 मई 2015			परमाणु ऊर्जा विभाग
237.	भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थान तथा मंगोलिया के विदेश मंत्रालय की राजनयिक अकादमी के बीच समझौता ज्ञापन	**मंगोलिया**	17 मई 2015			विदेश मंत्रालय
238.	भारत गणराज्य सरकार तथा मोरक्को की शाही सरकार के बीच **राजनयिक, आधिकारिक और सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की आवश्यकता से छूट के** करार पर हस्ताक्षर	**मोरक्को**	17 नवंबर 2015	17 दिसंबर 2015	21 जनवरी 2016	विदेश मंत्रालय
239.	फिक्की और सीजीईएम (मोरक्को का उद्यम महा परिसंघ) के बीच विस्तार और प्रगाढ़ आर्थिक, व्यापार और निवेश सहयोग से वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए समझौता ज्ञापन	**मोरक्को**				
240.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार तथा मोजाम्बिक गणराज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन।	**मोजाम्बिक**	5 अगस्त 2015		5 अगस्त 2015	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
241.	भारत गणराज्य सरकार तथा मोजाम्बिक गणराज्य सरकार के बीच **राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की आवश्यकता** से छूट पर करार।	**मोजाम्बिक**	7 अगस्त 2015	16 दिसंबर 2015		विदेश मंत्रालय

जारी है.......

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
242.	सॉफ्टवेयर विकास और प्रशिक्षण में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना पर समझौता ज्ञापन।	**म्यांमार**	6 अगस्त 2015		6 अगस्त 2015	विदेश मंत्रालय
243.	नेपाल अकादमी ऑफ फाइन आर्टस (एनएएफए) और ललित कला अकादमी, भारत के बीच समझौता ज्ञापन	**नेपाल**	23 अप्रैल 2015		23 अप्रैल 2015	संस्कृति मंत्रालय
244.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (भारत) तथा वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्रालय (नेपाल) के बीच **पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन** पर समझौता ज्ञापन	**नेपाल**	24 अगस्त 2015		24 अगस्त 2015	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
245.	त्रिभुवन यूनिवर्सिटी तथा साउथ एशिया यूनिवर्सिटी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए	**नेपाल**	22 जुलाई 2015		22 जुलाई 2015	मानव संसाधान और विकास मंत्रालय
246.	भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार तथा नीदरलैंड की शाही सरकार के आर्थिक कार्य मंत्रालय के बीच **इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर** सहयोग के संयुक्त कार्यक्रम	**नीदरलैंड**	5 जून 2015			भारी उद्योग विभाग
247.	भारत गणराज्य के नागरिक विमानन मंत्रालय तथा न्यूजीलैंड सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	**न्यूजीलैंड**	26 मई 2015			नागरिक विमानन मंत्रालय
248.	भारत गणराज्य सरकार तथा न्यूजीलैंड सरकार के बीच हवाई सेवा करार	**न्यूजीलैंड**	26 मई 2015			नागरिक विमानन मंत्रालय
249.	भारत गणराज्य सरकार तथा नॉर्वे की शाही सरकार के बीच **राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की आवश्यकता की छूट** पर करार	**नॉर्वे**	14 अक्टूबर 2014		7 फरवरी 2015	विदेश मंत्रालय
250.	भारत गणराज्य तथा नॉर्वे की शाही सरकार के बीच **सामाजिक सुरक्षा पर** करार	**नॉर्वे**	29 अक्टूबर 2010	1 फरवरी 2011	1 जनवरी 2015	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
251.	भारत गणराज्य सरकार तथा नार्वे, डेनमार्क और स्वीडन की शाही सरकार के बीच **हवाई सेवा** पर समझौता ज्ञापन	**नॉर्वे**	20 अक्टूबर 2015			नागरिक विमानन मंत्रालय
252.	भारत गणराज्य सरकार तथा ओमान के सल्तनत सरकार के बीच **आपराधिक मामलों पर कानूनी और न्यायिक सहयोग** पर करार।	**ओमान**	29 अक्टूबर 2014	28 नवंबर 2014	23 मार्च 2015	गृह मंत्रालय

जारी है......

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
253.	भारत गणराज्य के नागरिक विमानन मंत्रालय तथा ओमान सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	**ओमान**	20 अक्टूबर 2015			नागरिक विमानन मंत्रालय
254.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) तथा संस्कृति मंत्रालय, फिलिस्तीन राज्य के बीच समझौता ज्ञापन	**फिलिस्तीन**	12 अक्टूबर 2015	12 अक्टूबर 2015		संस्कृति मंत्रालय
255.	भारत गणराज्य सरकार तथा फिलीपींस गणराज्य सरकार के बीच वर्ष 2016–2018 के लिए **सांस्कृतिक आदान–प्रदान के कार्यकारी कार्यक्रम।**	**फिलिस्तीन**	14 अक्टूबर 2015		14 अक्टूबर 2015	संस्कृति मंत्रालय
256.	भारत गणराज्य सरकार तथा फिलीपींस की सरकार के बीच **प्रत्यर्पण संधि**	**फिलिस्तीन**	12 मार्च 2014	3 मई 2004	14 अक्टूबर 2015	विदेश मंत्रालय
257.	भारत गणराज्य सरकार तथा पोलैंड गणराज्य की सरकार के बीच **राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की आवश्यकता से छूट** पर करार	**पोलैंड**	5 अक्टूबर 2015	23 अक्टूबर 2015	7 दिसंबर 2015	विदेश मंत्रालय
258.	भारत और पुर्तगाल के बीच नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में समझौता ज्ञापन।	**पुर्तगाल**	9 अक्टूबर 2015		9 अक्टूबर 2015	विदेश मंत्रालय
259.	भारत गणराज्य सरकार तथा कतर की राज्य सरकार के बीच **सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण** पर करार।	**कतर**	25 मार्च 2015	09 अक्टूबर 2015		गृह मंत्रालय
260.	कतर नागरिक विमानन प्राधिकरण, परिवहन मंत्रालय, कतर राज्य तथा पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत गणराज्य के बीच **वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग** के लिए समझौता ज्ञापन।	**कतर**	25 मार्च 2015	10 नवंबर 2015		मौसम विज्ञान विभाग
261.	भारत गणराज्य के विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय तथा कतर राज्य के राजनयिक संस्थान, विदेश मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन।	**कतर**	25 मार्च 2015			विदेश मंत्रालय
262.	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत गणराज्य तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कतर राज्य के बीच **सूचना संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर** समझौता ज्ञापन।	**कतर**	25 मार्च 2015			संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

जारी है.......

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
263.	कतर राज्य सरकार तथा भारत गणराज्य सरकार के बीच **रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में सहयोग के लिए** समझौता ज्ञापन	**कतर**	25 मार्च 2015			सूचना और प्रसारण मंत्रालय
264.	कतर न्यूज एजेंसी तथा यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के बीच **आपसी सहयोग और समाचार के आदान प्रदान** के लिए करार	**कतर**	25 मार्च 2015			सूचना और प्रसारण मंत्रालय
265.	भारत गणराज्य और रूस के बीच **सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण** पर संधि	**रूस**	21 अक्टूबर 2013	1 जनवरी 2014	21 मार्च 2015	गृह मंत्रालय
266.	इसरो और रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी (आरओएससीओएसएमओएस) के बीच **बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अन्वेषण और उपयोग के क्षेत्र में सहयोग के विस्तार** पर समझौता ज्ञापन	**रूस**	22 जून 2015		22 जून 2015	अंतरिक्ष विभाग
267.	इसरो और रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी (आरओएससीओएसएमओएस) के बीच **बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अन्वेषण और उपयोग के क्षेत्र में सहयोग के विस्तार** पर समझौता ज्ञापन	**रूस**	22 जून 2015		22 जून 2015	इसरो
268.	केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत गणराज्य तथा संघीय सीमा शुल्क सेवा (रूस) के बीच **हवाई यातायात में सीमा उल्लंघन से निपटने में सहयोग** पर प्रोटोकॉल।	**रूस**	6 अप्रैल 2015		6 अप्रैल 2015	वित्त मंत्रालय
269.	प्रसार भारती तथा डिजिटल टेलीविजन रूस के बीच **प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग** पर समझौता ज्ञापन	**रूस**	20 अगस्त 2015		20 अगस्त 2015	प्रसार भारती
270.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुम्बई और नेशनल रिसर्च टॉम्सक स्टेट यूनिवर्सिटी के बीच **उनके संकाय और प्रशासनिक कर्मचारियों, विभागों और अनुसंधान संस्थानों के बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क को प्रोत्साहित करने और सहयोग को बढ़ावा देने** के लिए समझौता ज्ञापन।	**रूस**	8 मई 2015		8 मई 2015	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई

जारी है......

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
271.	दिल्ली विश्वविद्यालय तथा लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के बीच दो संस्थानों में मैत्री को बढ़ावा देने और अध्ययन विषयों के लिए दोनों संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सहयोगात्मक संबंध स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन।	**रूस**	8 मई 2015		8 मई 2015	विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
272.	इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) तथा रशियन यूनियन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एसोसिएशन्स के बीच दोनों देशों में आम तौर पर जनता में इंजीनियरिंग व्यवसाय में उनके सदस्यों की रुचि साधने और कल्याण की सेवा को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी, वैज्ञानिक और व्यावसायिक ज्ञान को बढ़ावा देने और आदान–प्रदान के लिए सहयोग के करार	**रूस**	8 मई 2015		8 मई 2015	विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
273.	भारत गणराज्य और रूसी संघ के **उच्च शिक्षा संस्थानों के नेटवर्क** की स्थापना के आशय का ज्ञापन।	**रूस**	8 मई 2015		8 मई 2015	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
274.	उच्च शिक्षा के संस्थानों के रूसी भारतीय नेटवर्क की **स्थापना की घोषणा।**	**रूस**	8 मई 2015		8 मई 2015	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
275.	केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (भारत गगणराज्य) तथा संघीय सीमा शुल्क सेवा (रूस) के बीच भारत गणराज्य और रूस के बीच ले जाई गई वस्तुओं और वाहनों के व्यापार और सीमा शुल्क नियंत्रण की सुविधा के लिए पूर्व आगमन सूचना के विनिमय में सहयोग पर प्रोटोकॉल	**रूस**	6 अप्रैल 2015		6 अप्रैल 2015	वित्त मंत्रालय
276.	भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा रशियन साइंस फाउंडेशन के बीच **अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक दलों द्वारा किए गए बुनियादी और खोजपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान के आयोजन के लिए अनुदान प्रतियोगिता के समन्वय के सहयोग पर** करार	**रूस**	8 मई 2015		8 मई 2015	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
277.	भारत गणराज्य सरकार तथा सेंट किट्स और नेविस की सरकार के बीच **करों से संबंधित सूचना के आदान प्रदान** के लिए करार	**सेंट किट्स**	11 नवंबर 2014	12 जनवरी 2015		वित्त मंत्रालय

जारी है......

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
278.	भारत गणराज्य तथा सऊदी अरब राज्य के बीच **रक्षा सहयोग** पर समझौता ज्ञापन	**सऊदी अरब**	26 फरवरी 2014	18 सितंबर 2014	5 मार्च 2015	रक्षा मंत्रालय
279.	भारत गणराज्य सरकार तथा सेशेल्स गणराज्य सरकार के बीच **करों के संबंध में सूचना के आदान–प्रदान** के लिए करार	**सेशेल्स**	26 अगस्त 2015	5 अक्टूबर 2015		वित्त मंत्रालय
280.	भारत गणराज्य सरकार तथा सेशेल्स गणराज्य सरकार के बीच **नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग** पर समझौता ज्ञापन।	**सेशेल्स**	11 मार्च 2015		11 मार्च 2015	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
281.	भारत गणराज्य सरकार तथा सेशेल्स गणराज्य सरकार के बीच **हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग** के लिए समझौता ज्ञापन।	**सेशेल्स**	11 मार्च 2015		11 मार्च 2015	रक्षा मंत्रालय
282.	भारत गणराज्य सरकार तथा सेशेल्स गणराज्य सरकार के बीच **नौवहन चार्ट / इलेक्ट्रॉनिक नौवहन चार्ट की बिक्री** पर प्रोटोकॉल।	**सेशेल्स**	11 मार्च 2015		11 मार्च 2015	
283.	भारत गणराज्य सरकार तथा सेशेल्स गणराज्य सरकार के बीच **एसम्पशंस द्वीप, सेशेल्स पर सुविधाओं के विकास** पर करार	**सेशेल्स**	11 मार्च 2015		11 मार्च 2015	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
284.	भारत गणराज्य सरकार तथा सेशेल्स गणराज्य सरकार के बीच हवाई सेवा करार।	**सेशेल्स**	26 अगस्त 2015			नागरिक विमानन मंत्रालय
285.	भारत गणराज्य सरकार तथा सेशेल्स गणराज्य सरकार के बीच **ब्लू अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग** की रूपरेखा पर प्रोटोकॉल	**सेशेल्स**	26 अगस्त 2015		26 अगस्त 2015	जहाजरानी मंत्रालय
286.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा सेशेल्स कृषि एजेंसी के बीच **कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग** के लिए समझौता ज्ञापन।	**सेशेल्स**	26 अगस्त 2015		26 अगस्त 2015	कृषि मंत्रालय
287.	भारत गणराज्य सरकार तथा सेशेल्स गणराज्य सरकार के बीच **"डोर्नियर–228 समुद्री विमान" प्रदान करने** के लिए समझौता ज्ञापन।	**सेशेल्स**	26 अगस्त 2015		26 अगस्त 2015	रक्षा मंत्रालय

जारी है........

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
288.	भारत गणराज्य और सिंगसेर्ट के बीच इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीआईआरटी) (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) **साइबर सुरक्षा** के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन।	**सिंगापुर**	24 नवंबर 2015		24 नवंबर 2015	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
289.	भारत गणराज्य के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तथा सिंगापुर गणराज्य के केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के बीच सहयोग पर नारकोटिक ड्रग, मादक पदार्थ और उनके प्रीकसर्स की अवैध तस्करी से निपटने के लिए समझौता ज्ञापन।	**सिंगापुर**	24 नवंबर 2015		24 नवंबर 2015	
291.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा सिंगापुर कॉर्पोरेशन इंटरप्राइज इन सिविल एविएशन के बीच समझौता ज्ञापन।	**सिंगापुर**	24 नवंबर 2015		24 नवंबर 2015	नागरिक विमानन मंत्रालय
292.	भारत गणराज्य सरकार तथा सिंगापुर गणराज्य सरकार के बीच सिंगापुर के एशियाई सभ्यता संग्रहालय के लिए कलाकृतियों के ऋण के विस्तार पर करार।	**सिंगापुर**	24 नवंबर 2015		24 नवंबर 2015	
293.	भारत गणराज्य और सिंगापुर गणराज्य के प्रधान मंत्री द्वारा एक सामरिक साझेदारी पर संयुक्त घोषणा।	**सिंगापुर**	24 नवंबर 2015			
294.	भारत सरकार के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गनाइजेशन तथा सिंगापुर सहयोग उद्यम के बीच शहरी योजना और प्रशासन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण पर समझौता ज्ञापन।	**सिंगापुर**	24 नवंबर 2015		24 नवंबर 2015	शहरी विकास मंत्रालय
295.	भारत गणराज्य सरकार और सिंगापुर गणराज्य सरकार के बीच वर्ष 2015.2018 के लिए कलाए विरासतए अभिलेखागार और लाइब्रेरी के क्षेत्र में सहयोग पर कार्यकारी कार्यक्रम	**सिंगापुर**	24 नवंबर 2015			
296.	भारत गणराज्य सरकार तथा सिंगापुर गणराज्य सरकार के बीच **रक्षा सहयोग** के संबंध में करार।	**सिंगापुर**	23 नवंबर 2015		23 नवंबर 2015	रक्षा मंत्रालय
297.	भारत गणराज्य और स्लोवाक गणराज्य के बीच **भारत–स्लोवाकिया संयुक्त आर्थिक समिति के आठ सत्रों (जे ईई सी) के प्रोटोकॉल**	**स्लोवाक गणराज्य**	25 फरवरी 2015			वाणिज्य मंत्रालय

जारी है.....

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
298.	भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और स्लोवाक ऑफिस ऑफ स्टैंडर्डए मेट्रोलॉजी एंड टेस्टिंग के बीच समझौता ज्ञापन।	**स्लोवाक गणराज्य**	29 जुलाई 2015			उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
299.	भारत गणराज्य सरकार तथा स्लोवेनिया गणराज्य सरकार के बीच **राजनयिक मिशनों और कौंसुलर पोस्ट के सदस्य के आश्रितों के लाभकारी व्यवसाय** पर करार	**स्लोवेनिया**	24 अप्रैल 2015		6 अगस्त 2015	विदेश मंत्रालय
300.	रक्षा के लिए वर्गीकृत जानकारी के संरक्षण पर करार	**स्पेन**	5 मार्च 2015			रक्षा मंत्रालय
301.	भारत गणराज्य और श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के बीच शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के उपयोग में सहयोग पर करार	**श्री लंका**	16 फरवरी 2015	25 मई 2015		परमाणु ऊर्जा विभाग
302.	भारत गणराज्य सरकार तथा श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य सरकार के बीच **सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और आपसी सहायता** पर करार	**श्री लंका**	13 मार्च 2015	25 मई 2015	25 दिसंबर 2015	वित्त मंत्रालय
303.	भारत गणराज्य सरकार तथा श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य सरकार के बीच वर्ष 2015–2018 के लिए **सांस्कृतिक सहयोग** के कार्यक्रम।	**श्री लंका**	16 फरवरी 2015		16 फरवरी 2015	संस्कृति मंत्रालय
304.	श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य सरकार तथा भारत गणराज्य सरकार के बीच **नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना** पर समझौता ज्ञापन।	**श्री लंका**	16 फरवरी 2015		16 फरवरी 2015	विदेश मंत्रालय
305.	भारत गणराज्य सरकार तथा श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य सरकार के बीच वर्ष 2015–2016 के लिए **कृषि के क्षेत्र में सहयोग** पर समझौता ज्ञापन के अंतर्गत कार्य योजना।	**श्री लंका**	16 फरवरी 2015		16 फरवरी 2015	कृषि मंत्रालय
306.	भारत गणराज्य के युवा कार्य और खेल मंत्रालय तथा श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के युवा कार्य मंत्रालय के बीच **युवा विकास के क्षेत्र में सहयोग** पर समझौता ज्ञापन।	**श्री लंका**	13 मार्च 2015		13 मार्च 2015	युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय जारी है.....

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
307.	भारत गणराज्य सरकार तथा श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य सरकार के बीच **राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की आवश्यकता से छूट** पर करार	**श्री लंका**	13 मार्च 2015	11 अगस्त 2015		विदेश मंत्रालय
308.	भारत गणराज्य सरकार तथा श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य सरकार के बीच **स्थानीय निकायों के गैर–सरकारी संगठनों के चैरिटेबल ट्रस्ट और शिक्षा और व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से लघु विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए** भारतीय अनुदान सहायता के संबंध में समझौता ज्ञापन।	**श्री लंका**	15 सितंबर 2015		15 सितंबर 2015	विदेश मंत्रालय
309.	भारत गणराज्य सरकार तथा श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य सरकार के बीच **जिला सामान्य अस्पताल, वावुनिया, श्रीलंका में 200 बिस्तर वाले वार्ड परिसर में चिकित्सा उपकरण और फर्नीचर के प्रावधान** के लिए समझौता ज्ञापन।	**श्री लंका**	15 सितंबर 2015		15 सितंबर 2015	विदेश मंत्रालय
310.	भारत और श्रीलंका के बीच **सार्क क्षेत्र के लिए उपग्रह के कक्षा आवृत्ति समन्वय पर** द्विपक्षीय समझौते	**श्री लंका**	15 सितंबर 2015			अंतरिक्ष विभाग
311.	श्रीलंका में आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा की स्थापना पर पत्र का आदान–प्रदान	**श्री लंका**	15 सितंबर 2015			विदेश मंत्रालय
312.	मतारा में रुहुना विश्वविद्यालय में **रवीन्द्रनाथ टैगोर सभागार के निर्माण** का समझौता ज्ञापन	**श्री लंका**	15 सितंबर 2015			
313.	भारत गणराज्य सरकार तथा स्वीडन राज्य की सरकार के बीच **राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की आवश्यकता से छूट** पर करार	**स्वीडन**	1 जून 2015	5 अक्टूबर 2015		विदेश मंत्रालय
314.	भारत और स्वीडन के बीच सतत् शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	**स्वीडन**	1 जून 2015			शहरी विकास मंत्रालय

जारी है.....

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
315.	भारत गणराज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा स्वीडन की शाही सरकार के उद्यम और अभिनव मंत्रालय के बीच **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग** पर समझौता ज्ञापन	**स्वीडन**	1 जून 2015			सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
316.	भारत सरकार के पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ईएसएसओ)ए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा स्वीडिश पोलर रिसर्च सचिवालय (एसपीआरएस) के बीच **ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान में सहयोग** पर आशय पत्र	**स्वीडन**	1 जून 2015			पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
317.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) तथा स्वीडिश अनुसंधान परिषद के बीच **स्वास्थ्य, कार्य जीवन और कल्याण (एफओटीआई)** के लिए आशय का ज्ञापन	**स्वीडन**	1 जून 2015			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
318.	भारत गणराज्य के केन्द्रीय मादक पदार्थ मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) तथा स्वीडिश मेडिकल प्रोडक्ट एजेंसी (एमपीए) के बीच आशय ज्ञापन	**स्वीडन**	1 जून 2015			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
319.	भारत गणराज्य के नागरिक विमानन मंत्रालय तथा स्वीडन सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	**स्वीडन**	20 अक्टूबर 2015			नागरिक विमानन मंत्रालय
320.	भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय तथा ताजिकिस्तान गणराज्य के विदेश मंत्रालय के बीच 2015–2017 की अवधि के लिए **सहयोग कार्यक्रम**	**तजाकिस्तान**	13 मई 2015		13 मई 2015	विदेश मंत्रालय
321.	भारत गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय तथा ताजिकिस्तान गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय के बीच **वर्ष 2016–2018 के लिए संस्कृति और कला** के क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रम।	**तजाकिस्तान**	13 जुलाई 2015		13 जुलाई 2015	संस्कृति मंत्रालय
322.	विदेश मंत्रालय तथा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के बीच ताजिकिस्तान के 37 स्कूलों में कंप्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना के लिए करार।	**तजाकिस्तान**	5 अक्टूबर 2015			विदेश मंत्रालय
323.	ताजिकिस्तान के 37 स्कूलों में कंप्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना के लिए नोट बरबाल का आदान–प्रदान	**तजाकिस्तान**	13 जुलाई 2015		13 जुलाई 2015	विदेश मंत्रालय

जारी है......

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
324.	भारत गणराज्य सरकार तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य सरकार के बीच **हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग** के लिए समझौता ज्ञापन।	**तंजानिया**	19 जून 2015		19 जून 2015	रक्षा मंत्रालय
325.	तंजानिया में पूर्वी अफ्रीका सांख्यिकीय प्रशिक्षण केन्द्र (ईएएसटीसी) तथा भारत में आईसीएआर–भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान (आईसीएकार आआईएएसआरआई) के बीच **कृषि सांख्यिकी, कंप्यूटर अनुप्रयोग और जैव सूचना विज्ञान में एक सहयोगी कार्यक्रम की स्थापना** पर समझौता ज्ञापन।	**तंजानिया**	19 जून 2015		19 जून 2015	कृषि मंत्रालय
326.	तंजानिया में पूर्वी अफ्रीका सांख्यिकीय प्रशिक्षण केन्द्र (ईएएसटीसी) तथा राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (एनएसएसटीए) के बीच **सरकारी आंकड़ों में एक सहयोगी कार्यक्रम की स्थापना** पर समझौता ज्ञापन।	**तंजानिया**	19 जून 2015		19 जून 2015	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
327.	भारत गणराज्य सरकार तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य सरकार के बीच **पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग** के लिए समझौता ज्ञापन	**तंजानिया**	19 जून 2015		19 जून 2015	पर्यटन मंत्रालय
328.	भारत गणराज्य सरकार तथा थाईलैंड की शाही सरकार के बीच **दोहरे कराधान से बचाव और आय पर करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम** के लिए करार।	**थाईलैंड**	29 जून 2015		11 जून 2015	वित्त मंत्रालय
329.	नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पर समझौता ज्ञापन।	**थाईलैंड**	29 जून 2015		29 जून 2015	विदेश मंत्रालय
330.	आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), आयुष मंत्रालय, भारत गणराज्य सरकार और थाईलैंड के बीच **आयुर्वेद में शैक्षणिक पीठ की स्थापना** पर समझौता ज्ञापन	**थाईलैंड**	29 जून 2015			आयुष मंत्रालय
331.	भारत सरकार और थाईलैंड की शाही सरकार के बीच **प्रत्यर्पण संधि**	**थाईलैंड**	30 मई 2013	19 जुलाई 2013	29 जून 2015	विदेश मंत्रालय

जारी है......

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
332.	विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय, भारत गणराज्य तथा इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन्स (आईआईआर) द यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट इंडीज, सेंट अगस्टीन, त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के बीच **आपसी सहयोग** पर समझौता ज्ञापन ।	**त्रिनिदाद और टोबैगो**	5 जून 2015			विदेश मंत्रालय
333.	भारत गणराज्य सरकार तथा ट्यूनीशिया गणराज्य सरकार के बीच **राजनयिक और आधिकारिक / विशेष पासपोर्ट धारकों के लिए आवश्यक वीजा की छूट** पर करार	**ट्यूनीशिया**	30 अप्रैल 2015	22 जून 2015		विदेश मंत्रालय
334.	तुर्कमेनिस्तान और भारत के बीच **अश्गाबात में तुर्कमेन–भारत प्रशिक्षण और औद्योगिक केन्द्र के सुधार और आधुनिकीकरण** के लिए आपसी समझौता ज्ञापन	**तुर्कमेनिस्तान**	8 अप्रैल 2015		8 अप्रैल 2015	विदेश मंत्रालय
335.	भारत गणराज्य सरकार तथा तुर्कमेनिस्तान सरकार के बीच **रक्षा के क्षेत्र में सहयोग** पर करार	**तुर्कमेनिस्तान**	11 जुलाई 2015	29 अक्टूबर 2015	18 नवंबर 2015	रक्षा मंत्रालय
336.	भारत गणराज्य सरकार तथा तुर्कमेनिस्तान सरकार के बीच 2015–2017 की अवधि के लिए **विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग** कार्यक्रम	**तुर्कमेनिस्तान**	11 जुलाई 2015		11 जुलाई 2015	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
337.	**'राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड' भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और तुर्कमेन राज्य के बीच 'तुर्कमेनहिमिया' संबंधित विषय पर रासायनिक उत्पादों की आपूर्ति** पर समझौता ज्ञापन	**तुर्कमेनिस्तान**	11 जुलाई 2015		11 जुलाई 2015	रसायन और उर्वरक मंत्रालय
338.	भारत गणराज्य सरकार तथा तुर्कमेनिस्तान सरकार के बीच **योग और पारंपरिक दवा के क्षेत्र में सहयोग** पर समझौता ज्ञापन	**तुर्कमेनिस्तान**	11 जुलाई 2015		11 जुलाई 2015	आयुष मंत्रालय
339.	भारत गणराज्य सरकार तथा तुर्कमेनिस्तान सरकार के बीच **पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग** पर समझौता ज्ञापन	**तुर्कमेनिस्तान**	11 जुलाई 2015		11 जुलाई 2015	पर्यटन मंत्रालय

जारी है.........

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
340.	भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थान तथा तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्रालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन्स के बीच समझौता ज्ञापन।	**तुर्कमेनिस्तान**	11 जुलाई 2015		11 जुलाई 2015	विदेश मंत्रालय
341.	भारत गणराज्य युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय तथा तुर्कमेनिस्तान की राज्य खेल समिति के बीच **खेल के क्षेत्र में सहयोग** पर करार	**तुर्कमेनिस्तान**	11 जुलाई 2015		11 जुलाई 2015	युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय
342.	अश्गाबात में तुर्कमेन भारत औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र के उन्नयन पर समझौता ज्ञापन।	**तुर्कमेनिस्तान**	8 अप्रैल 2015		8 अप्रैल 2015	विदेश मंत्रालय
343.	तुर्कमेनिस्तान गणराज्य सरकार तथा भारत गणराज्य सरकार के बीच अशगबत, तुर्कमेनिस्तान तुर्कमेन–भारत प्रशिक्षण –और औद्योगिक केन्द्र के आधुनिकीकरण में सुधार के लिए आपसी समझौता ज्ञापन	**तुर्कमेनिस्तान**	8 अप्रैल 2015		8 अप्रैल 2015	विदेश मंत्रालय
344.	भारतीय मानक ब्यूरो और एमिरेट्स अथॉरिटी फॉर स्टैंडर्डडाइजेशन एंड मैट्रोलोजी के बीच समझौता ज्ञापन।	**यूएई**	3 सितंबर 2015		3 सितंबर 2015	उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
345.	भारत गणराज्य के पर्यटन मंत्रालय तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय पर्यटन और पुरावशेष परिषद के बीच **पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग** पर समझौता ज्ञापन।	**यूएई**	3 सितंबर 2015		3 सितंबर 2015	पर्यटन मंत्रालय
346.	संयुक्त अरब अमीरात के उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय तथा भारत गणराज्य के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच **उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग** के संबंध में समझौता ज्ञापन।	**यूएई**	3 सितंबर 2015		3 सितंबर 2015	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
347.	भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) तथा यूएई के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन	**यूएई**	3 सितंबर 2015		3 सितंबर 2015	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
348.	संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच **निवेश और व्यापार के अवसरों को बढ़ाना**	**यूएई**	3 सितंबर 2015			

जारी है.....

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
349.	भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग तथा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉदर्न आयरलैंड की सरकार के ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन विभाग के बीच **भारतीय परमाणु ऊर्जा भागीदारी वैश्विक केंद्र के साथ सहयोग के संबंध में** समझौता ज्ञापन।	**यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन**	9 नंवबर 2015		9 नंवबर 2015	परमाणु ऊर्जा विभाग
350.	भारत सरकार तथा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉदर्न आयरलैंड की सरकार के बीच **परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग** के लिए करार	**यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन**	13 नवंबर 2015			परमाणु ऊर्जा विभाग
351.	भारत सरकार तथा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉदर्न आयरलैंड की सरकार के बीच **ऊर्जा क्षेत्र** में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	**यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन**	11 नवंबर 2015		11 नवंबर 2015	विद्युत मंत्रालय
352.	आयुष मंत्रालय और एकीकृत चिकित्सा के लिए एक अग्रणी ब्रिटेन संस्थान के बीच इस क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग का सुदृढ़ीकरण और विकास करने के लिए समझौता ज्ञापन।	**यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन**	11 नवंबर 2015		11 नवंबर 2015	आयुष मंत्रालय
353.	भारत गणराज्य सरकार के रेल मंत्रालय तथा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉदर्न आयरलैंड की सरकार के परिवहन विभाग के बीच **भारतीय रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग** पर समझौता ज्ञापन	**यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन**	10 नवंबर 2015		10 नवंबर 2015	विदेश मंत्रालय
354.	आयुष मंत्रालय और एकीकृत चिकित्सा के लिए एक अग्रणी ब्रिटेन संस्थान के बीच होम्योपैथिक **चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत बनाने और अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने** के लिए समझौता ज्ञापन	**यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन**	11 नवंबर 2015		11 नवंबर 2015	आयुष मंत्रालय
355.	भारत गणराज्य सरकार की प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, (भारत सरकार) तथा यूनाइटेड किंगडम के कैबिनेट कार्यालय के बीच **लोक प्रशासन और शासन सुधारों में सहयोग** पर समझौता ज्ञापन	**यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन**	11 नवंबर 2015		11 नवंबर 2015	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय जारी है......

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
356.	**क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला में क्षमता निर्माण के द्वारा अपनी विकास की चुनौतियों के समाधान में विकासशील देशों की सहायता करने के लिए तीसरे देशों में सहयोग के लिए भागीदारी** पर आशय का वक्तव्य	**यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन**	10 नवंबर 2015		10 नवंबर 2015	विकास साझेदारी प्रशासन –II, विदेश मंत्रालय
357.	**भारत में ब्रिटेन द्वारा निवेश के लिए फास्ट ट्रैक प्रणाली की स्थापना पर** भारत और ब्रिटेन द्वारा संयुक्त घोषणा	**यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन**	13 नवंबर 2015		13 नवंबर 2015	वाणिज्य मंत्रालय
358.	भारत गणराज्य सरकार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के बीच **अंतरराष्ट्रीय कर अनुपालन में सुधार करने के लिए और लागू करने के लिए** करार	**यूएसए**	9 जुलाई 2015	31 जुलाई 2015	31 अगस्त 2015	वित्त मंत्रालय
359.	भारत गणराज्य सरकार के शहरी विकास मंत्रालय तथा यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के बीच **पानीए सफाई और स्वच्छता के क्षेत्र में सहयोग** पर समझौता ज्ञापन	**यूएसए**	13 जनवरी 2015		13 जनवरी 2015	शहरी विकास मंत्रालय
360.	इसरो तथा संयुक्त राज्य अमेरिका भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के बीच **पृथ्वी अवलोकन (लैंडसेट उपग्रह) डेटा साझा करने के लिए** सहयोग पत्र	**यूएसए**	8 मई 2015		8 मई 2015	अंतरिक्ष विभाग
361.	इसरो और नासा के बीच मार्स ऑर्बिटर मिशन के नासा अंतरिक्ष यान संचार तथा नेविगेशन समर्थन के **प्रतिपूर्ति समझौते का संशोधन**	**यूएसए**	23 सितंबर 2015		23 सितंबर 2015	अंतरिक्ष विभाग
362.	भारत गणराज्य सरकार के संचार और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के विदेश विभाग के बीच **सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग** पर आशय की संयुक्त घोषणा।	**यूएसए**	23 जनवरी 2015		23 जनवरी 2015	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
363.	भारत गणराज्य सरकार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के बीच पेससेंटर निधि की स्थापना के लिए सहयोग पर समझौता ज्ञापन	**यूएसए**	30 जून 2015		30 जून 2015	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

जारी है....

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
364.	पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ईएसएसओ), भारतीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (बाद में जिसे "एमओईएस" कहा जाए) तथा द वुड्स होल ओसीनोग्राफिक इंस्टीट्यूट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (बाद में जिसे ''डब्ल्यूएचओआई'' कहा जाए) के बीच **समुद्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपसी सहयोग** पर आशय पत्र।	**यूएसए**	23 फरवरी 2015		23 फरवरी 2015	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
365.	संयुक्त राज्य अमेरिका के परिवहन विभाग तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय के बीच सहयोग ज्ञापन	**यूएसए**	8 अप्रैल 2015		8 अप्रैल 2015	रेल मंत्रालय
366.	भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र के बीच 2015–2018 के लिए सहयोग पर विश्व खाद्य कार्यक्रम पर समझौता ज्ञापन।	**यू एन ओ**	18 अगस्त 2015		18 अगस्त 2015	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
367.	भारत गणराज्य सरकार तथा उजबेकिस्तान गणराज्य सरकार के बीच **पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग** पर करार।	**उज़्बेकिस्तान**	6 जुलाई 2015		6 जुलाई 2015	पर्यटन मंत्रालय
368.	विदेश मंत्रालय, उजबेकिस्तान गणराज्य तथा विदेश मंत्रालय, भारत गणराज्य के बीच सहयोग पर प्रोटोकॉल।	**उज़्बेकिस्तान**	6 जुलाई 2015		6 जुलाई 2015	विदेश मंत्रालय
369.	भारत गणराज्य सरकार तथा उजबेकिस्तान गणराज्य सरकार के बीच 2015–2017 के लिए सांस्कृतिक सहयोग के कार्यक्रम।	**उज़्बेकिस्तान**	6 जुलाई 2015		6 जुलाई 2015	संस्कृति मंत्रालय
370.	भारत गणराज्य के रक्षा मंत्रालय तथा वियतनाम समाजवादी गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के बीच **2015–2020 की अवधि के लिए भारत–वियतनाम के रक्षा संबंध** पर संयुक्त दूरदृष्टि विवरण।	**वियतनाम**	25 मई 2015			रक्षा मंत्रालय
371.	भारत गणराज्य के भारतीय तट रक्षक तथा वियतनाम समाजवादी गणराज्य के वियतनाम के तट रक्षक के बीच **अंतरराष्ट्रीय अपराध से निपटने और विकास के लिए आपसी सहयोग हेतु सहयोगात्मक संबंधों की स्थापना हेतु** समझौता ज्ञापन।	**वियतनाम**	25 मई 2015		25 मई 2015	रक्षा मंत्रालय

जारी है.....

क्रम सं.	अभिसमय / संधि / समझौते का शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण / स्वीकृति की तारीख	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
372.	भारत गणराज्य के विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय तथा इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन्स (आईआईआर), द यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्टइंडीज, सेंट अगस्टीन के बीच **आपसी सहयोग** पर समझौता ज्ञापन ।	**वेस्ट इंडीज**	5 जून 2015		5 जून 2015	विदेश मंत्रालय
373.	शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच **स्वच्छ भारत मिशन** (शहरी स्वस्वच्छता) के लिए कार्यान्वयन का समर्थन पर सहयोग ज्ञापन।	**यूएसए**	13 जनवरी 2015			शहरी विकास मंत्रालय

जारी है.....

परिशिष्ट–II

1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2015 की अवधि के दौरान जारी किए गए पूर्ण अधिकार के दस्तावेज

क्र.सं.	अभिसमय / संधि	देश	जारी करने की तिथि
1.	भारत और अंतरराष्ट्रीय विकास हेतु ओपेक निधि (ओएफआईडी) के बीच भारत स्थायी नवीकरणीय ऊर्जा विकास (आईएसआरईडी) कार्यक्रम ऋण करार	विकास के लिए ईसीडी कोष	14 मई 2015
2.	भारत गणराज्य की सरकार और पोलैंड लोकतांत्रिक सरकार के बीच कूटनीतिज्ञ पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा की आवश्यकता से छूट	पोलैंड	6 अक्टूबर 2015
3.	भारत गणराज्य की सरकार और सेशेल्स लोकतांत्रिक सरकार के बीच एक ''डोर्नियर–228 समुद्री विमान प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन	सेशेल्स	25 अगस्त 2015
4.	संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच अंतरराष्ट्रीय कर अनुपालन में सुधार लाने और एफएटीसीए के कार्यान्वयन के लिए एक करार	अमेरीका	3 जुलाई 2015
5.	भारत गणराज्य की सरकार तथा भूटान की शाही सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के वंचन तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए करार	थाईलेंड	25 मई 2015
6.	भारत गणराज्य की सरकार और सेशेल्स लोकतांत्रिक सरकार के बीच एक ''डोर्नियर–228 समुद्री विमान प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन	सेशेल्स	25 अगस्त 2015
7.	भारत गणराज्य की सरकार और केन्या लोकतांत्रिक सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के वंचन तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए करार	केन्या	20 नवंबर 2015
8..	भारत गणराज्य की सरकार और ईरान की इस्लामिक लोकतांत्रिक सरकार के बीच वीज़ा जारी करने की सुविधा के लिए करार	ईरान	7 दिसंबरए 2015
9.	भारत गणराज्य की सरकार और जापान सरकार के बीच वर्गीकृत सैन्य सूचना की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय से संबंधित करार	जापान	9 दिसंबर 2015
10.	भारत गणराज्य की सरकार तथा जापान की सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के वंचन तथा राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम पर हुए अभिसमय के संशोधन के लिए प्रोटोकॉल	जापान	9 दिसंबर 2015
11.	भारत गणराज्य की सरकार तथा जापान सरकार के बीच रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी के अंतरण से संबंधित करार	जापान	9 दिसंबर 2015

जारी है.............

01 जनवरी, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 तक की अवधि के दौरान जारी किए गए अनुसमर्थन / परिग्रहण दस्तावेज

क्रम सं.	करार / संधि / समझौता ज्ञापन के नाम	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण की तिथि	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
1.	बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल (बीबीआईएन) के बीच **बीबीआईएन में यात्री, व्यक्तिगत और मालवाहक वाहनों की आवाजाही के नियमन के लिए मोटर वाहन करार**	बहुपक्षीय	10 जुलाई 2015	10 जुलाई 2015		सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
2.	भारत और ऑस्ट्रेलिया गणराज्य के बीच **सामाजिक सुरक्षा** करार	ऑस्ट्रेलिया	18 नवंबर 2014	10 अक्टूबर 2015		प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
3.	भारत सरकार और ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच **परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के सहयोग पर** करार।	ऑस्ट्रेलिया	5 सितंबर 2014	12 नवंबर 2015	13 नवंबर 2015	परमाणु ऊर्जा विभाग
4.	भारत गणराज्य सरकार और ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच **सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण** के विषय पर करार	ऑस्ट्रेलिया	11 नवंबर 2015	16 दिसंबर 2015		गृह मंत्रालय
5.	भारत गणराज्य और ऑस्ट्रिया गणराज्य के बीच **सामाजिक सुरक्षा** पर करार	ऑस्ट्रेलिया	4 फरवरी 2013	2 अप्रैल 2013	1 जुलाई 2015	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
6.	भारत गणराज्य सरकार और बांग्लादेश की जनवादी गणराज्य सरकार के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच **भूमि सीमा के सीमांकन** और संबंधित मामलों **के संबंध में** करार	बांग्लादेश	16 मई 1974	25 मई 2015		विदेश मंत्रालय
7.	भारत गणराज्य सरकार और बांग्लादेश की जनवादी गणराज्य सरकार के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच **भूमि सीमा के सीमांकन** और संबंधित मामलों के संबंध में प्रोटोकॉल करार	बांग्लादेश	6 सितंबर 2011	25 मई 2015		विदेश मंत्रालय
8.	भारत गणराज्य के वस्त्र मंत्रालय और बेलारूसी राज्य की कंपनी **(कंपनी ''बेलगप्रोम'')** के बीच **प्रकाश उद्योग माल के विनिर्माण और विपणन के लिए** समझौता ज्ञापन	बेलारूस	3 जून 2015	3 सितंबर 2015		वस्त्र मंत्रालय

जारी है.............

क्रम सं.	करार / संधि / समझौता ज्ञापन के नाम	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण की तिथि	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
9.	27 सितंबर, 1997 को भारत गणराज्य सरकार और बेलारूस गणराज्य सरकार के बीच हुए करार में **आय और संपत्ति (पूंजी पर दोहरे कराधान बचाव और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए करों के संबंध में** प्रोटोकॉल संशोधन	बेलारूस	3 जून 2015	31 जुलाई 2015	19 नवंबर 2015	वित्त मंत्रालय
10.	भारत गणराज्य सरकार और ब्राजील सरकार के बीच **प्रत्यर्पण संधि**	ब्राजील	16 अप्रैल 2008	14 अगस्त 2008	20 अगस्त 2015	विदेश मंत्रालय
11.	भारत गणराज्य के सूचना और प्रसारण मंत्रालय और चीनी जनवादी गणराज्य के प्रेस, प्रकाशन, रेडियो, फिल्म और टेलीविजन के राज्य प्रशासन के बीच **श्रव्य–दृश्य सह उत्पादन** पर करार	चीन	18 सितंबर 2014	1 मई 2015		सूचना और प्रसारण मंत्रालय
12.	भारत गणराज्य सरकार और क्रोएशिया गणराज्य सरकार के बीच दोहरे कराधान से बचाव और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए करार।	क्रोएशिया	12 फरवरी 2014	12 अगस्त 2014	6 फरवरी 2015	वित्त मंत्रालय
13.	क्यूबा गणराज्य सरकार और भारत गणराज्य सरकार के बीच राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकताओं की छूट पर करार	क्यूबा	23 मार्च 2015	1 मई 2015	7 जुलाई 2015	विदेश मंत्रालय
14.	आर्थिक सहयोग संघीय मंत्रालय और जर्मनी संघीय गणराज्य के विकास और आर्थिक सहयोग मंत्रालय तथा भारत गणराज्य के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच **भारत–जर्मन सौर ऊर्जा भागीदारी के संबंध में भारत–जर्मन विकास सहयोग** पर समझौता ज्ञापन	जर्मनी	5 अक्तूबर 2015	5 अक्तूबर 2015		नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
15.	भारत गणराज्य सरकार और ग्वाटेमाला गणराज्य सरकार के बीच **राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकता की छूट** पर करार	ग्वाटेमाला	28 मई 2015	9 अक्तूबर 2015		विदेश मंत्रालय

जारी है.............

क्रम सं.	करार / संधि / समझौता ज्ञापन के नाम	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण की तिथि	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
16.	भारत गणराज्य सरकार और चनी जनवादी गणराज्य सरकार के हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के बीच **सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण** पर करार।	हॉन्ग कॉन्ग	20 जनवरी 2015	11 मार्च 2015		गृह मंत्रालय
17.	भारत गणराज्य सरकार और इसराइल राज्य सरकार के बीच **आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता** पर संधि	इजराइल	27 फरवरी 2014	25 अप्रैल 2014	1 मार्च 2015	गृह मंत्रालय
18.	भारत गणराज्य सरकार और कज़ाखस्तान गणराज्य के बीच **सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण** पर करार	कज़ाखस्तान	8 जुलाई 2015	9 अक्तूबर 2015		गृह मंत्रालय
19.	कज़ाकस्तान गणराज्य सरकार और भारत गणराज्य सरकार के बीच **रक्षा और सेना तकनीकी सहयोग** पर करार।	कज़ाकस्तान	8 जुलाई 2015	29 अक्टूबर 2015		रक्षा मंत्रालय
20.	भारत गणराज्य सरकार और कोरिया गणराज्य सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान पर और चालू वित्त वर्ष में इसके बचाव पर करार	कोरिया	18 मई 2015	22 जून 2015		वित्त मंत्रालय
21.	भारत गणराज्य सरकार और कोरिया गणराज्य सरकार के बीच **श्रव्य–दृश्य सह–उत्पादन के सहयोग पर** करार	कोरिया	18 मई 2015	22 जून 2015		सूचना और प्रसारण मंत्रालय
22.	भारत गणराज्य सरकार और किर्गिज गणराज्य सरकार के बीच **रक्षा सहयोग पर** करार	किर्गिज गणराज्य	12 जुलाई 2015	29 अक्टूबर 2015		रक्षा मंत्रालय
23.	वस्त्र मंत्रालय, भारत गणराज्य और ऊर्जा और उद्योग मंत्रालय, किर्गिज गणराज्य के बीच **वस्त्र के क्षेत्र में** सहयोग पर समझौता ज्ञापन।	किर्गिज गणराज्य	17 मार्च 2015	3 सितंबर 2015		वस्त्र मंत्रालय
24.	भारत गणराज्य सरकार और मंगोलिया सरकार के बीच **सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण** पर संधि	मंगोलिया	17 मई 2015	14 जुलाई 2015		गृह मंत्रालय

जारी है.............

क्रम सं.	करार / संधि / समझौता ज्ञापन के नाम	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण की तिथि	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
25.	भारत गणराज्य सरकार और मोरक्को राज्य सरकार के बीच **राजनयिक, आधिकारिक और सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की आवश्यकता छूट** पर करार	मोरक्को	17 नवंबर 2015	7 दिसंबर 2015	21 जनवरी 2016	विदेश मंत्रालय
26.	भारत गणराज्य सरकार और मोजाम्बिक गणराज्य सरकार के बीच राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की आवश्यकता से छूट पर करार	मोजाम्बिक	7 अगस्त 2015	16 दिसंबर 2015		विदेश मंत्रालय
27.	**अंतरराष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन** पर सम्मेलन में संशोधन के प्रोटोकॉल	बहुपक्षीय	14 अप्रैल 2005	16 अप्रैल 2015		रक्षा मंत्रालय
28.	**जहाजों पर हानिकारक एंटी–फोलिंग सिस्टम के नियंत्रण पर** अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, 2001	बहुपक्षीय		25 मार्च 2015		जहाजरानी मंत्रालय
29.	**ब्रिक्स** आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था की स्थापना के लिए संधि	बहुपक्षीय	15 जुलाई 2014	25 मार्च 2015		वित्त मंत्रालय
30.	**नए विकास बैंक** पर करार	बहुपक्षीय	15 जुलाई 2014	25 मार्च 2015		वित्त मंत्रालय
31.	भारत गणराज्य और **दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों के संगठन** के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग फ्रेमवर्क करार के तहत **सेवा व्यापार** पर करार	बहुपक्षीय	12 नवंबर 2014	6 अप्रैल 2015		वाणिज्य मंत्रालय
32.	भारत गणराज्य और **दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों के संगठन** के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग फ्रेमवर्क करार के तहत **निवेश पर करार**	बहुपक्षीय	12 नवंबर 2014	6 अप्रैल 2015		वाणिज्य मंत्रालय
33.	एशियाई **मूल संरचना निवेश बैंक** के करार के अनुच्छेद	बहुपक्षीय	29 जून 2015	16 दिसंबर 2015		वित्त मंत्रालय
34.	**सूखे बंदरगाहों** पर अंतर सरकारी करार	बहुपक्षीय	1 मई 2013	10 नवंबर 2015		वाणिज्य मंत्रालय
35.	**ऊर्जा सहयोग (विद्युत)** केलिए सार्क करार की रूपरेखा	बहुपक्षीय	27 नवंबर 2014	31 जुलाई 2015		विदेश मंत्रालय
36.	नाविक 'पहचान दस्तावेज सम्मेलन (संशोधित),2003	बहुपक्षीय	9 जून 2003	31 जुलाई 2015		जहाजरानी मंत्रालय
37.	समुद्री श्रम सम्मेलन, 2006	बहुपक्षीय	23 फरवरी 2006	10 जुलाई 2015		जहाजरानी मंत्रालय

जारी है.............

क्रम सं.	करार / संधि / समझौता ज्ञापन के नाम	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण की तिथि	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
38.	भारत गणराज्य सरकार और ओमान सल्तनत सरकार के बीच **आपराधिक मामलों पर कानूनी और न्यायिक सहयोग** पर करार।	ओमान	29 अक्टूबर 2014	28 नवंबर 2014	23 मार्च 2015	गृह मंत्रालय
39.	भारत गणराज्य सरकार और पोलैंड गणराज्य सरकार के बीच **राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की आवश्यकता से छूट** पर करार	पोलैंड	5 अक्तूबर 2015	23 अक्तूबर 2015	7 दिसंबर, 2015	विदेश मंत्रालय
40.	भारत गणराज्य सरकार और कतर राज्य सरकार के बीच **सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण** पर करार।	कतर	25 मार्च 2015	9 अक्टूबर 2015		गृह मंत्रालय
41.	कतर नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, परिवहन मंत्रालय, कतर राज्य और पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन, पृथ्वी विज्ञान, मंत्रालय, भारत गणराज्य के बीच **वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग** के लिए समझौता ज्ञापन।	कतर	25 मार्च 2015	10 नवंबर 2015		मौसम विज्ञान विभाग
42.	विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय, भारत गणराज्य और राजनयिक संस्थान, विदेश मंत्रालय, कतर राज्य के बीच समझौता ज्ञापन।	कतर	25 मार्च 2015	8 सितंबर 2015		विदेश मंत्रालय
43.	भारत गणराज्य और रूस के बीच **सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण** पर संधि	रूस	21 अक्तूबर 2013	1 जनवरी 2014	2 मार्च 2015	गृह मंत्रालय
44.	भारत गणराज्य सरकार और सेंट किट्स और नेविस सरकार के बीच करों **से संबंधित सूचना के आदान प्रदान** के लिए करार	सेंट किट्स	11 नवंबर 2014	12 जनवरी 2015		वित्त मंत्रालय
45.	भारत गणराज्य और सऊदी अरब शाही सरकार के बीच **रक्षा सहयोग** पर समझौता ज्ञापन	सऊदी अरब	26 फरवरी 2014	18 सितंबर 2014	5 मार्च 2015	रक्षा मंत्रालय
46.	भारत गणराज्य सरकार और सेशेल्स गणराज्य सरकार के बीच **करों के संबंध में सूचना के आदान–प्रदान** के लिए करार	सेशेल्स	26 अगस्त 2015	8 अक्तूबर 2015		वित्त मंत्रालय
47.	भारत गणराज्य और श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के बीच **परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग** पर करार	श्रीलंका	16 फरवरी 2015	25 मई 2015		परमाणु ऊर्जा विभाग

जारी है.............

क्रम सं.	करार / संधि / समझौता ज्ञापन के नाम	देश	हस्ताक्षर की तिथि	अनुसमर्थन / परिग्रहण की तिथि	लागू होने की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
48.	भारत गणराज्य सरकार और श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य सरकार के बीच **सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और आपसी सहायता** पर करार	श्रीलंका	13 मार्च 2015	25 मई 2015		वित्त मंत्रालय
49.	भारत गणराज्य की सरकार और श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य सरकार के बीच **राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की आवश्यकता से छूट** पर करार	श्रीलंका	13 मार्च 2015	11 अगस्त 2015		विदेश मंत्रालय
50.	भारत गणराज्य सरकार और स्वीडन राज्य सरकार के बीच **राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की आवश्यकता से छूट** पर करार	स्वीडन	1 जून 2015	8 अक्तूबर 2015		विदेश मंत्रालय
51.	भारत गणराज्य सरकार और थाईलैंड राज्य सरकार के बीच **आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम से बचाव** के लिए करार	थाईलैंड	29 जून 2015	11 अगस्त 2015		वित्त मंत्रालय
52.	भारत गणराज्य सरकार और ट्यूनीशिया गणराज्य सरकार के बीच **राजनयिक का धारकों और आधिकारिक/ विशेष पासपोर्ट के लिए वीजा की आवश्यकता की छूट** पर करार	ट्यूनीशिया	30 अप्रैल 2015	22 जून 2015		विदेश मंत्रालय
53.	भारत गणराज्य सरकार और तुर्कमेनिस्तान सरकार के बीच **रक्षा के क्षेत्र में सहयोग** पर करार	तुर्कमेनिस्तान	11 जुलाई 2015	29 अक्टूबर 2015		रक्षा मंत्रालय
54.	भारत गणराज्य सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के बीच **अंतरराष्ट्रीय कर अनुपालन में सुधार करने और एफएटीसीए लागू करने** के लिए करार	संयुक्त राज्य अमेरिका	9 जुलाई 2015	31 जुलाई 2015	31 अगस्त 2015	वित्त मंत्रालय

■■

आईटीईसी तथा एससीएएपी देशों की सूची

आईटीईसी देश

क्रम सं	देश
1	अफगानिस्तान
2	अल्बानिया
3	अल्जीरिया
4	अंगोला
5	अंगुइला
6	एंटीगुआ एंड बरमुडा
7	अर्जेन्टीना
8	अर्मेनिया
9	अजरबैजान
10	बहामास
11	बहरीन
12	बांग्लादेश
13	बार्बाडोस
14	बेलारूस
15	बेलीज
16	बेनिन
17	भूटान
18	बोलीविया
19	बोस्निया–हर्जेगोविना
20	ब्राजील
21	ब्रूनी दार–ए–सलाम
22	बुल्गारिया
23	बुर्कीना फासो
24	बरून्डी
25	कंबोडिया
26	केप वर्डे द्वीप
27	केमन द्वीप
28	केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य
29	चाड
30	चिली
31	कोलंबिया
32	डोमिनिका राष्ट्रमंडल
33	कोमोरोस
34	कांगो
35	कुक्स द्वीप
36	कोस्टा रिका
37	कोट डि'आइवर
38	चैक गणराज्य
39	कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य
40	जिबूती
41	डोमीनिका गणराज्य
42	इक्वाडोर
43	मिस्र
44	अल–सल्वाडोर
45	इक्वेटोरियल गिनी
46	एरिट्रिया
47	एस्टोनिया
48	इथियोपिया
49	फिजी
50	गैबन
51	जॉर्जिया
52	ग्रेनेडा
53	ग्वाटेमाला
54	गुयाना
55	गुयाना बिसाऊ
56	गुयाना
57	हैती
58	होंडूरस
59	हंगरी
60	इंडोनेशिया
61	ईरान
62	ईराक

जारी है......

क्रम सं	देश
63	जमैका
64	जोर्डन
65	कज़ाकस्तान
66	किरिबाती
67	कोरि;ा ञडीपीआरके)
68	किर्गिस्तान
69	लाओस
70	लातविया
71	लेबनान
72	लाइबीरिया
73	लीबिया
74	लिथुआनिया
75	मेसीडोनिया
76	मेडागास्कर
77	मलेशिया
78	मालदीव
79	माली
80	मार्शल द्वीप
81	मॉरिटानिया
82	मेक्सिको
83	माइक्रोनेशिया
84	मोलदोवा
85	मंगोलिया
86	मोंटेनेग्रो
87	मोंटसेराट
88	मोरक्को
89	म्यांमार
90	नौरू
91	नेपाल
92	निकारागुआ
93	नाइजर
94	ओमान
95	पलाऊ
96	फिलीस्तीन
97	पनामा

क्रम सं	देश
98	पपुआ न्यूगिनी
99	पराग्वे
100	पेरू
101	फिलीपिन्स
102	पोलैंड
103	कतर
104	साओ टोम गणराज्य
105	रोमानिया
106	रूस
107	रवांडा
108	समोया
109	सेनेगल
110	सर्बिया
111	सिंगापुर
112	स्लोवाक गणराज्य
113	सोलोमन द्वीप
114	सोमालिया
115	श्रीलंका
116	सेंट किट्स एवं नेविस
117	सेंट लूसिया
118	सेंट विन्सेंट एवं ग्रेनाडिन्स
119	सूडान
120	दक्षिण सूडान
121	सूरीनाम
122	सीरिया
123	ताजीकिस्तान
124	थाइलैंड
125	तिमोर लेस्ट
126	टोगो
127	टोंगा
128	ट्रिनिदाद एंड टोबेगो
129	ट्यूनीशिया
130	तुर्की
131	तुर्कमेनिस्तान
132	तुर्क एवं कैकोज द्वीप

जारी है.......

क्रम सं	देश
133	तुवालु
134	यूक्रेन
135	उरूग्वे
136	उजबेकिस्तान
137	वनुआतु
138	वेनेजुएला
139	वियतनाम
140	यमन
एससीएएपी देश	
141	केमरून
142	केमरून
143	गांबिया
144	घाना
145	केन्या

क्रम सं	देश
146	लिसोथो
147	मलावी
148	मॉरीशस
149	मोजाम्बिक
150	नामीबिया
151	नाइजीरिया
152	सेशेल्स
153	सियरा लिओन
154	दक्षिण अफ्रीका
155	स्वाजीलैंड
156	तंजानिया
157	यूगांडा
158	जांबिया
159	जिम्बाब्वे

परिशिष्ट–V

आईटीईसी / एससीएएपी के सूचीबद्ध संस्थानों की सूची

क्र.सं.	संस्थान का नाम	शहर
	लेखा, लेखापरीक्षा, बैंकिंग और वित्त पाठ्यक्रम	
1.	सरकारी लेखा एवं वित्त संस्थान	नई दिल्ली
2.	अंतरराष्ट्रीय सूचना एवं प्रणाली लेखा परीक्षा केन्द्र	नोएडा
3.	राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान	पुणे
	पर्यावरण एवं नवीकरणीय ऊर्जा पाठ्यक्रम	
4.	आल्टरनेट हाइड्रो एनर्जी सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी	रुड़की
5.	राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान	चेन्नई
6.	राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान	गुड़गांव
7.	ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान	नई दिल्ली
	आईटी, दूरसंचार और अंग्रेजी पाठ्यक्रम	
8.	एप्टेक लिमिटेड	नई दिल्ली
9.	उन्नत संगणना विकास केन्द्र	मोहाली
10.	उन्नत संगणना विकास केन्द्र	नोएडा
11.	दूरसंचार प्रौद्योगिकी और प्रबंधन उत्कृष्टता केन्द्र	मुंबई
12.	सीएमसी लि.	नई दिल्ली
13.	अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	हैदराबाद
14.	एनआईआईटी लि.	नई दिल्ली
15.	यूटीएल टेक्नॉलाजी लि.	बैंगलोर
	प्रबंधन पाठ्यक्रम	
16.	भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय	हैदराबाद
17.	भारतीय प्रबंधन संस्थान	अहमदाबाद
18.	अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान	नई दिल्ली
19.	राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान	दिल्ली
	एसएमई / ग्रामीण विकास कार्यक्रम	
20.	भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान	अहमदाबाद
21.	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान	हैदराबाद
22.	राष्ट्रीय उद्यमशीलता एंव लघु व्यवसाय विकास संस्थान	नोएडा

जारी है......

क्र.सं.	संस्थान का नाम	शहर
23.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान	हैदराबाद
	विशेष पाठ्यक्रम	
24.	संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो	नई दिल्ली
25.	मानव रिहाइश प्रबंधन संस्थान	नई दिल्ली
26.	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान	नई दिल्ली
27.	भारतीय जन संचार संस्थान	नई दिल्ली
28.	अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी शिक्षा केंद्र	कोलकाता
29.	राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो	नई दिल्ली
30.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	चेन्नई
31.	राष्ट्रीय मानक प्रशिक्षण संस्थान	नोएडा
32.	राष्ट्रीय शिक्षा योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय	नई दिल्ली
33.	रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी	गाजियाबाद
34.	विकासशील देश अनुसंधान और सूचना प्रणाली	नई दिल्ली
35.	वी. वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान	नोएडा
	तकनीकी पाठ्यक्रम	
36.	केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान	फरीदाबाद
37.	केन्द्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान	हैदराबाद
38.	केन्द्रीय उपकरण डिजाइन संस्थान	हैदराबाद
39.	केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन	नई दिल्ली
40.	तरल पदार्थ नियंत्रण अनुसंधान संस्थान	केरल
41.	भारत–प्रशिक्षण भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान	हैदराबाद
42.	भारतीय उत्पादन प्रबंधन संस्थान	कंसबहल, उड़ीसा
43.	भारतीय दूर संवेदी संस्थान	देहरादून
44.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	रूड़की, जल संसाधन विकास और प्रबंधन विभाग
45.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	रूड़की, जल विज्ञान विभाग
46.	राष्ट्रीय भैषजिक शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान	एसएएस नगर, पंजाब
47.	दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ	कोयम्बटूर

परिशिष्ट – VI

वर्ष 2015–16 के दौरान नीति योजना और अनुसंधान प्रभाग द्वारा आंशिक अथवा पूरी तरह वित्त पोषित विश्वविद्यालय / संस्थाओं द्वारा आयोजित / प्रारंभ किए गए सम्मेलन / संगोष्ठियां /अध्ययन परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना विवरण	संस्थान
1.	लिटरेरी लिगेसी ऑफ़ इंडो–सेंट्रल एशियाई, इंडो–अफग़ानिस्तान एंड इंडो–ईरान रिजन्सए विद स्पेशल रिफरेन्स टू सबक–ए–हिंदी (इंडियन स्टाइल) पर 5 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन के लिए मध्य एशिया अध्ययन केंद्र, कश्मीर विश्वविद्यालय	कश्मीर विश्वविद्यालय
2.	26–28 अप्रैल 2015 के दौरान 21वीं शताब्दी के माध्यम से भारतीय विदेश नीति की कार्यनीतियों पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी	केरल विश्वविद्यालय
3.	सितम्बर 2015 में सामरिक और सुरक्षा के मुद्दों पर आयोजित सम्मेलन	आईसीआरआईईआर
4.	अप्रैल 2015 में आयोजित भारत फ्रांस विशेषज्ञों की नीति वार्ता	ओआरएफ
5.	अफ्रीका में भारत के विकास सहयोग कार्यक्रम पर अनुसंधान अध्ययन	आरआईएस

01 जनवरी से 31 दिसंबर 2015 तक पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा प्रदान की गई पासपोर्ट सेवाओं की संख्या प्रदर्शित करने का विवरण

आरपीओ	प्राप्त किए गए पासपोर्ट आवेदनों की कुल सं. (सामान्य + तत्काल)	जारी किए गए सामान्य पासपोर्ट की सं.	जारी किए गए तत्काल पासपोर्ट की सं.	जारी किए गए पासपोर्टों की कुल सं. (सामान्य + तत्काल)	प्राप्त विविध आवेदनों की संख्या	जारी की गई विविध सेवाओं की सं.	जारी किए गए कुल पासपोर्ट और विविध सेवाओं की सं.
अहमदाबाद	5,35,962	5,37,303	6,910	5,44,213	21,282	21,294	5,65,507
अमृतसर	1,25,094	1,26,752	1,997	1,28,749	7,276	7,114	1,35,863
बैंगलोर	6,30,602	5,74,608	43,807	6,18,415	14,251	14,474	6,32,889
बरेली	1,43,121	1,65,889	3,114	1,69,003	3,859	3,937	1,72,940
भोपाल	1,55,473	1,57,935	4,607	1,62,542	2,048	2,034	1,64,576
भुवनेश्वर	1,00,605	1,01,758	1,550	1,03,308	4,678	4,545	1,07,853
चंडीगढ़	4,43,495	4,30,558	11,936	4,42,494	20,236	20,667	4,63,161
चेन्नई	3,96,058	3,85,479	18,722	4,04,201	16,564	16,440	4,20,641
कोचीन	3,95,492	3,15,100	77,447	3,92,547	27,553	27,746	4,20,293
कोयंबटूर	1,29,463	1,28,441	1,190	1,29,631	2,453	2,525	1,32,156
देहरादून	80,930 7	8,349	3,206	81,555	2,589	2,759	84,314
दिल्ली	5,10,330	4,30,971	65,450	4,96,421	9,672	9,423	5,05,844
गाजियाबाद	2,06,421	2,00,982	12,121	2,13,103	3,030	2,976	2,16,076
गोवा	46,611	44,969	334	45,303	6,271	6,270	51,573
गोवाहाटी	85,428	75,485	6,773	82,258	1,957	1,958	84,216
हैदराबाद	6,97,299	6,89,700	25,528	7,15,228	42,661	44,275	7,59,503
जयपुर	2,97,636	2,92,275	5,542	2,97,817	13,178	13,159	3,10,976
जालंधर	2,56,322	2,57,459	483	2,57,942	27,755	27,876	2,85,818
जम्मू	37,285	38,262	72	38,334	4,485	2,017	40,351
कोलकाता	5,59,536	5,73,657	22,433	5,96,090	17,178	17,032	6,13,122
कोझीकोड	2,82,972	2,54,462	28,977	2,83,439	8,826	8,829	2,92,268
लखनऊ	8,54,872	8,87,611	28,126	9,15,737	32,220	31,863	9,47,600
मदुरई	2,47,508	2,51,928	66	2,51,994	11,269	11,633	2,63,627
मालापुरम	2,13,198	1,81,538	27,334	2,08,872	3,381	3,371	2,12,243
मुंबई	4,30,002	4,14,596	32,647	4,47,243	10,748	11,021	4,58,264
नागपुर	1,12,807	1,13,238	4,391	1,17,629	1,833	1,829	1,19,458
पटना	3,13,744	3,47,642	2,081	3,49,723	16,185	15,891	3,65,614
पुणे	2,82,722	2,64,674	20,481	2,85,155	5,428	5,166	2,90,321
रायपुर	39,415	37,666	762	38,428	376	356	38,784
रांची	81,540	80,440	1,154	81,594	2,799	2,768	84,362
शिमला	39,398	37,477	3,280	40,757	1,857	1,873	42,630
श्रीनगर	71,280	72,142	216	72,358	2,190	290	72,648
सूरत	1,75,023	1,73,569	3,080	1,76,649	9,131	9,324	1,85,973

जारी है......

01 जनवरी से 31 दिसंबर 2015 तक पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा प्रदान की गई पासपोर्ट सेवाओं की संख्या प्रदर्शित करने का विवरण

आरपीओ	प्राप्त किए गए पासपोर्ट आवेदनों की कुल सं. (सामान्य + तत्काल)	जारी किए गए सामान्य पासपोर्ट की सं.	जारी किए गए तत्काल पासपोर्ट की सं.	जारी किए गए पासपोर्टों की कुल सं. (सामान्य + तत्काल)	प्राप्त विविध आवेदनों की संख्या	जारी की गई विविध सेवाओं की सं.	जारी किए गए कुल पासपोर्ट और विविध सेवाओं की सं.
थाणे	3,03,847	2,99,392	17,775	3,17,167	7,016	7,106	3,24,273
त्रिची	1,95,600	1,96,739	474	1,97,213	12,073	13,844	2,11,057
त्रिवेंद्रम	2,09,856	1,89,793	19,580	2,09,373	13,334	13,412	2,22,785
विशाखापट्नम	2,13,603	2,13,883	3,274	2,17,157	13,166	14,684	2,31,841
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4,393	0	0	4,393	0	0	4,393
कुल	**99,04,943**	**96,22,722**	**5,06,920**	**1,01,34,035**	**4,00,808**	**4,01,781**	**1,05,35,816**
(1)	38 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (पासपोर्ट + विविध सेवाएं = **1,01,34,035+4,01,781**						**1,05,35,816**
	पीवी–**II**, विदेश मंत्रालय, और भारत में पासपोर्ट कार्यालय (सरकारी एवं राजनयिक पासपोर्ट) = **2,547+27,138**						**29,685**
	क्षे.पा.का. दिल्ली जारी (आईसी)						**3,852**
	अभ्यर्पित प्रमाणपत्र एवं जारी किए गए एलओसी						**9,228**
(2)	भारतीय मिशन / पोस्ट द्वारा पीपीटी + ईसीएस + विविध सेवाएं						**13,85,687**
	कुल योग (1+ 2)						**1,19,64,268**

31 दिसंबर 2015 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय पासपोर्ट संगठन की कैडर क्षमता

I समूह एवं पद का नाम	कुल स्वीकृत संख्या
समूह 'क'	
पासपोर्ट अधिकारी	17
उप पासपोर्ट अधिकारी	71
सहायक पासपोर्ट अधिकारी	135
उप योग :	223
समूह 'ख' ञराजपत्रित)	
पासपोर्ट प्रदाता अधिकारी	320
अधीक्षक	245
उप योग :	565
समूह 'ख' ञअराजपत्रित)	
सहायक	428
हिंदी अनुवादक	23
आशुलिपिक ग्रेड ८	17
उप योग :	468
समूह 'ग' (अराजपत्रित)	
अपर श्रेणी लिपिक	628
अपर श्रेणी लिपिक (हिंदी)	04
अवर श्रेणी लिपिक	648
ड्राइवर	00
आशुलिपिक ग्रेड ।।	13
कार्यालय सहायक	148
उप योग :	1441
Ii पासपोर्ट सेवा परियोजना की परियोजना प्रबंधन इकाई (पी एम यू) को जनशक्ति प्रदान करने के 2007 के केंद्रीय मंत्रि परिषद के निर्णय के द्वारा सृजित किए गए पद	
तकनीकी	15
प्रशासनिक	06
उप योग :	**21**
महा योग (I+II)	**2718**

31 मार्च, 2016 तक की स्थिति के अनुसार मुख्यालय तथा विदेश स्थित मिशनों / केंद्रों में संवर्ग सं. (वाणिज्य मंत्रालय द्वारा बजट में शामिल किए गए पदों एवं पूर्व संवर्ग आदि पदों सहित)

क्र. सं.	संवर्ग / पद	मुख्यालयों में पद	मिशनों में पद	कुल
1	ग्रेड-I	5	28	33
2	ग्रेड-II	6	40	46
3	ग्रेड-III	38	126	164
4	ग्रेड-IV	54	148	202
5	कनिष्ठ प्रशानिक ग्रेड / वरिष्ठ वेतनमान	98	231	329
6	(i) वरिष्ठ वेतनमान	10	25	35
	(ii) परिवीक्षा आरक्षित	62		62
	(iii) अवकाश आरक्षित	15		15
	(iv) प्रतिनियुक्ति आरक्षित	19		19
	(v) प्रशिक्षण आरक्षित	7		7
	उप योग I	**314**	**598**	912
	भारतीय विदेश सेवा (ख)			
7	(i) ग्रेड I	118	125	243
	(ii) प्रतिनियुक्ति आरक्षित	6		6
8	(i) एकीकृत ग्रेड II और III	341	223	564
	(ii) अवकाश आरक्षित	30		30
	(iii) प्रतिनियुक्ति आरक्षित	16		16
	(iv) प्रशिक्षण आरक्षित	25		25
9	(i) ग्रेड IV	188	526	714
	(ii) अवकाश आरक्षित	60		60
	(iii) प्रतिनियुक्ति आरक्षित	55		55
10	(i) ग्रेड V/VI	157	88	245
	(ii) अवकाश आरक्षित	60		60
	(iii) प्रतिनियुक्ति आरक्षित	14		14
11	(i) साइफर संवर्ग का ग्रेड II	47	47	94
	(ii) अवकाश आरक्षित	5		5
12	(i) आशुलिपिक संवर्ग	377	509	886
	(ii) अवकाश आरक्षित	47		47
	(पपप) प्रशि.ा आरक्षित ूहिन्दी)	10		10
	(iv) प्रतिनियुक्ति आरक्षित	12		12
13	दुभाषिया संवर्ग	20	3	23
14	एल और टी संवर्ग	20	3	23
	उप योग II	**1595**	**1547**	**3142**
	महा योग (उप योग I+II)	**1909**	**2145**	**4054**

01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक की अवधि के लिए आरक्षित रिक्तियों सहित सीधी भर्ती, विभागीय पदोन्नति तथा मंत्रालय में कराई गई सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से भर्ती संबंधी आकड़े

क्र. सं.	समूह	रिक्तियों की कुल संख्या	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ. पि. वर्ग
1.	समूह क'	165	19	12	12
2.	समूह ख	260	89	50	60
3.	समूह ग	182	1	19	70
	योग	607	109	81	142

विभिन्न भाषाओं में प्रवीणता के साथ भा. वि. से. अधिकारियों की संख्या (2015–16)

क्र. सं.	भाषा	अधिकारियों की संख्या
1.	अरबी	95
2.	भाषा इंडोनेशिया	10
3.	भाषा माले	1
4.	भाषा थाई	1
5.	बर्मी	6
6.	चीनी	75
7.	फ्रेंच	83
8.	जर्मन	31
9.	हीब्रू	6
10.	जापानी	25
11.	कजख	1
12.	किसवाहिली	2
13.	कोरेन	5
14.	फारसी	20
15.	पुर्तगाल	22
16.	पुश्तु	2
17.	रूसी	90
18.	सर्बी–क्रोएशिया	1
19.	सिंहली	3
20.	स्पैनिश	78
21.	तुर्की	7
22.	यूक्रेनियन	1
23.	वियतनामी	4
24.	**कुल**	569

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद – सम्मेलन और संगोष्ठियां
अप्रैल – नवम्बर 2016

क्र. सं.	सम्मेलन / संगोष्ठी का शीर्षक	सम्मेलन के विवरण / संगोष्ठी
1	**भारत–कोरियाई संबंधों में नए परिवर्तनशील रूप में विरासत साझा करना : अयोध्या की राजकुमारी की विरासत कथा और उनकी ऐतिहासिकता**	इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी), नई दिल्ली के सहयोग से 14–15 जुलाई 2015 को एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें कोरिया (कोरिया गणराज्य) के सात और भारत के नौ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मई, 2015 (20 सूत्री, यात्रा के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी) में दक्षिण कोरिया की अपनी यात्रा के दौरान भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा यह संगोष्ठी आयोजित की गई थी। संगोष्ठी का उद्देश्य अयोध्या राजकुमारी की कथा की ऐतिहासिकता का विश्लेषण और उस कथा का उपयोग करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना था। पौराणिक कथा के अनुसार, अयोध्या से राजकुमारी सुरीरत्ना ने 48 ईस्वी में कोरिया से भारत की यात्रा की और प्रिंस किम सुरो के साथ शादी की तथा इस तरह गराक कबीले की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा विद्वानों ने पौराणिक कथा भी प्रस्तुत की तथा भारत और कोरिया और इसके प्रभाव के बीच सदियों पुराने संबंधों के विभिन्न पहलुओं का विस्तार से विश्लेषण किया। प्रो लोकेश चंद्र, अध्यक्ष, आईसीसीआर ने 14 जुलाई 2015 की सुबह में संगोष्ठी का उद्घाटन किया।
2	**सॉफ्ट पावर के कई रूप : भारत और विश्व**	भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला के सहयोग से 14–16 सितम्बर 2015 के दौरान एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में संस्कृति, प्रशासन, फिल्म अध्ययन, मीडिया, इतिहास, खेल और समाजशास्त्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों ने भाग लिया था।
3	**भगवद्‌गीता और उसकी समकालीन प्रासंगिकता**	नेहरू सेंटर, लंदन में 24–25 सितम्बर, 2015 को एक दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें विभिन्न यूरोपीय देशों से ग्यारह प्रतिभागियों और सात भारतीय विद्वानों ने भाग लिया। ग्रेट ब्रिटेन में 24 सितंबर, 2015 को आयोजित उद्‌घाटन समारोह में भारत के उच्चायुक्त, महानिदेशक, आईसीसीआर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। यह सम्मेलन लंदन में भारतीय उच्चायोग, लंदन के एसओएएस विश्वविद्यालय, एसआरईआई फाउंडेशन और संस्कृत @ सेंट. जेम्स के सहयोग से आयोजित किया गया था।
4	**कश्मीर की ऋषि–सूफी परंपराएं**	मध्य एशियाई अध्ययन केंद्र, कश्मीर विश्वविद्यालय और जम्मू–कश्मीर कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी के साथ गांधी भवन, कश्मीर विश्वविद्यालय के सहयोग से 25–27 अक्टूबर 2015 को आईसीसीआर द्वारा 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्‌घाटन श्री एन एन वोहरा, माननीय राज्यपाल, जम्मू–कश्मीर द्वारा किया गया। समारोह में अन्य गणमान्य व्यक्ति, श्री सी राजशेखर, महानिदेशक, आईसीसीआर, प्रो खुर्शीद अंद्राबी, कुलपति, कश्मीर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर जी एन खाकी, निदेशक, मध्य एशियाई अध्ययन केंद्र, कश्मीर विश्वविद्यालय और सुश्री कामना प्रसाद, शैक्षणि ाक समन्वयक उपस्थित थे। इस सम्मेलन में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश, ईरान और ऑस्ट्रिया से पांच विदेशी विद्वान और पांच जम्मू–कश्मीर क्षेत्र से विद्वान थे। इसमें पूरे भारत से पांच विद्वान थे।

जारी है......

5	**भारत, रूस और पड़ोसी देशों में संस्कृत और विद्वान अध्ययन : भूत, वर्तमान और भविष्य**	मास्को के रूसी मानविकी राज्य विश्वविद्यालय (आरएसयूएच) के सहयोग से 28–29 अक्तूबर 2015 के बीच तीन दिनों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। रूस में भारत के राजदूत, माननीय पी. एस. राघवन ने 27 अक्टूबर 2015 को सम्मेलन का उद्घाटन किया जिसमें प्रो. ई. आई. पाइवोवार, रेक्टर, आरएसयूएच भी उपस्थित थे। सम्मेलन में भारत से 6 विद्वानों, बेलारूस, कजाखस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान से 4 विद्वानों और रूस के विभिन्न शहरों से 11 विद्वानों ने भाग लिया।
6	**अंतरराष्ट्रीय विद्वान सम्मेलन – 2015**	शष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में 21–23 नवंबर 2015 में एक तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें विदेश से इक्कीस प्रतिभागियों और सात भारतीय प्रतिभागियों ने भाग लिया। भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल में उद्घाटन समारोह आयोजित किया, विदेश मंत्री, श्रीमती सुषमा स्वराज, अध्यक्ष, आईसीसीआर, प्रो लोकेश चंद्र, पूर्व अध्यक्ष, आईसीसीआर, डॉ कर्ण सिंह, विभिन्न देशों के दूतावासों और उच्चायोग, विद्वानों और शिक्षाविदों के अलावा प्रतिष्ठित अधिकारियों ने भी भाग लिया। उद्घाटन समारोह में, भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रख्यात जर्मन विद्वान, प्रो हेनरिक फ्रेहेर वॉन स्टिइटेनकॉर्न को प्रथम गणमान्य विद्व ान पुरस्कार प्रस्तुत किया गया था। उद्घाटन और समापन सत्र के अलावा, सम्मेलन में आठ शैक्षणिक सत्र, डॉ कर्ण सिंह और प्रो नमन आहूजा द्वारा दो विशेष व्याख्यान दिए गए और एक परस्पर संवादात्मक सत्र किया गया। अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों ने भारतीय धर्म और संस्कृति की एक झलक पाने के लिए 24 नवंबर को ऋषिकेश और हरिद्वार का दौरा किया।

परिशिष्ट – XIII

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद

प्रदर्शनियां (बाह्य और आंतरिक)

अप्रैल – नवंबर 2015

बाह्य प्रदर्शनियां

क्र. सं.	देश	प्रदर्शनियों और कलाकारों के नाम	प्रदर्शन की अवधि
1.	स्पेन	श्री अमित मिश्रा द्वारा भारत के धर्म	अप्रैल - जुलाई, 2015
2.	ट्यूनीशिया	श्री काशीनाथ दास द्वारा भारत के स्मारक	अप्रैल - नवंबर, 2015
3.	ट्यूनीशिया	श्री बिनॉय के बहल द्वारा भारत के इस्लामी स्मारक	अप्रैल - नवंबर, 2015
4.	स्लोवेनिया	टैगोर की कलाकृति के डिजिटल प्रिंट	मई - अक्तूबर, 2015
5.	तंजानिया	अंजलि इला मेनन द्वारा 'कल्पना – आलंकारिक भारतीय समकालीन चित्रों की कृतियां'	मई - जून, 2015
6.	फिलिस्तीन	श्री बिनॉय के बहल द्वारा 'भारत के इस्लामी स्मारक'	मई - अगस्त, 2015
7.	रीयूनियन द्वीप	सुश्री राधिका श्रीनगेश द्वारा 'महिलाओं द्वारा महिलाएं'	अगस्त - नवंबर, 2015
8.	हंगरी	फुलकारी	अगस्त - सितंबर, 2015
9.	नीदरलैंड	साड़ी :श्रीमती रीता कपूर चिश्ती द्वारा भारतीय बुनाई का जादू	सितंबर – अक्तूबर, 2015
10.	ओमान	वस्त्रम - सुश्री शैली ज्योति द्वारा भारतीय वस्त्रों की शानदार दुनिया	अक्तूबर, 2015
11.	स्पेन	श्री चन्द्र शेखर जैन द्वारा चेतना की धारा	अक्तूबर –दिसंबर, 2015

समर्थन विस्तारित

क्र. सं.	समर्थन पाने वाले देश	टिप्पणियां
1.	भारत का महावाणिज्य दूतावास, हो ची मिन्ह सिटी, वियतनाम	युद्ध के दौरान वियतनाम को भारत के समर्थन और राष्ट्रपति हो ची मिन्ह तथा भारत के साथ संबंध की झलक पर प्रदर्शनी लगाने के लिए।
2.	सुश्री कुसुम जैन, कोलकाता क्षेत्र के लिए भारत – वियतनाम एकता समिति, कोलकाता की महासचिव, हो ची मिन्ह सिटी – कोलकाता	युद्ध के दौरान वियतनाम को भारत के समर्थन और राष्ट्रपति हो ची मिन्ह तथा भारत के साथ संबंध की झलक पर प्रदर्शनी के लिए।
3.	दिल्ली – ब्रसेल्स – दिल्ली क्षेत्र के लिए सुश्री भारती दयाल	पवित्र कला के संग्रहालय (एमओएसए), बेल्जियम में अपनी प्रदर्शनी के प्रदर्शन के लिए

आंतरिक प्रदर्शनियां

क्र. सं.	देश	प्रदर्शनियों का नाम	प्रदर्शन की अवधि
1.	दिल्ली	रोइरिच इंटरनेशनल सेंटर, मास्को के साथ सहयोग में 'रोरिक पैक्ट' इतिहास और आधुनिकता	15 - 27 मई, 2015

"क्षितिज" श्रृंखला के तहत प्रदर्शनियां

क्र. सं.	प्रदर्शित	प्रदर्शनी एवं कलाकार	प्रदर्शन की अवधि
1.	आजाद भवन आर्ट गैलरी, दिल्ली	सुश्री तबस्सुम मलिक, दिल्ली स्थित कलाकार द्वारा चित्रकला प्रदर्शनी	10 - 15 अप्रैल 2015
2.	आजाद भवन आर्ट गैलरी, दिल्ली	सुश्री मुक्ता गुप्ता, जमशेदपुर स्थित कलाकार द्वारा चित्रकला प्रदर्शनी	17 - 22 अप्रैल 2015
3.	आजाद भवन आर्ट गैलरी, दिल्ली	अमरेश कुमार, पटना स्थित कलाकार द्वारा मूर्तियों की प्रदर्शनी	24 - 29 अप्रैल 2015
4.	आजाद भवन आर्ट गैलरी, दिल्ली	सुश्री उषा वोहरा, जम्मू–कश्मीर स्थित कलाकार द्वारा फोटो प्रदर्शनी 'जांस्कर – इंद्रधनुष माउंटेन'	12 - 17 जून 2015

जारी है........

क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रदर्शनी

1.	**बैंगलोर**	मैत्री – जयपुर में चीन – भारत की महिला कलाकारों की रेजीडेंसी के दौरान कलाकारों द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शनी	15 - 15 मई 2015
2.	**चेन्नई**	मैत्री – जयपुर में चीन –भारत की महिला कलाकारों की रेजीडेंसी के दौरान कलाकारों द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शनी	1 - 7 जून 2015
3.	**तिरुवनंतपुरम**	मैत्री – जयपुर में चीन –भारत की महिला कलाकारों की रेजीडेंसी के दौरान कलाकारों द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शनी	10 - 15 जून 2015
4.	**गोवा**	मैत्री – जयपुर में चीन – भारत की महिला कलाकारों की रेजीडेंसी के दौरान कलाकारों द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शनी	20 - 30 जून 2015
5.	**हैदराबाद**	मैत्री – जयपुर में चीन – भारत की महिला कलाकारों की रेजीडेंसी के दौरान कलाकारों द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शनी	6 - 13 जुलाई 2015
6.	**कोलकाता**	मैत्री – जयपुर में चीन – भारत की महिला कलाकारों की रेजीडेंसी के दौरान कलाकारों द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शनी	20 - 31 जुलाई 2015
7.	**गुवाहाटी**	मैत्री – जयपुर में चीन – भारत की महिला कलाकारों की रेजीडेंसी के दौरान कलाकारों द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शनी	1 - 9 सितम्बर 2015
8.	**शिलांग**	मैत्री – जयपुर में चीन – भारत की महिला कलाकारों की रेजीडेंसी के दौरान कलाकारों द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शनी	14 - 18 सितम्बर 2015
9.	**पुणे**	मैत्री – जयपुर में चीन – भारत की महिला कलाकारों की रेजीडेंसी के दौरान कलाकारों द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शनी	31 अक्तूबर - 8 नवम्बर 2015
10.	**मुंबई**	मैत्री – जयपुर में चीन – भारत की महिला कलाकारों की रेजीडेंसी के दौरान कलाकारों द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शनी	16 - 22 नवम्बर 2015

निवास / शिविर

क्र. सं.	रेजीडेंसी का नाम	अवधि
1.	शंघाई, चीन में भारत – चीन महिला कलाकारों की रेजीडेंसी 'मैत्री'	24-30 अक्तूबर 2015

आईआरएस प्रकाशन
पुस्तकें और रिपोर्ट

- दक्षिण एशिया आर्थिक संघ की ओर; एआईसी – आरआईएस, नई दिल्ली, 2015
- आसियान–भारत सांस्कृतिक संबंध : ऐतिहासिक और समकालीन आयाम; एआईसी – आरआईएस, नई दिल्ली, 2015
- भारत–अफ्रीका भागीदारी सतत विकास की दिशा; आरआईएस, नई दिल्ली, 2015
- साझा करने के तर्क : दक्षिण–दक्षिण सहयोग के प्रति भारतीय दृष्टिकोण; नई दिल्ली, 2015
- आसियान–भारत विकास और सहयोग की रिपोर्ट 2015; एआईसी दृ आरआईएस, नई दिल्ली, 201
- हिंद महासागर में नील अर्थव्यवस्था की संभावनाएं; एस के मोहंती, प्रियदर्शी दाश, आस्था गुप्ता, पंखुड़ी गौर, आरआईएस, नई दिल्ली, 2015
- स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में भारत अफ्रीका भागीदारी : उपलब्धियां और संभावनाएं; टी सी जेम्स, प्रतिवा शॉ, पायल चटर्जी, दीप्ति भाटिया, आरआईएस, नई दिल्ली, 2015
- भारत–कोरिया सीईपीए – प्रगति का मूल्यांकन; वी एस शेषाद्रि एआईसी–आरआईएस नई दिल्ली, 2015
- आसियान–भारत आर्थिक संबंध : थिंक टैंक (एआईएनटीटी) के आसियान–भारत संबंध में तीसरे गोलमेज सम्मेलन के अवसर और चुनौतियां कार्रवाई; एआईसी–आरआईएस, नई दिल्ली, 2015
- दक्षिण एशिया विकास और सहयोग की रिपोर्ट 2015; आरआईएस, 2015
- भारत और एपीईसी : वी. एस. शेषाद्री एआईसी द्वारा एक मूल्यांकन; एआईसी–आरआईएस नई दिल्ली 2015
- विश्व व्यापार और विकास रिपोर्ट; आरआईएस, नई दिल्ली, 2015

पत्रिकाएं

- दक्षिण एशिया आर्थिक पत्रिका, खण्ड 16, सं. 2, सितंबर 2015
- एशियाई जैव प्रौद्योगिकी और विकास की समीक्षा : सतत विकास लक्ष्यों में विशेष मुद्दे, खण्ड 17, सं. 2, जुलाई 2015
- दक्षिण एशिया आर्थिक पत्रिका, खण्ड 16, सं. 2 (पूरक अंक)

नीति संक्षिप्त

- सं. 74 : अंडरसी पाइपड्रीम्स और इंडियन एनर्जी सिक्योरिटी, सितंबर 2015
- सं. 73 : मेक इन इंडिया : भारत में राज्य का विनिर्माण, सितंबर 2015
- सं. 72 : आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली का एक नया स्वरूप, मई 2015
- सं. 71 : देश का वर्गीकरण और जी–20, मई 2015
- सं. 70 : प्रवेश, इक्विटी और समावेशन : नैतिक मानदंड और एस एंड टी नीति परिणाम, मई 2015
- सं. 69 : प्रवेश, प्रौद्योगिकी विकास और राष्ट्रीय आईपीआर नीति, मई 2015
- सं. 68 : नए विकास बैंक : विकास वित्त के लिए एक योगदान, मई 2015

चर्चा पत्र

- सं. 200 : प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निर्धनता उन्मूलन : मनमोहन अग्रवाल और प्रज्ञा अत्री द्वारा क्षेत्रीय संदर्भ में भारत
- सं. 199 : 'मेक इन साउथ एशिया' की दिशा : क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला का विकास, राम उपेंद्र दास द्वारा
- सं. 198 : चीनी उत्पादन में इथियोपिया के साथ भारत विकास सहयोग : सुशील कुमार द्वारा एक आकलन
- सं. 197 : भारतीय विश्वविद्यालयों में नवाचार को बढ़ावा देना : विश्वविद्यालय उद्योग इंटरफ़ेस का एक सैद्धांतिक मॉडल, सब्यसाची साहा द्वारा
- सं. 196 : पुनः विन्यस्त अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं : ब्रिक्स पहल, मनमोहन अग्रवाल द्वारा

आरआईएस डायरी

- खण्ड 11 सं. 2, अप्रैल 2015
- खण्ड 11 सं. 3, जुलाई 2015
- खण्ड 11 सं. 4, अक्तूबर 2015
- खण्ड 12 सं. 11, जनवरी 2016

एआईसी समाचार पत्रिका

- खण्ड 1 सं. 1, जुलाई 2015

एफडीआईसी नीति संक्षिप्त

- सं. 5 : दक्षिण–दक्षिण सहयोग और भारत : एफडीआईसी बहु हितधारक नीतिगत वार्ताओं की अंतर्दृष्टि, अगस्त 2015

2015-16 का बजट आबंटन (बीई) 14,966.83 करोड़ रुपए है जो बीई 2014–15 की तुलना में 1.7 प्रतिशत अधिक है।

विदेश मंत्रालय का वास्तविक व्यय 2008–09 से 2014–15 (राजस्व और पूंजी)

वर्ष	वास्तविक (रुपए करोड़ में)	विगत वर्ष से प्रतिशतता में अंतर
2008-09	6630.73	45.02
2009-10	6290.77	-5.13
2010-11	7153.27	13.71
2011-12	7872.76	10.06
2012-13	10120.88	28.55
2013-14	11807.36	16.66
2014-15	12148.82	24.75

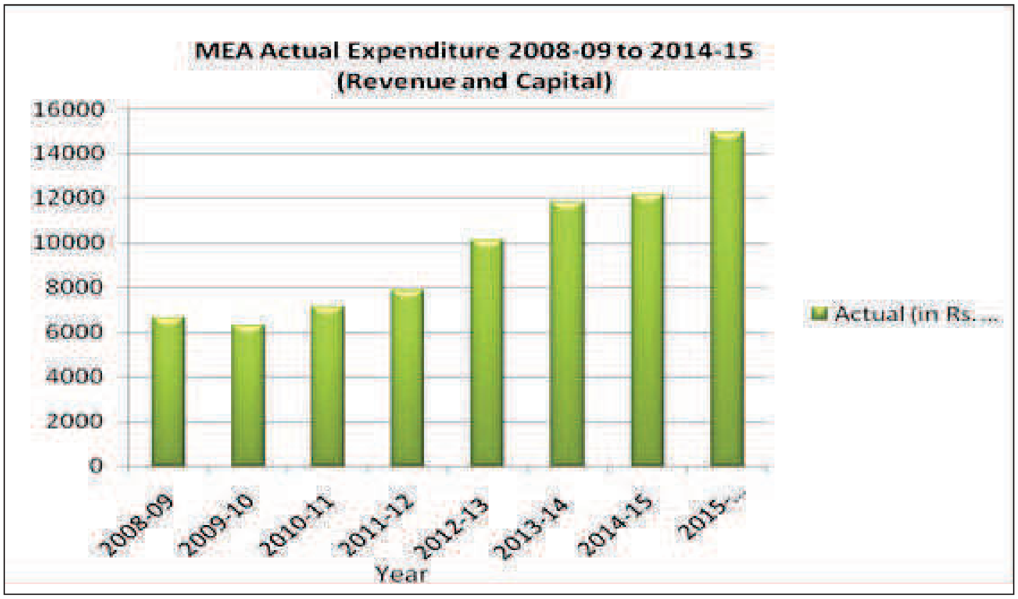

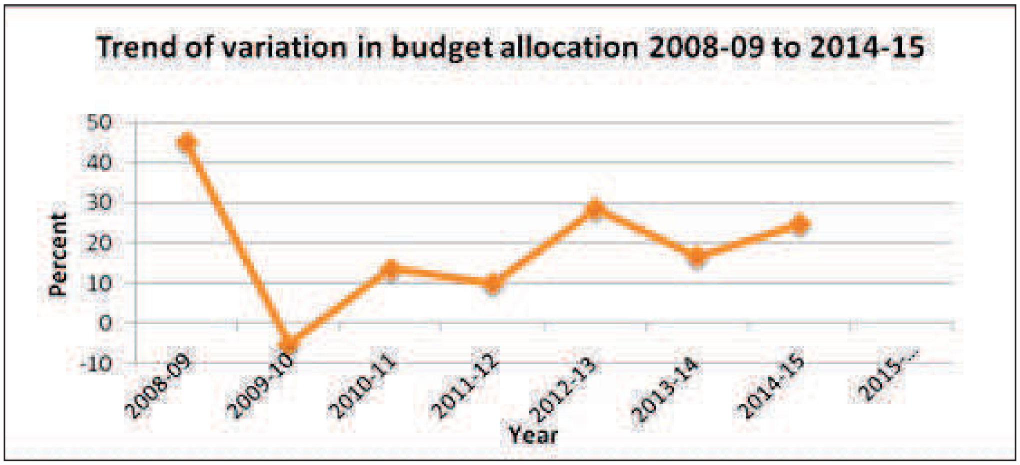

2015-16 में प्रमुख क्षेत्रवार आबंटन (बजट अनुमान)

क्षेत्र	आबंटन (करोड़ रुपए में)
तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग	5708.22
दूतावास और मिशन	2265.01
विदेशी सरकारों के लिए ऋण और अग्रिम	3398.80
विशेष राजनयिक व्यय	1650.01
पासपोर्ट और आप्रवास	597.72
अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए योगदान	386.03
विदेश मंत्रालय के सचिवालय	297.98
पूंजीगत व्यय	330.00
संस्थाओं का अनुदान	214.43
अन्य	118.63
कुल	**14966.83**

प्रमुख क्षेत्रवार आबंटन (2015–16)

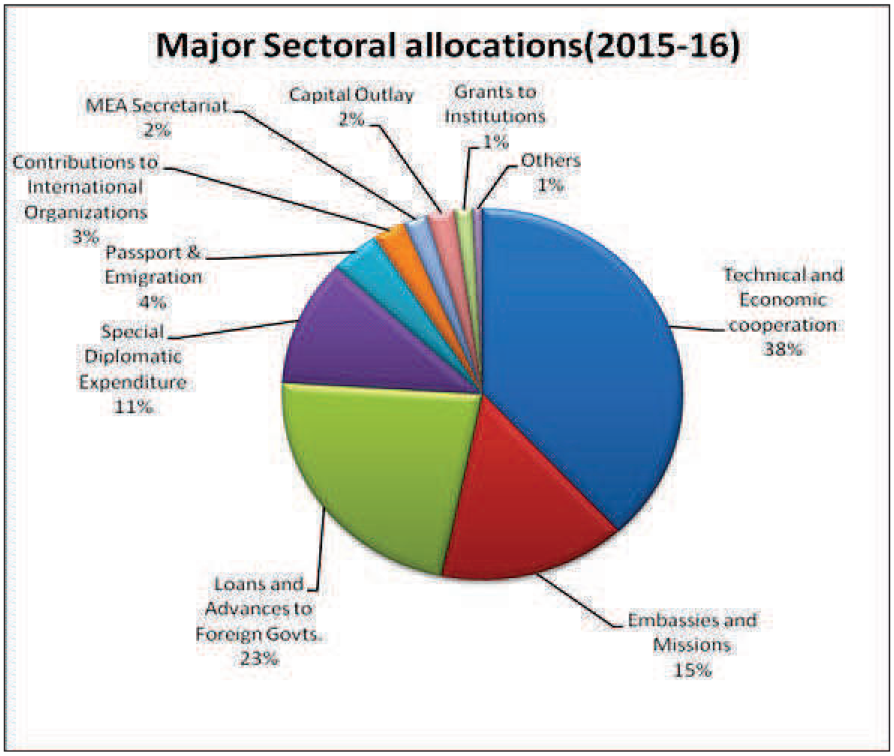

भारत के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य

वर्तमान वित्त वर्ष 2015–16 में भारत के तकनीकी सहयोग कार्यक्रमों के प्रमुख लाभग्राही इस प्रकार थे (ये आंकड़े बजट अनुमान 2015–16 से संबंधित हैं) :

क्र. स.	तकनीकी सहयोग बजट	(रुपए ककरोड़ में)	भारत की कुल सहायता एवं ऋण बजट का प्रतिशत
1.	भूटान	2919.40	32.06
2.	बांगलादेश	250.00	2.75
3.	अफगानिस्तान	676.00	7.42
4.	श्री लंका	500.00	5.49
5.	नेपाल	20.00	4.61
6.	म्यांमार	270.00	2.96
7.	अफ्रीकी देश	200.00	2.20
8.	यूरेशियाई देश	20.00	0.22
9.	मालदीव	25.00	0.27
10.	लैटिन अमेरिकी देश	15.00	0.16
11.	मंगोलिया	2.50	0.03
12.	अन्य	410.32	4.51
	कुल	**5708.22**	

03.12.2015 के अनुसार

लंबित सी एण्ड एजी लेखा परीक्षा के पैरों की स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	जिन पैराओं / पीए रिपोर्ट के संबंध में की गई कार्रवाई टिप्पणी लेखा परीक्षा के बाद पीएसी को प्रस्तुत की गई है, उनकी संख्या	जिन पैराओं/पीए रिपोर्ट के संबंध में एटीएन लंबित है उनका ब्यौरा		
			ऐसे एटीएन की संख्या जो पहली बार भी मंत्रालय द्वारा नहीं भेजी गई है।	ऐसे एटीएन की संख्या जो भेजी गई परन्तु टिप्पणी सहित वापस कर दी गई और मंत्रालय द्वारा लेखा परीक्षा को पुनः प्रस्तुत किए जाने की प्रतीक्षा है।	ऐसे एटीएन की संख्या जिन्हें लेखा परीक्षा द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षित किया गया है परन्तु उन्हें मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं किया गया है।
1	2010-11	-	-	-	-
2	2011-12	-	-	-	-
3	2012-13	-	-	-	-
4	2013	-	-	-	3
5	2014	-	-	3	3
6.	2015	-	2	-	1
कुल			**2**	**3**	**7**

सबसे नवीनतम लेखापरीक्षा रिपोर्टों (वर्ष 2014 और 2015 के लिए) में प्रदर्शित होने वाली महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सारांश 03/12/2015 नीचे दिए गए हैं: –

1	वैश्विक संपदा प्रबंध की निष्पादन लेखा–परीक्षा	डोमेन सूचना का अभाव और कार्य योजना की गैर तैयारी ऐसा देखा गया है कि अनिवार्य कार्य क्षेत्र (डोमेन) सूचना अर्थात् स्वामित्व वाले, किराए और पट्टे पर लिए गए चांसरी भवनों / दूतावास आवासों / स्टाफ आवासों इत्यादि की संख्या की जानकारी पहले से विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं थी। सूचना की अनुपलब्धता से पी.ए.सी. को दिए गए आश्वासन के अनुरूप किराए के दायित्व को घटाने के प्रति प्रणालीगत दृष्टिकोण की कमी का पता चलता है। पी.ए.सी. को दिए गए आश्वासन के बावजूद विदेश मंत्रालय को संपदा प्रबंध की कार्य योजना बनाना बाकी है। **संपत्ति अधिग्रहण में विलम्ब** मंत्रालय ने पी.ए.सी. को आश्वासन दिया था कि संपत्ति के अधिग्रहण एवं निर्माण से संबंधित आंतरिक प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने एवं उसमें तेजी लाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। जबकि लेखा परीक्षा द्वारा सात मामलों (जिनेवा एबर्न, हैमबर्ग, मुयुनिश, विश्केक, स्टॉकहोम और मिलान) को नोट किया गया था, निर्णय लेने में कमियां रह गई और विलंब हुआ। भूमि की खरीद / संपत्ति अधिग्रहण में विफलता के चलते 2011–12 के दौरान 7.83 करोड़ रुपए की किराया राशि खर्च हुई।

जारी है.......

		निर्माण गतिविधि में विलंब लेखा परीक्षा द्वारा 10 मामलों (शंघाई, पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट लउस, दार एस सलाम, काठमांडू, ताशकंद, कीव, ब्रासीलिया, दोहा और निकोसिया में संपत्तियों में निर्माण की शुरूआत में विलंब को नोट किया। ये विलंब ड्राइंग प्रस्तुत करने में विलंब अपेक्षित परिसंपत्तियों के प्रकार में पुष्टि करने में विफलता, परियोजना डिजाइनों को अंतिम रूपए दिए जाने, स्थानीय प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त होने में विलंब, परियोजना अपेक्षाओं में बार–बार परिवर्तन होने तथा अन्य क्रियाविधि संबंधी विलंब के कारण हुए। इस प्रकार के अधिकांश विलंब मंत्रालय की आंतरिक व्यवस्थाओं के कारण हुए। पी.ए.सी. ने संपत्ति प्रबंधन की विगत लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जाँच करने के दौरान विदेश मंत्रालय से यह भी अनुरोध किया था कि निर्माण पूर्व गतिविधियों में विलंब से बचने के लिए विशेष समय–सीमा निध्ंारित की जाए तथा अनुवीक्षण तंत्र स्थापित किया जाए। 2011–12 में इन मामलों में वार्षिक किराया खर्च 16.36 करोड़ रुपए था। **नवीकरण / पुनर्विकास गतिविधियों में विलंब** मंत्रालय द्वारा विभिन्न केंद्रों पर स्वामित्व वाले भवनों का नवीकरण / पुनर्विकास कार्य प्रारम्भ किया गया है। मंत्रालय / संबंधित मिशनों में रख–रखाव किए गए अभिलेखों की लेखा परीक्षा से पता चलता है कि चार केंद्रों सिडनी, हांगकांग, क्वालालंपुर और जकार्ता में 2011–12 के दौरान 7.44 करोड़ रुपए के परिहार्य किराया व्यय में अनियमिताएँ तथा व्याप्ति विलंब हुए थे। **भारत में निर्माण गतिविधियों में विलंब** घरेलू निर्माण परियोजनाओं में भी व्यक्तिगत दृष्टिकोण की कमी देखी गई थी। 5 परियोजनाओं (आर.पी.ओ. जयपुर, आर.पी.ओ. अमृतसर, आर.पी.ओ. मुम्बई, आर.पी.ओ. श्रीनगर और एफ.एसआई. दिल्ली) के रिकार्ड की लेखापरीक्षा से पता चला कि 22 वर्षों तक (आर.पी. जयपुर) परियोजनाओं को प्रारंभ करने में पर्याप्त विलंब हुआ। आर.पी.ओ. श्रीनगर में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था। हालांकि, भूमि 2006 में ही खरीद ली गई थी। अकेले 2011–12 के दौरान 3 आर.पी.ओ. (आर.पी.ओ. अमृतसर, आर.पी.ओ. मुम्बई, आर.पी.ओ. श्रीनगर) के संबंध में परिहार्य रैंटल आउटगो 3.98 करोड़ रुपए था।
2	वस्तुओं की खरीद में नियमों का उल्लंघन	भारत के महावाणिज्य दूत, अंटलाना ने नियमों का उल्लंघन करते हुए तथा उचित, पारदर्शी तथा सही प्रक्रिया का अनुपालन किए बगैर तीन अलग–अलग खरीदों में अर्थात् कम्प्यूटर हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर, कार्यालय उपस्कर तथा फर्नीचर / फिटिंग्स हेतु 1.61 करोड़ रुपए की खरीद की।
3	मासिक लेखे खाते में फर्जी भुगतान वाउचर / रसीद चालान	भारत के महावाणिज्य दूत, होस्टन, यू.एस.ए. ने 3,72,632 अमेरिकी डॉलर का फर्जी भुगतान वाउचर और 3,62,172 अमेरिकी डॉलर का रसीद चालान तैयार किया और इसे अपने मासिक खाते में डालकर मंत्रालय को प्रस्तुत किया रोकड़ बही में दर्शाए बिना 69,356 अमेरिकी डॉलर की निकासी की गई और 39,266 अमेरिकी डॉलर जमा किया गया। महावाणिज्य दूतावास का खाता गंभीर अशुद्धियों देखी गईं जो प्राप्तियों के कम लेखांकन और अलेखांकित आहरण से जोखिम भरा था।
4	परियोजना प्रबंधन दलों को विदेश भत्ते का अधिक भुगतान	मास्को और पैरिस स्थित मिशनों ने मास्को और पैरिस में परियोजना प्रबंधन दलों में तैनात भारतीय वायुसेना के 6 आधिकारियों को विदेश प्रतिपूरक भत्ते के स्थान पर विदेशी भत्ते का भुगतान किया। नवम्बर 2009 अगस्त 2013 के दौरान इन अधिकारियों को 74.69 लाख रुपए का अधिक भुगतान हुआ। (पैराग्राफ 5.4)
5	पासपोर्ट विविध सेवाओं हेतु शुल्क की कम उगाही	पासपोर्ट विविध सेवा शुल्क में संशोधन न किए जाने के कारण 1.52 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई। (पैराग्राफ 5.5)

जारी है......

6	सेवा प्रदाताओं को आबंधित वित्तीय लाभ	पासपोर्ट सेवाओं को अभ्यर्पित करने हेतु सेवा प्रभारों में अनियमित रूप से वृद्धि और ऐसी सेवाओं पर अननुमेय प्रशासनिक शुल्क की उगाही की वजह से सितंबर 2010 से मार्च 2013 के दौरान सेवा प्रदाता को 67.36 लाख रुपए अवांछित वित्तीय लाभ पहुँचा। (पैराग्राफ 5.6)
7	रोम में चांसरी भवन की खरीद करने में विफलता	मिशन और मंत्रालय जुलाई 2011 में गैर–योजना व्यय पर समिति द्वारा अपेक्षित अनुमति के बावजूद रोम में चांसरी के लिए इमारत की खरीद करने में असफल रहे तथा निर्गत खंड के बिना संपत्ति किराए पर रखने के कारण 41.71 करोड़ रुपए के एक प्रतिबद्ध दायित्व में परिणामस्वरूप धन की उपलब्धता हुई। (पैराग्राफ 5.1)
8	व्यापार वीजा शुल्क के अल्प संग्रह	व्यापार वीजा के मुद्दे पर मंत्रालय के निर्देशों का गैर कार्यान्वयन करने के कारण से मिशनों और पोस्ट विदेश में 10.20 करोड़ रुपए के व्यापार वीजा शुल्क की राशि का अल्प संग्रह किया गया। (पैराग्राफ 5.2)
9	मंजूरी के बिना आकस्मिक कर्मचारियों की नियुक्ति पर 429.81 लाख रुपए का अनधिकृत व्यय	मंत्रालय के नियमों और निर्देशों का उल्लंघन करते हुए भारत के महावाणिज्य दूतावासए ह्यूस्टन और शिकागो में आकस्मिक कर्मचारियों की नियुक्ति। (पैराग्राफ 5.3)

संक्षेपाक्षर

आलको	एशियाई अफ्रीकी विधिक परामर्शी संगठन
एआरएफ	आसियान क्षेत्रीय मंच
आसियान	दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ
एएसईएम	एशिया यूरोप बैठक
एसोचौम	एसोसिएट्स चौम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री
एयू	अफ्रीकी संघ
एडब्ल्यूजीएलसी	दीर्घावधिक सहयोगात्मक कार्रवाई पर एडी–एचओसी कार्य समूह
आयुष	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथिक
बार्क	भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
बिमस्टेक	बहु–क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल
बिप्पा	द्विपक्षीय निवेश संवर्धान तथा सुरक्षा करार विज्ञान संस्थान
ब्रिक	ब्राजील, रूस, भारत एवं चीन
सीबीएम	विश्वास उत्पादक उपाय
सीबीआरएन	रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल तथा परमाणु
सीका	व्यापक आर्थिक सहयोग करार
सीलैक	लातिन अमरीकी तथा कैरीबियाई देशों का समुदाय
सीईपीए	व्यापक आर्थिक भागीदारी करार
चोगम	राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की बैठक
सीआईआई	भारतीय उद्योग परिसंघ
सीएलएमवी	कंबोडिया, लाओ पीडीआर, बर्मा एवं वियतनाम
सीपीआईओ	मुख्य जन सूचना अधिकारी
सीपीवी	कोंसुलर, पासपोर्ट एवं वीजा
डीटीएए	दोहरा कर परिवर्जन करार
ईएएम	विदेश मंत्री
ईएएसए	विदेश मंत्रलय स्पाउजेज संघ
इकोसोक	आर्थिक एवं सामाजिक परिषद
ईईपीसी	इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद्
ईयू	यूरोपीय संघ
एक्जिम	भारतीय निर्यात–आयात बैंक
एफडीआई	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

फिक्की	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ
एफआईडीसी	भारतीय विकास सहयोग संघ
एफएमसीटी	फिसाइल सामग्री कट – ऑफ संधि
एफटीए	मुक्त व्यापार करार
जी–20	समूह 20
जीसीटीएफ	वैश्विक आतंकवाद निरोध मंच
जीएफएमडी	वैश्विक देशांतर तथा विकास मंच
जीओआई	भारत सरकार
एचईपी	जल–विद्युत परियोजना
एचआरसी	मानवाधिकार मंच
आईएएफएस	भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन
आईएएनएस	भारत–एशिया समाचार सेवा
इब्सा	भारत–ब्राजील–दक्षिण अफ्रीका वार्ता मंच
आई / सी	स्वतंत्र प्रभार
आईसीएओ	अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन
आईसीसीआर	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद
आईसीटी	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
आईसीडब्ल्यूए	भारतीय मामलों की विश्व परिषद
आईडीपी	आंतरिक विस्थापित व्यक्ति
आईडीएफआर	राजनय तथा विदेश संबंध संस्थान
आईडीएसए	रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान
आईईए	अंतरराष्ट्रीय उर्जा एजेंसी
आईएफएस	भारतीय विदेश सेवा
इग्नू	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
आईआईएफटी	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान
आईआईएमसी	भारतीय जनसंचार संस्थान
आईएलओ	अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन
आईओएम	अंतरराष्ट्रीय उत्प्रवासन संगठन
आईओएनएस	बौद्धिक विज्ञान संस्थान
आईओआरएआरसी	क्षेत्रीय सहयोग पर हिंद महासागर परिधि संघ
आईपीआर	बौद्धिक संपदा अधिकार
आईपीयू	अंतर–संसदीय संघ
आईआरईएनए	अंतरराष्ट्रीय पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी
इसरो	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
आईटेक	भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग
आईटीएमए	अंतरराष्ट्रीय वस्त्र विनिर्माता संघ
आईवीएफआरटी	उत्प्रवासन, वीजा तथा विदेशी पंजीकरण तथा ट्रैकिंग

जारी है....

जेसीबीसी	व्यापार सहयोग संयुक्त समिति
जेडब्ल्यूजी	संयुक्त कार्यकारी दल
एलसीएस	थल सीमा शुल्क केंद्र
एलडीसी	अल्पतम विकसित देश
एलओसी	ऋण श्रृंखला
एमईपी	यूरोपीय संसद सदस्य
मर्कोसुर	दक्षिणी शंकु देश बाजार
एमजीसी	मैकांग–गंगा सहयोग
एमओईएफ	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमपी	सांसद
एमटीसीआर	मिसाइल तकनीक नियंत्रण प्रणाली
नाम	गुट–निरपेक्ष आन्दोलन
नासा	राष्ट्रीय वैमानिकी तथा अंतरिक्ष प्रशासन
एनडीसी	राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज
एनजीओ	गैर–सरकारी संगठन
निफ्टी	राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान
एनपीटी	अप्रसार संधि
एनएससीएस	राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय
ओसीआई	भारतीय समुद्रपारीय नागरिकता
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन
ओपीसीडब्ल्यू	रासायनिक हथियार निषेध संगठन
ओटीएस	प्रशिक्षु अधिकारी
फारमैक्सिल	भारत भेषज निर्यात संवर्धन परिषद
पीआईओ	भारतीय मूल के व्यक्ति
पीएम	प्रधान मंत्री
पीटीए	अधिमानिक व्यापार करार
पीटीआई	भारतीय प्रेस ट्रस्ट
पीएसपी	पासपोर्ट सेवा परियोजना
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरजीओबी	भूटान की शाही सरकार
आरटीआई	सूचना का अधाकार
सार्क	दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग
साफ्टा	दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र
एसएयू	दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय
एसबीआई	भारतीय स्टेट बैंक
स्काप	अफ्रीकी कार्यक्रम के लिए विशेष राष्ट्रमण्डल सहायता
एससीओ	शंघाई सहयोग संगठन
एसडीपी	लघु विकास परियोजना
सेबी	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
एसईडी	सामरिक आर्थिक वार्ता
सिका	मध्य अमेरिकी एकीकरण प्रणाली
एसएमई	लघु एवं मझोले उद्यम
एसआर	विशेष प्रतिनिधिमंडल
टेरी	टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान
उनासुर	दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र संघ
अनसिट्रल	संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग
यूएसीओपीयूओएस	बाह् अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति
यूएनसीएसटीडी	विज्ञान तथा तकनीक विकास पर संयुक्त राष्ट्र समिति
यूएनसीटीएडी	संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूएनईपी	संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
यूनीस्काप	एशिया एवं प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग
यूनेस्को	संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन
यूएनएफसीसीसी	जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय
यूएनजीए	संयुक्त राष्ट्र महासभा
यूनिफिल	लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल
यूएनएससी	संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्
यूएनओडीसी	स्वापक तथा अपराध पर संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय
यूपीए	संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन
डब्ल्यूएचओ	विश्व स्वास्थ्य संगठन
डब्ल्यूआईपीओ	विश्व बौद्धिक अधिकार संगठन
डब्ल्यूटीओ	विश्व व्यापार संगठन
एक्सपीडी	विदेश प्रसार तथा लोक राजनय प्रभाग

VIII Ministerial Conference
Community of Democracies
"Democracy and Development"
San Salvador, El Salvador, July 22-24, 2015
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

INDIA AFRICA FORUM SUMMIT 2015

साझा दृष्टिकोण

सत्यमेव जयते

विदेश मंत्रालय
भारत सरकार

यह वार्षिक रिपोर्ट वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है **www.mea.gov.in**